



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 363]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 28, 2018/आश्विन 6, 1940

No. 363]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 28, 2018/ASVINA 6, 1940

## भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

(संसद् के अधिनियम द्वारा गठित)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2018

**सं. 1-CA(5)/69/2018.—** चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (5ख) के अनुसरण में, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) की परिषद् के 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संपरीक्षित लेखाओं और रिपोर्ट की एक प्रति जनसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित की जाती है।

### 69वीं वार्षिक रिपोर्ट

आईसीएआई की परिषद् को 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 69वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। 1 जुलाई, 1949 को संसद् के एक अधिनियम द्वारा आईसीएआई के प्रारंभ से लेखाकन वृत्ति का अत्यधिक विकास हुआ है। संस्थान, जिसे केवल 1700 सदस्यों के साथ स्थापित किया गया था, 1 जुलाई, 2018 को उसके सदस्यों की संख्या बढ़कर 2,82,193 तथा छात्रों की संख्या बढ़कर 7,25,632 से अधिक हो गई है। यह रिपोर्ट, परिषद् और इसकी विभिन्न समितियों की वर्ष 2017-2018 के दौरान की महत्वपूर्ण गतिविधियों और साथ ही संस्थान के 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखाओं की विशिष्टियों को उपदर्शित करती है। परिषद् इस अवसर पर इस रिपोर्ट में, इस अवधि के और जुलाई, 2018 के शुरूआती दिनों तक की अवधि के दौरान, सदस्यों और छात्रों के संबंध में की गई प्रमुख पहलों, महत्वपूर्ण घटनाओं, सांख्यिकीय रूपरेखाओं, आयोजित की गई संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के व्यौरों को भी समाविष्ट करती है। परिषद्, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की वृत्ति के समाज में विद्यमान वर्तमान सम्मान के लिए सदस्यों और छात्रों की सराहना करती है। इस उद्देश्य की पूर्ति सदस्यों और छात्रों द्वारा एक साथ मिलकर उपदर्शित की गई उत्कृष्टता, स्वतंत्रता और ईमानदारी के द्वारा हुई है।

### 1. परिषद्

तेइसवीं परिषद् का गठन 12 फरवरी, 2016 को तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। वर्तमान में, परिषद् 32 निर्वाचित सदस्यों और केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए गए 8 सदस्यों से मिलकर बनी है। इसकी संरचना पृथक रूप से दर्शित की गई है।

## 2. परिषद् की समितियां

परिषद् ने चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 17 के निबंधनानुसार 12 फरवरी, 2018 को चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की वृत्ति से संबंधित विषयों के बारे में स्थायी और विभिन्न अस्थायी समितियों/बोर्डों का गठन किया था। 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, परिषद् की विभिन्न स्थायी और अस्थायी समितियों और बोर्डों की 225 बैठकें आयोजित की गई थीं।

## 3. संपरीक्षक

मैसर्स हिंगोराणी एम. एंड कं., और मैसर्स खन्ना और आनंदनम वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आईसीएआई के संयुक्त संपरीक्षक थे।

## 4. स्थायी समिति

### 4.1 कार्यपालक समिति

कार्यपालक समिति आईसीएआई की परिषद् की स्थायी समितियों में से एक है। इस समिति के कृत्यों को चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 175 में विहित किया गया है। समिति आर्टिकलड सहायकों से संबंधित क्रियाकलापों का नियंत्रण, कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण करती है और सदस्यों से संबंधित कृत्यों का निष्पादन करती है, जैसे कि नामांकन, रजिस्टर से सदस्यों के नामों का हटाया जाना, व्यवसाय प्रमाणपत्र का रद्दकरण, उसे पुनः प्रदान करना, लेखांकन वृत्ति से भिन्न किसी अन्य कारबार या व्यवसाय में नियोजित होने के लिए अनुमति प्रदान करना। कार्यपालक समिति आईसीएआई की संपत्तियों, आस्तियों और निधियों की अभिरक्षक भी है और साथ ही आईसीएआई के कार्यालय के अनुरक्षण के लिए भी उत्तरदायी है।

### 4.2 वित्त समिति

वित्त समिति, जिसे चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 के अधीन स्थापित किया गया था, अन्य बातों के साथ, सत्य और सही लेखाओं को रखे जाने, वार्षिक बजट तैयार करने, निधियों के निवेश, निधियों से राजस्व और पूंजी दोनों प्रकार के व्ययों के लिए आहरण करने से संबंधित और अनुषंगी गतिविधियों का नियंत्रण, कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण करती है।

### 4.3 परीक्षा समिति

परीक्षा समिति, परीक्षाओं से संबंधित परिषद् के सभी कृत्यों का निर्वहन करती है। समिति ने, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मध्यवर्ती (आईपीसी) परीक्षाओं और फाइनल परीक्षाओं का 2 मई से 17 मई, 2017 के दौरान देश भर में और विदेशों में 450 केन्द्रों पर सुचारु रूप से संचालन किया था। उक्त मध्यवर्ती (आईपीसी) और फाइनल परीक्षाएं देने वाले और उन्हें उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार थी :-

	दोनों समूहों/समूहों में से किसी एक की परीक्षा देने वाले और उत्तीर्ण करने वाले		केवल समूह 1 की परीक्षा देने वाले और उत्तीर्ण करने वाले		केवल समूह 2 की परीक्षा देने वाले और उत्तीर्ण करने वाले	
	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले
मध्यवर्ती (आईपीसी)	49967	11550	66680	6562	65453	11440
फाइनल	34503	7928	41373	5717	38478	6234

इसके पश्चात्, समिति द्वारा, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मध्यवर्ती (आईपीसी) परीक्षाओं और फाइनल परीक्षाओं का 1 से 16 नवंबर, 2017 के दौरान देश भर में और विदेशों में 425 केन्द्रों पर सुचारु रूप से संचालन किया गया था। उक्त

मध्यवर्ती (आईपीसी) और फाइनल परीक्षाएं देने वाले और उन्हें उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार थी :-

	दोनों समूहों/समूहों में से किसी एक की परीक्षा देने वाले और उत्तीर्ण करने वाले		केवल समूह 1 की परीक्षा देने वाले और उत्तीर्ण करने वाले		केवल समूह 2 की परीक्षा देने वाले और उत्तीर्ण करने वाले	
	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले
मध्यवर्ती (आईपीसी)	49215	13149	72148	10042	65393	13330
फाइनल	30054	6841	39328	6257	39753	6006

इसके अलावा, सामान्य प्रवीणता परीक्षा (सीपीटी) संबंधी परीक्षाओं को 18 जून, 2017 और 17 दिसम्बर, 2017 को, विदेशों और देश भर में क्रमशः 372 और 327 परीक्षा केंद्रों पर सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। उक्त सीपीटी परीक्षाएं देने वाले और उन्हें उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार थी :-

	परीक्षाएं देने वाले अभ्यर्थी	उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी
18 जून, 2017 को आयोजित सीपीटी	88916	36028
17 दिसम्बर, 2017 को आयोजित सीपीटी	60586	23034

वर्ष के दौरान, अर्हतापश्च पाठ्यक्रम - सूचना प्रणाली संपरीक्षा - निर्धारण परीक्षा (आईएसए-एटी) का सफलतापूर्वक आयोजन 24 जून, 2017 को देश भर में 64 परीक्षा केन्द्रों पर किया गया था। एक अन्य आईएसए-एटी परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन 23 दिसंबर, 2017 को देश भर में 65 परीक्षा केन्द्रों पर किया गया था। उक्त परीक्षाओं को देने वाले और उन्हें उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार थी :-

	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले
24 जून, 2017 को आयोजित आईएसए-एटी	3533	766
23 दिसंबर, 2017 को आयोजित आईएसए-एटी	2641	370

बीमा और जोखिम प्रबंध तकनीकी परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन नवंबर, 2017 में देश भर में कराया गया था। इस परीक्षा को देने वाले और उसे उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार थी :-

	परीक्षा देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले
आईआरएम - तकनीकी परीक्षा	54	33

सदस्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कराधान – निर्धारण परीक्षा (आईएनटीटी-एटी) का सफलतापूर्वक आयोजन मई और नवंबर, 2017 के दौरान किया गया था। इस परीक्षा को देने वाले और उसे उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार थी :

	परीक्षा देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले
मई, 2017 में आयोजित आईएनटीटी – एटी	193	80
नवंबर, 2017 में आयोजित आईएनटीटी – एटी	131	20

नवंबर, 2017 में प्रबंध अकाउंटेंसी पाठ्यक्रम (एमएसी) (भाग 1), निगम प्रबंध पाठ्यक्रम (सीएमसी) (भाग 1), कर प्रबंध पाठ्यक्रम (टीएमसी) (भाग 1) और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि और विश्व व्यापार संगठन (आईटीएल एंड डब्ल्यूटीओ) (भाग 1) में अर्हतापश्च पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं का आयोजन भी किया गया था।

संस्थान अपनी परीक्षा संबंधी प्रक्रियाओं में, प्रश्नपत्र निर्धारित करने के प्रक्रम से आरंभ करते हुए परिणामों की घोषणा तक की प्रक्रियाओं में निरंतर रूप से सुधार करता रहा है, जिससे परीक्षा प्रणाली की सत्यनिष्ठा और संतता, जो कि पिछले सात दशकों से सुविख्यात है, अक्षुण्ण बनी रहे तथा उसे और अधिक मजबूत तथा विकसित किया जा सके।

संस्थान की परीक्षाएं सीए पाठ्यचर्या के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक विषय के संबंध में अवधारणात्मक समझ और साथ ही व्यावहारिक प्रयोग की जांच करती हैं, जिससे वे छात्र वृत्ति के पणधारियों की आशाओं पर खरे उतर सकें।

प्रश्नों की पूर्व अनुमानता की संभावनाओं को यथासंभव रूप से दूर रखते हुए छात्रों की विश्लेषणात्मक क्षमताओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए संस्थान की परीक्षाएं लगातार यह सुनिश्चित करती रहीं हैं कि अर्हित छात्र सुयोग्य वृत्तिक बन सकें।

**विशेष परीक्षा :** निम्नलिखित विदेशी वृत्तिक लेखांकन निकायों के साथ किए गए एमआरए (परस्पर मान्यता करार)/एमओयू (समझौता ज्ञापनों) से उदभूत होने वाली विशेष परीक्षाओं का, जिनमें आईसीएआई की सदस्यता को प्राप्त करने के लिए इच्छुक उक्त निकायों के सदस्य बैठना चाहते थे, सफलतापूर्वक आयोजन 19 से 23 जून, 2017 के दौरान नई दिल्ली में किया गया था :

1. दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स (आईसीईडब्ल्यू)
2. दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ आस्ट्रेलिया (आईसीए आस्ट्रेलिया)
3. दि इन्स्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक एकाउंटेंट्स इन आस्ट्रेलिया (सीपीए आस्ट्रेलिया)
4. दि इन्स्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक एकाउंटेंट्स इन आयरलैंड (सीपीए आयरलैंड)
5. कैनेडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (सीआईसीए)

इसके अतिरिक्त, आईसीएआई ने न्यूजीलैंड इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (एनजेडआईसीए) के साथ हुए समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

उपरोक्त विशेष परीक्षाएं, ऊपर उल्लिखित अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन निकायों के सदस्यों के लिए खुली हैं।

#### **छात्र परीक्षा जीवन चक्र प्रबंध संबंधी वेब इंटरफेस :--**

आईसीएआई ने एक छात्र परीक्षा जीवन चक्र प्रबंध संबंधी वेब इंटरफेस नामक एकीकृत वेब इंटरफेस प्रारंभ किया था, जहां सीए के छात्र एकल उपयोक्ता पहचान और पासवर्ड का उपयोग करते हुए विभिन्न परीक्षा संबंधी सेवाओं तक पहुंच बना सकते हैं, जिसके अंतर्गत द्वितीय अंक सूचियां/ उत्तीर्ण प्रमाणपत्र/प्रतिलिपियों, केंद्र/ माध्यम/समूह में परिवर्तन के लिए आवेदन, परीक्षा से परीक्षा तक प्रवेश-पत्रों को डाउनलोड करना, परिणामों की जांच करना और परिणाम के पश्चात् उत्तर-पुस्तिकाओं के सत्यापन/उनकी प्रमाणित प्रतियों को प्राप्त करने के लिए आवेदन करना आदि भी हैं।

**नए परीक्षा केन्द्र :** छात्रों द्वारा उनके आवास/आर्टिकलड प्रशिक्षण के स्थान से निकटतम स्थानों पर परीक्षाएं देने को सुकर बनाने के विचार से हरिद्वार और निज़ामाबाद में, मई, 2017 की परीक्षाओं से सीए मध्यवर्ती और फाइनल परीक्षाओं के लिए नए परीक्षा केन्द्रों की स्थापना की गई थी।

जून, 2017 की परीक्षाओं से बदलापुर, बांसवाड़ा, भिबंडी, बुरहानपुर, चंद्रपुर, छिंदवाड़ा, गोंडिया, हलद्वानी, हरिद्वार, इछलकरंजी, जलाना, जूनागढ़, मंदसौर, मुजफ्फरपुर, निज़ामाबाद, पालघर, परभनी, रतनागिरि, रीवा और यवतमाल में सीए सीपीटी केंद्रों को खोला गया था।

#### 4.4 अनुशासन समिति

आईसीएआई, न केवल परिवर्तनशील आर्थिक परिदृश्य से कदम से कदम मिलाते हुए लेखांकन मानकों को तैयार करके भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की वृत्ति के विनियामक के रूप में अपने कानूनी कर्तव्यों का निष्पादन करता है अपितु साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 और तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन यथा उपबंधित उसके सुपरिभाषित अनुशासन तंत्र के माध्यम से उसके गलती करने वाले सदस्यों के विरुद्ध किसी वृत्तिक और/या अन्य कदाचार के लिए सक्रिय रूप से कार्रवाई करके नैतिक संहिता में यथा अनुबंधित नैतिक मूल्यों को भी परिवर्तित करता है।

अनुशासन तंत्र के अधीन, आईसीएआई के अनुशासन निदेशालय पर एक आज्ञापक कर्तव्य अधिरोपित किया गया है कि वह देश भर में उसके सदस्यों के एक छोटे वर्ग द्वारा की जाने वाली अभिकथित त्रुटियों/अनियमितताओं की जांच करे, जिससे कि वृत्ति में प्रवेश करने वाले भावी सदस्यों के लिए विश्वसनीयता की एक सुदृढ़ नींव रखी जा सके। यद्यपि, वृत्ति के अधिकांश सदस्य अपनी वृत्तिक विशेषज्ञता और अनुभव के माध्यम से समाज और पूरे विश्व को निस्वार्थ और समर्पित सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं, फिर भी संस्थान अपने मजबूत अनुशासन तंत्र के माध्यम से सावधानी की निरंतर आवश्यकता को पूरा करता है और साथ ही ऐसे नगण्य सदस्यों को सही दिशा भी प्रदान करता है, जो अनवधानीवश विधि के विरुद्ध कार्य करने लगते हैं।

पुनर्विलोकनाधीन वर्ष के दौरान, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने तारीख 10 अप्रैल, 2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/7/2017-पीआई के द्वारा, 3 वृत्तिक संस्थानों, अर्थात् भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान और भारतीय लागत लेखा संस्थान में कदाचार के मामलों के संबंध में कार्यवाही करने वाले अनुशासन तंत्र से संबंधित अधिनियम, नियमों और विनियमों में विद्यमान उपबंधों की परीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था, जो विद्यमान तंत्र को मजबूत करने और अनुशासन संबंधी मामलों के शीघ्र निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम, तत्संबंधी नियमों और विनियमों के उपबंधों में संशोधनों, यदि कोई हों, और उनमें सम्मिलित किए जाने के लिए अपेक्षित नए उपबंधों के संबंध में विनिर्दिष्ट रूप से सिफारिश करेगी।

एमसीए द्वारा गठित उक्त उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के निबंधनानुसार, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम और तदधीन विरचित नियमों में परिवर्तन करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण संशोधन विचाराधीन हैं, जिससे कि संपूर्ण अनुशासन प्रक्रिया को त्वरित बनाया जा सके और मामलों को निश्चायक समय-सीमा के भीतर निपटाया जा सके।

पुनर्विलोकनाधीन वर्ष के दौरान, आईसीएआई की परिषद् ने, ऐसे क्षेत्रों में, जिनमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 और तदधीन विरचित नियमों के अधीन यथा उपबंधित अनुशासन तंत्र में परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो गया है, अंतर्विलित जटिलताओं की परीक्षा करने और उसके पश्चात् चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 और तदधीन विरचित नियमों में आगे और संशोधनों का सुझाव देने के लिए एक समूह का गठन किया था। इस समूह की रिपोर्ट को 17 मई, 2017 को आयोजित परिषद् की 365वीं बैठक में उसके समक्ष रखा गया था।

आईसीएआई वृत्ति को अंतर्विलित करने वाले मामलों में शीघ्र और पारदर्शी कार्रवाई कर रहा है और उसने राष्ट्र निर्माण के भागीदार के रूप में उसकी छवि के अनुरूप इस दिशा में अनेक नई पहलें की हैं। आईसीएआई ने पंजाब नेशनल बैंक के मामले में एक उच्चाधिकार प्राप्त समूह का गठन किया था, जो पंजाब नेशनल बैंक के मामले में प्रणालीगत मुद्दों का अध्ययन करेगा और बैंकिंग प्रणाली और किसी अन्य विषय में उपचारात्मक उपायों और सुधारों के संबंध में सुझाव देगा। समूह द्वारा सुझाव दिए गए विभिन्न उपचारात्मक उपायों में बैंकिंग प्रणाली को विभिन्न स्तरों पर मजबूत करने के उपाय सम्मिलित हैं।

अनुशासन बोर्ड (धारा 21क के अधीन)/ अनुशासन समितियों (धारा 21ख के अधीन) और अनुशासन समिति (धारा 21घ के अधीन) के क्रियाकलापों के संबंध में एक संक्षिप्त लेखन नीचे प्रस्तुत किया गया है।

### **चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथा संशोधित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21क के अधीन अनुशासन बोर्ड**

अनुशासन बोर्ड का गठन आईसीएआई की परिषद द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथासंशोधित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21क के अधीन किया गया है ताकि वह सदस्यों द्वारा वृत्तिक और अन्य कदाचार के ऐसे मामलों पर विचार कर सके, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथासंशोधित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की पहली अनुसूची के अंतर्गत आते हैं और/या ऐसे मामलों पर विचार करने के लिए भी जहां सदस्यों को निदेशक (अनुशासन) द्वारा प्रथमदृष्टया रूप से किसी कदाचार का दोषी नहीं पाया जाता है।

चालू वर्ष में, फरवरी, 2018 में अनुशासन बोर्ड (धारा 21क के अधीन) की एक अतिरिक्त खंडपीठ का गठन किया गया है ताकि पीएफओ प्रक्रम और जांच के प्रक्रम, दोनों पर, मामले के शीघ्र निपटारे की प्रक्रिया को संवहनीय बनाया जा सके। इस संबंध में, अनुशासन बोर्ड की खंडपीठ 1, जिसकी अध्यक्षता उपाध्यक्ष, आईसीएआई द्वारा की जाती है, वर्तमान में दक्षिणी और मध्य भारत के क्षेत्रों से संबंधित मामलों पर विचार कर रही है और खंडपीठ 2, जिसकी अध्यक्षता सीए जी. शेखर, केंद्रीय परिषद् के सदस्य द्वारा की जा रही है, भारत के पश्चिमी/पूर्वी/उत्तरी क्षेत्रों से संबंधित मामलों पर विचार कर रही है।

पुनर्विलोकनाधीन वर्ष के दौरान, अनुशासन बोर्ड ने देश के विभिन्न स्थानों पर **19 बैठकें** की थी, इन बैठकों में, बोर्ड ने **58 मामलों**, जिनके अंतर्गत पूर्व वर्षों में उसे निर्दिष्ट किए गए मामले भी सम्मिलित थे, में अपनी जांच पूरी की थी। ऐसे मामलों के, जिनका अनुशासन बोर्ड द्वारा विनिश्चय किया गया था, सांख्यिकी संबंधी व्यौरे नीचे दिए गए हैं :

#### **अनुशासन बोर्ड (धारा 21क के अधीन) – 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 की अवधि के दौरान**

क्रम सं.	विशिष्टियां	मामलों की सं.
क)	पूर्वोक्त अवधि के दौरान अनुशासन बोर्ड द्वारा की गई बैठकों की संख्या	19
ख)	ऐसे शिकायत/सूचना संबंधी मामलों की संख्या, जिन पर अनुशासन बोर्ड (धारा 21क के अधीन) द्वारा विचार किया गया था और जिनमें निदेशक (अनुशासन) की प्रथमदृष्टया राय प्राप्त की गई थी।*	629
ग)	ऐसे मामलों (शिकायत/सूचना संबंधी मामलों) की संख्या, जिनमें अनुशासन बोर्ड द्वारा जांच पूरी कर ली गई थी (ऐसे मामलों सहित, जिन्हें पूर्व वर्षों के दौरान अनुशासन बोर्ड को निर्दिष्ट किया गया था)	58
घ)	ऐसे मामलों (शिकायत/सूचना संबंधी मामले) की संख्या, जिनमें अनुशासन बोर्ड द्वारा दंड दिया गया था (ऐसे मामलों सहित, जिन्हें पूर्व वर्षों के दौरान अनुशासन बोर्ड को निर्दिष्ट किया गया था)	08

\* इसके अंतर्गत ऐसे मामले भी हैं, जिनके संबंध में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के मामलों का अन्वेषण और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 6/12 के अधीन कार्यवाही की गई थी।

### **चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथा संशोधित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की अनुशासन समिति (धारा 21ख के अधीन)**

अनुशासन समिति का गठन आईसीएआई की परिषद द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 21ख के अधीन किया गया है ताकि वह सदस्यों द्वारा वृत्तिक कदाचार के ऐसे मामलों पर विचार कर सके, जो केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथासंशोधित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की दूसरी अनुसूची और पहली तथा दूसरी अनुसूची, दोनों के अंतर्गत आते हैं।

वर्ष 2017-2018 के दौरान, अनुशासन समिति (धारा 21ख के अधीन) की दो खंडपीठों, अर्थात् खंडपीठ 1 और खंडपीठ 2 का गठन किया गया था। तथापि, मामलों को शीघ्र निपटाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और सरकारी/ विनियामकों/लोक हित के मामलों को त्वरित पद्धति से निपटाने के विचार से, फरवरी, 2018 में, दो विद्यमान खंडपीठों के अतिरिक्त अनुशासन समिति की एक अन्य खंडपीठ, अर्थात् खंडपीठ 3 का गठन किया गया था, जो अनन्य रूप से सरकारी/विनियामकों/लोक हित आदि के मामलों पर विचार कर रही है।

पुनर्विलोकनाधीन वर्ष के दौरान, समिति ने देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में अवस्थित स्थानों पर 23 बैठकें (खंडपीठ-1 : 9 बैठकें, खंडपीठ- 2 : 13 बैठकें और खंडपीठ 3 (जिसका गठन फरवरी, 2018 में किया गया था) - 1 बैठक) की थी। पूर्वोक्त बैठकों के अनुक्रम के दौरान, समिति ने 35 मामलों में अपनी जांच पूरी की थी, जिसके अंतर्गत पूर्व वर्षों में उसे निर्दिष्ट किए गए मामले भी सम्मिलित थे।

ऐसे मामलों के, जिनका अनुशासन समिति द्वारा विनिश्चय किया गया था, सांख्यिकी संबंधी व्यौरे नीचे दिए गए हैं :

**अनुशासन समिति (धारा 21ख के अधीन) – 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 की अवधि के दौरान**

क्रम सं.	विशिष्टियां	मामलों की सं.
क)	पूर्वोक्त अवधि के दौरान अनुशासन समिति द्वारा की गई बैठकों की संख्या	23
ख)	ऐसे शिकायत/सूचना संबंधी मामलों की संख्या, जिन पर अनुशासन समिति (धारा 21ख के अधीन) द्वारा विचार किया गया था और जिनमें निदेशक (अनुशासन) की प्रथमदृष्टया राय प्राप्त की गई थी।	217
ग)	उपरोक्त में से ऐसे शिकायत/सूचना संबंधी मामलों की संख्या, जिन्हें आगे और जांच के लिए अनुशासन समिति द्वारा निर्दिष्ट किया गया था	210
घ)	ऐसे मामलों (शिकायत/सूचना संबंधी मामलों) की संख्या, जिनमें अनुशासन समिति द्वारा जांच पूरी कर ली गई थी (ऐसे मामलों सहित, जिन्हें पूर्व वर्षों के दौरान अनुशासन समिति को निर्दिष्ट किया गया था)	35
ङ)	ऐसे मामलों (शिकायत/सूचना संबंधी मामले) की संख्या, जिनमें अनुशासन समिति द्वारा दंड दिया गया था (ऐसे मामलों सहित, जिन्हें पूर्व वर्षों के दौरान अनुशासन समिति को निर्दिष्ट किया गया था)	30

**धारा (21घ) के अधीन अनुशासन समिति**

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथासंशोधित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21घ के उपबंधों के अधीन कार्यरत अनुशासन समिति, 2006 में पूर्वोक्त अधिनियम में किए गए संशोधनों से पूर्व लंबित शेष मामलों के संबंध में जांच करती है और परिषद् को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ऐसे सदस्यों के, जिनके मामले उसे परिषद् द्वारा प्रथमदृष्टया राय बनाए जाने पर पुनर्विलोकनाधीन वर्ष के दौरान निर्दिष्ट किए गए हैं, विरुद्ध अनुशासन संबंधी जांच करने के अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए इस समिति ने 08 (आठ) बैठकों का आयोजन किया था।

**ऐसे मामले, जिन पर पुराने अनुशासन तंत्र के अधीन कार्यवाही की गई थी [धारा 21(घ)]**

1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक की अवधि के दौरान परिषद् और अनुशासन समिति के समक्ष रखे गए मामलों से संबंधित आंकड़े :

क्रम सं.	विशिष्टियां	मामलों की सं.
1.	(i) पूर्वोक्त अवधि के दौरान अनुशासन समिति द्वारा निपटाए गए मामलों की	04

	संख्या (समिति के समक्ष जांच के लिए लंबित कुल 04 मामलों में से) (ii) पूर्वोक्त अवधि के दौरान अनुशासन समिति द्वारा धारा 21घ के अधीन की गई बैठकें	08
2.	अनुशासन समिति की ऐसी रिपोर्टों की संख्या, जिन पर परिषद् द्वारा विचार किया गया था (इनके अंतर्गत उन मामलों की रिपोर्टें भी हैं, जिन पर पूर्व वर्षों के दौरान सुनवाई की गई थी)	21
3.	उपरोक्त में से (क) ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें प्रत्यर्थियों को दोषी पाया गया था किंतु चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21(4) के अधीन कोई आदेश पारित करने से पूर्व परिषद् के समक्ष सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु उपयुक्त पाया गया था (ख) ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें प्रत्यर्थियों को दूसरी अनुसूची और/या अन्य कदाचार के लिए दोषी पाया गया है किंतु जिनके मामले को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21(5) के अधीन उच्च न्यायालयों को निर्दिष्ट किया जाना है। (ग) ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें प्रत्यर्थियों को पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची/ अन्य कदाचार के लिए दोषी पाया गया है (घ) ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें मामला आगे और जांच हेतु अनुशासन समिति को वापस निर्दिष्ट किया गया है (ङ) ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें प्रत्यर्थियों को किसी कदाचार के लिए दोषी नहीं पाया गया है	शून्य  20  01  शून्य  10
4.	ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें ऐसे प्रत्यर्थियों के संबंध में धारा 21(4) के अधीन आदेश पारित किया गया था, जिन्हें पहली अनुसूची के अधीन दोषी पाया गया था	02
5.	उच्च न्यायालय द्वारा धारा 21(6) के अधीन निपटाए गए मामलों की संख्या	08

## 5. तकनीकी और वृत्तिक विकास

### 5.1 लेखांकन मानक बोर्ड

#### वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों का उन्नयन :

एएस 16, संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, एएस 23, उधार लागतें और एएस 24 संबंधित पक्षकार प्रकटनों से संबंधित समुन्नत लेखांकन मानकों पर लेखांकन मानक संबंधी राष्ट्रीय सलाहकार समिति (एनएसीएएस) द्वारा विचार किया गया और उनका अनुमोदन किया गया था।

#### आईएफआरएस/आईएस के अनुरूप भारतीय लेखांकन मानकों का जारी किया जाना/ पुनरीक्षण

- एमसीए द्वारा अधिसूचित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2018, जिसके अंतर्गत आईएएसबी द्वारा जारी किए गए आईएफआरएस 15 के तत्समान इंड एएस 115, ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व।



- तारीख 17 मार्च, 2017 की अधिसूचना के द्वारा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2017 के रूप में यथा अधिसूचित इंड एस 7 नकद प्रवाह, जो आईएस 7 नकद प्रवाहों का कथन के संशोधनों के तत्समान है और इंड एस 102, शेयर आधारित संदाय में संशोधनों को सम्मिलित करता है।
- अवास्तविक हानियों के लिए आस्थगित कर आस्तियों को मान्यता – इंड एस 12, आय-कर में संशोधन।
- इंड एस में वार्षिक सुधार – इंड एस 112 और 28 में संशोधन (आईएसबी द्वारा जारी आईएफआरएस मानकों के 2014-2016 चक्र में किए गए वार्षिक सुधारों के तत्समान)।
- निवेश संपत्ति के अंतरण, इंड एस 40, निवेश संपत्ति के संशोधन।
- इंड एस 101, भारतीय लेखांकन मानकों को सर्वप्रथम अपनाए जाने से संबंधित संशोधन।

इंड एस में ऐसे संशोधन, जिन पर लेखांकन मानकों पर लेखांकन मानक संबंधी राष्ट्रीय सलाहकार समिति (एनएसीएस) द्वारा विचार किया गया और उनका अनुमोदन किया गया – परिशिष्ट ग, आय-कर संबंधी व्यवहार के संबंध में अनिश्चितता, इंड एस 12, आय-कर, इंड एस 20, शासकीय अनुदानों और शासकीय सहायता के प्रकटन के लिए लेखांकन तथा इंड एस 116, पट्टे में संशोधन।

वर्ष के दौरान, समुन्नत लेखांकन मानकों के जारी किए गए उदभासन प्रारूप/जारी किए गए भारतीय लेखांकन मानक – समुन्नत लेखांकन मानक (एस) 109, वित्तीय लिखते का उदभासन प्रारूप ; इंड एस 117, बीमा संविदाएं का उदभासन प्रारूप और इंड एस 21, विदेशी मुद्रा संव्यवहार और अग्रिम प्रतिफल के परिशिष्ट ख का उदभासन प्रारूप।

### प्रकाशन

बोर्ड ने वर्ष के दौरान अनेक प्रकाशन, मार्गदर्शक टिप्पण, बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों तथा उदघोषणाओं को जारी किया, जैसे कि लेखांकन मानकों का सार संग्रह – 1 जुलाई, 2017 को यथा विद्यमान, भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) : एक पर्यावलोकन (पुनरीक्षित) (इंड एस कार्यान्वयन समूह के साथ संयुक्त रूप से), एसबी की 40वीं वर्षगांठ संबंधी ब्रॉशर : लेखांकन सुधारों में पथ प्रदर्शन, संक्रमण की तारीख को इंड एस के अधीन प्रतिभूति प्रीमियम खाते के संबंध में व्यवहार संबंधी बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न। (इनको 2 जून, 2017 तक अद्यतन किया गया था) इंड एस का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन : प्रभाव का विश्लेषण और उद्योग का अनुभव तथा इंड एस प्रकटन जांच सूची।

### अंतर्राष्ट्रीय पहलें : दीर्घ अवधि भागीदारियां बनाना

**आईसीएआई के प्रतिनिधियों ने विभिन्न मंचों पर भागीदारी की थी, जैसे कि :**

- अध्यक्ष, लेखांकन मानक बोर्ड, सीए शिवाजी भीकाजी ज़वारे को दो वर्ष की अवधि के लिए एशियाई-प्रशांत मानक निर्धारक समूह (एओएसएसजी) का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। उन्होंने 29-30 नवंबर, 2017 के दौरान हांगकांग (चीन) में आयोजित एओएसएसजी की 9वीं वार्षिक बैठक में उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था। वर्तमान व्यवहार के अनुसार, उपाध्यक्ष, अपना सम्यक् कार्यकाल पूरा करने के पश्चात्, अध्यक्ष, एओएसएसजी का पदभार ग्रहण करता है।
- अध्यक्ष, लेखांकन मानक बोर्ड ने 31 जनवरी, 2018 को हांगकांग में आईएफआरएस संस्थापक न्यासियों के साथ एक चेयर सलाहकार समिति (सीएसी) में भाग लिया था। इसके अतिरिक्त, आईसीएआई ने टेलीकांफ्रेंसिंग के माध्यम से एओएसएसजी की विभिन्न चेयर और वाईस चेयर (सीवीसी) और सीएसी बैठकों में भी भाग लिया था।
- अध्यक्ष, आईसीएआई और अध्यक्ष, एसबी के सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक संस्थापन (आईएफआरएसएफ) न्यासियों, एमसीए के प्रतिनिधियों और आईसीएआई के प्रतिनिधियों के बीच 5 से 7 जून, 2018 के दौरान लंदन में एक त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत में उपयोग की जा रही/उपयोग की जाने वाली आईएफआरएस प्रतिलिप्याधिकार वाली सामग्रियों के प्रतिलिप्याधिकार और अनुज्ञापन संबंधी मुद्दों पर बातचीत की गई थी। इस बैठक के सकारात्मक परिणामस्वरूप यह प्रस्ताव किया गया है कि तीन मास के भीतर आईएफआरएसएफ और आईसीएआई के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएं।

- 4-6 दिसंबर, 2017 के दौरान साओ पाआलो (ब्राजील) में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह (ईईजी) की 14वीं बैठक का आयोजन किया गया था।
- आईसीएआई के प्रतिनिधियों ने एओएसएसजी, विश्व मानक निर्धारकों (डब्ल्यूएसएस) और अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक निर्धारकों की फेडरेशन (आईएफएसएस) की 24-27 सितंबर, 2017 के दौरान लंदन में आईएसबी के तत्वावधान में आयोजित बैठकों और सम्मेलनों में भी भाग लिया था।
- 14-16 मई, 2018 के दौरान क्वालालम्पुर (मलेशिया) में आयोजित 15वीं ईईजी बैठक में संस्थान के एसबी प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आईसीएआई के प्रतिनिधियों ने कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों के संबंध में प्रस्तुतिकरण किया था और पट्टा संबंधी मानक तथा अंकीय मुद्राओं के लेखांकन से संबंधित मुद्दों को प्रमुख रूप से उपदर्शित किया था। इसके पश्चात्, आईएफआरएस 17, बीमा संविदाओं से संबंधित आईएफआरएस संस्थापन प्रादेशिक कार्यशाला में भी 17 मई, 2018 को भाग लिया था।

**अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आईएसबी) द्वारा जारी निम्नलिखित उद्भासन प्रारूपों/परिचर्चा पत्रों के संबंध में टिप्पणियों को आईएसबी को प्रस्तुत किया गया था।**

- 'सामग्री' की परिभाषा – आईएस 1 और आईएस 8 के प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में टिप्पणियां
- 'लेखांकन नीतियों और लेखांकन प्राक्कलनों – आईएस 8 में प्रस्तावित संशोधनों' के संबंध में टिप्पणियां
- आईएसबी के परिचर्चा पत्र 'प्रकटन संबंधी पहल – प्रकटन के सिद्धांत' के संबंध में टिप्पणियां
- आईएसबी के संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर – आशयित उपयोग से पूर्व आगमों (आईएस 16 में प्रस्तावित संशोधन) संबंधी उद्भासन प्रारूप के संबंध में टिप्पणियां
- आईएसबी के आईएफआरएस 8, प्रचालन खंडों में सुधारों (आईएफआरएस 8 और आईएस 34 में प्रस्तावित संशोधन) संबंधी उद्भासन प्रारूप के संबंध में टिप्पणियां
- आईएसबी द्वारा आईएफआरएस 13 उचित मूल्य मापमान के कार्यान्वयन पश्च पुनर्विलोकन के संबंध में जारी आरएफआई पर टिप्पणियां
- नकारात्मक प्रतिकर के साथ पूर्व संदाय विशिष्टियों (आईएफआरएस 9) में प्रस्तावित संशोधनों संबंधी उद्भासन प्रारूप के संबंध में टिप्पणियां
- आईएफआरएस मानकों में वार्षिक सुधारों – 2015-2017 चक्र संबंधी उद्भासन प्रारूप के संबंध में टिप्पणियां

**अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ परस्पर क्रिया**

- आईसीएआई ने 8-9 मई, 2017 के दौरान दूसरी बार उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह (ईईजी) की तेरहवीं बैठक की मेजबानी की थी, जिसमें आईएसबी और उभरती अर्थव्यवस्थाओं, अर्थात् ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की और भारत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। एसबी द्वारा सुक्ष्म अस्तित्वों संबंधी मुद्दे – वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी चुनौतियों विषय पर एक पत्र प्रस्तुत किया गया था।
- इंड एस 109 के अधीन सेवा रियायत ठहराव और आशयित प्रत्यय हानि मॉडल से संबंधित उभरती आईएफआरएस (इंड एस) चुनौतियों के विषय पर एक अर्धदिवसीय आईसीएआई-ईईजी संयुक्त पणधारी संगोष्ठी का आयोजन 9 मई, 2017 को किया गया था। इस संगोष्ठी में लगभग 80 सदस्यों, ईईजी के प्रतिनिधियों और अन्य पणधारियों ने भाग लिया था।
- आईसीएआई ने दूसरी बार 12-13 अप्रैल, 2018 के दौरान मुंबई में, भारत में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक निर्धारक मंच (आईएफएसएस) की बैठक की मेजबानी की थी। 25 से अधिक अधिकारिताओं से 60 से अधिक प्रतिनिधियों ने इस आयोजन में भाग लिया था, इन अधिकारिताओं में प्रमुख अधिकारिताएं सम्मिलित थीं। आईएफएसएस सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य अतिथि, न्यासी, आईएफआरएस संस्थापन और भारत के पूर्व नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, आईसीएआई, अध्यक्ष, एसबी, आईसीएआई, उपाध्यक्ष, आईएसबी और अध्यक्ष, आईएफएसएस द्वारा किया गया था।

- आईसीएआई ने 11 अप्रैल, 2018 को “आईएफआरएस 9 (इंड एस 109) ईसीएल मॉडल, बैंकिंग उद्योग में चुनौतियाँ” विषय पर एक आईसीएआई – आईएसबी संयुक्त पणधारी संगोष्ठी का आयोजन किया था।

विनियामक निकायों के साथ सुदृढ़ संबंध बनाना :

- एनएससीएस द्वारा अनुमोदित “कंपनी अधिनियम, 2013 की एनवीएफसी के लिए इंड एस अनुरूप अनुसूची 3” को अधिसूचना हेतु एमसीए को प्रस्तुत किया गया था।
- एसबी ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) की 1 अप्रैल, 2016 और 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होने वाले इंड एस के व्यापक समुन्नत पाठ को तैयार करने में इंड एस के ई पाठ को जारी करने में सहायता की है।
- आईसीएआई बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों को इंड एस अनुरूप प्रारूप में तैयार करने संबंधी प्रारूपण समूह की अध्यक्षता कर रहा है।
- आईसीएआई ने एक अध्ययन समूह की विरचना की है, जो बैंकों द्वारा इंड एस के कार्यान्वयन और बैंकों के वित्तीय विवरणों को इंड एस अनुरूप प्रारूप में तैयार करने वाले इंड एस के कार्यान्वयन में अंतर्वलित मुद्दों पर विचार करेगा।
- एसबी ने भारतीय पणधारियों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों को एक साथ लाने के लिए परस्पर क्रियाशील बैठकों और सम्मेलनों का आयोजन किया था, जैसे कि आईएसबी पदधारियों का राष्ट्रीय विनियामकों के साथ परस्पर क्रियाशील बैठक का आयोजन 10 अप्रैल, 2018 को और बीमा क्षेत्र के लिए आईएफआरएस – 17 (इंड एस 117, बीमा संविदाएं) बीमा उद्योग आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन 11 अप्रैल, 2018 को किया गया था।
- प्रारूप इंड एस 16, पट्टों के संबंध में एसबी ने दो आउटरीच बैठकों का आयोजन विभिन्न पणधारियों और क्षेत्र संबंधी विनियामकों के साथ किया था।
- विभिन्न विनियामकों जैसे कि एमसीए, आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई आदि, उद्योग संगमों और अन्य पणधारियों से प्राप्त हुए भिन्न-भिन्न मुद्दों और प्रतिवेदनों के संबंध में एसबी द्वारा समय-समय पर विचार किया जाता है।

## 5.2 स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक संबंधी समिति (सीएसएलबी)

हमारे लोकतांत्रिक समाज में, स्थानीय निकायों से यह आशा की जाती है कि वे उस प्रकार सार्वजनिक रूप से जवाबदेह होंगे जैसा कि देश के नागरिक इस संबंध में जानकारी चाहते हैं कि लोक निधियों का उपयोग इस प्रकार किया जा रहा है और अर्थव्यवस्था के वित्तीय कार्यों का प्रबंध किस प्रकार किया जा रहा है। अतः, भारत में स्थानीय निकायों के प्रचालनों में पारदर्शिता लाया जाना आवश्यक है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि स्थानीय निकाय आत्मनिर्भर हों और पूंजी बाजार के माध्यम से अपने लिए निधियां जुटाने में सक्षम हों क्योंकि शहरी विकास/अवसंरचना आदि की संवृद्धि के उद्देश्य को केवल अनुदानों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस दिशा में यह भी आवश्यक है कि प्रोदभवन आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों का उपयोग करते हुए वित्तीय विवरण तैयार किए जाएं क्योंकि ये विवरण निवेशकों और अन्य पणधारियों की सूचना संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने में समर्थ होंगे और वे उन्हें प्रबुद्ध निर्णय लेने में समर्थ बनाएंगे।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्र निर्माण के भागीदार के रूप में, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) ने सरकार के तीसरे टियर, अर्थात् स्थानीय स्वशासन आदि के लिए उच्च गुणवत्ता वाले प्रोदभवन लेखांकन ढांचे को विहित करने का उत्तरदायित्व हाथ में लिया था। तदनुसार, अपनी अस्थायी समितियों में से एक समिति, अर्थात् स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक संबंधी समिति (सीएसएलबी) के माध्यम से वर्ष 2005 से स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक (एसएलबी) तैयार किए जा रहे हैं। सीएसएलबी, स्थानीय निकायों और विभिन्न पणधारियों जैसे कि अंत उपयोगकर्ताओं और नागरिकों के बीच सरकार और स्थानीय निकायों में लेखांकन संबंधी सुधार प्रक्रिया के फायदों के संबंध में जागरूकता का सृजन करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन करता है। यह संस्थान के तकनीकी निदेशालय की तकनीकी समितियों में से एक है।

1 अप्रैल, 2017 से 30 जून, 2018 के दौरान किए गए महत्वपूर्ण क्रियाकलाप :

- “भारत में शहरी अवसंरचना का वित्तपोषण करने के लिए नगरपालिक बंधपत्र : एक पर्यावलोकन” संबंधी पुस्तिका
- समिति ने स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक (एसएलबी) एसएलबी 18, ‘खंड रिपोर्टिंग’, एसएलबी 2 ‘नकद प्रवाह विवरण’, एसएलबी 20 ‘संबंधित पक्षकार प्रकटन’ को जारी किया और विभिन्न अन्य एसएलबी के संबंध में विभिन्न प्रक्रमों पर कार्य किया जा रहा है।
- समिति ने इस वर्ष राज्यों के साथ, दिल्ली, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल जैसे राज्यों के शहरी स्थानीय निकायों के पदधारियों के लिए लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रोदभवन प्रणाली और वित्तीय प्रबंध सुधारों के कार्यान्वयन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया था। समिति ने आईसीएआई की जोधपुर शाखा के समर्थन से जोधपुर (राजस्थान) में प्रत्यक्ष कर समिति (डीटीसी) के साथ संयुक्त रूप से ‘प्रत्यक्ष करों के अधीन मुद्दे (न्यास और स्थानीय निकाय)’ विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया था।
- समिति ने अंतर्राष्ट्रीय पब्लिक सेक्टर लेखांकन मानक बोर्ड (आईपीएसएसबी) के दस्तावेजों/परामर्श पत्रों/उद्भासन प्रारूपों को प्रस्तुत किया था – ‘पब्लिक सेक्टर में विरासत के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग’ संबंधी परामर्श पत्र, ‘राजस्व और गैर-विनिमय व्ययों के लिए लेखांकन’ संबंधी परामर्श पत्र, ‘रणनीति और कार्ययोजना 2019-2023’ संबंधी दस्तावेज और ‘पट्टे’ संबंधी आईपीएसएसबी के 64वें उद्भासन प्रारूप को जारी किया गया था।
- समिति ने शासकीय लेखांकन मानक सलाहकार बोर्ड (जीएसएबी) के दस्तावेजों को जीएसएबी की 31वीं बोर्ड बैठक की कार्यसूची के संबंध में टिप्पणियों, प्रारूप रणनीतिगत विकास योजना, 2017 जीएसएबी की 32वीं बोर्ड बैठक की कार्यसूची, “नियत आस्तियां लेखांकन और अभिलेखन”, उपांतरित भारतीय शासकीय लेखांकन मानक (आईजीएस) 2, “लेखा अनुदानों का लेखांकन, आईजीएस 3 (उपांतरित)”, “ऋणों और अग्रिमों का लेखांकन” संबंधी मार्गदर्शक टिप्पणों और “सम्यक् प्रक्रिया” तथा “भारतीय शासकीय लेखांकन मानक और भारतीय शासकीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के प्राक्कथन” संबंधी प्रारूप को भी जारी किया था।

### 5.3 संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड

1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 की अवधि के दौरान, बोर्ड की सात बैठकों का आयोजन किया गया था।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, बोर्ड ने विभिन्न मंत्रालयों और विनियामकों को निम्नलिखित

अंतःनिवेश/प्रतिवेदन/सुझाव प्रस्तुत किए थे :

- बोर्ड ने सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को कंपनी अधिनियम, 2013 की इस अपेक्षा का अनुपालन करने में कंपनियों के लेखापरीक्षकों के समक्ष आने वाली कठिनाईयों के संबंध में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था कि वे वित्तीय विवरणों में सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के बकाया शोध्यों का प्रकटन करें।
- बोर्ड ने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) को सेबी (पूँजी और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2009 के पुनर्विलोकन के संबंध में सेबी द्वारा जारी परामर्श पत्र के संबंध में आईसीएआई के सुझाव प्रस्तुत किए थे।

**जारी किए गए संपरीक्षा मानक: बोर्ड ने निम्नलिखित संपरीक्षा मानक (एसए) जारी किए थे :**

- एसए 299 (पुनरीक्षित), वित्तीय विवरणों की संयुक्त लेखापरीक्षा। यह वित्तीय वर्ष 2018-19 और पश्चातवर्ती वर्षों की संपरीक्षाओं के लिए लागू होगा और यह आईसीएआई द्वारा वर्ष 1996 में जारी विद्यमान एसए 299 को प्रतिस्थापित करेगा।
- एसए 720 (पुनरीक्षित), संपरीक्षक के अन्य सूचना से संबंधित उत्तरदायित्व। यह वित्तीय वर्ष 2018-19 और पश्चातवर्ती वर्षों की संपरीक्षाओं के लिए लागू होगा और यह आईसीएआई द्वारा वर्ष 2009 में जारी विद्यमान एसए 720 को प्रतिस्थापित करेगा। इस मानक में विद्यमान एसए 720 की तुलना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं, विशेषकर संपरीक्षकों की

**रिपोर्ट में अन्य सूचना के संबंध में संपरीक्षा रिपोर्ट के लिए विनिर्दिष्ट अपेक्षाएं।**

**जारी किए गए प्रकाशन**

**बोर्ड ने संस्थान के सदस्यों के सर्वांग फायदे के लिए निम्नलिखित प्रकाशन जारी किए थे :**

- बैंकों की संपरीक्षा संबंधी मार्गदर्शक टिप्पण, 2018 संस्करण । यह टिप्पण बैंक शाखाओं की संपरीक्षाओं के विभिन्न पहलुओं के संबंध में ब्यौरेवार मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है । यह संस्थान का ऐसा उत्कृष्ट प्रकाशन है जिसे प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षित और जारी किया जाता है ।
- रिपोर्टिंग मानकों संबंधी कार्यान्वयन गाइड (पुनरीक्षित एसए 700, पुनरीक्षित एसए 705 और पुनरीक्षित एसए 706) । यह गाइड पुनरीक्षित रिपोर्टिंग मानकों, अर्थात् पुनरीक्षित एसए 700 – वित्तीय विवरणों पर राय बनाना और रिपोर्ट करना, पुनरीक्षित एसए 705 – स्वतंत्र संपरीक्षक की रिपोर्ट में दी गई राय को उपांतरित करना और पुनरीक्षित एसए 706 – स्वतंत्र संपरीक्षक की रिपोर्ट में विषय पैराओं और अन्य विषय पैराओं पर जोर देना, जो वित्तीय वर्ष 2018-19 और पश्चातवर्ती वर्षों की संपरीक्षाओं के लिए लागू होंगे, के संबंध में व्यावहारिक कार्यान्वयन मार्गदर्शन उपलब्ध कराती है ।
- एसए 701, स्वतंत्र संपरीक्षक की रिपोर्ट में प्रमुख संपरीक्षा संबंधी विषयों को संसूचित करना, संबंधी कार्यान्वयन गाइड । यह गाइड नए रिपोर्टिंग मानक अर्थात् एसए 701 जो वित्तीय वर्ष 2018-19 और पश्चातवर्ती वर्षों की संपरीक्षाओं के लिए लागू होगा, के संबंध में व्यावहारिक कार्यान्वयन मार्गदर्शन उपलब्ध कराती है । इस कार्यान्वयन गाइड को इस मानक से संबंधित बहुधा पुछे जाने वाले प्रश्नों और उनके प्रत्युत्तरों के रूप में साधारण भाषा में लिखा गया है ।

### अन्य तकनीकी उपलब्धियां

- आईएफएसी मानीटरी समूह ने लोक टिप्पणियों के लिए “शासन को सुदृढ़ बनाने और लोक हित में अंतर्राष्ट्रीय संपरीक्षा – संबंधी मानक – निर्धारक बोर्डों के निरीक्षण संबंधी एक परामर्श पत्र” जारी किया था, जिसमें आईएफएसी के मानक निर्धारक बोर्डों के कार्यकरण को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न प्रस्ताव अंतर्विष्ट थे । एएएसबी ने अपनी बैठकों में इस परामर्श पत्र पर विचार-विमर्श किया था और संस्थान की परिषद् को उसके संबंध में एक प्रारूप प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया था । परिषद् से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के पश्चात्, एएएसबी ने परामर्श पत्र के संबंध में प्रारूप प्रत्युत्तर को अंतिम रूप प्रदान किया था और उसे फरवरी, 2018 में आईएफएसी मानीटरी समूह को प्रस्तुत किया गया था ।
- क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड (क्यूआरबी) के अनुरोध पर एएएसबी ने क्वालिटी पुनर्विलोकनों के संचालन संबंधी एक तकनीकी गाइड को तैयार किया था और उसे क्यूआरबी को प्रस्तुत किया था । यह गाइड, क्यूआरबी द्वारा नियुक्त किए गए तकनीकी पुनर्विलोककों द्वारा किए जाने वाले क्वालिटी पुनर्विलोकनों की गुणवत्ता में अभिवृद्धि करेगी क्योंकि इसमें बेहतर अनुपालन और रिपोर्टिंग के लिए क्वालिटी पुनर्विलोकनों के लिए अनुसरित की जाने वाली मानक प्रक्रियाओं को अभिकथित किया गया है ।
- एएएसबी ने आरबीआई के परामर्श से शहरी सहकारी बैंकों के लिए कानूनी संपरीक्षकों की रिपोर्ट के पुनरीक्षित प्रारूप को भी विकसित किया था । आरबीआई से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् एएएसबी ने इन प्रारूपों को वर्ष 2017-18 में जारी किया था ।

### सदस्यों के लिए पहले

- एएएसबी ने संस्थान के सदस्यों की जागरूकता और वृत्तिक ज्ञान में अभिवृद्धि करने के लिए देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया था, जिनमें विभिन्न विषयों जैसे कि विभिन्न संपरीक्षा मानकों, बैंक संपरीक्षाओं, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन रिपोर्टिंग (उदाहरणार्थ, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों संबंधी रिपोर्टिंग, कपटों संबंधी रिपोर्टिंग, सीएआरओ 2016) और अन्य संपरीक्षा संबंधी पहलू, को सम्मिलित किया गया था । इन कार्यक्रमों का आयोजन मेरठ, ग्वालियर, सूरत, जयपुर, रायपुर, कोलकाता, एर्नाकुलम, बिलासपुर, आगरा, **वाराणसी**, नोएडा, तिनसुकिया, डिब्रुगढ़ और सिलिगुड़ी में किया गया था ।
- एएएसबी ने क्रमशः अगस्त, 2017 और अप्रैल, 2018 में जयपुर और इंदौर में “संपरीक्षा और उससे परे” और “बैंक संपरीक्षा और निगम विधियां” विषयों पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था । इन सम्मेलनों में 2800 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया था ।

- एएएसबी ने संस्थान की वृत्तिक विकास समिति के सहयोग से मार्च-अप्रैल, 2018 में दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में बैंकों के केंद्रीय कानूनी संपरीक्षकों के लिए परस्पर क्रियाशील संगोष्ठियों की एक श्रृंखला का आयोजन किया था।
- एएएसबी ने 26 जुलाई, 2017 को मुंबई में एसए 701 के नए रिपोर्टिंग मानक के संबंध में निगमों के साथ एक परस्पर क्रियाशील बैठक का आयोजन किया था। उसने 27 नवंबर, 2017 को “संपरीक्षा में एसएमपी के सामने आने वाली चुनौतियां” संबंधी विषय पर एक लाइव वेबकास्ट का भी आयोजन किया था।
- जैसा कि पूर्व में किया जाता रहा है, एएएसबी ने इस वर्ष भी वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बैंक शाखा संपरीक्षा के संबंध में सदस्यों की शंकाओं का समाधान करने के लिए विशेषज्ञों के एक आनलाइन पैनल का गठन किया था। इस पैनल ने 1 से 15 अप्रैल, 2018 के दौरान सदस्यों की शंकाओं का समाधान किया था।
- एएएसबी ने सदस्यों का मार्गदर्शन करने के लिए निम्नलिखित उद्घोषणाओं/स्पष्टीकरणों को भी जारी किया था।
  - एसए 570 (पुनरीक्षित), गोइंग कसर्न (वित्तीय वर्ष 2017-18 की संपरीक्षाओं के लिए लागू) के संबंध में बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न।
  - आरबीआई द्वारा जारी माल और सेवा कर (जीएसटी) के अधीन रजिस्ट्रीकृत एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए अनुतोष के संबंध में 7 फरवरी, 2018 के परिपत्र के संबंध में स्पष्टीकरण।
  - बैंक संपरीक्षा की दशा में संयुक्त संपरीक्षकों के बीच कार्य आबंटन के संबंध में सदस्यों के लिए सलाह। आरबीआई द्वारा आईसीएआई को दिए गए सुझावों के आधार पर एक सलाह जारी की गई थी कि बैंक संपरीक्षाओं में संयुक्त संपरीक्षकों के बीच कार्य का आबंटन ऐसे व्यक्तियों के साथ विचार-विमर्श करके किया जाना चाहिए, जो बैंकों के शासन के लिए प्रभारी हैं।
- एएएसबी ने समय-समय पर सदस्यों से प्राप्त होने वाली संपरीक्षा संबंधी विभिन्न शंकाओं के उत्तर/स्पष्टीकरण उपलब्ध कराए थे।

#### अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग

- एएएसबी ने, जून 2018 में न्यूयार्क में हुई अंतर्राष्ट्रीय संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड (आईएएसबी) की बैठक में आईसीएआई का प्रतिनिधित्व किया था।
- एएएसबी ने मई, 2018 में वियना में हुई अंतर्राष्ट्रीय संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड (आईएएसबी) की राष्ट्रीय मानक निर्धारकों (आईएएसबी-एनएसएस बैठक) की वार्षिक बैठक में आईसीएआई का प्रतिनिधित्व किया था। इस बैठक में, एएएसबी ने “एक्सपेक्टेड गैप/प्रसेप्शन गैप – इन करंट सिनेरियो एंड चैलेंजिज फार आडिटर्स” विषय के संबंध में प्रस्तुतिकरण किया था, जिसकी आईएएसबी के अध्यक्ष और बैठक में भाग लेने वाले अन्य व्यक्तियों द्वारा काफी सराहना की गई थी। इसके अतिरिक्त, आईसीएआई द्वारा दिए गए सभी सुझावों पर आईएएसबी द्वारा विचार किया गया था और आगे और कार्रवाई के लिए उन्हें नोट किया गया था।
- एएएसबी ने, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, 2017 में न्यूयार्क में और मार्च, 2018 में एमस्टरडेम में हुई अंतर्राष्ट्रीय संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड (आईएएसबी) की बैठकों में आईसीएआई का प्रतिनिधित्व किया था।

**अन्य वैश्विक पहलें:** आईएएसबी के अध्यक्ष प्रोफेसर आर्नोल्ड शिल्डर के साथ परस्पर क्रिया करने के लिए 7 दिसंबर, 2017 को मुंबई में एएएसबी की एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में आईएएसबी की अध्यक्ष सुश्री रेचल ग्रीम्स, तत्कालीन अध्यक्ष सीए नीलेश एस. विक्रमसे और आईसीएआई के अध्यक्ष (तत्कालीन उपाध्यक्ष सीए नवीन एन.डी. गुप्ता) ने भी भाग लिया था।

#### 5.4 बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा समिति (बीएफएस एंड आईसी)

##### मंत्रालयों और विनियामकों को प्रस्तुत प्रतिवेदन/सुझाव/टिप्पणियां

- लोक सभा सचिवालय ने अपने तारीख 20 अप्रैल, 2018 के पत्र द्वारा आईसीएआई से यह अनुरोध किया था कि वह वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017 के संबंध में अपने सुझाव/टिप्पणियां प्रस्तुत करे। समिति ने विधेयक के विभिन्न उपबंधों के गहन विश्लेषण के लिए एक अध्ययन समूह का गठन किया था और उनके संबंध

में अपनी टिप्पणियां उपलब्ध कराई थी। आईसीएआई के विचारों को 14 मई, 2018 को हुई संसद की संयुक्त समिति की बैठक में प्रस्तुत किया गया था, जिसकी संयुक्त समिति ने काफी सराहना की थी।

- आईसीएआई के अध्यक्ष ने 17 फरवरी, 2018 को हुई आईपीएफ प्राधिकरण की एक बैठक में भाग लिया था, जिसमें निवेशकों की जागरूकता और उसके संबंध में एक राष्ट्रीय कार्यसूची तैयार करने के लिए कार्ययोजना के संबंध में विचार-विमर्श किया गया था। इस बैठक की अध्यक्षता सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा की गई थी।
- भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के परामर्श से, बीमा कंपनियों के निवेश कृत्यों की आंतरिक/समवर्ती संपरीक्षा संबंधी मार्गदर्शक टिप्पण और आईआरडीएआई (निवेश) विनियम, 2016 में यथा अनुबंधित बीमा कंपनियों की निवेश जोखिम प्रबंध प्रणालियों के पुनर्विलोकन और प्रमाणन संबंधी मार्गदर्शक टिप्पण के आधारिक प्रारूप को तैयार करने के लिए एक अध्ययन समूह का गठन किया गया था।
- समिति ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को एक प्रतिवेदन भेजा था ताकि सरकार द्वारा अंकीय वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम (डीएफएलएपी) द्वारा की गई पहलों में उनकी सहायता की जा सके।
- समिति ने, मुंबई में 25 अक्टूबर, 2017 को आयोजित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) कार्यान्वयन संबंधी कार्यशाला के लिए अग्रिम वित्तीय अनुसंधान और पठन केंद्र को तकनीकी समर्थन उपलब्ध कराया था।

### संगोष्ठियां, कार्यशालाएं, प्रदर्शनियां, सम्मेलन आदि

- आईसीएआई निगम प्रदर्शनी, 2018 का आयोजन 19-20 जनवरी, 2018 के दौरान मुंबई में 11वें आईसीएआई पुरस्कार समारोह, 2017 के साथ-साथ किया गया था। यह आयोजन संस्थान की कारबार और उद्योग में लगे वृत्तिक अकाउंटेंटों संबंधी समिति द्वारा किया गया था।
- चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (एनपीएस) संबंधी एक संगोष्ठी का आयोजन 28 नवंबर, 2017 को नई दिल्ली में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के साथ संयुक्त रूप से किया गया था।
- 19 अगस्त, 2017 को मुंबई में विकासशील निवेश रणनीतियां और अवसरों के संबंध में सीए के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था।
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय के निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि अधिकरण के तत्वावधान में वर्ष 2017-18 के दौरान देश भर में 120 से अधिक निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।
- वर्ष 2017-18 के दौरान विदेशी मुद्रा और खजाना प्रबंध संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के चार बैचों का आयोजन किया गया था।
- मई, 2017 के मास में नई दिल्ली और मुंबई में आईसीएआई के डीआईआरएम तकनीकी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सदस्यों के लिए दो अनुकूलन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।
- 30 जून, 2018 तक डीआईआरएम पाठ्यक्रम के लिए 5074 रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुए थे।

### 5.5 व्यवसाय में लगे सदस्यों के लिए सक्षमता निर्माण संबंधी समिति (सीसीबीएमपी)

व्यवसाय में लगे सदस्यों के लिए सक्षमता निर्माण संबंधी समिति (सीसीबीएमपी) का सृजन फरवरी, 2010 में किया गया था। समिति के प्रमुख उद्देश्य सीए फर्मों और साथ ही लघु तथा मध्यम व्यवसायियों के व्यवसाय पोर्टफोलियों को सुदृढ़ बनाना है। समिति का प्रमुख कृत्य, प्रबंध परामर्शी सेवा फर्मों की नेटवर्किंग, विलयन और स्थापना के माध्यम से समेकन करके सीए फर्मों के बीच सक्षमता निर्माण के संबंध में जागरूकता का सृजन करना और बेहतर लेखांकन, संपरीक्षा और नैतिक मानकों के समेकन और स्थायित्व के फायदों के संबंध में कार्यशालाओं, सभाओं और शिखर सम्मेलनों का आयोजन करके यूनियन की अवधारणा को लोकप्रिय बनाना है। समिति लघु और मध्यम व्यवसायियों को, कारबार समुदाय के बीच उनकी दृश्यता में सुधार लाने में सहायता करती है और साथ ही उनके लिए अतिरिक्त वृत्तिक अवसरों का सृजन भी करती है।

आईसीएआई के विजन के अनुरूप, जो 'भारतीय चार्टर्ड लेखांकन वृत्ति' को विश्व स्तरीय वित्तीय सक्षमताओं, बेहतर

शासन और प्रतिस्पर्धियों के बीच मूल्यवान न्यासी के रूप में स्थापित करना है, समिति का मोटो भारतीय सीए फर्मों की सुदृढीकरण और लघु तथा मध्यम व्यवसायियों के सशक्तिकरण के माध्यम से उनकी सक्षमता निर्माण करना है, जो उनकी वृत्तिक सक्षमता को विकसित तथा उसका उन्नयन करके प्राप्त किया जा सकता है। तदनुसार, समिति निम्नलिखित मुद्दों के संबंध में कार्यवाही करती है :

- सीए फर्मों के सुदृढीकरण के लिए संहिता तैयार करना।
- एसएमपी के सशक्तिकरण के लिए उपायों और मार्गों की पहचान करना।
- मानक व्यवसाय से संबंधित ज्ञान और कौशल सेट को समुन्नत तथा अद्यतन करना।
- एसएमपी के लिए व्यवसाय संबंधी क्षेत्रों का विकास करना।
- उभरते क्षेत्रों में एसएमपी की भूमिका की पहचान करना।
- वृत्ति के नए क्षेत्रों में व्यवसाय को सुकर बनाने के लिए तकनीकी सामग्री को विकसित करना।
- सीए फर्मों और एसएमपी के लिए आईटी उन्नत कार्यालय प्रबंध और संपरीक्षा उपकरणों को उपलब्ध कराना।
- वृत्ति का पुनर्निर्माण करना और उत्तम अवसंरचना तथा वित्त के साथ सीए फर्मों की स्थापना करना।
- व्यवसायियों और सीए फर्मों के लिए सामाजिक सुरक्षा और बीमा संरक्षण के लिए व्यवस्था।

#### किए गए क्रियाकलाप:

- **सदस्यों के लिए जेट एयरवेज से वायुयान की टिकटों को बुक करने में रियायती किराए का प्रस्ताव**

समिति ने जेट एयरवेज द्वारा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए वायुयान की टिकटों को बुक करते समय रियायती किराए की व्यवस्था की थी। यह रियायती किराए की व्यवस्था आईसीएआई के सदस्यों के लिए परिकल्पित की गई थी और उनकी पहचान को उनके सदस्यता संख्याक के आधार पर स्थापित किया जाएगा। रियायती वायुयान किराए की दरें, किसी भी सदस्य के संबंध में उस समय तक बनी रहेंगी जब तक संस्थान के साथ उसकी सदस्यता/रजिस्ट्रीकरण जारी रहता है। उपरोक्त व्यवस्था के ब्यौरे [www.icaai.org](http://www.icaai.org) या [https://icaai.org/post.html?post\\_id=14203](https://icaai.org/post.html?post_id=14203) पर उपलब्ध हैं।

- **सदस्यों और छात्रों के लिए विशेष कीमत पर एंटी वायरस साफ्टवेयर**

समिति द्वारा सदस्यों की एंटी वायरस साफ्टवेयर तक पहुंच को समर्थ बनाने के लिए क्विक हील टेक्नोलॉजिस प्रा.लि., पुणे के साथ एक व्यवस्था की है, जिसके अंतर्गत वह मार्च, 2018 से मार्च, 2020 तक आईसीएआई के सदस्यों और छात्रों हेतु तीन वर्ष की अवधि के लिए एकल उपयोक्ता के लिए 1200/- रुपए धन लागू करें के विशेष रियायती मूल्य पर क्विक हील टोटल सिक्योरिटी उपलब्ध कराएगा, उपरोक्त व्यवस्था के ब्यौरे [www.icaai.org](http://www.icaai.org) या [https://icaai.org/post.html?post\\_id=11505](https://icaai.org/post.html?post_id=11505) पर उपलब्ध हैं।

- **टैक्स क्लाउड : सदस्यों के लिए क्लाउड आधारित और टीडीएस विवरणी तैयार करना**

“टैक्स क्लाउड : सदस्यों के लिए क्लाउड आधारित और टीडीएस विवरणी तैयार करना” आय-कर विवरणी और टीडीएस विवरणी को तैयार करने में समर्थ बनाता है, निर्धारितियों, जिनके अंतर्गत व्यष्टि, हिन्दु अविभक्त कुटुंब, फर्म और कंपनियां भी हैं, को सभी किस्म का समर्थन उपलब्ध कराता है, सभी शीर्षों, जैसे कि वेतन गृह संपत्ति, पूंजी अभिलाभ, कारबार और वृत्ति, अन्य तथा छूट प्राप्त आय शीर्षों के अधीन आय-कर की संगणना करता है, आय-कर विवरणियों की ब्यौरेवार संगणना का प्ररूप तैयार करता है, प्रपत्र रूप से फाइल किए जाने के लिए पीडीएफ और ई-फाइलिंग एक्सएमएल तैयार करता है तथा सीए के लिए क्लाउड सर्वर पर स्वतः ही डाटा का बैकअप लेता है।

- **बीमा स्कीमें**

**सदस्यों और छात्रों के लिए मोटर यान बीमा:** न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ मोटर यान बीमा की व्यवस्था करने के लिए समिति द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह मोटर यान बीमा आधिकारिक रूप से सदस्यों के लिए तैयार किया गया है किंतु इसे आईसीएआई के छात्रों और कर्मचारियों को भी विस्तारित किया



गया है। इस मोटर यान बीमा, जिसके लिए समझौता ज्ञापन का निष्पादन किया जा रहा है, में अनेक मूल्यवर्धित विशिष्टियां हैं, जैसे कि निजी कार और दोहपिया वाहन, दोनों के लिए 65% छूट (तत्कालीन टैरिफ दर पर) का विशिष्ट प्रस्ताव आदि। सदस्य और छात्र इस मोटर यान बीमा पालिसी का आनलाइन रूप से <http://icai.newindia.co.in> वेबसाइट पर क्रय कर सकता है।

**व्यवसायगत सदस्यों/सीए फर्मों के लिए विशेष प्रीमियम पर आफिस प्रोटेक्शन शील्ड बीमा के लिए व्यवस्था:** आईसीएआई की सीसीबीएमपी ने आईसीएआई के सदस्यों के लिए विशेष प्रीमियम पर आफिस प्रोटेक्शन शील्ड बीमा की व्यवस्था की है। इसमें दिलचस्पी लेने वाले सदस्य और सीए फर्म पूर्वोक्त स्कीम के बारे में <http://icai.newindia.co.in> वेबसाइट पर जानकारी ले सकती हैं।

**आईसीएआई के सदस्यों/सीए फर्मों के लिए वृत्तिक क्षतिपूर्ति बीमा:** आईसीएआई की सीसीबीएमपी ने आईसीएआई के व्यवसायगत सदस्यों/फर्मों के लिए युक्तियुक्त प्रीमियम, अर्थात् बाजार दर से 95% तक की छूट सहित, पर विशेष रूप से तैयार किए गए वृत्तिक क्षतिपूर्ति बीमा की व्यवस्था की है। यह स्कीम आईसीएआई के व्यवसायगत सदस्यों/फर्मों के लिए उपलब्ध है। पूर्वोक्त स्कीम के फायदों का लाभ उठाने के इच्छुक सदस्य और सीए फर्म इस स्कीम के बारे में <http://icai.newindia.co.in> वेबसाइट पर जानकारी ले सकती हैं।

- **आईसीएआई कनेक्ट – सदस्यों के लिए एक स्व सेवा पोर्टल:** सीसीबीएमपी ने आईसीएआई कनेक्ट, आईसीएआई के सदस्यों के लिए एक स्व सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया है। पूर्वोक्त एकल पटल स्व सेवा पोर्टल की विशिष्टियों में निजी प्रोफाइल और फर्म के संविधान, आईसीएआई की उदघोषणाओं, आईसीएआई को संदत्त फीसों और विनियामक प्रभारों के व्यौरों, माई आर्टिकल्स के व्यौरों को देखना, विनियामक प्ररूपों और आवेदनों की प्रास्थिति को ट्रेक करना, ई-सेवाओं, माई फर्मों, माई साफ्टवेयर, लेटर्स और प्रमाणपत्रों, प्रत्यय किए गए सीपीई घंटों, नेटवर्क करने, विलयन और निर्विलयन संबंधी दिशा-निर्देशों आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त करना सम्मिलित है।
- **समिति की अनन्य वेबसाइट [www.icai.org.in](http://www.icai.org.in):** सीसीबीएमपी ने एक वेबसाइट, अर्थात् [www.icai.org.in](http://www.icai.org.in) को विकसित किया है, जहां फर्म और व्यवसायी भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् द्वारा अधिकथित संनियमों के अनुसार अपने पोर्टलों का सृजन कर सकते हैं। यह वेबसाइट सीए फर्मों के लिए एक ऐसा मंच उपलब्ध कराती है, जहां वे अपनी फर्मों के व्यौरे अपलोड कर सकती हैं और इस प्रकार उन्हें सदस्यों और विश्व भर में व्यवसायगत सीए फर्मों तक पहुंच बनाने का अवसर प्राप्त होता है। यह वेबसाइट आईसीएआई के सदस्यों और सीए फर्मों के सुदृढीकरण के लिए भी एक ऐसे मंच के रूप में कार्य करती है, जो नेटवर्किंग, विलयन और व्यवसाय के निगम रूप जैसे सुदृढीकरण उपायों को उपलब्ध कराती है। इस वेबसाइट पर सदस्य अन्य सदस्यों और फर्मों के पोर्टल को देख सकते हैं और समान सोच वाले व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए और स्वयं का विकास करने के लिए हाथ मिला सकते हैं।
- **आईसीएआई के वरिष्ठ सदस्यों के लिए पोर्टल [www.seniormembers.icai.org](http://www.seniormembers.icai.org):** सीसीबीएमपी ने एक वेबसाइट अर्थात् [www.seniormembers.icai.org](http://www.seniormembers.icai.org) को विकसित किया है। यह वेबसाइट आईसीएआई के वरिष्ठ सदस्यों को, उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् नमनीय कार्य घंटों के समनुदेशन और साथ ही पूर्णकालिक कार्य प्राप्त करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराती है। साथ ही यह पोर्टल उद्योग की, ऐसे अनुभव प्राप्त योग्य पूल तक पहुंच स्थापित करने में सहायता करेगा, जिस तक सामान्य अनुक्रम में अन्यथा पहुंच संभव नहीं हो सकती थी। उक्त पोर्टल आईसीएआई के सभी वरिष्ठ सदस्यों के लिए उपयोगी और सुगम सिद्ध होगा।
- **ज्ञान का आदान-प्रदान और उसमें अभिवृद्धि: "प्रैक्टिकुअर" – चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए एक त्रैमासिक ई-न्यूज लैटर** सीसीबीएमपी ने सीए भ्रातृसंघ के लिए एक त्रैमासिक ई-न्यूज लैटर निकालने के लिए पहल की है, जिसमें वृत्ति से संबंधित नवीनतम घटनाओं को विशिष्ट रूप से दर्शित किया जाता है। यह ई-न्यूज लैटर, अर्थात् "प्रैक्टिकुअर" एक ऐसा सटीक उपकरण है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंटों को सभी अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराएगा। यह वृत्ति के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जानकारी का संकलन करता है और यह सदस्यों के लिए अत्यधिक फायदेमंद होगा। सीसीबीएमपी ने व्यवसायियों के ज्ञान आधार की अभिवृद्धि के लिए निम्नलिखित प्रकाशन निकाले हैं :
  - आय-कर व्यवसाय के लिए कार्ययोजना : व्यवसायियों का परिप्रेक्ष्य

- माल और सेवा कर के लिए कार्ययोजना : व्यवसायियों का परिप्रेक्ष्य
- आईसीएआई के सदस्यों और सीए फर्मों के लिए “विनियामक पहलुओं संबंधी सुगम संदर्भिका” संबंधी ई-पुस्तक
- **वर्ष 2018 पर एक नजर:** समिति ने सीए भ्रातृसंघ के लिए वर्ष 2018 पर एक नजर, नामक प्रकाशन निकालने की पहल की है, जिसमें वृत्ति से संबंधित नवीनतम घटनाओं को विशिष्ट रूप से दर्शित किया जाता है। इसमें कर, लेखांकन, सीमित दायित्व भागीदारी, प्रबंध परामर्शी सेवाओं, संपरीक्षा संबंधी कथनों और मानकों आदि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और साथ ही सीए छात्रों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रारूपों के संबंध में भी जानकारी अंतर्विष्ट है।
- **आईसीएआई नॉलेज बैंक के गेटवे पोर्टल <http://kb.icai.org/> का समेकन:** समिति ने आईसीएआई के सभी प्रकाशनों के समेकन के लिए आईसीएआई नॉलेज बैंक के गेटवे के रूप में एक पोर्टल <http://kb.icai.org/> का शुभारंभ किया था। इस पोर्टल को इस रूप में तैयार किया गया है कि इसमें खोज/उन्नत खोज की सुविधा और आईसीएआई के प्रकाशनों का उत्तम प्रबंध सम्मिलित किया गया है।
- **लर्निंग कर्व – बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों द्वारा शंकाओं का समेकन करने और शंकाओं के लिए समाधान उपलब्ध कराना और लाइव वेबकास्ट:** समिति ने विभिन्न वृत्तिक मुद्दों पर शंकाओं का समेकन करने और शंकाओं के लिए समाधान उपलब्ध कराने के लिए आईसीएआई के पोर्टल लर्निंग कर्व का शुभारंभ किया था, जो बहुल प्रक्रमों में इन शंकाओं के उत्तर प्रदान करता है ताकि व्यवसाय पोर्टफोलियो और अन्य पहलुओं के संबंध में अभिवृद्धि को सुकर बनाया जा सके।
- **27 जून, 2018 को अंतर्राष्ट्रीय एसएमपी दिवस के रूप में मनाया जाना:** भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ने अपनी समिति के माध्यम से, एसएमपी और एसएमई के विकास के लिए इन उद्यमों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के महत्व को मान्यता प्रदान करते हुए 27 जून, 2018 को अंतर्राष्ट्रीय लघु और मध्यम व्यवसायी दिवस के रूप में मनाया था, जिससे देश के विभिन्न भागों में एसएमपी और एसएमई के योगदान के संबंध में जन जागरूकता का सृजन किया जा सके। समिति ने अंतर्राष्ट्रीय एसएमपी दिवस की पूर्व संध्या पर व्यवसाय प्रबंध और व्याख्यान बैठकों संबंधी एक लाइव वेबकास्ट का आयोजन किया था।
- **नेटवर्किंग और विलयन - नेटवर्किंग के लिए पुनरीक्षित दिशानिर्देश :** सीसीबीएमपी ने नेटवर्किंग के माध्यम से सीए फर्मों के सुदृढीकरण में आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों पर विचार किया है। सीसीबीएमपी ने सदस्यों और फर्मों द्वारा नेटवर्किंग संबंधी पुनरीक्षित दिशानिर्देशों को सुगम रूप से अपनाए जाने को सुकर बनाने के लिए उन्हें उपयुक्त रूप से अंतिम रूप प्रदान किया है। नेटवर्किंग के पुनरीक्षित दिशानिर्देशों के ब्यौरे [http://www.icai.org/post.html?post\\_id=7710](http://www.icai.org/post.html?post_id=7710) पर उपलब्ध हैं। विलयन संबंधी नियमों के ब्यौरों को [www.icai.org.in](http://www.icai.org.in) पर अपलोड किया गया है।
- **उपापन संपरीक्षा के लिए विश्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन:** सीसीबीएमपी ने उपापन संपरीक्षा के क्षेत्र में आईसीएआई के सदस्यों के ज्ञान में अभिवृद्धि की व्यवस्था करने के लिए विश्व बैंक के साथ ठहराव के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। विश्व बैंक के साथ पूर्वोक्त ठहराव प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वाले व्यक्तियों के लिए संयुक्त प्रमाणन के साथ उपापन प्रशिक्षण प्रस्थापित करता है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य आईसीएआई के सदस्यों की सक्षमता में अभिवृद्धि करना है, जिससे वे बाह्य/आंतरिक संपरीक्षाओं : उपापन संपरीक्षाओं/पश्च पुनर्विलोकनों और आईसीएआई की फर्मों और व्यक्ति सदस्यों के लिए अन्य परामर्शी समनुदेशनों को अंतर्विलित करते हुए बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं हेतु विभिन्न समनुदेशनों में उपापन अवसरों का लाभ उठा सकें।
- **प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम:** सीसीबीएमपी, सदस्यों के लिए करियर संबंधी नए अवसरों में अभिवृद्धि करने के लिए धन प्रबंध और वित्तीय योजना संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम और अपीलों को तैयार किए जाने, विलेख और दस्तावेजों के प्रारूपण और अपील प्राधिकरणों तथा कानूनी निकायों के समक्ष प्रतिनिधित्व करने संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य, धन प्रबंध के सिद्धांतों में सदस्यों को ज्ञान से

सुसज्जित करना और साथ ही उनके प्रभावी प्रारूपण कौशलों में अभिवृद्धि करना तथा नीतिगत निवेशों और सेवानिवृत्ति फायदों संबंधी मार्गदर्शन के माध्यम से उनके धन प्रबंध को सशक्त बनाना है।

- **वर्ग 'क' और वर्ग 'ख' नगरों के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा किए गए वृत्तिक कार्यों के लिए फीस से संबंधित पुनरीक्षित न्यूनतम सिफारिश किए गए मान:** सीसीबीएमपी ने आईसीएआई के सदस्यों द्वारा किए गए वृत्तिक कार्यों के लिए फीस के मान के संबंध में विहित न्यूनतम सिफारिशों को आगे और पुनरीक्षित करने की एक प्रमुख पहल की है। यह सिफारिश, विभिन्न वृत्तिक कार्यों के लिए किए गए कार्य के अनुसार प्रभारित फीस और वृत्तिक कार्य के संबद्ध शीर्षों के अधीन कोट की गई रकमों से संबंधित है। इस फीस की वर्ग 'क' और वर्ग 'ख' नगरों के लिए पृथक् रूप से सिफारिश की गई है। विहित न्यूनतम सिफारिश की गई फीस के मान व्यवसायियों और सीए फर्मों की उत्पादकता और सक्षमता निर्माण में अभिवृद्धि करेंगे और बृहत् रूप से व्यवसायियों को फायदा पहुंचाएंगे। फीस के पुनरीक्षित मान के ब्यौरे [https://www.icai.org/post.html?post\\_id=14230](https://www.icai.org/post.html?post_id=14230) लिंक पर उपलब्ध हैं।
- **आईसीएआई की महिला सदस्यों का सशक्तिकरण:** समिति का महिला सदस्य सशक्तिकरण खंड निष्कपट रूप से महिला सीए के लिए कार्य कर रहा है ताकि उन्हें पूर्णतया सशक्त बनाया जा सके और उनके परिप्रेक्ष्य को बृहत् बनाया जा सके।
- **आईसीएआई की महिला सदस्यों के लिए एक पोर्टल [www.womenportal.icai.org](http://www.womenportal.icai.org):** सीसीबीएमपी के अधीन महिला सदस्यों के लिए एक पोर्टल कार्यकरण करता है, जो लेखांकन वृत्ति और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास के प्रति महिला सदस्यों के योगदान को बढ़ावा देता है और साथ ही उनकी घरेलू प्रतिबद्धताओं की भी देखभाल करता है।
- **लीड - महिला सीए के लिए एक विविध समर्थन:** सीसीबीएमपी और सीपीई समिति, लीड - महिला सीए के लिए एक विविध समर्थन, को प्रस्तुत करती हैं, जहां महिला सीए किसी भी क्षेत्र के संबंध में निजी विकास, वृत्तिक अभिवृद्धि और सशक्त बने रहने की रणनीतियों से संबंधित प्रश्न पूछ सकती हैं तथा अगुवाई कर सकती हैं।
- **सेतु – महिला सदस्यों और सीए फर्मों के बीच की खाई को भरना:** सीसीबीएमपी महिला सशक्तिकरण के संबंध में अपने सेतु कार्यक्रम, अर्थात् पूरे राष्ट्र में महिला सदस्यों और व्यवसायरत सीए फर्मों के बीच की खाई को भरने के संचालन के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण से संबंधित नियमित कार्यक्रमों/संगोष्ठियों का भी आयोजन करती है।
- **लाइव वेबकास्ट:** सीसीबीएमपी ने, व्यवसाय प्रबंध, जीएसटी संपरीक्षा, आईटीआर प्ररूपों में हाल ही में हुए परिवर्तनों, इंड एएस के अधीन उचित मूल्य मापमान, बैंक संपरीक्षा में दस्तावेजीकरण, सीए भ्रातृसंघ के लिए नई चुनौतियां और अवसर, धन प्रबंध और वित्तीय योजना, कर संपरीक्षा रिपोर्ट, अपील अधिकरणों के समक्ष उपस्थित होना, क्रेडिट रेटिंग, आय-कर अधिनियम, एफसीआरए और जीएसटी के अधीन न्यास और कराधान, इंड एएस : व्यवहारिक रूप से लागू होना और उभरती हुई प्रवृत्तियां और बैंक संपरीक्षा के संबंध में व्यवसायियों के सक्षमता निर्माण उपायों के रूप में लाइव वेबकास्टों का आयोजन किया था।

## 5.6 सतत् वृत्तिक शिक्षा संबंधी समिति (सीपीई समिति)

सीपीई समिति ने अपने सदस्यों को समकालीन ज्ञान और कौशलों को अर्जित करने में समर्थ बनाने की उभरती आवश्यकताओं के प्रति स्वयं को सक्रिय बनाए रखने के लिए अनथक प्रयास किए हैं, जिससे सदस्यों को इस सदैव परिवर्तनशील आर्थिक और कारबार वातावरण में जागरूक बनाने और उनकी चुनौतियों का सामना करने में समर्थ बनाया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए ऐसे उपायों को अपनाना, उनका निष्पादन और कार्यान्वयन करना है, जिससे सदस्यों को ऐसे पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जा सकें ताकि वे समकालीन ज्ञान से लैस हो सकें। वैश्विक अपेक्षाओं से कदम से कदम मिलाते हुए, सीपीई अपेक्षाओं को आईसीएआई के सभी सदस्यों के लिए आज्ञापक बनाया गया है चाहे वह व्यवसायरत हों या सेवा में हों और इसकी जांच संबंधी प्रणाली का वैज्ञानिक रूप से मापमान, मानीटरी और प्रबंध किया जाता है।

सीपीई समिति, अपने सदस्यों के ज्ञान आधार में वृद्धि करने के लिए अपने सदस्यों को नए-नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए सदैव अग्रसर रही है क्योंकि उनके लिए यह आवश्यक है कि वे सतत रूप से अपने ज्ञान और कौशलों को अद्यतन करें, जिससे वे पणधारियों की आशाओं पर खरे उतर सकें तथा स्वयं को वृत्तिक विकास और राष्ट्रीय हितों से संबंधित नए और उभरते क्षेत्रों से सुपरिचित करा सकें।

#### सदस्यों के पठन और वृत्तिक विकास के लिए ठोस तंत्र :--

##### • सीपीई विवरण

अपने सदस्यों को अपेक्षित वृत्तिक सक्षमता बनाए रखने में समर्थ बनाने और इस प्रकार उनके द्वारा दी जाने वाली वृत्तिक सेवाओं में उच्च क्वालिटी और मानकों को सुनिश्चित करने के विचार से आईसीएआई के सभी सदस्यों के लिए, चाहे वे व्यवसाय में हों या सेवा में, आईसीएआई की परिषद् द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट सीपीई प्रत्यय घंटों की अपेक्षाओं को पूरा करना आज्ञापक है।

वैश्विक अपेक्षाओं और व्यवहारों के अनुरूप सीपीई प्रत्यय घंटों की अपेक्षाएं, जो सदस्यों के भिन्न-भिन्न प्रवर्गों के लिए (1 जनवरी, 2017 से 31 दिसंबर, 2019) के तीन वर्षों के चालू ब्लॉक के दौरान लागू होंगी, निम्नानुसार हैं :

सदस्यों का प्रवर्ग	पुनरीक्षित (सीपीई घंटे) (01.01.2017 से प्रभावी)
व्यवसाय प्रमाणपत्र धारण करने वाले सभी सदस्य (जिनकी आयु 60 वर्ष से कम है) (सिवाय उनके, जो विदेश में रह रहे हैं)	120 (जिसमें से न्यूनतम 60 सीपीई घंटे असंरचित पठन के होने चाहिए) - प्रत्येक कलेंडर वर्ष में संरचित पठन के न्यूनतम 20 सीपीई प्रत्यय घंटे
व्यवसाय प्रमाणपत्र धारण करने वाले सभी सदस्य (जिनकी आयु 60 वर्ष और उससे अधिक है)	90 (या तो संरचित अथवा असंरचित) - प्रत्येक कलेंडर वर्ष में या तो संरचित या असंरचित पठन के न्यूनतम 20 सीपीई प्रत्यय घंटे
व्यवसाय प्रमाणपत्र धारण न करने वाले सभी सदस्य (जिनकी आयु 60 वर्ष से कम है) ; और ऐसे सभी सदस्य, जो विदेश में रह रहे हैं (चाहे वे व्यवसाय प्रमाणपत्र धारण कर रहे हैं अथवा नहीं)	60 (या तो संरचित अथवा असंरचित) - प्रत्येक कलेंडर वर्ष में या तो संरचित या असंरचित पठन के न्यूनतम 15 सीपीई प्रत्यय घंटे

#### सदस्यों को छूट :

क) किसी सदस्य को केवल ऐसे विशिष्ट कलेंडर वर्ष के लिए ही छूट प्राप्त है, जिसके दौरान वह पहली बार सदस्यता प्राप्त करता है।

ख) निम्नलिखित वर्ग के सदस्यों को सीपीई प्रत्यय घंटों की अपेक्षा से छूट प्राप्त है :

- व्यवसाय प्रमाणपत्र धारण न करने वाले सभी सदस्य (जिनकी आयु 60 वर्ष और उससे अधिक है)
- उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, जिला न्यायालयों और अधिकरणों के न्यायाधीश
- संसद् सदस्य/एमएलए/एमएलसी
- राज्यों के राज्यपाल

- (v) केंद्र और राज्य सिविल सेवाएं
- (vi) उद्यमी [वृत्तिक सेवाओं से भिन्न कारबार (विनिर्माण) संगठनों के स्वामी]
- (vii) न्यायिक अधिकारी
- (viii) सैन्य सेवा के सदस्य

### ग) अस्थायी छूट

- (i) महिला सदस्यों को, उनके गर्भधारण के आधार पर एक कलेंडर वर्ष के लिए
  - (ii) शारीरिक रूप से दिव्यांग सदस्यों के लिए मामला-दर-मामला आधार पर, जिनकी स्थायी दिव्यांगता कम से कम चालीस प्रतिशत और उससे अधिक है [भारतीय चिकित्सा परिषद् के पास रजिस्ट्रीकृत किसी ऐसे डाक्टर, जिसके पास सुसंगत विशेषज्ञता है, जैसा कि उसकी स्नातकोत्तर अर्हताओं (एमडी, एमएस आदि) से साबित होता है, के चिकित्सा प्रमाणपत्रों द्वारा समर्थित]
  - (iii) सीपीईसी द्वारा विनिर्दिष्ट या अनुमोदित की जाने वाली किसी लंबी गंभीर बीमारी/रोग या अन्य दिव्यांगता से पीड़ित सदस्य [भारतीय चिकित्सा परिषद् के पास रजिस्ट्रीकृत किसी ऐसे डाक्टर, जिसके पास सुसंगत विशेषज्ञता है, जैसा कि उसकी स्नातकोत्तर अर्हताओं (एमडी, एमएस आदि) से साबित होता है, के चिकित्सा प्रमाणपत्रों द्वारा समर्थित]
- घ) कोई सदस्य या सदस्यों का कोई वर्ग, जिसे समिति अपने नेतांत विवेकाधिकार से, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर विनिर्दिष्ट रूप से या सामान्य रूप से पूर्ण/अंशकालिक छूट प्रदान करती है, जो उसकी राय में ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) को यथाविनिर्दिष्ट सीपीई घंटों की अपेक्षाओं को पूरा करने से निवारित करती हैं।

### सीपीई पोर्टल और आईसीएआई मोबाइल ऐप के माध्यम से भी सीपीई क्रियाकलापों का एकीकरण

सीपीई क्रियाकलापों के संबंध में अपने सदस्यों के लिए एक और अधिक ठोस, उपयोक्ता मित्र तथा मोबाइल के अनुरूप कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाने को सुकर बनाने हेतु अपने सीपीई पोर्टल ([www.cpeicai.org](http://www.cpeicai.org)) में कतिपय उपबंधों को समय-समय पर और पुनः विकसित किया गया है, जिससे कि सीपीई समिति की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके। सीपीईसी पोर्टल का उद्देश्य, वृत्ति से संबंधित नवीनतम घटनाओं के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने और युवा चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए आईसीएआई की विभिन्न पहलों का संवर्धन करने के लिए एक ज्ञान मंच को विकसित करना है।

विद्यमान सीपीई पोर्टल को उस सीमा तक मोबाइल उपयोक्ता मित्र बनाने के लिए प्रयास किए गए हैं, जिससे सदस्य अपने सीपीई घंटों की अपने इस पोर्टल से लैस मोबाइल फोनों के माध्यम से जांच कर सकें। सीपीई समिति ने आईसीएआई मोबाइल ऐप (एंड्रायड और आईओएस प्लेटफार्म) पर “सीपीई कार्यक्रमों” के संबंध में पता लगाने के लिए एक पहल की है, जिसका उपयोग हमारे सदस्यों द्वारा कहीं भी और किसी भी समय सीपीई क्रियाकलापों की मानीटरी के लिए किया जा सकता है। सदस्यों से यह अपेक्षित है कि गूगल प्ले स्टोर से आईसीएआई मोबाइल ऐप डाउनलोड करके अपने मोबाइल में इंस्टाल कर लें।

इस ऐप पर “सीपीई कार्यक्रम” खंड में इस प्रकार की विशिष्टियां अंतर्विष्ट हैं जैसे कि आगामी कार्यक्रमों के ब्यौरे, कार्यक्रमों के लिए रजिस्ट्रीकरण, सीपीई कार्यक्रमों के संबंध में एलर्ट/नोटिफिकेशन प्राप्त करना और अपनी अधिमानताओं को निर्धारित करना, असंरचित पठन क्रियाकलापों को आनलाइन रूप से प्रस्तुत करना, अपने सीपीई घंटों के प्रत्यय के बारे में जानना, सीपीईसी न्यूज लैटर वेबकास्टों को देखना, की वड्स के माध्यम से नगरवार, पीओयू वार, विषयवार खोज सुविधा और सीपीई समिति के बारे में जानकारी आदि।

### सीपीई कार्यक्रमों की प्रभावी मानीटरी और क्वालिटी सीपीई कार्यक्रमों का आयोजन करने संबंधी सीपीई दिशानिर्देश

कार्यक्रम आयोजक ईकाईयों (पीओयू) के द्वारा क्वालिटी सीपीई कार्यक्रमों का आयोजन करने और सीपीई कार्यक्रमों की प्रभावी मानीटरी करने संबंधी निम्नलिखित संनियम, दिशानिर्देश और निर्देश सीपीई पोर्टल पर उपलब्ध हैं :

- सीपीई संबंधी विवरण

- सीपीई अध्ययन सर्कलों के लिए संनियम
- सीपीई अध्ययन चेप्टरों के लिए संनियम
- सीपीई अध्ययन समूहों के लिए संनियम
- सीपीई संबंधी सलाहें
- सीपीई कार्यक्रमों के आयोजन के वृत्तिककरण के लिए परिषद् के निदेश
- आईसीएआई की केंद्रीय समितियों द्वारा आयोजित किए जाने वाले ऐसे सभी कार्यक्रमों, जिनमें सीपीई प्रत्यय सम्मिलित हैं, यथा लागू ऐसे पैरामीटर, जो उन्हें राष्ट्रीय सम्मेलनों और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की प्रास्थिति प्रदान करते हैं।

### सीपीई कलेंडर

सीपीई समिति ने वर्ष 2018-19 के लिए सीपीई कलेंडर तैयार किया है, जिसमें तीन भागों में सदस्यों की सतत वृत्तिक शिक्षा के लिए सर्वाधिक सुसंगत और समकालीन विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। भाग क, वर्तमान वृत्तिक परिदृश्य में विभिन्न महत्वपूर्ण सुसंगत क्षेत्रों के लिए मानक कार्यक्रम संरचना का उपबंध करता है। भाग ख विनिर्दिष्ट रूप से विशिष्ट विषयों का उपबंध करता है और भाग ग के अंतर्गत ऐसे विषयों की सुविस्तृत सूची सम्मिलित है, जिन्हें पिछले वर्षों के दौरान सम्मिलित किया गया है।

### ई-न्यूज लैटर

त्रैमासिक ई-न्यूज लैटर “सीपीई बुलेटिन” को निकाला जा रहा है, जिससे हाल ही की ऐसी पहलों के बारे में जानकारी प्रदान की जा सके, जो समिति द्वारा की गई हैं और उसे सदस्यों, पीओयू और अन्यो की जानकारी के लिए आईसीएआई की वेबसाइट और साथ ही सीपीई पोर्टल पर रखा गया था।

### वैश्विक सत्ता बनना

सीपीई कार्यक्रम आयोजक ईकाईयों (पीओयू) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रूप से 25 सीपीई अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन दौरों/संगोष्ठियों का आयोजन थाइलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, भूटान, इंडोनेशिया, इंग्लैंड, स्काटलैंड, आस्ट्रेलिया और श्रीलंका में किया गया था।

### ब्रांड और क्षमता निर्माण

आईसीएआई, अपने सदस्यों को ऐसे वृत्तिक और प्रौद्योगिकी परिवर्तनों, जो पूरे विश्व में हो रहे हैं, के संबंध में, कक्षा पठन, ई पठन पद्धति, घरेलू कार्यपालक विकास कार्यक्रमों, वेबकास्टों, जागरूकता कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों आदि के माध्यम से निरंतर उनके कौशलों में सुधार करने की प्रक्रिया को अपनाते हुए उन्हें जागरूक बनाने और उन्हें उससे अवगत कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। उसकी कुछ उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :

### सीपीई लाइव वेबकास्ट

सीपीई समिति द्वारा वृत्तिक और राष्ट्रीय हितों के उभरते विषयों, अर्थात् आईसीडीएस का पर्यावलोकन, लागू किया जाना और उसकी विवक्षाएं, नई बेनामी विधि की कटु विवक्षाएं : पर्यावलोकन और मुद्दे, यूएई वेट, उभरता हुआ भारत-एनआरआई परिप्रेक्ष्य के संबंध में लाइव वेबकास्टों का आयोजन किया गया था। आईसीएआई की अन्य केंद्रीय समिति द्वारा वृत्तिक हित के विभिन्न विषयों पर 64 वेबकास्टों का आयोजन किया गया था। वेबकास्टों की रिकार्डिंग [www.icaity.com](http://www.icaity.com) पर उपलब्ध है।

### राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम और अन्य महत्वपूर्ण आयोजन

- अप्रैल, 2017 के पश्चात् से सीपीई समिति द्वारा राष्ट्रीय स्तर आदि पर 48 सीपीई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था जिनकी मेजबानी देश के भिन्न-भिन्न भागों में आईसीएआई की प्रादेशिक परिषदों/शाखाओं द्वारा की गई थी।
- सीपीई पीओयू द्वारा वृत्तिक हितों के विभिन्न विषयों पर देश भर में 9,653 सीपीई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। आईसीएआई की केंद्रीय समितियों के माध्यम से सदस्यों के लिए आईसीएआई के जीएसटी, धन

प्रतिशोधन विधियों, धन प्रबंध और वित्तीय योजना, बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा, इंड एस, न्यायालयीन लेखांकन और कपट का पता लगाने आदि संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों से संबंधित 194 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था तथा सूचना प्रणाली संपरीक्षा संबंधी अर्हता-पश्च पाठ्यक्रम (आईएसए), बीमा और जोखिम प्रबंध में डिप्लोमा (डीआईआरएम) और अंतर्राष्ट्रीय कराधान आदि संबंधी 97 अर्हता-पश्च पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया था।

### **नई सीपीई कार्यक्रम आयोजक इकाईयों (पीओयू) को प्रारंभ करना**

देश के मुफसिल/दुरस्थ स्थानों में अवस्थित सदस्यों को उनके निकट स्थानों पर सीपीई क्रियाकलापों में भाग लेने में सहायता करने के लिए 31 और सीपीई पीओयू आरंभ किए गए थे, जिससे भारत और विदेशों में 594 सीपीई पीओयू का एक सुदृढ़ नेटवर्क स्थापित हो गया है।

### **पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम**

आईसीएआई की अन्य केंद्रीय समितियों द्वारा आयोजित विभिन्न अन्य कार्यपालक विकास कार्यक्रमों के अलावा निम्नलिखित घरेलू कार्यपालक विकास कार्यक्रमों (आईएचईडीपीएस) का आयोजन किया था:--

- आईओसीएल, गुडगांव के पदधारियों के लिए 5 दिवसीय आईएचईडीपी।
- आईसीएआई की एसआईआरसी द्वारा चेन्नई स्थित आईओसीएल के पदधारियों के लिए 3 दिवसीय आईएचईडीपी।
- मुंबई स्थित ओएनजीसी के परिसरों में उसके पदधारियों के लिए 3 दिवसीय आईएचईडीपी।

### **समाज की सहायता करना – राष्ट्र के लिए प्रतिबद्धता**

आईसीएआई, देश के विभिन्न भागों में, सरकार की नई पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन का समर्थन करने के लिए अपनी सीपीई कार्यक्रम आयोजक इकाईयों के सुदृढ़ नेटवर्क आधार के माध्यम से निम्नलिखित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करता है :

- सीपीई पीओयू द्वारा विमुद्रीकरण, काला धन, बेनामी संव्यवहार और अप्रकटित आय संबंधी 164 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।
- सीपीई पीओयू द्वारा देश के विभिन्न भागों में जीएसटी संबंधी 3558 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।
- रेरा (भू-संपदा विनियामक अधिनियम) संबंधी 310 कार्यक्रम।
- आईसीडीएस (आय की संगणना और प्रकटन मानक) संबंधी 582 कार्यक्रम।
- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संबंधी 288 कार्यक्रम।
- कंपनी अधिनियम संबंधी 168 कार्यक्रम।
- सीपीई पीओयू द्वारा देश के विभिन्न भागों में निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) संबंधी 7 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।
- स्विफ्ट संव्यवहारों (अंतर्राष्ट्रीय अंतः बैंक अंतरण) संबंधी 48 कार्यक्रम।
- निवेशक जागरूकता संबंधी 29 कार्यक्रम।
- वृत्तिक नैतिकता संबंधी 71 कार्यक्रम।
- 21 जून को, जिसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, तनाव प्रबंध, जीवन शैली प्रबंध, जहां योग जीवन का सही मार्ग है, कार्य जीवन संतुलन आदि विषयों पर 62 सीपीई कार्यक्रमों का आयोजन।

### **अन्य प्रमुख पहलें**

**ई-पठन प्लेटफार्म – पठन और उत्कृष्टता के लिए वर्चुअल केंद्र** – आईसीएआई ने 1 जुलाई, 2018 से अपने हीरक जयंती वर्ष समारोह आरंभ कर दिए हैं। इस अवसर पर, सीपीई समिति ने एक ई-पठन प्लेटफार्म “पठन और उत्कृष्टता के लिए वर्चुअल केंद्र” का शुभारंभ किया है, जो [www.icailearning.org](http://www.icailearning.org) पर उपलब्ध है।

डेस्कटाप कंप्यूटरों, टैबलेट कंप्यूटरों, आई पेड आदि के बढ़ते उपयोग के साथ आईसीएआई ने यह महसूस किया था कि सदस्यों के पास तुरंत ही सदैव परिवर्तनशील वृत्तिक क्षेत्र से स्वयं को नियमित रूप से अद्यतन बनाए रखने का अवसर होना चाहिए। अतः, सीपीई समिति ने, वर्चुअल पठन को बढ़ावा देने के लिए एक ई-पठन प्लेटफार्म, जो [www.icailearning.org](http://www.icailearning.org) पर उपलब्ध हैं, पठन और उत्कृष्टता के लिए वर्चुअल केंद्र के रूप में विकसित किया है, जिसमें विशिष्ट विशेषज्ञों द्वारा समकालीन विषयों पर विभिन्न ई-पठन पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, जो सदस्यों की असंरचित सीपीई पठन क्रियाकलापों के माध्यम से सीपीई क्रेडिट घंटे अर्जित करने में सहायता करते हैं।

**आईसीएआई टीवी – सर्वांगीण ज्ञान केंद्र** – जैसे ही आईसीएआई ने 1 जुलाई, 2018 को अपने हीरक जयंती वर्ष में प्रवेश किया वैसे ही इस ऐतिहासिक अवसर पर आईसीएआई ने आईसीएआई टीवी को पुनः आरंभ किया है, जो एक आनलाइन 24X7 पोर्टल है, जिसमें महत्वपूर्ण आईसीएआई की पहलों/उपलब्धियों/उससे संबंधित घटनाओं को दर्शाया जाता है तथा विश्व भर से आईसीएआई के कार्यक्रमों के लाइव वेबकास्ट/टेलीकास्ट को रखा जाता है। आईसीएआई टीवी के इस नए अवतार के साथ, संस्थान का उद्देश्य सभी पणधारियों, जिनके अंतर्गत सदस्य, छात्र, सरकार और साधारण जनता भी है, के साथ एक सुदृढ़ विश्वास के बंधन का निर्माण करना है।

आईसीएआई का यह दृढ़ विश्वास है कि परस्पर जोड़ने की शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है और अपनी इस नवीन पहल के माध्यम से आईसीएआई का उद्देश्य लेखांकन, आश्वासन, कराधान, वित्त, कारबार, शिक्षा, अंकीय प्रवृत्तियों के क्षेत्र में और सीए वृत्ति से संबंधित समकालीन मुद्दों पर और अधिक गहन अंतर दृष्टियों के साथ उपयोगी सूचना का प्रसार करके राष्ट्र के प्रमुख लेखांकन निकाय के रूप में अपनी छवि को सुदृढ़ करने का है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आईसीएआई टीवी सदस्य, छात्र, सरकार और साधारण जनता को आईसीएआई के बारे में अद्यतन जानकारी से अवगत कराएगा और ऐसा केवल [www.icaity.com](http://www.icaity.com) पर अपने डेस्कटाप, लैपटाप, टैब या स्मार्ट फोन पर अपनी सुविधानुसार एक साधारण क्लिक से संभव हो सकेगा।

**समाधान : एक सीपीई – प्रश्न और उत्तर ई-समाधान मंच** – समाधान एक सीपीई – प्रश्न और उत्तर ई-समाधान मंच है, जिसके माध्यम से सदस्य विशेषज्ञों तक पहुंच बना सकते हैं और अथाह जानकारी या व्यवसाय के चुने गए क्षेत्रों में शंकाओं के समाधान का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। 18.05.2018 से 24.05.2018 के दौरान अनिवासी कराधान, जिसके अंतर्गत धारा 195 भी है, से संबंधित सत्रों को खोला गया था और 13.06.2018 से 18.06.2018 के दौरान युवा सदस्यों की व्यवसाय संबंधी रणनीति तथा माल और सेवा कर – इनपुट कर प्रत्यय विषयों पर सत्रों को खोला गया था।

साथ ही, सीपीई समिति और आईसीएआई की व्यवसायरत सदस्यों की सक्षमता निर्माण संबंधी समिति ने सीपीई और सीसीबीएमपी समितियों द्वारा महिला सीए के लिए बनाए गए लीड – विविध समर्थन मंच के संबंध में एक सत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें महिला सीए किसी भी क्षेत्र के संबंध में पूरे वर्ष के दौरान उनके निजी विकास, वृत्तिक अभिवृद्धि और सशक्त बने रहने की रणनीतियों संबंधी प्रश्न पूछ सकती हैं और अगुवाई कर सकती हैं।

**मेरा सीपीई – आपकी मर्जी का सीपीई कार्यक्रम** – यह अवधारणा सदस्यों के लिए एक विकल्प उपलब्ध कराती है, जिसके द्वारा वे मेरे सीपीई – सीपीई कार्यक्रमों के लिए अपनी मर्जी के कार्यक्रम संबंधी अधिमानताओं को गूगल फोरम पर उस कार्यक्रम को चुनकर, जिसमें वे दिलचस्पी रखते हैं, अद्यतन कर सकते हैं, जिससे कि इस प्रकार प्राप्त हुई अधिमानताओं का योग लगाया जा सके और संबंधित कार्यक्रम आयोजक इकाईयों (पीओयू) को वर्ष के अनुक्रम के दौरान इन कार्यक्रमों को आयोजन करने की संसूचना दी जा सकती है। कोई सदस्य, जो इनमें से किन्हीं विषयों में विशेषज्ञ हैं और इन कार्यक्रमों का अध्यापन करने में दिलचस्पी रखता है, इस संबंध में पीओयू को संसूचित करते हुए उसे इंगित कर सकता है।

**आईसीएआई – आईसीई : आईसीएआई परस्पर क्रियाशील सीपीई संबल** – सीपीई समिति ने 'आईसीएआई – आईसीई' को विकसित किया है, जो एक आईसीएआई परस्पर क्रियाशील सीपीई संबल है, जिस पर सीपीई कार्यक्रमों से पूर्व और उसके दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं तथा मतदान कराया जाता है। सीपीई – ई-पहल प्रयासों के भाग रूप में अब आईसीएआई – आईसीई के एक संपूर्ण पाठ को, विभिन्न पीओयू द्वारा आयोजित किए जाने वाले सभी सीपीई कार्यक्रमों के लिए समर्थ बनाया गया है, जिसके माध्यम से वक्ताओं से कार्यक्रम से पूर्व और कार्यक्रम के दौरान प्रश्न पूछे जा सकते



हैं, जिनमें से अनेक का उत्तर वक्ताओं द्वारा समय की उपलब्धता के अनुसार दिया जा सकेगा। सदस्य <https://ice.icaai.org> पर लॉगइन करके आईसीएआई परस्पर क्रियाशील सीपीई संबल पोर्टल तक कार्यक्रम के संबंधित आईसीई कोड का प्रयोग करके पहुंच बना सकते हैं।

**आनलाइन प्रतिक्रिया तंत्रों का विकास और कार्यान्वयन** – समिति ने विभिन्न आनलाइन प्रतिक्रिया प्रारूपों, अर्थात् त्वरित प्रतिक्रिया प्रारूप, व्यौरेवार प्रतिक्रिया प्रारूप और मानीटर प्रतिक्रिया प्रारूप को विकसित किया है, जिससे प्रक्रिया तंत्र को और सकल रूप से सीपीई ढांचे को सुदृढ़ बनाया जा सके।

**लीडर स्पीक** – लीडर स्पीक नेताओं द्वारा हित के समकालीन विषयों के संबंध में वेबकास्टों की एक शृंखला है, जिसका उद्देश्य सदस्यों के ज्ञान आधार को विस्तृत करना है। सीपीई समिति द्वारा 28 मई, 2018 को ऐसे ही एक वेबकास्ट का आयोजन किया गया था, जिसकी मेजबानी आईसीएआई के दोहा चेप्टर द्वारा की गई थी, जिसमें सीए सीतारमन, दोहा बैंक ने उभरते भारत – एक एनआरआई परिप्रेक्ष्य विषय पर एक लीडर स्पीक सत्र को संबोधित किया था।

## 5.7 निगम विधि और निगम शासन संबंधी समिति (सीएल एंड सीजीसी) तथा सीएल एंड सीजीसी का दिवाला और शोधन अक्षमता विधियों संबंधी समूह

### अ. निगम विधि और निगम शासन संबंधी समिति (सीएल एंड सीजीसी)

सीएल एंड सीजीसी का उद्देश्य सर्वोत्तम वैश्विक व्यवहारों के साथ एक उचित निगम व्यवस्था की स्थापना को सुकर बनाना है और ऐसा सरकार के साथ सहायक प्रयासों के माध्यम से किया जाता है जिससे विनियामक ढांचे, अर्थात् कंपनी अधिनियम, 2013 की नियम बनाने की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाया जा सके और कारपोरेट कार्य मंत्रालय के साथ नियमित रूप से परस्पर क्रियाकलाप किए जाते हैं तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के संबंध में उन्हें प्रतिवेदन/सुझाव/अंतःनिवेश उपलब्ध कराए जाते हैं।

### महत्वपूर्ण उपलब्धियां और पहलें

#### कारपोरेट कार्य मंत्रालय को प्रतिवेदन

#### क. कंपनी अधिनियम, 2013

सीएल एंड सीजीसी, कंपनी अधिनियम, 2013 के सुचारु कार्यान्वयन के लिए नियमित रूप से कारपोरेट कार्य मंत्रालय के साथ परस्पर क्रिया करती है। उसने मंत्रालय को निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे :

#### वर्ष 2017-18 के दौरान

- चार्टर्ड अकाउंटेंटों की सदस्यता संख्या को डीआईएन के साथ जोड़ने के संबंध में।
- कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन संपरीक्षाओं की संख्या पर निर्बंधन से संबंधित मुद्दों के संबंध में।
- कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन संपरीक्षा चक्रानुक्रम और कानूनी संपरीक्षकों के कार्यकाल की समाप्ति पर उनकी आंतरिक संपरीक्षक के रूप में नियुक्ति और विलोमतः।
- संपरीक्षा फर्मों से संबंधित मुद्दों पर एमसीए के विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट का प्रत्युत्तर। इसकी मुख्य अंतर्वस्तु निम्नानुसार थी:
  - भारत में अपनाए जाने वाले लेखांकन और संपरीक्षा मानकों और व्यवहारों को आवश्यक सीमा तक उपांतरणों के साथ अंतर्राष्ट्रीय मानकों और व्यवहारों से सुमेलित किया जाना चाहिए।
  - भारतीय संपरीक्षा फर्मों की तुलनात्मक रूप से कम संख्या वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने की राह में एक रोड़ा है, विलयन और भारतीय संपरीक्षा फर्मों की नेटवर्किंग के माध्यम से नीतिगत उपायों के द्वारा समेकन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
  - संपरीक्षा अब बहु-विषयक कृत्य बनता जा रहा है इसलिए बहु विषयक संपरीक्षा फर्मों को तैयार किए जाने का संवर्धन किया जाना चाहिए, इन फर्मों में अन्य सुसंगत वृत्तियों से वृत्तिक भी भागीदारी कर सकेंगे।

- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड, जो भारतीय संपरीक्षा फर्मों का तकनीकी मूल्यांकन करता है, की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाए।
- जब कभी संपरीक्षा और आश्वासन के क्षेत्रों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए खोला जाता है, पारस्परिकता के सिद्धांत का अनुपालन किया जाना चाहिए और भारतीय संपरीक्षा फर्मों के हितों पर सम्यक् रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 और कंपनी (लाभांश की घोषणा और संदाय) नियम, 2014 के उपबंधों के निर्वचन के संबंध में।
- कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन प्राइवेट कंपनियों के चक्रानुक्रम को प्रवर्तनशील [नियम 5ख के साथ पठित धारा 139(2)] से संबंधित मुद्दों के संबंध में।
- एमसीए से यह अनुरोध किया कि वह भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान से कंपनी अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन से उद्भूत होने वाले मुद्दों के संबंध में अंतःनिवेश प्राप्त करे।
- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड द्वारा जारी इस स्पष्टीकरण के संबंध में प्रतिवेदन की दिवाला वृत्तिक अस्तित्व को दिवाला वृत्तिक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड 87 के परंतुक (अनुषंगियों की परतों की संख्या के संबंध में निर्बंधन) के प्रारंभ के लिए लोक सूचना के संबंध में सुझाव।
- एमसीए से यह अनुरोध किया कि वह 30 मार्च, 2017 को एमसीए द्वारा विमुद्रीकरण के कारण संपरीक्षकों द्वारा प्रकटन और रिपोर्टिंग से संबंधित अधिसूचना के बारे में स्पष्टीकरण प्रदान करे।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 144(झ) के अधीन कर सेवाओं को अधिसूचित करने के लिए सुझावों के संबंध में पत्र का उत्तर दें क्योंकि उसके द्वारा कंपनी के संपरीक्षकों के लिए कुछ सेवाओं को प्रतिषिद्ध किया गया है।
- ऋण/उधारों के माध्यम से लाभांश के संदाय को वित्तपोषित करने के लिए अनुसरित किए जाने वाले व्यवहार के संबंध में सुझावों को प्रस्तुत किया।
- कंपनी अधिनियम, 2013 के विभिन्न उपबंधों के अनुसार समाचार-पत्रों में सूचना के प्रकाशन की अपेक्षा को समाप्त करने के प्रस्ताव के संबंध में अपने मत प्रस्तुत किए।
- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अनुसार दिवाला वृत्तिक के रूप में कार्य करते समय कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुपालन के लिए स्पष्टीकरण के संबंध में सुझाव प्रस्तुत किए।
- कंपनी अधिनियम, 2013 और तदधीन बनाए गए नियमों में अंतर्वलित ब्यौरेवार मुद्दे - उपांतरणों के लिए सुझाव।
- संयुक्त उद्यम कंपनियों की दशा में अनुषंगी कंपनियों के अतिरिक्त कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 187(1) के परंतुक की अपेक्षा से पब्लिक और प्राइवेट कंपनियों को छूट दिए जाने के संबंध में।

### वर्ष 2018-19 के दौरान

- प्रारूप कंपनी (फायदाप्रद हित और महत्वपूर्ण फायदाप्रद हित)
- 2013 में कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जनता की टिप्पणियों के लिए जारी प्रारूप राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नियमों के संबंध में आईसीएआई के सुझाव
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 140 के अधीन प्रादेशिक निदेशकों द्वारा संपरीक्षकों को हटाए जाने के लिए आवेदनों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए प्रक्रिया
- कंपनी (संपरीक्षा और संपरीक्षक) संशोधन नियम, 2018 के संबंध में सुझाव

### दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 से संबंधित प्रश्न बैंक

सीएल एंड सीजीसी ने दिवाला और शोधन अक्षमता विधियों से संबंधित समूह के साथ फरवरी, 2018 में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 से संबंधित प्रश्न बैंक जारी किया था।

## **प्रभाग 2 – इंड एस – कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 के संबंध में मार्गदर्शक टिप्पण**

ऐसी कंपनियों द्वारा, जिनसे इंड एस अनुसूची 3 के अनुसार उनके वित्तीय विवरणों को तैयार किया जाना अपेक्षित है, वित्तीय विवरणों को तैयार करने के कार्य को सुकर बनाने के लिए सीएल एंड सीजीसी ने ऐसी कंपनियों के लिए, जिनके लिए इंड एस का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है, प्रभाग 2 – इंड एस – कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 के संबंध में एक मार्गदर्शक टिप्पण जारी किया था।

### **उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक**

उद्योग की विभाग संबंधी माननीय संसदीय स्थायी समिति की बैठक में भाग लिया था, यह बैठक 27 अप्रैल, 2018 को केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उद्यमों के बोर्ड के वृत्तिकरण के संबंध में समीक्षा करने के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उद्यमों के बोर्ड के वृत्तिकरण के संबंध में एक प्रस्तुतीकरण किया गया था।

### **कारबार करने की सुगमता से संबंधित कार्यबल की बैठक**

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने, “कारबार आरंभ करने”, “दिवाला का समाधान करने” और “अल्पसंख्यक निवेशकों की संरक्षा करने” से संबंधित सूचकों के लिए “कारबार करने की सुगमता” संबंधी एक कार्यबल का गठन किया था। इस कार्यबल की तीसरी बैठक का आयोजन 11 अप्रैल, 2018 को किया गया था, जहां इस बात पर विचार किया गया था कि सरकार द्वारा कारबार करने की सुगमता के प्रति की गई पहलों, विशेषकर कारबार आरंभ करने और दिवाला का समाधान करने से संबंधित पहलों के संबंध में जागरूकता का सृजन किए जाने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया था। इस संबंध में, सीएल एंड सीजीसी ने मुंबई, नई दिल्ली और कोलकाता में तीन कार्यक्रमों/वेबकास्टों का आयोजन किया था।

### **पीएसयू में निगम शासन संबंधी एक ज्ञापन लोक उपक्रमों संबंधी संसदीय समिति को प्रस्तुत किया गया था**

लोक उपक्रमों संबंधित संसदीय समिति ने आईसीएआई से यह अनुरोध किया था कि वह एक समानांतर अध्ययन के रूप में “सीपीएसयू” में निगम शासन के विषय की समीक्षा करे और समिति को इस संबंध में एक ज्ञापन प्रस्तुत करे, जिसमें उसके संबंध में उसके मत, सुझाव और राय सम्मिलित की गई हो। इस संबंध में, आईसीएआई ने सीपीएसयू में निगम शासन के विभिन्न पहलुओं के संबंध में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था।

### **निगम शासन संबंधी सेबी समिति की प्रारूप रिपोर्ट के संबंध में सुझाव**

सेबी ने, भारत में सूचीबद्ध कंपनियों के निगम शासन के मानकों में सुधार लाने के उद्देश्य से और निगम शासन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर उसे सलाह देने के लिए निगम शासन संबंधी एक समिति का सृजन किया था। इस संबंध में, आईसीएआई ने सेबी और साथ ही एमसीए को निगम शासन संबंधी सेबी समिति की प्रारूप रिपोर्ट के संबंध में सुझाव प्रस्तुत किए थे। आईसीएआई ने कुछ सुझावों के संबंध में अपनी असहमति प्रकट की थी।

### **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) को लागू किए जाने के लिए प्राइवेट कंपनियों के संपरीक्षकों को दी जाने वाली छूटों के लागू होने के संबंध में स्पष्टीकरण**

एमसीए को प्रस्तुत हमारे प्रतिवेदनों के आधार पर, धारा 143(3)(i) के अधीन जारी तारीख 13 जून, 2017 की अधिसूचना के अनुसार, जिसके द्वारा प्राइवेट कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 462 के अधीन आगे और छूट प्रदान की गई है, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संबंधी रिपोर्टिंग के लिए दी गई छूट के लागू होने के संबंध में एक स्पष्टीकरण जारी किया गया है। मंत्रालय ने अपने परिपत्र में यह स्पष्ट किया है कि यह छूट, 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष से संबंधित ऐसे वित्तीय विवरणों के विवरणों से संबंधित उन संपरीक्षा रिपोर्टों को लागू होगी, जिन्हें उक्त अधिसूचना की तारीख को या उसके पश्चात् तैयार किया जाता है।

### **उत्तम निगम शासन व्यवहारों का संवर्धन करने के लिए संगोष्ठियों के आयोजन हेतु राष्ट्रीय निगम शासन फाउंडेशन को प्रस्ताव**

समिति ने निगम शासन के विभिन्न पहलुओं, अर्थात् निदेशकों/संकाय या अनुसंधान कार्य के लिए संगोष्ठियों के आयोजन हेतु एनएफसीजी को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिससे उत्तम निगम शासन व्यवहारों का संवर्धन किया जा सके। इस

संबंध में, देश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में पांच कार्यक्रमों के आयोजन की योजना बनाई गई है, जो परिवर्तनशील कारबार परिदृश्य में निगम शासन के विभिन्न पहलुओं के संबंध में परिचर्चा और विचार-विमर्श को सुकर बनाएंगे।

पहले ऐसे कार्यक्रम का आयोजन 30 जून, 2018 को कोलकाता में किया गया था।

### **एमसीए द्वारा यथा विरचित कंपनी अधिनियम, 2013 को सरल और कारगर बनाने संबंधी समिति**

कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन विद्यमान प्ररूपों की संवीक्षा करने के लिए विरचित समिति में भाग लेने और कठिनाईयों को दूर करने तथा कार्यान्वयन को सुगम बनाने के विचार से प्रक्रियाओं को सरल तथा कारगर बनाने हेतु नए प्ररूपों को लागू करने के लिए समिति की बैठकों में भागीदारी की थी।

### **एमसीए द्वारा यथा विरचित कंपनी (निक्षेप स्वीकार करना) नियम, 2014 की समीक्षा करने संबंधी समूह**

समिति ने कंपनी (निक्षेप स्वीकार करना) नियम, 2014 और उससे संबंधित विभिन्न मुद्दों की समीक्षा करने के लिए समूह की बैठकों में भाग लिया था। इस समूह की अंतिम रिपोर्ट को पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया है।

### **कंपनी अधिनियम, 2013 और इंड एस के उपबंधों के बीच असंगतता के संबंध में कार्य करना**

समिति ऐसे मुद्दों के संबंध में कार्य कर रही है, जिनकी पहचान ऐसे मुद्दों के रूप में की गई है जहां कंपनी अधिनियम, 2013 और इंड एस के उपबंधों के बीच असंगतता है और वह उनका समाधान करने का प्रयास कर रही है।

### **एसएफआईओ के अन्वेषण मैनुअल के परिशिष्ट के प्रारूपण के लिए समिति**

कंपनी अधिनियम, 2013 के नए/परिवर्तित उपबंधों के अवलोक में एसएफआईओ के अन्वेषण मैनुअल के परिशिष्ट के प्रारूपण के लिए समिति को सहयोग दिया था।

### **विमानपत्तन आर्थिक रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा बांछा किए गए अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 2 के अनुसार उपयोगी जीवन को विहित करने के लिए विमानपत्तन विनिर्दिष्ट आस्तियों का अध्ययन**

समिति ने भारतीय विमानपत्तन आर्थिक रिपोर्टिंग प्राधिकरण की विमानपत्तन आस्तियों के उपयोगी जीवन और अवमूल्यन दरों के अध्ययन संबंधी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। पणधारियों, अर्थात् विमानपत्तनों से भारतीय विमानपत्तन आर्थिक रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा जारी परामर्श पत्र के संबंध में विभिन्न विमानपत्तन प्राधिकरणों को प्राप्त सुझावों पर आगे और टीका-टिप्पणियां प्रस्तुत की गई हैं।

### **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 131 के अधीन वित्तीय विवरणों के स्वैच्छिक पुनरीक्षण के लिए प्रारूप नियमों को एमसीए को प्रस्तुत किया जाना**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 131 के अधीन वित्तीय विवरणों के स्वैच्छिक पुनरीक्षण के लिए एमसीए के अनुरोध पर तैयार किए गए प्रारूप नियमों को एमसीए को प्रस्तुत किया गया था। इस संबंध में, समिति ने अपना यह मत प्रस्तुत किया है कि वित्तीय विवरणों में पुनरीक्षण केवल आपवादिक परिस्थितियों में ही अनुज्ञात किया जाना चाहिए।

### **सीमित दायित्व भागीदारी के लिए वित्तीय विवरणों का प्ररूप**

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अनुरोध पर समिति ने सीमित दायित्व भागीदारियों के लिए वित्तीय विवरणों का एक प्ररूप प्रस्तुत किया था। यह प्ररूप एलएलपी अधिनियम, नियम और प्ररूपों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार विहित प्ररूप के आधार पर तैयार किया गया था।

### **प्रभाग 2 – इंड एस - कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 के अनुसरण में कंपनियों द्वारा फाइल किए जाने वाले संक्षिप्त वित्तीय विवरणों का प्ररूप (एओसी-3)**

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अनुरोध पर समिति ने ऐसे संक्षिप्त वित्तीय विवरणों के प्रारूप प्ररूप को तैयार और प्रस्तुत किया था, जिन्हें ऐसी कंपनियों द्वारा, जो प्रभाग 2 – इंड एस - कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 का अनुसरण कर रही हैं, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 136(1) के पहले परंतुक के अनुसार फाइल किया जाना अपेक्षित है।

### **असूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूतियों का अभौतिकीकरण करने के लिए प्रस्ताव**

आईसीएआई ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय के इस प्रस्ताव पर अपने सुझाव दिए थे कि असूचीबद्ध कंपनियों के लिए यह आज्ञापक बनाया जाए कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 29(1)(ख) के अनुसार अभौतिकीकृत रूप में अपनी प्रतिभूतियों को जारी करें।

### **कार्यान्वित किए गए सुधारों के संबंध में विश्व बैंक के संप्रेक्षणों के पीछे कारणों को बेहतर रूप से समझने और सुधारों की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए डीआईपीपी को प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना**

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के अनुरोध पर, आईसीएआई ने कार्यान्वित किए गए सुधारों के संबंध में विश्व बैंक के संप्रेक्षणों के पीछे कारणों को बेहतर रूप से समझने और सुधारों की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था।

### **मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) – अभियोजन/मुकदमों के लिए**

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) – अभियोजन/मुकदमों के लिए, तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया था। इस संबंध में, मुकदमों/अभियोजन के लिए प्रारूप एसओपी के संबंध में टिप्पणियों को एमसीए को प्रस्तुत किया गया था।

### **पठन प्रबंध प्रणाली**

पठन प्रबंध प्रणाली को एक सुगम्य मंच के रूप में विकसित किया गया है, जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के लिए संपूर्ण पाठ्यचर्या में अंतर्बलित अवधारणाओं को, पाठ्यचर्या के प्रत्येक अंग में प्रस्तुतिकरणों और मोक परीक्षाओं के रूप में प्रस्तुत करती है। इसकी एक अद्वितीय विशिष्टि यह है कि यह मोडूलर स्तर पर किसी भी व्यक्ति को परीक्षाएं देने में समर्थ बनाता है, जिससे कि वह व्यक्ति अपनी परीक्षा के अंकों में सुधार लाने के लिए पुनः पठन कर सके।

### **कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके नियमों के कार्यान्वयन संबंधी परीक्षण कार्यक्रम**

समिति ने, आईसीएआई के सदस्यों को, कंपनी अधिनियम, 2013 के संबंध में नवीनतम घटनाओं में उसके उपबंधों में परिवर्तनों/संशोधनों से लैस करने तथा उन्हें उनसे अवगत कराने के लिए एक पहल की है, जिसके अधीन देश भर में कंपनी अधिनियम, 2013 से संबंधित अद्यतन जानकारी के संबंध में परस्पर क्रियाशील बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, वेबकास्टों, संगोष्ठियों और सम्मेलनों के रूप में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

### **आ. सीएलसीजीसी का दिवाला और शोधन अक्षमता विधियों संबंधी समूह**

आईसीएआई ने फरवरी, 2017 में, दिवाला और शोधन अक्षमता विधि पर विनिर्दिष्ट ध्यान केंद्रित करने के विचार से निगम विधि और निगम शासन संबंधी समिति के अधीन दिवाला और शोधन अक्षमता विधियों संबंधी समूह का गठन किया था। इस समूह के लिए यह आज्ञापक है कि वह व्यवसाय के इस नए क्षेत्र में वृत्तिक अवसरों के प्रति जागरूकता का सृजन करे। यह समूह आईबीबीआई सीमित दिवाला परीक्षा की तैयारी के लिए और साथ ही दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के संबंध में जागरूकता कार्यक्रमों के संबंध में गहन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। यह समूह संहिता को बेहतर रूप से समझने के लिए सदस्यों की सहायता करने हेतु प्रकाशन भी निकालता है।

### **5.8 प्रत्यक्ष कर समिति (डीटीसी)**

#### **सीबीडीटी को प्रतिवेदन/परस्पर क्रिया**

समिति ने वर्ष के दौरान केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को आईसीएआई के निम्नलिखित वृत्तिक अंतःनिवेशों, अनुरोधों, प्रतिवेदनों आदि को प्रस्तुत किया था :

- आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(38) के अधीन जारी की जाने वाली प्रारूप अधिसूचना।
- धारा 269, धन के उपबंधों के लागू होने के संबंध में स्पष्टीकरण जारी करना।
- चार्टर्ड अकाउंटेंटों पर रिपोर्टों या प्रमाण पत्रों में गलत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए शास्ति अधिरोपित करने वाली धारा 271ज।

- असम और मेघालय के निवासी निर्धारितियों को धारा 139क (3) के अधीन छूट मंजूर करना । उक्त अनुरोध पर सीबीडीटी द्वारा अनुकूल रूप से विचार किया गया था ।
- सीपीसी बंगलुरु से प्राप्त संसूचना/आदेश/सूचना के संबंध में निर्धारितियों के समक्ष आने वाली शिकायतों का समाधान करने ।
- शून्य संव्यवहारों की दशा में, प्ररूप 61क में वितीय संव्यवहारों संबंधी विवरण (एसएफटी) और "एसएफटी प्रारंभिक प्रतिक्रिया" प्रस्तुत करने के संबंध में स्पष्टीकरण जारी करना । उक्त अनुरोध पर सीबीडीटी द्वारा अनुकूल रूप से विचार किया गया था ।
- प्ररूप 61क में वितीय संव्यवहारों संबंधी विवरण (एसएफटी) को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को 31 मई, 2017 से बढ़ाकर 31 जुलाई, 2017 करना । उक्त अनुरोध पर भी सीबीडीटी द्वारा अनुकूल रूप से विचार किया गया था ।
- आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 56 और धारा 50क के प्रयोजनों के लिए कोट न किए गए साम्या शेयरों के मूल्यांकन के संबंध में प्रारूप नियम ।
- भू-संपदा संव्यवहारों के संबंध प्रारूप आईसीडीएस ।
- प्ररूप संख्या 3क – 3घ और 3ख – 3घ की जावा उपयोगिता में सुधार/ उसे अद्यतन करने ।
- प्ररूप संख्या 3क – 3घ और 3ख – 3घ में सुधार करने के प्रतिवेदन के अनुसरण में प्ररूप संख्या 3क – 3घ और 3ख – 3घ की जावा उपयोगिता में सुधार/ उसे अद्यतन किया जाना ।
- सीबीडीटी द्वारा, ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध आईटीआर प्ररूपों की उपयोगिता में किए गए परिवर्तनों को एक समुचित अधिसूचना द्वारा अधिसूचित करने का अनुरोध करते हुए प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन के अनुसरण में प्रतिदाय के मामलों में गैर-निवासियों द्वारा एक विदेशी बैंक खाते के ब्यौरों की वैकल्पिक रिपोर्टिंग के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया था ।
- आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115ख में संशोधन करने और बैंकों /एनबीएफसी द्वारा मूलधन को अधित्यक्त करने की कराधेयता के संबंध में स्पष्टीकरण की ईप्सा की गई थी ।
- आय-कर विवरणियां फाइल करने के लिए तारीख को विस्तारित करने ।
- तारीख 31.07.2017 के कार्यालय जापन (फा.सं. 404/72/93-आईटीसीसी) के लागू होने की तारीख के संबंध में स्पष्टीकरण जारी करने का अनुरोध ।
- इंड एस अनुकूल कंपनियों में एमएटी उपबंधों में एमएटी इंड एस समिति द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से संशोधनों की सिफारिश की गई थी ।
- आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 143(1)(क) के अधीन प्रस्तावित समायोजन ।
- धारा 139(1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (क) के अधीन उल्लिखित निर्धारितियों के लिए आय-कर विवरणियां फाइल करने और निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए कर संपरीक्षा रिपोर्टें फाइल करने की अंतिम तारीख को 30 सितंबर, 2017 से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2017 करने ।
- धारा 44कघ के उपबंधों के संबंध में स्पष्टीकरण जारी करने ।
- प्ररूप संख्या 3घ के खंड 31(ग)(v) के अधीन रिपोर्टिंग अपेक्षा के संबंध में स्पष्टीकरण जारी करने ।
- आय-कर नियम, 1962 में नया नियम 39क अंतःस्थापित करने के लिए प्रारूप अधिसूचना के संबंध में ।
- ई-फाइलिंग पोर्टल पर यथा उपलब्ध आईटीआर प्ररूप 2, 3, 5 और 7 की उपयोगिता में उपयुक्त परिवर्तन करने ।
- निर्धारण वर्ष 2017-18 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए आईटीआर प्ररूप संख्या 2 की जावा/एक्सेल उपयोगिता में सुधार/ उसे अद्यतन करना ।

- आईटीआर प्ररूप 3, 5 और 6 में उपयुक्त परिवर्तन करना तथा इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी करना कि कारबार संबंधी आय और अन्य स्रोतों से आय के संबंध में आय संगणना और प्रकटन मानकों (आईसीडीएस) के प्रभाव को रिपोर्ट किया जाए और साथ ही प्ररूप 3गघ के खंड 13(च) के अधीन रिपोर्टिंग हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराए जाने।
- धारा 139(1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (क) के अधीन उल्लिखित निर्धारितियों के लिए आय-कर विवरणियां फाइल करने और निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए धारा 44कख के अधीन कर संपरीक्षा रिपोर्टें फाइल करने की अंतिम तारीख को 31 अक्तूबर, 2017 से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2017 करने।
- आय-कर नियम, 1962 के नियम 17क और प्ररूप 10क में संशोधनों की प्रारूप अधिसूचना।
- निर्धारण वर्ष (एवाई) 2015-16 और एवाई 2016-17 के लिए आय की विवरणी के संबंध में कार्यवाही किए जाने और उसके परिणामस्वरूप प्रतिदाय जारी करने के लिए निदेश/अनुदेश।
- धारा 199 के प्रयोजनों के लिए स्रोत पर कटौती किए गए कर के लिए प्रत्यय से संबंधित नियम 37खक की व्यावहारिक विवक्षाओं के मुद्दों पर विचार करने।
- "आय संगणनात्मक और प्रकटीकरण मानक (आईसीडीएस)"।
- तृतीय पक्षकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट) की, निर्धारण कार्यवाहियों -2014 की रिपोर्ट संख्या 32 के संबंध में रिपोर्टिंग के मूल्यांकन में निर्दिष्ट मामलों के ब्यौरे उपलब्ध कराए जाने।
- आईटीआर-4 (सुगम) में अंतर्वलित विभिन्न मुद्दों, आईटीआर -2 और आईटीआर -3, 5, 6 और 7 के अंतिम प्रारूप में अंतर्वलित विभिन्न मुद्दों पर विचार किए जाने।
- आईटीआर 3 में धारा 44कघक के मामलों के संबंध में वित्तीय विवरणों के ब्यौरे प्रस्तुत न करने – त्रुटिपूर्ण विवरणी के रूप में धारा 139(9) के अधीन सूचनाओं को जारी किए जाने।
- इंटरनेट सेवाओं को निलंबित किए जाने के कारण रानीगंज और आसनसोल के निर्धारितियों के लिए विलंबित और पुनरीक्षित आय-कर विवरणियों की अंतिम तारीख को विस्तारित करने।
- आय-कर नियम, 1962 के नियम 115 और 115क के लागू होने के संबंध में निर्धारितियों के समक्ष आने वाले मुद्दे (मुद्दों) पर विचार करने।
- उत्तर प्रदेश राज्य में सीआईटी (छूट) की खंडपीठों की संख्या में वृद्धि करने।
- सीबीडीटी के, सीसीआईटी की, सीआईटी (ए) द्वारा जारी किए जाने वाले आदेशों की मानीटरी की शक्ति के संबंध में तारीख 8 मार्च, 2018 के अनुदेश [फा.सं. डीजीआईटी(विज.)/मुख्यालय/ एसआई/अपील2017-18/9959] में संशोधन करने]।
- प्ररूप 3गक / 3गख / 3गघ के संबंध में।
- निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए आईटीआर उपयोगिताओं को जारी करने में तेजी लाने (अभी तक केवल आईटीआर 1 और 4 से संबंधित उपयोगिताओं को जारी किया गया है)।
- निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए कर संपरीक्षा प्ररूपों (3गक, 3गख और 3गघ) और उनकी उपयोगिताओं को जारी किए जाने में शीघ्रता लाने।
- तारीख 24 मई, 2018 की सं. अधिसूचना सं. 23/2018 के संबंध में, जिसके द्वारा नियम 11पक का संशोधन किया गया था और जिसके द्वारा "अकाउंटेंट" पद का लोप किया गया था, जिसके कारण चार्टर्ड अकाउंटेंट, छूट प्राप्त मुक्त नकद प्रवाह पद्धति के अनुसार कोट न किए गए साम्या शेयरों के उचित बाजार मूल्य को अवधारित करने के लिए पात्र नहीं रहे थे।
- आईसीएमएआई के तारीख 23.05.2018 के पत्र संख्या जी:142:05:2018 के प्रतिनिर्देश से आईसीएआई की चिंताओं को भारतीय लागत लेखा संस्थान द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 288(2) के साथ लगे स्पष्टीकरण में "अकाउंटेंट" पद की परिभाषा का संशोधन किया जाए।

### मंत्रालय/सीबीडीटी के साथ बैठकें

- विभाग के विभिन्न पदधारियों के साथ बैठकें की गई थी, जिसमें सीबीडीटी के अध्यक्ष, संयुक्त सचिव (टीपीएल-2) भी सम्मिलित थे।
- आईटीआर प्ररूप (निर्धारण वर्ष 2018-19) पुनर्विलोकन समिति की बैठक और निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए अधिसूचित किए जाने वाले आईटीआर प्ररूपों के संबंध में सुझाव प्रस्तुत किए गए थे।
- तारीख 26.02.2018 को आईटीआर प्ररूप (निर्धारण वर्ष 2018-19) पुनर्विलोकन समिति की तीसरी बैठक।
- श्री हरीश कुमार, अध्यक्ष डीजीआईटी (प्रणाली) के साथ बैठकें।

### संघीय बजट से संबंधित क्रियाकलाप

- बजट-पूर्व ज्ञापन, 2018 का प्रस्तुत किया जाना।
- 1 फरवरी 2018 को बजट अवलोकन कार्यशाला।
- 1 फरवरी 2018 को संघीय बजट 2018 के कर प्रस्तावों के संबंध में लाइव वेबकास्ट।
- 2 फरवरी, 2018 को संघीय बजट 2018 के संबंध में आईसीएआई की सभा।
- बजट-पश्च ज्ञापन, 2018 का प्रस्तुत किया जाना।

### अन्य पहलें

- समिति ने विभिन्न विषयों, जैसे कि प्ररूप 61क में वित्तीय संव्यवहारों का विवरण (एसएफटी), आय संगणना और प्रकटन मानकों का पर्यावलोकन, कर संपरीक्षा रिपोर्ट के विनिर्दिष्ट प्रतिनिर्देश से व्यवसायियों के सक्षमता निर्माण उपाय, वित्त अधिनियम, 2018 द्वारा किए गए प्रमुख संशोधन और इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों में हुए हाल ही के विकासों, ई-अनुपालन – मुद्दे और आगे की योजना, के संबंध में दिल्ली में 6 लाइव वेबकास्टों का आयोजन किया था और अनेक सदस्यों ने इन लाइव वेबकास्टों में भाग लिया था और अपनी जानकारी को अद्यतन बनाया था।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सीबीडीटी से प्राप्त एक पत्र के प्रत्युत्तर में प्रशिक्षु आईआरएस अधिकारियों के लिए एनएडीटी में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम की अंतर्वस्तुओं के संबंध में अंतःनिवेश और टीडीएस तथा टीसीएस अनुपालनों और सफेद धन आपरेशन के प्रसार में अंतर्वलित अन्य मुद्दे।
- "आय संगणना और प्रकटन मानकों संबंधी तकनीकी गाइड" नामक नए प्रकाशन का विमोचन।
- फरीदाबाद और गुरुग्राम के आय-कर विभाग के अधिकारियों के लिए इंड एस और आईसीडीएस के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- नागरिकों के चार्टर 2014 का पुनर्विलोकन – आय-कर निदेशालय से पत्र।
- वित्त मंत्री से यह अनुरोध करते हुए एक पत्र भेजा गया था कि आईसीएआई के प्रतिनिधि को नए प्रत्यक्ष कर विधान के प्रारूपण के लिए गठित कार्यबल में नामनिर्दिष्ट किया जाए।

### संगोष्ठियां/सम्मेलन/कर जागरूकता कार्यक्रम/कार्यशालाएं

डीटीसी ने वर्ष के दौरान 30 संगोष्ठियों/सम्मेलनों और कर जागरूकता कार्यक्रमों/ कार्यशालाओं/व्याख्यान/ बैठकों का आयोजन किया था।

### 5.9 आर्थिक, वाणिज्यिक विधियों और आर्थिक सलाह संबंधी समिति (सीईसीएल एंड ईए)

#### विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों/विनियामकों को प्रतिवेदन

सीईसीएल एंड ईए ने विभिन्न संबद्ध प्राधिकारियों को प्रतिवेदन किए थे। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगम (एशियान) के साथ व्यापार के संबंध में मतों को राज्य सभा सचिवालय को प्रस्तुत किया गया था। एसईजेड/अंतर्राष्ट्रीय



वित्तीय सेवा केंद्रों से व्यवसाय और प्रचालन करने के लिए विदेशी लेखांकन और संपरीक्षा फर्मों को अनुज्ञा देने से संबंधित मामले में और साथ ही सेवाओं में उत्कृष्ट क्षेत्रों के लिए कार्ययोजना संबंधी मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रारूप टिप्पण के संबंध में एमसीए को अंतःनिवेश प्रस्तुत किए गए थे। चीन द्वारा, लेखांकन और बहियां तैयार करने संबंधी सेवाओं (सीपीसी 862) में बाजार तक पहुंच बनाने की वांछा करने वाले अनुरोध के संबंध में अंतःनिवेश उपलब्ध कराए गए थे और भारत – स्विटजरलैंड संयुक्त आर्थिक आयोग (जेईसी) के 16वें सत्र के संबंध में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को अंतःनिवेश उपलब्ध कराए गए थे। भारत कनाडा सेवा संबंधी बातचीतों के लिए अंतर मंत्रालयीय पणधारी परामर्शों के संबंध में एक ब्यौरेवार अवधारणा पत्र वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है। श्री हरदीप सिंह पुरी, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार, शहरी विकास मंत्रालय) को महाराष्ट्र रेरा द्वारा जारी तारीख 31.05.2017 के परिपत्र सं. 2/2017 से संबंधित मामले और गुजरात रेरा द्वारा जारी तारीख 26.09.2017 के परिपत्र सं. 5/2017 से संबंधित मामले में प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए थे। गुजरात भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (साधारण) विनियम, 2017 के विनियम 3ख के और गुजरात भू-संपदा (विनियमन और विकास) (साधारण) नियम, 2017, दोनों में तुलनात्मक विसंगतियों के मामले में गुजरात रेरा के अध्यक्ष को भी प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए थे।

### **अंतर्राष्ट्रीय मुलाकातें और अंतर्राष्ट्रीय बैठकें/सभाएं**

आईसीएआई के प्रतिनिधियों ने बहराइन में, सीए के पाठ्यक्रम को बहराइन में अंतर्राष्ट्रीय वृत्तिक अर्हता के रूप में मान्यता प्रदान करने से संबंधित विषय पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय क्वालिटी ढांचा (एनक्यूएफ) के पदधारियों से बैठक की थी, जिससे सीए सदस्यों के लिए नियोजन अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अतिरिक्त, बहराइन में विश्व भर में लेखांकन वृत्ति को सुदृढ़ करना – भारत को वैश्विक निवेश गंतव्य बनाना, विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था।

### **अध्ययन समूह**

चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा रेरा के अधीन प्रमाणन और विशेष प्रयोजन संपरीक्षा शीर्षक वाले प्रकाशन को अंतिम रूप देने के लिए रेरा विधि के संबंध में मुद्दों और उनके संभाव्य समाधानों का अध्ययन करने और संकलन करने के लिए रेरा अध्ययन समूह का गठन किया गया था, जिससे इस क्षेत्र में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम/कार्यशाला/वेबकास्टों के आयोजन करने की संभावना/साध्यता के बारे में खोज की जा सके और जहां कहीं आवश्यक समझा जाए, संबद्ध प्राधिकारियों को समुचित संशोधनों/उपांतरणों के संबंध में सुझाव दिया जा सके।

### **कार्यशालाएं/संगोष्ठियां/सम्मेलन/वेबकास्ट**

रेरा और कराधान संबंधी मुद्दों, सीआईटी-ए और आईटीएटी के समक्ष अपील संबंधी कार्यवाहियों, विमुद्रीकृत करेंसी नोटों को जमा किए जाने संबंधी कराधान, एफडीआई सनियम और भू-संपदा में एनआरआई निवेशों तथा एनबीएफसी के लिए अनुपालन प्रबंध, पूर्त न्यासों, हिन्दू उत्तराधिकार, एचयूएफ, एलएलपी, एमएफ, जीएसटी आदि को सम्मिलित करते हुए विभिन्न वाणिज्यिक और आर्थिक विधियों के संबंध में, वेबकास्टों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, सम्मेलनों और संकाय विकास कार्यक्रमों (एफडीपी) के, जिनका आयोजन इस अवधि के दौरान किया गया था, माध्यम से सदस्यों के बीच जागरूकता का सृजन किया गया था।

### **धन शोधन निवारण विधियों संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम**

समिति ने देश भर के विभिन्न अवस्थानों पर धन शोधन निवारण विधियों संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के चार बैचों का सफलतापूर्वक आयोजन किया था। सरकारी विभागों, बैंकों, विधिक भ्रातृसंघ और उद्योग तथा व्यवसाय में लगे सदस्यों से युक्त विशिष्ट संकाय ने इस पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों को संबोधित किया था।

### **माध्यस्थम्, मध्यकता और सुलह संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम**

नवंबर-दिसंबर, 2017 के दौरान मुंबई में माध्यस्थम्, मध्यकता और सुलह संबंधी एक दस दिवसीय पुनरीक्षित प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के अग्रणी बैच का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था। विधिक भ्रातृसंघ, सेवानिवृत्त न्यायधीशों और उद्योग तथा व्यवसाय में लगे सदस्यों से युक्त विशिष्ट संकाय ने इस पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों को संबोधित किया था।

### 5.10 अंकीय लेखांकन और आश्वासन बोर्ड

आईसीएआई ने चार्टर्ड अकाउंटेंटों की सूचना के शासन नियंत्रण सुरक्षा और संपरीक्षा वृत्तिकों के रूप में चार्टर्ड अकाउंटेंटों की भूमिका को सुदृढ़ बनाने के लिए, वर्ष 2018 में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति (सीआईटी) का अंकीय लेखांकन और आश्वासन बोर्ड (डीएएबी) में विलयन कर दिया था। डीएएबी अपने प्रास्थिति पत्रों और लेखांकन तथा आश्वासन के संबंध में प्रौद्योगिकी के प्रभाव से संबंधित मुद्दों पर लेखों के माध्यम से ज्ञान का आधार विकसित कर रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोट संबंधी प्रक्रिया स्वचालन, ब्लॉकचेन, क्लाउड संगणना और लेखांकन तथा आश्वासन संबंधी बड़े डाटा के भावी प्रभावों के संबंध में अवधारणा पत्रों को तैयार करने के लिए अनुसंधान किया जा रहा है। इसका प्रयोजन चार्टर्ड अकाउंटेंटों की उनके ज्ञान में विस्तार करने और आज के अंकीय युग में नए क्षेत्रों में उनके कौशलों को विकसित करने में सहायता करना है। डीएएबी की कार्यसूची में विनियामकों और मानक निर्धारकों के साथ परस्पर बातचीत करना भी सम्मिलित है, जिससे इस बात का निर्धारण किया जा सके कि प्रौद्योगिकी किस प्रकार वित्तीय विनियमों और लेखांकन मानकों की प्रभाविकता और संगतता के बने रहने को प्रभावित कर सकती है।

वर्ष के दौरान, डीएएबी ने विभिन्न प्रकाशनों, जैसे कि डिजिटल कंपीटेन्सी मॉडल (डीसीएमएम) फार प्रोफेशन अकाउंटिंग फर्म – वर्शन 1.0, डिजिटल ईरा और चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन - सर्वे रिपोर्ट, 2017, पूर्व सिग्नल आफ फ्राड इन बैंकिंग सेक्टर आदि निकाले थे। आईसीएआई की सिफारिशों पर एसएएफए बोर्ड ने अपने सदस्य निकायों के बीच आईसीएआई के डीसीएमएम को बढ़ावा देने के लिए अपनाया है। यूरोपीय संघ के लेखाकार और लेखा परीक्षकों (ईएफएए) ने भी यूरोप में अपने प्रचार के लिए अपने अगले संस्करण को विकसित करने के लिए आईसीएआई के साथ सहयोग करने के लिए मॉडल की सराहना की है।

#### सूचना प्रणाली संपरीक्षा संबंधी अर्हता-पञ्च पाठ्यक्रम (डीआईएसए)

बोर्ड ने 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 के दौरान सूचना प्रणाली संपरीक्षा संबंधी अर्हता-पञ्च पाठ्यक्रम (डीआईएसए) के 120 बैचों का संचालन किया था। वर्ष 2001 में इसके प्रारंभ से ही 23000 सदस्यों ने पूरे भारत वर्ष में अभी तक संचालित 11308 बैचों में इस पाठ्यक्रम को अर्हित किया है। बोर्ड सूचना प्रणाली संपरीक्षा में एक अर्हता पञ्च पाठ्यक्रम का संचालन श्रीलंका और नेपाल के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थानों के लिए भी कर रहा है। डीआईएसए को विनियामकों द्वारा मान्यता प्रदान की गई है और आरबीआई द्वारा बैंक संपरीक्षा हेतु पैनलबद्ध किए जाने हेतु ऐसे सदस्यों को वरीयता प्रदान की जाती है, जिन्होंने डीआईएसए अर्हता प्राप्त की है।

आईएसए के संकाय सदस्यों की बैठक का संचालन नियमित अंतरालों पर किया जाता है। इस बैठक के दौरान ऐसे परिवर्तनों की पहचान करने के लिए रणनीति तैयार की जाती है, जिन्हें आईएसए संबंधी अर्हता पञ्च पाठ्यक्रम, आईएसए वृत्तिक प्रशिक्षण के व्यावहारिक पहलूओं, पाठ्यक्रम की पृष्ठभूमि सामग्री और इसी प्रकार के विषयों में आगे और सुधार के लिए कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता है। बोर्ड इस पाठ्यक्रम को और अधिक व्यवहारिक प्रशिक्षण उन्मुख बनाने के लिए आईएसए पृष्ठभूमि सामग्री में सुधार करने हेतु प्रक्रिया कर रहा है।

#### न्यायालयीन लेखांकन और कपट का पता लगाने संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

वर्ष 2009 में, बोर्ड ने उभरते आर्थिक परिदृश्य में न्यायालयीन लेखांकन और कपट का पता लगाने के लिए न्यायालयीन लेखांकन और कपट का पता लगाने संबंधी एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आरंभ किया था और आज की तारीख तक 4000 सदस्यों ने इस प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को अर्हित किया है।

बोर्ड ने 19-25 फरवरी, 2018 के दौरान पुणे में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन निगम लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए न्यायालयीन लेखांकन और कपट का पता लगाने संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का संचालन किया था और साथ ही 18-24 जून, 2018 के दौरान इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए न्यायालयीन लेखांकन और कपट का पता लगाने संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का संचालन किया था।

#### न्यायालयीन प्रयोगशाला (आईसीएआई की डाटा विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला)

डीएएबी ने, क्रमशः उत्कृष्टता केंद्र, हैदराबाद, आईसीएआई भवन, कानपुर, नोएडा, कोलकाता, चेन्नई और चंडीगढ़ में 6 न्यायालयीन प्रयोगशाला (आईसीएआई की डाटा विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला) का शुभारंभ किया था जहां सदस्यों को

सीएएटी उपकरणों के संबंध में व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। आज की तारीख तक समिति ने इन डीए प्रयोगशालाओं में 15 बैचों का संचालन किया है।

### **कपट और न्यायालयीन संबंधी वार्षिक सम्मलेन, प्रशिक्षण कार्यक्रम, संगोष्ठियां, कार्यशालाएं, शिखर सम्मेलन, वेबीनार आदि**

डीएएबी ने कपट और न्यायालयीन, न्यायालयीन संपरीक्षा, कपट का समय पर पता लगाने और बैंककारी कर्मचारियों के लिए न्यायालयीन अन्वेषण, जीएसटी में सूचना प्रौद्योगिकी, डाटा विश्लेषण उपकरण, वृहत् डाटा विश्लेषण और आश्वासन सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, प्रशिक्षण, डीआईएसए निर्धारण परीक्षण के लिए डीआईएसए पुनश्चर्या वेबकास्ट, अंकीकरण और वित्तीय नेतृत्व आदि के संबंध में अहमदाबाद, गुजरात, दिल्ली, लुधियाना, आगरा, भिलाई, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गुवाहाटी, इंदौर, एर्नाकुलम, रांची, सूरत, भुवनेश्वर, नोएडा, शिवाकाशी, उदयपुर और देहरादून में विभिन्न कार्यक्रमों, उदाहरणार्थ सम्मेलनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों आदि का आयोजन किया है, जिनमें 500 से 600 व्यक्तियों ने, जो उद्योग, वृत्ति और अन्य क्षेत्रों से संबंध रखते थे, भाग लिया था।

### **ज्ञान प्रबंध संबंधी वीडियो**

डीएएबी ने चार ज्ञान प्रबंधी संबंधी वीडियो को जारी किया है – अनलॉकिंग द पावर आफ डेटा एनालिटिक्स फार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टेक्नालोजी ट्रांसफार्मिंग आडिट, चेलेंजिस आफ ए सीएफओ इन ए डिजिटल ऐज और रिइन्वेन्टिंग बिजनेस इन द डिजिटल ऐज।

### **5.11 नैतिक मानक बोर्ड**

आईसीएआई की परिषद् ने, सदस्यों के लिए नैतिक मानकों को स्थापित करने और दिशानिर्देश जारी करने के लिए दिसंबर, 1975 में नैतिक मानक समिति (जो अब नैतिक मानक बोर्ड के रूप में ज्ञात है) का गठन किया था।

बोर्ड का मिशन, उत्कृष्टता, स्वतंत्रता, सत्यनिष्ठा के दीर्घकालिक नैतिक आदर्शों को अक्षुण्ण रखते हुए और साथ ही सदस्यों के सम्मान और हितों की संरक्षा करने के लिए तथा सदस्यों हेतु एक क्रियाशील और समकालीन नैतिक संहिता और नैतिक व्यवहार को तैयार करने के प्रति कार्य करना है।

### **क्रियाकलाप/पहलें**

ईएसबी ने विभिन्न प्रकाशन, जैसे कि नैतिक संहिता, नैतिक मुद्दों संबंधी बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न और संपरीक्षकों की स्वतंत्रता संबंधी मार्गदर्शक टिप्पण को निकाला था। यह सदस्यों को उनके दैनिक कार्यों के दौरान उनके समक्ष आने वाले वृत्तिक अंतरद्वंद्वों के संबंध में सलाह देता है। सदस्य नैतिक सहायता पटल, ई-सहायता और ई-मेल तथा पत्रों के माध्यम से बोर्ड तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। ईएसबी [www.icai.org](http://www.icai.org) पर भी विद्यमान है और साथ ही उसका अपना स्वतंत्र पोर्टल, अर्थात् [www.esb.icai.org](http://www.esb.icai.org) भी है।

बोर्ड ने जनवरी, 2017 में, परिषद् के समक्ष अकाउंटेंटों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नैतिक मानक बोर्ड (आईईएसबीए), 2016 पर आधारित आईसीएआई की नैतिक संहिता के पुनरीक्षण संबंधी अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी। तथापि, इसी दौरान आईईएसबीए ने अब अपनी नैतिक संहिता के 2018 संस्करण को जारी कर दिया है, जिसमें 2016 की संहिता की तुलना में व्यापक संरचनात्मक और सारवान परिवर्तन किए गए हैं। तदनुसार, परिषद् ने नैतिक संहिता के पुनरीक्षण के मुद्दों को वापस नैतिक बोर्ड के पास भेजा है, जिससे कि वह 2018 के आईईएसबीए संहिता के अनुसार आईसीएआई की नैतिक संहिता का पुनरीक्षण करे और तदनुसार आईईएसबीए की नैतिक संहिता, 2018 के संस्करण के अनुसार नैतिक संहिता के पुनरीक्षण के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे।

जीएसटी से संबंधित बहुधा पूछे जाने वाले मुद्दों के संबंध में 15 नवंबर, 2017 को एक उद्घोषणा जारी की गई थी।

### **कुछ महत्वपूर्ण विनिश्चय/स्पष्टीकरण**

कोई व्यवसायरत सदस्य किसी न्यास के अध्यक्ष या सचिव का पद स्वीकार कर सकता है, परंतु उक्त भूमिका में किसी अन्य कारबार या व्यवसाय में भागीदारी अंतर्वलित न हो। व्यवसायरत सदस्य को व्यक्तियों के किसी संगम का भाग होने की अनुमति नहीं है चाहे उसमें अन्य वृत्तिक सम्मिलित हों अथवा नहीं, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम,

1949 के उपबंधों के अनुसार केवल फर्मों और एलएलपी, व्यवसाय की इन दो पद्धतियों को ही व्यक्तिगत हैसियत व्यवसाय के अलावा अनुमति प्राप्त है।

व्यवसायरत कोई सदस्य किसी ई-पत्रिका में अवैतनिक संपादक का पद ग्रहण कर सकता है, परंतु सदस्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि वह किसी भी रीति में “अन्य कारबार/व्यवसाय” के वर्ग में नहीं आता है।

किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट और किसी कंपनी सचिव के लिए यह अनुज्ञात नहीं है कि वह एकसमान विजिटिंग कार्ड रखे, जिसके दोनों ओर उसके ब्यौरे मुद्रित हों।

व्यवसाय में लगा कोई सदस्य साम्या अनुसंधान सलाहकार बन सकेगा, किंतु वह कोई खुदरा रिपोर्ट प्रकाशित नहीं कर सकता क्योंकि यह अन्य कारबार या व्यवसाय के अंतर्गत आएगा।

व्यवसाय में लगा कोई सदस्य किसी कंपनी, किसी प्रबंध परामर्श कंपनी, जो आईसीएआई के साथ रजिस्ट्रीकृत है, में पूर्णकालिक निदेशक या कर्मचारी का पद धारण कर सकता है। उस दशा में, जहां वह ऐसी किसी कंपनी से भिन्न कोई निदेशक बनने का इच्छुक है, वहां वह उसके लिए परिषद् से पूर्व और विनिर्दिष्ट अनुमति प्राप्त करेगा (जिसमें उसके पास अधिप्रमाणन के अधिकार नहीं होंगे)।

व्यवसाय में लगा ऐसा कोई सदस्य, जो किसी कंपनी या किसी फर्म में, जहां वह भागीदार है, गैर-कार्यपालक निदेशक है, वहां उसे उस कंपनी, जो मूल कंपनी का संयुक्त उद्यम है, के कानूनी संपरीक्षक के रूप में नियुक्ति स्वीकार नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह उसकी स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा।

सेवा में लगा कोई सदस्य किसी कियोस्क के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध करा सकेगा, यदि उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अधीन अनुमति प्राप्त व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंट के वृत्तिक क्रियाकलापों के रूप में हैं।

व्यवसाय में लगे किसी सदस्य को यह अनुमति नहीं है कि वह उसके स्वामित्व वाले किसी डोमेन नाम का विक्रय करे, जिससे वह स्वामित्व का अर्जन कर सके, क्योंकि यह “अन्य कारबार/व्यवसाय” के वर्ग में आता है।

सेवा में लगा कोई सदस्य, उसके अपने नाम पर ई-विवरणी रजिस्ट्रीकरण प्राप्त कर सकता है, यदि वह उसके नियोजन से संबंधित प्रतिबद्धता के विरोध में नहीं है। तथापि, यदि सदस्य व्यवसाय प्रमाणपत्र को धारण नहीं करता है तो वह विवरणी को प्रमाणित नहीं कर सकता।

आईपी (दिवाला वृत्तिक) के रूप में पैनलबद्ध कोई सदस्य अपने विजिटिंग कार्ड, पत्र शीर्ष और अन्य संसुचनाओं में “दिवाला वृत्तिक” डिग्री को लिख सकता है, क्योंकि यह शीर्ष केंद्रीय सरकार द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की पहली अनुसूची के भाग 1 के खंड (7) के निबंधनानुसार मान्यताप्राप्त शीर्षक है। अन्य सभी नामकरण या पदनाम, जिनके अंतर्गत किसी आईपीए की सदस्यता भी है, अनुज्ञात नहीं है।

भारत से बाहर किसी अन्य लेखांकन निकाय से लेखांकन डिग्री धारण करने वाला कोई सदस्य भारत से बाहर गैर-संपरीक्षा व्यवसाय में नियोजित हो सकता है। तथापि, वह इस तथ्य का उल्लेख नहीं कर सकता कि वह ऐसी डिग्री को धारण करता है चाहे वह डिग्री “सीए” के अतिरिक्त हो अथवा उसके प्रतिस्थापन में हो, सिवाए उस दशा में, जहां उक्त डिग्री को परिषद् द्वारा मान्यता प्रदान की गई है।

दो या अधिक सदस्यों के लिए अनुज्ञात है कि वे जीएसटी से संबंधित अपने ग्राहकों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करें और उसके लिए ग्राहकों से एकत्रित फीस का अंशभाजन करें।

चार्टर्ड अकाउंटेंटों की किसी फर्म के लिए यह अनुज्ञात नहीं है कि वह किसी सम्मेलन को प्रायोजित करें। तथापि, व्यवसाय में लगा कोई व्यक्तिगत सदस्य ऐसे किसी सम्मेलन का ज्ञान भागीदार हो सकता है।

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की पहली अनुसूची के भाग 1 के खंड (6) और खंड (7) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए किसी फर्म की वेबसाइट पत्र शीर्ष या विजिटिंग कार्ड में किसी कैच वर्ड/कैच फ्रेज का उल्लेख करना अनुज्ञात नहीं है।

व्यवसाय में लगा कोई सदस्य किसी विदेशी कंपनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है, परंतु वह उक्त कंपनी का संपरीक्षक न हो और इस संबंध में हित का कोई अन्य विरोध न हो।

व्यवसाय में लगे किसी ऐसे सदस्य के लिए, जो किसी कंपनी में निदेशक सिम्पलीसीटर है, यह अनुज्ञात नहीं है कि वह कंपनी के आरओसी प्ररूपों पर हस्ताक्षर करे क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से भूमिकाओं का विरोध होगा।

व्यवसाय में लगे किसी सदस्य के लिए यह अनुज्ञात नहीं होगा कि वह अपने नए व्यवसाय के संबंध में लोगों को जागरूक बनाने के लिए वाट्सअप मैसेज भेजे और उनमें उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं का उल्लेख करे।

## 5.12 विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी)

### विशेषज्ञ राय

किसी अस्तित्व के वित्तीय विवरण उसके वित्तीय स्वास्थ्य के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इन विवरणों को, उसकी ऐसी दैनिक बहियों के आधार पर संकलित किया जाता है, जो कारबार में आने वाली और उससे जाने वाली निधियों को दर्शित करती हैं। किसी कारबार के लिए, सटीक वित्तीय विवरणों की महत्ता को निम्न रूप से आकलित नहीं किया जा सकता है। वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रक्रिया में वृत्तिकों के सामने प्रायः विशिष्ट परिस्थितियां आती हैं जहां लेखांकन सिद्धांतों का कार्यान्वयन उच्च स्तर की विशेषज्ञता के साथ उनके निर्वचन की अपेक्षा करता है, विशेष रूप से उच्च स्तर के सिद्धांतों पर आधारित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के कार्यान्वयन से संबंधित परिस्थितियों से सामना करने के लिए। इन परिस्थितियों से जुझने के लिए, संस्थान की परिषद् ने, संस्थान के सदस्यों की लेखांकन और/या संपरीक्षा सिद्धांतों और संबद्ध विषयों से संबंधित व्यापक मुद्दों पर शंकाओं का उत्तर देने के लिए वर्ष 1975 में विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन किया था। तथापि, समिति ऐसी शंकाओं का प्रत्युत्तर नहीं देती है, जिसमें विभिन्न अधिनियमितियों का केवल विधिक निर्वचन ही अंतर्बलित है। यह समिति ऐसी शंकाओं का भी उत्तर नहीं देती है, जो ऐसे किसी मामले से संबंधित हैं, जो संस्थान की अनुशासन समिति, विधि के किसी न्यायालय, आय-कर प्राधिकारियों या सरकार के किसी अन्य उपयुक्त विभाग के समक्ष लंबित हैं। समिति, सलाहकार सेवा नियमों, जिन्हें कालिक रूप से पुनरीक्षित किया गया है, के अनुसार रायों के लिए सदस्यों से प्रभारित की जाने वाली फीस के संबंध में शंकाओं का उत्तर उपलब्ध कराती है। उक्त नियम आईसीएआई की वेबसाइट पर हाइपर लिंक [[http://www.icai.org/new\\_category.html?c\\_id=142](http://www.icai.org/new_category.html?c_id=142)] के अधीन उपलब्ध है या उन्हें नई दिल्ली स्थित संस्थान के प्रधान कार्यालय से अभिप्राप्त किया जा सकता है।

समयानुसार, ईएसी की भूमिका को, उसके द्वारा प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर उद्यमों, उद्योग और व्यवसाय में लगे सदस्यों और साथ ही विनियामक और शासकीय प्राधिकारियों, जैसे कि भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक एमसीए आदि द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर उसकी स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ रायों के लिए भलीभांति मान्यताप्राप्त है। विशेषज्ञ सलाहकार समिति द्वारा जारी की गई राय, शंकाओं के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों, सुसंगत विधिक स्थिति और लेखांकन/संपरीक्षा मानकों, किसी विशिष्ट राय को समिति द्वारा अंतिम रूप दिए जाने की तारीख को यथा लागू संस्थान के मार्गदर्शक टिप्पणों और अन्य उद्घोषणाओं पर आधारित होती हैं। राय को अंतिम रूप दिए जाने की तारीख को प्रत्येक राय के साथ उपदर्शित किया जाता है। अतः, राय को पश्चातवर्ती घटनाओं और/या लागू विधिक स्थिति और लेखांकन/संपरीक्षा सिद्धांतों में संशोधनों के अवलोक में पढ़ा और लागू किया जाना चाहिए।

विनिर्दिष्ट अवधि, अर्थात् 1 अप्रैल, 2017 से 30 जून, 2018 के दौरान, समिति ने संस्थान के सदस्यों से प्राप्त प्रश्नों पर 39 रायों को और विनियामकों/शासकीय प्राधिकारियों से प्राप्त विभिन्न लेखांकन संबंधी मुद्दों पर 5 रायों को अंतिम रूप दिया था।

समिति द्वारा जारी सभी रायों को राय सारसंग्रह में भी प्रकाशित किया जाता है। अब तक सारसंग्रह की 35 जिल्दों को विक्रय हेतु जारी किया जा चुका है। सभी रायों के सारसंग्रह की सभी 35 जिल्दों में अंतर्विष्ट लगभग 1400 रायों को सम्मिलित करने वाली एक सीडी को, जिसमें वांछित विषय (विषयों) के संबंध में रायों का पता लगाने और/या किसी विशिष्ट अवधि के दौरान जारी की गई रायों को खोजने के लिए आधुनिक और प्रयोक्ता अनुकूल लक्षण सम्मिलित किए गए हैं, भी जारी किया गया है, जो रायों के सारसंग्रह की जिल्द 35 के साथ उपलब्ध है।

समिति द्वारा अंतिम रूप प्रदान की गई कुछ राय, जिनमें साधारण वृत्तिक हित अंतर्बलित होता है, आईसीएआई के जर्नल 'द चार्टर्ड अकाउंटेंट' के प्रत्येक अंक में प्रकाशित की जाती हैं। समिति की हाल ही की राय को संस्थान की वेबसाइट पर समिति के ज्ञान आदान-प्रदान संबंधी पृष्ठ पर भी रखा जाता है।

### 5.13 वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन बोर्ड (एफआरआरबी)

आईसीएआई, वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहारों में सुधार लाने के अपने प्रयासों के भागरूप में एफआरआरबी के माध्यम से विभिन्न उद्यमों के साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों और उन पर संपरीक्षकों की रिपोर्ट का पुनर्विलोकन करता है। एफआरआरबी का उद्देश्य उत्तम वित्तीय रिपोर्टिंग की परिस्थितियों को बनाए रखना और साथ ही वित्तीय रिपोर्टिंग और उत्तम शासन में पारदर्शिता का संवर्धन करना भी है, जो संपरीक्षित वित्तीय विवरणों में निवेशकों के विश्वास के संवर्धन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बोर्ड विभिन्न विनियामकों, अर्थात् भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की अर्हित संपरीक्षा रिपोर्ट पुनर्विलोकन समिति (क्यूएआरसी) का भी सूचीबद्ध उद्यमों की महत्वपूर्ण संपरीक्षा अर्हताओं के पुनर्विलोकन में और भारत निर्वाचन आयोग की राजनीतिक दलों के वार्षिक संपरीक्षित लेखाओं के पुनर्विलोकन में सहायता करता है और साथ ही समय-समय पर विनियामकों द्वारा उसे विनिर्दिष्ट अन्य मामलों का भी पुनर्विलोकन करता है।

#### किए गए पुनर्विलोकन (स्व:विवेक से या विशेष मामले के रूप में चुने गए मामलों का पुनर्विलोकन)

इस अवधि के दौरान, एफआरआरबी ने स्व:विवेक के अनुसार या विशेष रूप से चुने गए 90 मामलों का पुनर्विलोकन पूरा किया है। इनमें ऐसे उद्यमों के वित्तीय विवरणों का पुनर्विलोकन सम्मिलित है, जिनकी एमसीए द्वारा शैल कंपनियों के रूप में पहचान की गई थी और उनमें विभिन्न राजनीतिक दल भी सम्मिलित हैं, जिनका पुनर्विलोकन बोर्ड द्वारा सक्रिय रूप से किया गया था।

#### समाज के प्रति योगदान – राष्ट्र के लिए प्रतिबद्धता

एफआरआरबी भारत में विद्यमान वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी व्यवहारों में सुधार करने के लिए एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। विनियामक, उसके द्वारा विभिन्न समनुदेशनों को पूरा करने के अनुरोध के साथ उससे संपर्क कर रहे हैं। राष्ट्र निर्माण के भागीदार के रूप में एफआरआरबी द्वारा निष्पादित महत्वपूर्ण समनुदेशन निम्नानुसार हैं :

- भारत निर्वाचन आयोग ने, विभिन्न राजनैतिक दलों के वार्षिक संपरीक्षित लेखाओं के पुनर्विलोकन में एफआरआरबी की भूमिका की सराहना की थी और साथ ही पूर्व वर्षों में राजनैतिक दलों के संपरीक्षकों के लिए कार्यशाला का आयोजन करने के लिए भी उसकी अनुशंसा की थी। उसने एफआरआरबी से पुनः यह अनुरोध किया है कि वह कम से कम छह ऐसे राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के वार्षिक संपरीक्षित लेखाओं का पुनर्विलोकन करे, जो मान्यताप्राप्त दल हैं और जिनकी आय/व्यय 10 करोड़ रुपए से अधिक है। तदनुसार, एफआरआरबी ने राजनैतिक दलों के 21 वार्षिक संपरीक्षित लेखाओं (वर्ष 2013-14 और वर्ष 2014-15 के लिए) का पुनर्विलोकन किया था और उसने इस अवधि के दौरान ऐसे सभी मामलों पर विचार किया था।

भारत निर्वाचन आयोग ने आईसीएआई से यह अनुरोध किया था कि वह वित्तीय वर्ष 2016-17 से संबंधित विभिन्न राजनैतिक दलों के वार्षिक संपरीक्षित लेखाओं का पुनर्विलोकन करे। तदनुसार, एफआरआरबी ने ऐसे विभिन्न राजनैतिक दलों के, जिनकी आय/व्यय 10 करोड़ रुपए से अधिक थी, 8 वार्षिक संपरीक्षित लेखाओं का पुनर्विलोकन किया है।

- विनियामकों का समर्थन करने और साथ ही विनियामकों और सदस्यों के बीच की दूरी को समाप्त करने के अपने प्रयास के भाग रूप में एफआरआरबी निरंतर ऐसे मामलों का पुनर्विलोकन कर रहा है, जो उसे एमसीए, सेबी, ईसीआई और अन्य विनियामकों से प्रतिनिर्दिष्ट किए जा रहे हैं।

#### शैल कंपनी पुनर्विलोकन समूह के उद्देश्य और विस्तार क्षेत्र

बृहत् लोक हित को ध्यान में रखते हुए और एक स्व:विवेकानुसार किए जाने वाले एक सक्रिय उपाय के रूप में, परिषद् ने, संस्थान के वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन बोर्ड (एफआरआरबी) के अधीन शैल कंपनी पुनर्विलोकन समूह (एससीआरजी) का गठन किया है। एससीआरजी, विनियामक/शासकीय निकायों, जैसे कि भारत सरकार का 'शैल कंपनी संबंधी कार्यबल' से प्राप्त प्रतिनिर्देशों पर शैल कंपनियों के पुनर्विलोकन का कार्य करेगा। एससीआरजी शैल कंपनियों का पुनर्विलोकन करेगा और निम्नलिखित का यथासंभव रूप से अवधारण करने के लिए शैल कंपनियों के साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों और उन पर संपरीक्षक की रिपोर्ट का पुनर्विलोकन करेगा तथा ब्यौरवार पुनर्विलोकन के लिए शैल कंपनियों को एफआरआरबी को निर्दिष्ट करेगा:

- क) वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उनके प्रस्तुतिकरण में साधारण रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का अनुपालन;
- ख) विनियामक निकायों और उद्यम से सुसंगत कानूनों और नियमों तथा विनियमों द्वारा विहित प्रकटन संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन ; और
- ग) संपरीक्षक की रिपोर्टिंग संबंधी बाध्यताओं का अनुपालन ।

एफआरआरबी सभी पणधारियों विशेष रूप से विनियामक निकायों के पूर्ण समाधानप्रद रूप में प्रभावी रूप से तथा स्वतंत्रता से कार्यकरण कर रहा है। इसकी सेवाओं की सेबी, भारत निर्वाचन आयोग आदि द्वारा अनुशंसा की गई है और वह उत्कृष्टता, स्वतंत्रता और अखंडता की खोज में अपनी यात्रा को जारी रखे हुए हैं।

### **‘वित्तीय रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के अनुपालन संबंधी एक अध्ययन’ की तीसरी जिल्द**

‘वित्तीय रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के अनुपालन संबंधी एक अध्ययन’ की तीसरी जिल्द का विमोचन वार्षिक दिवस, 2018 के समारोह के दौरान किया गया था, जिससे वित्तीय विवरणों को तैयार करने वालों और संपरीक्षकों के ज्ञान में अभिवृद्धि की जा सके। इसमें लागू लेखांकन/संपरीक्षा मानकों और मार्गदर्शक टिप्पणों और साथ ही अन्य सुसंगत विधियों और कानूनों के संदर्भ में एफआरआरबी के आवश्यक संप्रेक्षण अंतर्विष्ट हैं।

### **सदस्यों को सशक्त करना और सक्षमता निर्माण**

- 21-22 नवंबर, 2017 के दौरान उत्कृष्टता केंद्र, हैदराबाद में एफआरआरबी के साथ पैनलबद्ध तकनीकी पुनर्विलोककों (टीआर) तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन समूहों (एफआरआरजी) का मार्गदर्शन करने और वित्तीय विवरणों का पुनर्विलोकन करने के उनके कौशल में अभिवृद्धि करने और पुनर्विलोकन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एफआरआरबी के साथ सीधे परस्पर क्रिया करने के उद्देश्य से एक 2 दिवसीय आवासीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था।
- सदस्यों की जानकारी में अभिवृद्धि करने और साथ ही उन्हें वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे में हुए परिवर्तनों से अवगत कराने के लिए त्रिवेन्द्रम में एक 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था और एफआरआरबी द्वारा 12 मई, 2018 को ‘वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहार और आज की परिवर्तनशील परिस्थितियों में संपरीक्षक से प्रत्याशा’ विषय पर एक जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था।

## **5.14 अप्रत्यक्ष कर समिति (आईडीटीसी)**

### **सरकार को अंतःनिवेश/समर्थन**

आईडीटीसी ने सरकार को निम्नलिखित अंतःनिवेश/सुझाव प्रस्तुत किए हैं :

- सात विभिन्न प्रक्रमों पर जीएसटी विधि के संबंध में व्यापक सुझाव, जिनमें से 135 सुझाव उनके द्वारा स्वीकार किए गए हैं।
- जीएसटी के अधीन गैर-लाभकारी खंड के संबंध में जीएसटी के अधीन राष्ट्रीय गैर-लाभकारी प्राधिकरण के अध्यक्ष के समक्ष सुझाव।
- संघ के माननीय वित्त मंत्री के समक्ष “जीएसटी कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों” के संबंध में प्रस्तुतिकरण, जिनमें से दिए गए अनेक सुझावों को जीएसटी परिषद् द्वारा 6 अगस्त, 2017 को हुई उनकी बैठक में स्वीकार कर लिया गया है।
- जीएसटी परिषद द्वारा सृजित जीएसटी संबंधी सलाहकार समूह के समक्ष “जीएसटी के अधीन महत्वपूर्ण मुद्दों” के संबंध में प्रस्तुतिकरण।
- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के समक्ष भारत में कारबार की सुगमता को सुकर बनाने संबंधी प्रस्तुतिकरण।
- जीएसटी संपरीक्षा रिपोर्ट (प्ररूप 9ग) और विवरण (प्ररूप जीएसटी 9घ)

- विवरणी फाइल करने और प्रत्यय को समर्थ बनाने के संबंध में सरलीकृत उपयोगकर्ता मित्र मॉडल (एसयूएफ), जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि पूर्तिकार द्वारा अपलोड किए गए बीजकों के ब्यौरों के संक्षिप्त विवरण के आधार पर क्रेता को इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञात किया जाए।
- अप्रत्यक्ष करों के संबंध में बजट-पूर्व और पञ्च ज्ञापन, 2018।
- माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) को दिए गए समर्थन : प्राप्त हुए अनुरोधों के आधार पर निम्नलिखित समर्थन प्रदान किए गए थे।

क. माल और सेवा कर नेटवर्क के कार्यालय से प्राप्त अनुरोध के प्रत्युत्तर में जीएसटी वार्षिक विवरणी प्ररूप 9/9क/9ख के संबंध में सरकार को सुझाव।

ख. जीएसटी प्ररूप में इनपुट की तुलना करने संबंधी प्रस्तुतिकरण।

ग. जीएसटीआर 1, जीएसटीआर-2क से विवरणी के परीक्षण के लिए 23 सदस्यों का नामांकन।

घ. जीएसटीएन द्वारा जीएसटी लेखांकन और बिल संबंधी सॉफ्टवेयर के लिए मूल्यांकन करने और प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए गठित की जाने वाली समिति के लिए चार वरिष्ठ विशेषज्ञों का नामांकन।

**सरकार को प्रतिवेदन :** समिति ने सरकार को निम्नलिखित विषयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे :

- जीएसटीआर- 1 को फाइल करने में अंतर्वलित मुद्दे और निर्धारित को संक्रमणकालीन प्रत्यय समर्थ करना।
- ट्रान्स 1 से संबंधित मुद्दों का समाधान करना और उसे फाइल करने की तारीख को विस्तारित करना।
- जीएसटी के अधीन केकेसी प्रत्यय अनुज्ञात करना।
- विक्रेता की गलती के लिए क्रेता को इनपुट कर प्रत्यय से इंकार नहीं किया जाना चाहिए।
- वेबसाइट पर अग्रिम विनिर्णय के निर्णय को रखे जाने के लिए प्रतिवेदन।
- पुनः बीमा छूट से संबंधित मुद्दा।
- जीएसटी की प्रारूपण समिति में आईसीएआई का नामांकन।
- मध्यवर्ती सीए को जीएसटी व्यवसायी के रूप में रजिस्ट्रीकृत करने के लिए अनुज्ञात करने।
- नियम 118, 119 और 120 के अधीन घोषणा प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा को विस्तारित करने।
- जीएसटी विवरणी प्ररूप को फाइल करने की तारीख को विस्तारित करने।

#### **प्रकाशन – एक अनुसंधान पहल**

आईडीटीसी ने जीएसटी/सेवा कर/ सीएसटी/ सीमाशुल्क/ एफटीपी के संबंध में निम्नलिखित प्रकाशन निकाले/उनका पुनरीक्षण किया:

- जीएसटी अधिनियम और नियमों संबंधी पृष्ठभूमि सामग्री – छठा संस्करण – मई, 2018 (तीन बार पुनरीक्षित)
- ई-वे बिल संबंधी ई-प्रकाशन – तीसरा संस्करण – जुलाई, 2018 (नया और दो बार पुनरीक्षित)
- जीएसटी संशोधनों संबंधी ई-हैंडबुक - पहला संस्करण - जून 2018
- जीएसटी संबंधी एफएक्यू और एमसीक्यू – तीसरा संस्करण जनवरी, 2018 (नया और दो बार पुनरीक्षित)
- जीएसटी अधिनियम (अधिनियमों) और नियम (नियमों) के बेयर लॉ – दूसरा संस्करण – जुलाई, 2017 (नया और पुनरीक्षित)
- विनिर्माताओं के लिए सरलीकृत जीएसटी गाइड - दूसरा संस्करण - अगस्त 2017
- जीएसटी सेवा प्रदाताओं संबंधी हैंडबुक - पहला संस्करण - नवंबर 2017
- जीएसटी के अधीन छूट प्राप्त सेवाओं संबंधी पृष्ठभूमि सामग्री – पहला संस्करण जनवरी, 2018



- जीएसटी के अधीन ई-वाणिज्य के कराधान संबंधी अध्ययन पत्र - दूसरा संस्करण - अगस्त 2017
- जीएसटी के अधीन जॉब संकर्म संबंधी ई-हैंडबुक - दूसरा संस्करण - जून 2018
- जीएसटी के अधीन, किस प्रकार रजिस्ट्रीकृत करें, से संबंधित ई-बुक - पहला संस्करण - जुलाई, 2017
- सतत प्रत्यय संबंधी पृष्ठभूमि सामग्री - पहला संस्करण - अक्टूबर 2017
- बैंककारी क्षेत्र में सेवा कर / जीएसटी का अनुपालन - 5 वां संस्करण - अप्रैल 2018
- सीएसटी संबंधी ई-गाइड - एक नया प्रकाशन - पहला संस्करण - नवंबर 2017
- अनुचित समृद्धि संबंधी अध्ययन पत्र - पहला संस्करण - फरवरी 2017
- सीमाशुल्क और एफटीपी संबंधी पृष्ठभूमि सामग्री - दूसरा संस्करण - अप्रैल 2018

### अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियां

**दुबई में वैट :** 1 जनवरी 2018 से संयुक्त अरब अमीरात में वैट को कार्यान्वित किया गया है। वहां मौजूद सदस्यों की सहायता करने के विचार से आईटीसी ने निम्नलिखित पहलें की :

- संयुक्त अरब अमीरात वैट संबंधी बीजीएम का विकास (तीसरा संस्करण)
- संयुक्त अरब अमीरात वैट संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम और विभिन्न सम्मेलनों और कार्यक्रमों का आयोजन
- संयुक्त अरब अमीरात वैट पर लाइव वेबकास्ट की श्रृंखला का आयोजन।
- संयुक्त अरब अमीरात वैट पर ई-लर्निंग की होस्टिंग
- संयुक्त अरब अमीरात वैट संबंधी नए वक्ताओं की पहचान और प्रशिक्षण
- अपनी वेबसाइट पर संयुक्त अरब अमीरात वैट संबंधी विभिन्न लेखों को रखा
- संयुक्त अरब अमीरात वैट पर मानकीकृत पीपीटी को होस्ट करना

### ई-पहलें

- **जीएसटी संबंधी ई-पठन :** समिति ने 7 जुलाई, 2017 को जीएसटी के लगभग सभी विषयों को सम्मिलित करते हुए रिकार्ड किए गए वीडियो सत्रों के माध्यम से जीएसटी संबंधी ई-पठन को आरंभ किया है। इसके लिए 2013 पणधारियों ने ग्राहकी प्राप्त की और इस पहल का फायदा उठाया।

इसके अतिरिक्त ई-पठन के दूसरे पाठ को 23 जनवरी, 2018 को सदस्यों के लिए आरंभ किया गया था। 30 जुलाई, 2018 तक 612 ग्राहकों ने इसके लिए अभिदाय किया है।

- **अप्रत्यक्ष कर संबंधी लाइव वेबकास्ट :** समिति ने जीएसटी के विभिन्न पहलूओं के संबंध में एक राष्ट्र व्यापी आउटरिच कार्यक्रम के रूप में नौ (9) वेबकास्टों का आयोजन किया था।
- **जीएसटी संबंधी संदाय युक्त लाइव वेबकास्ट श्रृंखला :** जीएसटी संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के सभी विषयों को अंतर्विष्ट करने वाली लाइव वेबकास्टों की एक श्रृंखला का आयोजन 15 दिसंबर, 2017 से 14 जनवरी, 2018 के दौरान किया गया था, जिसके लिए 466 दर्शकों ने अभिदाय किया था, जिनमें सदस्य और साधारण जनता भी सम्मिलित थी।
- **जीएसटी के विभिन्न पहलूओं पर लघु वीडियो व्याख्यान :** समिति ने सभी पणधारियों के फायदे के लिए जीएसटी के विभिन्न पहलूओं के संबंध में जिसके अंतर्गत जीएसटी में अंतरण की प्रक्रिया भी है और उसके फायदों से संबंधित 23 लघु वीडियो व्याख्यानों को रिकार्ड किया था।

**जीएसटी संबंधी आईसीएआई ई-न्यूज लैटर :** आईसीएआई अप्रैल, 2017 से अपना जीएसटी संबंधी ई-न्यूज लैटर जारी कर रहा है। जून, 2018 तक उसके 17 अंक निकाले जा चुके हैं।

**जीएसटी संबंधी मानकीकृत पीपीटी :** समिति ने संकाय सदस्यों के मार्गदर्शन के लिए और आईसीएआई द्वारा आयोजित कार्यक्रमों और सत्रों में जीएसटी के सत्र में एकसमानता लाने के लिए और पीपीटी के माध्यम से अपने सदस्यों को जीएसटी को समझने का उपकरण उपलब्ध कराने के लिए जीएसटी संबंधी मानकीकृत पीपीटी को विकसित किया है और उसे अपनी वेबसाइट पर रखा है।

**सरकार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम :** सक्षमता निर्माण में सरकार की सहायता करने और राष्ट्र निर्माण में भागीदारी करने के विचार से समिति ने देश भर में विभिन्न कमीशनरियों में जीएसटी संबंधी 19 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया था।

**व्यापार संगमों के लिए जीएसटी संबंधी परस्पर क्रियाशील कार्यक्रम :** समिति ने राष्ट्र निर्माण में भागीदारी करने की पहल के भागरूप में व्यापार संगमों के लिए जीएसटी संबंधी 21 परस्पर क्रियाशील कार्यक्रमों का आयोजन किया है।

**सेवाकर कमीशनरियों के सहयोग से जीएसटी संबंधी आउटरीच कार्यक्रम :** समिति ने कोलकाता, दिल्ली कमीशनरी (दो बार) और अहमदाबाद कमीशनरी के सहयोग से ज्ञान भागीदार के रूप में जीएसटी संबंधी चार आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन किया है।

**पाठ्यक्रमों, कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों आदि के माध्यम से सदस्यों के लिए जागरूकता कार्यक्रम**

- **जीएसटी संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम :** आईसीएआई ने प्रणालीगत रीति में जीएसटी से संबंधित विशेषीकृत और अद्यतन ज्ञान उपलब्ध कराने के विचार से 28 अप्रैल, 2017 को “माल और सेवाकर (जीएसटी) संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम” के पहले बैच का संचालन किया है। तब से देश भर में इस पाठ्यक्रम के 70 से अधिक बैचों का संचालन किया गया है, जिनमें लगभग 4000 सदस्यों ने भाग लिया है।
- **जीएसटी संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम – वर्चुअल कक्षाओं के माध्यम से :** समिति ने सदस्यों द्वारा जीएसटी संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की भारी मांग को ध्यान में रखते हुए वर्चुअल कक्षाओं के माध्यम से 9 जून, 2017 से 30 जून, 2017 के दौरान जीएसटी संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए वर्चुअल कक्षाओं का संचालन किया है, जिसका आयोजन एक साथ 63 नगरों में किया गया था और इसमें 1768 सदस्यों ने भाग लिया था। इसके अतिरिक्त, पाठ्यक्रम के दूसरे बैच का आयोजन 15 दिसंबर, 2017 से 15 जनवरी, 2018 के दौरान 21 केंद्रों में किया गया था, जिसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया था।
- **कार्यक्रम, संगोष्ठियां और सम्मेलन :** इस अवधि के दौरान समिति द्वारा 110 कार्यक्रमों, संगोष्ठियों और सम्मेलनों तथा कार्यशालाओं आदि का आयोजन किया गया है।

**जीएसटी के संबंध में नए वक्ताओं की पहचान और प्रशिक्षण :** जीएसटी विधि के संबंध में 200 नए वक्ताओं की पहचान की गई है तथा उन्हें प्रशिक्षित किया गया है जिससे पूरे भारत में इस विशेषज्ञ पूल की संकाय सदस्यता संख्या 800 से अधिक हो गई है।

**जीएसटी के सुचारू क्रियान्वयन में राज्य सरकार की सहायता करने के लिए अध्ययन समूह का सृजन :** समिति ने जीएसटी के सुचारू क्रियान्वयन में राज्य सरकार की सहायता करने के लिए राज्य स्तरीय जीएसटी संबंधी उन्नीस (19) अध्ययन समूहों का सृजन किया है।

**विधिक अद्यतन जानकारी सहित अप्रत्यक्ष कर संबंधी अद्यतन जानकारी –** सदस्यों को अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के विचार से, जीएसटी सहित अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अधिसूचनाओं, परिपत्रों और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के संक्षिप्त विवरण को नियमित रूप से आईडीटी नेट पर रजिस्ट्रीकृत सदस्यों के बीच समिति की वेबसाइट [www.idtc.icaai.org](http://www.idtc.icaai.org) के माध्यम से नियमित रूप से परिचालित किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, समिति ने हाल ही में उसकी वेबसाइट पर रजिस्ट्रीकृत सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष करों संबंधी अद्यतन विधिक जानकारी भेजनी आरंभ की है। इस संबंध में अंतिम जानकारी (3 विधिक अद्यतन जानकारियां) 30 जून, 2018 को भेजी गई थी।

### 5.15 आंतरिक संपरीक्षा मानक बोर्ड

बदलते समय को ध्यान में रखते हुए आंतरिक संपरीक्षा मानक बोर्ड ने, जिसे फरवरी, 2004 में आंतरिक संपरीक्षा संबंधी समिति के रूप में स्थापित किया गया था, इस वर्ष अपने निर्देश निबंधनों पर पुनः विचार किया था और निम्नलिखित के द्वारा उन्हें और अधिक सुगम्य बनाया था :

- अपने विस्तार क्षेत्र को भारत से परे विस्तारित करना और उसे विश्वव्यापी बनाना,
- न केवल विद्यमान अपितु उभरते व्यवहारों और मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना,
- विनिर्दिष्ट उद्योगों और साथ ही अन्य क्षेत्रों के लिए अपेक्षित मार्गदर्शन को अभिस्वीकृति प्रदान करना, और
- नए इलैक्ट्रॉनिक रूप में और साथ ही उच्च क्षमता वाले एक डिप्लोमा कार्यक्रम के माध्यम से ज्ञान के प्रसार का औपचारिककरण करना ।

अप्रैल, 2017 से जून, 2018 के दौरान बोर्ड की महत्वपूर्ण पहलों का पर्यावलोकन निम्नानुसार है :

#### चरणबद्ध रीति में आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानकों (एसआईए) को आज्ञापक बनाया जाना

आंतरिक संपरीक्षा को प्रभावी होने के लिए यह आवश्यक है कि उसका संचालन मान्यताप्राप्त मानकों के एक सेट के अनुसार किया जाए । आज की तारीख तक संस्थान ने आंतरिक संपरीक्षकों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्य की विश्वसनीयता, संगतता, स्पष्टता और तुलनात्मकता में सकल वृद्धि करने के लिए आंतरिक संपरीक्षा संबंधी 18 मानकों को जारी किया है । बोर्ड ने एसआईए के पुनरीक्षण की प्रक्रिया आरंभ की है और साथ ही उन्हें चरणबद्ध रीति में कंपनियों के कतिपय वर्ग के लिए आज्ञापक बनाने हेतु भी प्रक्रिया की जा रही है ।

#### “आंतरिक संपरीक्षा” की पुनरीक्षित परिभाषा

बोर्ड ने “आंतरिक संपरीक्षा” की पुनरीक्षित परिभाषा से संबंधित एक उद्भासन प्रारूप जारी किया है, जिसके अंतर्गत एक स्पष्टीकरण भी है, जो प्रस्तावित परिभाषा में प्रयुक्त प्रमुख पदों के बारे में अतिरिक्त स्पष्टता उपलब्ध कराता है । परिषद् द्वारा उसकी मार्च, 2018 में हुई 364वीं बैठक में यथा अनुमोदित आंतरिक संपरीक्षा की पुनरीक्षित परिभाषा को आंतरिक संपरीक्षा को शासित करने वाले पुनरीक्षित ढांचे के भागरूप में सम्मिलित किया गया है ।

#### आंतरिक संपरीक्षा संबंधी ढांचा और मानकों का पुनरीक्षित प्राक्कथन

आंतरिक संपरीक्षा संबंधी ढांचा और मानकों का प्राक्कथन, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् के प्राधिकार के अधीन बोर्ड की उद्घोषणाओं के विस्तार क्षेत्र और प्राधिकार को समझना सुकर बनाता है । परिषद् ने उसकी मार्च, 2018 में हुई 364वीं बैठक में पुनरीक्षित “आंतरिक संपरीक्षा संबंधी ढांचा और मानकों का पुनरीक्षित प्राक्कथन” का अनुमोदन किया था, जब कि उसे प्रभावी करने की तारीख के बारे में अभी विनिश्चय नहीं किया गया है ।

#### आंतरिक संपरीक्षा शासन के लिए पुनरीक्षित ढांचा

इस ढांचे का सकल उद्देश्य, आंतरिक संपरीक्षकों द्वारा किए जाने वाले आंतरिक संपरीक्षा संबंधी समनुदेशनों के संचालन में वृत्तिकतता का संवर्धन करना है और साथ ही यह सुनिश्चित करना भी है कि आंतरिक संपरीक्षा के रूप में अर्हता का एक आधारिक न्यूनतम क्वालिटी मानक सुनिश्चित किया जाए और साथ ही जारी की गई आंतरिक संपरीक्षा रिपोर्ट की विश्वसनीयता का संवर्धन करना भी है । आंतरिक संपरीक्षा जीवन चक्र के सभी क्रियाकलाप, उदाहरणार्थ विस्तार क्षेत्र तय करना और योजना बनाना, साक्ष्य इकट्ठा करना और उसका पुनर्विलोकन करना, क्षेत्र कार्य में परीक्षण, भौतिक संप्रेक्षण, दस्तावेजीकरण, अन्य विशेषज्ञों के कार्य का उपयोग करना, नियंत्रणों और प्रणालियों का मूल्यांकन करना, संसूचना और परिणामों को रिपोर्ट करना, को इस ढांचे में सम्मिलित किया गया है । परिषद् ने उसकी मार्च, 2018 में हुई 364वीं बैठक में पुनरीक्षित “आंतरिक संपरीक्षा के शासन संबंधी पुनरीक्षित ढांचे” का अनुमोदन किया था, जब कि उसे प्रभावी करने की तारीख के बारे में अभी विनिश्चय नहीं किया गया है ।

#### आंतरिक संपरीक्षा के आधारिक सिद्धांत

आंतरिक संपरीक्षा हेतु प्रभावी होने के लिए कतिपय आधारिक सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण और अनिवार्य हैं । ये सिद्धांत आंतरिक संपरीक्षा को शासित करने वाले ढांचे के चार प्रमुख संघटकों में से एक हैं, अर्थात् प्रमुख अवधारणाएं, आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक और मार्गदर्शन । इस दस्तावेज में ऐसे 10 आधारिक सिद्धांत सम्मिलित हैं, जो किसी आंतरिक

संपरीक्षा का संचालन करने के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जिनमें से पांच आंतरिक संपरीक्षक की विश्वसनीयता को स्थापित करते हैं और शेष पांच आंतरिक संपरीक्षा संबंधी क्रियाकलापों के निष्पादन के लिए अनिवार्य कारकों को संक्षिप्त रूप में वर्णित करते हैं।

### आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानकों (एसआईए) के उद्भासन प्रारूप

बोर्ड ने आंतरिक संपरीक्षा संबंधी निम्नलिखित मानकों के उद्भासन प्रारूप जारी किए थे, जो अब अंतिम रूप दिए जाने के प्रक्रम पर हैं :

- **एसआईए, सकल आंतरिक संपरीक्षा योजना का संचालन :** यह मानक आंतरिक संपरीक्षक के, सकल आंतरिक संपरीक्षा संबंधी योजना तैयार करने के उत्तरदायित्व से संबंधित है, जिसे वार्षिक आंतरिक संपरीक्षा (नियोजन योजना) के रूप में भी निर्दिष्ट किया जाता है।
- **एसआईए किसी आंतरिक संपरीक्षा समनुदेशन की योजना तैयार करना :** इसके अंतर्गत दूसरा स्तर आता है अर्थात् अस्तित्व के किसी विशिष्ट भाग के लिए आंतरिक संपरीक्षा समनुदेशन की योजना बनाना।
- **एसआईए, आंतरिक संपरीक्षा साक्ष्य :** यह आंतरिक संपरीक्षा संबंधी उपयुक्त और विश्वसनीय साक्ष्य एकत्रित करने, प्रतिधारित करने और उनके पश्चातवर्ती पुनर्विलोकन की प्रक्रिया के लिए कतिपय प्रमुख अपेक्षाओं को स्पष्ट करता है।
- **एसआईए, आंतरिक संपरीक्षा दस्तावेजीकरण :** यह आंतरिक संपरीक्षा संबंधी पूर्ण और पर्याप्त दस्तावेजीकरण को एकत्रित करने, तैयार करने, प्रतिधारित करने और उनके पश्चातवर्ती पुनर्विलोकन की प्रक्रिया के लिए कतिपय प्रमुख अपेक्षाओं को स्पष्ट करता है।
- **एसआईए, आंतरिक संपरीक्षा कृत्यों का प्रबंध करना :** यह मुख्य आंतरिक संपरीक्षक या ऐसे व्यक्ति के, जिसे आंतरिक संपरीक्षा से संबंधित क्रियाकलापों के सकल कार्यपालन का समन्वय करने और प्रबंध करने का कार्य सौंपा गया है, उत्तरदायित्व से संबंधित है।

### उद्योग – विनिर्दिष्ट आंतरिक संपरीक्षा गाइड

वर्ष 2017-18 के दौरान, बोर्ड ने निम्नलिखित परियोजनाएं आरंभ की हैं :

- **आंतरिक संपरीक्षा – सीमेंट उद्योग संबंधी दिशानिर्देशों का पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण :** बोर्ड ने आंतरिक संपरीक्षा - सीमेंट उद्योग संबंधी दिशानिर्देशों, जिन्हें आईसीएआई की अनुसंधान समिति द्वारा वर्ष 1994 में जारी किया गया था, में ऐसी सभी परिवर्तनों को सम्मिलित करने के लिए, जो सीमेंट उद्योग में हुए हैं और उनसे संबंधित विनियामक परिस्थितियों को भी उसमें समाविष्ट करने और सदस्यों को सीमेंट उद्योग से जुड़ी अद्वितीय संपरीक्षा प्रक्रियाओं के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए पुनरीक्षित करने का विनिश्चय किया गया है।
- **बैंकों में खजाना संबंधी कृत्यों की आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड का पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण :** बोर्ड ने बैंकों में खजाना संबंधी कृत्यों की आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड का पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण करने की परियोजना को आरंभ किया है ताकि बैंकों में खजाना और निवेश प्रबंध से संबंधित आरबीआई द्वारा परिपत्रों और आईसीएआई की उद्घोषणाओं को सम्मिलित किया जा सके।
- **बैंकों में जोखिम आधारित आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड का पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण :** बैंककारी उद्योग में नवीनतम घटनाओं और आरबीआई द्वारा जारी परिपत्रों को ध्यान में रखते हुए आंतरिक संपरीक्षा मानक बोर्ड ने बैंकों में जोखिम आधारित आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड का पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण करने की परियोजना को आरंभ किया है, जिन्हें मूल रूप से नवंबर, 2005 में जारी किया गया था।
- **खुदरा उद्योग में आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड का पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण :** खुदरा उद्योग में हुई घटनाओं तथा उसके विनियामक वातावरण को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने खुदरा उद्योग में आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड का पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण करने की परियोजना को आरंभ किया है, जिन्हें मूल रूप से फरवरी, 2011 में जारी किया गया था।

### बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का ई-पठन

सदस्यों को सुगम पहुंच उपलब्ध कराने के लिए आंतरिक संपरीक्षा मानक बोर्ड ने बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के ई-पठन मॉड्यूलों को विकसित करने की परियोजना को आरंभ किया है, जिसमें समवर्ती संपरीक्षा के व्यावहारिक पहलुओं से संबंधित क्विजों और मामला अध्ययनों को सम्मिलित किया जाएगा।

### बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा संबंधी वर्चुअल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

बोर्ड ने सदस्यों के लिए बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा संबंधी वर्चुअल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का संचालन करने का विनिश्चय किया है।

### यूएसए में आंतरिक संपरीक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

आईसीएआई की ओर से बोर्ड ने सिडनी में 23-26 जुलाई, 2017 के दौरान आयोजित दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया था, जिसके दौरान संस्थान को वृत्ति के बृहत्तर हित में आंतरिक संपरीक्षा के व्यवहार के संबंध में नेटवर्क और सूचना का आदान-प्रदान करने का अवसर प्राप्त हुआ था।

### प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

- **बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम :** बोर्ड सदस्यों को बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा के बारे में गहन जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का संचालन करता है। इस अवधि के दौरान, बोर्ड ने देश के विभिन्न स्थानों पर बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लगभग 45 बैचों का सफलतापूर्वक संचालन किया है और लगभग 1250 सदस्यों ने सफलतापूर्वक इस प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को अर्हित किया है।
- **आंतरिक संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम :** बोर्ड ने आंतरिक संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या संरचना में, उसमें नए विषयों और सूचना प्रौद्योगिकी को पूर्णरूपेण समाविष्ट करते हुए, पूर्णतया सुधार किया है।

इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों को आंतरिक संपरीक्षा के सिद्धांत और अवधारणाओं, विशेष रूप से जोखिम प्रबंध और शासन संबंधी अवधारणाओं से उनके जुड़े होने के संबंध में शिक्षित करना, आंतरिक संपरीक्षा की योजना को तैयार करने और उसका संचालन करने के लिए व्यावहारिक उद्भासन उपलब्ध कराना, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी और विशेषीकृत उपकरणों का उपयोग करते हुए, वर्तमान सर्वोत्तम व्यवहारों को समझना और जोखिमों को कम करने के लिए उन्हें उपयोग करने के मार्गों और कारबार संबंधी चुनौतियों का सामना करने और सदस्यों की, अत्यधिक वृत्तिक रूप से सर्वोत्तम आंतरिक संपरीक्षा संचालन करने के लिए अपेक्षित सभी कौशलों और ज्ञान को अर्जित करने में सहायता करना है, जो न केवल आधारीक आश्वासन उपलब्ध कराते हैं अपितु इन संगठनों से मूर्त मूल्य भी जोड़ने की वांछा करते हैं। परिषद् ने आंतरिक संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की पुनरीक्षित पाठ्यचर्या को हाल ही में अनुमोदित किया है और बोर्ड इस संबंध में मोडेलिटीज को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया कर रहा है। शीघ्र ही उक्त प्रमाणपत्र के बैचों को भारत के महानगरों में आरंभ किए जाने की आशा की जा रही है।

### आंतरिक संपरीक्षा संबंधी जागरूकता के लिए कार्यक्रम, संगोष्ठियां, सम्मेलन और वेबीनार

सदस्यों के बीच ज्ञान के प्रसार के लिए एक मंच उपलब्ध कराने के विचार से बोर्ड ने विभिन्न अवस्थानों, जिनमें मुंबई, नई दिल्ली, जमशेदपुर, नासिक, अहमदाबाद, वसई, औरंगाबाद, बेलगाम, बडौदा, भोपाल और भुवनेश्वर सम्मिलित हैं, में स्थित अपने सदस्यों के फायदे के लिए विभिन्न कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, परस्पर क्रियाशील बैठकों का आयोजन किया है। इस अवधि के दौरान बोर्ड ने आंतरिक संपरीक्षा – प्रभावी नेतृत्व तैयार करने और सक्षमता के माध्यम से कार्यपालन करने और समवर्ती संपरीक्षा को और अधिक प्रभावी और सुसंगत बनाने संबंधी वेबीनारों का भी आयोजन किया है।

## 5.16 अंतरराष्ट्रीय कराधान संबंधी समिति

### सरकार को प्रतिवेदन/उसके साथ परस्पर क्रियाएं

समिति ने विभिन्न मंत्रालयों को प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे, जैसे कि बजट-पूर्व और पश्च ज्ञापन, प्रभावी प्रबंध स्थान संबंधी दिशानिर्देश, आय-कर अधिनियम की धारा 115अ के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए सीबीडीटी द्वारा जारी प्रारूप अधिसूचनाओं के संबंध में सुझाव, अंतरण कीमत निर्धारण दस्तावेजीकरण को बनाए रखने और प्रस्तुत करने के लिए दिशानिर्देश अधिकथित करने वाली प्रारूप अधिसूचना भारत में बैंक खाता धारण न करने वाली विदेशी कंपनियों को सीबीडीटी द्वारा प्रतिदाय जारी करने, धारा 195(3) के अधीन विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की भारतीय शाखा को शून्य टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने में समर्थ बनाने के लिए अनुरोध और सीबीडीटी से यह अनुरोध किया कि वह एक ऐसी प्रक्रिया अधिकथित करें, जहां निर्धारिती को उसका पैन संख्यांक वापस करने की अनुज्ञा दी जाए परंतु उसकी कोई कराधेय आय न हो और साथ ही उस विनिर्दिष्ट पैन संख्यांक के संबंध में कोई मुकदमा भी लंबित न हों और इसी प्रकार के कई अन्य।

### अंतर्राष्ट्रीय कराधान संबंधी सम्मेलन/संगोष्ठियां/कार्यशालाएं/वेबकास्ट

समिति ने, जीएएआर, पीओईएम दिशानिर्देशों, बहुपक्षीय लिखते – भारत की कर संबंधी संधियों पर प्रभाव, सुरक्षित हेबर नियम, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 92ड के अधीन रिपोर्ट – व्यवहारिक मुद्दे और चुनौतियां, संघीय बजट, 2018 और संघीय बजट 2018-19 के कर प्रस्ताव संबंधी विषयों पर वर्ष के दौरान अनेक सम्मेलनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और वेबकास्टों का आयोजन किया था, जिनके द्वारा सदस्यों के ज्ञान और उनकी समझ को अद्यतन बनाया गया था।

**अंतर्राष्ट्रीय कराधान में अर्हता-पश्च डिप्लोमा** – समिति ने अभी तक पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, नई दिल्ली, ठाणे, मुंबई, अहमदाबाद और बंगलौर में अंतर्राष्ट्रीय कराधान में अर्हता-पश्च डिप्लोमा के नौ बैचों का संचालन किया था। लगभग 550 सदस्यों ने इस पाठ्यक्रम को पूरा किया है।

### अन्य पहलें

समिति ने विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कराधान संबंधी ई-न्यूज लैटर के चार संस्करणों को जारी किया था। अंतर्राष्ट्रीय कराधान प्रमाणपत्र कार्यक्रम में रजिस्ट्रीकृत ऐसे व्यक्तियों, जो अंतर्राष्ट्रीय कराधान में डिप्लोमा करना चाहते हैं, के लिए अंतरण स्कीम को आईसीएआई की वेबसाइट पर रखा गया था। इस स्कीम के माध्यम से सदस्यों को ई-पठन के द्वारा अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। समिति ने आईसीएआई के ई-पठन पोर्टल पर दो ई-पठन पाठ्यक्रमों – अंतर्राष्ट्रीय कराधान का पर्यावलोकन और अंतरण कीमत निर्धारण का पर्यावलोकन, को पुनरीक्षित किया था। विभिन्न प्रकाशनों का पुनरीक्षण भी किया गया था और इस सूची में अंतर्राष्ट्रीय कर पाठ्यक्रम में डिप्लोमा की पृष्ठभूमि सामग्री आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 92ड के अधीन रिपोर्ट संबंधी मार्गदर्शक टिप्पण (अंतरण कीमत निर्धारण), प्रवासी कराधान संबंधी तकनीकी गाइड और तकनीकी सेवाओं के लिए स्वामिस्व संबंधी तकनीकी गाइड और फीस।

## 5.17 उद्योग और कारबार में लगे सदस्यों संबंधी समिति

परिषद ने वर्ष 2018-19 में अपनी गैर-स्थायी समिति के रूप में व्यापार और उद्योग (सीपीएबीआई) में व्यावसायिक लेखाकारों की समिति गठित की। सीपीएबीआई के रूप में गठित, समिति को उद्योग और व्यापार में सदस्यों के लिए समिति के रूप में परिषद द्वारा दोबारा नामित किया गया था। समिति (सीएमआईएंडबी) और उद्योग के बीच एक सामान्य मंच के सृजन के लिए व्यष्टिक उद्देश्यों का संगठनात्मक उद्देश्यों के साथ सामंजस्य बिठाने और चार्टर्ड अकाउंटेंट को उसके पारंपरिक क्षेत्रों से परे कंपनी, कारबार और वाणिज्य के कार्यकरण से संबंधित सभी पहलुओं के संबंध में एक ज्ञानवान व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान करने/स्थापित करने के लिए एक प्रभावी मंच का प्रयोजन सिद्ध करती है। यह समिति उद्योग और कारबार में सेवारत सीए और संस्थान के बीच निकट संबंध को प्रोत्साहित करने तथा उसमें अभिवृद्धि करने का कार्य करती है। इस प्रयास का समर्थन करने के लिए, सीएमआईएंडबी विभिन्न ज्ञानवर्धन सम्मेलनों, उद्योग बैठकों, आउटरीच कार्यक्रमों का सदस्यों के फायदे के लिए आयोजन कर रही है। सीएमआईएंडबी के अन्य महत्वपूर्ण क्रियाकलापों में सदस्यों के हित में कैम्पस नियोजन कार्यक्रमों और आईसीएआई जॉब पोर्टल के माध्यम से युवा और अनुभव प्राप्त चार्टर्ड अकाउंटेंटों को नियोजन अवसर उपलब्ध कराना, कारबार और उद्योग चार्टर्ड

अकाउंटेंटों की उदाहरणात्मक उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करने के लिए गौरवशाली आईसीएआई पुरस्कारों का आयोजन करना, वृत्तिक दिलचस्पी के विषयों में साधारण प्रकाशन जारी करना, सीपीई अध्ययन सर्कलों का सृजन करना, ई-न्यूज लैटर का प्रकाशन करना, आदि सम्मिलित है।

**वर्ष 2017-18 के दौरान किए गए प्रमुख क्रियाकलापों को नीचे उपदर्शित किया गया है :**

**कैम्पस नियोजन कार्यक्रम :**

**अगस्त-सितंबर, 2017** - इसका आयोजन 17 केंद्रों में किया गया था, जिसके लिए 6278 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रीकृत किया था, जिनमें से 3937 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया था। इसमें 105 संगठनों ने भाग लिया था और कुल 1066 अभ्यर्थियों को नौकरियों के प्रस्ताव दिए गए थे। घरेलू नौकरी के लिए अधिकतम 20.00 लाख रुपए प्रतिवर्ष के वेतन (कंपनी को लागत) का प्रस्ताव किया गया था।

**फरवरी-मार्च, 2018** में - इसका आयोजन 17 केंद्रों में किया गया था, जिसके लिए 6029 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रीकृत किया था, जिनमें से 5306 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया था। इसमें 130 संगठनों ने भाग लिया था और कुल 1473 अभ्यर्थियों को नौकरियों के प्रस्ताव दिए गए थे। घरेलू नौकरी के लिए अधिकतम 22.30 लाख रुपए प्रतिवर्ष के वेतन (कंपनी को लागत) का प्रस्ताव किया गया था। सीएमआईएंडबी, वर्तमान नियोजन प्रतिशत में सुधार करने के लिए और अधिक कंपनियों को इसमें सम्मिलित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

**आईसीएआई पुरस्कार, 2017 के लिए ज्यूरी की बैठक**

सीएमआईएंडबी ने, आईसीएआई पुरस्कार, 2017 के लिए दो ज्यूरी बैठकों का आयोजन किया था : पहली सीए वी.आर. जाजू, सीएफओ, डी.बी. पावर लिमिटेड की अध्यक्षता के अधीन और दूसरी बैठक 12 जनवरी, 2018 को मुंबई में दो प्रवर्गों, अर्थात् सीए निगम योगदानकर्ता और सीए वृत्तिक उपलब्धिकर्ता, के अधीन पुरस्कृत किए जाने वाले व्यक्तियों के नामों को अंतिम रूप दिए जाने के लिए मुंबई में की गई थी तथा एक अन्य ज्यूरी की बैठक 8 जनवरी, 2018 को मुंबई में श्री अजय पीरामल, अध्यक्ष, पीरामल समूह की अध्यक्षता में की गई थी, जिसके दौरान शेष 6 प्रवर्गों के अधीन पुरस्कृत किए जाने वाले व्यक्तियों के नामों को अंतिम रूप दिया गया था।

**11वां आईसीएआई पुरस्कार 2017**

आईसीएआई पुरस्कार 2017 का आयोजन उद्योग में लगे चार्टर्ड अकाउंटेंटों के ऐसे उदाहरणात्मक कार्य को सम्मान देने के लिए एक वार्षिक आयोजन के रूप में किया जाता है, जो वृत्ति में उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते हैं, अपनी-अपनी कंपनियों के पणधारियों के लिए मूल्य का सृजन करते हैं, जो अन्य सदस्यों के लिए उदाहरणात्मक आदर्श प्रस्तुत करते हैं और जो समाज और सिविल सेवाओं के प्रति उत्कृष्ट योगदान देते हैं।

पुरस्कारों को आठ मुख्य श्रेणियों, अर्थात्, सीए निगम योगदानकर्ता, सीए वृत्तिक उपलब्धिकर्ता, सीए सीएफओ, सीए कारबार लीडर, सीए उद्यमी, सीए आजीवन उपलब्धिकर्ता, सीए के लिए अनुकरणीय योगदानकर्ता और सीए सेवाओं में सीए विशिष्ट योगदानकर्ताओं के अधीन प्रदान किया गया था। उभरते क्षेत्रों को सम्मिलित करने के लिए और अधिक प्रवर्गों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें आजीवन कार्य की उपलब्धि एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है। कुल 61 पुरस्कार प्रदान किए गए थे।

**आयोजित कार्यक्रम**

इस अवधि के दौरान, विभिन्न कार्यक्रमों, जिनके अंतर्गत संगोष्ठियां, लाइव वेबकास्ट, एक दिवसीय कार्यशालाएं, परस्पर क्रियाशील बैठकें, सीएफओ बैठकें आदि भी थे, का आयोजन किया गया था, इन कार्यक्रमों में हाल ही की विधियों, जिसमें जीएसटी पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया था, विलयन और अर्जन, संनिर्माण उद्योग, लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग, स्टार्ट अप तैयार करना आदि जैसे विषय सम्मिलित थे।

**उद्योग में लगे सदस्यों के लिए सात नए सीपीई अध्ययन सर्कल**

समिति ने इस अवधि के दौरान सात नए सीपीई अध्ययन सर्कलों को स्थापित किया था : साइबर सिटी फेस 2, गुरुग्राम, मैकक्वायर ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट का सीपीई अध्ययन सर्कल, उद्योग में लगे सदस्यों के लिए होंडा समूह कंपनियों का ग्रेटर नोएडा स्थित सीपीई अध्ययन सर्कल, जो आईसीएआई के उद्योग में लगे सदस्यों के लिए है, आईओसीएल का सादिक नगर स्थित सीपीई अध्ययन सर्कल, जो आईसीएआई के उद्योग में लगे सदस्यों के लिए है, जेके ग्राम सीपीई

अध्ययन सर्कल, फरीदाबाद सीपीई अध्ययन सर्कल, एलएंडटी एमएचपीएस बॉयलर, डीएक्ससी टेक्नोलॉजी ब्रुकफील्ड सीपीई अध्ययन सर्कल और सुंदरन क्लेटन लिमिटेड का हैडोज़ रोड सीपीई अध्ययन सर्कल।

### **स्टार्ट अप शिखर सम्मेलन और आईडिया नियोजन कार्यक्रम की प्रमुख विशिष्टियां**

समिति ने 29, जून, 2018 को अपने दो वृहत्त आयोजनों स्टार्ट अप शिखर सम्मेलन और आईडिया नियोजन कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया था, जिनमें 400 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया था।

स्टार्ट अप शिखर सम्मेलन, जो एक बहुमुखी आयोजन था, को स्टार्ट अप और निवेशकों के बीच संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन सीए सतीश सेठ, समूह एमडी, रिलायंस एडीए समूह और सीए सुधीर वालिया, सीएफओ सन फार्मा द्वारा किया गया था।

उक्त शिखर सम्मेलन में सदस्यों को शिक्षित करने और विभिन्न संबद्ध मुद्दों के बारे में उन्हें अंतरदृष्टि उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया था:

- सोचने पर मंजूर करने वाली पैनल परिचर्चाएं जैसे सफल संस्थापकों के साथ पैनल परिचर्चा, अगले दस करोड़ उपयोक्ताओं के लिए तैयारी, टॉप एंजेल निवेशकों के साथ पैनल परिचर्चा : जनता में निवेश करने बनाम विचार में निवेश करने और प्रमुख उद्यम पूंजीवादियों के साथ पैनल परिचर्चा : भारत उद्यमशीलता : मापमान सार और संवहनीयता।
- श्री किशोर बियानी के साथ लाइटनिंग टाक और फायर साइड चैट।
- उद्योग और बड़े निगमों से जुड़े अनुभव प्राप्त व्यक्तियों ने शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों को स्टार्ट अप से संबंधित उनके परिप्रेक्ष्य के संबंध में जागरूक बनाया था और उन्हें ऐसे नए और कठिन क्षेत्रों से अवगत कराया था जहां वे योगदान दे सकते हैं।
- शार्क टैंक प्रतिस्पर्धा, जिसका उद्देश्य सुदृढ़ कारबार विचारों के लिए उनके कारबार उद्यम हेतु तुरंत वित्तपोषण सुनिश्चित करने के लिए मंच उपलब्ध कराना था।
- आईडिया नियोजन कार्यक्रम, जहां 100 से अधिक स्टार्ट अप और 50 से अधिक निवेशकों के बीच क्रियाशील सत्रों का आयोजन किया गया था।

### **कैरियर एसेंट कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण**

सीएमआईएंडबी ने 29 जून, 2018 को मुंबई और चेन्नई में तथा 30 जून, 2018 को नई दिल्ली में कैरियर एसेंट कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया था। इस कार्यक्रम ने अनुभव प्राप्त चार्टर्ड अकाउंटेंटों को नियोजन अवसर प्रदान करने के लिए एक ऐसा मंच उपलब्ध कराया था, जहां वे अपने लिए प्रमुख संगठनों में कैरियर संबंधी उन्नति को सुनिश्चित कर सकते थे। यह एक विशेष रूप से तैयार किया गया कैम्पस नियोजन कार्यक्रम था, जो ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए था, जिनके पास तीन वर्ष से अधिक का उद्योग में कार्य करने का अनुभव है। इस कार्यक्रम में 17 संगठनों ने भाग लिया था और 291 रिक्तियों से संबंधित नौकरियों के प्रस्ताव दिए गए थे और इस कार्यक्रम के लिए 1000 से अधिक अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रीकृत किया था।

### **5.18 पियर पुनर्विलोकन बोर्ड (पीआरबी)**

पियर पुनर्विलोकन प्रक्रिया, किसी व्यक्ति के वृत्तिक उत्तरदायित्वों के अनुक्रम में संपरीक्षा और आश्वासन सेवाओं का निर्वहन करते समय गुणवत्ता को सुनिश्चित करने और उसे बनाए रखने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं और रखे गए अभिलेखों की प्रणालीगत मानीटरी के सिद्धांत पर आधारित है। आईसीएआई के पियर पुनर्विलोकन तंत्र का मुख्य उद्देश्य आश्वासन सेवाओं की गुणवत्ता को बनाए रखना और उसमें अभिवृद्धि करना तथा साथ ही सदस्यों को, उनके कार्यपालन और वृत्तिक कार्य की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए तथा विभिन्न कानूनी और अन्य विनियामक अपेक्षाओं का पालन करने के संबंध में मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है। पियर पुनर्विलोकन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संस्थान के सदस्य आश्वासन सेवा समनुदेशनों को पूरा करते समय ; (क) यथालागू तकनीकी, वृत्तिक और नैतिक मानकों, जिसके अंतर्गत उनसे संबंधित अन्य विनियामक अपेक्षाएं भी हैं, का अनुपालन करते हैं और (ख) उनके द्वारा दी जाने वाली आश्वासन सेवाओं की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए दस्तावेजीकरण सहित समुचित प्रणालियां



सुस्थापित हैं। किसी व्यवसायी इकाई के पियर पुनर्विलोकन का संचालन, पियर पुनर्विलोकन के रूप में ज्ञात एक स्वतंत्र मूल्यांकक द्वारा किया जाता है।

बोर्ड का प्रयास पियर पुनर्विलोकनों के प्रभावी कार्यपालन के साथ न केवल व्यवसायी इकाईयों को, समाज को उनके द्वारा साधारण रूप से दी जाने वाली उनकी सेवाओं की गुणवत्ता में सतत सुधार लाने के लिए प्रोत्साहित करना है अपितु उसे विभिन्न विनियामक प्राधिकारियों से मान्यता भी प्राप्त हुई है।

बोर्ड के प्रयास की दो विनियामकों, जैसे कि सेबी और सीएंडएजी द्वारा मान्यता की अपेक्षाओं का नीचे कथन किया गया है :—

- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने सूचीबद्ध अस्तित्वों के लिए 1 अप्रैल, 2010 से यह आज्ञापक बना दिया है कि संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत सीमित पुनर्विलोकन/कानूनी संपरीक्षा रिपोर्ट केवल उन संपरीक्षकों द्वारा तैयार की जाएगी, जिन्होंने स्वयं को पियर पुनर्विलोकन प्रक्रिया के अध्यक्षीन किया है और जो संस्थान के 'पियर पुनर्विलोकन बोर्ड' द्वारा जारी विधिमान्य प्रमाणपत्र धारण कर रहे हैं।
- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) ने भी पियर पुनर्विलोकन बोर्ड के कार्य को मान्यता प्रदान की है; अब वह आवेदन प्ररूप में चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों से उनकी पियर पुनर्विलोकन प्रास्थिति के बारे में अतिरिक्त ब्यौरे मांगता है, ताकि पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के लिए संपरीक्षा आबंटित की जा सके। इसके अतिरिक्त, पिछले कुछ वर्षों से सीएंडएजी वार्षिक रूप से आईसीएआई से उन फर्मों के ब्यौरे मांग रहा है, जिन्हें पियर पुनर्विलोकन बोर्ड द्वारा प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं।

बोर्ड द्वारा प्राप्त पियर पुनर्विलोकन रिपोर्टों पर विचार करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए उसने बोर्ड की एक उप समिति का गठन किया है। इस उप समिति ने 30.06.2018 तक इन मामलों पर विचार किया था और 10,746 व्यवसायी इकाईयों को पियर पुनर्विलोकन प्रमाणपत्र जारी किए थे। तदनुसार, ऐसी व्यवसायी इकाईयों की पूर्ण अद्यतन सूची, जिन्हें पियर पुनर्विलोकन प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं, प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख के साथ पियर पुनर्विलोकन बोर्ड के वेब पेज पर अपलोड कर दी गई हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुनर्विलोकनों द्वारा किए जाने वाले पुनर्विलोकन कार्य में संगतता और एकसमानता है, बोर्ड उन्हें पुनर्विलोकन हेतु व्यवसायी इकाईयां समनुदेशित करने से पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करता है। अभी तक पियर पुनर्विलोकन बोर्ड ने कुल 5821 पुनर्विलोकनों को प्रशिक्षित किया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य पियर पुनर्विलोकन प्रक्रिया की बारीकियों और जटिलताओं को समझना है, अर्थात् किसी व्यवसायी इकाई का पियर पुनर्विलोकन किस प्रकार किया जाए। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने, उसकी स्थापना से देश भर में 184 पियर पुनर्विलोकन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है।

### **अधिकाधिक फर्मों को पियर पुनर्विलोकन प्रक्रिया के अधीन लाना**

पियर पुनर्विलोकन बोर्ड, भारत में सीए फर्मों की आश्वासन सेवाओं के पुनर्विलोकन के संबंध में एक विनियामक है, जिसने विनिर्दिष्ट नए मानदंडों के आधार पर पियर पुनर्विलोकन के लिए अधिकाधिक फर्मों को उसके अधीन लाकर आश्वासन सेवाओं के परिधि क्षेत्र में अभिवृद्धि की है और साथ ही, नई स्थापित फर्मों के लिए पियर पुनर्विलोकन को आरंभ किया गया है। वित्तीय विवरणों में पाए गए अननुपालनों के ऐसे मामलों को, जो सत्य और उचित मत को प्रभावित नहीं करते हैं, अपितु संपरीक्षक की असावधानी को उपदर्शित करते हैं, एफआरआरबी द्वारा पियर पुनर्विलोकन के लिए अग्रेषित किया जाता है जिससे कि सदस्यों द्वारा लागू किए जाने वाला क्वालिटी नियंत्रण ढांचा अभिनिश्चित किया जा सके। ऐसे प्रयास संस्थान के विनियामक तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाएंगे।

### **प्रशिक्षण कार्यक्रम**

पीआरबी द्वारा नियमित आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। न्यूनतम दस वर्ष के निरंतर व्यवसाय का अनुभव रखने वाले सीए सदस्यों को, उन्हें पुनर्विलोकनों के रूप में सूचीबद्ध करने से पूर्व अपेक्षित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुनर्विलोकनों द्वारा किए जाने वाले पुनर्विलोकन कार्य में संगतता और एकसमानता है, बोर्ड उन्हें पुनर्विलोकन हेतु व्यवसायी इकाईयां समनुदेशित करने से पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस वर्ष बोर्ड ने हैदराबाद, सिलिगुडी, पटना, लुधियाना, कोलकाता, भोपाल, जमशेदपुर, लखनऊ, बेंगलूर, चेन्नई,

पुणे, अहमदाबाद, वाराणसी, विशाखापट्टनम, नोएडा, इलाहाबाद, कोलकाता, गुवाहाटी, गाजियाबाद और बदोदरा में 20 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया था, जिनमें लगभग 929 पियर पुनर्विलोककों को प्रशिक्षित किया गया था। इस प्रकार अभी तक कुल 5821 पुनर्विलोककों को प्रशिक्षित किया गया है।

विनियामक परिस्थितियों और तकनीकी मानकों में नियमित परिवर्तनों और इसके परिणामस्वरूप पुनर्विलोककों को इन घटनाओं की अद्यतन जानकारी बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बोर्ड द्वारा यह विनिश्चय किया गया था कि पियर पुनर्विलोकन प्रशिक्षण की विधिमान्यता केवल पांच वर्ष होगी।

### हाल ही की घटनाएं

पियर पुनर्विलोकन के परिधि क्षेत्र में विस्तार करने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं, जिनके द्वारा उसे और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है और साथ ही और अधिक व्यवसायी इकाइयों का पुनर्विलोकन किया जा रहा है। इस प्रयोजन के मद्दे बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों को पियर पुनर्विलोकन बोर्ड द्वारा पुनरीक्षित किया गया है और व्यवसायी इकाइयों को भेजे जाने वाले पियर पुनर्विलोकन संबंधी प्रश्नोत्तरों को भी क्वालिटी नियंत्रण संबंधी मानकों के अनुसार पुनरीक्षित किया गया है। प्रश्नोत्तरों के अनुलग्नक 2 को स्तर 1 तथा स्तर 2 की फर्मों की दशा में पुनर्विलोककों द्वारा भरे जाने को आज्ञापक बनाया गया है, जिससे पुनर्विलोकन की क्वालिटी को मजबूत बनाया जा सके। पीयू द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को पियर पुनर्विलोकन आश्वासन सेवाओं के परिधि क्षेत्र में लाया गया है और तदनुसार, पियर पुनर्विलोकन प्रश्नोत्तरों और अंतिम रिपोर्ट के अनुलग्नक 1 को पुनरीक्षित किया गया है। पियर पुनर्विलोकन बोर्ड ने भी फरवरी, 2018 में दो नए प्रकाशन जारी किए हैं, अर्थात् पियर पुनर्विलोककों के लिए सलाह संबंधी हैंडबुक और व्यवसायी इकाइयों के लिए सलाह संबंधी हैंडबुक।

### 5.19 वृत्तिक विकास समिति (पीडीसी)

वर्ष 1962 में उसकी स्थापना से ही, वृत्तिक विकास समिति संस्थान के सदस्यों के लिए अर्थव्यवस्था के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त अवसरों की खोज करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। वृत्तिक विकास में नए क्षेत्रों की खोज करने के अलावा समिति, समाज के विभिन्न वर्गों में फैले बहुल उपयोक्ताओं के साथ संसूचना प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने और उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंटों की भूमिका के बारे में शिक्षित करने के लिए भी प्रयास कर रही है। चार्टर्ड अकाउंटेंटों के विद्यमान और नए क्षेत्रों में कौशल सेटों में अभिवृद्धि करने के विचार से समिति हित के समकालीन क्षेत्रों के संबंध में सगोष्ठियों, कार्यशालाओं का भी आयोजन करती है।

### कानूनी बैंक शाखा आबंटन के लिए साफ्टवेयर

- संस्थान अनेक वर्षों से, पब्लिक सेक्टर बैंकों के बैंक बोर्डों द्वारा स्वयं संपरीक्षकों की नियुक्ति के मुद्दे पर अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहा है। पब्लिक सेक्टर बैंकों के प्रबंध मंडल का कोई प्रमुख स्वामित्व संबंधी हित नहीं होता है, प्रबंध मंडल द्वारा संपरीक्षकों की नियुक्ति किए जाने की यह स्वायत्तता बैंकिंग जैसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्र में अत्यंत जोखिम पूर्ण है।
- वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अनेक बैठकें की गई थी, जिनमें एक वेब आधारित ऐप्लीकेशन तैयार करने का प्रस्ताव किया गया था, जिसके माध्यम से पब्लिक सेक्टर बैंकों (पीएसबी) के लिए कानूनी संपरीक्षकों को बेतरतीब ढंग से चुना जा सकेगा और पीएसबी में उपलब्ध रिक्तियों को उनके द्वारा भरा जा सकेगा।
- पूर्वोक्त बैठकों के अनुसरण में आरबीआई ने बैंकों को यह सलाह दी थी कि आईसीएआई ने पात्र फर्मों के बीच ऐसी संपरीक्षा के पैरामीटर आधारित आबंटन के लिए एक साफ्टवेयर विकसित किया है और आगे यह और सलाह दी गई थी कि बैंक उस साफ्टवेयर या किसी अन्य उपयुक्त साफ्टवेयर, जो विशेष रूप से तैयार किया गया या अन्यथा हो, की सहायता से केंद्रीय रूप से एसबीए की नियुक्ति हेतु बैंक बोर्ड और एसबीबी द्वारा तैयार की गई/अनुमोदित नियुक्ति नीति के निबंधनानुसार संपरीक्षा फर्मों का चयन करने पर विचार कर सकेंगे।
- उसके पश्चात् समिति ने 27 दिसंबर, 2017 को मुंबई में बैंकरों की एक बैठक का आयोजन किया था, जिसमें उक्त साफ्टवेयर के कार्यकरण के संबंध में ब्यौरेवार चर्चा की गई थी और बैंकरों से उसके संबंध में अंतःनिवेश/सुझाव मांगे गए थे। आईबीए और 14 पब्लिक सेक्टर बैंकों के प्रतिनिधियों ने उस बैठक में भाग लिया था और उक्त साफ्टवेयर के संबंध में अपनी दिलचस्पी को दर्शाया था।

- वर्ष 2017-18 में कानूनी बैंक शाखा संपरीक्षा के आबंटन के लिए 3 बैंकों, अर्थात् देना बैंक, सिंडिकेट बैंक और ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स ने इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए अपने कानूनी संपरीक्षकों का चयन किया था और कार्यान्वयन के पश्चात् सभी तीन बैंकों ने इसकी सराहना की थी और पीडीसी को इस संबंध में उसके प्रयासों के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया प्रदान की थी।

### **आरबीआई के साथ समन्वय**

13 मार्च, 2018 को मुंबई में, एससीए सम्मेलन के साथ-साथ आरबीआई के कार्यपालक निदेशक, श्री ए.के. मिश्रा के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें परस्पर वृत्तिक मुद्दों, जिनके अंतर्गत कानूनी संपरीक्षकों के पारिश्रमिक में वृद्धि का मुद्दा भी था, पर विचार-विमर्श किया गया था। उसके पश्चात् इस संबंध में एक पत्र भी प्रस्तुत किया गया था।

### **आरआरबी के संपरीक्षकों की फीस में वृद्धि**

नाबार्ड के पदधारियों को किए गए प्रतिवेदनों और उनसे हुई बैठकों के अनुसरण में नाबार्ड ने यह सूचित किया है कि भारत सरकार ने आरआरबी के प्रधान कार्यालयों और साथ ही शाखा कार्यालयों में संपरीक्षकों को संदत्त की जा रही संपरीक्षा फीस के पुनरीक्षण के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है, जिसके अनुसार उनके कारबार के विभिन्न स्तरों पर इस फीस को वर्ष 2013 के वर्तमान परिपत्र के अनुसार संदत्त की जा रही फीस की तुलना में 25% से 40% वृद्धि की गई है।

### **नाबार्ड के साथ समन्वय**

समिति, आरआरबी के कानूनी संपरीक्षकों की नियुक्ति के सन्नियमों के संबंध में सतत रूप से नाबार्ड के साथ समन्वय कर रही है, जिनमें वर्ष 2016-17 के आगे से आरआरबी के लिए कानूनी केंद्रीय संपरीक्षकों और कानूनी शाखा संपरीक्षकों की नियुक्ति के लिए पुनरीक्षित दिशा-निर्देशों पर विचार विमर्श किया गया था। इस संबंध में, अध्यक्ष पीडीसी ने श्री नीरज वर्मा, जीएम, नाबार्ड के साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए 26 अप्रैल, 2018 को एक बैठक की थी और नाबार्ड के पदधारियों ने यह आश्वासन दिया था कि वे इस पर विचार करेंगे।

### **भारत के सी एंड एजी के कार्यालय के साथ समन्वय**

समिति भारत के सी एंड एजी के कार्यालय के साथ एक निकट समन्वय कर रही है। भारत के सी एंड एजी श्री राजीव महिषि के साथ अक्तूबर और नवंबर, 2017 में परस्पर वृत्तिक हितों के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठकें की गई थी।

### **ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ समन्वय**

समिति ने यह विनिश्चय किया है कि मंत्रालय को यह प्रस्ताव किया जाए कि आईसीएआई एमजी नरेगा निधि के लेखांकन और उसकी संपरीक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए सहयोग दे सकता है। निधियों के बेहतर शासन और उपयोग की आवश्यकता महसूस की गई थी जिससे खातों को बनाए रखने के लिए अनुशासन और पारदर्शिता लाई जा सके। इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय के पदधारियों के साथ विभिन्न बैठकें की गई थी, जिनमें इस बात पर परिचर्चा की गई थी कि निधियों और उनके उपयोग में बेहतर शासन की आवश्यकता है।

### **विशिष्ट दस्तावेज पहचान संख्या (यूडीआईएन)**

- संस्थान की जानकारी में ऐसी कई घटनाओं को लाया गया था जहां वित्तीय विवरणों और दस्तावेजों को हमारे सीए सदस्यों के स्थान पर किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा प्रमाणित/अधिप्रमाणित किया जा रहा है। ये विवरण ऐसे अनेक प्राधिकारियों/अन्य पणधारियों को गुमराह करते हैं, जो उन पर विश्वास करते हैं।
- उपरोक्त समस्या का समाधान करने के लिए, विशिष्ट दस्तावेज पहचान संख्या (यूडीआईएन) की एक नवीन अवधारणा को आईसीएआई की वृत्तिक विकास समिति द्वारा अभिकल्पित और विकसित किया गया है, जिसके संबंध में विभिन्न विनियामकों द्वारा मांग की जा रही थी। यूडीआईएन एक ऐसी विशिष्ट संख्या है, जो ऐसे प्रत्येक दस्तावेज के लिए सृजित की जाएगी, जिसे व्यवसायगत चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा प्रमाणित/अधिप्रमाणित किया जाता है और ऐसे सीए यूडीआईएन पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत होंगे, जो <https://udin.icaai.org> पर उपलब्ध हैं।
- उक्त पोर्टल विभिन्न विनियामकों/बैंकों/प्राधिकारियों/अन्य पणधारियों को यह सुविधा प्रदान करता है कि वे

व्यवसायगत ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंटों, जिन्होंने उक्त पोर्टल पर स्वयं को रजिस्ट्रीकृत किया है, द्वारा प्रमाणित दस्तावेजों की सत्यता की जांच कर सकते हैं। यह किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा किसी चार्टर्ड व्यक्ति के नाम पर धोखे से तैयार किए गए/गलत दस्तावेजों का पता लगाने में सहायता करेगा क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट से भिन्न कोई व्यक्ति उस पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने में समर्थ नहीं होगा।

### मुख्य सतर्कता आयुक्त के साथ बैठक

- राष्ट्र निर्माण के भागीदार के रूप में संस्थान कार्य की गुणवत्ता के बारे में अत्यधिक संवेदनशील है। इस संबंध में, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, आईसीएआई ने अध्यक्ष, वृत्तिक विकास समिति के साथ श्री वी.के. चौधरी, मुख्य सतर्कता आयोग (सीवीसी) और श्री टी.एम. भसीन, सतर्कता आयुक्त के साथ बैठक की थी।
- बैठक के दौरान, यह अभिव्यक्त किया गया था कि न्यूनतम दर वाली बोली का चयन करने (एलसीएस) की प्रणाली को वृत्तिक सेवाओं (संपरीक्षा सेवा) हेतु कार्य का आबंटन करने के लिए निविदाओं का मूल्यांकन करने का वर्तमान व्यवहार, जिसमें न्यूनतम बोली लगाने वाले को निविदा प्रदान की जाती है। चूंकि न्यूनतम लागत समनुदेशित कार्य की अपेक्षित गुणवत्ता के स्तर की गारंटी नहीं करती है, इसलिए यह सुझाव दिया गया था कि चयन की प्रक्रिया हेतु उपांतरण अपेक्षित है, विशेष रूप से वृत्तिक सेवाओं को नियोजित करने के लिए और आईसीएआई ने सीवीसी को अपना समर्थन दिया था ताकि एकसमानता को सुनिश्चित किया जा सके और सेवाओं हेतु निविदा प्रदान करने की संपूर्ण प्रक्रिया के लिए कोई उपयुक्त युक्ति विकसित की जा सके।
- आईसीएआई ने संपरीक्षा समनुदेशनों को सम्यक् महत्व देते हुए क्वालिटी और लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस) को एकसमान रूप से अपनाए जाने का सुझाव दिया था। वृत्तिक सेवाओं के लिए वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन एलसीएस मानदंड की बजाए क्यूसीबीएस के माध्यम से किया जाना चाहिए। इस मानदंड को अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी अपनाया जा रहा है क्योंकि यह तकनीकी रूप से अर्हित वृत्तिकों को निविदा प्रदान किए जाने का उचित अवसर उपलब्ध कराता है।

### नीति आयोग के साथ भागीदारी करने के लिए समन्वय

समिति ने नीति आयोग के साथ एक करार किया है, जिसके अधीन वे नीति आयोग द्वारा, उसके महिला उद्यमी प्रकोष्ठ में की जा रही पहलों में निम्नलिखित रूप से सहयोग करेंगे :

- आईसीएआई चार्टर्ड अकाउंटेंटों का एक पैनल उपलब्ध कराएगा।
- आईसीएआई प्रत्येक राज्य के लिए दो विशेषज्ञ उपलब्ध कराएगा, जिनमें कार्य के विस्तार क्षेत्र को नीति आयोग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
- आईसीएआई नीति आयोग द्वारा विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन करने के लिए निःशुल्क रूप से स्थानों की व्यवस्था कर सकता है। इस संबंध में, देश भर में स्थित हमारी प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं के 80 से अधिक सभागारों की एक सूची उपलब्ध कराई गई थी।
- आईसीएआई द्वारा उक्त कार्यशालाओं के दौरान सत्रों का आयोजन करने के लिए संकाय समर्थन/संसाधन व्यक्ति भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
- आईसीएआई नीति आयोग द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले वित्त और लेखा से संबंधित विभिन्न प्रकाशनों की अंतर्वस्तु की विधीक्षा में उसकी सहायता कर सकता है। आईसीएआई नीति आयोग की वेबसाइट को अपनी वेबसाइट के साथ और साथ ही पीडी ज्ञान पोर्टल के साथ ही सहयोजित कर सकता है जिससे उसके सदस्यों के बीच की जाने वाली पहलों के संबंध में जागरूकता का सृजन किया जा सके।

### आरबीआई द्वारा गठित एनपीए और कपट संबंधी विशेषज्ञ समिति से बैठक

- संस्थान के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ने केंद्रीय परिषद् के सदस्यों के साथ आरबीआई द्वारा गठित एनपीए और कपट संबंधी विशेषज्ञ समिति के साथ, जिसकी अध्यक्षता आईसीएआई के पूर्व अध्यक्ष और एनएसीएएस के संस्थापक अध्यक्ष सीए वाई.एच. मालेगम द्वारा की जा रही है, 20 जून, 2018 को मुंबई में एक बैठक की थी, जहां हमारे द्वारा संपरीक्षा के परिप्रेक्ष्य से एनपीए और कपटों के संबंध में सुझाव प्रस्तुत किए गए थे। उसके पश्चात् हमने यह

सिफारिश की थी कि कानूनी संपरीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में दी गई स्वायत्तता को वापस लिया जाना चाहिए। धन को कहीं ओर मोड़ने तथा कपट की घटनाओं को कम करने में बैंकों द्वारा की जाने वाली संपरीक्षाओं की विभिन्न किस्मों की भूमिका और प्रभाविकता की अनदेखी नहीं की जा सकती। तदनुसार, हमने यह सुझाव दिया था कि बैंक शाखा संपरीक्षा के विस्तार क्षेत्र को व्यापक बनाया जाना चाहिए। हमने इस बात पर भी बल दिया था कि सभी बैंक शाखाओं को कानूनी संपरीक्षा के अधीन नहीं किया जा रहा है और अन्यो के साथ ऐसे मुद्दों पर भी परिचर्चा की गई थी जिनमें बैंकों द्वारा कानूनी संपरीक्षकों की नियुक्ति समवर्ती संपरीक्षा का सीए द्वारा किया जाना और कार्य के विस्तार क्षेत्र से नियुक्ति और पारिश्रमिक को जोड़ने के लिए एकसमानता लाने, बैंकों के पास एक ठोस मूल्यांकन और एक प्रभावी ऋण मानीटरी तंत्र होने जैसे विषय सम्मिलित थे।

- हमने समिति को आईसीएआई द्वारा कानूनी संपरीक्षकों की नियुक्ति के लिए तैयार किए गए साफ्टवेयर और यूडीआईएन के कार्यान्वयन के संबंध में भी संक्षिप्त जानकारी प्रदान की थी। इसके द्वारा बेतरतीब ढंग से उपलब्ध कानूनी संपरीक्षकों को पब्लिक सेक्टर बैंकों में उपलब्ध रिक्तियों के साथ सहबद्ध किया जा सकता है। इस वर्ष तीन बैंकों, अर्थात् सिंडिकेट बैंक, देना बैंक और ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स ने पहली बार इस साफ्टवेयर का उपयोग किया है और एक सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। हमने विशेषज्ञ समिति को यह संप्रेषित किया है कि अन्य बैंकों को भी हमारे साफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

### इंफोसिस फिनेकल के साथ पहल

पीडीसी ने, बैंक संपरीक्षाओं में एक बैंचमार्क स्थापित करने के उद्देश्य से फिनेकल पार्टनरों, इंफोसिस की तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग किया है, जिसमें उन्होंने सीए के लिए बैंक संपरीक्षा हेतु फिनेकल द्वारा विशेष रूप से तैयार किए गए सात ई-पठन माड्यूल (120 मिनट की अवधि के 12 वीडियो के रूप में) उपलब्ध कराए हैं।

### सीए निदेशक परस्पर क्रियाशील बैठक

- पब्लिक सेक्टर अस्तित्वों के बोर्ड में विद्यमान चार्टर्ड अकाउंटेंट निदेशकों के साथ सतत बातचीत बनाए रखने के आशय से, निगम विधि, निगम शासन संबंधी समिति के साथ संयुक्त रूप से अस्ति प्रबंध कंपनियों, बीमा कंपनियों और बैंकों के अतिरिक्त अन्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के सीए निदेशकों के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया था।
- इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर श्री (डा.) नवरंग सैनी, पूर्णकालिक सदस्य, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पूर्व अध्यक्षों और 40 से अधिक सीए निदेशकों ने इसकी शोभा बढ़ाई थी इसे अत्यधिक सराहना प्राप्त हुई थी। समकालीन विषयों जैसे निगम शासन, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, बैंकों में जोखिम प्रबंध, साइबर सुरक्षा पर तकनीकी सत्रों में, उनमें भाग लेने वालों को गहन अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराई गई थी और इसके पश्चात् स्वतंत्र निदेशक – चुनौतियों का सामना करना और अवसरों का लाभ उठाना, विषय पर पैनल चर्चा का आयोजन किया गया था।

### पीडी पोर्टल का नया रूप

- समिति ने, सदस्यों को ऐसी सभी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए, जिसकी उन्हें स्वयं के व्यवसाय को समृद्ध बनाने और उनके ग्राहकों को मूल्यवर्धित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यकता है, पीडी पोर्टल ([www.pdicai.org](http://www.pdicai.org)) को विकसित किया है।
- इस पोर्टल का नवीकरण किया गया है, जिसमें वेबसाइट पर समिति के क्रियाकलापों के लिए एक पृथक् खंड का सृजन किया गया है। एमईएफ एप्लीकेशन, वेबकास्टों और कराए जाने वाले आयोजनों, भिन्न-भिन्न विनियामक प्राधिकारियों के साथ की गई संसूचनाओं, उनकी वेबसाइटों के लिंक आदि के संबंध में सभी संबद्ध जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध है।

### आयोजित कार्यक्रम

- बैंक संपरीक्षा में अंतर्बलित मुद्दों पर देश भर में पीडी समिति के तत्वावधान में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। इसके अतिरिक्त, चार स्थानों, अर्थात् दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में मार्च-अप्रैल, 2018 के दौरान संपरीक्षा और आश्वासन बोर्ड के साथ संयुक्त रूप से एससीए बैठकों की एक श्रृंखला का आयोजन किया गया

था।

- समिति ने वृत्तिक विकास से संबंधित आवश्यकताओं का अवधारण करने और उसके साथ ही ऐसी चिंताओं की पहचान करने, जो वृत्ति को प्रभावित कर रही है, सदैव प्रयास किए हैं। इसे ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा, अपने सदस्यों के कौशल सेट को सुदृढ़ बनाने और अभिवृद्धि करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।
- विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान समिति ने, केंद्रीय बैंक की कंपनियों के संपरीक्षकों से आशाएं, भविष्य का पुनःनिर्माण आदि विषयों पर दिल्ली, मुंबई, इंदौर, सीकर, जोधपुर, रायपुर, भोपाल, भिलाई आदि में 28 कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, बैठकों आदि का आयोजन किया था।

### **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और अनिगमित निकायों के कार्यक्रम के संबंध में राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) बैठक**

- गोवा, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात, त्रिपुरा, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, पांडिचेरी, रायपुर और चंडीगढ़ राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों के लिए पूरे वर्ष के दौरान विभिन्न एसएलसीसी बैठकों का आयोजन किया गया था।
- तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और अनिगमित निकायों के कार्यक्रम के संबंध में विभिन्न उप एसएलसीसी बैठकों का आयोजन किया गया था।

### **प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन**

निविदाओं के संबंध में प्रतिक्रिया किए जाने के संबंध में परिषद् के विनिश्चय की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्राधिकारियों को विभिन्न प्रतिवेदन भेजे गए थे, जिनके द्वारा उनसे अनुरोध किया गया था कि वे स्वयं निविदा दस्तावेज में कार्य समनुदेशन की ऐसी न्यूनतम फीस को नियत करें, जिससे कि अधिसूचना के उद्देश्य को पूरा किया जा सके।

### **बहु प्रयोजन पैनलबद्ध प्ररूप और पैनलों का प्रावधान :**

समिति, ऐसे नए/विद्यमान क्षेत्रों की खोज करके/ उन्हें लक्षित करके, जहां सदस्यों के वृत्तिक कौशलों का उपयोग एक उत्पादक और लाभदायक रीति में किया जा सकता है, सदस्यों के लिए और अधिक वृत्तिक अवसरों का जनन करने के लिए प्रयास करती रही है। व्यवहार के अनुसार, समिति ने इस वर्ष भी [www.meficai.org](http://www.meficai.org) पर बहु प्रयोजन पैनलबद्ध प्ररूप को आनलाइन रूप से रखा था। एमईएफ को अधिकाधिक सर्वग्राही बनाने के लिए और अधिकतम जानकारी एकत्रित करने तथा एक केंद्रीयकृत डाटा बेस के माध्यम से उसका प्रसार करने के लिए प्रत्येक प्रयास किया गया था।

समिति ने आरबीआई, नाबार्ड और विभिन्न अन्य प्राधिकारियों, जैसे कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, शासकीय परिसमापक, सिडबी, सेबी आदि को उनके द्वारा विनिर्दिष्ट मानदंड के अनुसार चार्टर्ड अकाउंटेंटों/फर्मों के पैनल उपलब्ध कराए थे।

### **5.20 लोक वित्त और शासकीय लेखांकन संबंधी समिति (सीपीएफएंडजीए)**

#### **कार्यक्रम/संगोष्ठियां/सम्मेलन/कार्यशालाएं/परस्पर क्रियाशील बैठकें**

समिति ने, मुंबई, दिल्ली, अकोला, पुणे, वाइजेग, मदुरै और अन्य कई नगरों में सहकारिता और एनपीओ सेक्टरों संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों, परस्पर क्रियाशील बैठकों और एनपीओ तथा सहकारी सोसाइटियों और एफसीआरए संबंधी मुद्दों पर संगोष्ठी आदि का आयोजन किया था।

लोक वित्त और शासकीय लेखांकन संबंधी समिति ने अपने “लोक वित्त और शासकीय लेखांकन में सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाले पदों” नामक एक प्रकाशन को पुनरीक्षित किया था जो लोक वित्त और अर्थशास्त्र से संबंधित शब्दावली/अर्थशास्त्र संबंधी पदों को समझने में उपयोगी होगा।

#### **प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं/वेबकास्ट/संकाय विकास कार्यक्रम**

वर्ष के दौरान समिति ने, विभिन्न स्थानों पर, जिनमें नई दिल्ली, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मुंबई, सिलवासा और

कोलकाता सम्मिलित थे, सरकारी विभागों/पीएसयू के साथ अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया था। समिति ने, नई दिल्ली आर्थिक दृष्टि से संघीय बजट के विश्लेषण संबंधी एक वेबकास्ट का भी आयोजन किया था।

### 5.21 जन संपर्क और सीएसआर क्रियाकलाप

वर्ष 2017-18 में, समिति ने अपने मिशन और उद्देश्य के अनुसरण में, चैम्बर आफ कामर्स/ व्यापार निकाय/ महत्वपूर्ण मीडिया गृहों और समान संगठनों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करके तथा उन्हें पोषित करके एक प्रमुख लेखांकन निकाय के रूप में आईसीएआई की छवि को विकसित करने, सुदृढ़ बनाने और उसमें अभिवृद्धि करने के प्रयासों को जारी रखा था। समिति ने ऐसी अर्थ पूर्ण और क्वालिटी पहलें की थी, जिनमें सामाजिक उत्तरदायित्व के ऐसे सटीक सार को इस रूप में दर्शित किया गया था, जिसके कारण पारदर्शिता और प्रभावी शासन के माध्यम से समाज के लिए मूल्य का सृजन हुआ था। वर्ष 2017-18 में, पीआर और सीएसआर समिति को जन संपर्क समूह के रूप में पुनः गठित किया गया था। पूर्वोक्त अवधि के दौरान पीआर समिति द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण क्रियाकलापों में निम्नलिखित सम्मिलित थे:

#### सरकार की पहलों में भागीदारी करना

फरवरी-दिसंबर, 2017 की अवधि के दौरान, राष्ट्र निर्माण में भागीदार के रूप में और निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के मद्दे सरकार की पहलों को अग्रसर करने जैसे कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह, स्वच्छता ही सेवा, विशेष अभियान स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छता पखवाड़ा, भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्ष गांठ, राष्ट्रीय एकता दिवस, संविधान दिवस और ईशा फाउंडेशन – नदियों के लिए रैली, इन क्रियाकलापों को अखिल भारतीय स्तर पर आईसीएआई की सभी प्रादेशिक परिषदों/शाखाओं को सहबद्ध करते हुए किया गया था।

#### आईसीएआई जीएसटी सहायता पटल

माल और सेवा कर (जीएसटी) ने बहु कर प्रणाली को 1 जुलाई, 2017 से एकल कराधान प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया है। जीएसटी के कार्यान्वयन को सभी तीन पणधारियों, अर्थात् सरकार, कारोबारी व्यक्तियों और उपभोक्ताओं, सभी के लिए एक विजयी परिस्थिति के रूप में परिकल्पित किया गया था। इस विशाल परिवर्तन का महत्वपूर्ण पहलू लघु कारबारियों, व्यापारियों आदि को अधिनियम के विभिन्न पहलुओं के बारे में उपयुक्त मार्गदर्शन उपलब्ध कराना था।

लघु कारबारियों, व्यापार और उद्योग और साधारण जनता के प्रतिनिधित्व को सुकर बनाने के लिए आईसीएआई ने पीआर और सीएसआर समिति के माध्यम से, अपनी प्रादेशिक परिषदों, शाखाओं और सीपीई चैप्टरों के माध्यम से पूरे देश भर में स्थित 125 अवस्थानों पर जीएसटी सहायता पटलों को कार्यरत बनाया था। ये सहायता पटल 28 मई, 2017 से 30 सितंबर, 2017 तक कार्यरत बने रहे थे। जीएसटी के संबंध में जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ व्यक्तियों ने इन सहायता पटलों पर पणधारियों द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान किया था और वे लक्षित समूहों की आरंभिक शंकाओं और संदेहों का समाधान करने में समर्थ रहे थे।

#### स्वच्छता अभियान

आईसीएआई, अपनी 164 शाखाओं और पांच प्रादेशिक परिषदों के सुदृढ़ नेटवर्क के माध्यम से प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत की परिकल्पना का एक भाग बना हुआ है। वर्ष के दौरान समिति ने, स्वच्छता अभियान/स्वच्छता प्रतिज्ञा/ पौधा रोपण/ ग्रीन मैराथन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के संबंध में जागरूकता जैसी विभिन्न पहलों को किया था। प्रधानमंत्री के स्वप्न को साकार करने के लिए नियमित आधार पर और विशेष रूप से महत्वपूर्ण अवसरों जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, सीए दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती आदि पर अनेक पहलें की जाती हैं। इनका उद्देश्य स्वच्छता और उससे सहबद्ध फायदों के संबंध में आईसीएआई के सदस्यों, छात्रों और पणधारियों, पदधारियों तथा कर्मचारिवृंद को संवेदनशील बनाना और उनकी जागरूकता में वृद्धि करना है।

#### राज्य कार्यबल

आईसीएआई और सीए की वृत्ति के स्थानीय स्तर पर ब्रांड निर्माण हेतु पीआर की पहुंच में वृद्धि करने के विचार से समिति ने चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू-कश्मीर में राज्य कार्यबलों (एसटीएफ) का गठन किया था। सभी नगरों से प्रमुख चार्टर्ड अकाउंटेंटों को इन एसटीएफ का भाग बनाया गया था, जिससे उनके मूल्यवान अंतःनिवेशों, बुद्धिमता और मार्गदर्शन से ब्रांड के निर्माण के मद्दे किए जाने वाले क्रियाकलापों/नए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए कराई

जाने वाली बैठकों के दौरान लाभान्वित हुआ जा सके। चंडीगढ़, पंजाब और जम्मू-कश्मीर के एसटीएफ की बैठकों का आयोजन किया गया था और उनमें वृत्ति के साधारण हित के विषयों पर परिचर्चा की गई थी।

### **सोशल मीडिया मंचों पर आईसीएआई से संबंधित समाचारों/घटनाओं को विशिष्ट रूप से दर्शित करना**

डिजिटल विकास को ध्यान में रखते हुए, सोशल मीडिया मंचों पर उपस्थिति, वर्तमान और भावी सदस्यों से जुड़ने और क्रियाकलापों का संवर्धन करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। यह महसूस किया गया था कि सभी सोशल मीडिया मंचों पर आईसीएआई की उपस्थिति में अभिवृद्धि करने की आवश्यकता है, अतः, यह विनिश्चय किया गया था कि संस्थान द्वारा की जाने वाली सभी प्रमुख पहलों को मुद्रण/इलेक्ट्रानिक और आनलाइन मीडिया के अतिरिक्त सोशल मीडिया के माध्यम से भी संवर्धित किया जाएगा। तदनुसार, विभिन्न समितियों/विभागों द्वारा की गई पहलों को फेसबुक, ट्वीटर, लिंकडइन और यू-ट्यूब जैसे सोशल मीडिया मंचों पर संवर्धित किया गया था।

### **अन्य पहलें**

- सीए दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए सीए जर्नल और तकनीकी पृष्ठभूमि में सम्मिलित किए जाने के लिए अतिविशिष्ट व्यक्तियों से संदेश देने का अनुरोध किया गया था।
- मीडिया के साथ परस्पर क्रियाओं में आमने-सामने साक्षात्कारों/प्रेस विज्ञप्तियों/प्रेस सम्मेलनों के माध्यम से अभिवृद्धि हुई थी, जिनके द्वारा मीडिया को निरंतर रूप से होने वाली पाठ्यचर्या, वृत्ति, नए पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने, सीए के लिए नए दिशानिर्देश, विदेशी प्रतिनिधि मंडलों के दौरे और अन्य क्रियाकलापों से संबंधित नवीनतम घटनाओं से अवगत कराया गया था।
- समिति ने, लेखों और साथ ही परस्पर क्रियाशील बैठकों, राष्ट्रीय/प्रादेशिक स्तर पर प्रैस को जारी विज्ञप्तियों और विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से आज के क्रियाशील संदर्भ में चार्टर्ड अकाउंटेंटसी वृत्ति की संभावनाओं और विस्तार क्षेत्र का संवर्धन किया था।
- आईसीएआई के संबंध में जागरूकता का सृजन करने और उसके मूल डोमेन का संवर्धन करने के लिए समाचार पत्रों/कारबार पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रकाशित किए गए थे।
- आईसीएआई के भीतर विभिन्न विभागों, प्रादेशिक कार्यालयों और शाखाओं को, आईसीएआई और उसके कार्यालयों/संबद्ध संगठनों से जोड़े रखने और संसूचना संबंध विकसित करने के विचार से संभार समर्थन उपलब्ध कराया गया था।
- पीआर कार्य के भागरूप में मुद्रण और इलेक्ट्रानिक मीडिया में आईसीएआई की विभिन्न संगोष्ठियों/कार्यक्रमों/आयोजनों को उपयुक्त रूप से कवर किया गया था।
- प्रैस और मीडिया को सतत रूप से, उनसे निरंतर परस्पर क्रियाएं करके वृत्ति के संबंध में उभरती घटनाओं से अवगत कराया गया था और ऐसा विशेष रूप से परिषद् की प्रत्येक बैठक के पश्चात् किया गया था।

## **5.22 अनुसंधान समिति**

अनुसंधान समिति भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) की गैर स्थायी समितियों में एक है, जिसकी स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी। अनुसंधान समिति का मुख्य उद्देश्य, वृत्ति द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का मूल्यवर्धन करने के विचार से लेखांकन और अन्य सहबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान करना है। यह समिति लेखांकन पहलुओं के संबंध में मार्गदर्शक टिप्पण तैयार करती है, जिन्हें परिषद् के प्राधिकार के अधीन जारी किया जाता है। समिति, साधारण रूप से स्वीकृत लेखांकन और/या संपरीक्षा सिद्धांतों के संबंध में तकनीकी गाइडों, अध्ययनों, मोनाग्राफों आदि को निकालती है। समिति अपनी वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति में सुधार करने के विचार से अपनी एक उप समिति, शील्ड पैनल के माध्यम से एक वार्षिक प्रतियोगिता, अर्थात् 'वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार' का भी आयोजन करती है।

### **वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार**

इन पुरस्कारों को वर्ष 1958 से वार्षिक रूप से प्रदान किया जा रहा है। विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में पुरस्कार विजेताओं का चयन एक 3 टियर ठोस मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है : सर्वप्रथम प्रारंभिक मूल्यांकन तकनीकी



पुनर्विलोककों द्वारा किया जाता है, जिसके पश्चात् शील्ड पैनल द्वारा सूचीबद्ध वार्षिक रिपोर्टों का पुनर्विलोकन किया जाता है और इनका अंतिम पुनर्विलोकन एक बाहरी ज्यूरी द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2016-17 की प्रतियोगिता के लिए ज्यूरी की बैठक 15 जनवरी, 2018 को मुंबई में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता श्री एम. दामोदरन, पूर्व अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा की गई थी। पुरस्कार विजेताओं का चयन करने के लिए बैठक में भाग लेने वाले जूरी के अन्य सदस्यों में : सीए. अमरजीत चोपड़ा, अध्यक्ष, एनएसीएएस और पूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई, श्री एच.आर. खान, पूर्व उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, श्री संजय झांवर, प्रबंध भागीदार, मैसर्स चीड अमृत लीगल एलएलपी, श्री नारायण मेहता, सीएफओ, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, श्री पी.पी. पारीक, पूर्व निदेशक बैंक आफ बड़ौदा और आंध्रा बैंक, सुश्री परामा सेन, प्रधान निदेशक (वाणिज्यिक), सीएंडएजी, श्री नितिन पारेख, समूह सीएफओ, कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड सम्मिलित थे।

पुरस्कारों की स्कीम के अनुसार सर्वोत्तम प्रविष्टि और दूसरी सर्वोत्तम प्रविष्टि के लिए क्रमशः एक स्वर्ण शील्ड और एक रजत शील्ड पुरस्कार में प्रदान की जाती है। ऊपर उल्लिखित पुरस्कारों के अलावा सराहनीय प्रविष्टियों के लिए पट्टिकाएं पुरस्कार में दी जाती हैं। हाल ऑफ फेम पुरस्कार ऐसे अस्तित्वों को प्रदान किया जाता है, जो किसी विशिष्ट प्रवर्ग में लगातार पांच स्वर्ण शील्ड का विजेता रहा हो। 'वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार' के विजेताओं को सम्मानित करने के लिए 25 जनवरी, 2018 को मुंबई में एक समारोह का आयोजन किया गया था। श्री एम. दामोदरन, पूर्व अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। कुल 11 पुरस्कार प्रदान किए गए थे, जिनमें 2 स्वर्ण शील्ड, 4 रजत शील्ड और 5 पट्टिकाएं सम्मिलित थीं।

इसके अतिरिक्त, 'एकीकृत रिपोर्टिंग : एकीकृत रिपोर्टिंग की ओर यात्रा' विषय पर एक तकनीकी सत्र और साथ ही 'वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के मद्दे कार्यशाला' का भी आयोजन किया गया था, जिसमें पुरस्कार दिए जाने के समारोह से पूर्व प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाले अस्तित्वों के वित्तीय रिपोर्टों और अन्य दस्तावेजों संबंधी संप्रेक्षणों को शील्ड पैनल द्वारा विशिष्ट रूप से दर्शित किया गया था।

### 5.23 पूंजी बाजार और निवेशकों के संरक्षण संबंधी समिति (सीसीएमएंडआईपी)

सीसीएमएंडआईपी को परिषद् द्वारा वर्ष 1993-94 में एक अस्थायी समिति के रूप में गठित किया गया था उसके पश्चात् 1998-99 में समिति के नाम को परिवर्तित करके वित्तीय बाजार और निवेशकों की संरक्षा संबंधी समिति कर दिया गया था। वर्ष 2017-18 में, तत्कालीन समिति का बैंककारी वित्तीय सेवा और बीमा समिति में विलयन कर दिया गया था और 2018 में पुनः उसे पूंजी बाजार और निवेशकों के संरक्षण संबंधी समिति के रूप में गठित किया गया है।

सीसीएमएंडआईपी सरकार/विनियामकों को प्रस्तुत किए जाने के लिए पूंजी बाजार से संबंधित विभिन्न विधेयकों/विनियमों/अधिसूचनाओं/परिपत्रों और अन्य दस्तावेजों के संबंध में सुझाव देती है। इसके अतिरिक्त, समिति नियमित रूप से आरबीआई और भारतीय बैंक संगम से नियमित रूप से परस्पर क्रियाएं करती है, उदाहरण के लिए, ऐसी परस्पर प्रतिक्रियाएं निक्षेपकर्ताओं, गैर-निष्पादनकारी आस्तियों का प्रबंध, बैंक प्रचालन और पर्यवेक्षण, प्रतिभूतिकरण से संबंधित मुद्दों, सीए द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका, गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), आरबीआई का एनबीएफसी विभाग, सहकारी बैंकों के विनियामक प्राधिकारी, उनके निवेश नीति से संबंधित रणनीतियां/सिफारिशें, उदाहरण के लिए प्राथमिक और द्वितीय बाजारों से संबंधित मामले, नियंत्रण अर्जित करने, सुमेलन, विलयन, (कर मुक्त क्षेत्र, भागीदारी टिप्पण, चलायमान मुद्रा, निगम शासन विनियामक अनुपालन आदि), परस्पर निधियां, विदेशी संस्थागत निवेशक, मध्यवर्ती, प्रतिभूति विधियां आदि, अग्रिम बाजार आयोग (एफएमसी), जिसके अंतर्गत एनसीडीएक्स और एमसीएक्स भी हैं, स्टॉक एक्सचेंजों को पूंजी बाजार और निवेशकों की संरक्षा संबंधी मुद्दे सम्मिलित हैं।

### राष्ट्र निर्माण में भागीदार

राष्ट्र निर्माण में अधिमानी भागीदार के रूप में उभरने के लिए और साधारण जनता के बीच वित्तीय प्रतिभूतियों में धन निवेश करने के लिए किए जाने और न किए जाने योग्य बातों के संबंध में जागरूकता का प्रसार करने और वित्तीय साक्षरता का संवर्धन करने के लिए समिति, विभिन्न संसाधन व्यक्तियों और प्रादेशिक परिषदों, शाखाओं, अध्ययन सर्कलों, अध्ययन चैप्टर, अध्ययन समूहों के माध्यम से कारपोरेट कार्य मंत्रालय की निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) के तत्वावधान में निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है।

### फरवरी, 2018 - जून, 2018 के दौरान आयोजित निवेशक जागरूकता कार्यक्रम

- **आईसीएआई की ईआईआरसी में आयोजित :** भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय की निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) के तत्वावधान में कोलकाता में ईआईआरसी के परिसरों में 13 अप्रैल, 2018 को निवेशक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में सम्मिलित किए गए विषयों के अंतर्गत गहन निवेश, दोनों बाजार मत, निवेश रणनीति संबंधी मत और निवेशक जागरूकता थे।
- **आईसीएआई की एसआईआरसी में आयोजित :** भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय की निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) के तत्वावधान में आईसीएआई एसआईआरसी द्वारा 30 मई, 2018 को हिन्दुस्तान चैम्बर्स आफ कामर्स के साथ संयुक्त रूप से निवेशक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में परिचरित विषयों में सुरक्षित निवेशक होना सुरक्षित है, सम्मिलित था।
- समिति ने देश भर में, अर्थात् अखिल भारतीय आधार पर **132** निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों (आईएपी) का आयोजन किया था, जिसमें भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय के आईईपीएफ के तत्वावधान में **7997 व्यक्तियों को शिक्षित** किया गया था। इस अवधि के दौरान, उक्त आईएपी का आयोजन आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल आदि के जिलों में किया गया था। उक्त आईएपी में सम्मिलित किए गए विषयों में पूंजी बाजार के लिए बजट उदघोषणाएं, निवेश पाठशाला, वित्तीय योजना और निवेश विकल्प, भारतीय स्टॉक बाजार, वर्तमान और भविष्य, परस्पर निधियां, अपने धन की जोखिम से संरक्षा कैसे करें और अवरुद्ध निवेशों की वसूली किस प्रकार करें, आदि सम्मिलित थे।

### सदस्यों के लिए पहले

#### सक्षमता निर्माण

वर्तमान में, सीसीएमएंडआईपी को आईसीएआई के अखिल भारतीय सदस्यों के लिए प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, अर्थात् विदेशी मुद्रा और खजाना प्रबंध संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का संचालन करने का कार्य सौंपा गया है।

- अभी तक विदेशी मुद्रा और खजाना प्रबंध संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के 48 बैचों का संचालन किया गया है। इस अवधि के दौरान, मई-जून, 2018 के दौरान नोएडा और मुंबई में इस प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का संचालन किया गया था।
- हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, पुणे के पदधारियों के लिए, आईसीएआई द्वारा उनके साथ हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसार 12-17 मार्च, 2018 के दौरान विदेशी मुद्रा और खजाना प्रबंध संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के चरण 1 का सफलतापूर्वक संचालन किया गया था।
- प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के पूर्व बैचों के लिए 27 और 28 जनवरी, 2018 के दौरान आयोजित मूल्यांकन परीक्षा के परिणामों की घोषणा 14 मार्च, 2018 को की गई थी।

### सदस्यों की वृत्तिक अभिवृद्धि के लिए कार्यशाला/वेबकास्ट (12 फरवरी – 30 जून, 2018)

समिति ने, डब्ल्यूआईआरसी की गांधी धाम शाखा में 28 अप्रैल, 2018 को पोर्टफोलियो प्रबंधन और बीयर मार्किट में व्यापार संबंधी एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया था। “स्टॉक बाजार में निवेश करने की कला” विषय पर एक लाइव वेबकास्ट का आयोजन 1 मई, 2018 को नई दिल्ली में किया गया था।

### 5.24 इंड एस कार्यान्वयन समूह

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई), जो भारत का एक प्रमुख लेखांकन निकाय है, भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एस) को तैयार करने में लगा है। वर्ष 2011 में आईसीएआई ने इंड एस कार्यान्वयन समिति का गठन किया था, जिसे भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एस) के संबंध में सदस्यों का मार्गदर्शन उपलब्ध कराने का कार्य सौंपा गया था। परिषद् वर्ष 2018-19 के दौरान उक्त समिति को लेखांकन मानक बोर्ड के तत्वावधान में इंड एस कार्यान्वयन समूह के रूप में पुनः गठित किया गया है। इंड एस कार्यान्वयन समूह (जो तत्कालीन रूप में इंड एस कार्यान्वयन समिति के नाम से जाना जाता था, इंड एस के प्रति सुचारु अंतरण के लिए अथक प्रयास कर रहा है)।

इंड एस के उसी भावना के साथ, जिसमें उन्हें तैयार किया गया है, कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और साथ ही

सदस्यों और अन्य पणधारियों को उपयुक्त मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के विचार से, इंड एस कार्यान्वयन समूह इंड एस के संबंध में शैक्षिक सामग्रियां जारी करता है, जिनमें संबंधित इंड एस का संक्षिप्त विवरण और ऐसे मुद्दों को सम्मिलित करते हुए, जिनके मानक के कार्यान्वयन के दौरान बार-बार सामने आने की संभावना है, बहुधा पुछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) अंतर्विष्ट होते हैं। इस अवधि के दौरान, पांच (5) इंड एस के संबंध में चार (4) शैक्षिक सामग्रियां निकाली गई हैं। अभी तक बारह (12) इंड एस से संबंधित ग्यारह (11) शैक्षिक सामग्रियां जारी की गई हैं। यह समूह सभी इंड एस पर शैक्षिक सामग्रियां निकालने के लिए कार्य कर रहा है।

उपरोक्त के अलावा, समूह अपने “भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस): एक पर्यावलोकन (पुनरीक्षित 2018)” शीर्षक वाले प्रकाशन का पुनरीक्षण किया था, जिसमें आईएफआरएस अभिसरित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एस) से संबंधित विभिन्न पहलुओं को अंतर्विष्ट करने वाला पर्यावलोकन सम्मिलित है, जैसे कि कार्ययोजना, आईएफआरएस/आईएस से ली गई सामग्री, विद्यमान लेखांकन मानक के अधीन वित्तीय रिपोर्टिंग की तुलना में इंड एस के अधीन वित्तीय रिपोर्टिंग में परिवर्तन सभी इंड एस का संक्षिप्त विवरण आदि। इसमें एमसीए द्वारा मार्च, 2018 में अधिसूचित इंड एस के सभी हाल ही के संशोधनों, विशेष रूप से नए राजस्व मानक (इंड एस 115) और उसके अन्य पारिणामिक संशोधनों को भी सम्मिलित किया गया है।

जैसे ही देश में इंड एस का कार्यान्वयन आरंभ हुआ, सदस्यों, तैयार करने वाले व्यक्तियों और अन्य पणधारियों द्वारा इंड एस के लागू होने/क्रियान्वयन के संबंध में अनेक मुद्दे उठाए गए थे। समयबद्ध और त्वरित रीति में अंतरण संबंधी शंकाओं का समाधान करने के लिए एक इंड एस संपरिवर्तन सुविधा सेवा समूह (आईटीएफजी) का वर्ष 2016 में गठन किया गया था, जो समय-समय पर कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए स्पष्टीकारक बुलेटिन निकालता है। इस समूह में अकाउंटेंसी फर्मों से विशेषज्ञ, उद्योग के प्रतिनिधि और अन्य विशिष्ट वृत्तिक व्यक्ति सम्मिलित हैं। इस अवधि के दौरान, आठ (8) आईटीएफजी स्पष्टीकारक बुलेटिन जारी किए गए हैं। आज की तारीख तक, समूह ने अपने 15 स्पष्टीकारक बुलेटिनों के माध्यम से 114 मुद्दों पर स्पष्टीकरण निकाले हैं।

इसके अतिरिक्त, सदस्यों हेतु संदर्भ की सुगमता के लिए आईटीएफजी स्पष्टीकारक बुलेटिनों शीर्षक वाला एक प्रकाशन निकाला गया है, जिसमें आईटीएफजी स्पष्टीकारक बुलेटिनों के माध्यम से पूर्व में स्पष्ट किए गए सभी मुद्दों का विषयवार संकलन एक स्थान पर उपलब्ध कराया गया है।

सदस्यों के समक्ष आने वाली कठिनाईयों का यथा संभवशीघ्र समाधान करने के लिए “इंड एस के कार्यान्वयन संबंधी सहायता - पटल” को भी आरंभ किया गया था, जिसमें सदस्य अपनी शंकाओं, प्रश्नों और सुझावों को आनलाइन रूप से एक लिंक को क्लिक करके प्रस्तुत कर सकते हैं।

समूह कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का संचालन करके इंड एस के समुचित कार्यान्वयन के लिए सदस्यों और अन्य पणधारियों के ज्ञान में अभिवृद्धि करने के लिए पर्याप्त उपाय भी कर रहा है।

समूह इंड एस के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए देश भर में तथा विदेशों में भी इंड एस संबंधी 12 दिवसीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का भी संचालन करता है। इस पाठ्यक्रम की व्यापक सत्र योजना को इस विचार से तैयार किया गया है कि वह सदस्यों को इंड एस के क्षेत्र में सक्षम बनाए। इस अवधि के दौरान इंड एस संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के 29 बैचों का संचालन किया गया है, जिनमें लगभग 1200 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है। अभी तक, लगभग 8900 सदस्यों ने देश भर में और विदेशों में स्थित अवस्थानों पर इंड एस संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

समूह देश भर के विभिन्न अवस्थानों पर एक/दो दिवसीय इंड एस संबंधित जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन भी करता है। इन जागरूकता कार्यक्रमों में, आधारीक मानकों, जो इंड एस के अधीन वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा उन्हें प्रस्तुत करने के लिए भूमिका स्वरूप हैं, के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, इंड एस और विद्यमान एस के बीच अंतर को भी विनिर्दिष्ट रूप से बताया जाता है ताकि सदस्यों और पणधारियों को इस संबंध में शिक्षित किया जा सके कि इंड एस के अधीन लेखांकन किस प्रकार विद्यमान एस के अधीन किए जाने वाले लेखांकन से भिन्न होगा। इस अवधि के दौरान देश भर में इंड एस संबंधी 11 ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।

इसके अतिरिक्त, समूह विभिन्न विनियामकों, संगठनों, निगम घरानों के पदधारियों/कर्मचारियों के लिए इंड एस संबंधी घरेलू प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन करता है। इस अवधि के दौरान, भारत के नियंत्रक और

महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी), आईआरडीएआई, सीबीडीटी, विभिन्न मंत्रालयों के विभागों आदि के पदधारियों और अन्य निगम अस्तित्वों के लिए इंड एस संबंधी विभिन्न ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। इसके पश्चात्, समूह ने इंड एस के संबंध में जागरूकता का सृजन करने के अपने कार्यवृत्त के भागरूप में इंड एस संबंधी वेबकास्टों की एक श्रृंखला का भी संचालन कर रहा है, जिससे इंड एस में परिवर्तन को सुगम बनाया जा सके।

### 5.25 संपरीक्षा समिति

संपरीक्षा समिति, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सत्य और उचित हैं, आईसीएआई की वित्तीय सूचना की रिपोर्टिंग प्रक्रिया और प्रकटन का पुनर्विलोकन करती है। यह समिति आईसीएआई की विभिन्न इकाइयों के लिए संपरीक्षकों की नियुक्ति के लिए उत्तरदायी है। संपरीक्षा समिति के पास पांच प्रादेशिक संपरीक्षा समितियां भी हैं, जो इसकी प्रत्येक प्रादेशिक परिषद में अवस्थित हैं।

### 5.26 अंकीय रूपांतरण और प्रक्रिया पुनः इंजीनियरी समूह (डीटीएंडपीआरजी)

डीटीएंडपीआरजी ने छात्रों, सदस्यों और फर्मों के लिए स्वःसेवा पोर्टल का शुभारंभ किया है। आईसीएआई मोबाइल ऐप – आईसीएआई नाओ और आईसीएआई सोशल मीडिया मंच, आईसीएआई के विभिन्न आयोजनों को लोकप्रिय बनाने और इसकी प्रमुख उपलब्धियों और पहलों के बारे में छात्रों, सदस्यों और संस्थान के अन्य पणधारियों को बिना किसी लागत के अवगत कराने में उल्लेखनीय भूमिका अदा की है।

अंकीय रूपांतरण और प्रक्रिया पुनः इंजीनियरी समूह ने आईसीएआई की वेबसाइट पर सदस्यों और छात्रों के लिए पेटीएम संदाय गेटवे सेवाओं को समर्थ बनाया है, जहां नेट बैंकिंग और पेटीएम वॉलेट से संबंधित सभी प्रकार के आनलाइन संव्यवहार प्रभार एक वर्ष के लिए निःशुल्क लागत पर अनुज्ञात हैं। समूह ने सदस्यों की आय-कर विभाग/एमसीए के माध्यम से उनकी पैन संख्या को ठीक करने संबंधी मुद्दों के संबंध में सहायता की थी।

वीआईपी आवेदन के साथ सदस्यता फीस को निर्बाध रूप से एकीकृत करने संबंधी कार्यान्वयन पूरा कर दिया गया था और इसके परिणामस्वरूप विभिन्न आनलाइन सुविधाएं जैसे कि सदस्य कार्ड और फर्म के गठन संबंधी प्रमाणपत्र/फर्म कार्ड, छात्रों/सदस्यों और फर्मों के लिए आनलाइन पुनः मुद्रित पत्र सुविधा, ई-मेल आईडी और मोबाइल में परिवर्तन किए जाने की सुविधा, पते में परिवर्तन करने की सुविधा – आईसीएआई मोबाइल ऐप पर ई-सहायता और अच्छी विश्वसनीयता संबंधी प्रमाणपत्र।

### 5.27 क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड (क्यूआरबी)

क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड को केंद्रीय सरकार द्वारा 28 जून, 2007 को निम्नलिखित कृत्य करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 28क के अधीन उसमें निहित शक्तियों के अनुसरण में गठित किया गया था:—

1. परिषद् को आईसीएआई के सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की क्वालिटी के संबंध में सिफारिशें करना ;
2. आईसीएआई के सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं, जिसके अंतर्गत संपरीक्षा संबंधी सेवाएं भी हैं, की क्वालिटी का पुनर्विलोकन करना ; और
3. आईसीएआई के सदस्यों का, सेवाओं की क्वालिटी में सुधार करने और विभिन्न कानूनी तथा अन्य विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन हेतु मार्गदर्शन करना।

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 15 की उपधारा (2) के खंड (ण) के अधीन परिषद् का एक कृत्य यह है कि वह उसके द्वारा बनाए गए क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की आईसीएआई के सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की क्वालिटी के संबंध में की गई सिफारिशों पर विचार करे। पूर्वोक्त खंड (ण) यह भी उपबंध करता है कि उसकी वार्षिक रिपोर्ट में ऐसी सिफारिशों के संबंध में की गई कार्रवाईयों के ब्यौरे अपनी वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित करे। पूर्वोक्त उपबंधों के अनुसरण में, यह रिपोर्ट किया जाता है कि रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान परिषद् को सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की क्वालिटी के संबंध में क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 28ख(क) के अधीन 1 प्रतिनिर्देश प्राप्त हुआ था। उस पर परिषद् द्वारा अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018 के वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित अपनी बैठक में विचार किया गया था। इस संबंध में की गई कार्रवाई के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

1. आईसीएआई के अनुशासन तंत्र के अधीन आगे और अन्वेषण करने के लिए निदेशक (अनुशासन) को निर्दिष्ट किए गए प्रतिनिर्देशों की संख्या – 1
2. ऐसे प्रतिनिर्देशों की संख्या, जहां तकनीकी पुनर्विलोकक की टीका-टिप्पणियों को सदस्यों/फर्मों को सलाह के रूप में जारी करने का विनिश्चय किया गया था – शून्य
3. ऐसे प्रतिनिर्देशों की संख्या, जिन्हें बंद करने का विनिश्चय किया गया था – शून्य
4. परिषद् के विचारार्थ लंबित प्रतिनिर्देशों की संख्या – शून्य

## 5.28 प्रबंध समिति

प्रबंध समिति, जिसका गठन वर्ष 2015 में परिषद् की एक अस्थायी समिति के रूप में किया गया था, के उद्देश्यों में शाखाओं के सृजन, विदेशों में चैप्टरों की स्थापना, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ एमओयू/एमआरए करने, आईसीएआई के केंद्रीय संपरीक्षकों की नियुक्ति, संस्थान के वार्षिक लेखाओं, केंद्रीय सरकार और अन्य विनियामक निकायों द्वारा निर्दिष्ट मामलों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 और तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों में संशोधन के प्रस्तावों से संबंधित मामलों, प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं से संबंधित मामलों, सदस्यों/सीए फर्मों/एलएलपी /विलयनों/निर्विलयनों/ नेटवर्किंग संबंधी मामलों और संस्थान की अन्य समितियों/विभागों से प्राप्त ऐसे प्रस्तावों, जिनमें प्रशासनिक और नीतिगत विवक्षाएं अंतर्बलित हैं, पर विचार करना और जहां कहीं अपेक्षित हो, परिषद् को अपनी सिफारिशें करना भी सम्मिलित है।

## 5.29 युवा सदस्य कौशल और नवीनता विकास समिति (वाईएमएसएंडआईडीसी)

आईसीएआई के लघु और मध्यम व्यवसायियों की सक्षमता निर्माण संबंधी समिति के तत्वावधान में युवा सदस्य सशक्तिकरण समूह को वर्ष 2018-19 के दौरान युवा सदस्य कौशल और नवीनता विकास समिति (वाईएमएसएंडआईडीसी) के रूप में पुनः गठित किया गया है।

### 1 अप्रैल, 2017 से 30 जून, 2018 के दौरान क्रियाकलाप

#### संगोष्ठियां/कार्यशालाएं/सम्मेलन/आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम/ वेबकास्ट :

समिति ने देश भर में ऐसे उभरते विषयों पर, जैसे कि स्टार्ट अप और उद्यमशीलता, जीएसटी, आय प्रकटन स्कीम, न्यायालयीन संपरीक्षा, आय-कर, ई-वाणिज्य और क्लाउड संगणना, आईसीडीएस और अपीलों, अंतर व्यक्ति कौशल और सार्वजनिक भाषण को तैयार करना आदि के संबंध में 19 कार्यक्रमों, एक आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और एक वेबकास्ट का आयोजन किया था। 23 मई, 2017 को नई दिल्ली में उद्यमशीलता और लोक सेवा में लगे सदस्यों संबंधी समिति के साथ संयुक्त रूप से “युवा चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए सिविल सेवा में अवसर” विषय पर एक वेबकास्ट का आयोजन किया गया था।

## 5.30 मूल्यांकन मानक बोर्ड

समय-समय पर निर्वचनों, मार्गदर्शन और तकनीकी सामग्री उपलब्ध कराने के लिए और मानकों का कार्यान्वयन करने के लिए मूल्यांकन मानकों को जारी करने पर ध्यान केंद्रित करने हेतु मूल्यांकन मानक बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड ऐसे क्षेत्रों के बारे में सुझाव देगा, जिनमें भारतीय मूल्यांकन मानकों (इंड वीएस) को विकसित किए जाने की आवश्यकता है।

### 1. भारतीय मूल्यांकनों की विरचना

संगत, एकसमान और पारदर्शी मूल्यांकन नीतियों को बनाए रखने और भारत में प्रयोग किए जाने वाले विविध व्यवहारों को सुमेलित करने की आवश्यकता को मान्यता प्रदान करते हुए, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) की परिषद् ने मूल्यांकन मानकों को जारी किया है, जो भारत में अपनी किस्म के प्रथम हैं।

व्यवसाय के इस मूल क्षेत्र में सर्वोत्तम व्यवहारों का संवर्धन करने के विचार से ये मानक चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए एक ढांचा अधिकथित करते हैं, जिससे मूल्यांकन परिणाम की उपधारणा और क्वालिटी में एकसमानता सुनिश्चित की जा सके। आईसीएआई द्वारा निम्नलिखित मूल्यांकन मानक जारी किए गए हैं :--

- भारतीय मूल्यांकन मानकों के लिए प्रस्तावना
- भारतीय मूल्यांकन मानकों के अनुसार मूल्यांकन रिपोर्ट को तैयार करने के लिए ढांचा
- भारतीय मूल्यांकन मानक 101 - परिभाषाएं
- भारतीय मूल्यांकन मानक 102 - मूल्यांकन आधार
- भारतीय मूल्यांकन मानक 103 – मूल्यांकन उपधारणा और पद्धति
- भारतीय मूल्यांकन मानक 201 - कार्य, विश्लेषण और मूल्यांकन का विस्तार क्षेत्र
- भारतीय मूल्यांकन मानक 202 - रिपोर्टिंग और दस्तावेज़ीकरण
- भारतीय मूल्यांकन मानक 301 – कारबार मूल्यांकन
- भारतीय मूल्यांकन मानक 302 - अमूर्त आस्तियां
- भारतीय मूल्यांकन मानक 303 - वित्तीय लिखतें।

ये भारतीय मूल्यांकन मानक, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन आज्ञापक आधार पर मूल्यांकन संबंधी नियोजनों के लिए लागू होंगे। आय-कर, सेबी, फेमा आदि जैसे अन्य कानूनों के अधीन मूल्यांकन संबंधी नियोजनों के संबंध में ये मानक संस्थान के सदस्यों के लिए सिफारिशात्मक आधार पर लागू होंगे। ये मूल्यांकन मानक 1 जुलाई, 2018 को या उसके पश्चात् जारी मूल्यांकन रिपोर्टों के लिए प्रभावी होंगे।

मूल्यांकन मानक तैयार करते समय, आईसीएआई ने भारत में और साथ ही पूरे विश्व में अनुसरित किए जाने वाले सर्वोत्तम व्यवहारों, भारतीय परिस्थितियों की विशिष्टता, भारत में विद्यमान व्यवहार, उनके फायदों और नुकसानों सहित तथा ऐसे विभिन्न प्रयोजनों को विचार में लिया था, जिनके लिए कंपनी अधिनियम की अपेक्षाओं से परे मूल्यांकन की अपेक्षा की जा सकती है।

ये मानक आईसीएआई के, उसके सदस्यों के लिए उच्च क्वालिटी के कार्य और मानकों को सुनिश्चित करने हेतु उनका मार्गदर्शन करने के सतत अभियान के परिणामस्वरूप सामने आए हैं।

ये भारतीय मूल्यांकन मानक तब तक प्रभावी रहेंगे, जब तक कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2018 के नियम 18 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा मूल्यांकन मानकों को अधिसूचित किया जाता है।

### **मूल्यांकन और रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों संबंधी राष्ट्रीय संगोष्ठी**

जनवरी, 2018 में हाल ही में हुए विनियामक परिवर्तनों में मूल्यांककों की भूमिका और मूल्यांकन से संबंधित विभिन्न जटिलताओं के संबंध में विचार-विमर्श करने के लिए मूल्यांकन और रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संबंधी राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों की नई अवधारणा को प्रारंभ किए जाने के साथ ही, मूल्यांकन वृत्ति को बढ़ावा मिलेगा और यह सदस्यों के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण वृत्तिक अवसर साबित होगा।

### **कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन प्रारूप कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के संबंध में गोलमेज विचार-विमर्श**

बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 247 के अधीन रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों और मूल्यांकन संबंधी प्रारूप नियमों के प्रति प्राप्त हुए सुझावों पर विचार करने के लिए जून, 2017 मास में चेन्नई, बंगलौर और मुंबई में गोलमेज विचार-विमर्शों का आयोजन किया था, ताकि उन्हें आगे कारपोरेट कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत किया जा सके।

मुंबई में कंपनी अधिनियम, 2013 रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों और मूल्यांकन संबंधी प्रारूप नियमों के प्रति प्राप्त हुए सुझावों पर विचार करने के लिए आईएनएसओएल इंडिया और एसआईपीआई के साथ संयुक्त रूप से एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था।

### मूल्यांकक संगठन और वृत्तिक संस्थानों के साथ आईबीबीआई द्वारा एक परस्पर क्रियाशील सत्र

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) द्वारा मूल्यांकक संगठनों और वृत्तिक संस्थानों के साथ मूल्यांकक वृत्तिक संगठनों (वीपीओ) और नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों की भूमिका, वीपीओ और मूल्यांककों द्वारा की जाने वाली तैयारियों, पाठ्यचर्या और परीक्षा, आरवीओ द्वारा शैक्षिक पाठ्यक्रमों तथा मूल्यांककों और आरवीओ की मानीटरी के संबंध में विचार-विमर्श करने के लिए परस्पर क्रियाशील सत्र का आयोजन किया था। साथ ही, प्रतिभूतियों या वित्तीय आस्तियों का मूल्यांकन या फर्मों का मूल्यांकन करने की प्रक्रियाओं/पद्धतियों के संबंध में भी एक प्रस्तुतिकरण किया गया था।

### कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी प्रारूप कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के संबंध में सुझाव प्रस्तुत किया जाना

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने आईसीएआई से यह अनुरोध किया था कि वह रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों और मूल्यांकन संबंधी प्रारूप नियमों पर अपने सुझाव प्रस्तुत करे। प्रारूप कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के संबंध में 30 जून, 2017 को कारपोरेट कार्य मंत्रालय को सुझाव प्रस्तुत किए गए थे।

### 5.31 कराधान संपरीक्षा पुनर्विलोकन बोर्ड

परिषद् ने परिषद् वर्ष, 2018-19 में, अपनी एक अस्थायी समिति के रूप में कर निर्धारण पुनर्विलोकन बोर्ड का गठन किया है। 'कर निर्धारण पुनर्विलोकन बोर्ड' के रूप में गठित बोर्ड का नाम परिषद् द्वारा बदल कर 'कराधान संपरीक्षा पुनर्विलोकन बोर्ड' कर दिया गया था।

#### बोर्ड के उद्देश्य

बोर्ड का कार्य विभिन्न कराधान विधियों (प्रत्यक्ष और साथ ही अप्रत्यक्ष, दोनों) के अधीन विहित रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाओं के अनुपालन का पुनर्विलोकन करना है।

तदनुसार, बोर्ड आय-कर अधिनियम, 1961 और तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन विहित किसी रिपोर्ट का पुनर्विलोकन करेगा और साथ ही ऐसी किसी रिपोर्ट का भी निम्नलिखित के संबंध में यथासंभव रूप से अवधारण करने के विचार से पुनर्विलोकन करेगा, जिसे माल और सेवा कर विधि सहित अप्रत्यक्ष कर विधियों के अधीन विहित किया गया है और जिन्हें किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किया गया है :

- (क) आय-कर अधिनियम, 1961 और तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन विहित रिपोर्टिंग अपेक्षाओं का अनुपालन ;
- (ख) माल और सेवा कर विधि सहित अप्रत्यक्ष कर विधियों के अधीन विहित रिपोर्टिंग अपेक्षाओं का अनुपालन ; और
- (ग) आईसीएआई की संबंधित उद्घोषणाओं, मार्गदर्शक टिप्पणों का अनुपालन।

बोर्ड आय-कर अधिनियम, 1961 और तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन विहित किसी रिपोर्टों का और माल और सेवा कर विधि सहित अप्रत्यक्ष कर विधियों के अधीन विहित विभिन्न रिपोर्टों का, स्व:विवेकानुसार या उसे किसी विनियामक निकाय, जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत के नियंत्रण और महालेखापरीक्षक, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड, राज्य वाणिज्यिक कर विभागों आदि द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली रिपोर्टों का पुनर्विलोकन कर सकेगा। बोर्ड, ऐसे उद्यमों की रिपोर्टों का भी पुनर्विलोकन कर सकेगा, जिनके संबंध में मीडिया रिपोर्टों द्वारा कराधान संबंधी मामलों (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर) में गंभीर अनियमितताओं के बारे में रिपोर्ट किया गया है।

यह परिकल्पना की गई है कि बोर्ड द्वारा किए जाने वाले पुनर्विलोकन, यह सुनिश्चित करेंगे कि सदस्य, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान के अधीन विहित विभिन्न रिपोर्टों को प्रमाणन करते समय और अधिक तत्परता का प्रयोग करेंगे और यह दीर्घावधि में उनके द्वारा की जाने वाली सकल रिपोर्टिंग और प्रमाणन में सुधार लाएगा।

#### उद्यमों का चयन

बोर्ड ने स्व:विवेकानुसार, निर्धारण वर्ष, 2017-18 से संबंधित कर संपरीक्षा रिपोर्टों का पुनर्विलोकन करने के लिए परिषद् वर्ष 2018-19 के लिए 100 कंपनियों का चयन किया है। इस संबंध में, कर संपरीक्षकों से 88 कर संपरीक्षा रिपोर्टें प्राप्त की गई हैं।

## तकनीकी पुनर्विलोककों को पैलबद्ध करना

प्रथम टियर पुनर्विलोकन का संचालन करने के लिए, बोर्ड ऐसे तकनीकी पुनर्विलोककों को पैलबद्ध करने के लिए कार्यवाही कर रहा है, जिनके पास कराधान (प्रत्यक्ष और साथ ही अप्रत्यक्ष, दोनों) में विशेषज्ञता है और जो ब्यौरेवार पुनर्विलोकन कर सकते हैं। इस संबंध में, ऐसे सदस्यों को, जो बोर्ड के साथ तकनीकी पुनर्विलोककों के रूप में स्वयं को पैलबद्ध करने के लिए अवधारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, आमंत्रित करते हुए आईसीएआई की वेबसाइट पर एक उद्घोषणा रखी गई थी, जिसके द्वारा उनसे उक्त प्रयोजन के लिए तैयार किए गए आनलाइन पैलबद्ध किए जाने संबंधी प्ररूप को भरा जाना अपेक्षित है।

## 6. अंतरराष्ट्रीय कार्य समिति (आईसीएएन)

### मुख्य रिपोर्ट के लिए क्रियाकलाप

#### (i) विदेशों में वृत्तिक अवसरों की मान्यता हेतु आईसीएआई की पहलें

- **आईसीएएन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर :** आईसीएआई ने नेपाल के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएएन) के साथ 23 अगस्त, 2017 को एक परस्पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे लेखांकन और संबद्ध क्षेत्रों के विकास के लिए परस्पर सहयोग को स्थापित किया जा सके। सीए निलेश एस विक्रमसे, तत्कालीन अध्यक्ष, आईसीएआई और सीए नवीन एन.डी. गुप्ता, तत्कालीन उपाध्यक्ष, आईसीएआई, इस अवसर पर आईसीएआई की ओर से और आईसीएएन की ओर से सीए प्रकाश जंग थापा, अध्यक्ष, आईसीएएन और सीए जगन्नाथ उपाध्याय, उपाध्यक्ष, आईसीएएन उपस्थित हुए थे।
- **एसएआईसीए के साथ एमआरए :** आईसीएआई और दक्षिण अफ्रीकी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (एसएआईसीए) के बीच जोहान्सबर्ग में 4 जून 2018 को, आईसीएआई के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और डॉ. के.जे. श्रीनिवास, माननीय कौंसल जनरल, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका की उपस्थिति में एक एमआरए पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस एमआरए का उद्देश्य लेखांकन संबंधी ज्ञान, वृत्तिक और बौद्धिक विकास, उनके अपने-अपने सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि और दक्षिण अफ्रीका और भारत में लेखांकन वृत्ति के विकास के संबंध में सकारात्मक योगदान देने के लिए परस्पर सहयोग का ढांचा स्थापित करना है।
- **आईआईआरसी की सदस्यता :** अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत रिपोर्टिंग परिषद् (आईआईआरसी) विनियामकों, निवेशकों, कंपनियों, मानक निर्धारकों, लेखांकन वृत्ति और गैर सरकारी संगठनों का एक वैश्विक गठबंधन है। आईसीएआई ने वर्ष 2017 में आईआईआरसी की सदस्यता प्राप्त की थी, जिसमें पदासीन अध्यक्ष आईआईआरसी की परिषद में आईसीएआई का प्रतिनिधित्व करेंगे।

### आईसीएआई का अंतरराष्ट्रीय निकायों में प्रतिनिधित्व

- सीए एस बी जवारे, परिषद् सदस्य, आईसीएआई को नवंबर 2017 से आरंभ होने वाली दो वर्ष की अवधि के लिए एशियाई ओशनियन मानक निर्धारक समूह (एओएसएसजी) का उपाध्यक्ष चुना गया था।
- सीए मनोज फडनीस, पूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई को नवंबर 2017 से आरंभ होने वाली दो वर्षों की अवधि के लिए एशियाई और प्रशांत क्षेत्र के अकाउंटेंटों की कन्फेडरेशन (सीएपीए) का अध्यक्ष चुना गया है।
- सीए प्रफुल्ल छाजेड, उपाध्यक्ष, आईसीएआई को सीएपीए की पब्लिक क्षेत्र वित्तीय प्रबंध समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है।
- सीए नवीन एन.डी. गुप्ता, पदासीन अध्यक्ष सीएपीए के बोर्ड सदस्य हैं।
- सीए जी. शेखर, परिषद् सदस्य, आईसीएआई को 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2019 तक की तीन वर्ष की अवधि के लिए आईएफएसी के अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन शिक्षा मानक बोर्ड के परामर्शी सलाहकारी समूह में सीएपीए के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है।
- पदासीन अध्यक्ष, आईआईआरसी परिषद के सदस्य हैं।

**मलेशिया (कुआलालम्पुर) में आईसीएआई के 32वें चैप्टर का उद्घाटन :** आईसीएआई की परिषद ने मलेशिया में उसके 32वें चैप्टर को खोले जाने का अनुमोदन किया है, जिसका उद्घाटन 5 जुलाई 2018 को किया गया था। आईसीएआई की



प्रबंध समिति ने टोक्यो (जापान) में 33वें चैप्टर का सृजन करने का अनुमोदन कर दिया है, जिसका उद्घाटन शीघ्र ही किया जाएगा।

**सीए एएनजेड द्वारा आईसीएआई सदस्यों के लिए एकपक्षीय सदस्यता स्कीम का प्रस्ताव :** आईसीएआई ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के चार्टर्ड अकाउंटेंटों (सीए एएनजेड) के साथ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में स्थित आईसीएआई के सदस्यों के लिए एक एकपक्षीय ठहराव, अर्थात् पायलट इंटरनेशनल पाथवे स्कीम के संबंध में हस्ताक्षर किए हैं। उक्त पाथवे कार्यक्रम प्रस्तावित एमओयू के अतिरिक्त है, जो अनुमोदन हेतु सरकार के विचाराधीन है।

इस स्कीम के माध्यम से, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में स्थित आईसीएआई के सदस्य, आईसीएआई की सदस्यता के अतिरिक्त, एक 40 घंटे के स्व-अध्ययन कार्यक्रम को पूरा करके तथा एक दो दिवसीय कार्यशाला में भाग लेकर एक मास से भी कम समय में सीए – एएनजेड की सदस्यता प्राप्त कर सकेंगे। इसमें भाग लेने वाले सदस्यों का मूल्यांकन कार्यशाला के दौरान मौखिक और लिखित निर्धारणों के माध्यम से किया जाएगा।

**मई और जून 2018 में आईसीएआई-सीपीए ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्यशाला-सह-सूचना सत्र का आयोजन :** आईसीएआई और सीपीए ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त रूप से मई, 2018 में नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु तथा जून, 2018 में नई दिल्ली, मुंबई, इंदौर, लुधियाना और हैदराबाद में कार्यशालाओं की एक श्रृंखला का आयोजन किया था, जिनमें आईएफआरएस का पर्यावलोकन उपलब्ध कराया था। मई, 2018 में आयोजित संयुक्त कार्यशाला-सह-सूचना सत्रों का समन्वयन इंड एएस कार्यान्वयन समूह और सीपीई समिति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कार्य समिति के साथ संयुक्त रूप से किया गया था।

**आईसीएआई द्वारा मुंबई में अकाउंटेंटों की 21वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी :** आईएफएसी के तत्वावधान में प्रत्येक चार वर्ष में अकाउंटेंटों की विश्व कांग्रेस (डब्ल्यूसीओए), जो लेखांकन वृत्ति के लिए एक विश्वव्यापी संगठन है, का आयोजन किया जाता है और जो लेखांकन वृत्ति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण वैश्विक आयोजनों में से एक है, जहां लगभग 6000 प्रतिनिधि इकट्ठा होते हैं और लेखांकन तथा संबद्ध क्षेत्रों के संबंध में विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। आईसीएआई ने बोली जीती थी और इस प्रकार वह मुंबई में वर्ष, 2022 में 21वें डब्ल्यूसीओए की मेजबानी करेगा, जिससे आईसीएआई और साथ ही राष्ट्र को अपने ब्रांड में अभिवृद्धि करने और उसका संवर्धन करने में सहायता प्राप्त होगी। 2022 में डब्ल्यूसीओए की भारत में मेजबानी भारत जैसे विकासशील देशों के महत्व को दर्शित करेगी।

## (ii) प्रतिनिधि मंडलों के दौर

- आईआईआरसी के एक प्रतिनिधिमंडल ने 19 जुलाई 2017 को, अनन्यता के पैरामीटरों सहित भारत में आईसीएआई की एक प्रमुख नीतिगत भागीदार के रूप में भूमिका पर चर्चा करने के लिए आईसीएआई का दौरा किया।
- सुश्री ताशिया बैटस्टोन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सीपीए कनाडा ने 15 सितंबर, 2017 को, आईसीएआई और सीपीए कनाडा के बीच हस्ताक्षरित किए जाने वाले समझौता ज्ञापन की प्रास्थिति पर विचार-विमर्श करने और सीपीए कनाडा के लेखा और वित्त में अग्रिम प्रमाणपत्र संबंधी योजनाओं पर विचार करने के लिए आईसीएआई का दौरा किया।
- डॉ. स्टाव्रोस थॉमडाकिस, अध्यक्ष, आईईएसबीए (अंतर्राष्ट्रीय नैतिक मानक बोर्ड), और श्री केन सिऑंग, तकनीकी निदेशक आईईएसबीए ने 2-3 नवंबर 2017 के दौरान आईसीएआई का दौरा किया। उन्होंने आईसीएआई की परिषद को भी संबोधित किया और साथ ही आईईएसबीए की नैतिक संहिता में प्रस्तावित पुनरीक्षण के संबंध में एक लाइव वेबकास्ट के माध्यम से सदस्यों को भी संबोधित किया।
- आईएफएसी से एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें उसकी अध्यक्ष सुश्री रैचल ग्रिम्स, कार्यपालक निदेशक सुश्री सिल्विया त्सेन और संसूचना के अध्यक्ष श्री टोनी मिरांडा ने मुंबई में आयोजित आईसीएआई के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया। उन्होंने एमसीए के सचिव, अपर लेखा महानियंत्रक और उप नियंत्रक और लेखा महापरीक्षक के साथ 6 दिसंबर 2017 को बैठकें की थीं। 7 दिसंबर को प्रतिनिधिमंडल मुंबई गया और उसने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, सेबी के अध्यक्ष और सेबी के कार्यपालक निदेशक से मुलाकात की।

- श्री लेस्ली लियो, विकास प्रबंधक, सीपीए ऑस्ट्रेलिया और सुश्री प्रीती डंग, कारबार अध्यक्ष, वृत्तिक कनेक्ट ने 15 जनवरी, 2018 को, एक विशेष मॉड्यूल को विकसित करने हेतु पद्धतियों पर परिचर्चा करने तथा पेपरवार छूट के आधार पर अर्ध-अर्हित सीए के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संभावना का पता लगाने के लिए आईसीएआई का दौरा किया।
- श्री नसिर एच. अल रावाही, उपाध्यक्ष, ओमान, स्टेट ऑडिट इंस्टीट्यूशन ने आईसीएआई का दौरा किया और उन्होंने आईसीएआई से यह अनुरोध किया कि वह लेखांकन और संपरीक्षा के क्षेत्रों में ओमान, स्टेट ऑडिट इंस्टीट्यूशन के पदधारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था करे। श्री रावाही ने 8-9 दिसंबर, 2017 के दौरान मुंबई में आयोजित आईसीएआई की अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भी भाग लिया था।
- श्री अब्दुलवाहिद आबू, पूर्व सदस्य, आईएफएसी एसएमपी समिति ने 13-23 अप्रैल के दौरान भारत का दौरा किया और भारत में एसएमपी के सक्षमता निर्माण के संबंध में दिल्ली, जयपुर और मुंबई में सदस्यों को संबोधित किया। व्याख्यानों का समन्वय आईसीएआई की सेवारत सदस्यों की सक्षमता निर्माण समिति द्वारा किया गया था।
- आईएफएसी के एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें सुश्री रैचल ग्रिम्स, अध्यक्ष, आईएफएसी, श्री फैजुल चौधरी, सीईओ, आईएफएसी और डॉ. गैरी फलुग्राथ, वरिष्ठ निदेशक (लोक नीति और विनियमन), आईएफएसी ने 1-2 जून, 2018 के दौरान क्रमशः दिल्ली और मुंबई का, भारत में डब्लूसीओए 2022 की मेजबानी के स्थल का दौरा और निरीक्षण करने के लिए दौरा किया।

### (iii) सम्मेलन / कार्यक्रम

**मुंबई में ईईजी की बैठक :** अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आईएसबी) ने, वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी ऐसे मुद्दों, जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए विशेष महत्व रखते हैं, का समाधान करने में सहायता करने के लिए उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह (ईईजी) का गठन किया था। आईसीएआई ने 8-9 मई, 2017 के दौरान मुंबई में 13वीं ईईजी बैठक की मेजबानी की। इसके साथ ही, आईएफआरएस (इंड एसएस), सेवा रियायत ठहरावों के संबंध में चुनौतियां का सामना करने और इंड एसएस 109 के अधीन आशयित प्रत्यय हानि माडल के संबंध में एक अर्ध-दिवसीय आईसीएआई – ईईजी संयुक्त पणधारी संगोष्ठी का आयोजन किया था।

**मुंबई में सीएडब्ल्यू आयोजन :** आईसीएआई, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वर्ल्डवाइड का एक सदस्य है और उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वर्ल्डवाइड (सीएडब्ल्यू) के सहयोग से, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स : नए युग के लिए तैयारी विषय पर 30 अगस्त, 2017 को एक आईसीएआई – सीएडब्ल्यू सदस्यों के लिए एक आयोजन किया था। इस आयोजन के दौरान, दो सत्रों, अर्थात् अंकीय संपरिवर्तन और लेखांकन वृत्ति के लिए संगतता और वैश्विक रूप से कार्य करना – एक सीएडब्ल्यू मंच परिप्रेक्ष्य के संबंध में विचार-विमर्श किया गया था। आईसीएआई ने सीएडब्ल्यू की बोर्ड बैठक की भी मेजबानी की थी, जहां आयरलैंड, आईसीएडब्ल्यू, सिंगापुर, बांग्लादेश, इंडोनेशिया के सीईओ ने भाग लिया था और सीए ब्रांड की नेटवर्किंग, संवर्धन और वृत्तिक निकायों की सदस्यता को पुनः प्राप्त करने पर विचार-विमर्श किया था।

**मुंबई में आईसीएआई का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 2017 :** 'लेखांकन वृत्ति' : आज के डिजिटल युग में अभिसारिता और संवहनीयता विषय पर आईसीएआई के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन 8 दिसंबर, 2017 को देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में सुश्री रैचल ग्रिम्स, आईएफएसी की अध्यक्ष द्वारा सीए मनोज फडनीस, अध्यक्ष सीएपीए, श्री निक पार्कर, अध्यक्ष, आईसीएडब्ल्यू, सुश्री जॉय थामस, अध्यक्ष, सीपीए कनाडा और श्री नसीर अल रावाही, उपाध्यक्ष, ओमान स्टेट ऑडिट इंस्टीट्यूशन की उपस्थिति में किया गया था।

**मुंबई में दो दिवसीय आईएफएसएस बैठक :** आईसीएआई ने 12-13 अप्रैल, 2018 के दौरान मुंबई में, लेखांकन मानकों के उभरते प्रतिमान के संबंध में परिचर्चा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक निर्धारकों के मंच (आईएफएसएस) की एक दो दिवसीय की मेजबानी की थी। अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक निर्धारकों के मंच (आईएफएसएस), जो पूर्व में राष्ट्रीय मानक निर्धारक (एनएसएस) के नाम से ज्ञात था, विश्व भर से राष्ट्रीय लेखांकन मानक निर्धारकों और साथ ही ऐसे अन्य संगठनों का एक समूह है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित मुद्दों में गहन रूप से सम्मिलित हैं।

**(iv) अविकसित देशों को तकनीकी सहायता**

**सक्षमता निर्माण में सीपीए अफगानिस्तान को आईसीएआई का समर्थन :** आईसीएआई ने सीपीए अफगानिस्तान के अनुरोध पर, 2-6 अगस्त, 2017 के दौरान नई दिल्ली में सीपीए अफगानिस्तान के 31 प्रतिनिधियों को सक्षमता निर्माण में प्रशिक्षण उपलब्ध कराया था। आईसीएआई ने एसएएफए की सहबद्ध सदस्यता प्राप्त करने के लिए समर्थ पत्र उपलब्ध कराके भी सीपीए अफगानिस्तान की सहायता की है। आईसीएआई और सीपीए अफगानिस्तान ने लेखांकन और संबद्ध क्षेत्रों में परस्पर सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर करने के लिए सहमति दी है। यह समझौता ज्ञापन कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष लंबित है।

**तकनीकी सहयोग के लिए करार:** आईसीएआई सदस्य प्रबंध, वृत्तिक आचार, तकनीकी अनुसंधान सतत वृत्तिक विकास, वृत्तिक लेखांकन प्रशिक्षण, संपरीक्षा क्वालिटी मानीटरी, लेखांकन ज्ञान को बढ़ावा देने, वृत्तिक और बौद्धिक विकास के क्षेत्रों में निम्नलिखित संस्थानों के साथ परस्पर सहयोग स्थापित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर करने जा रहा है और ये एमओयू अनुमोदनार्थ कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष लंबित हैं।

- नेशनल बोर्ड ऑफ अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर (एनबीएए), तंजानिया
- इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ऑफ कीनिया (आईसीपीएके)
- साऊदी आर्गनाइजेशन फार सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स (एसओसीपीए)
- बहरीन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस (बीआईबीएफ), बहरीन

**(v) रचना खंडों के लिए कार्यकरण**

**वैश्विक ई-किटों का पुनरीक्षण :** आईसीएआई वैश्विक कैरियर ई-किटों का सृजन करने की पहल परिषद् वर्ष 2014-15 में की गई थी और तब से ई-किटों को प्रत्येक वर्ष, चैप्टरों, संबंधित अधिकारिताओं, एमओयू/ एमआरए के ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाले सूचना संसाधन, विदेशों में स्थित सदस्य/छात्रों के लिए एफओक्यू और आर्टिकलशिप प्रशिक्षण से संबंधित अद्यतन जानकारी को सम्मिलित करने के लिए पुनरीक्षित किया जा रहा है। समिति ने चालू परिषद् वर्ष के दौरान आईसीएआई के 12 चैप्टरों को सम्मिलित करने वाली सभी 9 ई-किटों को पुनरीक्षित किया था और अद्यतन बनाया था।

**आईसीएआई के सर्वोत्तम चैप्टर पुरस्कार के लिए क्रियाकलाप संबंधी रिपोर्ट के मानदंड का पुनरीक्षण :** अंतर्राष्ट्रीय कार्य समिति, चैप्टरों को और अधिक सक्रिय होने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सर्वोत्तम चैप्टर पुरस्कारों को आयोजन करती है, ये पुरस्कार चैप्टरों की, चार्टर्ड लेखांकन वृत्ति को अग्रसर करने में किए जाने वाले विशिष्ट प्रयासों और उदाहरणात्मक उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हैं। वर्ष 2017 में आईसीएआई ने इस मानदंड का पुनर्विलोकन किया था और उसमें कतिपय उपांतरण किए थे, जिससे कि चैप्टर के ब्रांड सीए भारत का संवर्धन करने संबंधी प्रयासों; नियोजन सृजित करने में उनकी भूमिका और औद्योगिक प्रशिक्षण संबंधी अवसरों को प्रदान करने से संबंधित क्षेत्रों में किए जाने वाले प्रयासों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा सके। अन्य कारकों को भी और अधिक परिमाणात्मक बनाया गया है।

**7. अन्य क्रियाकलाप****7.1 प्रबंध लेखांकन संबंधी समिति****वृत्ति के लिए पहले**

- समिति ने 24 जून, 2017 को मुंबई और दिल्ली में कारबार वित्त में मास्टर संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (एमबीएफ) के ग्याहवें बैच का आयोजन किया था। उसने अगस्त और नवंबर, 2017 मासों के दौरान कारबार वित्त में मास्टर संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों के लिए दो आवासीय कार्यक्रमों का आयोजन भी किया था। समिति ने मई-जून, 2018 के दौरान कारबार वित्त में मास्टर संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों के लिए सभी तीन स्तरों की परीक्षा का भी आयोजन किया था, जहां प्रत्येक स्तर में दो पेपर अंतर्विष्ट थे।

**राष्ट्र निर्माण में भागीदारी**

- समिति ने अगस्त और नवंबर, 2016 मासों तथा जनवरी और मार्च, 2018 मासों के दौरान एचपीसीएल के सीए कार्यपालकों के लिए प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के तीसरे बैच का आयोजन किया था।

- समिति ने क्रमशः नवंबर, 2017, जनवरी, 2018 और मार्च, 2018 के दौरान प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों के लिए सभी तीन स्तरों की परीक्षा का भी आयोजन किया था, जहां प्रत्येक स्तर में दो पेपर अंतर्विष्ट थे।

### उद्योग/निगम पहलें/कार्यक्रम

- समिति ने 10 नवंबर, 2017 को मुंबई में फिनोवेट इंडिया : भारत में वित्तीय नवीनता और आगे की राह विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी द्वारा की गई थी। समिति ने एशिया के एक प्रमुख वित्तीय आयोजन, एशियाई वित्तीय मंच (एएफएफ) में भाग लेने के लिए 15-16 जनवरी, 2018 के दौरान हांगकांग के एक दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन दौरे का आयोजन किया था।

### 7.2 उद्यमों और लोक सेवा में लगे सदस्यों संबंधी समिति (सीएमईएंडपीएस)

सीएमईएंडपीएस का उद्देश्य, आईसीएआई और उद्यमों या लोक सेवा में लगे सदस्यों के बीच परस्पर फायदाप्रद लाईव संबंध स्थापित करना तथा ऐसे सदस्यों और साथ ही संस्थान के अन्य सदस्यों के परस्पर फायदे के पहलुओं का पता लगाने और उन्हें वास्तविक बनाने हेतु कार्य करना है। यह युवा चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए अतिरिक्त अवसरों का सृजन करने और उन्हें जागरूक बनाने में भी सहायता करेगी और इस प्रकार वृत्ति को अग्रसर करने के प्रति अपना सहयोग देगी।

**नई दिल्ली में लोक सेवा में आईसीएआई के सदस्यों की क्षेत्रीय बैठक:** लोक सेवा में लगे सदस्यों से लेखांकन वृत्ति से सुसंगत विभिन्न उभरते मुद्दों के संबंध में मत प्राप्त करने के संबंध में आईसीएआई की उद्यमों और लोक सेवा में लगे सदस्यों संबंधी समिति (सीएमईएंडपीएस) ने 12 अप्रैल, 2017 को दिल्ली में लोक सेवा में आईसीएआई के सदस्यों की एक क्षेत्रीय बैठक को आयोजित किया था।

इस बैठक में लोक सेवा में लगे वृत्ति के 16 वरिष्ठ सदस्यों ने भाग लिया था, जिनमें सीए के. रहमान खान, माननीय संसद सदस्य, राज्य सभा, सीए. सुभाष चंद्र बहेरिया, भीलवाड़ा से माननीय संसद सदस्य, न्यायमूर्ति (सीए) अनिल आर. दवे, माननीय सेवानिवृत्त न्यायाधीश, भारत का उच्चतम न्यायालय सम्मिलित थे। सदस्यों ने आईसीएआई की छवि को अग्रसर करने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में विचारों का आदान-प्रदान किया था जिनके अंतर्गत पीआर को सुदृढ़ करना, सरकारी विभागों की, प्रोदभवन लेखांकन में सपरिवर्तन में सहायता करना, जीएसटी कार्यान्वयन और जागरूकता संबंधी पहलें और अन्य समान विषय भी थे।

**युवा चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए सिविल सेवाओं में अवसरों संबंधी लाइव वेबकास्ट:** सीएमईपीएस ने, आईसीएआई की व्यवसायगत सदस्यों की सक्षमता निर्माण संबंधी समिति (सीसीबीएमपी) के युवा सदस्य सशक्तिकरण समूह के साथ संयुक्त रूप से 13 मई, 2017 को नई दिल्ली में युवा चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए सिविल सेवाओं में अवसरों संबंधी एक लाइव वेबकास्ट का आयोजन किया था।

सीए. महावीर सिंघवी, आईएफएस, संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय ने इस परिचर्चा का संचालन किया था। सीए. रविन्द्र, आईएएस मंत्री के निजी सचिव, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय तथा सीए. नमित मेहता, आईएएस, अपर आयुक्त बैठ, जयपुर इस सत्र के दौरान पैनल वार्ताकार थे। इस वेबकास्ट का उद्देश्य हमारे ऐसे युवा चार्टर्ड अकाउंटेंटों को प्रोत्साहित करना था, जो सिविल सेवाओं में प्रवेश पाने के लिए इच्छुक हैं। इस वेबकास्ट को आईसीएआई के 550 से अधिक सदस्यों द्वारा देखा गया था।

**कोलकाता में लोक सेवा में आईसीएआई के सदस्यों की क्षेत्रीय बैठक:** सीएमईपीएस ने 22 जून, 2017 को कोलकाता में लोक सेवा में आईसीएआई के सदस्यों की एक अन्य क्षेत्रीय बैठक का आयोजन किया था, जिसमें लोक सेवा में लगे वृत्ति के नौ वरिष्ठ सदस्यों ने भाग लिया था, जिन्होंने आईसीएआई की छवि को अग्रसर करने के लिए विभिन्न सुसंगत वृत्तिक मुद्दों के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए थे।

**पुरी में लोक सेवा में आईसीएआई के सदस्यों का आवासीय शिखर सम्मेलन:** राष्ट्रीय महत्व के ऐसे मुद्दों, जिनके संबंध में आईसीएआई अनुसंधान तथा आगे और अध्ययन आरंभ कर सकता है और साथ ही वृत्ति द्वारा प्रतिक्रिया हेतु समकालीन महत्व के विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए समिति ने लोक सेवा में लगे सदस्यों के मतों को जानने के विचार से पुरी में, आर्थिक विकास के लिए लेखांकन वृत्ति विषय पर लोक सेवा में आईसीएआई के सदस्यों के आवासीय शिखर

सम्मेलन का आयोजन किया था।

न्यायमूर्ति (सीए) अनिल आर. दवे, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, भारत का उच्चतम न्यायालय और सीए अरुण कुमार गुजराती, पूर्व अध्यक्ष महाराष्ट्र विधान सभा ने इस शिखर सम्मेलन में आधार व्याख्यान प्रस्तुत किया था। इस शिखर सम्मेलन में 33 व्यक्तियों ने भाग लिया था, जो लोक सेवा में लगे वृत्ति के वरिष्ठ सदस्य थे, जिनके अंतर्गत सांसद, न्यायाधीश, भारतीय प्रशासनिक और अन्य सिविल सेवाओं के अधिकारी, अधिकरणों के सदस्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में नियोजित सदस्य सम्मिलित थे।

**नई दिल्ली में लोक सेवा में आईसीएआई के सदस्यों की क्षेत्रीय बैठक:** सीएमईपीएस में 25 मई, 2018 को नई दिल्ली में लोक सेवा में आईसीएआई के सदस्यों की एक क्षेत्रीय बैठक का आयोजन किया था। इस क्षेत्रीय बैठक में लोक सेवा में लगे अन्य सीए सदस्यों के साथ न्यायमूर्ति (सीए) अनिल आर. दवे, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, भारत का उच्चतम न्यायालय, सीए विभू बखर, आसीन न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय, सीए दीपक कुमार केडिया, अपर निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, दिल्ली, सीए राकेश राठी, डीआईजी पुलिस, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, दिल्ली, सीए उपेन्द्र गुप्ता, आईआरएस, आयुक्त, जीएसटी राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय ने भाग लिया था।

इस क्षेत्रीय बैठक के दौरान, आईसीएआई ने लोक सेवा में लगे सीए सदस्यों को आईसीएआई के साथ सुगम रूप से जुड़ने का अवसर प्रदान करने और उनके अभिलेखों को सुगमता से अद्यतन करने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया था। वृत्तिक अकाउंटेंटों की सक्षमताओं और कौशल सेटों में सुधार करने उपायों संबंधी महत्वपूर्ण परिचर्चाएं की गई थी। इसके अतिरिक्त, इस बात पर भी विचार-विमर्श किया गया था कि पणधारियों की आशाओं की पूर्ति करने के बीच आने वाली खाई को किस प्रकार भरा जाए और आईसीएआई की लोक छवि में किस प्रकार सुधार किया जाए। सदस्यों ने डिजिटल प्रौद्योगिकियों में हुए परिवर्तनों से उद्भूत होने वाली वृत्ति की परिवर्तनशील आवश्यकताओं के संबंध में भी परिचर्चा की थी। इसके अतिरिक्त, आईसीएआई ने इस क्षेत्रीय बैठक के दौरान सीए. उपेन्द्र गुप्ता, आयुक्त, जीएसटी को, “टीम जीएसटी, राजस्व विभाग, भारत सरकार” को प्रदान किए गए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया था।

### 7.3 सहकारिताओं और एनपीओ क्षेत्रों संबंधी समिति (सीसीओएंडएनपीओ)

सीसीओएंडएनपीओ को सहकारिताओं और एनपीओ के लिए एक समान लेखांकन ढांचे का संवर्धन करने और दोनों क्षेत्रों में उत्तम शासन और सर्वोत्तम व्यवहारों को प्रोत्साहित करने के लिए गठित किया गया था। समिति सहकारिताओं और एनपीओ के संबंध में कानूनों में उपयुक्त सुधारों का सुझाव देती है और उसका उद्देश्य इस क्षेत्र से विनिर्दिष्ट मुद्दों पर अवधारणात्मक स्पष्टता लाने को सुकर बनाना है जिससे कि कार्य को, उन क्षेत्रों में नियोजित सभी पणधारियों द्वारा प्रभावी तथा दक्ष रूप से पूरा किया जा सके। साथ ही सदस्यों को संगोष्ठियों, व्यवहारिक कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के माध्यम से सहकारिताओं और एनपीओ के क्षेत्र में नवीनतम घटनाओं की अद्यतन जानकारी प्रदान की जा सके।

#### प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन

- तारीख 20 अप्रैल, 2017 का एक प्रतिवेदन आयुक्त, सहकारिता और सहकारी सोसाइटी रजिस्ट्रार, मध्य प्रदेश राज्य, भोपाल को संपरीक्षा फर्म में कर्मचारिवृंद की परिभाषा के संबंध में प्रस्तुत किया गया था।
- तारीख 9 अगस्त, 2017 का एक प्रतिवेदन अपर प्रधान सचिव, सहकारिता, मंत्रालय, महाराष्ट्र को संपरीक्षा हेतु पैनल तैयार करने और चार्टर्ड अकाउंटेंटों के समक्ष महाराष्ट्र में सहकारी सोसाइटियों की संपरीक्षा के संबंध में आने वाली अन्य कठिनाईयों के संबंध में प्रस्तुत किया गया था।
- तारीख 1 और 16 मार्च, 2018 के दो प्रतिवेदन, सचिव-सह-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी रजिस्ट्रार कार्यालय, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार को, सीए/सीए फर्मों द्वारा, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार के संबंधित विभाग के साथ रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों की संपरीक्षा का संचालन करने के लिए सहकारी सोसाइटी रजिस्ट्रार कार्यालय में संपरीक्षकों के रूप में अपने नामों को पैनलबद्ध करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को विस्तारित करने का अनुरोध करते हुए प्रस्तुत किए गए थे।

## संचालित प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

सीसीओ और एनपीओ ने जमशेदपुर और मुंबई में दो प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों का संचालन किया था – सहकारिता संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम और एनपीओ संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम।

### 7.4 विधिक सलाहकार खंड

इस अवधि के दौरान, विधिक खंड द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्रियाकलाप किए गए थे : 1.4.2017 से 31.03.2018 तक की अवधि के दौरान विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21(6) के अधीन निपटाए गए मामलों की कुल संख्या 8 है।

विधिक रायों के रूप में प्रभावी विधिक सहायता अध्ययनों और रिपोर्टों को उपलब्ध कराना, जैसा कि समय-समय पर संस्थान की परिषद्/कार्यपालक समिति/ विभिन्न अस्थायी समितियों और विभागों द्वारा अपेक्षा की जाए।

आईसीएआई के हित को ठोस रूप से सुनिश्चित करने के लिए संस्थान के प्रशासनिक कार्यकरण से उदभूत होने वाली विधि के सारवान और प्रक्रियात्मक प्रश्नों की विविध श्रृंखला पर उपयुक्त विधिक सलाह उपलब्ध कराना, जैसा कि प्रचालनात्मक विभागों द्वारा अपेक्षित किया जाए।

आईसीएआई के प्रचालन विभागों और विभिन्न समितियों द्वारा अपेक्षा किए गए अनुसार संविदाओं, निविदाओं, दस्तावेजों और अन्य विधिक दस्तावेजों के पुनर्विलोकन, उनके संबंध में बातचीत, उनके प्रारूपण और विधीक्षा संबंधी कार्य का पर्यवेक्षण और पर्यावलोकन करना।

नीतियों को तैयार करने के संबंध में विधिक सूक्ष्मताओं का ध्यान रखने के लिए यथाअपेक्षित रूप में विभिन्न स्थाई और अस्थायी समितियों, अध्ययन समूहों और कार्यबलों में सेवा प्रदान करना।

जब कभी आवश्यक हो, विधिक उपचारों का अवलंब लेने के विषयों में सलाह देना और प्राप्त हुई विधिक सूचनाओं का उत्तर तैयार करने में प्रचालन विभागों और समितियों की सहायता करना।

### 7.5 अवसंरचना विकास संबंधी समिति (आईडीसी)

अवसंरचना विकास संबंधी समिति का सृजन वर्ष 2014 में संस्थान की एक अस्थायी समिति के रूप में किया गया था। इस समिति ने शाखाओं और प्रादेशिक परिषदों/कार्यालयों के लिए अवसंरचना नीति की विरचना की थी। वर्ष 2014 से, आईसीएआई में एक ठोस अवसंरचना नीति स्थापित की है, जो वित्तीय विवेक और अनुशासन को सुनिश्चित करती है। यह नीति इस बात को परिभाषित करती है कि किस प्रकार की प्रसुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं, स्थानीय अवसंरचना समितियों की संरचना कैसी हो, भूमि/भवन के अर्जन के नीति और प्रक्रिया, संकेतात्मक क्षेत्र, प्रधान कार्यालय से अनुज्ञेय अनुदान, संस्थान के भीतर विभिन्न प्राधिकारियों में निहित शक्तियां और उनका प्रत्यायोजन। चूंकि नीति स्वयं वित्तीय शक्तियों को परिभाषित करती है इसलिए वर्ष 2014 के पश्चात् से सभी अवसंरचना परियोजनाएं वित्त समिति की बजाए आईडीसी द्वारा अनुमोदित की जा रही हैं। आईडीसी के प्राधिकार के अधीन, संनिर्मित की जा रही अवसंरचना परियोजनाओं को मानीटर और उनको त्वरित करने के लिए वर्ष 2018 में एक अवसंरचना मानीटरी और त्वरित समूह को स्थापित किया गया था।

**अवसंरचना नीति को तैयार करने के पश्चात् आईसीएआई ने निम्नलिखित परियोजनाओं को आरंभ किया है :**

नई अवसंरचना का क्रय	अनुमोदित संनिर्माण संबंधी प्रस्ताव
कन्नूर, जालंधर, जबलपुर, गोवा, गुरुग्राम, मुरादाबाद, पाली, आगरा, गोरखपुर, करनाल, किशनगढ़, लातूर और पटियाला	अजमेर, सूरत, हुबली, राजमहेन्द्रवरम, उत्कृष्टता केंद्र जयपुर, बठिंडा, बरेली, भोपाल, जोधपुर, रायपुर, कन्नूर, गज़ियाबाद, गोवा और मुरादाबाद

आईसीएआई द्वारा अभी तक स्थापित 164 शाखाओं में से, 91 शाखाओं के पास अपने स्वयं के परिसर हैं, जिनके अंतर्गत 17 ऐसी शाखाएं भी हैं, जिन्होंने अतिरिक्त परिसरों के लिए भूमि का उपापन किया है और या तो उन्होंने संनिर्माण आरंभ कर दिया है या संनिर्माण आरंभ होने वाला है। 16 शाखाओं में, जिनके पास अभी तक अपने स्वयं के परिसर नहीं हैं, भूमि का उपापन किया है और या तो उन्होंने संनिर्माण आरंभ कर दिया है या संनिर्माण आरंभ होने वाला है। 57 शाखाओं के पास अपने स्वयं की भूमि या भवन नहीं हैं। मार्च, 2018 तक क्षेत्रवार व्यौरे निम्नानुसार हैं :

	पश्चिमी	दक्षिणी	पूर्वी	मध्य	उत्तरी	योग
शाखाओं की कुल संख्या	35	45	13	47	24	164
अपने स्वयं का परिसर रखने वाली शाखाओं की संख्या	22	32	6	23	8	91
उपरोक्त में से ऐसी शाखाओं की संख्या, जो अतिरिक्त परिसर तैयार कर रही हैं	6	2	1	7	1	17
ऐसी शाखाओं की संख्या, जिनके पास भूमि है और जिस पर संनिर्माण या तो आरंभ हो गया है या आरंभ होने वाला है	0	2	0	10	4	16
ऐसी शाखाओं की संख्या, जिनके पास न तो भूमि है और न ही भवन	13	11	7	14	12	57

## 7.6 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 एक ऐसा अधिनियम है, जो नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार से संबंधित एक व्यवहारिक व्यवस्था की स्थापना करने का उपबंध करता है, जिसमें नागरिक लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन जानकारी तक पहुंच सुनिश्चित कर सकेंगे और इस प्रकार प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और जवाबदेही का संवर्धन होगा। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई), जो संसद् के एक अधिनियम, अर्थात् चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अधीन स्थापित एक कानूनी निकाय है, जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(ज) में परिकल्पित किए गए अनुसार एक लोक प्राधिकारी है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों और केन्द्रीय सूचना आयोग के निदेश के अनुपालन में इस लोक प्राधिकरण द्वारा अपने अधिकारियों को केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी, प्रथम अपील प्राधिकारी (एफएए) और पारदर्शिता अधिकारी के रूप में पदाभिहित किया गया है।

### सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अधीन प्रकटन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के निबंधनों के अनुसार संस्थान द्वारा आवश्यक प्रकटन किए गए हैं और उन्हें संस्थान की वेबसाइट [www.icaai.org](http://www.icaai.org) पर रखा गया है और उसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। वर्ष 2017-18 के दौरान कुल 618 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनका उत्तर दिया गया था।

## 7.7 एक्सबीआरएल

आईसीएआई ने वर्ष 2010 में एक्सबीआरएल इंडिया के सृजन के साथ देश में एक एक्सबीआरएल पहल की अगुवाई की थी, जो एक धारा 8 की कंपनी है। उसके पश्चात् से एक्सबीआरएल इंडिया भारत में मानक इलेक्ट्रॉनिक कारबार रिपोर्टिंग भाषा के रूप में एक्सबीआरएल को अपनाए जाने और उसका संवर्धन करने के लिए कार्यकरण कर रहा है।

एक्सबीआरएल इंडिया का मुख्य उद्देश्य, वर्गीकरणों के विकास के माध्यम से एक्सबीआरएल, प्रबंध सूचना और नियंत्रण प्रणालियों और संबद्ध विधाओं संबंधी शिक्षा और प्रशिक्षण आदि को सुकर बनाकर एक्सबीआरएल को बढ़ावा देना है, भारत में जिसका समर्थन भारत सरकार और विभिन्न विनियामक निकायों, अर्थात् कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) आदि द्वारा किया जा रहा है। एक्सबीआरएल इंडिया, एक्सबीआरएल प्ररूप में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के लिए वर्गीकरणों को विकसित करता है।

### • कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा एक्सबीआरएल फाइलिंग संबंधी अपेक्षाएं

#### इंड एस वर्गीकरण और कारबार नियम

कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने कतिपय प्रवर्ग की कंपनियों के लिए यह आज्ञापक बनाया है कि वे अपने वित्तीय विवरणों को भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एस), जिन्हें वित्तीय वर्ष 2016-17 से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के साथ अभिसरित किया गया है, के अनुसार तैयार करें।

कारबार नियमों और इंड एस के वर्गीकरणों के एक सेट को तैयार किया गया है, जिसे कारपोरेट कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है। एमसीए ने प्ररूप में वित्तीय वर्ष 2016-17 की वार्षिक फाइलिंग के लिए उसे अधिसूचित किया था। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए इंड एस का अनुपालन करने वाली कंपनियों द्वारा एक्सबीआरएल फाइलिंग को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। इंड एस एक्सबीआरएल वर्गीकरण के लिए दस्तावेज के विस्तार क्षेत्र और उसे टैग करने के स्तर को तैयार किया गया है और कारपोरेट कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है।

**वाणिज्यिक और औद्योगिक (सीएंडआई) वर्गीकरण:** चुने गए वर्ग की कंपनियों के वित्तीय विवरणों की वार्षिक फाइलिंग के लिए वर्ष 2010-11 से कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा वाणिज्यिक और औद्योगिक (सीएंडआई) वर्गीकरण का उपयोग किया जा रहा है। इस वर्गीकरण को, लेखांकन ढांचे में हुए परिवर्तनों पर विचार करते हुए प्रत्येक वर्ष अद्यतन बनाया जाता है।

हाल ही में, लेखांकन मानकों में नवीनतम संशोधनों के अनुसार वाणिज्यिक और औद्योगिक (सीएंडआई) वर्गीकरणों में कुछ परिवर्तन अपेक्षित थे। वित्तीय वर्ष 2017-18 की एक्सबीआरएल फाइलिंग के लिए इन अपेक्षित परिवर्तनों को एमसीए को प्रस्तुत किया गया था। एमसीए के अनुमोदन के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2017-18 की एक्सबीआरएल फाइलिंग के लिए पुनरीक्षित सीएंडआई वर्गीकरणों को एमसीए को प्रस्तुत किया गया था।

**अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां:** एक्सबीआरएल इंडिया के निदेशक, सीए. अतुल कुमार गुप्ता ने 18 -20 जून, 2018 से फुकुओका सिटी (जापान) में आयोजित 28 वें आसियान + 3 बॉण्ड मार्केट फोरम (एबीएमएफ) की बैठक में भाग लिया। उन्होंने 21 जून, 2018 को वहां 9वीं एक्सबीआरएल एशिया गोलमेज पर बैठक में भी भाग लिया।

## 7.8 आईसीएआई – एआरएफ

लेखांकन अनुसंधान फाउंडेशन (आईसीएआई एआरएफ) को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (जो अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 है) के अधीन जनवरी, 1999 में लेखांकन, संपरीक्षा, पूंजी बाजारों, राजकोषीय और धनीय नीतियों के क्षेत्रों में मूल अनुसंधान करने के लिए आईसीएआई द्वारा स्थापित किया गया था। आईसीएआई एआरएफ द्वारा पूरी की गई परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :--

- **भारतीय रेल** – वर्ष के दौरान आईसीएआई एआरएफ की नोडल टीम ने, “सभी ज़ोनल रेलों, उत्पादन इकाइयों और भारतीय रेल के अन्य कार्यालयों में प्रोदभवन लेखांकन को लागू करने” की परियोजना संबंधी मूल्यांकन रिपोर्ट के व्यापक विस्तार क्षेत्र को प्रस्तुत किया था और अब वर्ष 2015-16 और 2016-17 से भारतीय रेल के वित्तीय विवरणों को प्रोदभवन आधार पर तैयार किया जा रहा है।
- **तमिलनाडु सिविल आपूर्ति निगम** : आईसीएआई एआरएफ ने परियोजना के निम्नलिखित परिदानों के संबंध में कार्यकरण आरंभ कर दिया है :
  - प्रमुख अंतरों की पहचान करना और की जाने वाली प्रक्रिया संबंधी दस्तावेज तैयार करना
  - प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) दस्तावेज तैयार करना, जिससे निगम को एक उपयुक्त विक्रेता का चयन करने/किसी घरेलू विकल्प पर विचार करने में समर्थ बनाया जा सके, जो एक व्यापक आईटी प्रणाली को विकसित करेगा
- **भारतीय समर्पित माल भाड़ा कारीडोर निगम लिमिटेड** : आईसीएआई एआरएफ, संविदाकारों को कीमत में अंतर के संदाय के लिए डब्ल्यूपीआई (श्रृंखला – 2004-05) को डब्ल्यूपीआई (श्रृंखला 2011-12) के साथ प्रतिस्थापित करने के लिए पद्धति का सुझाव देने हेतु नियोजित किया गया था, जिसके संबंध में रिपोर्ट को तैयार किया जा रहा है।
- आईसीएआई एआरएफ ने सुश्री शगुफ्ता उज्जमा, सहायक प्रोफेसर, एनआईटी, राऊरकेला द्वारा विरचित ‘आईएफआरएस के अधीन आज्ञापक रिपोर्टिंग का भारत में निगम शासन पर प्रभाव’ विषय पर परियोजना रिपोर्ट का प्रकाशन किया था।
- आईसीएआई एआरएफ ने 6 दिसंबर, 2017 को नई दिल्ली में देश के आर्थिक विकास में प्रोदभवन लेखांकन की भूमिका के विषय पर एक पूर्ण दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया था। श्री इयन बल, अध्यक्ष, सीआईपीएफ इंटरनेशनल, श्री नरेश सलेचा, प्रधान कार्यपालक निदेशक, वित्त, रेल बोर्ड, श्री रजनीश कुमार, जेना, सीसीए



जम्मू, डाक विभाग ने अपने अनुभवों को श्रोताओं के साथ साझा किया था, जिसमें सीएंडएजी के कार्यालय, भारतीय क्वालिटी परिषद्, रेल बोर्ड, भारतीय रेल, उत्तरी रेल, मुद्रण निदेशालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, शासकीय लेखांकन मानक सलाहकार बोर्ड, एनएफसीएच, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संगठन, ऐरोनॉटिक्स विकास अभिकरण और अन्य शासकीय स्थानीय निकायों के वरिष्ठ पदधारी सम्मिलित थे।

## 7.9 आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन

आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन (आईसीएआई आरवीओ), कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के अनुसार रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों या मूल्यांकक सदस्य को उसके सदस्यों के रूप में नामांकित करने और उनका विनियमन करने के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा सृजित एक धारा 8 प्राइवेट कंपनी है और वह उससे अनुषंगी कृत्यों का निर्वहन करता है।

### आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन की भूमिका

आईसीएआई आरवीओ की महत्वपूर्ण भूमिका में से कुछ निम्नलिखित हैं :—

- (क) कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन के कृत्यों को करना तथा उससे संबद्ध और अनुषंगी कृत्यों को पूरा करना ;
- (ख) रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों को नामांकित करना और प्रभावी मूल्यांकन करने के लिए उन्हें शिक्षित और प्रशिक्षित करना ;
- (ग) उसके सदस्यों के नामांकन और विनियमन के लिए उचित, सुसंगत, न्यायोचित और गैर-विभेदकारी व्यवहारों को अपनाना ;
- (घ) रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों की वृत्ति को विकसित करना ;
- (ङ) मूल्यांकन वृत्तिकों के सतत वृत्ति विकास का संवर्धन करना ;
- (च) अपने सभी सदस्यों के बीच व्यवसाय और वृत्ति के उच्च मानकों को स्थापित करना तथा उनका संवर्धन करना और उसके आंतरिक विनियमों और दिशानिर्देशों में सतत सुधार करके उनके आचार में कठपूर्वक व्यवहार और दुष्करण का निवारण करना ;
- (छ) अपने सदस्यों के अधिकारों, विशेषाधिकारों और हितों का संवर्धन करना और उनके लिए सुरक्षोपाय करना ;
- (ज) उसके सदस्यों के विरुद्ध और स्वयं अपने विरुद्ध शिकायतों का समाधान करना ;
- (झ) कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के उपबंधों के कार्यान्वयन में बोर्ड के साथ समन्वय करना और उसकी सहायता करना।

आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन को 15 मई, 2018 को रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन के रूप में भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुई थी। कंपनी ने जून, 2018 में अपने क्रियाकलाप आरंभ किए थे।

## 7.10 आईसीएआई का भारतीय दिवाला वृत्तिक संस्थान

आईसीएआई का भारतीय दिवाला वृत्तिक संस्थान (आईआईआईपीआई), जो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की पूर्ण स्वामित्व वाली एक अनुषंगी कंपनी है, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा सृजित एक धारा 8 की एक पब्लिक कंपनी है, इसका कार्य दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 और उससे संबंधित विनियमों और उसके आनुषंगिक कृत्यों के अनुसार उसके सदस्यों को दिवाला वृत्तिकों के रूप में नामांकित करना और उनका विनियमन करना है।

इसे, 28 नवंबर, 2016 को दिल्ली में संघ के माननीय वित्त मंत्री, श्री अरुण जेटली द्वारा भारत के प्रथम दिवाला वृत्तिक अभिकरण के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था। आईआईआईपीआई में विविध क्षेत्रों से सदस्य सम्मिलित हो रहे हैं, जिनके अंतर्गत चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव, लागत लेखापाल, अधिवक्ता और प्रबंधकीय वृत्तिक हैं। सीए आईआईआईपीआई के आधार स्वरूप बने हुए हैं, जिस पर इसकी इमारत खड़ी होती है, जिसके कुल सदस्यों में

से 90% से अधिक सदस्य चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आईबीबीआई के साथ रजिस्ट्रीकृत कुल 2037 दिवाला वृत्तिकों में से 1241 आईआईआईपीआई से हैं।

आईआईआईपीआई के प्रचालनों के प्रथम चरण में उसकी सदस्यता के आधार को स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है और उसे सुदृढ़ बनाने के पश्चात् अब क्रियाकलापों को और अधिक व्यापक बनाया जा रहा है।

## पहलें

- ❖ **इंस्टिट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ इंग्लैंड एंड वेल्स (आईसीएईडब्ल्यू) के साथ ठहराव** – आईआईआईपीआई ने ज्ञान संबंधी भागीदारी के लिए इंस्टिट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ इंग्लैंड एंड वेल्स (आईसीएईडब्ल्यू) के साथ एक ठहराव पर हस्ताक्षर किए हैं।
- ❖ **विश्व बैंक समूह के साथ सहबद्धता** – आईआईआईपीआई ने विश्व बैंक समूह (डब्ल्यूबीजी) के सहयोग से संयुक्त कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए एक ठहराव पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में आईपी के लिए **पहले चयनित प्रशिक्षण कार्यक्रम** का आयोजन इस वर्ष जनवरी में मुंबई में किया गया था और वह अत्यंत सफल सिद्ध हुआ था। उसके पश्चात् आईआईआईपीआई द्वारा जून, 2018 में दिल्ली और मुंबई में विश्व बैंक के साथ **“मीट अप”** सत्र का आयोजन किया है। इसी दौरान, आईआईआईपीआई ज्ञान के गहन प्रसार के लिए **“प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने”** संबंधी कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक के साथ निकटता से कार्य कर रहा है।
- ❖ **भारतीय बैंक संगम (आईबीए) – बैंकों के लिए आईआईआईपीआई कार्यक्रम का आयोजन** – आईआईआईपीआई ने आईबीए के साथ बैंकों, आईपी और अन्य संबद्ध अस्तित्वों के लिए, इस क्षेत्र में वास्तविक आधारिक स्तर के उदभासन के लिए मुंबई में एक परस्पर क्रियाशील कार्यक्रम का आयोजन किया था।
- ❖ **आईसीएआई के भारतीय दिवाला वृत्तिक संस्थान की पठन प्रबंध प्रणाली** – आईआईआईपीआई ने आईसीएआई के साथ संयुक्त रूप से, दिवाला संबंधी परीक्षा की तैयारी करने में वृत्तिकों को समर्थ बनाने के लिए भारतीय दिवाला वृत्तिक संस्थान की पठन प्रबंध प्रणाली को तैयार किया है।
- ❖ **आईआईआईपीआई न्यूज लैटर और जर्नल** – आईआईआईपीआई न्यूज लैटर, जिसमें दिवाला वृत्तिक से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं के ब्यौरे दिए गए हैं, वेबसाइट पर रखा जा रहा है। “द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल” – आईआईआईपीआई के एक त्रैमासिक जर्नल का भी शुभारंभ किया गया है।
- ❖ **अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन** – राष्ट्रीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता परिषद्, एसोचेम इंडिया, एसआईपीआई, इनसोल इंडिया, एडलवाइज, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि संबंधी संयुक्त राष्ट्र आयोग, ए एंड एम के सहयोग से “नई निगम दिवाला व्यवस्था” विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था।
- ❖ **आईपी सभा** – आईआईआईपीआई द्वारा 26 मई, 2018 को मुंबई में आईबीबीआई दिवाला वृत्तिक सभा का आयोजन किया गया था।
- ❖ **बीएफएसआई क्षेत्र कौशल परिषद् और एनएसडीसी के साथ सहयोग** – आईआईआईपीआई ने बीएफएसआई क्षेत्र कौशल परिषद् और एनएसडीसी के साथ, (क) सभी रजिस्ट्रीकृत दिवाला वृत्तिकों के लिए एक दिवसीय कौशल विकास कार्यक्रम, (ख) आईपी के लिए एक समर्थन सेवा के रूप में “दिवाला सहबद्ध पाठ्यक्रम” को आरंभ करने के लिए हाथ मिलाया था।
- ❖ **आनलाइन उपयोगिताएं** – आईआईआईपीआई ने अपनी वेबसाइट [www.iiipicai.in](http://www.iiipicai.in) पर विभिन्न आनलाइन उपयोगिताओं को विकसित किया है जिससे दिवाला और परिसमापन समनुदेशनों की प्रास्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित की जा सके।

## 8. अन्य मामले

### 8.1 आईसीएआई का वार्षिक समारोह

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) के 68वें वार्षिक समारोह का आयोजन 6 फरवरी, 2018 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में हुआ था, जिसमें आईसीएआई ने अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों और प्राप्त किए गए बहुल मील के पथरों का जश्न मनाया था। इस अवसर पर न केवल वर्ष 2017-18 में आईसीएआई की उपलब्धियों की

सफलताओं का स्मरण किया गया था, अपितु इसमें संस्थान और भारतीय लेखांकन वृत्ति की आने वाले समय में राष्ट्र निर्माण के भागीदार के रूप में संभावनाओं की कार्ययोजनाओं पर भी विचार किया गया था। संघ के वाणिज्य और उद्योग मंत्री, सी.ए. सुरेश पी. प्रभु और संघ के रेल और कोयला मंत्री सी.ए. पीयूष गोयल ने मुख्य अतिथियों के रूप में इस समारोह की शोभा बढ़ाई थी, जबकि विधि और न्याय तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री पी.पी. चौधरी इस समारोह के सम्मानित अतिथि थे, जिन्होंने भारतीय लेखांकन वृत्ति की अनुशंसा की थी। संसद् के नए निर्वाचित सदस्य (राज्य सभा) और आईसीएआई के पूर्व अध्यक्ष, सी.ए. नारायण दास गुप्ता को भी इस अवसर पर, उपस्थित व्यक्तियों की एक बहुत बड़ी संख्या के समक्ष सम्मानित किया गया था, जिनमें लेखांकन वृत्ति के अनेक गणमान्य व्यक्ति तथा सरकार और अन्य पणधारियों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। इस अवसर पर प्रतिभाशाली सी.ए. छात्रों और उत्कृष्ट प्रादेशिक परिषदों, शाखाओं और विदेशी चैप्टरों को भी वर्ष के दौरान उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया था। इस अवसर पर आईसीएआई के विभिन्न प्रकाशनों का भी विमोचन किया गया था।

## 8.2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस और हीरक जयंती समारोह

आईसीएआई ने, 1 जुलाई, सी.ए. दिवस को अपने विद्यमानता के 70वें स्वर्णिम वर्ष में प्रवेश किया। हीरक जयंती समारोह का शुभारंभ भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा श्री मनोज सिन्हा संघ के माननीय संचार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और रेल राज्य मंत्री और श्री पी.पी. चौधरी, संघ के माननीय कारपोरेट कार्य मंत्री की उपस्थिति में 1 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित समारोह के दौरान सी.ए. दिवस मनाया गया था।

प्लैटिनम जयंती समारोह के साथ मिलकर, निम्नलिखित गतिविधियां लॉन्च की गई हैं:

- डाक विभाग ने राष्ट्रीय आर्थिक विकास में आईसीएआई के तारकीय योगदान को दर्शाते हुए विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया है।
- भारतीय सशस्त्र बलों, पैरा सैन्य बलों और रेलवे कार्मिक के मेधावी वाडों के लिए विशेष छात्रवृत्ति।
- एकाउंटेंसी पेशे के इतिहास की रिलीज, भाग III।
- सदस्यों और छात्रों के लाभ के लिए लॉन्च की गई अन्य प्रमुख पहल अनन्य दस्तावेज़ पहचान संख्या (यूडीआईएन) सेवा, ई-सीपीई और आईसीएआई टीवी, आईसीएआई नॉलेज बैंक, आईसीएआई लर्निंग वक्र।
- अंडर ग्रेजुएट गर्ल्स के छात्रों के लिए जीएसटी पर कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया।
- आईसीएआई के सदस्यों और छात्रों के बीच अंग दान के लिए रक्तदान शिविर और जागरूकता अभियान।

इस अवसर पर, स्वामी सुखाबोधनंद द्वारा 'सकारात्मक सोच की शक्ति' पर विशेष व्याख्यान, 'आईसीएआई @ 70: पद्म श्री सी.ए. द्वारा अतीत का जश्न मनाने, भविष्य को प्रेरणा देना'। टी। एन मनोहरन, पिछले राष्ट्रपति आईसीएआई और 'आप जीत सकते हैं ... अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं' श्री शिव खेरा भी 1 जुलाई, 2018 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे।

पूर्व परंपरा के अनुसार, पीआर समूह द्वारा प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं को अग्रेषित संसूचनाओं के आधार पर देश भर में स्थित सदस्य/छात्र/पदधारी, सामाजिक क्रियाकलापों और समान प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करके इस गौरवपूर्ण अवसर को मनाने के अपने प्रयासों में संगठित हुए थे।

## 8.3 केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय

संस्थान का केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय उसके पणधारियों की सूचना संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है। इसका उद्देश्य, आईसीएआई के वर्तमान और भावी सदस्यों/छात्रों, अनुसंधान अध्येताओं और पदधारियों को प्रारंभिक और द्वितीय मुद्रण और गैर-मुद्रण सामग्रियों का व्यापक और अद्यतन संग्रह उपलब्ध कराना है। पुस्तकालय ने समितियों, विभागों में जानकारी प्रदान करने और मूल्यवान सूचना का प्रसार करने के वृहत्तर उत्तरदायित्व को ग्रहण किया है, यह इस उत्तरदायित्व का निर्वहन पुस्तकों, ई-पुस्तकों, जर्नलों, पत्रिकाओं, ऑनलाइन डाटाबेसों, मुद्रित समाचारपत्रों और साथ ई-समाचारपत्रों के माध्यम से करता है। केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय विभिन्न समितियों के कार्य के लिए अपेक्षित जर्नलों और पुस्तकों को उपलब्ध कराने तथा उन्हें अद्यतन करने के लिए उत्तरदायी है।

**केंद्रीय परिषद् पुस्तकालय पूर्णतया कंप्यूटरीकृत है और वह लिबर्टी-एक पुस्तकालय प्रबंधन साफ्टवेयर के माध्यम से कार्य करता है।** पुस्तकालय की सामग्रियों, जिनके अंतर्गत पुस्तकों, जर्नलों और लेखों का डाटा बेस भी है, के लिए विषय, लेखक, शीर्षक, टापिक, कुंजी शब्द और प्रकाशक के माध्यम से खोज की जा सकती है। ये अभिलेख पुस्तकालय में इंटरनेट ऑनलाइन सर्विस [www.icaai.org](http://www.icaai.org) पर "नो युअर इंस्टीट्यूट सेंट्रल काउंसिल लाइब्रेरी" पुस्तकों, जर्नलों, लेखों आदि के लिए पुस्तकालय में ऑनलाइन सर्च ओपीएसी लिबर्टी के अधीन उपलब्ध है।

संस्थान के जर्नल के स्तंभ "अकाउंटेंट्स ब्राउजर" के अधीन लेखांकन वृत्ति से सुसंगत लेखों की अनुक्रमणिका को प्रत्येक मास प्रकाशित किया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि "अकाउंटेंट्स ब्राउजर" पूर्ववर्ती लेखों के अभिलेखागार के साथ महत्वपूर्ण/वृत्तिक लेखों की एक अनुक्रमणिका है। निर्देश सेवा विभिन्न शोधकर्ताओं और विद्वानों, संकाय और छात्रों तथा सदस्यों को प्रदान की जाती है।

पुस्तकालय द्वारा अनेक ऑन लाइन डाटाबेस भी अर्जित किए गए हैं जिनके ब्यौरे [www.icaai.org](http://www.icaai.org)—Central Council Library पर उपलब्ध हैं। पुस्तकालय ने इन आनलाइन ज्ञान डाटाबेसों को केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय परिसरों और विभिन्न विभागों तथा साथ ही आईसीएआई की प्रादेशिक परिषदों के पुस्तकालयों में भी अपेक्षित सामग्री की सर्च को सुकर बनाने के लिए आनलाइन रूप से प्रतिष्ठापित किया है। पुस्तकालय द्वारा अनेक आनलाइन जर्नलों की ग्राहकी भी प्राप्त की गई है। केंद्रीय परिषद् पुस्तकालय के क्रमशः प्रधान कार्यालय और नोएडा कार्यालय में स्थित पुस्तकालयों में 1 अप्रैल, 2017 से 30 जून, 2018 की अवधि के दौरान जोड़े गए नए संसाधनों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

केंद्रीय परिषद् पुस्तकालय (मुख्यालय)

क्रम सं.	शीर्षक	आंकड़े
1.	जर्नल (मुद्रण) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय	37
2.	ग्राहकी प्राप्त किए गए जर्नलों तक ई-पहुंच	8
3.	आनलाइन संसाधन	11
4.	अवधि के दौरान जोड़ी गई पुस्तकें	826

**केंद्रीय परिषद् लाइब्रेरी, सेक्टर 62 नोएडा**

क्रम सं.	शीर्षक	आंकड़े
1.	जर्नल (मुद्रण) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय	32
2.	ग्राहकी प्राप्त किए गए जर्नलों तक ई-पहुंच	02
3.	आनलाइन संसाधन	06
4.	अवधि के दौरान जोड़ी गई पुस्तकें	207

केंद्रीय परिषद् पुस्तकालय नियमित रूप से अपने संसाधनों को अद्यतन बना रहा है ताकि वृत्तिक सदस्यों, छात्रों, संकायों आदि को नवीनतम और अद्यतन जानकारी और सूचना उपलब्ध कराई जा सके।

#### 8.4 संपादक बोर्ड

**संपादक बोर्ड : वृत्तिक ज्ञान आधार का अक्षरशः प्रसार**

संपादक बोर्ड भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) की एक अस्थायी समिति है जिसका उद्देश्य सदस्यों को निरंतर रूप से वृत्तिक ज्ञान, वृत्ति से हितबद्ध अन्य विषयों पर एक संरचित रीति में 'दि चार्टर्ड अकाउंटेंट' जर्नल के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराना है। जर्नल की पहुंच और प्रभाव का अनुमान इसके परिचालन से संबंधित आंकड़ों से लगाया जा सकता है, जो आज के दिन 3,00,000 से अधिक है।

यह आईसीएआई का 'ब्रांड अम्बेसेडर' है और सदस्यों, छात्रों तथा बाह्य श्रोताओं के लिए संस्थान के प्रोफाइल को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। आज द चार्टर्ड अकाउंटेंट विश्व की ख्याति प्राप्त पत्रिकाओं से टक्कर ले रहा है। विभिन्न विषयों और मुद्दों पर आईसीएआई के सदस्यों और द चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल के अन्य पाठकों की विभिन्न विषयों और मुद्दों पर जानकारी को अद्यतन बनाए रखने के अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए संपादक बोर्ड निरंतर प्रयासरत है।

31 मार्च, 2017 से 30 जून, 2018 की अवधि के बीच संपादक बोर्ड द्वारा की गई महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

#### **क्वालिटी और समकालीन अंतर्वस्तु :**

**विषयों की व्यापक रेंज को सम्मिलित किया जाना :** अप्रैल, 2017 से जून, 2018 तक के जर्नल के अंकों में विभिन्न नवीन विषय संबंधी मुद्दों के अधीन 400 से अधिक लेख/फीचर और विभिन्न विषयों पर रिपोर्टों का प्रकाशन किया गया था।

**जुलाई, 2018 का आईसीएआई जर्नल का कलेक्टर्स संस्करण निकाला जाना :** आईसीएआई के हीरक जयंती समारोह के शुभारंभ के साथ इस वर्ष के सीए दिवस के उपलक्ष में जर्नल के विशेष जुलाई, 2018 अंक को, कलेक्टर्स संस्करण के रूप में निकाला गया था। 2004 पृष्ठ के इस जर्नल में, 18 विशिष्ट लेखों, जिन्हें विशेष रूप से लेखांकन वृत्ति से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्तियों द्वारा जर्नल के लिए लिखा गया था, का प्रकाशन किया गया था। इसके अतिरिक्त, जर्नल में 26 विशिष्ट व्यक्तियों के सीए दिवस से संबंधित उत्साहवर्धक संदेशों को भी सम्मिलित किया गया था, जिनमें भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम. वैकेया नायडू और अनेक संघीय मंत्री, राज्य मंत्री, न्यायमूर्ति विनित कोठारी आदि सम्मिलित थे। इस अंक की अन्य विशिष्टियों में भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के अध्यक्ष डा. एम.एस. साहू और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री मुकेश अंबानी के साथ साक्षात्कार और अन्य विशेष फीचर जैसे कि 'एक्सीलेंस विद द डिफ्रेंस' 'डाउन द मेमेरी लेन' और 'ट्रेसिंग द रूट्स' सम्मिलित थे। इस अंक के 'अवर अचीवर' खंड में संघ के रेल और कोयला मंत्री सीए पीयूष गोयल को सम्मिलित किया गया था। जर्नल के मुख्य पृष्ठ पर अत्यंत कलात्मक रूप से आईसीएआई के, उसके हीरक जयंती वर्ष में प्रवेश करने संबंधी जश की भावना को उपलक्षित किया गया था।

**एक अन्य नियमित फीचर 'अवर अचीवर' का आरंभ किया जाना :** ब्रांड निर्माण संबंधी कार्य के रूप में और सार्वजनिक/वृत्तिक जीवन में हमारे उत्कृष्ट सदस्यों के विजन को विशिष्ट रूप से दर्शित करने के लिए एक नए दो पृष्ठ के फीचर, जिसका शीर्षक 'अवर अचीवर' है, मार्च, 2018 के अंक से आरंभ किया गया था। मार्च, 2018 के अंक में इस फीचर के अंतर्गत आईसीएआई बैंक की कार्यपालक निदेशक सीए विशाखा मूले को दर्शाया गया था, अप्रैल, 2018 के अंक में संघ के वाणिज्य और उद्योग तथा सिविल विमानन मंत्री, सीए सुरेश प्रभु, मई 2018 के अंक में दिल्ली उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सीए) राजीव शकधर, जून, 2018 के अंक में आईटीएटी (आय-कर अपील अधिकरण) के अध्यक्ष सीए जी.डी. अग्रवाल और जुलाई-अगस्त, 2018 के अंकों में क्रमशः संघ के रेल और कोयला मंत्री सीए पीयूष गोयल और विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव सीए महावीर सिंघवी, आईएफएस को दर्शित किया गया था।

**प्रत्येक वर्ष वार्षिक बजट के अवसर पर ई-फ्लैश :** संसद् में बजट के प्रस्तुतिकरण और बजट संबंधी मुद्दों के जर्नल में वास्तविक प्रकाशन के बीच समय अंतराल को ध्यान में रखते हुए, सदस्यों को वास्तविक समय में अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के लिए संसद् में बजट के वास्तविक प्रस्तुतिकरण के तुरंत पश्चात् वित्त विधेयक में अंतर्विष्ट संशोधनों के एक ई-प्रकाशन (ई-फ्लैश) को आईसीएआई की वेबसाइट पर रखा गया था और उसके लिंक को सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेज दिया गया था।

**जर्नल के अद्यतन विधिक खंड (निर्णय) का उन्नयन :** अध्ययन बोर्ड, प्रत्यक्ष कर समिति, अप्रत्यक्ष कर समिति, अंतर्राष्ट्रीय कराधान समिति, निगम विधि और निगम शासन समिति, बैंककारी, बीमा और पेंशन संबंधी समिति, संपादकीय बोर्ड और आर्थिक, वाणिज्यिक विधियों और डब्ल्यूटीओ संबंधी समिति के सहयोग और समन्वय से मूल्यवर्धित सेवा के रूप में पाठकों/सदस्यों के फायदे के लिए जर्नल के विधिक निर्णयों संबंधी खंड/फीचर का उन्नयन/उसमें सुधार करने के लिए एक प्रणाली स्थापित की गई है।

**जर्नल की विधिक अद्यतन जानकारी खंड के अधीन दिवाला और अनुशासन संबंधी मामलों की दो नई श्रृंखलाएं :** विधिक अद्यतन जानकारी खंड को आगे और सुदृढ़ किया गया था और उसमें दो सर्वाधिक सुसंगत दिवाला और शोधन

अक्षमता मामलों और अनुशासन संबंधी मामलों की नई श्रृंखलाओं को जर्नल के जून, 2017 के अंक से सम्मिलित करके और अधिक जानकारी को समाविष्ट किया गया था।

**अपने आचार को जानें, पुनः आरंभ किया जाना :** सदस्यों के लिए एक अन्य उपयोगी फीचर, अपने आचार को जानें, को जून, 2017 के अंक से पुनः आरंभ किया गया था, इस फीचर को नैतिक मानक बोर्ड द्वारा तैयार किया जाता है और यह फीचर वृत्तिक और सदस्यों से संबंधित नैतिक मुद्दों को प्रश्नोत्तर रूप में उपदर्शित करता है।

**प्रकाशित वेबकास्टों से संबंधित संक्षिप्त जानकारी :** संपादकीय बोर्ड ने, जर्नल के नवंबर, 2017 अंक से यथा संभव रूप से पाठकों की जानकारी और उपयोग के लिए यथासंभव आवर्तिता के साथ पिछले तीन मास के दौरान आयोजित वेबकास्टों (वेबकास्टों के विषय, उनके वेब लिंक सहित) के संबंध में संक्षिप्त जानकारी प्रकाशित करने का विनिश्चय किया था।

**"मीडिया में आईसीएआई" नामक एक नए नियमित फीचर को आरंभ करना :** जर्नल के दिसंबर, 2017 के अंक से "मीडिया में आईसीएआई" नामक एक नए नियमित फीचर को आरंभ किया गया था, जिसके अधीन आईसीएआई के संबंध में सकारात्मक मीडिया कवरेज की कुछ चुनी गई मुद्रित प्रतियों को प्रकाशित किया गया था।

### **अंकीय पाठों के अनेक रूपों का उन्नयन**

**ई-जर्नल :** द चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल, जो कि इस जर्नल का इलेक्ट्रानिक पाठ है, आईसीएआई की वेबसाइट [www.icaai.org](http://www.icaai.org) पर आनलाइन रूप से एक उच्च प्रौद्योगिकी और उपयोक्ता मित्र ई-पत्रिका के रूप में उपलब्ध है, को और अधिक समुन्नत किया गया था तथा उसे नवीनतम एचटीएमएल 5 प्रौद्योगिकी पर आधारित एक नए ई-पत्रिका मंच वी 6 पर पूर्ण रूप से स्थानांतरित किया गया था। ई-जर्नल का नया पाठ, पूर्ववर्ती पाठ की तुलना में तीव्र तथा अधिक क्रियाशील है, जिससे एक बेहतर उपयोक्ता अनुभव प्राप्त होता है तथा यह और अधिक बेहतर मोबाइल अनुरूपता प्रस्थापित करता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंटों की नई पीढ़ी की अपेक्षाओं के अनुरूप है।

**पीडीएफ प्ररूप में जर्नल :** तथापि, पाठकों के लिए और अधिक तथा वैकल्पिक सुविधाओं को आरंभ करने, विशिष्ट रूप से अंतर्वस्तुवार पृथक् डाउनलोड के लिए जर्नल को पीडीएफ प्ररूप में वेबसाइट पर रखा जाता है और साथ ही इसके लिए अनुक्रमणिका पद्धति को अपनाया जाता है। अंकीय जर्नल के जुलाई, 2002 के आगे से पिछले सार संग्रह आईसीएआई की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

**मोबाइल पर जर्नल :** इसके अतिरिक्त, यह ई-जर्नल अब मोबाइल पर भी उपलब्ध है तथा यह आईओएस (आई पैड/आई फोन आदि) और एंड्रयाड युक्तियों के समनुरूप है। इस जर्नल तक पहुंच को <http://www.icaai.org/> के अधीन 'ई-जर्नल' टैब पर सुकर बनाया जा सकता है। यह ई-जर्नल आईसीएआई मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है।

**जर्नल हार्डलाईट ईमेलर्स :** एक अतिरिक्त सेवा के रूप में जर्नल के प्रत्येक अंक की विशिष्टियों को संक्षिप्त रूप में तथा जर्नल में सम्मिलित अध्यक्ष के संदेश को सभी सदस्यों को ई-मेल किया जाता है।

**वर्ष 1952 से सभी जर्नलों की डीवीडी :** चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल के सभी पाठकों को एकल बिन्दु संदर्भिका उपलब्ध कराने की एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में तथा उनकी बेहतर रूप से सेवा करने में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के विचार से, जर्नल के सभी पूर्व अंकों की एक डीवीडी भी पाठकों और अन्य पणधारियों के लिए उपलब्ध है। यद्यपि, दस वर्ष के जर्नलों (जुलाई, 2002 – जून, 2012) की एक डीवीडी पीडीएफ प्ररूप में न्यूनतम लागत पर पाठकों के लिए निकाली गई थी, अभी हाल ही में एक एचटीएमएल कृत डीवीडी, जिसमें द चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल के 63 वर्षों के सभी अंक (जुलाई, 1952 से जून, 2015) अंतर्विष्ट हैं, भी जारी की गई है। इस एचटीएमएल – पाठ डीवीडी में खोज पद्धति समाविष्ट है, जिससे पाठक अंतर्वस्तु को लेखांकन, संपरीक्षा, कराधान आदि जैसे कुंजी शब्दों और साथ ही मास, वर्ष, जिल्द, प्रवर्ग (जैसे कि परिपत्र और अधिसूचना, आईसीएआई समाचार, विधिक निर्णय आदि), लेखक आदि के माध्यम से खोज सकेंगे।

### **'आई गो ग्रीन विद आईसीएआई' पहल**

आईसीएआई के बहु आयामी हरित अभियान के भागरूप में, हरित क्रांति की सोच रखने वाले सदस्यों और द चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल के अन्य पाठकों को हाल ही में एक विकल्प प्रदान किया गया था, जिसके अधीन वे वृक्षों को बचाने के लिए जर्नल की हार्ड प्रति को न लेकर जर्नल के विभिन्न इलेक्ट्रानिक पाठों का विकल्प ले सकते थे। इस संबंध में

प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने के लिए एक माइक्रो वेबसाइट को भी स्थापित किया गया था। एक उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया के रूप में, लगभग 7,000 पाठकों ने जर्नल की हार्ड कॉपी को न लेने का विकल्प चुना था। यह सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। आईसीएआई के मुख पृष्ठ पर सतत उद्घोषणाओं, जर्नल में नियमित उद्घोषणाओं, ई-मेल की टैग लाइन आदि के माध्यम से इस पहल का प्रचार करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

### **आईसीएआई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में योगदान**

(क) सम्मेलन के प्रत्येक दिन की कार्यवाहियों के पूर्ण व्यौरों के साथ दैनिक क्रानिकल (समाचार-पत्र) निकाला था, जिसे सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों के बीच परिचालित किया गया था।

(ख) मुंबई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (7-8 दिसंबर, 2017 के लिए 300 पृष्ठ + पृष्ठभूमि सामग्री को प्रकाशित किया गया था, जिसमें वक्ताओं के प्रस्तुतिकरणों और प्रपत्रों के साथ सम्यक् रूप से 41 संपादित लेखों को सम्मिलित किया गया था।

### **अन्य उपलब्धियां :**

**मानार्थ सूची को अद्यतन करना :** ब्रांड के निर्माण संबंधी कार्य के भागरूप में और साथ ही आईसीएआई की वृत्ति से सुसंगत विख्यात व्यक्तियों के बीच पहुंच को गहन बनाने के लिए और संपादक बोर्ड द्वारा 28 मार्च, 2017 को आयोजित उसकी 313वीं बैठक में लिए गए विनिश्चयों के परिणामस्वरूप और संपादक बोर्ड के पदाभिहित उपसमूह द्वारा उसके पश्चात् दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए, जर्नल की विद्यमान मानार्थ सूची में असंगत 647 प्रविष्टियों को हटाकर और 203 सुसंगत प्रविष्टियों को सम्मिलित करके एक गहन पुनरीक्षण किया गया है, जो जर्नल के जुलाई, 2017 के अंक से प्रभावी हुआ है।

**जर्नल के कागज की क्वालिटी की मानीटरी :** मुद्रक द्वारा जर्नल में प्रयुक्त किए जाने वाले कागज की क्वालिटी को सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जाने वाली सतत पूर्वावधानी/मानीटरी प्रक्रिया के भाग रूप में, कार्यालय ने यादृच्छिक रूप से, केंद्रीय पलप और कागज अनुसंधान संस्थान (सीपीपीआरआई), जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है, के माध्यम से मुद्रक द्वारा प्रयुक्त कागज की परीक्षा की गई थी।

**जर्नल के मुद्रण, विपणन और प्रेषण के लिए नए विक्रेता का चुना जाना :** जर्नल के अगस्त, 2018 अंक से आईसीएआई ने जर्नल के मुद्रण, विपणन और सदस्यों को उसके प्रेषण के लिए विद्यमान स्पेंटा मल्टीमीडिया, मुंबई को हटाकर उसके स्थान पर मुंबई के ही एसएपी प्रिंट्स को नए विक्रेता के रूप में नियुक्त किया गया था। इस प्रभाव के करार पर मार्च, 2017 में हस्ताक्षर किए गए थे।

**जर्नल को डाक द्वारा भेजे जाने के लिए आरएनआई प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति का नवीकरण :** विधिक अनुपालनों के भाग रूप में बिना किसी पूर्व संदाय के जर्नल को डाक द्वारा भेजने के लिए जर्नल के आरएनआई प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति का नवीकरण किया गया था।

**सरकारी रियायती दरों पर जर्नल के निर्बाध और समय पर मुद्रण और प्रेषण को सुनिश्चित करने के लिए प्ररूप ख का पुनरीक्षण :** अनुपालन संबंधी प्रक्रियाओं के भागरूप में, कार्यालय ने आईसीएआई जर्नल द चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्ररूप ख घोषणा को पुनरीक्षित कराया है, जो सरकारी रियायती दरों पर जर्नल के निर्बाध और समय पर मुद्रण और डाक विभाग द्वारा प्रेषण के लिए आवश्यक था।

**जर्नल के अभिदाय, एयर मेल अधिभार के लिए आनलाइन संदाय करने की सुविधा :** हमारे सदस्यों को वर्धित सुविधा और सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग करने के समर्पित प्रयास के अनुरूप संपादक बोर्ड ने द चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल के लिए आनलाइन संदाय सुविधा को कार्यरत बनाया था, जिससे पूरे विश्व में फैले उसके पाठकों को फायदा हो सके। यह पाठकों के लिए सुविधापूर्ण आनलाइन संदाय सुविधा आईसीएआई की वेबसाइट पर पाठकों के दस प्रवर्गों के लिए उपलब्ध है, जिसके अंतर्गत ग्राहक, विदेशों में सदस्य, वर्गीकृत विज्ञापनकर्ता और छात्र ग्राहक सम्मिलित हैं।

**साहित्य-चोरी रोधी साफ्टवेयर करार का नवीकरण :** शिक्षाविदों, आईसीएआई के सदस्यों, छात्रों आदि सहित लेखकों द्वारा चोरी की गई साहित्य की अंतर्वस्तु को प्रस्तुत किए जाने के मामलों में हुई अत्यधिक वृद्धि का संज्ञान लेते हुए, जिसके कारण चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल की विश्वसनीयता और विश्वस्तता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना थी,

एक व्यापक साहित्य-चोरी रोधी नीति को स्थापित किया गया था और उसे इस वर्ष के लिए साहित्य-चोरी रोधी साफ्टवेयर करार के नवीकरण और उसे पुनः प्रचालन में लाकर सुदृढ़ बनाया गया था।

**मुद्रित/प्रेषित की गई जर्नल की प्रतियों की कुल संख्या के सत्यापन की प्रक्रिया को और सुदृढ़ किया जाना :** जैसा कि संपादक बोर्ड द्वारा विनिश्चय किया गया था, मुद्रित/प्रेषित की गई जर्नल की प्रतियों की कुल संख्या के सत्यापन की प्रक्रिया को और सुदृढ़ किया गया है, इस प्रक्रिया के दौरान एक ऐसे तंत्र को स्थापित किया गया है, जिसके द्वारा आईसीएआई के मुंबई स्थित कार्यालय (डब्ल्यूआईआरसी) के एक कार्मिक ने, यह अभिनिश्चित करने के लिए कि मुद्रण आदेश में उल्लिखित सभी जर्नलों को प्रेषित किया जा रहा है, (जर्नल के मई, 2017 के अंक से) मुंबई जीपीओ में जर्नल को डाक द्वारा प्रेषित किए जाने की तारीखों का मासिक निरीक्षण करना आरंभ किया है। यह तंत्र नवी मुंबई आधिकारिक संपरीक्षक द्वारा नियमित पृथक् सत्यापन के अतिरिक्त है।

## 8.5 भारत का लेखांकन संग्रहालय

लेखांकन संग्रहालय को फरवरी 2009 में सी-1, सेक्टर 1 नोएडा में स्थित संस्थान के परिसरों में स्थापित किया गया था। कारपोरेट कार्य मंत्रालय से अप्रैल, 2009 में सम्यक् अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् संग्रहालय के नाम को परिवर्तित करके भारत का लेखांकन संग्रहालय किया गया था। वर्ष 2011 में इस संग्रहालय को संस्थान के सेक्टर 62, नोएडा स्थित परिसरों में स्थानांतरित किया गया था।

आईसीएआई का लेखांकन संग्रहालय पूरे गर्व से अन्य वस्तुओं के साथ, पुरानी पांडुलिपियों, मूर्तिकलाओं, ऐतिहासिक संगतता की महत्वपूर्ण छवियों का प्रदर्शन करता है। सुमेरियाई मिट्टी का बुल्ला डिब्बा, (एक अंदर से खाली डिब्बा, जिसमें मिट्टी के टोकनों का भंडारण किया जाता था), जटिल संगणना वाले टोकनों, मिट्टी के टेबलेटों आदि, जिनमें लेखांकन संबंधी लेख, भारत और विश्व के पहले सिक्के आदि को भी प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शित की गई मर्दों में 1848एडी की एक पुरानी बही और मुनिम या पारंपरिक अकाउंटेंटों की प्रतिमाएं, कुबेर, धन के देवता (राष्ट्रीय संग्रहालय में कुबेर की प्रतिमा पर आधारित), चाणक्य और लुका पासिओली, दोहरी प्रविष्टि लेखांकन के संबंध में प्रथम प्रकाशित पुस्तक के लेखक, जिन्हें इसी कारण से लेखांकन के पिता के रूप में भी जाना जाता है, प्रतिमाएं प्रदर्शित की गई हैं। हडप्पा काल की मुद्राओं की प्रतिलिपियों को भी दर्शित किया गया है।

**प्रादेशिक परिषदों, डीसीओ और शाखाओं में प्रोटोटाइप :** संग्रहालय के सभी प्रोटोटाइपों को संस्थान के सभी पांच प्रादेशिक परिषद् कार्यालयों और 12 डीसीओ (विकेन्द्रीकृत कार्यालय) में स्थापित किया गया है। इसके पश्चात्, यह विनिश्चय किया गया था कि इन प्रोटोटाइपों की स्थापना संस्थान की सभी शाखाओं में भी की जाए। इस प्रकार अभी तक 107 शाखाओं में प्रोटोटाइपों की स्थापना की गई है, उन शाखाओं को छोड़कर, जिन्होंने अभिव्यक्त रूप से स्थान की कमी के कारण अपनी असमर्थता व्यक्त की थी। लेखांकन संग्रहालय के प्रोटोटाइप से आधिकारिक रूप से प्रदर्शन हेतु लेखांकन संग्रहालय का कार्यरत माडल अभिप्रेत है – जिसमें लेखांकन वृत्ति के पणधारियों को उसकी विरासत के संबंध में संसूचित करना और साथ ही संस्थान के सेक्टर 62, नोएडा स्थित परिसरों में अवस्थित भारतीय लेखांकन संग्रहालय की विद्यमानता के संबंध में जानकारी का प्रसार करना भी है। इसका उद्देश्य लेखांकन वृत्ति के बौद्धिक और आदर्श व्यवसाय और उसकी विरासत को लोकप्रिय बनाना भी था।

## प्रकाशन

संग्रहालय ने, उसके शुभारंभ के साथ ही फरवरी, 2008 में एक बुकलैट का प्रकाशन किया था, जिसमें उसके संबंध में संक्षिप्त विवरण और साथ ही सुसंगत छवियों को अंतर्विष्ट करने वाले पांच पोस्टकार्डों का एक सेट भी सम्मिलित था। इसके पश्चात् इस बुकलैट को पुनरीक्षित किया गया था और इसके दूसरे संस्करण का प्रकाशन किया गया था, जो आज की तारीख में 10 रूपए प्रत्येक प्रति की अत्यधिक कम कीमत पर उपलब्ध है। तथापि, इसकी प्रतियां संस्थान के विभिन्न महत्वपूर्ण आयोजनों में भाग लेने वाले व्यक्तियों/प्रतिनिधि मंडलों को निःशुल्क रूप से वितरित की जाती हैं। इसे म्यूजियम की वेबसाइट पर भी रखा गया है।

## संग्रहालय की वेबसाइट

संग्रहालय की एक स्वतंत्र वेबसाइट, अर्थात् <http://ami-icai.org/>, को भी वर्ष 2017 में स्थापित किया गया है जिससे संग्रहालय और साथ ही वृत्तिक के पणधारियों के फायदे के लिए संग्रहालय की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके।



## 8.6 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 में संशोधन

परिषद् ने 24 से 26 मई, 2018 के दौरान आयोजित अपनी 375वीं बैठक, जो आस्थगित हुई थी और / उसके पश्चात् पुनः 13 और 14 जून तथा 18 जून, 2018 को जारी रही थी, में संस्थान की परिषद् और प्रादेशिक परिषदों के त्रैवार्षिक निर्वाचनों से संबंधित विद्यमान प्रक्रियाओं, नियमों और विनियमों के पुनर्विलोकन संबंधी समूह की रिपोर्ट पर विचार किया था, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक मतदान भी है। परिचर्चाओं के पश्चात्, परिषद् ने समूह द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार किया था और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (परिषद् का निर्वाचन) नियम, 2006, चार्टर्ड अकाउंटेंट (निर्वाचन अधिकरण) नियम, 2006 और चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 में प्रारूप संशोधनों का अनुमोदन किया था, जिन्हें अनुमोदनार्थ केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत किया है।

## 9. सदस्य

### 9.1 सदस्यता

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान आईसीएआई द्वारा 11,886 नए सदस्यों को दर्ज किया गया था, जिससे 1 अप्रैल, 2018 को आईसीएआई की कुल सदस्यता संख्या 2,82,193 हो गई है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, पूर्व वर्ष के 6,712 के आंकड़ों की संख्या की तुलना में 3,367 सहयोजित सदस्यों को प्रविष्ट किया गया था।

#### 1 अप्रैल, 2018 को सदस्यों की कुल संख्या

सदस्यों का प्रवर्ग	अध्येता (1)	सहयोजित (2)	स्तंभ (1) और (2) का योग
पूर्णकालिक व्यवसाय में	75093	49580	124673
अंशकालिक व्यवसाय में	2741	5066	7807
जो व्यवसाय में नहीं हैं	14255	135458	149713
<b>योग</b>	<b>92089</b>	<b>190104</b>	<b>282193</b>

### 9.2 दीक्षांत समारोह

संस्थान, नवम्बर, 2008 से अपने नए नामांकित सदस्यों को सदस्यता प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन कर रहा है। पांचों प्रादेशिक कार्यालयों के अधीन निम्नलिखित नौ स्थानों पर 2 सितंबर, 2018 को नवंबर, 2017 से मई, 2018 की अवधि को सम्मिलित करते हुए नए नामांकित सदस्यों के लिए "दीक्षांत समारोह 2018" के पहले चरण को आयोजित करने का प्रस्ताव किया गया है :

1. अहमदाबाद	6. कोलकाता
2. मुंबई	7. जयपुर
3. पुणे	8. कानपुर
4. चेन्नई	9. नई दिल्ली
5. हैदराबाद	

### 9.3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कल्याण निधि

दिसम्बर, 1962 में स्थापित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कल्याण निधि ऐसे जरूरतमंद व्यक्तियों को, जो संस्थान के सदस्य हैं या रहे हैं और उनके आश्रितों को, उनके भरण पोषण तथा शिक्षा और चिकित्सा आदि की उभरती अत्यावश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। निधि की वित्तीय और अन्य विशिष्टियां निम्नानुसार हैं :

**सदस्यता के ब्यौरे**

1.	31 मार्च, 2017 को कुल आजीवन सदस्य	132883
2.	31 मार्च, 2018 को कुल आजीवन सदस्य	134596
3.	नए आजीवन सदस्यों में कुल वृद्धि (31 मार्च, 2018 को यथाविद्यमान)	1713

**वित्तीय विशिष्टियों के ब्यौरे**

	31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान (रुपए)	31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान (रुपए)
1. दी गई कुल वित्तीय सहायता	92,10,500	1,13,28,500
2. प्रशासनिक खर्चे	1,000	567
3. वर्ष के दौरान निधि में अधिशेष	2,04,80,000	69,93,000
4. निधि का अतिशेष	3,68,34,000	1,63,54,000
5. कोरपस का अतिशेष	19,86,23,000	18,49,63,000

**9.4 एस. वैद्यनाथ अय्यर स्मारक निधि**

निधि की आजीवन सदस्यता 31 मार्च, 2017 को 7,682 के मुकाबले 31 मार्च, 2018 को बढ़कर 7,795 हो गई थी। 31 मार्च, 2017 को निधि के पास जमा अतिशेष 46,84,000/- रुपए के मुकाबले 31 मार्च, 2018 को 47,97,000/- रुपए है।

**9.5 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स छात्र कल्याण निधि (सीएएसबीएफ)**

आईसीएआई के साथ रजिस्ट्रीकृत छात्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लक्ष्य और उद्देश्यों से अगस्त, 2008 में इस निधि की स्थापना की गई थी। वर्ष 2017-18 के लिए 480 ऐसे आर्टिकलड सहायकों, जो आईपीसीसी और आईआईपीसीसी के लिए रजिस्ट्रीकृत हैं, को वित्तीय सहायता के रूप में 1500 रुपए प्रति मास की दर पर और 231 ऐसे आर्टिकलड सहायकों, जो फाइनल पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत हैं, को वित्तीय सहायता के रूप में 2000 रुपए प्रति मास की दर पर एक वर्ष के लिए वित्तीय सहायता मंजूर किए जाने पर विचार किया जा रहा है। 31 मार्च, 2017 को 12,59,75,000/- रुपए की तुलना में 31 मार्च, 2018 को साधारण निधि में 13,91,82,000/- रुपए का अतिशेष जमा था।

**01.04.2018 को सदस्यों संबंधी आंकड़े**

<b>अध्येता :</b>	पूर्णकालिक व्यवसाय में	75093
	अंशकालिक व्यवसाय में	2741
	जो व्यवसाय में नहीं हैं	14255
		<b>92089</b>
<b>सहयोजित :</b>	पूर्णकालिक व्यवसाय में	49580
	अंशकालिक व्यवसाय में	5066
	जो व्यवसाय में नहीं हैं	135458

कुल सदस्यता :

190104

282193

	अध्येता				सहयोजित				
	व्यवसाय में				व्यवसाय में				
क्षेत्र	पूर्णकालिक	अंशकालिक	जो व्यवसाय में नहीं हैं	योग	पूर्णकालिक	अंशकालिक	जो व्यवसाय में नहीं हैं	योग	कुल योग
पश्चिमी	21824	779	4133	26736	17388	1859	51436	70683	97419
दक्षिणी	16124	740	3416	20280	7357	1059	26317	34733	55013
पूर्वी	7400	204	1308	8912	3846	323	11437	15606	24518
मध्य	14266	365	1863	16494	10806	778	20510	32094	48588
उत्तरी	15479	653	3535	19667	10183	1047	25758	36988	56655
योग	75093	2741	14255	92089	49580	5066	135458	190104	282193

## 10. अध्ययन बोर्ड (बीओएस)

संस्थान का अध्ययन बोर्ड, चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठ्यचर्या के प्रशासन और चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठ्यक्रम करने वाले लगभग 7,25,632 छात्रों को सैद्धांतिक अनुदेश प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। इस अवधि के दौरान बोर्ड की महत्वपूर्ण पहलों और उपलब्धियों को नीचे उल्लिखित किया गया है :

### I. शैक्षिक अंतःनिवेश

शिक्षा और प्रशिक्षण की नई स्कीम का कार्यान्वयन

नई स्कीम वृत्ति की समकालीन अपेक्षाओं और प्रत्याशाओं के अनुरूप हैं और साथ ही यह सक्रिय वैश्विक कारबार परिस्थितियों को अध्ययपेक्षाओं के अनुसार सुमेलित है।

### अध्ययन सामग्रियों का पुनरीक्षण

छात्रों की जानकारी को अद्यतन करने की सतत प्रक्रिया के भागरूप में मध्यवर्ती (आईपीसी) और फाइनल स्तर पर विभिन्न अध्ययन सामग्रियों की अंतर्वस्तु को अद्यतन/पुनरीक्षित किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित सामग्रियों को भी जारी किया गया था :

(1) अनुपूरक अध्ययन सामग्री :--

- लेखांकन
- कारबार विधि नैतिक और संसूचना
- निगम और संबद्ध विधियां
- अप्रत्यक्ष कर विधियां

## 2) पुनरीक्षण प्रश्न-पत्र और सुझाए गए उत्तर

इसे संस्थान की वेबसाइट पर भी निःशुल्क डाउनलोडिंग सुविधा के साथ रखा गया था।

पुनरीक्षित स्कीम के अनुसार, फाउंडेशन, मध्यवर्ती पाठ्यक्रमों और फाइनल पाठ्यक्रम की अध्ययन सामग्री की अंतर्वस्तु को भी पुनः तैयार और विकसित किया गया है।

### छात्र जर्नल

वर्ष 2017-18 के दौरान बीओएस के द्वारा उठाया गया एक अन्य महत्वपूर्ण कदम छात्र जर्नल में विषयवार कैप्सूल को तैयार करना और उसका प्रकाशन करना था। इस कदम ने संबंधित विषयों को दोहराए जाने में छात्रों की सहायता की है।

### II. आईटी संबंधी पहलें

आईसीएआई क्लाउड परिसर सीए पाठ्यक्रम के छात्रों की जानकारी, नामांकन, शैक्षणिक, प्रशासनिक, परीक्षा संबंधी तथा अन्य अपेक्षाओं के लिए एकल विंडो का कार्य करता है। ईट और गारे से बने परिसर की प्रणाली से आगे बढ़ते हुए, यह परिसर बटन के एक क्लिक के साथ ही छात्रों को उनके घर पर सीए. पाठ्यक्रम के लिए दूरस्थ शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराता है। यह निम्नलिखित दूरस्थ शिक्षा सुविधाएं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराता है :

- **वीडियो व्याख्यान :** सीए पाठ्यक्रम के सभी विषयों के लिए वीडियो आधारित प्रशिक्षण (वीवीटी) व्याख्यान आईसीएआई के क्लाउड परिसर पर उपलब्ध हैं, जिनका उद्देश्य कदम-दर-कदम व्यावहारिक समस्याओं की समाधान प्रक्रिया का अध्यापन करना और व्यवहारिक विषयों तथा सैद्धांतिक विषयों के लिए अवधारणात्मक स्पष्टता उपलब्ध कराना है। इस समय, 29 जून, 2018 तक, नई स्कीम के लिए 469 घंटों के 274 व्याख्यानों और पुरानी स्कीम के लिए 559 घंटों के 664 व्याख्यानों को क्लाउड परिसर पर रख दिया गया है।
- **डिजिटल पठन केंद्र :** शिक्षा और प्रशिक्षण की नई स्कीम के सभी विषयों के लिए अध्यायवार ई-पुस्तकें डिजिटल पठन केंद्र के माध्यम से आईसीएआई क्लाउड कैम्पस पर उपलब्ध हैं। छात्र अब उनकी व्याख्या करने और उनके संबंध में नोट तैयार करने में समर्थ हैं, जिन्हें उनके उपयोक्ता अकाउंट में प्रतिधारित किया जाएगा। आज की तारीख तक एक लाख छात्रों ने इस मंच पर स्वयं को रजिस्टर किया है और वे इस सुविधा का उपयोग कर रहे हैं।
- **वेबकास्ट :** फाइनल और मध्यवर्ती (आईपीसी) के लिए मई, 2017 और नवंबर, 2017 में कराई जाने वाली परीक्षाओं के लिए प्रत्येक विषय को उत्तीर्ण करने के लिए पद्धति के संबंध में विशिष्ट संकाय सदस्यों द्वारा लाइव वेबकास्टों का आयोजन किया गया था। जीएसटी, समवर्ती संपरीक्षा, अपीलों का प्रारूपण, विवरणियों की फाइलिंग आदि जैसे विषयों पर विशेषीकृत वेबकास्टों का भी आयोजन किया गया था। इन वेबकास्टों की रिकार्डिंग बाद में देखने के लिए आईसीएआई के क्लाउड परिसर पर उपलब्ध है।
- **आनलाइन परामर्शी सत्र :** बीओएस ने, किसी विशिष्ट विषय पर छात्राओं की शंकाओं का समाधान करने के लिए बीओएस के संकाय सदस्यों द्वारा लाइव आनलाइन परामर्शी कथनों का आयोजन किया है। इन सत्रों की रिकार्डिंग आईसीएआई के क्लाउड परिसर पर उपलब्ध है।
- **बीओएस ज्ञान पोर्टल :** बीओएस ज्ञान पोर्टल सीए पाठ्यक्रम के लिए सभी शैक्षिक अंतर्वस्तु उपलब्ध कराता है।

क्लाउड कैम्पस पर उपलब्ध अन्य सुविधाओं में आर्टिकल नियोजन पोर्टल, केंद्रीयकृत वितरण प्रणाली और जीएमसीएस, ओसी और आईटीटी पाठ्यक्रमों के लिए आनलाइन रजिस्ट्रीकरण पोर्टल सम्मिलित हैं।

- **आर्टिकल नियोजन पोर्टल :** आर्टिकल नियोजन पोर्टल लिंक छात्रों को, उनके अधिमानी अवस्थान पर व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए सीए फर्मों के साथ ऑनलाइन रूप से रजिस्टर करने और चुने जाने के लिए समर्थ बनाता है।
- **केंद्रीयकृत वितरण प्रणाली :** इस आनलाइन भंडार पोर्टल के माध्यम से, छात्र, सदस्य और अन्य पणधारी आनलाइन रूप से सभी सुसंगत प्रकाशनों और वस्तुओं के लिए क्रय आदेश करने में समर्थ हो गए हैं। पुस्तकों को उनके घर में परिदत्त किया जाता है।

- आईसीआईटीएसएस और उन्नत आईसीआईटीएसएस पाठ्यक्रमों के लिए आनलाइन रजिस्ट्रीकरण पोर्टल : यह आनलाइन रजिस्ट्रीकरण पोर्टल छात्रों को एमसीएस/ओसी/आईटीटी पाठ्यक्रमों के लिए आनलाइन रजिस्ट्रीकरण, अधिमानी अवस्थानों पर सुविधापूर्ण बैचों का चयन करने, बैच अंतरित करने, संकाय के आबंटन, पाठ्यक्रम संबंधी अनुसूची, प्रतिक्रिया को प्रस्तुत करने और प्रमाणपत्र का सृजन करने में समर्थ बनाता है। छात्र इस पोर्टल के माध्यम से आनलाइन रूप से फीस का संदाय करने में भी समर्थ है।

### III. अन्य पहलें

#### छात्र क्रियाकलाप संबंधी पोर्टल

छात्रों को संस्थान के छात्रों से संबंधित विभिन्न आयोजनों (सम्मेलनों, संगोष्ठियों, क्विज, टैलेंट हंट, कार्यशालाओं, अल्पकालिक पाठ्यक्रमों, मौक परीक्षाओं, त्यौहारों, खेल कूद प्रतियोगिताओं, विशेष परामर्शी कार्यक्रमों आदि) के लिए आनलाइन रूप से रजिस्टर करने हेतु समर्थ बनाने के लिए एक सामान्य छात्र क्रियाकलाप संबंधी पोर्टल को स्थापित किया गया है। छात्र अब स्वयं को संस्थान के किसी क्रियाकलाप हेतु इस पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर कराने में समर्थ होंगे। इससे समय और ऊर्जा की बचत होगी। इसके अतिरिक्त, यह पोर्टल छात्रों की, विभिन्न आयोजनों के संबंध में प्रतिक्रिया को प्राप्त करने में भी समर्थ होगा यह उन्हें उनके सीपीई घंटों के बारे में जांच करने की अनुज्ञा भी प्रदान करेगा।

#### आनलाइन आर्टिकल नियोजन पोर्टल

संस्थान ने एक वैकल्पिक आनलाइन आर्टिकल नियोजन पोर्टल स्थापित किया है। यह पोर्टल पात्र छात्रों को उनके आर्टिकल प्रशिक्षण हेतु सीए फर्मों में नियोजन प्राप्त करने में सहायता करता है। यह चार्टर्ड अकाउंटेंटों की ऐसी फर्मों, जिनमें आर्टिकल सहायकों के लिए रिक्तियां विद्यमान हैं, डाटा बेस से अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध करने और उन अभ्यर्थियों के साथ परस्पर क्रिया करने के लिए उन्हें उनके कार्यालयों में साक्षात्कार/परस्पर क्रिया करने हेतु बुलाने में समर्थ बनाता है। भाग लेने वाली सीए फर्मों और पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत करने वाले छात्रों से कोई फीस प्रभारित नहीं की जाती है।

#### पठन कक्ष

सीए छात्रों को उनके पठन हेतु स्थान उपलब्ध कराने तथा उनके द्वारा चुने गए स्थान पर कहीं भी और किसी भी समय उनके द्वारा स्थान बुक किए जाने के लिए बीओएस ने एक पठन कक्ष पोर्टल आरंभ किया है। छात्र आनलाइन रूप से, हमारी प्रादेशिक परिषदों/शाखाओं में देश भर में चलाए जा रहे पठन कक्षों, जो 24x7 उपलब्ध हैं, के लिए एक दिन/एक सप्ताह/एक मास के लिए रजिस्ट्रीकृत करने और रजिस्ट्रीकरण के 24 घंटे के भीतर चुने गए केंद्र को सीधे पेटीएम (क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग/पेटीएम वॉलेट) के द्वारा संदाय करके अपने स्थान की पुष्टि करने में समर्थ होंगे। अभी तक, 116 पुस्तकालय-सह-पठन कक्षों तथा 41 अतिरिक्त पठन कक्षों को प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं द्वारा चलाया जा रहा है।

#### बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा, भारतीय कौशल परिषद् के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

आईसीआई ने बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा, भारतीय कौशल परिषद् (बीएफएसआई एसएससी) के साथ 19 जनवरी, 2018 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के तत्वावधान में सृजित किया गया है।

इस समझौता ज्ञापन के अनुसार, आईसीआई और बीएफएसआई एसएसआई, दोनों एक साथ मिलकर अगले पांच वर्षों में पूरे देश में लगभग 5,00,000 व्यक्तियों हेतु नौकरियों का सृजन करने के लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए प्रयास करेंगे। ये नौकरियों मुख्यतः लेखांकन, वित्त, बीमा, बैंकारी और कराधान, जिसके अंतर्गत जीएसटी भी है, के क्षेत्रों में होंगी।

बीएफएसआई एसएससी विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पाठ्यक्रम आरंभ करेगी और आईसीआई उसके ज्ञान भागीदार के रूप में कार्य करेगा। आईसीआई, पाठ्यक्रमा को तैयार करने और अंतर्वस्तु के सृजन में बीएफएसआई एसएससी की सहायता करेगा।

आईसीआई देश भर में मौजूद प्रशिक्षकों के अपने नेटवर्क को भी संसाधनों के रूप में उपलब्ध कराएगा और साथ ही अपने सदस्यों के बीच बीएफएसआई एसएससी के प्रशिक्षण संबंधी क्रियाकलापों के बारे में जागरूकता का सृजन करेगा।

यह समझौता ज्ञापन आईसीएआई के इस मिशन के अनुरूप है कि वह राष्ट्र निर्माण में एक सक्रिय भागीदार है और सरकार की पहलों का प्रचार और प्रसार करने के लिए एक प्रभावी माध्यम है और वांछित लक्ष्यों की पूर्ति में सरकार की सहायता करता है।

#### IV. विकास संबंधी कार्यक्रम

वृत्तिक कौशल विकास संबंधी चार सप्ताह का आवासीय कार्यक्रम : वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के छह बैचों (पांच उत्कृष्टता केंद्र हैदराबाद में और एक उत्कृष्टता केंद्र जयपुर में) का संचालन किया गया था और 191 छात्रों को प्रशिक्षित किया गया था।

#### राष्ट्रीय टैलेंट हंट 2017-18

इस वर्ष पहली बार 16 दिसंबर, 2017 को राष्ट्रीय टैलेंट हंट के बैनर के अधीन वक्तृता और क्विज प्रतिस्पर्धा की फाइनल प्रतियोगिताओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था, जिसमें देश के 20 सर्वोत्तम वक्ताओं ने 89 भाग लेने वाली शाखाओं के 1292 छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करके आगे बढ़ते हुए इसमें भाग लिया था। अध्ययन बोर्ड ने उनके वक्तृता संबंधी तथा प्रस्तुतिकरण कौशलों को और अधिक तीक्ष्ण करने हेतु मुख्य आयोजन से पूर्व 13 से 15 दिसंबर, 2017 के दौरान उनके लिए अनुकूलन सत्रों का आयोजन किया था।

श्री मनोज तिवारी, (संसद् सदस्य, लोक सभा) ने मुख्य अतिथि के रूप में इस समारोह की शोभा बढ़ाई थी और ज्यूरि सदस्यों में सीए रोहिणी अग्रवाल, सीए अमेय नायक, सीए अतुल चावला और सीए धर्मेन्द्र जैमिनी, संस्थान के माननीय उपाध्यक्ष और परिषद् के सदस्यों के साथ सम्मिलित हुए थे।

वक्तृता प्रतिस्पर्धा के पहले दो विजेताओं और क्विज प्रतियोगिता की विजेता टीम ने, दक्षिण भारत अकाउंटेंट्स फेडरेशन, जो सार्क देशों को सम्मिलित करने वाला एक निकाय है, द्वारा 30 जनवरी, 2018 को कांठमाडू में आयोजित क्विज और वक्तृता प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था। चेन्नई से सुश्री जनानी कादिरवेलू पलानीवेलू और मेरठ से श्री सत्यम श्रेय गुप्ता को भारत से प्रथम और द्वितीय विजेता के रूप में घोषित किया गया था।

#### 5 सितंबर, 2017 को शिक्षक दिवस :

इस वर्ष शिक्षक दिवस को 5 सितंबर, 2017 को अपनी प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं के माध्यम से देश भर में, मेरा प्रधानाचार्य – मेरी दृढ़ता, विषय के साथ मनाया गया था, ताकि सीए और सीए छात्रों के बीच एक सुदृढ़ अध्यापक और छात्र संबंधों को स्थापित किया जा सके। छात्रों के बीच उनके शिक्षकों के प्रति आदर और आभार की भावना का सृजन करने के लिए बोर्ड ने इस विषय से संबंधित डिस्प्ले पिक्चर (डीपी) के साथ कुछ ई-कार्डों और एसएमएस कोड्स को छात्रों को उपलब्ध कराया था।

इस अवसर पर फोटो प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था, जिसमें छात्रों से भी यह अपेक्षा की गई थी इस वर्ष की थीम के अनुसार पोर्टल पर अपने प्रधानाचार्य के साथ अपनी फोटो अपलोड करें। प्रादेशिक और शाखा स्तर पर निबंध प्रतियोगिता और कोटेशन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था।

इस अवसर पर सीए छात्रों और सदस्यों के लिए वेबकास्ट का आयोजन किया गया था, जिसे आईसीएआई के अध्यक्ष, बीओएस के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदमश्री से सम्मानित सीए टी.एन. मनोहरन और केंद्रीय परिषद् के सदस्यों द्वारा संबोधित किया गया था। शिक्षक दिवस समारोह एक अत्यंत सफल आयोजन था।

#### सीए छात्र टैलेंट खोज – 2018

आईसीएआई के बीओएस ने 28 जून, 2018 को नई दिल्ली में 'सीए छात्र टैलेंट खोज – 2018' का आयोजन किया था जिसमें देश भर से आए छात्रों ने आईसीएआई की विभिन्न शाखाओं में क्विज प्रतियोगिता, वक्तृता, वाद्य संगीत और नुक्कड़ ड्रामा में भाग लिया था और इनके विजेता आगे प्रादेशिक स्तर की प्रतियोगिताओं तक पहुंचे थे। 69 छात्र अंतिम प्रतियोगियों के रूप में सामने आए थे, जिन्हें ग्रांड फिनाले के लिए आमंत्रित किया गया था।

बीओएस ने वक्तृता के 20 प्रतियोगियों को ग्रांड फिनाले से एक दिन पूर्व प्रशिक्षित किया था जिससे की उनके वक्तृता और प्रस्तुतिकरण संबंधी कौशलों को अधिक समृद्ध बनाया जा सके।

इस आयोजन में सुश्री रैचेल ग्रिम्स, (अध्यक्ष, आईएफएसी) ने मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होकर इसकी शोभा बढ़ाई थी और उनके अतिरिक्त इस आयोजन में आईसीएआई के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, बीओएस के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, आईसीएआई की केंद्रीय परिषद् के सदस्य, साफा प्रतिनिधिमंडल भी सम्मिलित हुए थे। ज्यूरी में सीए भावना सिंघल, सीए अरुण गर्ग, डा. पी.सी. जैन और सीए मनप्रीत सिंह सम्मिलित हुए थे।

### मई, 2018 की परीक्षाओं के लिए छात्रों हेतु मोक परीक्षा

अध्ययन बोर्ड ने फाउंडेशन, मध्यवर्ती, आईपीसीसी और फाइनल (पुराने और नए) हेतु मई, 2018 की परीक्षाओं के लिए छात्रों हेतु मोक परीक्षा का आयोजन किया था। मई, 2018 की परीक्षाओं के लिए मोक प्रश्न पत्र से संबंधित आंकड़ों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

पाठ्यक्रम	स्तर	शृंखला - I		शृंखला - II	
		आयोजित करने वाली आरसी/शाखा की संख्या	सभी प्रश्न पत्रों में बैठने वाले छात्रों की संख्या	आयोजित करने वाली आरसी/शाखा की संख्या	सभी प्रश्न पत्रों में बैठने वाले छात्रों की संख्या
पुराना	आईपीसीसी	115	8695	32	6641
	फाइनल	115	17447	32	14698
नया	फाउंडेशन	115	2179	32	1559
	मध्यवर्ती	115	8027	32	6234
	फाइनल	115	1430	32	1274

इसी प्रकार अध्ययन बोर्ड ने, जून, 2018 की परीक्षाओं के लिए सीपीटी के छात्रों हेतु मोक परीक्षा का आयोजन किया था। मई, 2018 की परीक्षाओं के लिए मोक प्रश्न पत्र से संबंधित आंकड़ों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

पाठ्यक्रम	शृंखला - I		शृंखला - II	
	आयोजित करने वाली आरसी/शाखा की संख्या	सभी प्रश्न पत्रों में बैठने वाले छात्रों की संख्या	आयोजित करने वाली आरसी/शाखा की संख्या	सभी प्रश्न पत्रों में बैठने वाले छात्रों की संख्या
सीपीटी	85	6694	73	4127

छात्र समर्थन पहलें - सीए छात्रों के लिए बीओएस, सेक्टर 62, नोएडा में निःशुल्क टेलीफोन सेवा

- निःशुल्क टेलीफोन सेवा : बीओएस ने 11 मई, 2017 से, छात्र समर्थन पहल के रूप में देश भर के सीए छात्रों के प्रश्नों और समस्याओं का उत्तर देने के लिए एक निःशुल्क टेलीफोन सेवा आरंभ की है।

नंबर : 18001211330

समय : प्रातः 10 बजे से सायं 5.30 तक सोमवार से शुक्रवार तक

- एकल संपर्क बिन्दु : यह सुविधा देश भर में अवस्थित छात्रों के लिए एकल संपर्क बिन्दु के रूप में कार्य करती है।
- उच्च प्रतिक्रिया दर : प्रत्येक दिन 150 से अधिक फोन काल प्राप्त होती हैं, जिनका उत्तर, छात्र परामर्शी के पर्यवेक्षण के अधीन चार कार्यपालकों के एक सुप्रशिक्षित कार्यबल द्वारा छात्रों के समाधानप्रद रूप में दिया जाता है। आज की तारीख तक देश भर के छात्रों से प्राप्त हुए लगभग 90,000 प्रश्नों का उत्तर दिया गया है।

- **निःशुल्क पहुंच** : यह सेवा निःशुल्क है, जिससे देश भर के दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को सुगम रूप से पहुंच वाली सेवा के माध्यम से बीओएस तक पहुंच बनाने में समर्थ बनाया जा सके।
- **शिकायतों का समय पर समाधान और निपटान** : इस सेवा पहल का प्रयोजन छात्रों को उनकी अपेक्षा के अनुसार समय पर जानकारी (साधारण और विषय विनिर्दिष्ट, दोनों प्रकार की) उपलब्ध कराने और उनकी समस्याओं का शीघ्रताशीघ्र समाधान करना है।
- **नवीनतम जानकारी का प्रसार (सुस्पष्ट)** : ऐसी जानकारी, जिसका प्रचार और प्रसार किया जा रहा है, अद्यतन और सुस्पष्ट होती है, जिससे छात्र विनियमों, प्रणाली और प्रक्रियाओं को बारिकी से समझ सकें और उनसे संबंधित अधिसूचनाओं को समय-समय पर वेबसाइट पर रखा जाता है।

**1. जीएमसीएस, एमसीएस पाठ्यक्रम और अनुकूलन पाठ्यक्रम के ब्यौरे (01/04/2017 से 30/06/2018)**

**जीएमसीएस पाठ्यक्रम (01/04/2017 से 30/08/2017)**

क्रम सं.	क्षेत्र/केंद्र	केंद्रों की संख्या	बैचों की संख्या	छात्रों की संख्या
1	डब्ल्यूआईआरसी और शाखा	13	55	2597
2	एसआईआरसी और शाखा	10	27	1182
3	ईआईआरसी और शाखा	03	07	287
4	सीआईआरसी और शाखा	17	31	1203
5	एनआईआरसी और शाखा	09	28	1305
योग		52	148	6574

**अग्रिम आईसीआईटीएसएस-एमसीएस पाठ्यक्रम (01/07/2017 से 30/06/2018)**

क्रम सं.	क्षेत्र/केंद्र	केंद्रों की संख्या	बैचों की संख्या	छात्रों की संख्या
1	डब्ल्यूआईआरसी और शाखा	27	271	12164
2	एसआईआरसी और शाखा	25	173	7940
3	ईआईआरसी और शाखा	06	44	2071
4	सीआईआरसी और शाखा	42	198	8196
5	एनआईआरसी और शाखा	16	151	7025
6	दुबई	01	02	16
योग		117	839	37412

**आईसीआईटीएसएस-अनुकूलन पाठ्यक्रम (01/04/2017 से 30/06/2018)**

क्रम सं.	क्षेत्र/केंद्र	केंद्रों की संख्या	बैचों की संख्या	छात्रों की संख्या
1	डब्ल्यूआईआरसी और शाखा	35	459	21214
2	एसआईआरसी और शाखा	43	559	25701
3	ईआईआरसी और शाखा	9	99	4183
4	सीआईआरसी और शाखा	45	370	16392
5	एनआईआरसी और शाखा	21	182	7462



6	दुबई	1	1	17
योग		154	1670	74969

**2. 29-30 जनवरी, 2017** को नई दिल्ली में एक दो दिवसीय मास्टर प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमटीपी) का आयोजन किया गया था, जिसमें 36 संकाय सदस्यों को एमसीएस पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षित किया गया था।

### 1. आईसीआईटीएसएस और एआईसीआईटीएसएस (आईटी और उन्नत आईटी) पाठ्यक्रम की सामग्री का विकास

नई स्कीम के अधीन, परिषद् द्वारा अनुमोदित की गई पाठ्यचर्या के अनुसार नई अंतर्वस्तु को विकसित/परिवर्तित किया गया है। आईटी और उन्नत आईटी पाठ्यक्रम के लिए सुझाव दिए गए आबंटन घंटों निम्नानुसार हैं :

#### आईसीआईटीएसएस – सूचना प्रौद्योगिकी

क्रम सं.	विषय	अवधि (घंटे)
1.	ई पठन – कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ओएस, सीबीएस	10
2.	एमएस- वर्ड	6
3.	एमएस – एक्सेल	30
4.	एमएस – पावर पाइंट	12
5.	एमएस – एक्सेस	6
6.	सीएएटी	18
7.	लेखांकन पैकेज	18

#### एआईसीआईटीएसएस – उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी

क्रम सं.	विषय	अवधि (घंटे)
1.	ईआरपी परिस्थितियों में संपरीक्षा	44
2.	एडवांस्ड एक्सेल	18
3.	संपरीक्षा उपकरण के रूप में एमएस एक्सेल	18
4.	एमएस एक्सेस का उपयोग करने के लिए डाटाबेस एप्लीकेशन	12
5.	उद्यम संसाधन योजना	18

### 2. उन्नत आईटी पाठ्यक्रम के लिए अभ्यास मैनुअल का विकास/उसे अद्यतन बनाना

132 अभ्यासों/मामला अध्ययनों को अंतर्विष्ट करने वाला एक अभ्यास मैनुअल, पाठ्यक्रम के भाग रूप में बृहत्तर व्यवहारिक घरेलू प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए आरंभ किया गया है।

### 3. एआईसीआईटीएसएस – उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी वीडियो व्याख्यान

संपरीक्षा उपकरण के रूप में एमएस एक्सेल, ईआरपी परिस्थितियों में संपरीक्षा, एमएस एक्सेस का उपयोग करने के लिए डाटाबेस एप्लीकेशन, उन्नत एमएस एक्सेल और ईआरपी (टेली), से संबंधित पाठ्यचर्या को सम्मिलित करते हुए 26 घंटों के वीडियो व्याख्यानों को रिकार्ड किया गया है।

### 4. एआईसीआईटीएसएस – सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी वीडियो व्याख्यान

संपरीक्षा उपकरण के रूप में एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस – पावर पाइंट, ई पठन – कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ओएस और सीबीएस, सीएएटी, लेखांकन पैकेज और एमएस – एक्सेस से संबंधित पाठ्यचर्या को सम्मिलित करते हुए 20 घंटों के वीडियो व्याख्यानों को रिकार्ड किया गया है।

### 5. एआईसीआईटीएसएस के संकाय का विकास – उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी

उन्नत आईटी पाठ्यक्रम से संबंधित 3 (तीन) संकाय विकास कार्यक्रमों का आयोजन नई दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई में किया गया था, जिसमें 116 संकाय सदस्यों को, सीए पाठ्यक्रम की नई शिक्षा और प्रशिक्षण स्कीम के अधीन अद्यतन पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। इस प्रशिक्षण में नए विषयों, अर्थात् ईआरपी परिस्थितियों में संपरीक्षा, संपरीक्षा उपकरण के रूप में एमएस एक्सेल, सीएएटी, जीएसटी का पर्यावलोकन आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

### 6. 1 अप्रैल, 2017 से 30 जून, 2018 तक प्रादेशिक कार्यालयों और शाखाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रम और प्रशिक्षित छात्र

पाठ्यक्रम	बैचों की संख्या	प्रशिक्षित छात्रों की संख्या
आईटीटी	837	26294
आईसीआईटीएसएस-आईटी	1406	40089
उन्नत आईटी	139	4026
एआईसीआईटीएसएस- उन्नत आईटी	822	26668
<b>योग</b>	<b>3204</b>	<b>97077</b>

### 7. सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्ट कौशलें संबंधी उन्नततम एकीकृत पाठ्यक्रम – उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी परीक्षा के परिणामों के घोषणा की प्रास्थिति

कार्यालय द्वारा अथक प्रयासों के पश्चात्, 21 जनवरी, 18 फरवरी, 18 मार्च और 22 अप्रैल, 2018 को आयोजित एआईसीआईटीएसएस और उन्नत आईटी परीक्षा की वर्तमान प्रास्थिति निम्नानुसार है :

परीक्षा तारीख	कुल उपस्थित परीक्षार्थी	परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र
<b>21 जनवरी, 2018</b>	2,956	2,843
<b>18 फरवरी, 2018</b>	5,070	4,890
<b>18 मार्च, 2018</b>	5,183	5,121
<b>22 अप्रैल, 2018</b>	2,373	2329
<b>योग</b>	<b>15,582</b>	<b>15,183</b>

**टिप्पण :** 8 जुलाई, 2018 को आयोजित होने वाली पांचवीं परीक्षा (एआईसीआईटीएसएस) – उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी में 8239 छात्र भाग लेंगे।

### V. एमओ/यू/एमआरए/मान्यता/अन्य ठहराव

#### सीए पाठ्यक्रम को पीएच.डी कार्यक्रम के लिए मान्यता

विभिन्न विश्वविद्यालयों से निरंतर संपर्क करने के पश्चात् अध्ययन बोर्ड पीएचडी/अध्येता कार्यक्रम के प्रयोजन के लिए 102 विश्वविद्यालयों, 6 भारतीय प्रबंध संस्थानों और 2 आईआईटी, बंबई और मद्रास (कुल 110) से सीए पाठ्यक्रम के लिए मान्यता प्राप्त करने में सफल रहा है।

### VI. सम्मेलन/सभाएं/संगोष्ठियां और अन्य क्रियाकलाप

**छात्र सम्मेलन :** राष्ट्रीय सम्मेलन, सीए छात्रों के लिए सम्मेलन, सीए छात्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन : 2017-18 की अवधि के दौरान, अध्ययन बोर्ड ने मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और इंदौर में राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया था। इसके अलावा संपूर्ण देश के विभिन्न भागों में 39 सीए छात्र सम्मेलनों तथा पुणे में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था और लगभग 33,000 छात्रों ने इन छात्र सम्मेलनों में भाग लिया था।

**विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त संगोष्ठियां :** पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी के साथ एक संयुक्त संगोष्ठी का आयोजन किया गया था।

## VII. छात्रों को प्रदान की गई छात्रवृत्तियां

अध्ययन बोर्ड विभिन्न प्रवर्गों, अर्थात् मेरिट, मेरिट-सह-आवश्यकता, आवश्यकता आधारित और कमजोर वर्गों को, वृत्तिदान के अधीन वर्ष में दो बार छात्रवृत्तियां प्रदान करता है।

तदनुसार, वर्ष के दौरान अध्ययन बोर्ड ने उपरोक्त प्रवर्गों के अधीन चुने गए छात्रों को 1144 छात्रवृत्तियां प्रदान की थी।

### 11. प्रादेशिक परिषदें और उनकी शाखाएं

संस्थान की पांच प्रादेशिक परिषदें हैं, अर्थात् पश्चिमी भारत प्रादेशिक परिषद्, दक्षिणी भारत प्रादेशिक परिषद्, पूर्वी भारत प्रादेशिक परिषद्, मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् और उत्तरी भारत प्रादेशिक परिषद्, जिनके मुख्यालय क्रमशः मुम्बई, चैन्नई, कोलकाता, कानपुर और नई दिल्ली में हैं। इस समय इसके पास पूरे भारत में 164 शाखाएं और भारत से बाहर 31 विदेशी चैप्टर तथा 15 प्रादेशिक पुस्तकालय हैं।

#### 11.1 सर्वोत्तम प्रादेशिक परिषद्, प्रादेशिक परिषद् की सर्वोत्तम शाखा, सर्वोत्तम छात्र संघ और छात्र संघ की सर्वोत्तम शाखा के लिए पुरस्कार :

ये पुरस्कार आईसीएआई द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार सकल कार्यपालन और स्थापित संनियमों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। वर्ष **2017** के लिए ये शील्डें 6 फरवरी, **2018** को आयोजित वार्षिक समारोह में निम्नलिखित विजेताओं को दी गई थी।

#### 1. सर्वोत्तम प्रादेशिक परिषद्

प्रथम पुरस्कार: पश्चिमी भारत प्रादेशिक परिषद्

दूसरा पुरस्कार: पूर्वी भारत प्रादेशिक परिषद्

#### 2. प्रादेशिक परिषदों की सर्वश्रेष्ठ शाखा :-

##### 1. बृहत्त श्रेणी

प्रथम पुरस्कार: आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरएसी की अहमदाबाद शाखा

दूसरा पुरस्कार: आईसीएआई की सीआईआरएसी की इंदौर शाखा

##### 2. बड़ी शाखा प्रवर्ग

प्रथम पुरस्कार: आईसीएआई की एसआईआरएसी की एर्नाकुलम शाखा

दूसरा पुरस्कार: आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की नागपुर शाखा

##### 3. मध्यम शाखा प्रवर्ग

प्रथम पुरस्कार: आईसीएआई की ईआईआरएसी की सिलिगुड़ी शाखा

दूसरा पुरस्कार: आईसीएआई की एसआईआरसी की सलेम शाखा

##### 4. लघु शाखा प्रवर्ग

प्रथम पुरस्कार: आईसीएआई की सीआईआरसी की भिलाई शाखा

दूसरा पुरस्कार: आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की जलगांव शाखा

##### 5. सुक्ष्म शाखा प्रवर्ग

प्रथम पुरस्कार: आईसीएआई की एसआईआरसी की शिवकाशी शाखा

दूसरा पुरस्कार: आईसीएआई की एसआईआरसी के तूतीकोरन शाखा

### 3. सर्वश्रेष्ठ छात्र संघ

प्रथम पुरस्कार: पश्चिमी भारत चार्टर्ड अकाउंटेंट्स छात्र संघ

दूसरा पुरस्कार: पूर्वी भारत चार्टर्ड अकाउंटेंट्स छात्र संघ

### 4. छात्र संघ की सर्वश्रेष्ठ शाखा

क. बड़ी शाखा प्रवर्ग

प्रथम पुरस्कार: आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की डब्ल्यूआईसीएएसए की अहमदाबाद शाखा

दूसरा पुरस्कार: आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी के डब्ल्यूआईसीएएसए की नागपुर शाखा

ख. मध्यम शाखा प्रवर्ग

प्रथम पुरस्कार: आईसीएआई की सीआईआरसी की सीआईसीएएसए की भिलाई शाखा

दूसरा पुरस्कार: आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की डब्ल्यूआईसीएएसए की औरंगाबाद शाखा

ग. लघु शाखा प्रवर्ग

प्रथम पुरस्कार: आईसीएआई की एसआईआरसी की एसआईसीएएस की शिवकाशी शाखा

दूसरा पुरस्कार: आईसीएआई की ईआईआरसी की ईआईसीएएस की सिलिगुड़ी शाखा

### 11.2 विकेन्द्रीकृत कार्यालय

आईसीएआई की परिषद् ने, त्वरित और व्यक्तिगत सेवा के मूल्य को मान्यता प्रदान करते हुए, जिन्हें विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, निम्नानुसार रूप से 18 विकेन्द्रीकृत कार्यालयों की स्थापना की है :

मुंबई	चेन्नई	कोलकाता	कानपुर	नई दिल्ली	अहमदाबाद
बैंगलोर	हैदराबाद	पुणे	जयपुर	नागपुर	सूरत
वदोदरा	ठाणे	एर्नाकुलम	कोयंबटूर	इंदौर	चंडीगढ़

### 12. वित्त और लेखा

31 मार्च, 2018 को यथाविद्यमान तुलन पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय-व्यय का लेखा, जो संपरीक्षकों द्वारा सम्यक्तः संपरीक्षित है, इसमें इसके पश्चात् प्रकाशित किए गए हैं।

### 13. अनुशंसा

परिषद् व्यवसाय के उन सदस्यों की आभारी है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अधीन गठित संस्थान के बोर्डों/समितियों में सहयोजित सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट हुए थे और उस रूप में कार्य किया था और वह उनके प्रति आभार व्यक्त करती है, जो व्यवसाय के सदस्य नहीं हैं लेकिन जिन्होंने परिषद् के शैक्षिक, तकनीकी, अन्य विकास क्रियाकलापों में और उसकी परीक्षाओं के संचालन में वर्ष 2017-2018 के दौरान परिषद् की सहायता की और वह प्रादेशिक परिषदों, उनकी शाखाओं और उनके सदस्यों के प्रति भी आभार व्यक्त करती है।

परिषद् की हार्दिक कामना है कि वर्ष 2017-2018 के दौरान केन्द्रीय सरकार और परिषद् में उनके मनोनीत सदस्यों द्वारा दी गई निरंतर सहायता और समर्थन की प्रशंसा अभिलेख पर अंकित की जाए।

परिषद्, भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द, संघ के माननीय संचार राज्य (स्वतंत्र प्रभार) और रेल राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा, संघ के माननीय कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री श्री पी.पी. चौधरी, संघ के माननीय वाणिज्य और

उद्योग मंत्री सीए सुरेश प्रभु, संघ के रेल और कोयला मंत्री, श्री पीयूष गोयल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का, जिन्होंने आईसीएआई द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर उन्हें गौरवान्वित किया, दिल से आभार व्यक्त करती है।

परिषद् राज्य स्तर पर विभिन्न कृत्यकारियों की भी, जिन्होंने आईसीएआई के विभिन्न अंगों द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर उन्हें गौरवान्वित किया, सराहना करती है।

परिषद् आईसीएआई द्वारा की गई अनेक पहलों में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दिखाई गई गहन रुचि और की गई पहल के अनुसरण में उनके द्वारा पहले ही उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों की प्रशंसा करती है।

परिषद्, आईसीएआई के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2017-2018 के दौरान और उसके पश्चात् उनके द्वारा किए गए निष्ठापूर्ण और समर्पित प्रयासों के लिए उनकी अनुशंसा करती है।

### सांख्यिकी एक दृष्टि में

#### सदस्य रजिस्ट्रीकरण

(1 अप्रैल, 2007 से)

#### सारणी 1

वर्ष (को यथाविद्यमान)		पश्चिमी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	उत्तरी क्षेत्र	योग
1 अप्रैल, 2007	सहयुक्त	31159	18237	7829	9642	14182	81049
	अध्येता	16896	13646	6488	8882	12880	58792
	योग	48055	31883	14317	18524	27062	139841
1 अप्रैल, 2008	सहयुक्त	32364	19203	7939	10045	14642	84193
	अध्येता	17646	14034	6738	9472	13398	61288
	योग	50010	33237	14677	19517	28040	145481
1 अप्रैल, 2009	सहयुक्त	34294	20666	8193	10578	15951	89682
	अध्येता	18442	14516	7002	10007	13951	63918
	योग	52736	35182	15195	20585	29902	153600
1 अप्रैल, 2010	सहयुक्त	36390	21733	8512	11252	17104	94991
	अध्येता	19181	15076	7192	10615	14461	66525
	योग	55571	36809	15704	21867	31565	161516
1 अप्रैल, 2011	सहयुक्त	38608	22998	9154	12329	18547	101636
	अध्येता	19831	15612	7406	11182	14943	68974
	योग	58439	38610	16560	23511	33490	170610
1 अप्रैल, 2012	सहयुक्त	45273	25505	11069	15963	23332	121142
	अध्येता	20510	16132	7578	11720	15431	71371
	योग	65783	41637	18647	27683	38763	192513
1 अप्रैल, 2013	सहयुक्त	52846	28020	13258	20606	27743	142473
	अध्येता	21522	16918	7815	12327	16051	74633
	योग	74368	44938	21073	32933	43794	217106

1 अप्रैल, 2014	सहयुक्त	56595	29401	14035	22978	29467	152476
	अध्येता	22313	17460	8007	12915	16508	77203
	योग	78908	46861	22042	35893	45975	229679
1 अप्रैल, 2015	सहयुक्त	60229	30126	14514	24702	31137	160708
	अध्येता	22838	17864	8137	13441	16986	79266
	योग	83067	47990	22651	38143	48123	239974
1 अप्रैल, 2016	सहयुक्त	64235	31919	15046	27353	32774	171327
	अध्येता	23700	18495	8223	14071	17521	82010
	योग	87935	50414	23269	41424	50295	253337
1 अप्रैल, 2017	सहयुक्त	67746	33591	15580	30036	34632	181585
	अध्येता	25742	19711	8718	15618	18933	88722
	योग	93488	53302	24298	45654	53565	270307
1 अप्रैल, 2018	सहयुक्त	70683	34733	15606	32094	36988	190104
	अध्येता	26736	20280	8912	16494	19667	92089
	योग	97419	55013	24518	48588	56655	282193

### सदस्य

(1 अप्रैल, 1950 से)

### सारणी 2

	सहयुक्त	अध्येता	योग
1 अप्रैल, 1950 को	1,120	569	1,689
1 अप्रैल, 1951 को	1,285	672	1,957
1 अप्रैल, 1961 को	4,059	1,590	5,649
1 अप्रैल, 1971 को	7,901	3,326	11,227
1 अप्रैल, 1981 को	16,796	8,642	25,438
1 अप्रैल, 1991 को	36,862	22,136	58,998
1 अप्रैल, 2001 को	51,603	44,789	96,392
1 अप्रैल, 2002 को	54,666	47,064	1,01,730
1 अप्रैल, 2003 को	60,619	49,637	1,10,256
1 अप्रैल, 2004 को	63,384	52,707	1,16,091
1 अप्रैल, 2005 को	68,052	55,494	1,23,546
1 अप्रैल, 2006 को	73,778	57,168	1,30,946
1 अप्रैल, 2007 को	81,049	58,792	1,39,841

1 अप्रैल, 2008 को	84,193	61,288	1,45,481
1 अप्रैल, 2009 को	89,682	63,918	1,53,600
1 अप्रैल, 2010 को	94,991	66,525	1,61,516
1 अप्रैल, 2011 को	1,01,636	68,974	1,70,610
1 अप्रैल, 2012 को	1,21,142	71,371	1,92,513
1 अप्रैल, 2013 को	1,42,473	74,633	2,17,106
1 अप्रैल, 2014 को	1,52,476	77,203	2,29,679
1 अप्रैल, 2015 को	1,60,708	79,266	2,39,974
1 अप्रैल, 2016 को	1,71,327	82,010	2,53,337
1 अप्रैल, 2017 को	1,81,585	88,722	2,70,307
1 अप्रैल, 2018 को	1,90,104	92,089	2,82,193

### रजिस्ट्रीकृत छात्र

(31 मार्च, 2010 से)

वर्ष के दौरान	नए सीआरईटी के अनुसार फाउंडेशन	फाइनल	नया फाइनल	सीपीटी	पीसीसी	आईपीसीसी एवं आईआईपी सीसी	मध्यवर्ती	एटीसी	योग
2009-10	-	24,172	-	1,67,073	1,860	80,745	-	3,376	2,77,226
2010-11	-	57,175	-	1,55,217	329	67,984	-	1,906	2,82,611
2011-12	-	47,515	-	1,61,712	-	85,053	-	2,099	2,96,379
2012-13	-	45,102	-	1,61,084	-	1,02,406	-	2,615	3,11,207
2013-14	-	39,348	-	1,54,742	-	96,285	-	3,209	2,93,584
2014-15	-	36,950	-	1,41,241	-	66,570	-	881	2,45,642
2015-16	-	31,669	-	1,25,140	-	77,962	-	1,249	2,36,020
2016-17	-	27,611	-	1,07,392	-	81,886	-	1,430	2,18,319
2017-18	9,788	26,291	14,056	73,804	-	22,657	63,693	-	2,10,289

### परिषद् की संरचना

#### परिषद् (2018-19)

अध्यक्ष	परिषद् के सदस्य (2018-19)	
सीए. नवीन एन.डी. गुप्ता	निर्वाचित सदस्य	
	सीए. रंजीत कुमार अग्रवाल	कोलकाता

	सीए. संजय कुमार अग्रवाल	नई दिल्ली
	सीए. श्याम लाल अग्रवाल	जयपुर
<b>उपाध्यक्ष</b>	सीए. मनु अग्रवाल	कानपुर
सीए. प्रफुल प्रेमसुख छाजेड	सीए. बाबु अब्राहम कल्लीवयालिल	कोच्ची
	सीए. अनिल सत्यनारायण भंडारी	मुंबई
	सीए. संजीव कुमार चौधरी	नई दिल्ली
	सीए. जय छैयरा	सूरत
	सीए. प्रफुल प्रेमसुख छाजेड	मुंबई
<b>अवधि</b>	सीए. एम. देवराजा रेड्डी	हैदराबाद
12 फरवरी, 2018 से आगे	सीए. तरुण जमनादास घिया	मुंबई
	सीए. सुशील कुमार गोयल	कोलकाता
	सीए. अतुल कुमार गुप्ता	दिल्ली
	सीए. नवीन एन.डी. गुप्ता	नई दिल्ली
<b>परिषद् के सचिव</b>	सीए. विजय कुमार गुप्ता	फरीदाबाद
श्री वी. सागर	सीए. नंदकिशोर चिदम्बर हेगड़े	मुंबई
	सीए. निहार निरंजन जम्बुसरिया	मुंबई
	सीए. धीरज कुमार खंडेलवाल	मुंबई
	सीए. मंगेश पांडुरंग किनारे	ठाणे
	सीए. श्रीप्रिया कुमार	चेन्नई
	सीए. मुकेश सिंह कुशवाहा	गाजियाबाद
	सीए. नारायण हीरिंगंगे मधुकर	बंगलुरु
	सीए. (डा.) देबाशीष मित्रा	गुवाहाटी
	सीए. जी.सेकर	चेन्नई
	सीए. धीनल अश्विनभाई शाह	अहमदाबाद
	सीए. प्रकाश शर्मा	जयपुर
	सीए. राजेश शर्मा	दिल्ली
	सीए. केमिशा सोनी	इंदौर
	सीए. संजय वासुदेव	नई दिल्ली
	सीए. एम.पी.विजय कुमार	चेन्नई
	सीए. निलेश शिवजी विक्रमसे	मुम्बई
	सीए. शिवाजी भीकाजी जावरे	पुणे
	<b>नामनिर्दिष्ट सदस्य</b>	
	श्री अनुराग अग्रवाल (05.06.2018 से)	नई दिल्ली



श्री मनोज कुमार (12 फरवरी, 2016 से 23 मार्च, 2017 तक)	नई दिल्ली
श्री के.वी.आर. मूर्ति (23 मार्च, 2017 से 5 जून, 2018)	नई दिल्ली
श्री विठयाथिल कुरियन (11 अप्रैल, 2016 से 28 अगस्त, 2018)	नई दिल्ली
सुश्री रितिका भाटिया (28 अगस्त, 2018 से)	नई दिल्ली
डा. गुरुप्रसाद मोहपात्रा (12 फरवरी, 2016 से 23 मार्च, 2017 तक)	नई दिल्ली
डा. सुधांशु पांडे (23 मार्च, 2017 से)	नई दिल्ली
श्री चन्द्र बाधवा	नई दिल्ली
डा. पी.सी. जैन	दिल्ली
श्री सुनील कनोरिया	नई दिल्ली
श्री इंदु मल्होत्रा (12 फरवरी, 2016 से 23 मार्च, 2017 तक)	नई दिल्ली
डा. रवि गुप्ता (23 मार्च, 2017 से)	नई दिल्ली
श्री विजय कुमार झालानी	नई दिल्ली

### 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा

हिंगोरानी एम. एंड कंपनी  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

खन्ना एंड आन्नदनम  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

#### स्वतंत्र संपरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

परिषद्, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

#### वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ("संस्थान") के संलग्न वित्तीय विवरणों, जिसमें 31 मार्च, 2018 को यथा विद्यमान तुलनपत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए संलग्न आय और व्यय लेखा तथा नकद प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का संक्षिप्त विवरण तथा अन्य स्पष्टीकारक जानकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् "वित्तीय विवरण" कहा गया है) सम्मिलित हैं, की संपरीक्षा की है।

#### वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधमंडल का उत्तरदायित्व

चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के अनुसार, इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व संस्थान के प्रबंधमंडल का है, जो भारत में साधारण रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों, जिनके अंतर्गत भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक भी हैं, के अनुसार संस्थान की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यपालन और नकद प्रवाह के संबंध में सत्य और उचित विवरण प्रस्तुत करते हैं।

इस उत्तरदायित्व के अंतर्गत संस्थान की आस्तियों को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त लेखांकन अभिलेख रखना तथा कपटों और अन्य अनियमितताओं का निवारण करना और उनका पता लगाना, समुचित लेखांकन नीतियों का चयन करना और उन्हें लागू करना, ऐसे निर्णय और प्राक्कलन करना, जो युक्तियुक्त और विवेकपूर्ण हों तथा डिजाइन कार्यान्वयन और ऐसे पर्याप्त आंतरिक नियंत्रणों को बनाए रखना भी है, जो ऐसे वित्तीय विवरणों, जो सत्य और उचित

मत प्रदान करते हैं और सारवान मिथ्या कथनों, चाहे वे कपट के कारण हों या त्रुटिवश हों, से मुक्त हैं, को तैयार करने और उनके प्रस्तुतिकरण से सुसंगत लेखांकन अभिलेखों की सत्यता और अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्यकरण कर रहे थे।

### संपरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व, हमारी संपरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अपनी राय व्यक्त करना है।

हमने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी संपरीक्षा मानकों के अनुसार अपनी संपरीक्षा की है। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें तथा इस बाबत युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए संपरीक्षा की योजना बनाएं और उसके अनुसार संपरीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण किसी तात्विक मिथ्या कथन से मुक्त हैं।

किसी संपरीक्षा में, वित्तीय विवरणों में रकमों और प्रकटनों का समर्थन करने वाले संपरीक्षा संबंधी साक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना सम्मिलित है। चुनी गई प्रक्रियाएं संपरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसके अंतर्गत वित्तीय विवरणों में सारवान मिथ्या कथनों, चाहे वे कपट के कारण हों अथवा त्रुटि के कारण, के जोखिमों का निर्धारण करना भी है। ऐसे जोखिम निर्धारणों में, संपरीक्षक, संपरीक्षा संबंधी ऐसी प्रक्रियाओं को, जो दी गई परिस्थितियों में उपयुक्त हों, तैयार करने के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा उनके उचित प्रस्तुतिकरण हेतु संस्थान के सुसंगत आंतरिक नियंत्रणों को भी विचार में लेते हैं, किंतु ऐसा इस प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता कि इस संबंध में राय व्यक्त की जाए कि क्या संस्थान ने वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए हैं और क्या ऐसे नियंत्रण प्रभावी हैं। संपरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंध मंडल द्वारा किए गए महत्वपूर्ण लेखांकन आकलनों तथा संपूर्ण वित्तीय विवरण प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी सम्मिलित होता है।

हमारा यह विश्वास है कि हमारे द्वारा ऐसे संपरीक्षा संबंधी साक्ष्य अभिप्राप्त किए गए हैं जो हमारी संपरीक्षा संबंधी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

### राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पूर्वोक्त वित्तीय विवरण चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अनुसार सभी तात्विक अपेक्षाओं को पूरा करते हुए, तैयार किए गए हैं और वे भारत में साधारण रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार 31 मार्च, 2018 को संस्थान के मामलों की स्थिति और उसके अधिशेष और नकद प्रवाह के संबंध में एक सत्य और उचित मत प्रदान करते हैं।

### अन्य विषय

1. संस्थान ने भारत में और विदेशों में बड़ी संख्या में चैप्टरों को प्राधिकृत किया है। संस्थान ने हमें यह प्रतिवेदन किया है कि चूंकि ये चैप्टर पृथक् अस्तित्व हैं और उनके लेखाओं के समेकन की अपेक्षा नहीं है।
2. हमने संस्थान के विकेन्द्रीकृत कार्यालयों, कंप्यूटर केंद्रों, छात्र संघों, प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं (जो एकीकृत रूप में शाखाओं के नाम से ज्ञात हैं) के वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण कुल 82,141 लाख रुपए की आस्तियां, 24,123 लाख रुपए का कुल राजस्व और 596 लाख रुपए की रकम का शुद्ध नकद प्रवाह/(बहिर्गामी) उपदर्शित करते हैं और जिन्हें वित्तीय विवरणों में विचारार्थ लिया गया है। इन वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा अन्य संपरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्टें प्रबंधमंडल द्वारा हमें प्रस्तुत की गई थीं। इन वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारी राय, जहां तक उसका संबंध इन शाखाओं के संबंध में सम्मिलित की गई रकमों और प्रकटनों से है, पूर्णतया उन अन्य संपरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

### अन्य विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

#### हम यह और रिपोर्ट करते हैं कि :

- क) हमने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे ;
- ख) हमारी राय में संस्थान द्वारा समुचित लेखा बहियां रखी गई हैं, जैसा कि इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है और हमारी संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए विकेन्द्रीकृत कार्यालयों, कंप्यूटर केंद्रों, छात्र संघों, प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं से समुचित और पर्याप्त विवरणियां प्राप्त हुई हैं ;
- ग) इस रिपोर्ट से संबंधित संस्थान के तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा और नकद प्रवाह विवरण, लेखा बहियों के अनुसार हैं।

कृते हिंगोरानी एम. एंड कंपनी  
 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
 फर्म रजि. सं. 006772एन  
 ह/  
 सीए. जगदीश प्रसाद धमीजा  
 भागीदार  
 सदस्यता सं. 015020

खन्ना एंड आन्नदनम  
 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
 फर्म रजि. सं. 001297एन  
 ह/  
 सीए. बी.जे. सिंह  
 भागीदार  
 सदस्यता सं. 007884

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 26 सितंबर, 2018

**भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान**  
 आईसीएआई भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली-110 002  
**31 मार्च, 2018 को यथाविद्यमान तुलन पत्र**

		31 मार्च, को यथा विद्यमान	
विशिष्टियां	टिप्पण सं.	2018	2017
<b>I. निधियों के स्रोत :</b>		(लाख रुपए में)	
<b>i. अधिशेष और उद्दिष्ट निधियां</b>			
क. आरिश्चितियां और अधिशेष	<b>3</b>	128,239	113,941
ख. उद्दिष्ट निधियां	<b>4</b>	39,370	34,329
<b>ii. गैर चालू दायित्व</b>			
क. अन्य दीर्घकालिक दायित्व	<b>5</b>	1,219	731
ख. दीर्घकालिक प्रावधान	<b>6</b>	22,941	16,338
<b>iii. चालू दायित्व</b>			
क. व्यापार संबंधी देय	<b>7</b>	3,677	3,191
ख. अन्य चालू दायित्व	<b>8</b>	24,274	19,345
ग. अल्पकालिक प्रावधान	<b>6</b>	1,307	937
<b>योग</b>		<b>221,027</b>	<b>188,812</b>
<b>निधियों का उपयोग</b>			
<b>II. i. गैर चालू आस्तियां</b>			
<b>क. नियत आस्तियां</b>			
i) मूर्त आस्तियां	<b>9</b>	54,363	51,615
ii) अमूर्त आस्तियां	<b>10</b>	55	19
iii) चालू पूंजी संकर्म	<b>11</b>	10,877	13,875
ख. गैर-चालू निवेश	<b>12</b>	76,535	24,631
ग. उद्दिष्ट और अन्य निधियों के लिए धारित आस्तियां	<b>13</b>	5,229	3,630
घ. दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	<b>14</b>	3,397	2,987
ङ. अन्य गैर चालू आस्तियां	<b>15</b>	678	1,684
<b>ii. चालू आस्तियां</b>			
क. चालू निवेश	<b>12</b>	2,506	8,091
ख. उद्दिष्ट और अन्य निधियों के लिए धारित आस्तियां	<b>13</b>	54,704	70,388
ग. वस्तु-सूचियां	<b>16</b>	1,080	1,001
घ. नकद और बैंक अतिशेष	<b>17</b>	6,824	5,035
ङ. अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	<b>14</b>	2,714	2,252
च. अन्य चालू आस्तियां	<b>15</b>	2,065	3,604
<b>योग</b>		<b>2,21,027</b>	<b>1,88,812</b>

संलग्न टिप्पण 1 से 27 देखें, जो वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

परिषद् के लिए और उसकी ओर से

ह./-  
सी.ए. सुदीप श्रीवास्तव  
संयुक्त सचिव

ह./-  
बी. सागर  
सचिव

ह./-  
सी.ए. प्रफुल पी. छाजेड  
उपाध्यक्ष

ह./-  
सी.ए. नवीन एन. डी. गुप्ता  
अध्यक्ष

हमारी सम संख्यांक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते हिंमोरानी एम. एंड कंपनी  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फर्म रजि. सं. 006772एन

ह/

सी.ए. जगदीश प्रसाद धर्मीजा भागीदार

सदस्यता सं. 015020

खन्ना एंड आनन्दनम

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फर्म रजि. सं. 001297एन

ह/

सी.ए. बी.जे. सिंह

भागीदार

सदस्यता सं. 007884

स्थान : नई दिल्ली, 26 सितंबर, 2018

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

आईसीएआई भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली-110 002

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए			
	विशिष्टियां	टिप्पण सं.	2018
			2017
			(रुपए लाख में)
I	<b>आय</b>		
	क) फीस	18	62,526
	ख) संगोष्ठियां	19	5,761
	ग) अन्य आय	20	12,322
	<b>कुल आय</b>		<b>80,609</b>
II	<b>व्यय</b>		
	क) संगोष्ठियों और प्रशिक्षण कार्यक्रम		6,036
	ख) कर्मचारी फायदा संबंधी व्यय	21	16,872
	ग) मुद्रण और लेखन सामग्री		5,810
	घ) परीक्षकों और परामर्शियों को संदत्त वृत्तिक फीस	9-10	8,005
	ङ) अवक्षयण और परिशोधन संबंधी व्यय	22	2,257
	च) अन्य व्यय		22,770
	<b>कुल व्यय</b>		<b>61,750</b>
III	<b>शुद्ध अधिशेष (I-II)</b>		<b>18,859</b>
IV	<b>निधियों/आरक्षितियों को विनियोग:</b>		<b>6,316</b>
	क) शिक्षा निधि [टिप्पण 2.6(iii) देखें]		5,073
	ख) कर्मचारी कल्याण निधि [टिप्पण 2.6(iv) देखें]		78
	ग) उद्दिष्ट निधियां और अन्य निधियां (व्ययों का शुद्ध योग)		2,296
	घ) सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण निधि [टिप्पण 2.6(vii) देखें]		1,001
	ङ) साधारण आरक्षित		10,411
	<b>योग</b>		<b>18,859</b>
			<b>6,316</b>

संलग्न टिप्पण 1 से 27 देखें, जो वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

परिषद् के लिए और उसकी ओर से

ह./-  
सी.ए. सुदीप श्रीवास्तव  
संयुक्त सचिव

ह./-  
बी. सागर  
सचिव

ह./-  
सी.ए. प्रफुल पी. छाजेड  
उपाध्यक्ष

ह./-  
सी.ए. नवीन एन. डी. गुप्ता  
अध्यक्ष

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते हिंमोरानी एम. एंड कंपनी  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
फर्म रजि. सं. 006772एन

खन्ना एंड आनन्दनम  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
फर्म रजि. सं. 001297एन

ह/  
सीए. जगदीश प्रसाद धमीजा  
भागीदार  
सदस्यता सं. 015020

ह/  
सीए. वी.जे. सिंह  
भागीदार  
सदस्यता सं. 007884

स्थान : नई दिल्ली, 26 सितंबर, 2018

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान  
31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

(लाख रुपए में)

		31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए	
		2018	2017
I.	<b>विविष्टियां</b>		
	<b>प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह</b>		
	पूर्वावधि समायोजनों के पश्चात् शुद्ध अधिशेष	18,859	6,316
	निम्नलिखित के लिए समायोजन :		
	- अवक्षयण और परिशोधन संबंधी व्यय	2,540	2,334
	- ऐसे प्रावधान, जो अब अपेक्षित नहीं हैं, अपलिखित	(193)	(114)
	- व्याज संबंधी आय	(8,743)	(7,686)
	- सदस्यों से प्रवेश फीस, जिसे सीधे आरक्षिती को आवंटित किया गया है	367	242
	<b>कार्यकरण पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन अधिशेष</b>	<b>12,830</b>	<b>1,092</b>
	<b>कार्यकरण पूंजी में परिवर्तन :</b>		
	<b>प्रचालन संबंधी आस्तियों में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन :</b>		
	वस्तु सूचियां	(79)	242
	दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	(8)	416
	अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	(462)	1,718
II.	<b>प्रचालन संबंधी आस्तियों में वृद्धि/(कमी) के लिए समायोजन</b>		
	- अन्य दीर्घकालिक दायित्व	488	(70)
	- दीर्घकालिक प्रावधान	6,603	6,647
	- व्यापार संबंधी देय	679	(666)
	- अन्य चालू दायित्व	4,904	634
	- अल्पकालिक प्रावधान	370	609
		<b>25,325</b>	<b>10,622</b>
	स्रोत पर कटौती किया गया कर (वसूलनीय)	(402)	318
	<b>प्रचालन क्रियाकलापों से हुई आय (ख)</b>	<b>24,923</b>	<b>10,940</b>
	<b>निवेश संबंधी क्रियाकलापों से नकद प्रवाह</b>		
	- गैर-चालू निवेशों का क्रय	(51,904)	(24,631)
	- चालू निवेशों का विक्रय/मोचन/क्रय	5,585	(8,091)
	- नियत आस्तियों पर पूंजी व्यय	(2,104)	(2,858)
	- नियत आस्तियों के विक्रय से आगम	(197)	103
	- उद्दिष्ट और अन्य निधियों में कमी	14,085	18,434
	- प्राप्त व्याज आय	11,288	6,033
III.	<b>निवेश संबंधी क्रियाकलापों में (प्रयुक्त) नकद (आ)</b>	<b>(23,247)</b>	<b>(11,010)</b>
	<b>वित्तीय क्रियाकलापों से नकद प्रवाह</b>		
	- भवन के लिए प्राप्त सदान	11	18
	- प्राप्त अभिदाय	83	3
	- पर्याप्त/(प्रयुक्त) अन्य निधि	19	(1)
	<b>वित्तीय क्रियाकलापों से नकद (इ)</b>	<b>113</b>	<b>20</b>
	<b>नकद और नकद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (ख+आ+इ)</b>		
	<b>वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकद समतुल्य</b>	<b>1,789</b>	<b>(50)</b>
	<b>वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य</b>	<b>5,035</b>	<b>5,085</b>
		<b>6,824</b>	<b>5,035</b>

संलग्न टिप्पण 1 से 27 देखें, जो परिषद् के लिए और उसकी ओर से वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग है।

**टिप्पणी: (1)** नकद और नकद समतुल्य, हाथ में नकदी और बैंकों में जमा धन को बताते हैं (टिप्पणी 17 देखें)।

(2) कोष्ठकों में दी गई रकमें बहिर्गम्य धन को बताती हैं।

परिषद् के लिए और उसकी ओर से

ह./-  
सी.ए. सुदीप श्रीवास्तव  
संयुक्त सचिव

ह./-  
बी. सागर  
सचिव

ह./-  
सी.ए. प्रफुल पी. छाजेड  
उपाध्यक्ष

ह./-  
सी.ए. नवीन एन. डी. गुप्ता  
अध्यक्ष

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते हिंशोराणी एम. एंड कंपनी  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फर्म रजि. सं. 006772एन

ह/  
सी.ए. जगदीश प्रसाद धमीजा  
भागीदार  
सदस्यता सं. 015020

खन्ता एंड आनन्दनम  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फर्म रजि. सं. 001297एन

ह/  
सी.ए. बी.जे. सिंह  
भागीदार  
सदस्यता सं. 007884

स्थान : नई दिल्ली, 26 सितंबर, 2018

## भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली टिप्पणियां

### 1. साधारण जानकारी

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ("संस्थान या आईसीएआई") जिसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है, को 1 जुलाई, 1949 को संसद् के एक अधिनियम, अर्थात् चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अधीन भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की वृत्ति का विनियमन करने के प्रयोजन के लिए स्थापित किया गया था। उक्त अधिनियम के निबंधनों के अनुसार संस्थान की परिषद् को, संस्थान के कार्यों के प्रबंध का कार्य सौंपा गया है। इस प्रयोजन के लिए, परिषद् ने अभी तक मुंबई, कोलकाता, कानपुर, चैन्नई और नई दिल्ली प्रत्येक में एक और कुल 5 प्रादेशिक परिषदों, 5 विकेन्द्रीकृत कार्यालयों, 13 उप-विकेन्द्रीकृत कार्यालय, 163 शाखाओं और दुबई में एक विदेशी कार्यालय का भी गठन किया है।

### 2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का संक्षिप्त विवरण

**2.1 लेखांकन का आधार :** वित्तीय विवरणों को, जिनमें तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा तथा नकद प्रवाह विवरण, टिप्पणों के साथ सम्मिलित है, संस्थान द्वारा जारी और लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करने के लिए भारत में साधारण रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) के अनुसार तैयार किया जाता है। वित्तीय विवरणों को, जब तक कि अन्यथा कथित न हो, गोईंग कन्सर्न संबंधी ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अधीन तथा प्रोदभवन आधार पर तैयार किया जाता है। वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियां, पूर्व वर्ष में अपनाई गई नीतियों से संगत हैं।

**2.2 प्राक्कलनों का उपयोग:** भारतीय जीएएपी के अनुसार वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति प्रबंधमंडल से यह अपेक्षा करती है कि वे ऐसे प्राक्कलन और पूर्वानुमान करें, जो वर्ष के दौरान आस्तियों और दायित्वों की रिपोर्टित रकमों (जिसके अंतर्गत आकस्मिक दायित्व भी हैं) और आय और व्यय की रिपोर्टित रकमों हेतु विचार में लिए जाते हैं। प्रबंधमंडल यह विश्वास करता है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण और तर्कसंगत हैं। वास्तविक परिणाम उन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणामों तथा प्राक्कलनों के बीच अंतर को ऐसी अवधियों में मान्यता प्रदान की जाती है, जिनमें परिणामों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी/ वे कार्यान्वित किए गए थे।

**2.3 वस्तु-सूचियां:** वस्तु-सूचियों में प्रकाशनों, अध्ययन सामग्रियों, लेखन सामग्रियों और अन्य भंडारों की वस्तु-सूचियां सम्मिलित होती हैं, जिनका मूल्यांकन प्रथम आगम, प्रथम जावक ("एफआईएफओ") पद्धति के आधार पर, जिसके दौरान जहां आवश्यक समझा जाए, अप्रचलन और अन्य हानियों के लिए उपबंध करने के पश्चात् संगणित निम्नतर लागत और शुद्ध वसूलनीय मूल्य के आधार पर किया जाता है।

लागत में माल को विक्रय के बिन्दु पर लाने संबंधी सभी प्रभार सम्मिलित होते हैं, जिसके अंतर्गत चुंगी, अन्य उदग्रहण, प्रवहन बीमा और अन्य आकस्मिक भी हैं।

**2.4 नकद और नकद समतुल्य (नकद प्रवाह विवरण के प्रयोजनों के लिए):** नकद में, हाथ में नकदी और बैंकों में मानदेय निक्षेप अंतर्विष्ट हैं। अत्यधिक नकद समतुल्य ऐसे अल्पकालिक अतिशेष हैं (जिनकी मूल परिपक्वता, उनके अर्जन की तारीख से तीन मास या उससे कम की अवधि है), जो अत्यधिक रूप से चल निवेश हैं, जिन्हें सुगम रूप से नकद की ज्ञात रकमों में परिवर्तित किया जा सकता है और जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।

**2.5 नकद प्रवाह विवरण:** नकद प्रवाहों को अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है, जिसमें गैर-नकद प्रकृति के संव्यवहारों के प्रभावों और पूर्ववर्ती या भावी नकद प्राप्तियों या संदायों में किसी आस्थगन या प्रोदभवनों के लिए शुद्ध अधिशेष को समायोजित किया जाता है। संस्थान के प्रचालन, निवेश और वित्तपोषण संबंधी क्रियाकलापों से होने वाले नकद प्रवाहों को उपलब्ध जानकारी के आधार पर पृथक् किया जाता है।

### 2.6 आरक्षितियों में विनियोग और उद्दिष्ट निधियों को आबंटन

(i) संस्थान के अध्येता के रूप में प्रवेश हेतु सदस्यों से प्राप्त फीस को अवसंरचना संबंधी आरक्षित खाते में जमा किया जाता है।

- (ii) भवनों और अनुसंधान के लिए प्राप्त संदानों को सीधे संबंधित आरक्षित खाते में जमा किया जाता है।
- (iii) दूरस्थ शिक्षा फीस के 25 प्रतिशत, जो वर्ष के शुद्ध अधिशेष के 50 प्रतिशत से अधिक न हो, शिक्षा निधि को अंतरित किया जाता है।
- (iv) वर्ष के दौरान प्राप्त सदस्यता फीस (वार्षिक और व्यवसाय प्रमाणपत्र संबंधी फीस) के 0.75 प्रतिशत को कर्मचारी कल्याण निधि को अंतरित किया जाता है।
- (v) उद्दिष्ट निधियों से शिक्षा आरक्षित खाते को निम्नलिखित अंतरण किए जाते हैं :

(क) लेखांकन अनुसंधान भवन निधि से लेखांकन अनुसंधान भवन निधि से भवन से संबंधित अभिवृद्धियों की लागत (कटौतियों का शुद्ध, यदि कोई हों) का 100 प्रतिशत

(ख) शिक्षा निधि से फिक्स्ड एसेट्स फंड्स में 50% लागत वृद्धि (कटौती का शुद्ध)

(vi) उद्दिष्ट निधियों के निवेश से होने वाली आय को उद्दिष्ट निधियों में जोड़ा जाता है। इस आय को, संबद्ध उद्दिष्ट निधियों के प्रारंभिक अतिशेष के आधार पर, भारत औसत का आधार बनाते हुए आबंटित किया जाता है।

(vii) सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण (आईटीटी)/उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की फीस के 25% की एक आरक्षिती का सृजन, भविष्य में कंप्यूटरों के प्रतिस्थापन और अन्य आईटीटी केंद्र अवसंरचना को प्रतिस्थापित करने के लिए किया गया है।

**2.7 अवक्षयण और परिशोधन:** आस्तियों के लिए अवक्षयण संबंधी रकम, आस्ति की लागत या लागत के लिए प्रतिस्थापित कोई अन्य रकम है, जिसमें से उसके प्राक्कलित शेष मूल्य को घटा दिया गया हो।

मूर्त नियत आस्तियों के संबंध में अवक्षयण को संस्थान की परिपद् द्वारा अनुमोदित उपयोगी जीवन के अनुसार अपलिखित मूल्य पद्धति पर उपलब्ध कराया जाता है।

आस्तियों के उपयोगी जीवन का निर्धारण, तकनीकी सलाह के आधार पर आस्ति की प्रकृति, आस्ति के प्राक्कलित उपयोग, आस्ति के प्रचालन की परिस्थितियों, प्रतिस्थापन के पूर्व ईतिवृत्त, अनुमानिक प्रौद्योगिकी संबंधी परिवर्तनों, विनिर्माताओं की वारंटियों और अनुरक्षण समर्थन आदि को ध्यान में रखते हुए निम्नानुसार किया जाता है। नियत आस्तियों के परिशोधन के लिए प्रयुक्त परिशोधन दरें निम्नानुसार हैं।

## 2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का संक्षिप्त विवरण

	आस्तियों का वर्ग	अवक्षयण की दर
(i)	भवन	5%
(ii)	लिफ्ट, इलैक्ट्रीकल प्रतिष्ठापन और फीटिंग	10%
(iii)	कंप्यूटर	60%
(iv)	फर्नीचर और फिक्सचर	10%
(v)	वातानुकूलक और कार्यालय उपस्कर	15%
(vi)	वाहन	20%
(vii)	पुस्तकालय की पुस्तकें	100%

पट्टाधृत भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि के पश्चात् किया जाता है।

अमूर्त आस्तियों का परिशोधन उनके प्राक्कलित उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी कटौती पद्धति के अनुसार निम्नलिखित रूप में किया जाता है :

कंप्यूटर साफ्टवेयर : 3 वर्ष

अमूर्त आस्तियों के प्राक्कलित उपयोगी जीवन और परिशोधन अवधि का पुनर्विलोकन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत पर किया जाता है और परिवर्तित पैटर्न, यदि कोई हो, उपदर्शित करने के लिए हानिकरण की अवधि का पुनरीक्षण किया जाता है।

**2.8 राजस्व मान्यता:** संस्थान राजस्व को निम्नानुसार मान्यता प्रदान करता है :

- दूरस्थ शिक्षा फीस को संबद्ध पाठ्यक्रम की अवधि के आधार पर अनुपाततः मान्यता प्रदान की जाती है।
- कक्षा प्रशिक्षण फीस में साधारण प्रबंध और संसूचना कौशल कार्यक्रम ("जीएमसीएस") सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण ("आईटीटी") और अनुकूलन कार्यक्रम ("ओपी") के लिए प्राप्त फीस सम्मिलित होती है, इस आय को उस समय मान्यता प्रदान की जाती है, जब सेवाओं को प्रदान किया जाता है और संबद्ध लागतों को उपगत किया जाता है।

- iii) परीक्षा फीस को संबंधित परीक्षाओं के आयोजन के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है।
- iv) संगोष्ठी फीस को संबद्ध क्रियाकलाप के आयोजन के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है।
- v) वार्षिक सदस्यता फीस (जिसके अंतर्गत व्यवसाय प्रमाण-पत्र और उसे पुनः स्थापित करने की फीस भी सम्मिलित है) और प्रवेश फीस से मिलकर बनने वाली सदस्यता फीस को निम्नानुसार मान्यता प्रदान की जाती है :

(क) वार्षिक सदस्यता फीस (जिसके अंतर्गत व्यवसाय प्रमाणपत्र के लिए फीस भी है) को उस समय आय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जब वह वर्ष के दौरान शोध्य हो जाती है। नाम को पुनः प्रविष्ट करने संबंधी फीस की आय को, उसके प्राप्त होने पर मान्यता प्रदान की जाती है।

(ख) प्रवेश फीस :

- सहयोजित सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति को प्रवेश दिए जाने के समय एकत्रित प्रवेश फीस के एक-तिहाई भाग को उस वर्ष की प्रवेश संबंधी आय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है और शेष भाग को अवसंरचना आरक्षिती में मान्यता प्रदान की जाती है।
- अध्येता सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति को प्रवेश दिए जाने के समय एकत्रित प्रवेश फीस को अवसंरचना आरक्षिती में मान्यता प्रदान की जाती है।

- vi) छात्र रजिस्ट्रीकरण फीस को संबद्ध पाठ्यक्रमों की अवधि के अनुसार अनुपाततः मान्यता दी जाती है।
- vii) छात्र संगमों संबंधी आय को उस समय मान्यता दी जाती है जब छात्रों को पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश प्रदान किया जाता है।
- viii) अर्हता-पश्च पाठ्यक्रमों और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के राजस्वों को उस अवधि में मान्यता प्रदान की जाती है, जिसमें सेवाएं दी जाती हैं।

## 2.9 अन्य आय:

क) प्रकाशन के विक्रय से होने वाली आय को उस समय मान्यता प्रदान की जाती है जब जोखिम और पुरस्कारों को क्रेता को अंतरित किया जाता है, जो सामान्यतः माल के परिदान के समय होता है। इस आय में, प्राप्त हुआ यह प्राप्य प्रतिफल, बट्टों का शुद्ध और अन्य विक्रय संबंधी कर (यदि कोई हों) सम्मिलित हैं।

ख) छात्र न्यूज लैटर और जर्नल के अभिदाय से होने वाली आय को अभिदाय के समय के अनुसार अनुपाततः मान्यता प्रदान की जाती है।

ग) कैम्पस साक्षात्कारों और विशेषज्ञ सलाहकार फीस से होने वाली आय को उस समय मान्यता दी जाती है, जब सेवाएं प्रदान की जाती हैं और संबद्ध लागतों को उपगत किया जाता है।

घ) व्याज संबंधी आय में बैंकों में साधारण रूप से जमा निक्षेपों और उद्दिष्ट निधियों पर प्राप्त व्याज सम्मिलित होता है।

## 2.10 नियत आस्तियां

**क) मूर्त आस्तियां:** मूर्त आस्तियों का कथन, एकत्रित अवक्षयण और हानिकरण हानियों (यदि कोई हों) को घटाकर लागत पर किया जाता है। किसी नियत आस्ति की लागत में सामग्रियों की क्रय लागत, किन्हीं व्यापार संबंधी बट्टों और छूटों के शुद्ध को गणना में लेते हुए, सम्मिलित होती है, जिसके अंतर्गत लगने वाले आयात शुल्क और अन्य कर (उनसे भिन्न, जो पश्चातवर्ती रूप से कर अधिकारियों से वसूलनीय होते हैं), किसी आस्ति को उसके आशयित उपयोग के लिए तैयार करने हेतु होने वाली कोई प्रत्यक्ष लागत, अन्य अनुषंगी व्यय और आशयित उपयोग के लिए आस्ति के तैयार होने की तारीख तक अर्हित नियत आस्तियों के अर्जन के मद्दे लिए गए उधारों पर व्याज भी है। मूर्त आस्तियों के क्रय/उनके पूर्ण होने के पश्चात् उनसे संबंधित पश्चातवर्ती व्यय को केवल उस दशा में पूंजीकृत किया जाता है, यदि ऐसे व्ययों के परिणामस्वरूप उसके पूर्व में निर्धारित कार्यपालन संबंधी मानक से परे ऐसी आस्ति से होने वाले किन्हीं भावी फायदों में वृद्धि होती है।

**ख) अमूर्त आस्तियां:** अमूर्त आस्तियों का कथन, एकत्रित परिशोधन और एकत्रित हानिकरण (यदि कोई हों) को घटाकर लागत पर किया जाता है। किसी अमूर्त आस्ति की लागत में, उसकी क्रय लागत (छूट और बट्टों का शुद्ध) सम्मिलित होती है, जिसके अंतर्गत लगने वाले आयात शुल्क और अन्य कर (उनसे भिन्न, जो पश्चातवर्ती रूप से कर अधिकारियों से वसूलनीय होते हैं), किसी आस्ति को उसके आशयित उपयोग हेतु तैयार करने के लिए होने वाली कोई प्रत्यक्ष लागत भी है। किसी आस्ति को उसके आशयित उपयोग के लिए तैयार करने हेतु होने वाली कोई प्रत्यक्ष लागत, अन्य अनुषंगी व्यय और आशयित उपयोग के लिए आस्ति के तैयार होने की तारीख तक अर्हित नियत आस्तियों के अर्जन के मद्दे लिए गए उधारों पर व्याज भी है। अमूर्त आस्तियों के क्रय/उनके पूर्ण होने के पश्चात् उनसे संबंधित पश्चातवर्ती व्यय को केवल उस दशा में पूंजीकृत किया जाता है, यदि ऐसे व्ययों के परिणामस्वरूप उसके पूर्व में निर्धारित कार्यपालन संबंधी मानक से परे ऐसी आस्ति से होने वाले किन्हीं भावी फायदों में वृद्धि होती है।



ग) **चालू पूंजी संकर्म:** ऐसी आस्तियों के, जो उनके आशयित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, संनिर्माण पर उपगत व्यय को, चालू पूंजी संकर्म के अधीन हानिकरण (यदि कोई हो) को घटाकर लागत पर संगणित किया जाता है। इस लागत में, सामग्रियों की क्रय लागत सम्मिलित होती है, जिसके अंतर्गत लागतों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े आयात-शुल्क और गैर-प्रतिदेय कर भी हैं।

## 2.11 निवेश

क) आईसीएआई, केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित भारत सरकार की प्रतिभूतियों और राष्ट्रीकृत बैंकों में सावधि निक्षेपों में निवेश करता है।

ख) सावधि निक्षेपों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

ग) प्रतिभूतियों में निवेशों को अर्जन लागत के आधार पर संगणित किया जाता है। क्रय के समय पर संदत्त प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि के अनुसार परिशोधित किया जाता है। प्रीमियम के परिशोधन को "निवेशों पर ब्याज" शीर्ष के अधीन आय के प्रति समायोजित किया जाता है।

घ) क्रय के समय संदत्त प्रोदभूत ब्याज का मुजरा आय की प्रथम प्राप्ति के प्रति किया जाता है।

ङ) व्यष्टिक रूप से प्रत्येक निवेश के लिए अस्थायी, यदि कोई हो, के अलावा मूल्य में कमी के लिए प्रावधान किया जाता है।

**2.12 विदेशी मुद्रा संव्यवहार:** विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को, संव्यवहार की तारीख को लागू विनिमय दरों पर लेखांकित किया जाता है। संस्थान की विदेशी मुद्रा धनीय मदों, जो तुलन-पत्र की तारीख को बकाया हैं, वर्ष अंत की दरों पर पुनः प्रारंभ किया जाता है। संस्थान की गैर-धनीय मदों का लेखांकन ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है।

संस्थान की विदेशी मुद्रा धनीय आस्तियों और दायित्वों के समाधान/पुनर्कथन पर उदभूत होने वाले विनिमय संबंधी अंतरों को आय और व्यय के विवरण में आय या व्यय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

**2.13 कर्मचारी फायदे:** कर्मचारी फायदों में भविष्य निधि, उपदान निधि, प्रतिपूरित अनुपस्थिति, दीर्घ सेवा पुरस्कार, पेंशन स्कीम और सेवा-पश्च चिकित्सीय फायदें सम्मिलित हैं

i) **परिभाषित अभिदाय योजनाएं:** परिभाषित अभिदाय योजनाएं, ऐसी योजनाएं हैं, जहां भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के भविष्य निधि न्यास ("न्यास") को अभिदाय के रूप में भविष्य निधि स्कीम में किए गए संस्थान के अभिदाय को, परिभाषित अभिदाय योजनाओं के रूप में विचार में लिया जाता है और उसे अभिदाय की रकम पर आधारित ऐसे व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है, जिसे उपगत किया जाना अपेक्षित था और जब यह कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले किया जाता है। न्यास का प्रबंध भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा निर्वाचित शासी निकाय द्वारा किया जाता है।

ii) **परिभाषित फायदा योजनाएं:** उपदान और सेवानिवृत्ति पेंशन के रूप में परिभाषित फायदा योजनाओं के लिए, फायदे उपलब्ध कराने की लागत का अवधारण प्रक्षेपित यूनिट प्रत्यय पद्धति का उपयोग करते हुए किया जाता है, जिसके दौरान प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। बीमांकिक अभिलाभों और हानियों को उस अवधि के आय और व्यय विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है, जिसमें वे उदभूत होते हैं। पूर्व सेवा संबंधी लागत को, फायदों के पहले से ही निहित किए जाने की सीमा तक तुरंत मान्यता प्रदान की जाती है और उन्हें अन्यथा फायदों के निहित हो जाने तक की औसत अवधि के अनुसार सीधी कटौती पद्धति के आधार पर परिशोधित किया जाता है। तुलन-पत्र में मान्य ठहराई गई सेवानिवृत्ति फायदे संबंधी बाध्यता, गैर-मान्यताप्राप्त पूर्व सेवा लागत के लिए यथा समायोजित परिभाषित फायदा बाध्यता के वर्तमान मूल्य को उपदर्शित करती है, जिसमें से स्कीम संबंधी अस्तियों के उचित मूल्य को घटा दिया गया हो। इस परिगणना के पारिणामिक कोई आस्ति, पूर्व सेवा लागत धन उपलब्ध प्रतिदायों और स्कीमों में भावी अभिदायों में कमी के वर्तमान मूल्य तक सीमित है।

उपदान संबंधी दायित्व को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। इन परिभाषित फायदा बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य को लेखांकन मानक (एएस) - 15, कर्मचारी फायदे के अनुसार एक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकनकर्ता द्वारा अभिनिश्चित किया जाता है।

iii) **अल्पकालिक कर्मचारी फायदे:** अल्पकालिक कर्मचारी फायदों (जैसे कि वेतन, भत्ते, अनुग्रह आदि) की बढ़ा रहित रकम को, कर्मचारियों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बदले संदत्त किए जाने की आशा की जाती है, जिसे वर्ष के दौरान उस समय मान्यता प्रदान की जाती है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करते हैं। अल्पकालिक कर्मचारी फायदे संभावी रूप से उस अवधि के अंत के 12 मास के पश्चात् उत्पन्न होते हैं, जिसमें कर्मचारियों द्वारा संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

अल्पकालिक प्रतिपूरित अनुपस्थिति की लागत को निम्नानुसार लेखांकित किया जाता है:

क) एकत्रित प्रतिपूरित अनुपस्थितियों की दशा में, जब कर्मचारी ऐसी सेवाएं प्रदान करते हैं, जो उनकी भावी प्रतिपूरित अनुपस्थितियों की हकदारी में वृद्धि करती हैं; और

ख) गैर-एकत्रित प्रतिपूरित अनुपस्थितियों की दशा में, जब अनुपस्थितियां दर्ज की जाती हैं।

**iv) दीर्घकालिक कर्मचारी फायदे:** ऐसी प्रतिपूरित अनुपस्थितियां, जिनकी उस अवधि के अंत के पश्चात् 12 मास के भीतर उत्पन्न होने की संभावना नहीं है, जिसमें कर्मचारी द्वारा दी गई संबद्ध सेवाओं को तुलन-पत्र की तारीख को परिभाषित फायदा बाध्यता के वर्तमान मूल्य पर एक ऐसे दायित्व के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जिसमें से योजना आस्तियों के उचित मूल्य को घटा दिया गया हो और जिसमें से बाध्यताओं के समाधान होने की आशा की जाती है।

### **भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण**

#### **v) अन्य फायदे**

**क) पेंशन स्कीम:** संस्थान पेंशन के रूप में अपने कर्मचारियों को फायदे की प्रस्थापना करता है। तुलन-पत्र की तारीख को इस बाध्यता के वर्तमान मूल्य को बीमाकंक से बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है।

**ख) सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पति/पत्नी को सेवानिवृत्ति-पश्च चिकित्सीय स्कीम संबंधी फायदे:** संस्थान एक चिकित्सा स्कीमों के रूप में अपने कर्मचारियों को फायदे की प्रस्थापना करता है। तुलन-पत्र की तारीख को इस बाध्यता के वर्तमान मूल्य को बीमाकंक से बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है।

**2.14 पट्टे :** ऐसे पट्टा संबंधी ठहरावों में, जहां किसी आस्ति के स्वामित्व से अनुषंगी जोखिम और पुरस्कार सारवान रूप से पट्टाकर्ता में निहित होते हैं, वहां उन्हें चालू पट्टों के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। चालू पट्टों के अधीन पट्टा संबंधी किरायों को पट्टे की अवधि के अनुसार सीधे कटौती पद्धति के आधार पर आय और व्यय के विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है।

**2.15 मूर्त और अमूर्त आस्तियों का हानिकरण:** प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को आस्तियों के अग्रेषण मूल्य को हानिकरण हेतु पुनर्विलोकित किया जाता है। यदि हानिकरण का कोई संकेत विद्यमान होता है तो ऐसी आस्तियों की वसूलनीय रकम को प्राक्कलित किया जाता है और हानिकरण को उस समय मान्यता प्रदान की जाती है, यदि इन आस्तियों की अग्रणीत रकम उनकी वसूलनीय रकम से अधिक हो जाती है। वसूलनीय रकम, शुद्ध विक्रय कीमत और उनके उपयोग मूल्य दोनों में से उच्चतर है। उपयोग मूल्य की गणना, भावी नकद प्रवाहों को एक समुचित बट्टा कारक के आधार पर बट्टा देते हुए उनके वर्तमान मूल्य के आधार पर की जाती है। जब इस बात का कोई संकेत प्राप्त होता है कि किसी आस्ति के लिए पूर्ववर्ती लेखांकन अवधियों के दौरान मान्यता प्रदान किया गया हानिकरण अब विद्यमान नहीं है या उसमें कोई कमी आई है तो ऐसे हानिकरण की वापसी को आय और व्यय के विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है।

**2.16 आय पर कर :** संस्थान को आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) और 11 के अधीन आय-कर से छूट प्रदान की गई है।

**2.17 उद्दिष्ट और अन्य निधियों के लिए धारित आस्तियां :** उद्दिष्ट निधियों और बैंकों में निक्षेपों के रूप में धारित ऐसे अन्य निक्षेपों के रूप में अन्य निधियों को, जो तुलन-पत्र की तारीख से 12 मास की अवधि के पश्चात् परिपक्व हो रहे हैं, गैर-चालू और अन्य निधियों को चालू निधियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ये निधियां संस्थान की परिषद् के विवेकानुसार उपयोग के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध हैं, सिवाय उद्दिष्ट और कर्मचारी फायदा निधियों की कुल योग की सीमा तक।

**2.18 प्रावधान और आकस्मिकताएं:** किसी प्रावधान को उस समय मान्यता दी जाती है, जब किन्हीं पूर्व घटनाओं के परिणामस्वरूप संस्थान की कोई बाध्यता विद्यमान है और इस बात की संभावना है कि ऐसी बाध्यता को पूरा करने के लिए संसाधनों का बहिर्गमन अपेक्षित होगा, जिसके संबंध में कोई विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सकता है।

आकस्मिक दायित्व ऐसी संभाव्य बाध्यता है, जो किन्हीं पूर्व घटनाओं से उद्भूत होती है और जिसकी विद्यमानता की पुष्टि एक या अधिक अनिश्चित ऐसी भावी घटनाओं के घटित या घटित न होने पर निर्भर हो सकती है, जो पूर्णतया संस्थान के नियंत्रणाधीन नहीं है या जो कोई ऐसी वर्तमान बाध्यता है, जो किसी पूर्व घटना से उद्भूत हुई है, किंतु जिसे या तो इस कारण से कि यह संभाव्य नहीं है कि उस बाध्यता को पूरा करने के लिए आर्थिक फायदों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों का बहिर्गमन अपेक्षित होगा या इस कारण से कि बाध्यता को पूरा करने के लिए किसी रकम का विश्वसनीय प्राक्कलन नहीं किया जा सकता है, मान्यता प्रदान नहीं की गई है। आकस्मिक दायित्वों का प्रकटन किया जाता है और उन्हें मान्यता प्रदान नहीं की जाती है।

आकस्मिक आस्तियों को न तो मान्यता प्रदान की जाती है और न ही उनका प्रकटन किया जाता है।

**भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान**  
**वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण**

**टिप्पण # 3. आरक्षितियां और अधिशेष**

(लाख रुपए में)

विविधियां	साधारण		शिक्षा		अवसंरचना		अन्य		कुल	
	31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
वर्ष के आरंभ में अतिशेष	71,796	71,810	35,854	34,874	5,304	5,068	987	741	113,941	112,493
जोड़ें: आय और व्यय विवरण से विनियोग	10,411	834	-	-	-	-	1,001	-	11,412	834
साधारण आरक्षित, अवसंरचना आरक्षित और अन्य आरक्षित से/(को) अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उद्दिष्ट निधियों से/(को) अंतरण	-	(848)	2,489	980	-	(24)	-	247	2,489	355
दाखिला फीस और आर्बिट्रट प्रवेश फीस	-	-	-	-	367	242	-	-	367	242
भवनों के लिए प्राप्त संदान	-	-	-	-	11	18	-	-	11	18
(उपयोग)/परिवृद्धियां	-	-	-	-	18	-	1	(1)	19	(1)
वर्ष के अंत में अतिशेष	82,207	71,796	38,343	35,854	5,700	5,304	1,989	987	128,239	113,941

\* अन्य आरक्षितियों में, पुस्तकालय आरक्षितियां और कक्षा प्रशिक्षण आरक्षितियां, विदेशी मुद्रा अनुवाद आरक्षित (दुबई नाका) जैसी आरक्षितियां सम्मिलित हैं।

**भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान**  
**वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण**

**टिप्पण : #4. उद्दिष्ट निधियां**

(लाख रुपए में)

विविधियां	अनुसंधान निधियां		लेखांकन अनुसंधान भवन निधि		शिक्षा निधि		पदक और पुरस्कार निधि		छात्रों की छात्रवृत्ति निधियां		कर्मचारी कल्याण निधि		अन्य निधियां		योग	
	31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
वर्ष के प्रारंभ में अतिशेष	2,282	2,094	793	727	25,204	21,107	236	222	127	120	661	572	5,026	4,357	34,329	29,199
आय और व्यय के विवरण से विनियोग	-	-	-	-	5,073	3,158	-	-	-	-	78	43	-	-	5,151	3,201
आरक्षितियों और अधिशेष से/(को) अंतरण	-	-	-	-	(2,489)	(980)	-	-	-	-	-	-	-	625	(2,489)	(355)
वर्ष के दौरान प्राप्त अभिदाय/परिवृद्धियां	24	-	-	-	-	-	23	3	36	-	-	-	-	-	83	3
वर्ष के दौरान आय और व्यय के विवरण के माध्यम से विनियोग की गई व्याज आय	173	188	61	66	1,925	1,919	15	16	10	11	50	52	83	92	2,317	2,344
वर्ष के दौरान उपयोजित	-	-	-	-	-	-	(9)	(5)	(6)	(4)	-	(6)	(6)	(48)	(21)	(63)
वर्ष के अंत में अतिशेष	2,479	2,282	854	793	29,713	25,204	265	236	167	127	789	661	5,103	5,026	39,370	34,329

39,370 रुपए (पूर्व वर्ष में 34,329) की कुल उद्दिष्ट निधियों को सावधि निक्षेपों और सरकारी प्रतिभूतियों में धारण किया जाता है (टिप्पण 12 और 13 देखें)

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

**वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण**

(लाख रुपए में)

टिप्पण #5: अन्य दीर्घकालिक दायित्व		31 मार्च को यथा विद्यमान	
		2018	2017
क) अग्रिम में प्राप्त फीस			
i) शिक्षा फीस		1,206	723
ii) जर्नल का अभिदाय		13	8
<b>योग</b>		<b>1,219</b>	<b>731</b>

टिप्पण #6 : प्रावधान	31 मार्च को यथा विद्यमान		31 मार्च को यथा विद्यमान	
	2018	2017	2018	2017
	दीर्घकालिक	दीर्घकालिक	अल्पकालिक	अल्पकालिक
कर्मचारी फायदों के लिए प्रावधान				
क) नियोजन पश्च परिभाषित फायदे				
i) उपदान	567	-	454	186
ii) पेंशन	11,426	10,710	464	406
ख) छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	3,748	3,528	389	345
ग) शाखा कर्मचारियों के लिए प्रावधान (टिप्पण-24.17)	2,800	2,100		
घ) वेतन पुनरीक्षण के लिए प्रावधान (टिप्पण-24.18)	4,400	-	-	-
<b>योग</b>	<b>22,941</b>	<b>16,338</b>	<b>1,307</b>	<b>937</b>

टिप्पण #7 : व्यापार संबंधी देय	31 मार्च को यथा विद्यमान	
	2018	2017
व्यापार संबंधी देय	3,677	3,191
<b>योग</b>	<b>3,677</b>	<b>3,191</b>

टिप्पण #8 : अन्य चालू दायित्व	31 मार्च को यथा विद्यमान	
	2018	2017
क) अग्रिम में प्राप्त फीस		
i) परीक्षा फीस	7,231	7,106
ii) जर्नल अभिदाय	21	16
iii) सदस्यता फीस	2,876	1,886
iv) शिक्षा फीस	9,060	7,327
v) अर्हता पश्च पाठ्यक्रम फीस	111	110
vi) प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम फीस	118	40
vii). संगोष्ठी फीस और अन्य संग्रहण		
क) संगोष्ठी सदस्य	105	62
ख) संगोष्ठी छात्र	2	1
viii) कक्षा प्रशिक्षण फीस	1,325	652
ix) कोचिंग कक्षा फीस	84	133
x) अन्य संग्रहण	64	81
<b>कुल योग (क)</b>	<b>20,997</b>	<b>17,414</b>

ख)	अन्य दायित्व		
i)	नियत आस्तियों के क्रय के लिए देनदार	29	4
ii)	भविष्य निधि, ईएसआईसी को अभिदाय, वृत्तिक कर आदि	96	166
iii)	कानूनी देय (प्रतिधारण संबंधी कर)	317	258
iv)	जीएसटी संदेय	1,389	-
v)	प्रतिभूति और अग्रिम संदाय संबंधी निक्षेप	832	787
vi)	अन्य	614	716
	<b>कुल योग (ख)</b>	<b>3,277</b>	<b>1,931</b>
	<b>योग (क+ख)</b>	<b>24,274</b>	<b>19,345</b>

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान  
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण

(लाख रुपए में)

टिप्पण 9. # पूर्व आस्तियां		सकल ब्लॉक		अवक्षयण		अवक्षयण		अवक्षयण		अवक्षयण	
विशेषियां	31 मार्च को बचा विद्यमान	वर्ष के प्रारंभ में लागत	परिवृद्धि वां	हस्तांतरण/ विलोपन	वर्ष के अंत में लागत	वर्ष के प्रारंभ में संचयी अवक्षयण	वर्ष के लिए प्रचारित	हस्तांतरण/ विलोपन	वर्ष के अंत में संचयी अवक्षयण	वर्ष के अंत में शुद्ध बही मूल्य	
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	2018	19,214	270	(1,821)	17,663	-	-	-	-	17,663	
	2017	18,817	397	-	19,214	-	-	-	-	19,214	
पट्टाश्रुत भूमि	2018	5,879	112	1,558	7,549	668	107	49	824	6,725	
	2017	5,682	197	-	5,879	582	86	-	668	5,211	
भवन	2018	28,441	3,096	263	31,800	6,600	* 1,449	(283)	7,766	24,034	
	2017	27,789	680	(28)	28,441	5,492	1,127	(19)	6,600	21,841	
लिफ्ट तथा इलेक्ट्रीकल प्रतिष्ठापन और फीटिंग	2018	1,863	342	(22)	2,183	1,063	106	(12)	1,157	1,026	
	2017	1,806	63	(6)	1,863	973	92	(2)	1,063	800	
कंप्यूटर	2018	5,129	178	(74)	5,233	4,767	242	(61)	4,948	285	
	2017	4,867	301	(39)	5,129	4,383	399	(15)	4,767	362	
फर्नीचर और फिक्सचर	2018	4,192	401	(21)	4,572	1,990	241	(10)	2,221	2,351	
	2017	4,070	151	(29)	4,192	1,756	237	(3)	1,990	2,202	
वातानुकूलक और कार्यालय उपस्कर	2018	4,801	634	(48)	5,387	2,850	325	(40)	3,135	2,252	
	2017	4,586	259	(44)	4,801	2,535	320	(5)	2,850	1,951	
वाहन	2018	135	-	-	135	101	7	-	108	27	
	2017	135	1	(1)	135	92	9	-	101	34	
पुस्तकालय की पुस्तकें	2018	1,009	32	-	1,041	1,009	32	-	1,041	-	
	2017	968	41	-	1,009	968	41	-	1,009	-	
<b>योग</b>	<b>2018</b>	<b>70,663</b>	<b>5,065</b>	<b>(165)</b>	<b>75,563</b>	<b>19,048</b>	<b>2,509</b>	<b>(357)</b>	<b>21,200</b>	<b>54,363</b>	
	<b>2017</b>	<b>68,720</b>	<b>2,090</b>	<b>(147)</b>	<b>70,663</b>	<b>16,781</b>	<b>2,311</b>	<b>(44)</b>	<b>19,048</b>	<b>51,615</b>	

\* पूर्व अवधि अवक्षयण सहित

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान  
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण

(लाख रुपए में)

टिप्पण 10.# अमूर्त आस्तियां कंप्यूटर साफ्टवेयर	31 मार्च को यथाविद्यमान	
	2018	2017
वर्ष के प्रारंभ में लागत	663	646
परिवृद्धियां	62	19
अंतरण/विलोपन	21	(2)
<b>वर्ष के अंत में लागत</b>	<b>746</b>	<b>663</b>
वर्ष के प्रारंभ में परिशोधन	644	623
वर्ष के लिए प्रभार	31	23
अंतरण/विलोपन	16	(2)
<b>वर्ष के अंत में परिशोधन</b>	<b>691</b>	<b>644</b>
वर्ष के अंत में शुद्ध बही मूल्य	<b>55</b>	<b>19</b>
वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध बही मूल्य	<b>19</b>	<b>23</b>

	31 मार्च को यथाविद्यमान	
	2018	2017
<b>टिप्पण 11. #: चालू पूंजी संकर्म</b>		
प्रारंभिक अतिशेष	13,875	13,202
जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवृद्धियां	561	673
घटाएं : वर्ष के दौरान पूंजीकृत/ समायोजित रकम	(3,559)	-
<b>अंतिम अतिशेष</b>	<b>10,877</b>	<b>13,875</b>

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान  
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण

(लाख रुपए में)

टिप्पण # 12: निवेश (लागत पर)	31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान	
	2018	2017	2018	2017
	गैर-चालू	गैर-चालू	चालू	चालू
<b>क. केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियां</b>				
व्यापार योग्य प्रतिभूतियां				
i. 8.27% भारत सरकार 2020	2,588	2,628	-	-
ii. 7.46% भारत सरकार 2017	-	-	-	1,651
iii. 7.49% भारत सरकार 2017	-	-	-	861
iv. 7.80% भारत सरकार 2021	2,588	2,618	-	-
v. 6.35% भारत सरकार 2020	995	-	-	-
	<b>6,171</b>	<b>5,246</b>	<b>-</b>	<b>2,512</b>

<u>गैर-व्यापार योग्य प्रतिभूतियां</u>					
vi. 8.00% पर भारत सरकार के कराधेय बंधपत्र – संचयी	11,200	-	-	-	-
vii. 8.0% बचत (कराधेय) बंधपत्र 2003 – गैर संचयी	44,000	-	-	-	-
	55,200	-	-	-	-
<b>बही मूल्य</b>	61,371	5,246	-	2,512	
बाजार मूल्य					
- व्यापार योग्य	6,112	5,214	-	2,514	
- गैर-व्यापार योग्य (बही मूल्य)	55,200	-	-	-	
	61,312	5,214	-	2,514	
<b>ख. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां</b>					
i. 8.47% तमिलनाडु एसडीएल 2017	-	-	-	3,042	
ii. 8.21% राजस्थान उदय एसडीएल 2018	-	-	-	2,537	
iii. 7.75% राजस्थान उदय एसडीएल 2018	-	2,532	2,506	-	
iv. 8.45% पंजाब एसडीएल – 2023	2,572	-	-	-	
v. 8.45% कर्नाटक एसडीएल – 2024	3,068	-	-	-	
vi. 8.45% कर्नाटक एसडीएल – 2024	2,045	-	-	-	
vii. 8.62% महाराष्ट्र एसडीएल – 2023	514	-	-	-	
viii. 8.75% पश्चिमी बंगाल जीएस – 2022	514	-	-	-	
ix. 8.39% राजस्थान उदय एसडीएल – 2022	1,537	-	-	-	
x. 8.39% राजस्थान बांड – 2021	3,904	-	-	-	
<b>बही मूल्य</b>	14,154	2,532	2,506	5,579	
बाजार मूल्य	14,209	2,527	2,506	5,574	
<b>कुल योग</b>	75,525	7,778	2,506	8,091	

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान  
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण

(लाख रुपए में)

<b>टिप्पण # 12: निवेश</b> <b>(लागत पर)</b>		<b>31 मार्च को</b> <b>यथाविद्यमान</b>		<b>31 मार्च को</b> <b>यथाविद्यमान</b>	
		2018	2017	2018	2017
<b>ग. सतत बेसल III बंधपत्रों के पब्लिक सेक्टर अधीनस्थ</b>		गैर-चालू	गैर-चालू	चालू	चालू
i. 10.75% आईडीबीआई बैंक लिमिटेड		-	3,018	-	-
ii. 10.95% ओरियंटल बैंक आफ कामर्स		-	1,021	-	-
iii. 10.95% ओरियंटल बैंक आफ कामर्स		-	1,532	-	-
iv. 9.00% भारतीय स्टेट बैंक		-	511	-	-
v. 9.00% भारतीय स्टेट बैंक		-	4,576	-	-
vi. 11.00% बैंक आफ इंडिया		-	1,047	-	-
vii. 11.00% बैंक आफ इंडिया		-	1,047	-	-

viii. 10.99% आंध्र बैंक	-	3,101	-	-
<b>बही मूल्य</b>	-	15,853	-	-
बाजार मूल्य	-	15,878	-	-
<b>घ. समनुषंगी की साम्या लिखतों में निवेश</b>				
(पूर्ण समादत्त)				
i. आईसीएआई के दीवाला वृत्तिक संस्थान के 100 रुपए प्रत्येक के 10,00,000 साधारण शेयर	1,000	1,000	-	-
ii. आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन निवेश	10	-	-	-
<b>बही मूल्य</b>	1,010	1,000	-	-
<b>कुल योग</b>	1,010	16,853	-	-
<b>योग</b>	76,535	24,631	2,506	8,091

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान  
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण

(लाख रुपए में)

टिप्पण # 13: उद्दिष्ट और अन्य निधियों के लिए धारित आस्तियां	31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान	
	2018	2017	2018	2017
	गैर-चालू	गैर-चालू	चालू	चालू
बैंकों में सावधि निक्षेप (नीचे टिप्पण देखें)	5,229	3,630	54,704	70,388
<b>योग</b>	5,229	3,630	54,704	70,388
<b>टिप्पण : धारित आस्तियों में निम्नलिखित हैं:</b>				
- निवेश (टिप्पण # 12)	76,535	24,631	2,506	8,091
- उद्दिष्ट और अन्य निधियों के लिए धारित आस्तियां (टिप्पण #13)	5,229	3,630	54,704	70,388
<b>योग</b>	81,764	28,261	57,210	78,479
आयोजित संपत्ति (वर्तमान और गैर-वर्तमान) शामिल हैं				
- उद्दिष्ट निधियां (टिप्पण # 4)			39,370	34,329
- कर्मचारी फायदे (टिप्पण # 6)			24,248	17,275
- अन्य			75,356	55,136
<b>योग</b>			138,974	106,740

टिप्पण # 14: ऋण और अग्रिम (असुरक्षित, उत्तम समझे गए)	गैर चालू	गैर चालू	चालू	चालू
क) प्रतिभूति निक्षेप	190	254	362	145
ख) स्रोत पर कर कटौती	2,256	1,854	-	-



ग)	इनपुट कर प्रत्यय	-	-	966	-
घ)	अग्रिम पर जीएसटी सदस्यों से प्राप्त	-	-	366	-
ङ)	अन्य ऋण और अग्रिम				
i)	कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	660	634	551	561
ii)	अन्य प्राप्य	291	245	698	1,878
	घटाएं : संदेहस्पद प्राप्तियों के लिए प्रावधान	-	-	(229)	(332)
	<b>योग</b>	<b>3,397</b>	2,987	<b>2,714</b>	2,252

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान  
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण

(लाख रुपए में)

टिप्पण # 15 : अन्य आस्तियां	31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान	
	2018	2017	2018	2017
	गैर-चालू	गैर-चालू	चालू	चालू
क) प्रोदभूत ब्याज				
i. बैंक के साथ सावधि जमा पर	28	452	1,045	3,449
ii. निवेशों पर	506	1,111	981	123
iii. कर्मचारियों के ऋणों पर	144	121	39	32
<b>योग</b>	<b>678</b>	1,684	<b>2,065</b>	3,604

टिप्पण # 16 : वस्तु-सूचियां (निम्नतर लागत और शुद्ध वसूलनीय मूल्य पर)		31 मार्च को यथाविद्यमान	
		2018	2017
क) प्रकाशन और अध्ययन सामग्रियां		1,038	949
ख) लेखन सामग्रियां और भंडार		42	52
<b>योग</b>		<b>1,080</b>	1,001

टिप्पण # 17 : नकद और नकद समतुल्य		31 मार्च को यथाविद्यमान	
		2018	2017
क) हाथ में नकदी		43	36
ख) बैंकों में अतिशेष		6,781	4,999
<b>योग</b>		<b>6,824</b>	<b>5,035</b>

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान  
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण

टिप्पण # 18 : फीसें	31 मार्च को यथाविद्यमान (लाख रुपए में)	
	2018	2017
क) दूरस्थ शिक्षा	20,292	18,971
ख) कक्षा प्रशिक्षण आय	9,209	6,388
ग) परीक्षा	16,870	13,099
घ) छात्र रजिस्ट्रीकरण	948	515
ङ) छात्र संघ	414	386
च) अर्हतापश्च पाठ्यक्रम	747	797
छ) सदस्यता	10,830	5,869
ज) प्रवेश	106	74
झ) प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	1,825	1,265
ञ) कोचिंग	1,285	1,221
<b>योग</b>	<b>62,526</b>	<b>48,585</b>
<b>टिप्पण # 19 : सम्मेलन आय</b>		
a) सदस्य	3,555	3,529
b) छात्र	834	904
c) गैर सदस्य	1,328	1,088
d) ई-पठन आय	44	8
<b>योग</b>	<b>5,761</b>	<b>5,529</b>

टिप्पण # 20 : अन्य आय	31 मार्च को यथाविद्यमान	
	2018	2017
क) व्याज आय		
i. साधारण निधियों में धारित बैंक निक्षेप पर	3,234	4,098
ii. निवेशों से	3,114	1,172
iii. उद्दिष्ट निधियों के लिए धारित बैंक निक्षेप पर	2,317	2,344
iv. कर्मचारियों के ऋणों पर	78	72
ख) प्रकाशनों का विक्रय	1,568	1,540
ग) न्यूजलेटर	187	149
घ) जर्नल अभिदाय	113	52
ङ) कैम्पस साक्षात्कार	782	759
च) विशेषज्ञ सलाहकार फीस	23	25
छ) अनापेक्षित प्रावधानों का अपलेखन	193	114
ज) प्रकीर्ण आय	713	664
<b>योग</b>	<b>12,322</b>	<b>10,989</b>

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान  
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण

(लाख रुपए में)

टिप्पण # 21: कर्मचारी फायदा संबंधी व्यय	31 मार्च को यथाविद्यमान	
	2018	2017
क) वेतन, पेंशन और अन्य भत्ते	14,612	16,151
ख) भविष्य निधि और अन्य निधियों को अभिदाय	2,113	847
ग) कर्मचारिवृंद कल्याण व्यय	147	192
<b>योग</b>	<b>16,872</b>	<b>17,190</b>

टिप्पण # 22. अन्य व्यय			
क)	डाक और टेलीफोन	2,869	2,639
ख)	किराया, दरें और कर	5,242	5,232
ग)	यात्रा घरेलू	1,761	1,418
घ)	विदेशों से संबद्ध		
	i) विदेश यात्रा	310	256
	ii) विदेशी वृत्तिक निकायों की सदस्यता फीस	403	342
	iii) अन्य	103	52
ङ)	मरम्मत और अनुरक्षण	2,301	1,775
च)	कक्षा प्रशिक्षण व्यय	3,835	4,833
छ)	विज्ञापन और प्रचार	170	398
ज)	बैठक व्यय	895	595
झ)	योग्यता छात्रवृत्ति	176	124
ञ)	संपरीक्षा फीस : प्रधान कार्यालय	11	11
ट)	: अन्य कार्यालय	35	33
	उद्दिष्ट निधियों से संदाय	21	63
ठ)	पूर्वावधि समायोजन (शुद्ध) (टिप्पण 23)	748	227
ड)	जीएसटी व्यय	2,059	-
ढ)	संदेहास्पद उधारों और अग्रिमों के लिए प्रावधान	229	332
ण)	निवेश की विक्रय पर हानि	285	-
त)	प्रकीर्ण व्यय	1,317	1,572
<b>योग</b>		<b>22,770</b>	<b>19,902</b>

टिप्पण # 23 : पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)			
i)	आय	(116)	(173)
ii)	व्यय (अवक्षयण सहित)	864	400
<b>योग</b>		<b>748</b>	<b>227</b>

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान  
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण

**24. वित्तीय विवरणों से संबंधित अतिरिक्त जानकारी**

**24.01 आकस्मिक दायित्व और प्रतिबद्धताएं :**

(लाख रुपए में)

	2018	2017
<b>क. आकस्मिक दायित्व</b>		
i) संस्थान के विरुद्ध ऐसे दावे, जिन्हें ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नहीं किया गया है	1,830	1,216
ii) आयकर की मांग - (टिप्पण #24.03 देखें)	4,142	4,142

iii) संस्थान को, अपर महा निदेशक, माल और सेवा कर सतर्कता से एक कारण बताओ सूचना प्राप्त हुई थी कि संस्थान से 7032 लाख रुपए की रकम की मांग किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें यह दावा किया गया कि वार्षिक फीस, व्यवसाय प्रमाणपत्र फीस, प्रवेश फीस, आदि सेवा कर के लिए दायी हैं। संस्थान की यह राय है कि कारण बताओ सूचना में यथा उल्लिखित सेवा कर संदेय नहीं है। उक्त कारण बताओ सूचना का उपयुक्त प्रत्युत्तर भेजने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। सालिसीटर के साथ हुए विचार-विमर्श के आधार पर मामले में विशेषज्ञ से राय ली गई थी। प्रास्थिति पर विचार किया गया था। प्रबंध मंडल यह विश्वास करता है कि उसके पास ऊपर उल्लिखित मामलों में सफल होने की प्रबल संभावना है और अतः, इस समय इसके लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।

**ख. प्रतिबद्धताएं :**

(लाख रुपए में)

i) पूंजी प्रतिबद्धताएं (अग्रिमों का शुद्ध)	3,654	4,252
--	-------	-------

24.02 टिप्पण #14 दीर्घकालिक ऋणों और अग्रिमों के अधीन अन्य प्राप्ति में, नागपुर में भू-संपत्ति के अर्जन के लिए मूल और अनुपूरक करारों के रद्द हो जाने के कारण, स्टाम्प शुल्क के लिए 243.75 लाख रुपए के प्रतिदेय प्राप्य सम्मिलित हैं, जिसे संयुक्त जिला रजिस्ट्रार (जेडीआर), नागपुर द्वारा नामंजूर कर दिया गया है। संस्थान ने, मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी, पुणे के समक्ष महाराष्ट्र स्टाम्प शुल्क अधिनियम की धारा 53 के अधीन, जेडीआर, नागपुर द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देते हुए दो अपील फाइल की हैं, जो अंतिम अधिनिर्णयन के लिए लंबित हैं। संस्थान को यह सलाह दी गई है कि स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय प्राप्त करने के लिए उनके पास उत्तम विधिक मामला है।

24.03 निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए आयकर विभाग से एक संसूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कुल 41.42 करोड़ रुपए के आयकर की मांग रखी गई थी। आय-कर अपील अधिकरण ने यह मामला निर्धारण अधिकारी को निर्दिष्ट कर दिया है। प्रबंध मंडल का मत यह है कि आईटीएटी के आदेशों को ध्यान में रखते हुए निर्धारण अधिकारी द्वारा नए न्यायनिर्णयन के पूरा होने पर कोई मांग नहीं उठाई जाएगी।

24.04 संगोष्ठियों संबंधी क्रियाकलापों के मद्दे प्रत्यक्ष रूप से होने वाले व्ययों को संगोष्ठी संबंधी व्ययों के अधीन प्रभारित किया गया है और इससे संबंधित अप्रत्यक्ष व्ययों को व्यय के कार्यकरण शीर्षों के अधीन प्रभारित किया गया है।

**24. वित्तीय विवरणों से संबंधित अतिरिक्त जानकारी**

24.05 छात्रों से, छात्र संघ फीस के मद्दे प्राप्त फीस में से, 1 अप्रैल, 2009 के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक छात्र के लिए 250 रुपए प्रति छात्र की एक राशि को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स छात्र कल्याण निधि में जमा किया जा रहा है।

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान  
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण

24.06 पट्टाधृत भूमि के मूल्य में 6.17 लाख रुपए सम्मिलित हैं, जो भूमि और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा इंद्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली में विद्यमान (प्रधान कार्यालय के प्लॉट के साथ लगी) आबंटित भूमि से संबंधित हैं, जिसके लिए करार और पट्टाभिलेख के ज्ञापन के निष्पादन संबंधी कार्यवाही की जा रही है।

24.07 संस्थान ने, सभी स्तरों पर संस्थान की संपूर्ण गतिविधियों, जिनके अंतर्गत सदस्य, छात्र और अन्य वृत्तिक गतिविधियां भी हैं, के अंकीकरण के उद्देश्य से एक प्रक्रिया संबंधी पहल की है, जिसे "परिवर्तन परियोजना" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। इस प्रयोजन के

लिए, संस्थान ने एक वैश्विक रूप से ख्यातिप्राप्त परियोजना प्रबंध परामर्शी के द्वारा पर्यवेक्षित एक वैश्विक एकीकृत सेवा प्रदाता (विक्रेता) को नियुक्त किया था, जिसकी कुल लागत 3,981 लाख रुपए है। 31 मार्च, 2015 तक 867 लाख रुपए की राशि उपगत की गई है।

चूंकि एकीकृत सेवा प्रदाता ने, उसे विस्तारित समय सीमाएं प्रदान करने के पश्चात् भी अपेक्षा के अनुसार विकास कार्य नहीं किया था, जिसके परिणामस्वरूप संस्थान ने इस संबंध में विवाद उठाते हुए संविदा को रद्द कर दिया था और जून, 2015 में 295 लाख रुपए की बैंक प्रत्याभूति का नकदीकरण किया था और शेष 572 लाख रुपए के लिए 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष में अपलिखित किया गया था।

विक्रेता ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसमें संस्थान द्वारा वापस ली गई बैंक प्रत्याभूतियों की रकम के अतिरिक्त संस्थान से 807 लाख रुपए का संदाय करने की अपेक्षा की गई थी। संस्थान द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया है और साथ ही सेवा प्रदाता के साथ मास्टर कारबार करारों को संस्थान द्वारा उसके तारीख 8 फरवरी, 2017 के पत्र द्वारा समाप्त कर दिया गया है और तब से इस संबंध में विक्रेता से कोई और संसूचना प्राप्त नहीं हुई है।

24.08 आईसीएआई भवन, फरीदाबाद से 225 वर्ग मीटर के मापमान वाली भूमि को जनवरी, 2013 में डीएमआरसी द्वारा अधिगृहीत किया गया था, जिसके लिए फरीदाबाद शाखा ने डीएमआरसी द्वारा किए गए अधिग्रहण के विरुद्ध प्रतिकर के रूप में शाखा के आसपास और अधिक भूमि के लिए अनुरोध किया था। इस मामले पर वर्तमान में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) द्वारा विचार किया जा रहा है।

24.09 अन्य व्यय में 262 लाख रुपए (278 लाख) भी सम्मिलित हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 28-क के अधीन गठित क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड द्वारा उपगत लागतों की प्रतिपूर्ति है। अन्य व्ययों में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अधीन गठित अपील प्राधिकरण को दिया गया 67.50 लाख (25 लाख) रुपए का अभिदाय भी सम्मिलित है। क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड और अपील प्राधिकरण के व्ययों का वहन संस्थान द्वारा किया जाना है। अन्य व्ययों के अंतर्गत एक्सेटेंसीबल बिजनेस रिपोर्टिंग लेंगेज (एक्सबीआरएल) को दिया गया 10 लाख (शून्य) रुपए का अनुदान भी है।

24.10 पूर्व वर्षों में सृजित विभिन्न आरक्षित निधियों और उद्दिष्ट निधियों का और उद्दिष्ट निवेशों का व्यौरेवार पुनर्विलोकन आरंभ किया गया है ताकि संस्थान की वर्तमान अपेक्षाओं और कार्यकरण के अनुसार इन निधियों को पुनः संरचित किया जा सके।

## **24. वित्तीय विवरणों से संबंधित अतिरिक्त जानकारी**

24.11 वर्ष के दौरान, संस्थान ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी, आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी है, की शेयर पूंजी के मद्दे 10 लाख रुपए का अभिदाय किया है। निवेश को एक दीर्घकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उसे लागत पर मूल्यांकित किया गया है।

### **भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण**

24.12 वर्ष के अंत पर शाखा संव्यवहारों/अतिशेषों को सुमेलित किया जा रहा है, लेखाओं में 26.81 लाख रुपए के शुद्ध अंतर के लिए प्रावधान किया गया है, यद्यपि, प्रबंध मंडल की यह राय है कि यह लंबित सुमेलन का वित्तीय विवरणों पर कोई सारवान प्रभाव नहीं पड़ेगा।

24.13 यद्यपि, संस्थान की आय को आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग)(iv) के अधीन पूर्णतया छूट प्राप्त है, फिर भी कुछ अस्तित्वों ने संस्थान को किए जाने वाले संदायों पर स्रोत पर कर की कटौती की है। कुल 2,256 लाख रुपए का स्रोत पर कटौती किए गए कर का प्रतिदाय, लंबित सुधार/ अपील में अंतिम निर्णय पर प्राप्त होने की संभावना है।

24.14 संस्थान ने यह मत लिया है कि उसे जीएसटी अधिनियम लागू है। संदत्त जीएसटी, संदेय जीएसटी और जीएसटी इनपुटों का सुमेलन किया जा रहा है। 2059 लाख रुपए की रकम में अपात्र इनपुट कर प्रत्यय और छूट प्राप्त पूर्तियों के कारण प्रत्यय सम्मिलित है और देर से किए गए संदायों पर ब्याज की 140 लाख रुपए की रकम को आय और व्यय लेखा से प्रभारित किया गया है। वर्ष के अंत पर संदेय 1389 लाख रुपए के जीएसटी को अन्य दायित्वों (टिप्पण सं. 8) के अधीन सम्मिलित किया गया है। 966 लाख रुपए की रकम को, जो जीएसटी इनपुट के रूप में वसूलनीय है, 'अग्रिम (टिप्पण सं. 14)' के अधीन सम्मिलित किया गया है। प्रबंध मंडल की यह राय है कि सुमेलन पूरा हो जाने पर कोई सारवान समायोजन किए जाने की संभावना नहीं है।

24.15 प्रबंध मंडल की राय में अध्ययन सर्कल, अध्ययन चैप्टर और विदेशी चैप्टर पृथक् अस्तित्व हैं और उनके लेखाओं को समेकित नहीं किया गया है।

24.16 वर्ष के दौरान, अधिकांश शाखाओं में नियत आस्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है और भौतिक अतिशेष को वही अतिशेष से सुमेलित किए जाने का कार्य किया जा रहा है। प्रबंध मंडल की यह राय है कि इससे वित्तीय विवरणों पर कोई सारवान प्रभाव नहीं पड़ेगा।

24.17 शाखा कर्मचारी स्कीम, 2006 को पुनरीक्षित करके उसे नई शाखा कर्मचारी स्कीम, 2014 से प्रतिस्थापित किया गया है, जिसका अनुमोदन केंद्रीय परिषद् द्वारा कर दिया गया है किंतु इसे अभी कार्यान्वित नहीं किया गया है। वर्ष 2014-15 से, 7 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का एक प्रावधान लेखाओं में किया जा रहा है, जिसका योग 31 मार्च, 2018 को 28 करोड़ रुपए हो गया है। प्रावधान में कमी/आधिक्य का अवधारण उस समय किया जाएगा, जब पुनरीक्षित स्कीम को पूर्णतया कार्यान्वित किया जाएगा।

24.18 क्रमशः 1.1.2016 और 1.7.2017 से प्रभावी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप, वर्ष के दौरान 44 करोड़ रुपए का एक प्रावधान किया गया है, जिसे कर्मचारी कल्याण व्ययों में सम्मिलित किया गया है।

### लेखांकन मानकों के अधीन प्रकटन

#### 25. कर्मचारी फायदे

**परिभाषित अभिदाय योजनाएं:** संस्थान ने भविष्य निधि में अभिदाय के मद्दे 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 597.36 लाख रुपए (पूर्व वर्ष में 594.30 लाख रुपए) की राशि को मान्यता प्रदान की है।

**परिभाषित फायदा योजनाएं:** संस्थान ने अपने कर्मचारियों को निम्नलिखित परिभाषित फायदा योजनाएं प्रदान की हैं —

उपदान :	वित्तपोषित
सेवानिवृत्ति पश्च पेंशन :	गैर-वित्तपोषित
क्षतिपूरित अनुपस्थिति :	गैर-वित्तपोषित

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान  
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण

#### 25.01 उपदान योजना से संबंधित व्यौरे निम्नानुसार हैं :

(लाख रुपए में)					
	वर्ष	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
<b>1.</b>	<b>बाध्यता के आरंभिक और अंतिम अतिशेषों का समाधान</b>				
	क. वर्ष के आरंभ में बाध्यता	2,510	2,358	2,213	2,057
	ख. चालू सेवा लागत	187	202	184	167
	ग. सेवा पश्च लागत	915			
	घ. व्याज लागत	176	166	169	154
	ङ. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	(204)	44	(53)	32
	च. संदत्त फायदे	(286)	(260)	(155)	(197)
	छ. वर्ष के अंत में बाध्यता	3,298	2,510	2,358	2,213
<b>2.</b>	<b>योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन</b>				
	क. वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	2,325	2,292	2,232	2,103
	ख. योजना आस्तियों पर प्रत्याशित आय	165	183	191	184
	ग. बीमांकिक अभिलाभ/ (हानि)	6	2	6	3
	घ. संस्थान द्वारा किया गया अभिदाय	84	132	78	239
	ङ. संदत्त फायदे	(303)	(284)	(215)	(297)
	च. वर्ष के अंत पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	2,277	2,325	2,292	2,232
<b>3.</b>	<b>योजना, आस्तियों और बाध्यताओं के उचित मूल्य का समाधान</b>				
	क. बाध्यताओं का विद्यमान मूल्य	3,298	2,510	2,358	2,213
	ख. योजना आस्तियों का उचित मूल्य	2,277	2,325	2,292	2,232
	ग. तुलन पत्र आस्ति/(दायित्व) में मान्यता प्रदान की गई रकम	(1,021)	(185)	(66)	19
<b>4.</b>	<b>वर्ष के दौरान माने गए व्यय</b>				
	क. चालू सेवा लागत	187	202	184	167

5.	ख. ब्याज लागत	176	166	169	154
	ग. योजना आस्तियों पर प्रत्याशित आय	(165)	(183)	(191)	(184)
	घ. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	(210)	42	(59)	29
	ङ. वर्ष के दौरान माने गए व्यय	(12)	227	103	166
	<b>निवेशों के ब्यौरे</b>	<b>निवेश का प्रतिशत</b>	निवेश का प्रतिशत	निवेश का प्रतिशत	निवेश का प्रतिशत
	क. अन्य – भारतीय जीवन बीमा निगम के पास निधियां	100.00	100.00	100.00	100.00

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान  
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण

(लाख रुपए में)

6.	पूर्वानुमान				
	क. बट्टा दर (प्रतिवर्ष)	7.65%	7.45%	7.92%	7.85%
	ख. योजना आस्तियों से आय की प्राक्कलित दर (प्रतिवर्ष)	7.45%	7.45%	8.85%	8.85%
	ग. वेतन में वृद्धि की दर	मूल 3% : डीए 6%	मूल 3% : डीए 6%	मूल 3% : डीए 6%	मूल 3% : डीए 6%
	घ. संनिघर्षण दर	2%	5%	5%	5%
	ङ. नश्वरता सूची	आईएएल 2006-08	आईएएल 2006-08	आईएएल 2006-08	आईएएल 2006-08
		अंततोगत्वा	अंततोगत्वा	अंततोगत्वा	अंततोगत्वा

## 25.02 सेवानिवृत्ति पश्च पेंशन योजनाओं के ब्यौरे

	वर्णन	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
1.	<b>बाध्यता के प्रारंभिक और अंतिम बतिशेषों में समाधान</b>				
	क. वर्ष के प्रारंभ में बाध्यता	11,115	5,086	2,684	1,406
	ख. ब्याज लागत	813	357	211	110
	ग. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	378	6,063	2,210	1,169
	घ. संदत्त फायदे	(416)	(391)	(19)	(1)
	ङ. वर्ष के अंत में बाध्यताएं	11,890	11,115	5,086	2,684
2.	<b>योजना आस्तियों और बाध्यताओं के उचित मूल्य में समाधान</b>				
	क. बाध्यता का वर्तमान मूल्य	11,890	11,115	5,086	2,684
	ख. तुलन-पत्र आस्ति/(दायित्व) में मानी गई रकमें	(11,890)	(11,115)	(5,086)	(2,684)
3.	<b>वर्ष के दौरान माने गए व्यय</b>				
	क. ब्याज लागत	813	357	211	110
	ख. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	378	6,063	2,210	1,169
	ग. वर्ष के दौरान माने गए व्यय	1,191	6,420	2,421	1,279
4.	<b>पूर्वानुमान</b>				
	क. बट्टा दर (प्रतिवर्ष)	7.50%	7.30%	7.90%	7.90%
	ख. वेतन में वृद्धि की दर	मूल 3% : डीए 6%	मूल 3% : डीए 6%	मूल 3% : डीए 6%	मूल 3% : डीए 6%
	ग. संनिघर्षण दर	2%	5.00%	5%	5%
	घ. नश्वरता सूची	आईएएल 1996-98	आईएएल 1996-98	आईएएल 1996-98	आईएएल 1996-98
		अंततोगत्वा	अंततोगत्वा	अंततोगत्वा	अंततोगत्वा

**25.03. कर्मचारी फायदे - छुट्टी नकदीकरण के ब्यौरे :**

वर्ष	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
<b>1. बाध्यता के प्रारंभिक और अंतिम बतियशेषों में समाधान</b>				
क. वर्ष के प्रारंभ में बाध्यता	<b>3,873</b>	3,217	2,857	2,359
ख. चालू सेवा लागत	<b>182</b>	305	280	338
ग. ब्याज लागत	<b>274</b>	227	216	175
घ. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	<b>188</b>	127	115	259
ङ संदत्त फायदे	<b>(380)</b>	(348)	(251)	(274)
च. वर्ष के अंत में बाध्यताएं	<b>4,137</b>	3,528	3,217	2,857

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान  
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण

(लाख रुपए में)

<b>2. योजना आस्तियों और बाध्यताओं के उचित मूल्य में समाधान</b>				
क. बाध्यता का वर्तमान मूल्य	<b>4,137</b>	3,528	3,217	2,857
#ख. तुलन-पत्र आस्ति/(दायित्व) में मानी गई रकमे	<b>(4,137)</b>	(3,528)	(3,217)	(2,857)
<b>3. वर्ष के दौरान माने गए व्यय</b>				
क. चालू सेवा लागत	<b>182</b>	305	280	338
ख. ब्याज लागत	<b>274</b>	227	216	175
ग. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	<b>188</b>	127	115	259
घ. वर्ष के दौरान माने गए व्यय	<b>644</b>	659	611	772
<b>4. पूर्वानुमान</b>				
क. बढ़ा दर (प्रतिवर्ष)	<b>7.65%</b>	7.45%	7.92%	7.85%
ख. वेतन में वृद्धि की दर	<b>मूल 3% : डीए</b>	मूल 3% : डीए	मूल 3% : डीए	मूल 3% : डीए
	<b>6%</b>	6%	6%	6%
ग. संनिघर्षण दर	<b>2%</b>	5.00%	5%	5%
घ. नश्वरता सूची	<b>आईएएल 2006-08</b>	आईएएल 2006-08	आईएएल 2006-08	आईएएल 2006-08
	<b>अंततोगत्वा</b>	अंततोगत्वा	अंततोगत्वा	अंततोगत्वा

**26. खंड रिपोर्टिंग**

संस्थान के प्रचालन "चार्टर्ड अकाउंटेंसी की वृत्ति को अग्रसर करना" तक सीमित हैं और यह मुख्यतः भारत में प्रचालन करता है। अतः, इसके सभी प्रचालन, लेखांकन मानक (एएस-17) खंड रिपोर्टिंग के अर्थातगत एकल खंड के अंतर्गत आते हैं।

**27. पूर्व वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं उन्हें चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटन के तत्समान बनाने के लिए, जहां कहीं आवश्यक है, पुनः समूहित/पुनः वर्गीकृत किया गया है।**

ह./-  
सी.ए. सुदीप श्रीवास्तव  
संयुक्त सचिव

ह./-  
बी. सागर  
सचिव

ह./-  
सी.ए. प्रफुल पी. छाजेड  
उपाध्यक्ष

ह./-  
सी.ए. नवीन एन. डी. गुप्ता  
अध्यक्ष

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते हिंशोरानी एम. एंड कंपनी  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
फर्म रजि. सं. 006772एन  
ह/  
सी.ए. जगदीश प्रसाद धर्मीजा  
भागीदार  
सदस्यता सं. 015020

खन्ना एंड आन्नदनम  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
फर्म रजि. सं. 001297एन  
ह/  
सी.ए. बी.जे. सिंह  
भागीदार  
सदस्यता सं. 007884

स्थान : नई दिल्ली, 26 सितंबर, 2018

[विज्ञापन-III/4/असा./239/18]

बी. सागर, सचिव



**THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**  
**(set up by an Act of Parliament)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th September, 2018

**No. 1-CA(5)/69/2018.**—In pursuance of sub-Section (5B) of Section 18 of the Chartered Accountants Act, 1949, a copy of the audited accounts and the Report of Council of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) for the year ended 31<sup>st</sup> March 2018 is hereby published for general information.

**69<sup>th</sup> Annual Report**

The Council of ICAI takes immense pleasure in presenting its 69<sup>th</sup> Annual Report for the year ended 31<sup>st</sup> March 2018. Since the inception of the Institute on 1<sup>st</sup> July 1949 by an Act of Parliament, the accountancy profession has grown tremendously. Founded with about 1,700 members, the Institute has today more than 2,82,193 members and 7,25,632 students as on 1<sup>st</sup> July 2018. The Report highlights the important activities of the Council and its various Committees during the year 2017-2018, besides the accounts of the Institute for the year ended on 31<sup>st</sup> March 2018. The Council also takes this opportunity to submit in this Report major initiatives, important events, statistical data relating to members, students, details of seminars, conference, workshop, training programmes organised during the period upto early July 2018. The Council commends its members and students for the respect which the chartered accountancy profession commands today in the Society. This has been achieved through excellence, independence and integrity displayed by the members and students all along.

**1. THE COUNCIL**

The twenty-third Council was constituted on 12<sup>th</sup> February 2016 for a period of three years. It comprises 32 elected members and 8 members nominated by the Central Government. Its composition is shown separately.

**2. COMMITTEES OF THE COUNCIL**

The Council, in terms of Section 17 of the Chartered Accountants Act, 1949, constituted, on 12<sup>th</sup> February 2018, Standing and Non-Standing Committees/Boards to deal with the matters concerning the profession of Chartered Accountants. During the year ended 31<sup>st</sup> March 2018, 225 meetings were held of various Standing and Non-Standing Committees and Boards of the Council.

**3. AUDITORS**

M/s. Hingorani M.&Co. and M/s. Khanna & Annadhanam were the joint auditors of ICAI for the financial year 2017-18.

**4. STANDING COMMITTEE**

**4.1 Executive Committee**

Executive Committee is one of the Standing Committees of the Council of ICAI. The functions of this Committee have been prescribed in the Regulation 175 of Chartered Accountants Regulations, 1988. Some of these functions are relating to articulated and audit assistants and enrolment, removal, restoration of members from the Register, cancellation of certificate of practice, permission to engage in any other business or occupation other than profession of accountancy. Executive Committee is also the custodian of the property, assets and funds of the Institute beside maintenance of the Institute's offices.

**4.2 Finance Committee**

Finance Committee introduced vide the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006, controls, implements and supervises the activities related with and incidental, inter alia, to maintenance of true and correct accounts, formulation of annual budget, investment of the funds, and disbursements from the funds for expenditure – both revenue and capital.

### 4.3 Examination Committee

Examination Committee performs all functions of the Council relating to examinations. The Committee conducted the Chartered Accountants Intermediate (IPC) and Final Examinations smoothly all over the country and abroad in 450 centres from 2<sup>nd</sup> May to 17<sup>th</sup> May 2017. Total numbers of candidates, who appeared in the said Intermediate (IPC) and Final Examinations and passed, were:

	<b>Appeared and Passed Both Groups/ Either of the Groups</b>		<b>Appeared and Passed Group I only</b>		<b>Appeared and Passed Group II only</b>	
	<b>Appeared</b>	<b>Passed</b>	<b>Appeared</b>	<b>Passed</b>	<b>Appeared</b>	<b>Passed</b>
Intermediate (IPC)	49967	11550	66680	6562	65453	11440
Final	34503	7928	41373	5717	38478	6234

Then, the next batch of Chartered Accountants Intermediate (IPC) and Final Examinations were smoothly conducted all over the country and abroad at 425 centres from 1<sup>st</sup> to 16<sup>th</sup> November 2017. Total numbers of candidates, who appeared in the said Intermediate (IPC) and Final Examinations and passed, were:

	<b>Appeared and Passed Both Groups/ Either of the Groups</b>		<b>Appeared and Passed Group I only</b>		<b>Appeared and Passed Group II only</b>	
	<b>Appeared</b>	<b>Passed</b>	<b>Appeared</b>	<b>Passed</b>	<b>Appeared</b>	<b>Passed</b>
Intermediate (IPC)	49215	13149	72148	10042	65393	13330
Final	30054	6841	39328	6257	39753	6006

Apart from the above, the Common Proficiency Test [CPT] was held successfully on June 18<sup>th</sup>, 2017 and on December 17<sup>th</sup> 2017 across the country and abroad at 372 and 327 examination centres respectively. The total numbers of candidates who appeared and passed in the CPT are as under:

	<b>Appeared</b>	<b>Passed</b>
CPT held on June 18 <sup>th</sup> , 2017	88916	36028
CPT held on December 17 <sup>th</sup> , 2017	60586	23034

During the year, Post-Qualification Course in Information Systems Audit – Assessment Test (ISA –AT) was held successfully on 24<sup>th</sup> June 2017 all over the country at 64 examination centres. Another ISA-AT was held successfully on 23<sup>rd</sup> December 2017 all over the country at 65 examination centres.

Total numbers of candidates, who appeared in these examinations and passed, were:

	<b>Appeared</b>	<b>Passed</b>
ISA – AT held on June 24 <sup>th</sup> , 2017	3533	766
ISA – AT held on December 23 <sup>rd</sup> , 2017	2641	370

Insurance and Risk Management Technical Examination was held successfully in November 2017 all over the country. Total numbers of candidates, who appeared in these examinations and passed, were:

	<b>Appeared</b>	<b>Passed</b>
IRM – Technical Examination	54	33

International Taxation-Assessment Test (INTT-AT) for members was held successfully in May and November 2017. Total numbers of candidates, who appeared and passed in this examination, were:

	<b>Appeared</b>	<b>Passed</b>
INTT – AT held in May, 2017	193	80
INTT – AT held in November, 2017	131	20

Examinations of Post-Qualification Courses in Management Accountancy Course (MAC) (Part-1), Corporate Management Course (CMC) (Part-1), Tax Management Course (TMC) (Part-1), and International Trade Laws and World Trade Organization (ITL & WTO) (Part-1), were also conducted in November 2017.

The Institute has been continuously improving its examination processes right from the setting up of question papers to the declaration of results, so that the integrity and sanctity of its examination system, which is well-known for around seven decades, are maintained and further strengthened.

The Institute's examinations test the conceptual understanding as well as practical application of each of the topics covered in the CA curriculum so that the students could meet the expectations of the stakeholders of the profession.

By focusing on the analytical abilities of students and by avoiding the predictability of questions, the Institute's examinations continue to ensure that the qualifying candidates are well-groomed professionals.

**Special Examination:** Arising out of the MRAs (mutual recognition agreements)/ MoUs (memoranda of understanding) entered with the following foreign professional accounting bodies, the Special Examination for their members, who want to have the membership of ICAI were successfully conducted from 19<sup>th</sup> to 23<sup>rd</sup> June 2017 in New Delhi.

1. The Institute of Chartered Accountants of England & Wales (ICAEW)
2. The Institute of Chartered Accountants of Australia (ICA Australia)
3. The Institute of Certified Public Accountants in Australia (CPA Australia)
4. The Institute of Certified Public Accountants in Ireland (CPA Ireland)
5. Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA)

Beside this, the ICAI has also entered into an MoU with the New Zealand Institute of Chartered Accountants (NZICA). These Special Examinations are open to the members of the above-mentioned international accounting bodies.

**Web-Interface on Students Exam Life Cycle Management:** ICAI embarked on an integrated web-interface called Student Exam Life Cycle Management Project, where CA students using a single user ID and password, can access various examination-related services, including application for duplicate marksheets/ pass certificates/ transcripts, change of centre/ medium/ group, downloading admit cards, checking results, and applying for verification/seeking certified copies of answer books post result, etc., from examination to examination.

**New Examination Centres:** With a view to facilitate students to appear in the examination centres as nearer to their place of residence/ articulated training as possible, new examination centres were opened in Haridwar and Nizamabad for *CA Intermediate and Final examinations with effect from May 2017 examinations.*

With effect from June 2017 examinations, CA CPT centres were opened in Badlapur, Banswara, Bhiwandi, Burhanpur, Chandrapur, Chhindwara, Gondia, Haldwani, Haridwar, Ichalkaranji, Jalna, Junagadh, Mandsaur, Muzaffarpur, Nizamabad, Palghar, Parbhani, Ratnagiri, Rewa and Yavatmal.

#### 4.4 Disciplinary Committee

ICAI not only performs its statutory duties as a regulator of the profession of Chartered Accountancy in India by formulating Accounting Standards in keeping pace with changing economic-scenario but also enforces the ethical values as enshrined in Code of Ethics by proactively taking action against its erring members for any professional and/or other misconduct through its well-defined disciplinary mechanism as provided under the Chartered Accountants Act, 1949 and the Rules framed thereunder.

Under the disciplinary mechanism, a mandatory duty has been cast upon the Disciplinary Directorate of ICAI to look into any alleged lapses/irregularities committed by a small cross-section of its members across the country so as to lay down a strong foundation of credibility to the future members joining the

profession. While, most of the members of the profession are providing selfless dedicated services through their professional expertise and experience to the Society and world at large, yet through its robust Disciplinary mechanism there is a constant need to caution and to correct the negligible few who inadvertently fallen on the wrong side of the law.

During the year under review, the Ministry of Corporate Affairs, Govt. of India, vide Office Memorandum no. 1/7/2017-PI dated 10<sup>th</sup> April 2017 had constituted a high-level committee to examine the existing provisions in the Act, Rules and Regulations pertaining to disciplinary mechanism of dealing with the cases of misconduct in the three professional Institutes, viz. The Institute of Chartered Accountants of India, The Institute of Company Secretaries of India and The Institute of Cost Accountants of India, and to give its specific recommendations on the amendments, if any, and new provisions required to be incorporated in the Act, corresponding Rules and Regulations, for strengthening the existing mechanism and ensure speedy disposal of the disciplinary cases.

In terms of recommendations of the said High-Power Committee constituted by the MCA, several significant amendments in the Chartered Accountants Act and the Rules framed thereunder are under consideration so as to fast track the whole disciplinary process and conclude cases within definitive time frame.

During the year under review, the Council of ICAI had constituted a Group to examine the intricacies involved in the areas wherein changes need to be made pertinent to the Disciplinary mechanism as provided under the Chartered Accountants Act, 1949 and the Rules framed thereunder and thereafter suggesting further amendments to the Chartered Accountants Act, 1949 and the Rules framed thereunder. Report of the Group was placed before the Council at its 365<sup>th</sup> meeting held on 17<sup>th</sup> May 2017.

The ICAI has been coming out with quick and transparent action in matters involving the profession and taken new initiatives in consonance with its image as a partner in National Building. The ICAI constituted a High Power Group on Punjab National Bank matter to study the systemic issues in the Punjab National Bank matter and suggest remedial measures and improvement in the banking system and any other matter. Various remedial measures have been suggested by the Group including strengthening the system at various levels.

A brief write-up of the activities of Board of Discipline (under Section 21A)/Disciplinary Committees (under Section 21B) and Disciplinary Committee (under Section 21D) has been provided below.

#### **Board of Discipline under Section 21A of the Chartered Accountants Act, 1949 as amended by the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006.**

The Board of Discipline has been constituted by the Council of ICAI under Section 21A of the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006 so as to look into matters of professional and other misconduct by members which fall within the purview of First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 as amended by Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006 and/or cases wherein the members are held prima facie NOT guilty of any misconduct by Director (Discipline).

In the current year, in February 2018, an additional Bench of the Board of Discipline (under Section 21A) has been constituted with a view to sustain the process of expeditious disposal of cases at both PFO stage and at stage of enquiry. In this regard, Bench-I of the Board of Discipline, headed by the Vice-President, ICAI, is presently looking into the cases pertaining to Southern and Central Regions and Bench-II, headed by CA. G. Sekar, Central Council Member, is looking into the cases relating to Western/Eastern/Northern Regions.

During the year under review, the Board of Discipline held **19 meetings** at various places across the country. In these meetings, the Board concluded its enquiry in **58 cases**, including cases which had been referred to it in previous years. The statistical break-up of the cases decided by the Board of Discipline is given below:

**Board of Discipline (under Section 21A)–Period from 1<sup>st</sup> April, 2017 to 31<sup>st</sup> March, 2018**

Sl. No.	Particulars	No. of cases
a)	No. of meetings of the Board of Discipline held during the aforesaid period	19
b)	Number of Complaint/Information cases considered by the Board of Discipline (under Section 21A) wherein prima facie opinion of the Director (Discipline) was formed.*	629
c)	Number of cases (Complaint/Information cases) in which enquiry was completed by the Board of Discipline (including those cases, which were referred to the Board of Discipline during the earlier years).	58
e)	Number of cases (Complaint/Information) in which punishment has been awarded by the Board of Discipline (including those cases, which were referred to the Board of Discipline during the earlier years).	08

*\*including cases dealt with under Rule 6/12 of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of cases) Rule, 2007.*

**Disciplinary Committee (under Section 21B) of the Chartered Accountants Act, 1949 as amended by the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006.**

Disciplinary Committee has been constituted by the Council of ICAI under Section 21B of the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006 so as to look into matters of professional misconduct by members which fall within the purview of Second Schedule and both First and Second Schedules to the Chartered Accountants Act, 1949 as amended by Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006.

During the year 2017-18, two Benches of the Disciplinary Committee (under Section 21B) had been constituted i.e Bench I and II. However, considering the need to expedite and take cases of Govt./Regulators/matters of Public Interest on a fast track mode, in February, 2018, another Bench in addition to the two existing Benches of Disciplinary Committee was constituted, i.e. Bench III looking exclusively into cases of Government/ regulators/ public interest, etc.

During the year under review, the Committee held **23 meetings (Bench I: 9 meetings, Bench II: 13 Meetings and Bench III (constituted in February 2018): one meeting** at the venues in different parts across the country. During the course of the aforesaid meetings, the Committee concluded its enquiry in **35 cases**, which included cases, referred to it in previous years. The statistical break-up of the cases decided by the Disciplinary Committee is given below:

**Disciplinary Committee (under Section 21B)–Period from 1<sup>st</sup> April 2017 - 31<sup>st</sup> March 2018**

Sl. No.	Particulars	No. of cases
a)	No. of meetings of the Disciplinary Committee held during the aforesaid period	23
b)	Number of Complaint/Information cases considered by the Disciplinary Committee (under Section 21B) wherein prima facie opinion of the Director (Discipline) was formed.	217
c)	Out of the above, number of Complaint/Information cases referred by the Disciplinary Committee for enquiry	210
d)	Number of cases (Complaint/Information cases) in which enquiry was completed by the Disciplinary Committee (including those cases, which were referred to the Disciplinary Committee during the earlier years).	35
e)	Number of cases (Complaint/Information) in which punishment has been awarded by the Disciplinary Committee (including those cases, which were referred to the Disciplinary Committee during the earlier years).	30

**Disciplinary Committee under Section (21D)**

The Disciplinary Committee functioning under the provisions of Section 21D of the Chartered Accountants Act, 1949 as amended by the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006 conducts enquiry and submits its report to the Council in respect of residual cases pending prior to the amendments made in the aforesaid Act in 2006. In discharging its avowed responsibility of conducting disciplinary enquiries against members whose cases have been referred to it by the Council upon prima facie opinion, during the year under review, this Committee held 8 (eight) meetings.

**Cases dealt with under the Old Disciplinary Mechanism [Section 21(D)]**

Statistics of cases placed before the Council and the Disciplinary Committee during the period from 1<sup>st</sup> April 2017 to 31<sup>st</sup> March 2018:

Sl. No.	Particulars	No. of cases
1.	(i) Number of cases concluded by the Disciplinary Committee during the above period (out of 04 total pending cases with the Committee for enquiry) (ii) Meetings of the Disciplinary Committee under Section 21D held during the aforesaid period	04 08
2.	Number of reports of Disciplinary Committee considered by the Council (including reports of those cases, which were heard during the earlier years).	21
3.	Out of the above	
	a) Number of cases in which Respondents have been found guilty under the First Schedule for affording an opportunity of hearing before the Council before passing an order under Section 21(4) of the Chartered Accountants Act, 1949.	Nil
	b) Number of cases in which Respondents have been found guilty under the Second Schedule and/or other misconduct to be referred to High Courts under Section 21(5) of the Chartered Accountants Act, 1949.	20
	c) Number of cases in which Respondents have been found guilty under the First Schedule and the Second Schedule/other misconduct	01
	d) Number of cases referred back to the Disciplinary Committee for further enquiry.	Nil
	e) Number of cases in which Respondents have been found not guilty of any misconduct.	10
4.	Number of cases in which Orders passed under Section 21(4) in respect of the Respondents who were found guilty under the First Schedule.	02
5.	Number of cases disposed of by the High Court under Section 21(6)	08

**5. TECHNICAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT****5.1 Accounting Standards Board (ASB)****Upgrading financial reporting standards:**

Upgraded Accounting Standards considered and approved by the National Advisory Committee on Accounting Standards (NACAS) - AS 16, *Property, Plant and Equipment*, AS 23, *Borrowing Costs* & AS 24, *Related Party Disclosures*.

**Issuance/revision of Indian Accounting Standards in line with IFRS/IAS**

- Companies (Indian Accounting Standards) Amendments Rules, 2018, notified by the MCA including Ind AS 115, *Revenue from Contracts with Customers*, corresponding to IFRS 15 issued by the IASB.
- Amendments to Ind AS 7, *Statements of Cash Flows*, corresponding to amendments to IAS 7 Statement of Cash Flows and Amendments in Ind AS 102, *Share Based Payments* have been notified as Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2017, vide notification dated 17<sup>th</sup> March, 2017.
- Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealised Losses-Amendments in Ind AS 12, *Income taxes*
- Annual Improvements to Ind AS - Amendments in Ind AS 112 and 28 (corresponding to Annual Improvements to IFRS Standards 2014-2016 cycle issued by the IASB)
- Transfers of Investment Property, Amendments to Ind AS 40, *Investment Property*
- Amendments to Ind AS 101, *First-time Adoption of Indian Accounting Standards*

Amendments in Ind AS considered and approved by the National Advisory Committee on Accounting Standards (NACAS) - Appendix C, *Uncertainty over Income Tax Treatments*, to Ind AS 12, *Income Taxes*, Amendments to Ind AS 20, *Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance*, and Ind AS 116, *Leases*.

Exposure Drafts of upgraded Accounting Standards/Indian Accounting Standards issued during the year - Exposure Draft of upgraded Accounting Standard (AS) 109, Financial Instruments; Exposure Draft of Ind AS 117, *Insurance Contracts*; and Exposure Draft of Appendix B of Ind AS 21, *Foreign Currency Transactions and Advance Consideration*.

### Publications

The Board released many publications, guidance notes, FAQs and issued announcements during this year such as Compendium of Accounting Standards - as on 1st July, 2017, Indian Accounting Standards (Ind AS): An Overview (Revised) (jointly with Ind AS Implementation Group), Brochure on 40<sup>th</sup> Anniversary of ASB: Leading the way in Accounting Reforms, FAQs on Treatment of Securities Premium Account under Ind AS on the Date of Transition. (Last updated on 2<sup>nd</sup> June 2017), *Ind AS Successful Implementation: Impact Analysis and Industry Experience* and *Ind AS Disclosure Checklist*.

**International Initiatives: Forging Long-Lasting Partnership** - ICAI representatives participated at various forums, such as:

- Chairman, Accounting Standards Board, CA. Shiwaji Bhikaji Zaware, was elected Vice-chair, Asian-Oceanian Standard-Setters Group (AOSSG) for a term of two years. He took over the charge as Vice-chair at 9<sup>th</sup> Annual meeting of AOSSG held in Hangzhou (China) on 29<sup>th</sup>-30<sup>th</sup> November 2017. As per the current practice, Vice-chair takes over as Chair, AOSSG, after completing its due term.
- Chairman, Accounting Standards Board, attended a Chair Advisory Committee (CAC) meeting with IFRS Foundation trustees held on 31<sup>st</sup> January 2018 in Hong Kong. Apart from that, ICAI also participated in various Chair and Vice Chair (CVC) and CAC meetings of AOSSG through teleconferencing.
- As a result of continuous efforts of President ICAI and Chairman, ASB, a tripartite meeting of International Financial Reporting Standards Foundation (IFRSF) Trustees, MCA representative and ICAI representatives was held in London, on 5<sup>th</sup>-7<sup>th</sup> June 2018, in relation to the *copyright and licensing* issues of IFRS copyrighted materials used/ to be used by India. As a positive outcome of the meeting, it is proposed to enter a Memorandum of Understanding between IFRSF and ICAI within three months.
- 14<sup>th</sup> meeting of Emerging Economies Group (EEG) was held in Sao Paulo (Brazil) on 4<sup>th</sup>-6<sup>th</sup> December 2017. ICAI representatives participated in the meeting.
- ICAI representatives also participated at the meetings and conferences of AOSSG, World Standards-Setters (WSS) and International Federation of Accounting Standard-setters (IFASS) held in London on 24<sup>th</sup>-27<sup>th</sup> September 2017 under the aegis of IASB.
- 15<sup>th</sup> EEG meeting, held on 14<sup>th</sup>-16<sup>th</sup> May 2018 in Kuala Lumpur (Malaysia), was attended by the ASB representatives of the Institute. ICAI representatives presented on the implementation issues and highlighted the issues relating to lease standard and accounting for digital currencies. Later, IFRS Foundation Regional Workshop on IFRS 17, *Insurance Contracts* was also attended on 17<sup>th</sup> May 2018.

Comments on the following Exposure Drafts/Discussion Papers issued by the International Accounting Standards Board (IASB) were submitted to the IASB.

- Comments on 'Definition of 'Material'- Proposed amendments to IAS 1 and IAS 8
- Comments on 'Accounting Policies and Accounting Estimates- Proposed amendments to IAS 8'
- Comments on IASB's Discussion Paper on 'Disclosure Initiative - Principles of Disclosure'
- Comments on IASB's Exposure Draft on *Property, Plant and Equipment* - Proceeds before Intended Use (Proposed amendments to IAS 16)
- Comments on IASB's Exposure Draft on Improvements to IFRS 8, *Operating Segments* (Proposed amendments to IFRS 8 and IAS 34)
- Comments on RFI issued by IASB on Post - Implementation Review - IFRS 13 *Fair Value Measurement*
- Comments on Exposure draft on Prepayment Features with Negative Compensation (Proposed amendments to IFRS 9)
- Comments on Exposure draft on Annual Improvements to IFRS Standards 2015–2017 Cycle

### Interaction with International Bodies

- ICAI hosted the 13<sup>th</sup> meeting of Emerging Economies Group (EEG) for the second time on 8<sup>th</sup>-9<sup>th</sup> May 2017 which was attended by the representatives of IASB and emerging economies, viz. Brazil, China, Indonesia, Malaysia, Russia, South Africa, Turkey and India. A paper was presented by the ASB on *Issue of Micro Entities - Financial Reporting Challenges*.
- ICAI-EEG Joint Stakeholders Seminar was organized on 9<sup>th</sup> May 2017 for half a day on the theme of *Emerging IFRS (Ind AS) Challenges dealing with Service Concession Arrangements and Expected Credit Loss Model* under the Ind AS 109. The seminar was well attended by about 80 members, EEG representatives and other stakeholders.
- ICAI hosted the International Forum of Accounting Standard Setters (IFASS) Meeting in India on 12<sup>th</sup>-13<sup>th</sup> April 2018 in Mumbai for the second time. Over 60 delegates from more than 25 jurisdictions, including prominent ones took part in the event. IFASS conference was inaugurated by Chief Guest, Trustee, IFRS Foundation and former Comptroller and Auditor General of India (C&AG), President and Vice-President, ICAI, Chairman, ASB, ICAI, Vice Chair, IASB and Chair, IFASS.
- ICAI organised ICAI-IASB Joint Stakeholders' Seminar on "IFRS 9 (Ind AS 109) ECL Model - Challenges in Banking Industry" on 11<sup>th</sup> April 2018.

### Building Robust Relationship with Regulatory Bodies

- "Ind AS-compliant Schedule III to the Companies Act, 2013 for NBFCs" approved by NACAS, submitted to the MCA for notification.
- ASB has facilitated Ministry of Corporate Affairs (MCA) in releasing e-version of Ind AS in preparing comprehensive updated version of Ind AS effective as on 1<sup>st</sup> April 2016 and 1<sup>st</sup> April 2017.
- ICAI is chairing the drafting group on Ind AS Compliant Formats for Preparation of Financial Statements of Insurance Companies.
- ICAI has formed a Study Group to consider issues involved in Implementation of Ind AS by Banks and Ind AS Compliant Formats for Preparation of Financial Statements of Banks.
- ASB organised interactive meetings and conferences to bring together the Indian stakeholders and the international bodies, such as, *Interaction of IASB Official with National Regulators* was organised on 10<sup>th</sup> April 2018, *IFRS – 17 (Ind AS 117, Insurance Contracts) Insurance Industry Outreach* was organised for insurance sector on 11<sup>th</sup> April 2018.
- With regard to Draft Ind AS 116, *Leases*, ASB organised two outreach meetings with the stakeholders and sectoral Regulators.
- Issues and representations received from various regulators, such as, MCA, RBI, SEBI, IRDAI, etc., industry associations and other stakeholders are taken up by the ASB from time to time.

## 5.2 Committee on Accounting Standards for Local Bodies (CASLB)

In our democratic society, the Local Bodies are supposed to be publically accountable as the citizens want to have information how public funds are being used and how the financial affairs of the economy are being managed. Therefore, there is a need to bring transparency in the operations of Local Bodies in India. There is also a need that local bodies should become self-reliant and raise the funds through capital market as the objective of urban growth/development of infrastructure, etc., cannot be achieved solely from the grants. In this direction also, there is a need to produce financial statements prepared using accrual based high quality financial reporting Standards, as these statements would be able to meet the information requirements of the investors and other stakeholders enabling them to make rational decisions.

In light of the above, as a partner in nation-building, the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) took up the responsibility to prescribe high quality Accrual Accounting Framework for third tier of government, i.e., Local-self Government. Accordingly through one of its non-standing Committee namely the Committee on Accounting Standards for Local Bodies (CASLB), Accounting Standards for Local Bodies (ASLBs) are being formulated since 2005. CASLB also organises various training programmes to create awareness amongst the Local Bodies and various stakeholders such as end users and citizens about the benefits of the accounting reform process in Government and Local Bodies. It is one of the Technical Committees in the Technical Directorate of the Institute.

### Important Activities Undertaken during 1<sup>st</sup> April 2017-30<sup>th</sup> June 2018 are:

- Booklet on "*Municipal Bonds for Financing Urban Infrastructure in India: An Overview*"
- The Committee issued Accounting Standards for Local bodies (ASLBs) ASLB 18, '*Segment Reporting*', ASLB 2, '*Cash Flow Statements*', ASLB 20, '*Related Party Disclosures*' and Various other ASLBs are progressing at different stages.



- The Committee organized training programmes on Implementation of Double Entry Accrual System of Accounting and Financial Management Reforms in Urban Local Bodies with State for officials of ULBs of States such as Delhi, Chhattisgarh, West Bengal during this year. The Committee organized one day seminar on '*Issues under Direct Taxes (Trusts & Local Bodies)*' jointly with Direct Tax Committee (DTC) at Jodhpur (Rajasthan) with the support of Jodhpur Branch of ICAI.
- The comments submitted to International Public Sector Accounting Standards Board's (IPSASB) documents/Consultation Papers/Exposure Drafts – Consultation Paper on '*Financial Reporting for Heritage in the Public Sector*', Consultation Paper on '*Accounting for Revenue and Non-Exchange Expenses*', Document on '*Strategy and Work Plan 2019-2023*' and Exposure Draft (ED) 64 of IPSASB on '*Leases*'.
- The Committee submitted the comments to Government Accounting Standard Advisory Board (GASAB)'s documents on Agenda of 31<sup>st</sup> board meeting of GASAB, Draft Strategic Development Plan 2017, Agenda of 32<sup>nd</sup> board meeting of GASAB, Draft Guidance Note on '*Fixed Assets Accounting and Recording*', Modified Indian Government Accounting Standard (IGAS) 2, '*Accounting of Grants-in-Aid*', Modified IGAS 3, '*Accounting of Loans & Advances*', and Draft on "*Due process*" and "*Preface to Indian Government Accounting Standards & Indian Government Financial Reporting Standards*".

### 5.3 Auditing & Assurance Standards Board (AASB)

Seven meetings of the Board were held during the period from 1<sup>st</sup> April 2017 to 31<sup>st</sup> March 2018. During the period under report, the Board submitted the following inputs /representations/suggestions to various Ministries and Regulators:

- The Board submitted a representation to the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises regarding the difficulties faced by auditors of companies in complying with the requirements of Companies Act, 2013 to disclose the outstanding dues of micro, small and medium enterprises (MSME) in the financial statements.
- The Board submitted to the Securities and Exchange Board of India (SEBI), the ICAI's suggestions on the Consultation Paper on *Review of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009* issued by the SEBI.

**Standards on Auditing Issued:** The Board issued following Standards on Auditing (SAs):

- *SA 299 (Revised), Joint Audit of Financial Statements.* This will be applicable for the audits of financial year 2018-19 and onwards, and this will replace the existing SA 299 issued by the ICAI in 1996.
- *SA 720 (Revised), The Auditor's Responsibilities Relating to Other Information.* This will be applicable for the audits of financial year 2018-19 and onwards, and this will replace the existing SA 720 issued by the ICAI in 2009. This standard has significant changes vis-à-vis the existing SA 720, particularly, the specific requirement for auditors to report on other information in their audit reports.

**Publications Issued:** The Board issued the following publications for the benefit of the Institute's members at large:

- *Guidance Note on Audit of Banks 2018 edition.* This provides a detailed guidance on various aspects of the audits of banks and bank branches. Being revised and issued every year, this is a benchmark publication of the Institute.
- *Implementation Guide on Reporting Standards (Revised SA 700, Revised SA 705 and Revised SA 706).* This provides a practical implementation guidance on the revised reporting standards, i.e. revised SA 700–*Forming an Opinion and Reporting on Financial Statements*, revised SA 705–*Modifications to the Opinion in the Independent Auditor's Report* and revised SA 706–*Emphasis of Matter Paragraphs and Other Matter Paragraphs in the Independent Auditor's Report*, which will be applicable for the audits of financial year 2018-19 and onwards. The Implementation Guide has been written in simple language in form of FAQs on these standards and their responses.
- *Implementation Guide to SA 701, Communicating Key Audit Matters in the Independent Auditor's Report.* This provides a practical implementation guidance on the new reporting standard, i.e. SA 701, which will be applicable for the audits of financial year 2018-19 and onwards. The Implementation Guide has been written in simple language in form of FAQs on this standard and its responses.

**Other Technical Accomplishments**

- IFAC Monitoring Group issued a "Consultative Paper on strengthening the governance and oversight of the international audit-related standard-setting Boards in the public interest" for public comments, which contains various proposals to strengthen the functioning of IFAC's standards-setting boards. AASB discussed the *Consultative Paper* at length in its meetings and submitted a draft response to the Council of the Institute. After getting feedback from the Council, AASB finalized the draft response on the Consultative Paper and submitted to the IFAC Monitoring Group in February 2018.
- On the request of Quality Review Board (QRB), AASB developed a *Technical Guide on Conducting Quality Reviews* and submitted to the QRB. This Guide will enhance the quality of Quality Reviews conducted by the technical reviewers as appointed by the QRB, since it lays down the standard procedures to be followed in Quality Reviews for better compliance and reporting.
- AASB had developed the revised formats of statutory auditor's report for urban co-operative banks in consultation with RBI. After getting approval from the RBI, AASB issued these formats in 2017-18.

**Initiatives for Members**

- AASB organised a number of programmes across the country for awareness and professional enhancement of the members of the Institute, covering various topics including various auditing standards, bank audits, reporting under Companies Act, 2013 (e.g. reporting on internal financial controls, reporting on frauds, CARO 2016), and other auditing aspects. Programmes were held in Meerut, Gwalior, Surat, Jaipur, Raipur, Kolkata, Ernakulam, Bilaspur, Agra, Varanasi, Noida, Tinsukia, Dibrugarh and Siliguri.
- AASB organized a Two-Day National Conference on "Auditing and Beyond" and "Bank Audit and Corporate Laws" in Jaipur and Indore in August 2017 and April 2018 respectively. The conferences were attended by more than 2800 participants.
- AASB in association with the Professional Development Committee of the Institute, organized a series of interactive seminars for the central statutory auditors of banks in Delhi, Kolkata, Chennai and Mumbai in March-April 2018.
- AASB organized an Interactive Meet with Corporates on new reporting standard, SA 701 in Mumbai on 26<sup>th</sup> July 2017. It also organized a live webcast on "Challenges faced by SMPs in Audit" on 27<sup>th</sup> November 2017.
- As in the past, AASB constituted an online panel of experts this year too, to address the members' queries regarding bank branch audit for the financial year 2017-18. The panel addressed and resolved the members' queries during 1<sup>st</sup>-15<sup>th</sup> April 2018.
- AASB issued the following announcements/ clarifications to provide guidance to the members:
  - Frequently Asked Questions on SA 570(Revised), *Going Concern* (applicable for the audits of financial year 2017-18)
  - Clarification on the circular dated 7<sup>th</sup> February 2018 regarding Relief for MSME Borrowers Registered under Goods and Services Tax (GST) issued by RBI.
  - Advisory for the Members regarding Allocation of Work among the Joint Auditors in Case of Bank Audit. An advisory was issued based on the suggestions given by the RBI to ICAI that allocation of work among the joint auditors in bank audits should be in discussion with those charged with governance of banks.
- AASB provided replies/ clarifications to various queries on auditing as received from the members from time to time.

**Contribution at International Platform**

- AASB represented the ICAI at the meeting of International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) held in New York in June 2018.
- AASB represented the ICAI at the annual meeting of International Auditing and Assurance Standards Board with the National Standards-Setters (IAASB-NSS meeting) held in Vienna in May 2018. At the meeting, AASB presented on "Expectation Gap/ Perception Gap - in Current Scenario & Challenges for Auditors", which was highly appreciated by IAASB Chairman and other participants at the meeting. Further, almost all suggestions given by ICAI were considered and noted for further actions by the IAASB.

AASB represented the ICAI at the meetings of International Auditing and Assurance Standards Board held in September, October and December 2017 in New York, and then in March 2018 in Amsterdam.

### ***Other Global Initiatives***

A special meeting of AASB was held in Mumbai on 7<sup>th</sup> December 2017 to interact with IAASB Chairman Prof. Arnold Schilder. The meeting was also attended by IFAC President Ms. Rachel Grimes, ICAI the-then President CA. Nilesh S. Vikamsey, and ICAI President (and the-then Vice-President) CA. Naveen N. D. Gupta.

## **5.4 Banking, Financial Services and Insurance Committee (BFS&IC)**

### **Representations/ Suggestions/ Comments Submitted to Ministries and Regulators**

- Lok Sabha Secretariat vide its letter dated 20<sup>th</sup> April 2018 had requested ICAI to give its suggestions/comments on the Financial Resolution and Deposit Insurance Bill 2017. The Committee constituted a study group for in-depth analysis of various provisions of the Bill and provide its comments thereon. The views of ICAI were presented at the meeting of the Joint Committee of the Parliament held on 14<sup>th</sup> May 2018, which were well received by the Joint Committee.
- A meeting of IEPF Authority was attended by ICAI President on 17<sup>th</sup> February 2018 to discuss the Action Plan for Investor awareness and developing a national agenda thereof. The meeting was chaired by the Secretary, Ministry of Corporate Affairs.
- A study group was constituted in consultation with Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) for preparing the basic draft of the Guidance Notes on Internal/Concurrent Audit of Investment Functions of Insurance Companies and Guidance Note on Review and Certification of Investment Risk Management Systems of Insurance Companies as stipulated in the IRDAI (Investment) Regulations 2016.
- The Committee sent a representation to National Bank for Agricultural and Rural Development (NABARD) to assist them in the initiative taken by Government for Digital Financial Literacy Awareness Programme (DFLAP).
- The Committee provided technical support to Centre for Advanced Financial Research and Learning (CAFRAL) for the workshop on Implementation of Indian Accounting Standards (Ind AS) organized on 25<sup>th</sup> October 2017 in Mumbai.

### **Seminars, Workshops, Expo, Conferences, etc.**

- *ICAI Corporate Expo 2018* was organized on 19<sup>th</sup>-20<sup>th</sup> January 2018 in Mumbai coinciding with the 11<sup>th</sup> ICAI Award 2017 as organised by the Committee for Professional Accountants in Business & Industry of the Institute.
- A seminar on National Pension System (NPS) for Chartered Accountants was organized on 28<sup>th</sup> November 2017 in New Delhi jointly with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA).
- A Seminar on *Evolving Investment Strategies & Opportunities for CAs* was organized on 19<sup>th</sup> August 2017 in Mumbai.
- More than 120 Investor Awareness Programmes were organized under the aegis of Investor Education and Protection Fund Authority of Ministry of Corporate Affairs across the country in the year 2017-18.
- Four batches of *Certificate Course on Forex and Treasury Management* were organised during the year 2017-18.
- Two Orientation Programmes were organized for the DIRM Technical Examination passed members of ICAI in the month of May 2017 at New Delhi & Mumbai. There were 5074 registrations to the DIRM Course as on 30<sup>th</sup> June 2018.

## **5.5 Committee for Capacity Building of Members in Practice (CCBMP)**

Committee for Capacity Building of Members in Practice (CCBMP) was formed in February 2010. Main objective of the Committee is to strengthen the CA firms as well as small and medium practitioners to rejuvenate their practice portfolio. Prime function of the Committee is to create awareness amongst the CA

firms on capacity building through consolidation by networking, merger & setting up management consultancy services firm and popularizing the concept of union through arranging workshops, symposia and summit on the benefits of consolidation and endurance to better accounting, auditing and ethical standards. The Committee assists small & medium practitioners in improving their visibility amongst the business community and also creates additional professional opportunities for them.

In line with vision of ICAI, which is 'The Indian Chartered Accountancy Profession' will be the valued trustees of world-class financial competencies, good governance and competitors, the Committee has its motto for Capacity Building of Indian CA firms through consolidation and empowering small & medium practitioners by developing and upgradation of their professional competence. Accordingly, the Committee has following issues to deal with;

- Preparation of code for consolidation of CA firms.
- Identifying means and ways for empowering SMPs.
- Upgrading and updating the knowledge and skills set on standard practice.
- Developing practice areas for SMPs.
- Identifying Role of SMPs in emerging areas.
- Developing technical material to facilitate practice in new areas of profession.
- Facilitation on IT savvy office management and audit tools for CA firms & SMPs.
- Re-engineering of profession and establishment of CA Firms with sound infrastructure and finance.
- Arrangement of social security & insurance protection for Practitioners & CA Firms

### Activities Undertaken

#### ➤ **Concessional fare offer for Members in booking of air tickets from Jet Airways**

The Committee arranged the Concessional fare while booking of air tickets for domestic & International travel by Jet Airways. The Concessional Fare arrangement envisaged for ICAI members and their identity shall be established on the basis of their membership number. The concessional airfare rates shall remain in vogue with respect to any member so long as his/her Membership/ Registration with the Institute continues. Details of above arrangement are available at [www.icaai.org](http://www.icaai.org) or [https://icaai.org/post.html?post\\_id=14203](https://icaai.org/post.html?post_id=14203).

#### ➤ **Antivirus software at special price for Members and Students**

An arrangement made by the Committee to enable members to have access to antivirus software, has tied up with Quick Heal Technologies Pvt. Ltd. Pune for providing access to Quick Heal Total Security at a special discounted price of Rs. 1200/- plus applicable taxes from March, 2018 to March, 2020 for single user for a period of 3 years for the Members & students of ICAI. Details of above arrangement are available at [www.icaai.org](http://www.icaai.org) or [https://icaai.org/post.html?post\\_id=11505](https://icaai.org/post.html?post_id=11505).

#### ➤ **Tax Cloud: Cloud based & TDS Return Preparation for Members**

'Tax Cloud: Cloud based ITR & TDS Return Preparation for CAs' enables Income Tax Return and TDS Return preparation, provides all types of assessee support including Individuals, HUFs, Firms and Companies, calculates Income Tax under all heads such as Salary, House Property, Capital Gain, Business and Profession, Other and Exempt Income Heads, generates detailed computation of Income Tax Returns, PDF for paper filing and XML for e-Filing, automatic data backup for CAs for cloud serve

#### ➤ **Insurance Schemes**

**Motor Vehicle Insurance for Members and Students:** An MoU with New India Assurance Co. Ltd for Motor Vehicle Insurance arranged by the Committee. The Motor Vehicle Insurance is basically designed for the members but also has been extended to the students and employees of ICAI. The Motor Vehicle Insurance for which MOU is being executed has value added features such as Unique Offer of 65% discount (on erstwhile Tariff Rate) for both Private car and two Wheeler etc. Members and students may purchase the Motor Vehicle Insurance Policy online at the website <http://icaai.newindia.co.in>.

**Arrangement for Office Protection Shield Insurance at special premium for the Members in Practice/CA Firms:** CCBMP of ICAI has arranged Office Protection Shield Insurance at special premium for members of ICAI. Interested Members and CA firms may check the aforesaid scheme at <http://icai.newindia.co.in> .

**Professional Indemnity Insurance for Members & CA Firms of ICAI:** CCBMP has arranged insurance protection for members in practice/ firms in the form of specially-designed professional indemnity insurance at a reasonable premium i.e. upto 95% discount in market rate. The scheme is for the Members-in-practice/ firms of the ICAI. Members and CA firms desirous to avail the benefits of the aforesaid scheme may check <http://icai.newindia.co.in>.

- **ICAI Connect – A self-service portal for Members:** CCBMP has launched ICAI Connect, a self-service portal for the members of ICAI. The features of the aforesaid single window self-service portal includes viewing personal Profile and firms constitution, Announcements of ICAI, details of payments of fees and regulatory charges to ICAI, My Articles details, tracking regulatory forms and application status, e-Services, My Firms, My Software(s), Letters and Certificates, CPE Hours credited, Guidelines of Networking, Merger & Demerger, etc.
- **Committee's Exclusive Website** [www.icai.org.in](http://www.icai.org.in): The Committee has developed a Website namely [www.icai.org.in](http://www.icai.org.in), where the Firms and Practitioners may create their portals as per the norms laid down by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India. The website provides a platform for the CA Firms to upload their firms' details and gives them an opportunity to reach out to the members and CA firms practicing worldwide.

The website also acts as a forum for consolidation of the members and CA Firms by providing for consolidation measures like Networking, Merger and Corporate Form of Practice. The members may visit portals of other members and firms and like-minded persons may join hands to grow big to compete in the international front.

- **A portal for Senior Members of ICAI** [www.seniormembers.icai.org](http://www.seniormembers.icai.org): CCBMP has developed a website namely [seniormembers.icai.org](http://www.seniormembers.icai.org). The website provides a platform for senior members of ICAI for getting flexi working hours assignment as well as fulltime assignment after their retirement. At the same time it will also help industry to tap experienced talent pool which might not be accessible otherwise in normal course. The said portal would be useful and handy to all the senior members of ICAI.

#### ➤ **Knowledge sharing & Enhancement**

**"Practiquer"- A Quarterly e-Newsletter for the Chartered Accountants:** CCBMP has taken an initiative to bring out an e-Newsletter quarterly for the CA fraternity, highlighting the latest developments in the profession. The e-Newsletter, i.e. "Practiquer" is a perfect tool which will provide the Chartered Accountants with all requisite information. It compiles information on all important areas of the profession and will be of great benefit to the members. CCBMP has brought out the following publications for enhancement of the knowledgebase of the practitioners:

- Roadmap to Income Tax Practice : A Practitioners Perspective
- Roadmap to Goods & Services Tax : A Practitioners Perspective
- E-Book on "Ready Reckoner on Regulatory Aspects of ICAI for Members & CA Firms"

- **Quick Insight 2018:** The Committee has taken an initiative to bring out Quick Insight 2018 for the CA fraternity, highlighting latest developments in the profession. Quick Insight contains important information on tax, accounting, limited liability partnership, Management consultancy services, statements and standards on audit etc. as well as information on important forms related to CA students.
- **Portal** <http://kb.icai.org/>: **a gateway to ICAI Knowledge Bank – Consolidation:** The Committee launched a portal [kb.icai.org](http://kb.icai.org/) gateway to ICAI Knowledge Bank for Consolidation of all the Publications of ICAI. The portal in such a way designed for search/Advance search facility and management of ICAI publications.

- **Learning Curve—Consolidation of Queries and Solution for Queries by FAQs and Live Webcast:** The Committee launched the portal ICAI Learning Curve for Consolidating the Query on Various Professional Issues and answers these queries in Multiple phases for enhancement of the Practice portfolio and other aspects.
- **International SMP Day on 27<sup>th</sup> June 2018:** The Institute of Chartered Accountants of India through the Committee, recognizing the importance of services provided by SMPs to SMEs in the development of these enterprises, observed 27<sup>th</sup> June 2018 as the International Small and Medium Practitioner Day to raise public awareness of the contribution of SMPs to SMEs in various parts of the Country. The Committee organised a live webcast on Practice Management and lecture meeting on the eve of International SMP day.
- **Networking & Merger: Revised Guidelines of Network:** CCBMP has considered practical difficulties in consolidation of CA Firms through medium of Networking. The CCBMP has appropriately finalized the revised Guidelines of Networking facilitating members and firms for its easy adoption. The details of the Revised Guidelines of Networking is available at [http://www.icai.org/post.html?post\\_id=7710](http://www.icai.org/post.html?post_id=7710). The details of the Rules on Merger is uploaded at [www.icai.org.in](http://www.icai.org.in).
- **MoU with World Bank for Procurement Audit:** CCBMP entered into an MoU with the World Bank for the arrangement of knowledge enhancement of the Members of ICAI in procurement audit. This aforesaid arrangement with the World Bank offers procurement training with Joint Certification to the participants of the training programme. These trainings are meant to enhance the capacity of ICAI members to participate in procurement opportunities in Bank funded Projects for various assignments including external/internal audits; procurement audits/post reviews, and other consultancy assignments for firms and individual members of ICAI.
- **Certificate Courses:** CCBMP has launched Certificate Course on Wealth Management and Financial Planning and Certificate Course on Preparation of Appeals, Drafting of Deed & Documents and Representation before Appellate Authorities and Statutory Bodies, for enhancing the career opportunities of the members, with the objective to equip their knowledge in principles of financial planning and wealth management through guidance on strategic investments and retirement benefits, and for the enhancement of their effective drafting skills.
- **Revised Minimum Recommended Scale of the fees for the Professional Assignments done by the Chartered Accountants for Class 'A' & Class 'B' cities:** CCBMP has taken a major initiative for further revising the prescribed Minimum Recommended Scale of Fees for the professional assignments done by the members of ICAI. The recommendation is about the fee to be charged as per the work performed for various professional assignments and the amount quoted under respective heads of professional work. The fee has been recommended separately for Class A and Class B Cities. The prescribed Minimum Recommended Scale Fees will enhance the productivity and Capacity Building of Practitioners & CA Firms and will largely benefit the Practitioners. The revised scale of fee is available on the link - [https://www.icai.org/post.html?post\\_id=14230](https://www.icai.org/post.html?post_id=14230).
- **Empowerment of Women Members of ICAI:** Women Members Empowerment wing of the Committee is sincerely working for the development of women CAs to make them fully empowered and broaden their horizons.
  - **A Portal for Women Members of ICAI [www.womenportal.icai.org](http://www.womenportal.icai.org)**
  - The portal for women members functions under CCBMP, helping them in contributing towards the growth of accountancy profession and national economy, while it takes care of their domestic commitments too.
  - **LEAD - A Diversity Support for Women CAs**
  - CCBMP and CPE Committee present LEAD – A Diversity Support Initiative, where women CAs in any stream can ask questions on personal development, professional enhancement and strategies to stay empowered and become leaders. Their questions will be addressed by a panel of experts.
  - **SETU-Bridging the Gap between Women Members & CA Firms**
  - CCBMP organizes regular programmes/ seminars on women empowerment, along with the SETU programme, i.e. bridging gap between women Members and practicing CA firms across the nation.
- **Live Webcasts:** CCBMP organized following live webcasts for the capacity-building measures of practitioners on Practice Management, GST Audit, Recent Changes in ITR Forms, Fair Value

Measurement under Ind AS, Documentation in Bank Audit, New Challenges and Opportunities for CA Fraternity, Wealth Management and Financial Planning, Tax Audit Report, Appearance before Appellate Tribunal, Credit Rating, Trust and Taxation under IT Act, FCRA and GST, Ind AS: Practical Application and Emerging Trends, and Bank Audit.

## 5.6 Continuing Professional Education Committee (CPE Committee)

CCBMP has all along endeavoured to keep proactive to the emerging needs of its members enabling them to acquire contemporary knowledge and skills to face the challenges effectively in this ever changing economic and business environment. The main objective is to adopt, execute and implement such measures using latest technology in order to provide sufficient opportunity to Members to keep abreast with current knowledge. To keep pace with the global requirements, CPE requirements are mandatory for all the members of the ICAI, whether he/ she be in practice or in service and such system is measured, monitored and managed scientifically.

CPE Committee has always been the foremost to provide opportunities to their members to boost their knowledge base as it is necessary for them to constantly update their knowledge and skills to meet the expectations of the stakeholders and familiarize with the new and emerging areas related to professional development and national interests.

### Robust Members' Learning & Professional Development Mechanism:

- **CPE Statement-** With a view to enable its members to maintain the requisite professional competence and thus ensure high quality and standards in the professional services that they render, all the members of the ICAI, be in practice or in service, are mandatorily required to meet the CPE credit hours requirements from time to time, as specified by the Council of ICAI.

Contemporary with Global requirements & Practices, the CPE Credit Hours requirements for various categories of members as applicable from the current block of 3 years (1-1-2017 to 31-12-2019) are:

Category of Members	CPE Hours requirement
Members (aged less than 60 years) who are holding Certificate of Practice (except all those members who are residing abroad)	120 (out of which minimum 60 CPE hours should be of Structured learning) -minimum 20 CPE credit hours of structured learning in each calendar year
Members (aged 60 years & above) who are holding Certificate of Practice	90 (either structured or unstructured learning) - minimum of 20 CPE credit hours either Structured or Unstructured Learning in each calendar year
Members (aged less than 60 years) who are not holding Certificate of Practice; and all the members who are residing abroad (whether holding Certificate of Practice or not)	60 (either structured or unstructured learning) -minimum 15 CPE credit hours either structured or unstructured learning in each calendar year

### Exemptions to Members:

- a) A member is exempted only for the particular calendar year during which he gets his membership for the first time.
- b) Following classes of members are exempted from CPE credit hours requirement:
  - (i) All the members (aged 60 years and above) who are not holding Certificate of Practice.
  - (ii) Judges of Supreme Court, High Court, District Courts and Tribunal
  - (iii) Members of Parliament/MLAs/MLCs
  - (iv) Governors of States
  - (v) Centre and State Civil Services
  - (vi) Entrepreneurs (owners of Business (manufacturing) organizations other than professional services)
  - (vii) Judicial officers
  - (viii) Members in Military Service

c) Temporary Exemptions:

- (i) Female members for one Calendar year on the grounds of pregnancy.
- (ii) Physically disabled members on case to case basis having permanent disability of not less than 40% and above (Supported with medical certificates from any doctor registered with Indian Medical Council with relevant specialisation as evidenced by Post Qualifications (M.D., M.S. etc.).
- (iii) Members suffering from prolonged critical diseases/illnesses or other disability as may be specified or approved by the CPEC. (Supported with medical certificates from any doctor registered with Indian Medical Council with relevant specialisation as evidenced by Post Qualifications (M.D., M.S. etc.).

d) A member or class of members to whom the CPEC may in their absolute discretion grant full/partial exemption specifically or generally on account of facts and circumstances of the case which in their opinion prevent such person(s) from compliance with the requirements of CPE as specified in the Statement.

**CPE Portal and Integration of CPE Activities through ICAI Mobile App:** With a view to facilitate our members with more robust, user friendly and mobile compatible functionalities with regard to CPE activities, time and again certain provisions have been developed in the CPE Portal [www.cpeicai.org](http://www.cpeicai.org) to cater the requirements of the CPE Committee. The CPEC Portal is meant to develop the knowledge hub providing information regarding latest developments relating to the profession and to promote various ICAI initiatives for young Chartered Accountants.

Efforts have been made to make the existing CPE Portal mobile friendly to the extent that members will be able to check their CPE hours through their equipped mobile phones. CPE Committee has taken an initiative to configure "CPE Programs" in ICAI Mobile App on (Android and IOS Platform) which is being used for monitoring CPE activities from anywhere any time by our members. The members are required to download ICAI Mobile App from the Google Play Store and install it on their Mobile.

The Segment "CPE Programs" contains the features such as Details of upcoming programs, Register for Program Alert/Receive notifications regarding CPE programs and set preferences, Online Submission of Unstructured Learning Activities, Know your CPE hours credit, CPEC Newsletter, View Webcasts, Search event facility through keywords, City-Wise, POU-Wise, Subject-Wise and About CPE Committee etc.

**CPE Guidelines for Effective Monitoring and Organizing Quality CPE Programmes:** For effective monitoring and organizing quality CPE Programmes, following norms, guidelines and directions for the CPE programme organising units (POUs) are available at the CPE Portal:

- Statement on CPE
- Norms for CPE Study Circles
- Norms for CPE Study Chapters
- Norms for CPE Study Groups
- CPE Advisories
- Council Directions for professionalization of Conduct of CPE Programmes
- Parameters for granting the status of National Conference and International Conference as applicable to all programmes having CPE Credit to be organized by the Central Committees of the ICAI.

**CPE Calendar:** CPE Committee has come up with its Calendar for 2018-19 that focuses on the most relevant and contemporary topics for continuing professional education of Members in three parts. *Part A* provides standard programme structure for various thrust areas relevant in current professional scenario. *Part B* provides specific focus topics and *Part C* covers an exhaustive list of topics which have been covered in the past years.

**E-Newsletter:** Quarterly e-newsletter "CPE Bulletin" is being brought out to share recent initiatives that have been taken by the Committee and was hosted at the ICAI Website as well as at the CPE Portal for information of members, POUs and others.

**Spreading Wings Globally:** 25 CPE international study tours / seminars were organised internationally by the CPE POUs in Thailand, Singapore, Malaysia, Bhutan, Indonesia, England, Scotland, Australia, and Sri Lanka.



**Brand- and Capacity-Building:** ICAI has all along endeavoured to keep its members aware of and abreast with the professional and technological changes that are taking place, around the globe through the process of continuous skill honing by way of classroom teaching, e-Learning mode, In-house Executive Development Programmes, Webcasts, Awareness programmes, Seminars, Conferences etc. Few of the milestones are as follows:

**CPE Live Webcasts - 5** Live Webcasts were organised by CPE Committee on emerging topics of professional and national interest namely Overview, application and implications of ICDS, Stinging Implications of New Benami Law: Overview and Issues, UAE VAT, Emerging India – An NRI perspective. 64 webcasts were organised by other Central Committees of ICAI on various topics of professional interest. The recordings of webcasts are available at [www.icaity.com](http://www.icaity.com).

**National Level Programmes and other Important Events - 48** CPE Programmes were organised by the CPE Committee at National level etc. and hosted by Regional Councils/Branches of ICAI in different parts of the Country since April, 2017.

9653 CPE programmes were organised across the country, by CPE POU's on various topics of professional interests. 194 programmes on Certificate Courses of ICAI on GST, Anti-Money Laundering Laws, Wealth Management and Financial Planning, Concurrent Audit of Banks, IndAS, Forensic Accounting and Fraud Detection, etc., and 97 Post-Qualification Courses on Information Systems Audit (ISA), Diploma in Insurance and Risk Management (DIRM) and International Taxation, were organised through Central Committees of ICAI.

**Opening of New CPE POU's:** 31 more CPE POU's were opened for helping the members in mofussil/ remote areas of the country to undergo CPE activities in their nearby places, reaching to strong network base of 594 CPE POU's in India and abroad.

**Training Programmes for Public-Sector Undertakings:** Following In-House Executive Development Programmes (IHEDPs) were organised apart from various other Executive Development Programmes organised by other Central Committees of ICAI :-

- Five days IHEDP for the officials of IOCL, Gurgaon.
- Three days IHEDP for the officials of IOCL at Chennai hosted by the SIRC of ICAI.
- Three days IHEDP for the officials of ONGC at their Premises at Mumbai.

**Supporting Society – Commitment to Nation:** ICAI organises various other programmes supporting the initiatives of the Government for effective implementation of the same in various parts of Country through its strong Network base of CPE Program Organising Units.

- 164 programmes have been organised by the CPE POU's on Demonetization, Black Money, Benami Transactions and Undisclosed Income.
- 3558 programmes on GST were organised by the CPE POU's in various parts of the Country.
- 310 programmes on RERA (Real Estate Regulatory Act).
- 582 programmes on ICDS (Income Computation and Disclosure Standards).
- 288 programmes on Insolvency and Bankruptcy Code.
- 168 programmes on Companies Act.
- 7 programmes on Corporate Social Responsibility (CSR) were organised by CPE POU's at various parts of the country.
- 48 programmes on SWIFT Transactions (International InterBank Transfer).
- 29 programmes on Investor Awareness.
- 71 programmes on Professional Ethics.
- Total 62 CPE Programmes were organised on Stress Management, Lifestyle Management where Yoga is way of life, Work Life Balance etc. on 21<sup>st</sup> June celebrated as International Yoga Day.

### Other Major Initiatives

**E-Learning platform - Virtual Centre for Learning and Excellence -** ICAI has commenced its Platinum Jubilee Year Celebrations on 1st July, 2018. On this occasion, the CPE Committee has launched an E-Learning- 'Virtual Centre for Learning and Excellence' available at [www.icaielearning.org](http://www.icaielearning.org).

With the increase usage of desktops, tablets, I-pads, etc., it was felt at ICAI that the Members should have an opportunity to regularly update themselves with the ever-changing professional sphere on-the-go. Hence the CPE Committee has developed an E-Learning platform [www.icaielearning.org](http://www.icaielearning.org), Virtual Centre for Learning and Excellence – to foster virtual learning, wherein various E-learning courses on contemporary topics by eminent experts are available to support the members to earn CPE credit hours through Unstructured CPE Learning activities.

**ICAI TV- One Stop Knowledge Hub** - As ICAI has entered its Platinum Jubilee Year on 1<sup>st</sup> July 2018, so on this historic occasion the ICAI has re-launched the ICAI TV, an online 24x7 portal to showcase important ICAI initiatives/ achievements/developments and the live webcasts/telecast of ICAI programs from across the globe. With this new avatar of ICAI TV, the Institute aims to build a strong bond of trust with all the stakeholders including members, students, government and general public at large.

ICAI firmly believes in the power of connectivity and through this innovative initiative, the ICAI aims to strengthen its image as the Nation's premier accounting body, by disseminating useful information in the areas of Accounting, Assurance, Taxation, Finance, Business, Education, Digital trends and much more incisive insights on contemporary issues relating to CA Profession. Needless to say, ICAI TV will enable the members, students, stakeholders, government and general public to stay updated about ICAI, with just a simple click on [www.icaitv.com](http://www.icaitv.com) from the convenience of their desktops, laptops, tabs or smartphones.

**Samadhan: a CPE – QnA e-Solution Forum** - Samadhan is a CPE – QnA e-Solution Forum through which the members can reach out to experts and seek guidance for seamless information and query resolution experiences in the select areas of practice. The sessions on Non Resident Taxation including Section 195 was opened from 18.05.2018 to 24.05.2018 and sessions on Young Members Practice Strategies and Goods and Service Tax – Input Tax Credit was opened from 13.06.2018 to 18.06.2018.

Also, the CPE Committee and the Committee for Capacity Building for Members in Practice of ICAI presented session on LEAD - Diversity Support Forum - for Women CAs by the CPE and CCBMP Committees where Women CA's in any stream can ask questions throughout the year on Personal development, Professional Enhancement and strategies to stay empowered and be leaders.

**My CPE - CPE Programs of Your Choice** - The concept seeks a bottom up approach for Members to update their preference for My CPE - CPE Programs of their Choice at google form for the programs that they are interested in, so that the total interest can be aggregated from the members and the respective Program Organising Units (POUs) can be intimated to organise these programs during the course of the year. A member, who is an expert in any of these topics and is interested to teach in these programs, may also indicate the same for communicating to the POU.

**ICAI-ICE: ICAI Interactive CPE Enabler** - The CPE Committee has developed 'ICAI-ICE' which is an ICAI-Interactive CPE Enabler for questions and polls ahead of and during CPE programs. As a part of CPE e-initiative endeavors, now a full-fledged version of ICAI-ICE has been enabled for all the CPE Programmes organised by various POU's to ask queries from speakers before and during the programme many of which would be answered by the Speakers, according to the availability of time. Members may login at <https://ice.icaai.org> for accessing the ICAI-Interactive CPE Enabler Portal by using the respective ICE code of the Programme.

**Development and implementation of Online Feedback Mechanisms** - The Committee has developed various online feedback forms namely Quick feedback form, detailed feedback form and monitor feedback form for strengthening the feedback mechanism and overall CPE framework.

**Leader Speak** - Leader Speak is a series of webcasts by Leaders on contemporary topics of interest to expand the knowledge base of Members. A Webcast on May 28, 2018 was organised by the CPE Committee and hosted by the ICAI Doha Chapter with CA. Seetharaman, Doha Bank addressing a Leader Speak session on Emerging India – An NRI perspective.

## **5.7 Corporate Laws & Corporate Governance Committee (CL&CGC) & Insolvency and Bankruptcy Laws Group of CL&CGC**

### **A. Corporate Laws & Corporate Governance Committee (CL&CGC)**

CL&CGC aims to facilitate a fair corporate regime with the best global practices, through collaborative efforts with the Government to strengthen the regulatory framework, i.e. Rule-making process of the Companies Act, 2013, and regular interactions with Ministry of Corporate Affairs and submission of representations/ suggestions/ inputs on the Companies Act, 2013.

### **Representation to MCA**

**a. The Companies Act, 2013:** CL&CGC regularly interacts with the Ministry of Corporate Affairs for smooth implementation of the Companies Act 2013. It submitted the following representations to the Ministry:

#### **During 2017-2018:**

- Regarding linking membership number of Chartered Accountants with DIN.
- Regarding issues w.r.t restriction on number of audits under the Companies Act, 2013.
- Regarding Audit Rotation under Companies Act 2013 and appointment of Internal Auditors as Statutory Auditors on completion of their term and vice-a- versa.
- Response on the Report of MCA's Expert Group on Issues related to Audit Firms. The main contents were as under:
  - The accounting and auditing standards and practices followed in India should be aligned to international standards and practices with customization to the extent necessary.
  - The small size of majority of Indian audit firms being a constraint in facing global competition, consolidation through merger and networking of Indian audit firms should be encouraged through policy measures.
  - With audit becoming a multi-disciplinary function, formation of multi-disciplinary audit firms with participation by professionals from other relevant professions should be promoted.
  - It should be ensured that the recommendations of Quality Review Board conducting technical evaluations of Indian audit firms are implemented.
  - If and when audit and assurance are opened to global competition, the principle of reciprocity should be followed and the interests of Indian audit firms should be given due consideration.
- Regarding interpretation of the provisions of Section 123 (1) of the Companies Act 2013 and Companies (Declaration and Payment of Dividend) Rules, 2014.
- Issues in the Operationalisation of Rotation of Auditors in private companies (Section 139 (2) read with Rule 5 (b) of the Companies Act 2013.
- Requested MCA to take inputs from the Institute of Chartered Accountants of India in the issues arising out of implementation of the Companies Act, 2013.
- Representation regarding the clarification issued by the Insolvency and Bankruptcy Board of India that Insolvency Professional Entity cannot be appointed as Insolvency Professional.
- Suggestions regarding Public Notice for Commencement of Proviso to clause 87 of section 2 of the Companies Act, 2013 (restrictions on the number of layers of subsidiaries).
- Requested MCA to give clarification on the Notification regarding disclosure and reporting by auditors due to Demonitisation as issued by MCA on 30th March, 2017.
- Reply to the Letter regarding suggestion for notifying tax services under Section 144(i) of the Companies Act, 2013 as prohibited services for the Auditor of the Company.

- Suggestions submitted regarding practice followed for financing the payment of dividend through Debt/ Loans.
- Submitted Views on the proposal to dispense with the requirement of publication of Notice in Newspapers as per various provisions of the Companies Act, 2013.
- Suggestion submitted regarding clarification for the compliance with the provisions of the Companies Act 2013 while acting as an Insolvency Professional as per the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.
- Detailed Issues in the Companies Act 2013 and Rules thereunder – Suggestions for Modifications.
- Regarding providing exemption to be provided to public and private companies from the requirement of proviso to Section 187 (1) of the Companies Act, 2013 in case of Joint Venture Companies in addition to Subsidiary Companies.

### **During 2018-2019**

- Draft Companies (Beneficial Interest and Significant Beneficial Interest) Rules, 2018.
- ICAI Suggestions on Draft National Financial Reporting Authority Rules issued in 2013 for Public Comments by the Ministry of Corporate Affairs.
- Procedure for dealing with applications for removal of auditors under section 140 of the Companies Act, 2013 by the Regional Directors.
- Suggestions on the Companies (Audit and Auditors) Amendment Rules, 2018.

**Question Bank on Insolvency and Bankruptcy Code, 2016:** CL&CGC along with the Insolvency and Bankruptcy Laws Group released a Question Bank on the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 in February 2018.

**Guidance Note on Division II – Ind AS – Schedule III to the Companies Act, 2013:** To facilitate the exercise of preparation of financial statements by companies which are required to prepare its financial statements as per Ind AS Schedule III, CL&CGC brought out a Guidance Note on Division II- Ind AS Schedule III to the Companies Act, 2013 for the companies which are required to comply with Ind AS.

**Meeting of Parliamentary Standing Committee on Industry:** Participated in the Meeting of the Hon'ble Department related Parliamentary Standing Committee on Industry regarding examination on Professionalisation of Board of Central Public-Sector Enterprises was held on 27<sup>th</sup> April 2018, where a presentation was made on Professionalisation of Board of Central Public-Sector Enterprises.

**Meeting of Taskforce on Ease of Doing Business:** Ministry of Corporate Affairs had formed a Taskforce on 'Ease of Doing Business' for the indicators "Starting a Business", "Resolving Insolvency" and "Protecting Minority Investors". The third meeting was held on 11<sup>th</sup> April 2018, where it was discussed to create awareness of the initiatives taken by the Government towards Ease of Doing Businesses especially in starting a business and resolving insolvency. In this regard, CL&CGC conducted three programmes/webcasts in Mumbai, New Delhi and Kolkata.

**Memoranda on Corporate Governance in PSUs submitted to Parliamentary Committee on Public Undertakings:** Parliamentary Committee on Public Undertakings had requested ICAI to examine the subject "Corporate Governance in CPSUs" as a horizontal study and submit a memorandum to the Committee giving its views, suggestions and opinion on the same. In this regard, ICAI submitted the memoranda on various aspects of Corporate Governance in CPSUs.

**Suggestions on the Draft Report of SEBI Committee on Corporate Governance:** SEBI formed a Committee on Corporate Governance with the aim of improving standards of corporate governance of listed companies in India and to advise on issues relating to corporate governance. In this regard, ICAI has submitted suggestions on the draft Report of SEBI Committee on Corporate Governance to SEBI as well as MCA. On some of the suggestions ICAI has submitted its dissent.

**Clarification regarding applicability of exemption provided to Auditors of Private Companies for Applicability of Section 143 (3) (i) of Companies Act, 2013:** Based on our representations submitted to MCA, clarification has been issued regarding the applicability of exemption provided for Reporting on Internal Financial Control as per Section 143 (3) (i) as per Notification dated 13<sup>th</sup> June 2017 giving further exemptions to private companies under Section 462 of the Companies Act, 2013. The Ministry had clarified in the circular that the exemption shall be applicable for those audit reports in respect of financial statements pertaining to financial year, commencing on or after 1<sup>st</sup> April 2016, which are made on or after the date of the said notification.

**Proposal to National Foundation for Corporate Governance for Conducting Seminar for promoting good Corporate Governance Practices:** The Committee submitted proposal to NFCG for conducting seminar on various aspects of Corporate governance, i.e. for Directors / Faculty or Research work with a view to promote good Corporate Governance practices. In this regard, five programmes have been planned to be conducted in different regions of the Country which will facilitate deliberations and discussions on the various aspects of corporate governance in the changing business scenario. The first programme was conducted on 30<sup>th</sup> June 2018 in Kolkata.

**Committee for Streamlining Companies Act, 2013 as Formed by MCA:** Participating in the Committee formed to examine the existing Forms under the Companies Act, 2013 and for introduction of new Forms, for streamlining the process with a view to remove difficulty and ease of operationalization.

**Group to Examine Companies (Acceptance of Deposit) Rules, 2014 as Formed by MCA:** The Committee participated in the Group Meetings to examine the Companies (Acceptance of Deposit) Rules, 2014 and various issues related to it. The Final Report of the Group already submitted.

**Working on Inconsistency between Provisions of Companies Act, 2013 and IND AS:** The Committee is working on the issues identified where there is an inconsistency between the provisions of the Companies Act, 2013 and IND AS and moving towards resolving the same.

**Committee for Drafting Appendix to Investigation Manual of SFIO:** Contributing in the Committee for drafting Appendix to the investigation manual of SFIO in the light of new/changed provisions of the Companies Act, 2013.

**Study of Airport-Specific Assets for Prescribing a Useful Life as per Schedule II of Companies Act, 2013 as Desired by Airport Economic Reporting Authority**

The Committee has submitted report on study of useful life and depreciation rates for Airport Assets to Airports Economic Regulatory Authority of India. Further comments have been submitted on the suggestions received from Stakeholders, i.e., Airports, on the Consultation Papers issued by the Airport Economic Regulatory Authority to various Airport Authorities.

**Draft Rules for Voluntary Revision of Financial Statements under Section 131 of Companies Act, 2013 Submitted to MCA**

Draft Rules for Voluntary Revision of Financial Statements under Section 131 of the Companies Act, 2013 as prepared on the request of MCA were submitted to MCA. In this regard, the Committee has given the view that the revision of Financial Statements should be allowed in exceptional circumstances.

**Formats of Financial Statements for Limited Liability Partnership:** On the request of Ministry of Corporate Affairs, the Committee prepared and submitted the Format of Financial Statements for Limited Liability Partnerships. The formats were prepared on the basis of LLP Act, Rules and Forms and the format prescribed as per the Schedule III to the Companies Act, 2013

**Format of Abridged Financial Statements (AOC-3) to be Filed by Companies Following Division II- Ind AS Schedule III to Companies Act, 2013.**

As requested by the Ministry of Corporate Affairs, the Committee prepared and submitted the draft Format of Abridged Financial Statements that are required to be filed by company as per first proviso to

Section 136 (1) of the Companies Act, 2013 by the companies that are following Division II- Ind AS Schedule III to the Companies Act, 2013.

**Proposal for Dematerialisation of Securities as Issued by Unlisted Companies:** ICAI gave suggestions on the proposal of The Ministry of Corporate Affairs to make it mandatory for unlisted Companies to issue its Securities in dematerialised form as per Section 29 (1) (b) of the Companies Act, 2013.

**Proposal Submitted to DIPP to Expedite the Process of Reforms and Better Comprehend Reason behind World Bank's Observation pertaining to Reforms Implemented**

On the request of the Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), ICAI submitted its proposal to expedite the process of reforms and better comprehend the reason behind World Bank's observation pertaining to reforms implemented.

**Standard Operating Procedure (SOP) -for Prosecutions/ Litigations:** The Ministry of Corporate Affairs had constituted a Committee to prepare Standard Operating Procedure for Prosecution/litigation. In this regard, the comments on the draft SOP for litigation/ prosecution were submitted to MCA.

**Learning Management System:** Learning Management System has been developed as an easy to use platform which delivers the concepts across the entire syllabus for the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, in the form of presentations and supplemented by mock tests in each component of the syllabus. A unique feature is that it enables one to take the tests at a modular level so that one can re-learn to improve the test scores.

**Training Programme on Implementation of Companies Act, 2013 and Rules Thereof:** The Committee has taken an initiative to keep the members of ICAI, equipped and abreast with the latest developments/ changes/ amendments in the provisions of the Companies Act 2013, by conducting various programme across the country, in the form of Interactive meetings, training Programmes, webcasts, Seminars and Conferences on Update on Companies Act, 2013.

**B. Insolvency and Bankruptcy Laws Group of CLCGC**

ICAI in February 2017 with a view to give specific focus on the Insolvency and Bankruptcy Law, formed Insolvency and Bankruptcy Laws Group under Corporate Laws & Corporate Governance Committee. The Group has the mandate to create awareness about the professional opportunities in this new area of practice. The Group conducts intensive training programmes/ webcast for preparation of IBBI Limited Insolvency Examination as well as awareness programmes on the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. The Group also brings out publications to help members to understand the Code better.

**5.8 Direct Taxes Committee (DTC)**

**Representations/Interactions with CBDT:** DTC submitted the following professional inputs, requests, representations, etc., of ICAI to the Central Board of Direct Taxes (CBDT) during this year:

- Draft Notification to be issued under Section 10(38) of the Income-tax Act, 1961.
- To issue clarifications regarding applicability of provisions of section 269ST.
- Section 271J imposing penalty on Chartered Accountant for furnishing incorrect information in reports or certificates.
- To grant exemption under section 139AA(3) to the resident assessee of Assam and Meghalaya. The said request was favourably considered by the CBDT.
- To resolve the grievance(s) faced by assessee regarding Communication/ Order /Notice received from CPC Bengaluru.
- To issue clarification regarding submission of Statement of Financial Transaction (SFT) in Form No. 61A and "SFT Preliminary Response" in case of NIL transactions. The request was considered favourably and the CBDT.

- To extend the due date for submission of Statement of Financial Transaction (SFT) in Form No. 61A from 31st May, 2017 to 31st July, 2017. The said request was also considered favourably by the CBDT.
- Draft rules relating to valuation of unquoted equity share for the purposes of section 56 and section 50CA of the Income-tax Act, 1961.
- Draft ICDS on Real Estate transactions.
- To rectify/update the Java Utility of Form No 3CA-3CD and 3CB-3CD.
- Rectification/updation made in the Java Utility of Form No 3CA-3CD and 3CB-3CD pursuant to representation submitted to rectify the same.
- Clarification issued by CBDT regarding optional reporting of details of one foreign bank account by the non-residents in refund cases pursuant to representation submitted requesting to notify the change made in the utility of ITR Forms available on the e-filing portal by a suitable notification.
- To amend section 115JB of the Income-tax Act, 1961 and clarification sought in respect of taxability of waiver of Principal amount by banks/ NBFC.
- Extension of date for filing of Income Tax Returns.
- Request to issue clarification regarding date of applicability of Office Memorandum (F.No. 404/72/93-ITCC) dated 31.07.2017.
- Retroactive amendment recommended by MAT Ind-AS Committee in MAT provisions for Ind-AS compliant companies.
- Proposed adjustment u/s 143(1)(a) of Income-tax Act, 1961.
- To extend the due date of filing Income-tax returns for assessee mentioned under clause (a) of Explanation 2 to Section 139(1) and Tax Audit reports for the AY 2017-18 from 30th September, 2017 to 30th November, 2017.
- To issue clarifications regarding provisions of section 44AD.
- To issue clarification regarding the reporting requirement under Clause 31(c)(v) of Form No 3CD.
- On the draft notification for insertion of new rule 39A in the Income-tax Rules, 1962.
- To make appropriate changes in the utility of ITR Forms 2,3,5 & 7 as available on the e-filing portal
- To rectify/update the Java/ Excel Utility of ITR Form No. 2 for the AY 2017-18 and subsequent AYs.
- To issue clarification and make suitable changes in the ITR Forms 3, 5 and 6 to report the effect of Income Computation and Disclosure Standards (ICDS) on business income and income from other sources AND to provide sufficient space for reporting under clause 13(f) of Form 3CD.
- To extend the due date of filing Income-tax returns for assessee mentioned under clause (a) of Explanation 2 to Section 139(1) and Tax Audit report u/s 44AB for the AY 2017-18 from 31st October, 2017 to 30th November, 2017.
- Draft notification of amendment of Rule 17A and Form 10A of the Income-tax Rules, 1962.
- Direction /instruction for processing of return of income and issuance of consequent refund for Assessment Year ('AY') 2015-16 and AY 2016-17.
- To consider the issues in practical implication of Rule 37BA dealing with Credit for tax deducted at source for the purposes of section 199.
- "Income Computational and Disclosure Standards (ICDS)".
- To provide details of cases referred in Appreciation of third party (Chartered Accountant) Reporting in Assessment Proceedings- Report No. 32 of 2014.
- To consider various issues in ITR-4 (SUGAM), various issues in ITR-2 and final draft of ITR-3, 5, 6 and 7.
- Non-submission of details of financial statements in respect of section 44ADA cases in ITR 3 – Triggering notices under section 139(9) as defective return.
- To extend the due date of filing Belated and Revised Income Tax Returns for assessee in Raniganj and Asansol due to suspension of Internet Services.

- To consider issue(s) faced by assessee(s) w.r.t. application of Rule 115 & 115A of the Income-tax Rules, 1962.
- To increase number of benches of CIT (Exemptions) in the state of Uttar Pradesh.
- To amend CBDT instruction (F.No. DGIT(vig.)/HQ/SI/Appeals/2017-18/9959) dated 8th March, 2018 with respect to power of CCIT to monitor orders issued being issued by the CIT (A).
- On forms 3CA/ 3CB/ 3CD.
- To expedite the release of ITR utilities for AY 2018-19 (only relating to ITR 1 and 4 released so far).
- To expedite release of new tax audit forms (3CA, 3CB & 3CD) and its utilities for AY 2018-19.
- Notification No 23/2018, dated 24th May, 2018 amending Rule 11UA omitting reference to term "accountant", thereby making Chartered Accountants ineligible to determine the FMV of unquoted equity shares as per the Discounted Free Cash Flow Method.
- Concerns of ICAI in reference to the ICAI letter No. G:142:05:2018 dated 23.05.2018 submitted by the Institute of Cost Accountants of India to amend the definition of "Accountant" in the Explanation appended to section 288(2) of the Income-tax Act, 1961.

#### **Meetings with the Ministry/CBDT**

- Meetings with various officials of the Department, including CBDT Chairman, Joint Secretary (TPL-II).
- Meeting of ITR Forms (AY 2018-19) Review Committee and submission of suggestions on ITR Forms to be notified for AY 2018-19.
- 3<sup>rd</sup> meeting of the ITR Form (AY 18-19) Review Committee on 26.02.2018.
- Meetings with Shri Harish Kumar, Pr. DGIT (Systems).

#### **Activities relating to Union Budget**

- Submission of Pre-Budget Memorandum, 2018.
- Budget Viewing Workshop on 1st February 2018.
- LIVE Webcast on tax proposals of Union Budget, 2017 on 1st February 2018.
- ICAI Conclave on Union Budget 2017 on 2nd February 2018.
- Submission of Post-Budget Memoranda, 2018.

#### **Other Initiatives**

- The Committee organized 6 live webcast on various topics such as Statement of Financial Transactions (SFT) in Form 61A, Overview of Income Computation and Disclosure Standards, Capacity Building Measures of Practitioners with specific reference to Tax Audit Report, Key amendments by Finance Act, 2018 and Recent Developments in Electronic Systems, E-compliances -Issues and Way Forward in Delhi and many members were attended this live webcast and get updated their knowledge.
- Inputs on the contents of training programme conducted at NADT for trainee IRS officers in response to the letter received from Human Resource Development, CBDT, E and other issues in TDS and TCS Compliances and Propagation of Operation Clean Money.
- Release of New Publication 'Technical Guide on Income Computation and Disclosure Standards'.
- Training Programme on Ind AS and ICDS for Officers of Income Tax Department of Faridabad and Gurugram.
- Review of Citizen's Charter 2014 – Letter from Directorate of Income Tax.
- Letter to FM requesting to nominate ICAI representative in the task force constituted for drafting a new Direct Tax Legislation.

#### **Seminars/Conferences and Tax Awareness Programmes/Workshops**

- DTC organized 30 seminars/ conferences and tax awareness programmes/workshops/lectures/ meetings during the year.



## 5.9 Committee on Economic, Commercial Laws & Economic Advisory (CECL&EA)

**Representations to Various Government Authorities/Regulators:** CECL&EA made representations to various concerned authorities. Views on *Trade with Association of South East Asian Nations (ASEAN)* were submitted to the Rajya Sabha Secretariat. Inputs were submitted to the MCA in the matter regarding allowing foreign Accounting and Audit firms to practice and operate from SEZ/ International Financial Services Centre, and on the draft note for Cabinet on *Action Plan for Champion Sectors in Services*. Inputs with respect to request made by China in seeking market access in *Accounting & Book Keeping Services (CPC 862)* and on 16<sup>th</sup> Session of India-Switzerland Joint Economic Commission (JEC) have been submitted to Ministry of Commerce & Industry. A detailed concept paper regarding Inter Ministerial stakeholder consultations for India Canada Services negotiations has been submitted to the Ministry of Commerce & Industry. Representation was submitted to Shri Hardeep Singh Puri, Minister of State (Independent Charge) for Urban Development, in the matter regarding Circular No 2/2017 dated 31-05-2017 issued by MahaRERA and Circular No 5/2017 dated 26-09-2017 issued by GujRERA. Representations were also submitted to the Chairperson GujRERA in the matter of inconsistency in the provisions of Regulation 3B of Gujarat Real Estate Regulatory Authority (General) Regulations, 2017 vis-à-vis the Gujarat Real Estate (Regulation and Development) (General) Rules, 2017.

**International Appointments and International Meetings/Conclaves:** ICAI representatives met with the officials of National Quality Framework (NQF) in Bahrain to discuss the matter relating to the recognition of the CA Course as International Professional Qualification in Bahrain in order to improve employment opportunities for the CA members. Further, a Seminar on *Strengthening the Accountancy Profession Worldwide- Making India a Global Investment Destination* was also organized in Bahrain.

**Study Groups:** RERA Study group was constituted for studying and compiling the issues and probable solutions in respect of RERA Law, to finalize the publication titled *Certifications and Special Purpose Audit under RERA by Chartered Accountants*, for exploring the possibility/ feasibility of conducting certificate course/ workshop/ webcast, making representations to the concerned suggesting suitable amendments/modifications, wherever deemed fit.

**Workshops/ Seminars/ Conferences/ Webcasts:** Awareness on various Commercial & Economic laws including RERA and taxation issues, Appellate Proceedings at CIT-A & ITAT, taxation of deposited demonetized currency notes, FDI norms and NRI investments in real estates and compliance management for NBFCs, charitable trusts, Hindu Succession, HUF, LLP, MF, GST, etc., was created among members by way of webcasts, workshops, seminars, conferences and faculty development programmes (FDPs), which were organised during the period.

**Certificate Course on Anti-Money laundering Laws:** The Committee successfully conducted four batches of *Certificate Course on Anti-Money laundering Laws* at various locations across the country. Eminent faculties from the Government departments, banks, legal fraternity and members from industry and practice addressed the participants.

### Certificate Course on Arbitration, Mediation & Conciliation

The pilot batch of the revised 10-day *Certificate Course on Arbitration, Mediation & Conciliation* was successfully conducted in November-December 2017 in Mumbai. Eminent faculties from legal fraternity, retired Judges and members from industry and practice addressed the participants.

## 5.10 Digital Accounting and Assurance Board

Strengthening the role of chartered accountants as information governance, control, security and audit professionals, ICAI in the year 2018 merged Committee on Information Technology (CIT) with Digital Accounting and Assurance Board (DAAB). DAAB is developing knowledge base through position papers and articles on issues related to impact of technology on accounting and assurance. Research on potential impact of Artificial Intelligence, Robotics Process Automation, Blockchain, Cloud Computing and Big Data on accounting and assurance is being undertaken to develop concept papers. The purpose is to help chartered accountants expand their knowledge and enhance their skills in new areas of digital era. DAAB's agenda also includes engaging with regulators and standard setters to assess how technology might impact the continuing effectiveness and relevance of financial regulations and accounting standards.

DAAB released various publications such as *Digital Competency Maturity Model (DCMM) for Professional Accounting Firms – Version 1.0*, *Digital Era and the Chartered Accountancy Profession – Survey Report 2017*, *Early Signals of Fraud in Banking Sector*, etc., during this year. SAFA Board, on ICAI's recommendations, has adopted to promote the DCMM of ICAI amongst its member bodies. European Federation of Accountants and Auditors (EFAA) too has appreciated the Model, seeking to collaborate with ICAI to develop its next Version, for its propagation in Europe.

**Post-Qualification Course on Information Systems Audit (DISA):** The Board conducted around 120 batches of *Post-Qualification Course on Information Systems Audit* from 1<sup>st</sup> April 2017 to 31<sup>st</sup> March 2018. Since its inception in 2001, around 23,000 members have qualified this Course in the 11308 pan-India batches conducted so far. The Board is also conducting the *Post-Qualification Course on Information Systems Audit* for the members of Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka and Nepal. DISA has been recognized by the regulators, and RBI has given weightage to the members who have qualified DISA in empanelment for bank audit.

ISA Faculty Meet are conducted at regular intervals for charting a strategy for identifying changes that need to be implemented for further improvement in the post-qualification course on ISA, practical aspects of the ISA professional training, background material of the Course and so on. The Board is in the process of revamping the ISA Background Material to make the course more Practical Training Oriented.

**Certificate Course on Forensic Accounting and Fraud Detection :** In the year 2009, the Board recognizing the need for *forensic accounting and fraud detection* in the emerging economic scenario, launched *Certificate Course on Forensic Accounting and Fraud Detection*, and till date around 4,000 members have qualified this Certificate Course.

The Board had conducted Certificate Course on Forensic Accounting & Fraud Detection for the employees of Hindustan Petroleum Corporation Limited from 19<sup>th</sup>-25<sup>th</sup> February 2018 in Pune. It also conducted this Course for the employees of Indian Oil Corporation Limited on 18<sup>th</sup>-24<sup>th</sup> June 2018.

**Forensic Lab (Data Analytics lab of ICAI):** DAAB has launched 6 Forensic Labs (Data Analytics labs), Centre of Excellence, Hyderabad, ICAI Bhawan, Kanpur, Noida, Kolkata, Chennai and Chandigarh where hands-on training on CAAT tools is given to the members. Till date 15 batches have been conducted at these DA Labs.

#### **Annual Conference, Training Programmes, Seminars, Workshops, Summit, Webinars, etc., on Fraud and Forensic**

DAAB has organized various programmes, e.g. conferences, training programmes, seminars, etc., on fraud and forensic, forensic audit, time detection of fraud and forensic investigation for banking employees, information technology in GST, data analytic tools, big data analytics and artificial intelligence in assurance services, training, DISA Refresher Webcast for DISA Assessment Test, webinars on *Digitization and Finance Leaders*, etc., in Ahmedabad, Gujarat, Delhi, Ludhiana, Agra, Bhilai, Lucknow, Kanpur, Varanasi, Guwahati, Indore, Ernakulam, Ranchi, Surat, Bhubaneswar, Noida, Sivakasi, Udaipur and Dehradun, wherein more than 500 to 600 participants attended these programmes from industry, profession and other sectors.

**Knowledge Management Videos:** DAAB has released four knowledge management videos – *Unlocking the Power of Data Analytics for Chartered Accountants*, *Technology Transforming Audit*, *Challenges of a CFO in a Digital Age* and *Reinventing Business in the Digital Age*.

#### **5.11 Ethical Standards Board (ESB)**

For formulation of ethical standards for members and issuing guidance, the Council of ICAI constituted Ethical Standard Committee (Now Ethical Standards Board) in December, 1975.

The mission of the Board is to work towards evolving a dynamic and contemporary Code of Ethics and ethical behaviour for members while retaining the long cherished ideals of 'excellence, independence, integrity' as also to protect the dignity and interests of the members.

**Activities/ Initiatives:** ESB has issued various publications, such as *Code of Ethics*, *FAQs on Ethical Issues* and *Guidance Note on Independence of Auditors*. It advises members on their professional dilemmas in day-to-day affairs. Members can reach the Board vide Ethics Help Desk, E-Sahayataa, and

through emails and letters. ESB is also present on [www.icaai.org](http://www.icaai.org) as well as on an independent portal, i.e. [www.esb.icaai.org](http://www.esb.icaai.org).

The Board had in January, 2017 submitted its recommendations on revision of ICAI Code of Ethics, based on International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA), 2016 before the Council. However, meanwhile IESBA has now issued 2018 edition of its Code of Ethics, which has wide range of structural and substantive changes over the 2016 Code. Accordingly, Council has referred the issue of revision of Code of Ethics back to Ethical Standards Board to revise the ICAI Code of Ethics as per 2018 IESBA Code. The Ethical Standards Board has considered, and accordingly submitted its recommendations on revision of Code of Ethics as per the IESBA Code of Ethics, 2018 edition. An Announcement was issued on 15<sup>th</sup> November 2017 on frequently-asked issues relating to GST.

**Some Important Decisions/Clarifications:** A member in practice may accept the position of Chairman or Secretary of a Trust, provided, the said role does not involve participation in any other business or occupation.

A member in practice is not permitted to be part of Association of persons, whether or not comprising of other professionals, since as per the provisions of Chartered Accountants Act, 1949, only Firms and LLPs are the two modes of practice, apart from practicing in individual capacity.

A member in practice can be a honorary editor in a E-Magazine, provided it is ensured by the member that it does not amount to "other business/occupation" in any manner.

It is not permissible for a Chartered Accountant and a Company Secretary to have a common visiting card, with their details printed on the two sides of the card.

A member in practice may be an equity research adviser, but he cannot publish retail report as it would amount to other business or occupation.

A member in practice can hold the position of whole time Director or employee in a company, in a Management Consultancy Company registered with ICAI. In case he wants to be a Director otherwise than in such Company, he will have to seek prior and specific permission of the Council for the same (wherein he will not have attestation rights).

A member in practice being a non-executive director in a company, or a Firm where he is a partner, should not accept the appointment as a statutory auditor of a Company which is a joint venture of the original Company, as it would impact independence.

A member in practice can provide services through kiosk if the services provided are professional activities of a practicing chartered accountant, permitted under the Chartered Accountants Act, 1949.

It is not permissible for a member in practice to engage in selling domain names owned by him for earning Royalty, as it would amount to "other business/occupation".

A member in service may take E-return registration in his name if it does not conflict with employment obligation. However, if the member does not hold CoP, he cannot certify the return.

A member empanelled as IP (Insolvency Professional) can write the degree "Insolvency Professional" in his visiting cards, letter heads and other communication as this is a title recognized by the Central Government in terms of Clause (7) of Part –I of First Schedule to The Chartered Accountants Act, 1949. All other nomenclatures or designations including membership of any IPA are not allowed.

A member holding accountancy degree with another accountancy body outside India, may engage in non-audit practice outside India. However, he cannot mention the fact of holding such degree, whether in addition or substitution of "CA", except in case where the said degree has been recognized by the Council.

It is permitted for two or more members to collectively have joint training session for their clients on GST, and share the fees collected from the clients thereof.

It is not permissible for a Firm of Chartered Accountants to sponsor a Conference. However, an individual member in practice can be a knowledge partner to such conference.

It is not permissible to mention catchwords/catchphrases on a Firm's website, Letter heads or visiting cards in view of the provisions of Clauses (6) and (7) of Part-I of the First Schedule to The Chartered Accountants Act, 1949.

A member in practice can act as Authorized Representative of a Foreign Company, provided he is not the auditor of the said Company, and there is no any other conflict of interest.

It is not permissible for a member in practice being Director *Simplicitor* in a Company to sign ROC Forms of the Company as it is a direct conflict of role.

It is not permissible for a member in practice to send WhatsApp messages to make people aware about his new practice, and mention the services provided therein.

## **5.12 Expert Advisory Committee (EAC)**

### **Expert Opinions**

An entity's financial statements provide vital information about its financial health. These statements are compiled based on day-to-day bookkeeping that tracks funds flowing in and out of the business. For any business, the importance of accurate financial statements cannot be underestimated. In the process of financial reporting, the professionals are often posed with peculiar situations, where implementation of accounting principles requires interpretation with a high level of expertise, particularly in the evolving situation of implementation of highly principle based Indian Accounting Standards (Ind AS). To tackle with these situations, the Council of the Institute constituted the Expert Advisory Committee in 1975 for answering the queries of the members of the Institute on wide ranging issues relating to accounting and/or auditing principles and allied matters. However, the Committee does not respond to queries which involve only legal interpretation of various enactments. It also does not answer queries which concern a matter which is pending before the Disciplinary Committee of the Institute, any court of law, the Income-tax authorities or any other appropriate department of the Government. The Committee answers the queries in accordance with Advisory Service Rules, which have been revised during the period with regard to fees charged from the members for opinions. The said rules are available on the web-site of the ICAI, at its hyperlink, [http://www.icai.org/new\\_category.html?c\\_id=142](http://www.icai.org/new_category.html?c_id=142) or can be obtained from the Institute's Head Office at New Delhi.

Over the period, the role of EAC has been well-recognised for its independent and objective opinions on the queries raised by private- and public-sector enterprises, members-in-industry and -practice, as well as by regulatory and government authorities, such as C&AG of India, MCA, etc. Opinions issued by the Expert Advisory Committee are based on the given facts and circumstances of the query, the relevant legal position and the accounting/auditing standards, guidance notes, and other pronouncements of the Institute prevailing on the date the Committee finalises the particular opinion. The date of finalisation of the opinion is indicated with each opinion. The opinion must, therefore, be read and applied in the light of subsequent developments and/or amendments in the applicable legal position and accounting/auditing principles.

During the specified period, i.e. from 1<sup>st</sup> April 2017 to 30<sup>th</sup> June 2018, the Committee finalised **39** opinions received from the members of the Institute and **5** opinions on different accounting issues received from the Regulators/ Government authorities.

The opinions issued by the Committee are also published in the Compendium of Opinions. Till now, thirty-five volumes of the Compendium have been released for sale. A CD containing around 1400 opinions contained in all the thirty-five volumes of Compendium of Opinions with advanced and user friendly search facilities to locate the opinions on desired subject(s) and/or the opinions issued during a particular period has also been released, which is available with Volume XXXV of the Compendium of Opinions.

Some of the opinions finalised by the Committee which are of general professional interest, are published in every issue of the Institute's journal *The Chartered Accountant*. Recent opinions of the Committee are also hosted on the knowledge sharing page of the Committee on the website of the Institute.

### 5.13 Financial Reporting Review Board (FRRB)

In its endeavor to improve financial-reporting practices, ICAI through FRRB reviews the general-purpose financial statements of various enterprises and the auditors' report thereon. FRRB aims to maintain an environment of sound financial reporting and also to improve transparency in financial reporting and good governance, which is important to promote the investor confidence in audited financial statements. It also supports various regulators, viz. Qualified Audit Report Review Committee (QARC) of SEBI in review of significant audit qualifications of the listed enterprises, Election Commission of India in review of annual audited accounts of political parties and undertakes review of other cases as referred by the regulators time to time.

**Undertaken Review (Review of Cases Selected suo motto or as Special):** During this period, FRRB completed the review of 90 cases selected *suo motto* or as special cases. It includes the review of financial statements of enterprises which were identified by MCA as Shell Companies and various political parties, which have been undertaken by the Board proactively.

**Contribution to Society – Commitment to Nation:** FRRB plays a paramount role in improving the financial-reporting practices prevailing in India. Regulators are approaching it to perform various assignments for it. Significant assignments that were performed by FRRB towards partner-in-nation-building are:

- Election Commission of India appreciated the FRRB's role in reviewing annual audited accounts of various political parties and also holding a workshop for auditors of political parties in previous years. It has again requested the FRRB to undertake review of the annual audited accounts of at least six national political parties and recognized parties with income/ expenditure exceeding Rs. 10 crore. Accordingly, FRRB has undertaken the review of 21 annual audited accounts of political parties (for the year 2013-14 and 2014-15) and considered all these cases during this period. Election Commission of India has further requested ICAI to undertake the review of annual audited accounts of various political parties pertaining to financial year 2016-17 too. Accordingly, FRRB has undertaken 8 annual audited accounts of various political parties with income/ expenditure exceeding Rs. 10 crore.
- In its endeavour to support the regulators as well as to bridge the gap between regulators and members, FRRB is constantly reviewing the cases on reference as received from MCA, SEBI, ECI or other regulators.

#### Shell Companies Review Group

As suo motto proactive measure and in view of larger public interest, the Council has constituted a Shell Companies Review Group (SCRG) under Financial Reporting Review Board (FRRB) of the Institute. The SCRG will be undertaking the review of shell companies on references received from Regulatory / Government bodies like 'Task Force on Shell Companies' of GOI. The SCRG will review and refer the shell companies to FRRB, for detailed review of the general purpose financial statements and Auditor's report thereon of shell companies with a view to determine, to the extent possible:

- a) compliance with the generally accepted accounting principles in the preparation and presentation of financial statements;
- b) compliance with the disclosure requirements prescribed by regulatory bodies, statutes and rules and regulations relevant to the enterprise; and
- c) compliance with the reporting obligations of the auditor.

FRRB is functioning quiet effectively and independently to the complete satisfaction of stakeholders especially the regulatory bodies. Its services have been acclaimed by SEBI, Election Commission of India, etc., and it has continued its journey in pursuit of excellence, independence and integrity.

**Third Volume of 'A Study on Compliance of Financial Reporting Requirements':** Third volume of the publication, *A Study on Compliance of Financial Reporting Requirements*, was released on the Annual Day 2018 to enhance the knowledge of preparers and auditors of the financial statements. It contains pertinent observations of FRRB in the context of applicable Accounting / Auditing Standards and Guidance Notes as well as other relevant laws and statutes.

**Empowering Members and Capacity Building:** 2-Day Residential Workshop has been organized at the Centre of Excellence in Hyderabad on 21<sup>st</sup>-22<sup>nd</sup> November 2017, to guide the technical reviewers (TRs) empanelled with the FRRB and the members of Financial Reporting Review Groups (FRRGs) enhance their review skills of Financial Statements and to have direct interaction with the FRRB to improve the quality of review.

To enhance the members' knowledge as well as to update them with the changes made in financial reporting framework, two-day National Conference was organised in Trivandrum and an Awareness Programme on "Financial Reporting Practices & Expectation from Auditor in Today's Changing Environment" was organized by the FRRB on 12<sup>th</sup> May 2018.

#### 5.14 Indirect Taxes Committee (IDTC)

**Input/ Support to the Government:** IDTC has submitted the following inputs/ suggestions to the Government:

- Comprehensive suggestions on GST Law in 7 different stages, out of which, 135 suggestions have been accepted by them.
- Suggestions on Anti-Profitteering clause under GST before the Chairman, National Anti-profitteering Authority under GST.
- Presentation before Hon'ble Union Finance Minister on "GST Implementation issues, out of which many of the suggestions submitted have been accepted by the GST Council at its meeting held on 6<sup>th</sup> Oct, 2017.
- Presentation on "important issues under" before the Advisory Group on GST formed by GST Council.
- Presentation to facilitate ease of doing business in India before Ministry of Commerce & Industry
- GST Audit Report (Form 9C) and Statement of Particulars (Form GSTR 9D).
- Simplified User Friendly Model (SUF) on return filing & enabling of credit suggesting that based on the summary details of invoices uploaded by supplier, credit of input be allowed to the Buyer.
- Pre & Post Budget Memorandum, 2018 relating to Indirect Taxes.
- Support extended to Goods and Services Tax Network (GSTN): On the request being received, following supports were extended:
  - a. Suggestions to Govt. on the GST Annual Return Form 9/9A/9B in response to a request received from the office of *Goods Services Tax Network*.
  - b. Presentation on matching of input in GST Form.
  - c. Nomination of 23 members for testing of return form GSTR 1, GSTR-2A.
  - d. Nomination of four senior experts for a Committee to be constituted by GSTN for evaluating and finalising proposal for its GST accounting and billing software.

**Representation to the Government:** The Committee submitted representation to the Government on the following matters:

- Issues in filing of GSTR-1 & Enabling Transitional Credit to assessee.
- Resolving issues related to TRANS 1 and extending date of its filing.
- Allowing credit of KKC under GST.
- Input Tax Credit should not be denied to buyer for mistake of seller.
- Representation for hosting Judgement of Advance Ruling on the Website.
- Issue pertaining to Re-insurance exemption.
- Nominating ICAI in drafting Committee of GST.
- Allowing CA. Inter to register as GST Practitioner.
- Extending time limit for submitting the declaration under Rule 118, 119 and 120.
- Extending date of filing GST Return form.

#### Publication – A research Initiatives

IDTC brought out/ revised the following publications on GST/ Service Tax/ CST/ Customs/ FTP:

- Background Material on GST Acts and Rules – 6<sup>th</sup> Edition – May 2018 (revised thrice).
- E-Publication on E-way bill – 3<sup>rd</sup> Edition – July 2018 (New & revised twice).
- E-Handbook on GST Amendments – 1<sup>st</sup> Edition – June 2018.
- FAQ and MCQ on GST– 3<sup>rd</sup> Edition – January 2018 (New & revised twice).

- Bare Law on GST Act(s) and Rule(s) – 2<sup>nd</sup> Edition - July 2017 (*New & revised*).
- Simplified GST Guide for Manufacturer – 2<sup>nd</sup> Edition – August 2017.
- Handbook on GST Service Providers – 1<sup>st</sup> Edition – November 2017.
- Background Material on Exempted Services under GST – 1<sup>st</sup> Edition – January 2018.
- Study Paper on Taxation of E-Commerce under GST - 2<sup>nd</sup> Edition – August 2017.
- E-Handbook on Job-work under GST – 2<sup>nd</sup> Edition – June 2018.
- E-Book on how to get registered under GST - 1<sup>st</sup> Edition – July 2017.
- Background Material on Seamless Credit - 1<sup>st</sup> Edition – October 2017.
- Compliances of Service Tax/GST in Banking Sector – 5<sup>th</sup> Edition – April 2018.
- E-Guide on CST- a new publication – 1<sup>st</sup> Edition - November 2017.
- Study Paper on Unjust Enrichment - 1<sup>st</sup> Edition - February 2017.
- Background Material on Customs and FTP - 2<sup>nd</sup> Edition – April 2018.

### International Achievements

**VAT in Dubai:** VAT has been implemented in UAE from 1<sup>st</sup> January 2018. With a view to support the members there, IDTC took following initiatives:

- Develop a BGM on UAE VAT (3 editions).
- Organising Certificate Course on UAE VAT and various conferences and programme.
- Organised series of LIVE Webcasts on UAE VAT.
- Hosted E-learning on UAE VAT.
- Identification and Training of new speakers on UAE VAT.
- Hosted various Article on UAE VAT on its website.
- Hosted Standardised PPT on UAE VAT.

### E-Initiatives

- **E-learning on GST:** Committee launched E-learning on GST through recorded video sessions covering almost the entire topics of GST on 7<sup>th</sup> July 2017. This was subscribed by 2013 stakeholders and benefited out of this initiative. Further, 2<sup>nd</sup> version of E-learning was launched for the members on 23<sup>rd</sup> January 2018. This has been subscribed by 612 subscribers till 30<sup>th</sup> July 2018.
- **Live Webcasts on Indirect Taxes:** The Committee organised Nine (9) webcasts on different aspects of GST as a nationwide outreach programme.
- **Paid LIVE Webcasts series on GST:** A series of live webcasts covering all topics of Cert. Course on GST was organised from 15<sup>th</sup> December 2017 to 14<sup>th</sup> January 2018 which was subscribed by 466 viewers, including members and general public.
- **Short video lectures on various concepts of GST:** Committee recorded 23 short video lectures on various concepts of GST including process of migration into GST and its benefits for benefits of the all the stakeholders.

**ICAI E-Newsletter on GST:** ICAI has been issuing its newsletter on GST from April, 2017. 17 issues so far have been released till June 2018.

**Standardised PPT on GST:** The Committee has developed Standardized PPT on GST and hosted on the website with a view to provide guidance to the faculty members and bring uniformity in the session of GST in the programme as well as proving a tool to members to learn GST through PPT.

**Training Programme for Government:** With a view to help the Government in capacity building and partner them in Nation Building, the Committee organised 19 training programmes on GST at various Commissionerates across the Country.

**Interactive Programme on GST for Trade Associations:** The committee has organised 21 interactive programmes on GST for trade association as part of its initiative towards partnering in nation building.

**Outreach Programme on GST in Association with Service Tax Commissionerate:** The Committee has organised 4 outreach programmes on GST as knowledge partner in association with Kolkata, Delhi Commissionerate (twice) and Ahmedabad.



**Awareness Programme for Members through Course, programme, workshop, conferences etc.**

- **Certificate Course on GST:** ICAI has launched its first batch of *Certificate Course on Goods and Services Tax (GST)* on 28<sup>th</sup> April 2017 with a view to provide specialized and updated knowledge of GST in a systematic manner. Since then, more than 70 batches of the Course have been organised across the Country, which have been attended by approx. 4000 members.
- **Certificate Course on GST – through Virtual Classes:** Considering the humongous demand for Certificate Course on GST by members, the Committee organised virtual classes for Certificate Course on GST from 9<sup>th</sup> June, 2017 to 30<sup>th</sup> June 2017 which was concurrently organised at 63 cities and attended by 1768 members. Further, 2<sup>nd</sup> Batch of the Course was organised from 15<sup>th</sup> December 2017 to 14<sup>th</sup> January 2018 at 21 Centres which was attended by 211 members.
- **Programmes, Seminars and Conferences:** During the period, 110 programmes, seminars, conferences and workshops etc. have been organised by the Committee.

**Identification and Training of new speakers on GST:** 200 new speakers have been identified and trained on GST Law making the expert pool of over 800 faculties across India.

**Formation of Study Group for helping State Government in smooth implementation of GST:**

Committee has formed nineteen (19) State level Study Group on GST for extending its support to the State Government in smooth implementation of GST.

**Indirect Taxes Updates including legal update-** With a view to update the members, summary of significant notifications, circulars and other important development in the area of Indirect Taxes, including GST are regularly been circulated among the IDT NET registered members on the website of the Committee [www.idtc.icaai.org](http://www.idtc.icaai.org)

Further, the Committee has recently started sending Legal Update on Indirect Taxes to the members registered on its website, Last one (Legal Update 3) being sent on 30<sup>th</sup> June 2018.

**5.15 Internal Audit Standards Board**

In view of changing times, the Internal Audit Standards Board, established as Committee on Internal Audit in February 2004, revisited its *terms of reference* this year and chose to refine it by:

- expanding its scope beyond India and making it worldwide,
- focusing on, not just existing but emerging practices and issues,
- acknowledging guidance required for specific industries as well as other areas; and
- formalizing knowledge dissemination in new electronic form as well as of higher calibre through a Diploma Program.

An overview of the important initiatives of the Board during April 2017-June 2018 is:

**Making Standards on Internal Audit (SIAs) Mandatory in a Passed Manner:** Internal audit, to be effective, needs to be conducted in accordance with a set of recognized Standards. Till date, the Institute has issued 18 Standards on internal audit, to increase the overall credibility, consistency, clarity and comparability of the work performed by the internal auditors. The Board has initiated the process of revising SIAs and making them mandatory for certain class of companies in a phased manner.

**Revised Definition of "Internal Audit":** The Board had issued Exposure Draft of Revised Definition of "Internal Audit", including an explanation which provides additional clarity on the key terms used in the proposed definition. Revised definition of internal audit as approved by the Council at its 364<sup>th</sup> meeting held in March 2018 has been included as part of the *Revised Framework Governing Internal Audit*.

**Revised Preface to Framework and Standards on Internal Audit:** Preface to the Framework and Standards on Internal Audit facilitates understanding of the scope and authority of the pronouncements of the Board under the authority of the Council of the Institute of Chartered Accountants of India. The Council, at its 364<sup>th</sup> meeting held in March 2018 approved the revised "*Preface to the Framework and Standards on Internal Audit*" while leaving the effective date open for the time being.

**Revised Framework Governing Internal Audit:** Overall objective of the framework is to promote professionalism in the conduct of an internal audit assignment by the internal auditor and to ensure basic minimum standards of quality worthy of the qualification of the internal auditor and to promote the



credibility of the internal audit report issued. All activities of an internal audit life cycle, e.g. scoping and planning, gathering and review of evidence, fieldwork testing, physical observations, documentation, using work of other experts, evaluating controls and systems, communication, and reporting of results, are included in the Framework. The Council, at its 364<sup>th</sup> meeting held in March 2018 approved the revised *Framework Governing Internal Audit* leaving the effective date open for the time-being.

**Basic Principles of Internal Audit:** For internal audit to be effective, certain basic principles are critical and essential. These principles are one of the four key components of the Framework Governing Internal Audit, viz. Key Concepts, Standards on Internal Audit and Guidance. This document includes ten basic principles, which are fundamental to conduct an internal audit, five of which establish the credibility of internal auditor and the remaining five outline the elements essential for the performance of internal audit activities.

**Exposure Drafts of Standards on Internal Audit (SIAs):** The Board had issued Exposure Drafts of following Standards on Internal Audit, which are now in finalization stage.

- **SIA, Conducting Overall Internal Audit Planning:** This deals with internal auditor's responsibility to prepare the overall internal audit plan, also referred to as *annual internal audit (engagement) plan*.
- **SIA, Planning an Internal Audit Assignment:** This covers the second level, i.e. planning the *internal audit assignment*, for a particular part of the entity.
- **SIA, Internal Audit Evidence:** This explains certain key requirements in the process of collection, retention and subsequent review of appropriate and reliable internal audit evidence.
- **SIA, Internal Audit Documentation:** This explains certain key requirements in the process of collection, preparation, retention and subsequent review of complete and sufficient internal audit documentation.
- **SIA, Managing the Internal Audit Function:** This deals with the responsibility of Chief Internal Auditor or a person who has been assigned to coordinate and manage the overall performance of activities related to internal audit.

**Industry-Specific Internal Audit Guides -** During 2017-18, the Board has undertaken the following projects:

- **Review and revision of Guidelines on Internal Audit-Cement Industry:** The Board has decided to revise the *Guidelines on Internal Audit-Cement Industry*, as issued by the Research Committee of ICAI in 1994 to include all the changes that have taken place in the cement industry and regulatory environment thereof, and issue guidance to the members regarding the audit procedures unique to the cement industry.
- **Review and revision of Technical Guide on Internal Audit of Treasury Functions in Banks:** The Board has undertaken the project to review and revise the *Technical Guide on Internal Audit of Treasury Functions in Banks* to incorporate the circulars issued by RBI and ICAI pronouncements related to treasury and investment managements in the banks.
- **Review and revision of Technical Guide on Risk Based Internal Audit in Banks:** Considering the latest developments in banking industry and circulars as issued by RBI, the Internal Audit Standards Board has undertaken a project to review and revise the *Technical Guide on Risk Based Internal Audit in Banks*, which had originally been issued in November 2005.
- **Review and revision of Technical Guide on Internal Audit of Retail Industry:** In view of the developments in retail industry and regulatory environment thereof, the Board has undertaken a project to review and revise the *Technical Guide on Internal Audit of Retail Industry*, which had originally been issued in February 2011.

**E-Learning of Certificate Course on Concurrent Audit of Banks:** To provide easy access to the members, the Internal Audit Standards Board has taken up the project of developing the e-learning modules of *Certificate Course on Concurrent Audit of Banks*, which would include quizzes and case studies on the practical aspects of concurrent audit.

**Virtual Certificate Course on Concurrent Audit on Banks:** The Board has decided to conduct *Virtual Certificate Course on Concurrent Audit of Banks* for the members.

**International Conference of Internal Auditors in USA:** On behalf of ICAI, the Board attended the IIA International Conference held on 23<sup>rd</sup>-26<sup>th</sup> July 2017 in Sydney, which also provided an opportunity to the Institute to network and exchange information on the practice of internal audit in the larger interests of profession.

### Certificate Courses

- **Certificate Course on Concurrent Audit of Banks:** The Board conducts *Certificate Course on Concurrent Audit of Banks* to provide an opportunity to the members to understand the intricacies of concurrent audit of banks. During the period, the Board has conducted around 45 batches of the Certificate Course at various locations in the country and about 1,250 members have successfully qualified the Course.
- **Certificate Course on Internal Audit:** The Board has revised the course structure of the *Certificate Course on Internal Audit*, revamping it completely by including new topics and heavy dose of information technology.

The main thrust of the course is to educate the participants on the theory and concepts of internal audit, especially its linkage with risk management and governance concepts, provide practical exposure to the design and conduct of internal audit, especially through the deployment of information technology and specialised tools, understand the current best practices and the way to deploy these to mitigate risks and address business challenges, and help the members acquire all the skills and knowledge required to conduct highly professional, best-in-class internal audit, which not just provides basic assurance but seeks to add tangible value to their organisations. The Council has approved the revised curriculum of *Certificate Course on Internal Audit* recently and the Board is in the process finalizing the modalities. It hopes to launch the batches of the said Certificate Course in the metro cities of India.

**Programmes, Seminars, Conferences and Webinars for Awareness on Internal Audit:** With a view to provide platform for dissemination of knowledge among members, the Board has organized various workshops, seminars, training programmes, interactive meets for the benefits of members in various locations including Mumbai, New Delhi, Jamshedpur, Nashik, Ahmedabad, Vasai, Aurangabad, Belgaum, Baroda, Bhopal and Bhubaneswar. The Board has also conducted webinars on *Internal Audit—Building Effective Leadership and Performance through Competence*, and *Making Concurrent Audit More Effective and Relevant* during this period.

### 5.16 Committee on International Taxation

**Representations/Interactions with Government:** The Committee submitted representations to various Ministries like Pre- and Post-Budget Memoranda, Guidelines on Place of Effective Management, suggestions on draft notifications issued by CBDT in view of the provisions of Section 115JH of the Income-tax Act, Draft notification laying down the guidelines for maintaining and furnishing of transfer pricing documentation, CBDT for issuance of refund to foreign companies not having bank account in India, requested to enable issuance of NIL TDS Certificate to Indian Branch of foreign reinsurers under section 195(3) and requested to CBDT to lay down a procedure where the assessee be allowed to surrender his/her PAN provided he has no taxable income and also no litigation is pending with regard to that specific PAN, and so on.

**Conferences/Seminars/Workshops/Webcast on International Taxation:** The Committee organized many conferences, seminars, workshops, live webcasts, etc., on GAAR, POEM Guidelines, Multilateral Instruments – Impact on India's tax treaties, Safe Harbour Rules, Report under section 92E of the Income tax Act, 1961- Practical issues and challenges, Tax proposals of Union Budget 2018, and Union Budget 2018-19 during the year, updating the members' knowledge and understanding.

**Post-Qualification Diploma in International Taxation:** The Committee has so far conducted nine batches of *Diploma Course in International Taxation* at Pune, Hyderabad, Chennai, New Delhi, Thane, Mumbai, Ahmedabad and Bangalore. Approximate 550 members have completed the Course.

**Other Initiatives:** The Committee had released four editions of e-newsletter on International Taxation during the specified period. Transition scheme for the registrants of Certificate course on International Taxation who want to pursue Diploma in International Taxation was hosted on the ICAI website. Through this scheme, members are being imparted additional training by e-learning. The Committee had revised two e-learning courses on the e-learning portal of ICAI—*An Overview of International Taxation* and *An Overview of Transfer Pricing*. Revision of various publications was undertaken and the list included *Background Material of Diploma in International Tax Course*, *Guidance Note on Report under Section 92E of the Income-tax Act, 1961 (Transfer Pricing)*, *Technical Guide on Expatriates Taxation* and *Technical Guide on Royalty and Fees for Technical Services*.

### 5.17 Committee for Members in Industry & Business

The Council constituted the Committee for Professional Accountants in Business & Industry (CPABI) as its non-standing Committee in the year 2018-19. Constituted as CPABI, the Committee was rechristened by the Council as Committee for Members in Industry & Business. The Committee serves as a platform to facilitate synchronization between individual and organizational goals, create an interface between ICAI and industry, and recognize/ project Chartered Accountants beyond the traditional fields and as skilled and knowledgeable professionals on all aspects of functioning in company, business and commerce. The Committee seeks to encourage and enhance the close links between CAs in industry and business, and the Institute. To support this endeavor, the CMI&B has been organizing various knowledge-enriching conferences, industry meets and outreach programmes for the benefit of the members. Other important activities of CMI&B include providing placement opportunities to both young and experienced Chartered Accountants through campus placement programmes and ICAI job portal, organizing the prestigious ICAI Awards to recognize exemplary achievements of Chartered Accountants in business and industry, releasing general publications on the matters of professional interest, formation of CPE study circles, e-newsletter, etc., in the interests of members. Major activities that took place during 2017-18 are:

#### Campus Placement Programmes

**August-September 2017:** Held at 17 centres, 6,278 candidates registered, out of which 3,937 were shortlisted for interview. 105 organisations participated and offered jobs to 1,066 candidates. Highest salary (cost to company) offered was Rs. 20.00 lakh per annum as domestic posting.

**February-March 2018:** Held at 17 centres, 6029 candidates registered, out of which 5306 were shortlisted for interview. 130 organisations participated and offered job to 1473 candidates. Highest salary (cost to company) offered was Rs. 22.30 lakh per annum for domestic posting. CMI&B is committed to involve more companies to improve the present placement percentage.

**Jury Meet for ICAI Awards 2017:** CMI&B conducted two Jury Meets for the ICAI Awards, 2017: First, under the chairmanship of CA. B.R. Jaju, CFO, D.B. Power Ltd., 2<sup>nd</sup> Jury Meet was held on 12<sup>th</sup> January 2018 in Mumbai to finalise awardees under two categories, i.e. *CA Corporate Contributor* and *CA Professional Achiever*, and another Jury Meet was held on 8<sup>th</sup> January 2018 in Mumbai under the chairmanship of Shri Ajay Piramal, Chairman, Piramal Group, to finalise the awardees under remaining six categories.

**11<sup>th</sup> ICAI Awards, 2017:** ICAI Awards, 2017 was organized as an annual event to honour the exemplary work of Chartered Accountants in industry, who demonstrated excellence in profession, created value for their respective company's stakeholders, exemplary role models for other members, and outstanding contributors to society and those in civil services. Awards were presented under eight major categories, namely, CA Corporate Contributor, CA Professional Achiever, CA CFO, CA Business Leader, CA Entrepreneur, CA Lifetime Achievement, CA Exemplary Contributor to Society and CA Distinguished Contributor in Civil Services. More categories were added to cover the emerging areas. Lifetime Achievement remains the significant one. In total, 61 awards were given.

**Programmes Organised:** Various programmes, including seminars, live webcasts, one-day work, interactive meets, CFO Meets, etc., were organized on recent laws with special focus on GST, merger & acquisition, construction industry, accounting & financial reporting, building startups, etc., during this period.

**7 New CPE Study Circles for Members in Industry:** The Committee formed CPE Study Circles: Cyber City Phase II, Gurugram, CPE Study Circle of Macquarie Global Services Pvt. Ltd, for Members in Industry, Greater Noida CPE Study Circle of Honda Group Companies for Members in Industry of ICAI, Sadiq Nagar CPE Study Circle of IOCL for Members in Industry of ICAI, J K Gram CPE Study Circle, Faridabad CPE Study Circle, L&T MHPS Boilers, Brookfield CPE Study Circle of DXC Technology and Haddows Road CPE Study Circle of Sundaran Clayton Ltd.

**Highlights of Startup Summit and Idea Placement Programme:** The Committee fruitfully organized its mega event STARTUP SUMMIT and Idea Placement Programme in Mumbai on 29<sup>th</sup> June 2018 with participation of more than 400 attendees. Startup Summit, a multifaceted event, was organised with an objective to connect the startups and the investors, which was inaugurated by CA Sateesh Seth, Group MD, Reliance ADA Group, and CA. Sudhir Valia, CFO, Sun Pharma. To educate the members and provide them an insight into various related issues, the said summit included:

- Thought provoking Panel Discussions such as Panel Discussion with successful founders: Building for next billion Users, Panel Discussion with Top Angel Investors: Investing in People vs Investing in Ideas and Panel Discussion with Top Venture Capitalists: India Entrepreneurship: Scale, Substance & Sustainability.
- With Lightening talk and Fireside chat with Mr. Kishore Biyani.
- Experienced hats from industry and large corporates enlightened participants on their perspectives on starts ups, new or pain areas where they can contribute.
- Shark Tank Contest which was aimed to be a platform for promising business ideas to secure immediate funding for their business venture.
- Idea Placement Programme, where the pitching sessions were organised between more than 100 start ups and more than 50 investors.

**Snapshot of Career Ascent Programme:** CMI&B successfully organized Career Ascent programme on 29<sup>th</sup> June 2018 in Mumbai and in Chennai and New Delhi on 30<sup>th</sup> June 2018. This provided the platform for placement opportunities to experienced Chartered Accountants to secure career advancement in leading organizations. It was a customized campus placement programme for the chartered accountants who have three-year-plus experience of working in industry. 17 organisations participated offering 291 vacancies and more than 1000 candidates registered for this programme.

### 5.18 Peer Review Board (PRB)

Peer Review process is based on the principle of systematic monitoring of the procedures adopted and records maintained while carrying out audit & assurance services in the course of one's professional responsibility to ensure and sustain quality. The Peer Review mechanism of ICAI is directed towards maintenance as well as enhancement of quality of assurance services and to provide guidance to members to improve their performance and quality of professional work and adhere to various statutory & other regulatory requirements. The main objective of Peer Review is to ensure that in carrying out the assurance service assignment, the members of the Institute (a) comply with Technical, Professional and Ethical Standards as applicable including other regulatory requirements thereto and (b) have in place proper systems including documentation thereof, to amply demonstrate the quality of the assurance services. The Peer Review is conducted of a Practice Unit by an independent evaluator known as a Peer Reviewer.

The Planned effort of the Board coupled with effective performance of the Peer Reviewers not only inspired the practice Units to continually improve the quality of service that they render to the society at large, but also received recognition from various regulatory authorities.

The requirement in recognition of the Board's endeavor, of two regulators such as SEBI and C&AG are stated below:-

- The Securities & Exchange Board of India (SEBI), has made it mandatory with effect from April 1, 2010 for the listed entities, that limited review / statutory audit reports submitted to the concerned stock exchanges shall be given only by those auditors who have subjected themselves to peer review process and who hold a valid certificate issued by the 'Peer Review Board' of the Institute.
- The Comptroller and Auditor General of India (C&AG) has recognized Peer Review Board's work; now it seeks additional details from the Chartered Accountants firms about their Peer Review Status in the application form for allotment of audit for Public Sector Undertakings. Furthermore, from last few years the C&AG annually seeks details from ICAI of those firms which have been issued certificate by the Board.

In order to expedite the process of consideration of Peer Review reports received by the Board, it constitutes a Sub-Committee of the Board. The Sub-Committee has considered and issued 10,746 Peer Review Certificates till 30.06.2018, to Practice Units. Accordingly, the complete updated list of the Practice Units issued Peer Review Certificates has been uploaded on the web page of the Peer Review Board along with the date of issuance of the certificate.

To ensure that there is consistency and uniformity in carrying out reviews by the Reviewers, the Board imparts training to the Reviewers before assigning them the practice units for review. A total of 5821 reviewers have been trained so far. The training programme is aimed to understand the nuances and intricacies of the peer review process i.e. how to carry out peer review of a Practice Unit. Further the Board since its inception has organized 184 Peer Review Training Programmes across the country.

**Coverage of More Firms under Peer Review Process:** Peer Review Board as a regulator for review of assurance services of CA firm in India, has increased its scope of assurance services by coverage of more firms for peer review on the basis of specified new criteria. Also peer review has been started, for newly established firms. Cases of non-compliances observed in the Financial Statements which may not affect the True and Fair view but indicates negligence on the part of the auditor, are forwarded by the FRRB for peer review so that the quality control framework applied by the member may be ascertained. Such efforts are aimed to make the regulatory mechanism of the Institute more effective.

**Training Programmes:** On regular basis training programmes are being conducted by PRB. CA Members with minimum 10 years of experience in continuous practice as member are given requisite training before enlisting them as Reviewers.

- In order that there is a consistency and uniformity in carrying out reviews by the Reviewers, the Board imparts training to the Reviewers, before assigning them the practice units for review. This year the Board organized 20 Training Programmes at Hyderabad, Siligui, Patna, Ludhiana, Kolkata, Bhopal, Jamshedpur, Lucknow, Bangalore, Chennai, Pune, Ahmedabad, Varanasi, Vishakhapatnam, Noida, Allahabad, Kolkata, Guwahati, Ghaziabad & Vadodara and trained approximately 929 Peer Reviewers. With this total of 5821 reviewers have been trained so far.
- In view of regular changes in regulatory environment and technical standards and resultant need for Reviewers to be updated with developments it was decided by the Board that Peer Review Training will have validity of 5 years.

**Recent Developments:** Continuous efforts are being made to enhance the scope of peer review making it more effective and also to have more practicing units peer review. Towards this, the FAQ's has been revised by the Peer Review Board and Questionnaire on Peer Review sent to the Practice Units has also been revised in accordance with Standards on Quality Control. Annexure II to the Questionnaire has been made mandatory to be filled by Reviewer in case of Level 1 and Level 2 firms, for strengthening the Quality of Review. Services provided on Tender rendered by PU have been brought into the ambit of Peer Review assurance services and accordingly Peer Review Questionnaire and Annexure I to the final report has been revised. Peer Review Board has also released two new publications in February 2018 namely, Handbook on Advisories for Peer Reviewers and Handbook on Advisories for Practice Units.

### 5.19 Professional Development Committee (PDC)

Since its establishment in 1962, Professional Development Committee has been making vigorous efforts towards exploring ample opportunities for the members of the Institute in different sectors of the economy. Apart from exploring uncharted territories in the professional development, the Committee strives to strengthen the communication process with multitude of users across the different sections of the society and educate them about the role of Chartered Accountants. With a view to enhance skill sets of Chartered Accountants in the existing and new areas, it also organizes seminars, workshops on contemporary areas of interest.

### Software for Statutory Bank Branch Allotment

- The Institute has over the years expressed its concerns on the issue of appointment of auditors of Public Sector Banks by the Banks' Board themselves. The Management of Public Sector Banks do not

have any major ownership interest, this autonomy of appointment of auditors by management is fraught with risk in a very important and sensitive sector like banking.

- A number of meetings were held with the Ministry of Finance and Reserve Bank of India, wherein it had been proposed to design a web based application through which the Statutory Auditors of Public Sector Banks (PSBs) can be randomly mapped and associated with the vacancies available in the PSBs.
- Pursuant to the above meetings, RBI advised the banks that ICAI has developed a software for parameter based allocation of such audit amongst the eligible firms and further advised that banks may consider appointing SBAs centrally at Corporate Office with the help of such or other suitable software, customized or otherwise, to select audit firms in terms of the appointment policy formulated/approved by the Banks Board/ACB.
- Thereafter, the Committee has organized a Meet for the Bankers on 27<sup>th</sup> December 2017 at Mumbai to deliberate the working of said Software in detail and seek the inputs/ suggestions from the bankers. Representatives from IBA and 14 public-sector banks attended the said meet and shown their interest in the said software.
- For the allotment of statutory bank branch audit in the year 2017-18, three banks, namely *Dena Bank*, *Syndicate Bank* and *Oriental Bank of Commerce* have selected their statutory auditors using this software and post-implementation, all the three have appreciated and given a positive feedback to the PDC for its efforts in this regard.

**Coordination with RBI:** A meeting was held with Shri A. K. Misra, Executive Director, RBI on 13<sup>th</sup> March 2018 on the side-lines of the Conference for SCAs at Mumbai wherein the issues of mutual professional including increase in remuneration for statutory auditors were discussed. Subsequently, a letter in this regard was submitted.

**Increase in Auditors' Fee of RRBs:** Pursuant to the representations and meetings held with the officials of NABARD, NABARD has informed that Government of India has approved the proposal of revision in audit fee being paid to the auditors of head offices as well as Branch offices of RRBs for their various business levels have been increased from 25% to 40% as compared the fees being paid as per the existing circular of the year 2013.

**Coordination with NABARD:** The Committee is constantly co-ordinating with NABARD regarding norms of appointments of statutory auditors of RRBs wherein the Revised Guidelines for appointment of statutory central auditors and statutory branch auditors for RRBs from the year 2016-17 onwards was discussed. In this regard, the Chairman, PDC met with Shri Neeraj Verma, GM, NABARD on 26<sup>th</sup> April, 2018 to discuss the same and officials of NABARD assured that they would look into the same.

**Co-ordination with Office of C&AG of India:** The Committee is having a close coordination with the office of C&AG of India. Meetings were held with Shri Rajeev Mehrishi, C&AG of India, in October and November 2017 to discuss the issues of mutual professional interests.

**Coordination with Ministry of Rural Development:** The Committee had decided to propose to the Ministry that ICAI could support in improving the accounting and auditing system of MGNREGA Fund. It was felt that there is a need of better governance of the funds and its utilization so that there is discipline and transparency in maintenance of accounts. In this regard, various meetings were held with the officials of Ministry of Rural Development, wherein it was deliberated that there is a need of better governance of funds and its utilization.

### Unique Identification Number (UDIN)

- Many instances were brought to the notice of the Institute that financial statements and documents are being certified/ attested by third persons in lieu of our CA members. These statements mislead various authorities/ other stakeholders, who rely upon them.
- To address above, an innovative concept of Unique Document Identification Number (UDIN) has been conceptualized and developed by Professional Development Committee of ICAI which was also being demanded by various regulators. UDIN is a unique number, which will be generated for every document certified/ attested by the practising Chartered Accountants and registered with the UDIN portal, available at <https://udin.icai.org/>.
- The said portal offers the facility to various regulators/ banks/ authorities/ other stakeholders to check the authenticity of documents certified by the practicing Chartered Accountants, who have

registered on the said portal. It would help them in tracing the forged/ wrong documents prepared by any third person in the name of a Chartered Accountant, as a person other than Chartered Accountant will not be able to upload the documents on this portal.

**Meeting with Chief Vigilance Commissioner:** As a partner in nation building, the Institute is very concerned about the quality of work. In this regard, the President & Vice-President, ICAI along with The Chairman, Professional Development Committee met Shri K. V. Chowdary, Chief Vigilance Commissioner (CVC), and Shri T. M. Bhasin, Vigilance Commissioner. During the meeting, it was expressed that the present practice of evaluating tenders for awarding the work for professional services (audit service) is on the Least Cost Selection (LCS) System, wherein the tender is awarded to the lowest bidder. However, as the lowest cost does not guarantee the requisite level of quality of the work assigned, it was suggested that the process of selection requires modifications especially for hiring the professional services and ICAI extended its support to CVC to have the uniformity and devise a rationale in the entire process of tendering of services.

ICAI suggested adoption of Quality & Cost Based Selection (QCBS) uniformly giving due weightage to audit assignments. Evaluation of financial bids for professional services should be done through QCBS instead of LCS criteria. The same is being adopted internationally also as it provides fair chance to the technically qualified professionals of being awarded the tender.

**Coordination to Partner with NITI Aayog:** The Committee has entered into an agreement with NITI Aayog to support the initiative undertaken by NITI Aayog in its Women Entrepreneurship Cell in the following ways:

- ICAI would provide the panel of Chartered Accountants.
- ICAI would provide 2 experts per State wherein the scope of work would be provided by NITI Aayog.
- ICAI can arrange for venues free of cost for conducting different workshops by NITI Aayog. In this regard, the list of 80 plus auditorium of our Regional Councils as well as Branches all across the Country would be provided.
- Faculty support /Resource persons would be provided by ICAI to take sessions during the said workshops.
- ICAI can provide its support in vetting the content of various publications related to finance and accounts published by NITI Aayog. ICAI can link the website of NITI Aayog with its Website as well as the PD Knowledge Portal to create awareness of the initiative amongst its members.

#### **Meeting on Expert Committee on NPAs and Frauds constituted by RBI**

- President, Vice-President alongwith Central Council members represented the Institute at the meeting of Expert Committee on NPAs and Frauds, constituted by RBI under the Chairmanship of ICAI Past President and NACAS founder Chairman CA. Y. H Malegam, held on 20<sup>th</sup> June, 2018 at Mumbai, where we submitted our suggestions on the NPAs and frauds from audit perspective. Then we recommended that autonomy with regard to the appointment of statutory auditors should be reversed. The role and effectiveness of various types of audits conducted in banks in mitigating the incidence of divergence and frauds cannot be overlooked. Accordingly we suggested that the scope of bank-branch audit should be enlarged. We also stressed that not all bank branches are being subjected to statutory audit, and discussed the issues that included the appointment of statutory auditors by banks, concurrent audit to be done by CAs and uniformity be maintained for appointment, remuneration to be linked with scope of work, banks to have robust appraisal and an effective credit monitoring mechanism, among others.
- We also briefed the Committee about a software developed by ICAI regarding the appointment of statutory auditors and implementation of UDIN. This can randomly map the statutory auditors associating them with the available vacancies in the public-sector banks. This year, three banks, namely Syndicate Bank, Dena Bank and Oriental Bank of Commerce, have used the software for the first time and submitted a positive feedback. We have conveyed to the Expert Committee that other banks should also be encouraged to use our software.

**Initiative with Infosys Finacle:** PDC with an aim to set up a benchmark in Bank Audits has utilized the technical expertise of Finacle partners, Infosys wherein they have provided seven e-learning modules (in 12 videos of 120-minute duration) on Finacle customised for the bank audit for CAs.

**CA Directors Interactive Meet**

- With the intent to have continued dialogues with the Chartered Accountant Directors on the Board of Public Sector Entities, a meet was jointly organized with Corporate Laws Corporate Governance Committee for CA Directors of Asset Management Companies, Insurance Companies & Public Sector Undertakings in addition to Banks.
- The meet was graced by Shri (Dr). Navrang Saini, Whole-Time Member, Insolvency and Bankruptcy Board of India as Chief Guest and by President, Vice-President, Past Presidents and more than 40 CA Directors and was highly appreciated. The Technical sessions on contemporary topics such as Corporate Governance, Internal Financial Control, Risk Management in Banks, Cyber Security gave insights to the participants and was followed by panel discussion on Independent Directors- Facing Challenges and seizing Opportunities.

**New Face of PD Portal**

- The Committee had developed PD Portal ([www.pdicai.org](http://www.pdicai.org)) to provide members with all the information that they need to enrich their own practice and provide value added services to their clients.
- The Portal has been revamped, wherein a separate section for Committee's activities has been created at the Website. All related information as to MEF Application, Webcasts & Upcoming events, communications made with different regulatory authorities, links of their websites are available at one place.

**Programmes Organized**

- Several Programmes were Organised under the aegis of PD Committee all across the country on issues in Bank Audit. Further, a series of SCA Meet was organized jointly with Auditing & Assurance Board at four places i.e. in Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai during March- April 2018.
- The Committee has always endeavor to determine the professional developmental needs and simultaneously identifying concerns which has been impacting the profession. Keeping this in view, various programmes were organised by the Committee with an aim to strengthen and enhance the skill set of our members.
- The Committee organized 28 programmes, seminars, meets, etc., on expectation of Central Bank from auditors of the companies, redesigning the future, etc., in Delhi, Mumbai, Indore, Sikar, Jodhpur, Raipur, Bhopal, Bhilai, etc., during the specified period.

**State Level Co-ordination Committee (SLCC) Meeting on Working of Non-Banking Financial Companies and Unincorporated Bodies**

- Various SLCC meetings were held throughout the year for the states of Goa, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, Karnataka, Maharashtra, NCT of Delhi, Himachal Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Haryana, Tamil Nadu, Arunachal Pradesh, Rajasthan, Kerala, Gujarat, Tripura, Nagaland, Andhra Pradesh, Telangana, Madhya Pradesh, Pondicherry, Raipur, and Chandigarh.
- Various Sub- SLCC meetings on the working of Non-Banking Financial Companies & Unincorporated Bodies were held for states of Tamil Nadu, Uttar Pradesh and Haryana.

**Representations Submitted:** Various representations were sent to various authorities to draw their kind attention to the decision of the Council regarding Responding to tenders thereby requesting them to fix the minimum fee of the assignment in the tender document itself so that the objective of the notification is met.

**Multipurpose Empanelment Form and Provision of Panels:** The Committee has been striving to generate more professional opportunities for the members of the Institute by exploring/ pursuing new/existing areas where the professional skills of the members could be utilized in a productive and fruitful manner. As per the practice, the Committee this year also hosted Multipurpose Empanelment Form online at [www.meficai.org](http://www.meficai.org). Every effort was made to make MEF more comprehensive to collect maximum information and disseminate through a centralized database.

Panels of Chartered Accountants/Firms were provided to RBI, NABARD and various other authorities such as Central Bureau of Investigation, Official Liquidator, SIDBI, SEBI, etc., as per the criteria specified by them.



## 5.20 Committee on Public Finance & Government Accounting (CPF&GA)

**Programmes/ Seminars/ Conferences/ Workshops/ Interactive Meets:** The committee conducted various programmes, seminars conferences, interactive meet on Cooperatives and NPO Sectors, seminar on issues of NPO and Cooperative Societies & FCRA, etc., in Mumbai, Delhi, Akola, Pune, Vizag, Madurai and so on.

The Committee on Public Finance & Government Accounting has revised its publication "Commonly Used Terms in Public Finance & Government Accounting" which shall be useful in understanding the terminology/economic terms related to public finance & economics.

**Training Programmes/ Workshops/ Webcasts/ Faculty Development Programmes:** The Committee organized number of programmes with Government Departments/ PSUs at various places including New Delhi, Chhattisgarh, Uttarakhand, Mumbai, Slivassa, and Kolkata, during the year. The Committee also conducted the Webcast on *Analysis of Union Budget* from economic point of view in New Delhi.

## 5.21 Public Relations and CSR Activities

In the year 2017-18, the Committee in pursuance of its mission and goals, continued its endeavor to enhance the visibility of ICAI by establishing & fostering good relations with Chambers of Commerce / Trade bodies/ important media houses and similar organizations. The Committee undertook meaningful and quality initiatives that captured the true essence of social responsibility in such a way that lead to value creation for the Society through transparency and effective governance. In the year 2017-18, the PR & CSR Committee was reconstituted as Public Relations Group. Some of the important activities undertaken by the Committee during the aforesaid period include the following:

**Partnering in Initiatives of Government:** During the period, as a partner-in-Nation-Building and to take forward the initiatives of Government towards Corporate Social Responsibility (CSR) such as *Vigilance Awareness Week*, *Swachhta Hi Sewa*, Special Drive *Swachh Bharat* Mission, *Swachhta Pakhwada*, 75<sup>th</sup> Anniversary of Quit India Movement, National Integration Day, Constitution Day and Isha Foundation – Rally for Rivers, these activities were undertaken PAN India by associating all Regional Councils /Branches of the ICAI.

**ICAI GST Sahayata Desks:** The Goods and Services Tax (GST) replaced multiple taxes system in a single taxation system with effect from 1<sup>st</sup> July 2017. Implementation of GST was envisaged to be a win-win situation for all the three stakeholders viz Government, businessman and consumers. One of the important aspect of this mammoth transformation was to provide suitable guidance to small businessmen, traders etc. about the various aspects of the act.

To facilitate small businessman, representatives of trade and industry and public at large, ICAI through PR & CSR Committee made operational *GST Sahayata Desks* at 125 locations all across the country through its Regional Councils, Branches & CPE Chapters of ICAI. The Sahayata Desks were operational from 28<sup>th</sup> May 2017 till 30<sup>th</sup> September 2017. Experts having GST knowledge resolved the issues raised by stakeholders at the Sahayata Desks and was able to address the initial queries and doubts of the target groups.

**Swachhta Abhiyaan:** ICAI through its network of 164 branches and 5 Regional Councils have been a part of the Prime Minister's vision of Clean India. During the year, the Committee undertook various initiatives like Cleanliness Drives/ Swachhta Pledge/ Tree Plantation/ creating awareness about environment conservation through *Green Marathon*. Several initiatives towards realising the vision of the Prime Minister are being undertaken on regular basis and especially on important occasions like International Day of Yoga, CA Day, Independence Day, Gandhi Jayanti, etc. The aim is to sensitize and raise awareness on need for cleanliness and its associated benefits amongst the members, students and stake holders, officials and staff of ICAI.

**State Taskforces:** In order to increase the PR reach for brand building of ICAI and CA profession at local level, the Committee constituted *State Taskforces* (STFs) in Chandigarh, Delhi, Haryana, Punjab and Jammu & Kashmir. Eminent Chartered Accountants from all cities were made part of the STFs so that their

valuable inputs, wisdom and guidance can be sought during the meetings to identify new areas/ activities to be undertaken towards brand building. Meetings of STFs of Chandigarh, Punjab and J & K were organized and matters of general interest to the professions were discussed.

**Highlighting News/Events on ICAI Social Media Platforms:** In the wake of digital evolution, the presence on social media platform is a powerful tool to connect with current and potential members and promote activities. It was felt that there is a need to enhance the presence of ICAI on all social media platforms therefore it was decided that all major initiatives taken by the Institute shall also be promoted through Social media in addition to print/electronic & online media. Accordingly, the Initiatives taken by the various Committees/Departments were promoted on social media platforms like FaceBook, Twitter, LinkedIn and YouTube.

**Other Initiatives:** For the CA day and International Conference, messages were requested from eminent dignitaries to be included in the CA Journal and Technical Backgrounder.

- The Media interactions increased through one to one interviews, constantly apprising the media of the latest developments regarding the curriculum, profession, introduction of new courses, new guidelines for CAs, visit of foreign delegations, other activities and events etc.
- The Committee promoted the potential and scope of Chartered Accountancy Profession in today's dynamic context by way of articles as well as through interactive meetings/releases issued to the press at national /regional level and through various TV channels.
- To create awareness and promote the core domain of ICAI, advt.s were published in News/Business magazines.
- Provided logistic support to various departments within ICAI, to the regional Offices and Branches with a view to develop communication link between ICAI and its offices/related organizations.
- As part of the PR exercise, organized appropriate coverage in Print and Electronic Media for different seminars/ programmes/ events of ICAI.
- The press and media continues to be apprised of the emerging developments in the profession through constant interactions and in particular after each of the Council meetings.

## 5.22 Research Committee

Research Committee is the non-standing committees of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) established in the year 1955. The primary objective of Research Committee is to undertake research in the field of accounting and other affiliated areas with a view to enhance the value of services rendered by the profession. It formulates Guidance Notes on accounting aspects which are issued under the authority of the Council. It also brings out Technical Guides, Studies, Monographs, etc., on generally accepted accounting and/or auditing principles. The Committee, through its sub-committee, the Shield Panel, also conducts an annual competition, 'ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting' with a view to improve the presentation of financial statements.

**ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting for Financial Year 2016-17:** These awards are being presented annually since 1958. Selection of awardees in specified categories is made through a robust three tier process: first review by Technical Reviewers followed by review of short listed annual reports by Shield Panel and final review by External Jury.

Jury Meeting for the competition year 2016-17 was held on 15<sup>th</sup> January 2018, at Mumbai and was chaired by Shri M. Damodaran, former Chairman, Securities and Exchange Board of India (SEBI). Other members of the Jury, who participated in the meeting to select the awardees, were: CA. Amarjit Chopra, Chairman, NACAS & Past President ICAI, Shri H. R. Khan, Former Deputy Governor, Reserve Bank of India, Shri Sanjay Jhanwar, Managing Partner, M/s Chir Amrit Legal LLP, Shri Nayan Mehta, CFO, Bombay Stock Exchange, Shri P. P. Pareek, Former Director, Bank of Baroda & Andhra Bank, Ms. Parama Sen, Principal Director (Commercial), C&AG, Shri Nitin Parekh, Group CFO, Cadila Healthcare Limited.

As per the scheme of awards, one Gold Shield and one Silver Shield are awarded for the best entry and the next best entry, respectively. Apart from the above-mentioned awards, Plaques are awarded for commendable entries. Hall of Fame award is bestowed on an entity which wins five consecutive Gold Shields in a particular category. A function to honour the awardees of 'ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting' was held on 25<sup>th</sup> January 2018 in Mumbai. Shri M. Damodaran, former Chairman,

Securities and Exchange Board of India (SEBI) was the Chief Guest at the occasion. A total of 11 awards – Two Gold Shield, Four Silver Shields and Five Plaques were given away.

Further, a Technical session on 'Integrated Reporting: A journey towards Integrated Reporting' and also 'Workshop towards Excellence in Financial Reporting' wherein the Shield Panel highlighted the observations on the Annual Report and other documents of the entities participated in the competition were also held before the awards presentation ceremony.

### 5.23 Committee on Capital Market and Investors' Protection (CCM&IP)

CCM&IP was constituted by the Council as a Non-Standing Committee in the year 1993-94. Then in 1998-99, the Committee's name changed to *Committee on Financial Market Markets and Investors Protection*. In 2017-18, the erstwhile Committee was merged with the Banking Financial Services and Insurance Committee and reconstituted as *Committee on Capital Market and Investors Protection* in 2018.

CCM&IP provides suggestions on various Bills/ regulations/ notifications/ circulars and other documents relating to capital market for submission to the Government/ Regulators. Besides this, the Committee regularly interacts with RBI and Indian Banks Association, for example, relating to depositors, non-performing assets management, bank operation and supervision, issues relating to securitisation, role played by CAs, non-banking finance companies (NBFCs), Department of NBFC of RBI, regulatory authority of Co-operative Banks, strategies/ recommendations relating to their investment patterns, SEBI, e.g. matters relating to primary and secondary markets, take-overs, amalgamation, mergers, (tax-havens, participatory note, hot-money, corporate governance regulatory compliances, etc.), mutual funds, foreign institutional investors, intermediaries, securities laws, etc., Forward Markets Commission (FMC) including NCDX and MCX, Stock Exchanges on the issues relating to capital markets and investors protection.

**Partner in Nation-Building:** To emerge as preferred partner in nation-building and to spread awareness in public at large about the dos and don'ts of investing money in financial securities and to promote financial literacy, the Committee is organizing investor awareness programmes under the aegis of *Investor Education and Protection Fund* (IEPF) of the Ministry of Corporate Affairs, through various resource persons and Regional Councils, Branches, Study Circles, Study Chapters and Study Groups.

#### Investor Awareness Programmes conducted during February 2018–June 2018

- **Organised in EIRC of ICAI:** Investor Awareness Programme was organized on 13<sup>th</sup> April 2018 at the EIRC Premises in Kolkata under the aegis of IEPF of Ministry of Corporate Affairs, Govt. of India. Topics covered were investments in depth, both market views, investment strategy views and investment awareness.
- **Organised in SIRC of ICAI:** Investor Awareness Programme was organised jointly with Hindustan Chamber of Commerce on 30<sup>th</sup> May 2018 by SIRC of ICAI under the aegis of IEPF of Ministry of Corporate Affairs, Govt. of India. Topics discussed included *SAFE to be SAFE Investor*.
- The Committee had organized 132 Investor Awareness Programmes (IAPs) across India i.e. on PAN India basis wherein 7997 people were educated under the aegis of IEPF of Ministry of Corporate Affairs, Govt. of India. The said IAP's were organised in the districts of Andhra Pradesh, Assam, Gujrat, Haryana, Maharashtra, Odisha, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Kerala etc., during this period. Topics covered in the said IAP's were Budget Announcements for Capital Market, Nivesh Pathshala, Financial Planning and Investment Options, Indian Stock Market Present and Future, Mutual Funds, How to Protect Wealth from disaster and how to recover blocked investments, etc.

#### Initiatives for Members

**Capacity-Building:** Presently, CCM&IP is entrusted with the task of conducting Certificate Course for All India Members of ICAI, i.e. *Certificate Course on Forex and Treasury Management*.

- The 48 batches of Certificate Course on Forex and Treasury Management course have been conducted till date. During the period, 2 batches of the Certificate Course were conducted in Noida and Mumbai during May-June 2018.

- Phase I of the Certificate Course on Forex and Treasury Management was successfully organized on 12<sup>th</sup>-17<sup>th</sup> March 2018 for the officials of Hindustan Petroleum Corporation Ltd., Pune, as per the ICAI's MoU signed with them.
- Results of an evaluation test held on 27<sup>th</sup> and 28<sup>th</sup> January 2018 of the past batches Certificate Course was declared on 14<sup>th</sup> March 2018.

**Workshop/Webcast for Professional Enhancement of Members (12<sup>th</sup> February – 30<sup>th</sup> June 2018):** The Committee organized a one-day workshop on Managing Portfolio & Trading in Bear Market on 28<sup>th</sup> April 2018 at Gandhidham Branch of WIRC. A live Webcast on *Art of Investing in Stock Market* was also organized on 1<sup>st</sup> May 2018 in New Delhi.

#### 5.24 Ind AS Implementation Group

The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) being the premier accounting body in India has been engaged in formulation of Indian Accounting Standards (Ind AS). In the year 2011, ICAI constituted Ind AS Implementation Committee which was entrusted with the task of providing guidance to the members on Indian Accounting Standards (Ind AS). During the council year 2018-19, the said committee has been reconstituted as Ind AS Implementation Group under the aegis of Accounting Standards Board. Ind AS Implementation Group (erstwhile known as *Ind AS Implementation Committee*) has been making relentless efforts in making the transition to Ind AS smooth.

In order to ensure implementation of Ind AS in the same spirit in which these have been formulated and to provide appropriate guidance to the members and other stakeholders, the Ind AS Implementation Group issues Educational Materials on Ind AS, which contains summary of the respective Ind AS and the Frequently Asked Questions (FAQ) covering the issues, which are being faced or are expected to be encountered frequently while implementing the Standard. During the period, four (4) Educational Material on five (5) Ind AS have been issued. So far, eleven (11) Educational Materials on twelve (12) Ind AS have been issued. The Group is working to bring out Educational Materials on all the Ind AS. In addition to the above, the Group has revised its publication titled "Indian Accounting Standards (Ind AS): An Overview (Revised 2018)", which is an overview containing various aspects related to IFRS-converged Indian Accounting Standards (Ind AS) such as Roadmap, carve-outs from IFRS/IAS, changes in financial reporting under Ind AS compared to financial reporting under existing Accounting Standards, Summary of all the Ind AS etc. It captures all the recent amendments to Ind AS notified by the MCA in March 2018 specifically issuance of new revenue standard (Ind AS 115) and other consequential amendments thereto.

As the implementation of Ind AS began in the country, a number of issues were being raised by the members, preparers and other stakeholders with regard to applicability/implementation of Ind AS. For addressing transition related queries in a timely and speedy manner, an Ind AS Transition Facilitation Group (ITFG) was constituted in the year 2016 which issues clarification bulletins addressing implementation issues from time to time. The Group comprises of experts from accountancy firms, industry representatives and other eminent professionals. During the period, eight (8) ITFG Clarification bulletins have been issued. Till date, the Group has brought out clarifications on 114 issues through its 15 clarification bulletins.

Furthermore, for ease of reference of members, a publication titled *Compendium of ITFG Clarification Bulletins* has been brought out, which brings a topic-wise compilation of all the issues clarified earlier through ITFG Clarifications Bulletins, in one place.

*Support-Desk for Implementation of Ind AS* were also launched to address the difficulties being faced by the members, wherein the members can submit their queries, questions, suggestions, etc., online by clicking on a link.

This Group is also taking adequate steps to enhance the knowledge of the members and other stakeholders for proper implementation of Ind AS by conducting workshops, seminars and Certificate Course.

The Group organises a 12-day *Certificate Course on Ind AS* throughout the country and abroad to impart knowledge about the Ind AS. Comprehensive session plan of the course has been designed with a view to make members competent in field of Ind AS. During the period, 29 batches of Ind AS Certificate course have been conducted wherein around 1200 members have been trained. So far, around 8900 members

have been successfully trained in the Certificate Course on Ind AS across various locations throughout the country and abroad.

The Group also organises one-/two-day awareness programmes on Ind AS at various locations across the country, where training on basic Standards which form the premise for preparation and presentation of financial statements under Ind AS, difference between Ind AS and existing AS are specifically covered in order to educate the members and stakeholders about how accounting under Ind AS would be different from the existing ASs. During the period, 11 such awareness programmes were organised across the country.

Additionally, the Group also organises in-house training programmes on Ind AS for the officials/ employees of various regulators, organisations and corporate houses. During the period, various such training programmes on Ind AS were organised for the officials of Comptroller & Auditor General of India (C&AG), IRDAI, CBDT, departments of various Ministries, etc., and other corporate entities. Then, the Group is also conducting a series of webcasts on Ind AS, as part of its agenda to create awareness about Ind AS and to make the transition to Ind AS smooth.

### 5.25 Audit Committee

Audit Committee reviews the reporting process and disclosure of financial information of the ICAI to ensure that the financial statements are true and fair. It is also responsible for appointment of auditors for various units of the ICAI. It has five Regional Audit Committees located at each of its Regional Councils.

### 5.26 Digital Transformation & Process Re-engineering Group (DT&PRG)

DT&PRG has launched *Self-Service Portal for Students, Members and Firms*. ICAI Mobile app *ICAI Now* and ICAI social media platforms have been instrumental in the popularization of various ICAI events and key achievements and initiatives at no cost amongst the students, members and other stakeholders of the Institute.

DT&PRG has enabled *Paytm Payment Gateway* services on the ICAI website for members and students, where there is no online transaction charges for one year for Net-banking and Paytm-wallet. Group helped the members at large to rectify their PAN issues with the Income-tax Department/ MCA.

The implemented Seam less integration of Membership fees with the VIP application, various online facilities such as member card and firm constitution certificate / firm card, online re-print letter facility for student / members and firms, facility for change in email id & mobile, facility for change in address, e-*Sahaayataa* on ICAI mobile app and Good Standing Certificate.

### 5.27 Quality Review Board (QRB)

The Quality Review Board was constituted on 28<sup>th</sup> June, 2007 by the Central Government pursuant to the powers vested in it under Section 28A of the Chartered Accountants Act, 1949 to perform the following functions:

1. To make recommendations to the Council with regard to the quality of services provided by the members of ICAI;
2. To review the quality of services provided by the members of ICAI including audit services; and
3. To guide the members ICAI to improve the quality of services and adherence to the various statutory and other regulatory requirements.

One of the functions of the Council under clause (o) of sub-section (2) of Section 15 of the Chartered Accountants Act, 1949 is to consider the recommendations of the Quality Review Board made by it with regard to the quality of services provided by the members of ICAI. The aforesaid clause (o) also provides that the details of action taken on such recommendations shall be published in its Annual Report. In accordance with the aforesaid provisions, during the period under Report, the Council received 1 reference under Section 28B(a) of the Chartered Accountants Act, 1949 from the Quality Review Board with regard to the quality of services provided by the members. The same was considered by the Council at its meeting held during the financial year April 2017 to March, 2018. The following is the details of action taken:

1. Number of references referred to the Director (Discipline) for making further investigation under the disciplinary mechanism of ICAI-1.
2. Number of references where comments of the Technical Reviewer were decided to be issued as an Advisory to the members / firms – NIL.
3. Number of references which were decided to be closed – Nil.
4. Number of references pending for consideration of the Council – Nil

### 5.28 Management Committee

Management Committee, constituted in 2015 as non-standing Committee of the Council, is mandated to consider matters pertaining to formation of Branches, setting up of Chapters abroad, MoUs/ MRAs with national/ international bodies, appointment of central auditors of ICAI, annual accounts of the Institute, matters referred by the Central Government and other regulatory bodies, proposals for amendments in the Chartered Accountants Act, 1949, Rules and Regulations framed thereunder, Regional Councils and Branches matters, Members/ CA firms/ LLPs/ mergers/ demergers/ networking related matters and proposals received from other committees/ departments of the Institute having administrative and policy implications and making its recommendations to the Council wherever required.

### 5.29 Young Members Skill and Innovation Development Committee

Young Member Empowerment Group under the aegis of the Committee for Capacity Building of Small and Medium Practitioners of ICAI has been reconstituted as a Committee in the year 2018-19 as *Young Members Skill and Innovation Development Committee* (YMS & IDC). Activities during 1<sup>st</sup> April, 2017-30<sup>th</sup> June, 2018 are given as under:

**Seminars/Workshops/Conferences/Residential Refresher Courses/ Webcasts:** The Committee organized 19 programmes, one Residential Refresher Course and one webcast across the country on emerging topics such as Start-Up and Entrepreneurship, GST, Income Disclosure Scheme, Forensic Audit, Income Tax, E-Commerce and Cloud Computing, ICDS and Preparation of Appeals, interpersonal Skills and Public Speaking. Webcast on "Opportunities for Young Chartered Accountants in Civil Services" was organized on 13<sup>th</sup> May 2017 in New Delhi, jointly with the Committee for Members in Entrepreneurship & Public Services.

### 5.30 Valuation Standards Board (VSB)

Valuation Standards Board is constituted to focus on releasing of Valuation Standards, providing Interpretations, Guidance and Technical Materials from time to time and implementation of the Standards. The Board will suggest areas in which Indian Valuation Standards (Ind VS) need to be developed.

**Formulation of Indian Valuation Standards:** Recognising the need to have the consistent, uniform and transparent valuation policies and harmonise the diverse practices in use in India, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) has issued the Valuation Standards which are 1st of its kind in India.

With a vision to promote best practices in this niche area of practice, the Standards lay down a framework for the chartered accountants to ensure uniformity in approach and quality of valuation output. The following Valuation Standards have been issued by ICAI:

- Preface to the Indian Valuation Standards
- Framework for the Preparation of Valuation Report in accordance with the Indian Valuation Standards
- Indian Valuation Standard 101 - Definitions
- Indian Valuation Standard 102 - Valuation Bases
- Indian Valuation Standard 103 - Valuation Approaches and Methods
- Indian Valuation Standard 201 - Scope of Work, Analyses and Evaluation
- Indian Valuation Standard 202 - Reporting and Documentation
- Indian Valuation Standard 301 - Business Valuation
- Indian Valuation Standard 302 - Intangible Assets
- Indian Valuation Standard 303 - Financial Instruments.

These Indian Valuation Standards will be applicable for all valuation engagements on mandatory basis under the Companies Act 2013. In respect of Valuation engagements under other Statutes like Income Tax, SEBI, FEMA etc, it will be on recommendatory basis for the members of the Institute. These Valuation Standards are effective for the valuation reports issued on or after 1<sup>st</sup> July 2018.

In formulating the Valuation Standards, ICAI considered best valuation practices followed globally as well as in India, uniqueness of Indian conditions, current practices in India along with their advantages and disadvantages and various purposes for which valuations might be required over and above the requirements of Companies Act.

These standards come as ICAI's consistent drive to guide its members for ensuring high quality work and standards.

These Indian Valuation Standards will be effective till Valuation Standards are notified by the central Government under Rule 18 of the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2018.

**National Seminar on Valuation and Registered Valuers:** National Seminar on Valuation and Registered Valuers was organised in January 2018 to discuss various technicalities and the role of valuers in the recent regulatory changes. With the introduction of new concept of *Registered Valuers*, the valuation profession will get a boost and this will prove to be another professional opportunity for the members.

**Roundtable Discussions on Draft Companies (Registered Valuers and Valuation), Rules, 2017 under Companies Act, 2013:** The Board organised the Roundtables to collate the suggestions on Draft Rules for Registered Valuers and Valuation under Section 247 of the Companies Act, 2013, for onward submission to the Ministry of Corporate Affairs, in Chennai, Bangalore and Mumbai in the month of June 2017.

A Roundtable Conference jointly with INSOL India and SIPI was also organised to discuss and collate suggestions on the Draft Rules for Registered Valuers and Valuation under the Companies Act, 2013 in Mumbai.

**Interactive Session by IBBI with Valuer Organisation and Professional Institutes:** An interactive session was held by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) with Valuer Organisations and Professional Institutes to discuss the role of Valuer Professional Organisations (VPO) and Registered Valuers under the Rules, Preparations by VPOs and Valuers, Syllabus and Examination, Educational courses by RVOs and Monitoring of Valuers and RVOs. Also, a presentation was made on the valuation procedures/ methodologies for the valuation of securities or financial assets and valuation of firms.

**Suggestions Submitted on Draft Companies (Registered Valuers and Valuation), Rules, 2017 as Issued by Ministry of Corporate Affairs:** Ministry of Corporate Affairs has requested ICAI to submit its suggestions on the Draft Rules on Registered Valuers and Valuation. Suggestions on the Draft Companies (Registered Valuers and Valuation), Rules, 2017 were submitted to the Ministry of Corporate Affairs on 30<sup>th</sup> June 2017.

### 5.31 Taxation Audits Quality Review Board

The Council has constituted the Tax Assurance Review Board as its non-standing Committee in the Council year 2018-19. Constituted as 'Tax Assurance Review Board', the Board was rechristened by the Council as 'Taxation Audits Quality Review Board'.

**Objectives of the Board:** The Board is to review the compliance, with the reporting requirements prescribed under various taxation laws (both direct as well as indirect).

Accordingly, the Board would review any report prescribed under the Income-tax Act, 1961 and Rules thereunder and any report prescribed under the Indirect Tax Laws including Goods and Services Tax Law which are certified by a Chartered Accountant in respect of certain enterprises with a view to determine, to the extent possible:

- a) Compliance with the reporting requirements prescribed under various sections of the Income-tax Act, 1961 and Rules thereunder;
- b) Compliance with the reporting requirements prescribed under various provisions of the Indirect Tax Laws including Goods and Services Tax Law; and
- c) Compliance with the respective pronouncements, guidance notes of ICAI.

The Board may review the various reports prescribed under the Income-tax Act, 1961 and Rules thereunder and under the provisions of the Indirect Tax Laws including Goods and Services Tax Law either *suomoto* or on a reference made to it by any regulatory body like, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India, Insurance Regulatory and Development Authority, Ministry of Corporate Affairs, Comptroller and Auditor General of India, Central Board of Direct Taxes, Central Board of Indirect Taxes and Customs, State Commercial tax Departments etc. The Board may also review the reports of the enterprises relating to which serious irregularities in taxation matters (Direct and Indirect) have been highlighted by the media reports.

It is envisaged that the reviews carried out by the Board, will ensure that the members will exercise greater diligence while certifying the various reports prescribed under direct and indirect taxation and in the long-run would improve the overall reporting and certification done by them.

**Selection of enterprises:** The Board has selected 100 companies for the Council Year 2018-19 for review of their tax audit reports pertaining to Assessment Year 2017-18 on suo motto basis. In this regard, 88 tax audit reports have been received from the tax auditors.

**Empanelment of Technical Reviewer:** In order to conduct the first tier review, the Board is in the process of empanelling Technical Reviewers having expertise in taxation (both direct as well as indirect) who can conduct the detailed reviews. In this regard, an Announcement was hosted on the ICAI website inviting members who fulfill the eligibility criteria determined by the Board to empanel themselves as technical reviewers with the Board by filling an online Empanelment Form developed for the said purpose.

## 6. International Affairs Committee (IAC)

### (i) Initiatives of IAC for Recognition of Professional Opportunities Abroad

**Signing of MoU with ICAN:** ICAI signed the Memorandum of Understanding (MoU) with the Institute of Chartered Accountants of Nepal (ICAN) on August 23, 2017 to establish mutual co-operation for the advancement of accounting and allied areas. CA. Nilesh S Vikamsey, the then President, ICAI and CA. Naveen N D Gupta, the then Vice President, ICAI, were present from ICAI and CA. Prakash Jung Thapa, President, ICAN and CA. Jagannath Upadhyay, Vice President, ICAN were present from ICAN.

- **MRA with SAICA:** MRA between ICAI and South African Institute of Chartered Accountants (SAICA) was signed on 4<sup>th</sup> June 2018 in Johannesburg in the presence of ICAI President, Vice-President and Dr. K J Srinivasa, Hon'ble Consul General, Johannesburg, South Africa. The MRA is to establish a mutual co-operation framework for the advancement of accounting knowledge, professional and intellectual development, advancing the interests of their respective members and positively contributing to the development of the accounting profession in South Africa and India.
- **Membership of IIRC:** International Integrated Reporting Council (IIRC) is a global coalition of regulators, investors, companies, standard setters, the accounting profession and NGOs. ICAI has obtained membership of IIRC in the year 2017, wherein the President-in-office would represent ICAI at the Council of IIRC.

### ICAI's Representatives on International Bodies

- CA. S B Zaware, Council Member, ICAI, was elected Vice Chair of the Asian Oceanian Standard Setters Group (AOSSG) for two years commencing from November 2017.
- CA. Manoj Fadnis, Past President, ICAI, has been elected President of Confederation of Asian and Pacific Accountants (CAPA) for a period of two years commencing from November 2017.
- CA. Prafulla P. Chhajed, Vice President, ICAI, has been nominated as Member of the Public Sector Financial Management Committee of CAPA.
- CA. Naveen N D Gupta, President-in-office, is a CAPA Board Member.



- CA. G Sekar, Council Member, ICAI, has been elected as CAPA representative at the Consultative Advisory Group of the International Accounting Education Standards Board of IFAC for a period of three years commencing from 1<sup>st</sup> January 2017-31<sup>st</sup> December 2019.
- President-in-office is the member of IIRC Council.

**Inauguration of 32<sup>nd</sup> Chapter of ICAI in Malaysia (Kuala Lumpur):** ICAI Council has approved the formation of its 32<sup>nd</sup> Chapter in Malaysia, which was inaugurated on 5<sup>th</sup> July 2018. The Management Committee of ICAI has approved the formation of the 33<sup>rd</sup> Chapter in Tokyo (Japan), which will be inaugurated soon.

**CA ANZ Offers Unilateral Scheme of Membership to ICAI Members:** ICAI has entered into a unilateral arrangement, i.e. *Pilot International Pathway Scheme*, with the Chartered Accountants Australia & New Zealand (CA ANZ) for the ICAI members based in Australia and New Zealand. The said pathway program is in addition to the proposed MoU, which is under consideration of the Government for approval.

Through this Scheme, ICAI members based in Australia and New Zealand would get the membership of CA ANZ in addition to ICAI membership by completing a 40-hour self-study programme and attending a two-day workshop in less than one month's time. The participants shall be evaluated through oral and written assessments during the workshop.

**ICAI-CPA Australia Joint Workshop-cum-Information Session Organised in May and June 2018:** ICAI and CPA Australia jointly organized a series of workshops in New Delhi, Mumbai, Chennai and Bengaluru in May 2018 and in New Delhi, Mumbai, Indore, Ludhiana and Hyderabad in June 2018, which provided an overview of IFRSs. The Joint Workshops cum Information Sessions in May 2018 were coordinated by Ind (AS) Implementation Group and CPE Committee jointly with International Affairs Committee.

**ICAI to Host 21<sup>st</sup> World Congress of Accountants in Mumbai:** World Congress of Accountants (WCOA) is held every four years under the auspices of IFAC, the worldwide organization for the accountancy profession, and is one of the most prestigious global events of professional accountants, where about 6000 delegates gather and exchange views on accounting and allied areas. ICAI won the bid and therefore, would be hosting the 21<sup>st</sup> WCOA in 2022 in Mumbai, which will help ICAI in enhancing and promoting its brand and that of the nation. Hosting WCOA 2022 in India will signify the importance of developing countries like India.

## (ii) Visits of Delegations

- Delegation from IIRC visited ICAI on 19<sup>th</sup> July 2017 to discuss the role of ICAI as a key strategic partner in India with exclusivity parameters.
- Ms. Tashia Batstone, Senior Vice President, CPA Canada visited ICAI on 15<sup>th</sup> September 2017 to discuss the status of MoU to be signed between ICAI and CPA Canada, and to dwell upon the plans for CPA Canada's Advanced Certificate in Accounting and Finance.
- Dr. Stavros Thomadakis, Chair, IESBA (International Ethics Standards Board), and Mr. Ken Siong, Technical Director, IESBA, visited ICAI on 2<sup>nd</sup>-3<sup>rd</sup> November 2017. They also addressed the ICAI Council and addressed the members at a live webcast on the *Proposed Revision in the IESBA Code of Ethics*.
- A delegation from IFAC comprising its President Ms. Rachel Grimes, Executive Director Ms. Sylvia Tsen and Head of Communications Mr. Tony Miranda, visited India to attend the ICAI International Conference held in Mumbai. They had meetings with MCA Secretary, Addl. Controller General of Accounts and Deputy Comptroller and Auditor-General of India on 6<sup>th</sup> December 2017. On 7<sup>th</sup> December, the delegation went to Mumbai and met RBI Deputy Governor, SEBI Chairman and SEBI Executive Director.
- Mr. Leslie Leow, Development Manager CPA Australia and Ms. Preeti Dang, Business Head Professional Connect, visited ICAI on 15<sup>th</sup> January 2018 to discuss modalities for developing a special module and exploring for the possibility of training programme for semi-qualified CAs on the basis of paper-wise exemption.
- Mr. Nasser H. Al Rawahy, Vice Chairman of State Audit Institution of Oman, visited ICAI and requested ICAI to arrange for training programmes for the officials of State Audit Institution of Oman in the areas

of Accounting and Auditing. Mr. Rawahy also attended the ICAI International Conference held in Mumbai on 8<sup>th</sup>-9<sup>th</sup> December 2017.

- Mr. Abdulwahid Aboo, former Member of IFAC SMP Committee visited India on 13<sup>th</sup>-23<sup>rd</sup> April and addressed the members in Delhi, Jaipur, and Mumbai on capacity-building of SMPs in India. Lectures were coordinated by the Committee of Capacity Building of Members in Practice of ICAI.
- Delegation from IFAC comprising of Ms. Rachel Grimes, IFAC President, Mr. Fayezul Choudhury, CEO, IFAC, and Dr. Gary Pflugrath, Senior Director (Public Policy & Regulation), IFAC, visited Delhi and Mumbai on 1<sup>st</sup>-2<sup>nd</sup> June 2018 respectively to visit and inspect the site to host WCOA 2022 in India.

### (iii) Conferences/ Programmes

**EEG Meeting in Mumbai:** International Accounting Standards Board (IASB) constituted an Emerging Economies Group (EEG) to help in addressing the financial reporting issues that are of special significance to the emerging economies. ICAI hosted the 13<sup>th</sup> EEG meeting on 8<sup>th</sup>-9<sup>th</sup> May 2017 in Mumbai. On the sidelines, a half-day ICAI-EEG Joint Stakeholders Seminar was organised on Emerging IFRS (Ind AS) Challenges dealing with Service Concession Arrangements and Expected Credit Loss Model under Ind AS 109.

**CAW Event in Mumbai:** ICAI is one of the members of the Chartered Accountants Worldwide and, in association with the Chartered Accountants Worldwide (CAW), it organized the ICAI-CAW Members Event on *Chartered Accountants: Gearing Up For New Era* on 30<sup>th</sup> August 2017. During the event, two sessions *Digital Transformation and relevance to Accountancy Profession* and *Working Globally- A CAW Forum Perspective* were deliberated. ICAI also hosted the Board Meeting of CAW, where CEOs of Ireland, ICAEW, Singapore, Bangladesh, Indonesia participated and discussed networking, promotion of CA brand and revival of the membership of professional bodies.

**ICAI International Conference 2017 in Mumbai:** ICAI International Conference on the theme of *Accountancy Profession: Convergence and Sustainability in Digital Era* was inaugurated on 8<sup>th</sup> December 2017 in the financial capital of the country, Mumbai, by Ms. Rachel Grimes, IFAC President, in the august presence of CA. Manoj Fadnis, CAPA President, Mr. Nick Parker, ICAEW President, Ms. Joy Thomas, President, CPA Canada and Mr. Naseer Al Rawahy, Vice-Chairman, State Audit Institution, Oman. Over 1500 delegates participated in the event.

**2-Day IFASS Meeting in Mumbai:** ICAI hosted a two-day meeting of International Forum of Accounting Standard-Setters (IFASS) on 12<sup>th</sup>-13<sup>th</sup> April 2018 in Mumbai to deliberate on the emerging paradigm of accounting standards. International Forum of Accounting Standard-Setters (IFASS), formerly known as National Standard-Setters (NSS), is a grouping of national accounting standard-setters from around the world, plus other organisations that have a close involvement in financial reporting issues.

### (iv) Technical Co-operation to Underdeveloped Countries

**ICAI's support to CPA Afghanistan in Capacity Building:** ICAI on request of CPA Afghanistan had provided training in capacity-building to 31 delegates from CPA Afghanistan on 2<sup>nd</sup>-6<sup>th</sup> August 2017 in New Delhi. ICAI has also assisted CPA Afghanistan by providing Letter of Support for taking Associate Membership of SAFA. ICAI and CPA Afghanistan have agreed to enter into an MoU towards mutual co-operation in the accounting & allied areas. The MoU is pending with the Ministry of Corporate Affairs, Government of India.

**Technical Co-operation Agreements:** ICAI is going to enter into MoU to establish Mutual Co-operation in the areas of Member Management, Professional Ethics, Technical Research, Continuing Professional Development, Professional Accountancy Training, Audit Quality Monitoring, Advancement of Accounting Knowledge, Professional and Intellectual Development with the following Institutes and the MoUs are pending with the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, for its approval.

- National Board of Accountants and Auditors (NBAA), Tanzania
- Institute of Certified Public Accountants of Kenya (ICPAK).
- Saudi Organisation for Certified Public Accountants (SOCPA)
- Bahrain Institute of Banking and Finance (BIBF), Bahrain

**(v) Working for building blocks**

**Revision of Global E-Kits:** The initiative of forming the ICAI Global Career E-Kits was done in the Council year 2014-2015 and since then the E-Kits are being revised every year to incorporate the updates related to Chapters, respective jurisdictions, Information Resource comprising MoU/ MRA details, FAQs for members/ students abroad and articleship training. Committee in the current Council year has thoroughly revised and updated all the 9 E-Kits covering 12 Chapters of ICAI.

**Revision of Criteria of Activity Report for ICAI Best Chapter Award:** International Affairs Committee organizes the Best Chapter Awards to encourage Chapters to be more vibrant. These Awards recognize the distinguished efforts and exemplary achievements of the Chapters in furtherance of the mission of the Chartered Accountancy profession. In 2017, ICAI had reviewed the criteria sheet and had made certain modifications to have focused attention of the Chapters on the areas relating to the Chapter efforts on promoting Brand CA India; their role in generating employment and Industrial training opportunities. The other factors have also been made more quantitative.

**7. OTHER ACTIVITIES****7.1 Committee on Management Accounting**

**Initiatives for members:** The Committee organized the 11<sup>th</sup> batch of *Certificate Course on Master in Business Finance* in Mumbai and Delhi on 24<sup>th</sup> June 2017. It conducted two residential programmes for the participants of *Certificate Course on Master in Business Finance* during the months of August and November 2017. It also conducted the examination for the participants of Certificate Course on Master in Business Finance of all three levels where each level contained two papers, during the May-June 2018.

**Partner in Nation-Building**

- The Committee organized the 3<sup>rd</sup> batch of Certificate Course for the CA executives of HPCL during the months of August and November 2017, and January and March 2018.
- It then conducted examination for the participants of Certificate Course of all three levels, where each level contained two papers, in November 2017, January 2018 and March 2018 respectively.

**Industry/Corporate Initiatives/Programmes**

- The Committee organized a Conference on *FINOVATE INDIA: Financial Innovation in India and Way Forward* on 10<sup>th</sup> November 2017 in Mumbai, which was hosted by WIRC of ICAI. It also organized a two-day International Study Tour to attend Asia's premier financial event, the Asian Financial Forum (AFF) on 15<sup>th</sup>–16<sup>th</sup> January 2018 in Hong Kong.

**7.2 Committee for Members in Entrepreneurship & Public Services (CME&PS)**

Objective of CME&PS is to have a mutually advantageous live connect between ICAI and its members in entrepreneurship or public services and to work on the aspects realizing mutual benefit of such members as well as of other members of the Institute. This would help create and enlighten additional opportunity areas for the young Chartered Accountants and thus motivate them to contribute to the furthering of profession.

**Regional Meet of ICAI Members in Public Service in New Delhi:** With a view to solicit views of members in Public Service on various emerging issues relevant for the Accountancy profession, the Committee for Members in Entrepreneurship & Public Services (CME&PS) of ICAI has organized a Regional Meet of ICAI Members in Public Service on 12<sup>th</sup> April 2017 in New Delhi.

The meet was attended by 16 senior members of the profession in Public service including CA. K. Rahman Khan, Hon'ble Member of Parliament, Rajya Sabha, CA. Subhash Chandra Baheria, Hon'ble Member of Parliament from Bhilwara, Justice (CA.) Anil R. Dave, Hon'ble Retired Judge, Supreme Court of India. The members shared their views on various important matters for furthering the image of ICAI which included strengthening PR, assisting Government department in shifting to accrual accounting; GST implementation and awareness initiatives and alike.

**Live Webcast on Opportunities for Young Chartered Accountants in Civil Services:** CMEPS jointly with the Young Members Empowerment Group of the Committee for Capacity Building of Members in

Practice (CCBMP) of ICAI organised a live webcast on *Opportunities for Young Chartered Accountants in Civil Services* on 13<sup>th</sup> May 2017 in New Delhi.

CA. Mahaveer Singhvi, IFS, Joint Secretary, Ministry of External Affairs moderated the discussion. CA. Ravinder, IAS, Private Secretary to Minister, Ministry of Tourism & Culture & CA. Namit Mehta, IAS, Additional Commissioner VAT, Jaipur were the panelist for the session. The objective of the Webcast was to motivate and guide our young Chartered Accountants aspiring to join Civil Services. The webcast was viewed by over 550 ICAI members.

**Regional Meet of ICAI Members in Public Service in Kolkata:** CMEPS organized another Regional Meet of ICAI Members in Public Service on 22<sup>nd</sup> June 2017 in Kolkata, which was attended by 9 senior members of the profession in Public service who shared their views on various relevant professional issues for furthering the image of ICAI.

**Residential Summit of ICAI Members in Public Service in Puri:** With a view to elicit views of members in Public Service on matters of national importance which ICAI can take up for research and further study and also to brainstorm on various matters of current significance for response by the profession, the Committee organized a Residential Summit of ICAI Members in Public Service on *Accountancy Profession for Economic Development* in Puri.

Justice (CA.) Anil R. Dave, Retired Judge, Supreme Court of India and CA. Arun Kumar Gujrathi, Former-Speaker of Maharashtra Legislative Assembly presented their key note addresses at the Summit. The Summit was attended by 33 participants who were senior members of the profession in Public service which included Parliamentarians, Judges. Officers of Indian Administrative and other Civil services, Members of the Tribunal and Member in Journalism.

**Regional Meet of ICAI Members in Public Service in New Delhi:** The CMEPS organized a Regional Meet of ICAI Members in Public Service in New Delhi on 25<sup>th</sup> May 2018. The Regional meet was attended, among other CA Members in Public Service, by CA. Anil R. Dave, Hon'ble Retired Judge Supreme Court of India, CA. Vibhu Bakhru, Sitting Judge, Delhi High Court, CA. Deepak Kumar Kedia, Additional Director, Enforcement Directorate, Delhi, CA. Rakesh Rath, D.I.G. of Police, Central Bureau of Investigation, Delhi, CA. Upender Gupta, IRS, Commissioner (GST) Department of Revenue, Ministry of Finance.

During the Regional meet, ICAI launched a Mobile Application to provide a easy connect of CA Members in Public Service with ICAI and to facilitate updations of their records easily. Important discussions on measures to improve the competencies and skill sets of Professional Accountants were discussed. Further, deliberations on how to meet the expectation gap of the stakeholders and improve the public image of ICAI was also discussed. The Members also discussed the changing needs of the profession arising out of the change in the digital technologies. Further, during the regional meet ICAI felicitated CA. Upendra Gupta, Commissioner, GST for receiving Prime Minister award for Excellence in Public Administration presented to "Team GST, Department of Revenue, Government of India".

### 7.3 Committee for Co-operatives & NPO (CCO&NPO)

CCO&NPO has been set up to promote uniform accounting framework for cooperatives and NPOs and to encourage good governance and best practices in the two sectors. The Committee suggests suitable reforms in the statutes regarding cooperatives and NPOs and aims to facilitate in bringing in conceptual clarity on the issues specific to the sectors so that work can be done effectively and efficiently by all the stakeholders engaged in those fields. Also the members are kept updated about the latest developments in cooperatives and NPOs through seminars, practical workshops, training programmes etc.

#### Representations submitted:

- Representation dated 20<sup>th</sup> April 2017 submitted to the Commissioner, Cooperatives and Registrar Cooperative Societies, State of Madhya Pradesh, Bhopal with regard to the definition of staff in the Audit Firm.
- Representation dated 9<sup>th</sup> August 2017 submitted to the Additional Chief Secretary, Cooperation, Mantralaya, Maharashtra regarding audit empanelment and other concerns faced by Chartered Accountants with regard to Cooperative Societies audit in Maharashtra.

- Representations dated 1<sup>st</sup> and 16<sup>th</sup> March 2018 submitted to the Secretary-cum-Registrar, Office of the Registrar Cooperative Societies, Government of National Capital Territory of Delhi, for extension of last date for the submission of application form by CA/ CA firms for the empanelment of their names as auditor in the Office of Registrar Cooperative Societies, for conducting the Audit of the Societies registered with the Department, Govt. of N.C.T. of Delhi.

**Certificate Courses Conducted:** CCO&NPO conducted two Certificate Courses—*Certificate Course on Cooperatives* and *Certificate Course on NPO* in Jamshedpur and Mumbai.

#### 7.4 Legal Advisory Wing

The following important activities were undertaken by the Legal Wing during the period:

Total number of cases disposed of by the various High Courts under Section 21(6) of the Chartered Accountants Act, 1949 during the period from 1<sup>st</sup> April 2017 to 31<sup>st</sup> March 2018 are eight.

Rendering effective legal assistance in the form of legal opinions, studies and reports, as required from time to time by the Council /Executive Committee / various Non Standing Committees and departments of the Institute.

Providing appropriate legal advice on diverse range of substantive and procedural questions of law arising in administrative functioning of the Institute to firmly secure the interest of ICAI, as required by the operational departments.

Supervising and overseeing the review, negotiations, drafting and vetting of contracts, tender documents and other legal documents, as required by the operational departments and various committees of ICAI.

Serving on various Standing and non-standing Committees, Study groups and taskforce, as required, to take care of legal niceties in framing of policies.

Advising in the matters of taking recourse to legal remedies whenever necessary and assisting the operational departments and committees in preparing reply to legal notices received.

#### 7.5 Infrastructure Development Committee (IDC)

In the year 2014, Infrastructure Development Committee was formed as a non-standing Committee of the Institute. This Committee formulated Infrastructure policy for Branches and Regional Councils/offices. Since 2014, the ICAI has a robust infrastructure policy in place, which ensures financial prudence and discipline. The policy defines what all facilities can be provided, composition of local Infrastructure Committees, policy and procedure for acquisition of land/ building, indicative area, permissible grant from Head Office, powers and delegation vested with various authorities within the Institute. Since the policy itself defines the financial powers, all infrastructure projects from the year 2014 onwards are being approved by IDC, instead of the Finance Committee. In order to monitor and accelerate the pace of infrastructure projects being constructed under the authority of IDC, an Infrastructure Monitoring and Acceleration Group was set up in the year 2018. Since formulation of the Infrastructure Policy, the ICAI has initiated the following projects:

Purchase of new Infrastructure	Construction proposals approved
Kannur, Jalandhar, Jabalpur, Goa, Gurugram, Moradabad, Pali, Agra, Gorakhpur, Karnal, Kishangarh, Latur and Patiala	Ajmer, Surat, Hubli, Rajamahendravaram, Centre of Excellence Jaipur, Bathinda, Bareilly, Bhopal, Jodhpur, Raipur, Kannur, Ghaziabad, Goa and Moradabad

Out of the 164 Branches set up by the ICAI so far, 91 branches are having their own premises which include 17 Branches who have procured land for additional premises and have either commenced construction or the construction is under-way. 16 Branches, which hitherto did not have their own premises, have procured land where either construction has started or construction is under-way. 57 Branches do not own either land or building. The Region-wise break-up as on March, 2018 is as under:

	Western	Southern	Eastern	Central	Northern	Total
Total number of branches	35	45	13	47	24	164
Number of branches having own premises	22	32	6	23	8	91
Out of the above, number of branches which have gone for additional premises	6	2	1	7	1	17
Number of branches having land on which construction is either started or yet to be started	0	2	0	10	4	16
Number of Branches which neither have land nor building	13	11	7	14	12	57

## 7.6 Right to Information Act, 2005

Right to information Act, 2005 an Act to provide for setting out the practical regime of right to information for citizens to secure access to information under the control of public authorities, in order to promote transparency and accountability in the working of every public authority. The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) a statutory body set up by an Act of Parliament i.e. The Chartered Accountants Act, 1949 is a public authority as envisaged under section 2(h) of the RTI Act, 2005. In compliance of the provisions of the RTI Act, 2005 and direction of the Central Information Commission, officers of the Institute have been designated as Central Public Information Officer, Central Assistant Public Information Officer, First Appellate Authority (FAA) and Transparency Officer.

**Disclosure under Section 4 (1) (b) of RTI Act, 2005:** In terms of the Section 4(1) (b) of the Right to Information Act, 2005, necessary disclosures have been made by the Institute by hosting them on the website of the Institute [www.icai.org](http://www.icai.org) and the same are updated from time to time. Total 618 applications have been received and replied in the year 2017-18.

## 7.7 XBRL

ICAI spearheaded the XBRL initiative in the country with formation of XBRL India, a Section 8 company, in the year 2010. Since then XBRL India have been working for the promotion and adoption of XBRL as a standard electronic business reporting language in India.

The main objective of XBRL India is promotion of XBRL through development of taxonomies, facilitation of education and training on XBRL, management information and control systems and allied disciplines, etc. in India supported by the Government of India and various Regulatory bodies i.e. Ministry of Corporate Affairs (MCA), Securities and Exchange Board of India (SEBI), Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA), Reserve Bank of India (RBI) etc. XBRL India develops taxonomies for Ministry of Corporate Affairs (MCA) for the purpose of financial reporting in XBRL format.

### • XBRL filing requirements by the Ministry of Corporate Affairs (MCA)

#### Ind AS Taxonomy and Business Rules

Ministry of Corporate Affairs (MCA) has mandated certain classes of companies to prepare their financial statements as per Indian Accounting Standards (Ind AS) which are converged with International Financial Reporting Standards (IFRS) with effect from the financial year 2016-17.

A set of business rules and Ind AS taxonomy has been developed and submitted to the Ministry of Corporate Affairs. MCA notified the same for annual filing of financial year 2016-17 in XBRL format. XBRL filing for Ind AS compliant companies for financial year 2016-17 has been successfully completed. Scope and level of tagging document for Ind AS XBRL Taxonomy has been prepared and submitted to Ministry of Corporate Affairs.

**Commercial & Industrial (C&I) taxonomy:** For annual filings of the financial statements of a selected class of companies, the Commercial & Industrial (C&I) taxonomy is used by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) from the year 2010-11. The taxonomy is updated every year considering the changes in accounting framework.

Recently, Commercial & Industrial (C&I) Taxonomy required some changes as per latest amendments in Accounting Standards. The required changes were submitted to MCA for XBRL filling of financial year 2017-18. After MCA approval, revised C&I taxonomy submitted to MCA for annual filing of financial year 2017-18.

**International Activities:** CA. Atul Kumar Gupta, Director, XBRL India attended the 28<sup>th</sup> ASEAN+3 Bond Market FORUM (ABMF) Meeting held in Fukuoka City (Japan) from 18<sup>th</sup>-20<sup>th</sup> June, 2018. He also attended the meeting on 9<sup>th</sup> XBRL Asia Roundtable there on 21<sup>st</sup> June, 2018

## 7.8 ICAI-ARF

ICAI Accounting Research Foundation (ICAI ARF) was established in January, 1999 as a Section 25 Company (now Section 8 Company under the Companies Act, 2013) for doing core research in the areas of accounting, auditing, capital markets, fiscal and monetary policies. The following is the detail of projects completed by ICAI ARF during the last year:

- **Indian Railways** – During the year, ICAI ARF Nodal Team submitted Comprehensive Scope Evaluation Report of the "Roll out of accrual accounting in all the Zonal Railways, Production Units and other offices across Indian Railways "Project and is now recasting the Financial Statements of Indian Railways for the year 2015-16 and 2016-17 on accrual basis.
- **Tamil Nadu Civil Supplies Corporation** : ICAI ARF has started working on the following deliverables of the project:
  - Identify key gaps and prepare a Should Be Process document
  - Prepare a Request for Proposal (RFP) document to enable the corporation to select a suitable vendor / consider in-house option to develop a comprehensive IT system
- **Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited** :ICAI ARF was engaged to suggest Methodology for replacement of WPI) series 2004-05 (with WPI) series 2011-12 (for payment of price variation to contractors, the report on which is under preparation.
- ICAI ARF published the Project Report *The Impact of Mandatory Reporting under IFRS on Corporate Governance in India* "by Ms .Shigufta Uzma, Asst .Prof., NIT, Rourkela.
- ICAI ARF organized a full-day Conference on *Role of Accrual Accounting in Economic Development of Country* on 6<sup>th</sup> December 2017 in New Delhi. Mr. Ian Ball, Chairman, CIPFA International, Sh. Naresh Salecha, Principle Executive Director/Finance, Railway Board, Sh. Rajnish Kumar Jenaw, CCA, Jammu, Department of Posts shared their experiences with the audience which consisted of senior officials from O/o C&AG, Quality Council of India, Railway Board, Indian Railways, Northern Railway, Directorate of Printing, Ministry of Housing & Urban Affairs, Government Accounting Standards Advisory Board, NFCH, Ministry of Home Affairs, National Power Training Organization, Aeronautical Development Agency and other Government Local Bodies.

## 7.9 ICAI REGISTERED VALUERS ORGANISATION

ICAI Registered Valuers Organisation (ICAI RVO) is a Section 8 private Company formed by the Institute of Chartered Accountants of India to enroll and regulate the registered valuers or valuer member as its members in accordance with the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017, and functions incidental thereto.

**Role of ICAI Registered Valuers Organisation** - Following are some of the important Roles of ICAI RVO:

- a) To carry out the functions of the Registered Valuers Organization under the Companies Act 2013 read with Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017 and functions connected therewith and incidental thereto;
- b) to enrol the Registered Valuers and to educate and train them for carrying out effective Valuations;
- c) to employ fair, reasonable, just, and non-discriminatory practices for the enrolment and regulation of its members;
- d) to develop the profession of registered valuers;
- e) to promote continuous professional development of valuation professionals;
- f) to establish and promote high standards of practice and professional conduct of all its members and to prevent fraudulent behaviour and malfeasance in their conduct by continuously improve upon its internal Regulations and guidelines;
- g) to promote and safeguard the rights, privileges and interests of its members;

- h) to redress grievances against its members or against itself;
- i) to co-ordinate with and assist the Board in the implementation of the provisions of the Companies Act 2013 and the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017;

The ICAI Registered Valuers Organisation got recognition from the Insolvency and Bankruptcy Board of India as Registered Valuers Organisation on 15<sup>th</sup> May, 2018. The company commenced its activities in June 2018.

## 7.10 INDIAN INSTITUTE OF INSOLVENCY PROFESSIONALS OF ICAI

Indian Institute of Insolvency Professionals of ICAI (IIPI), is a Section 8 Public Company formed by the Institute of Chartered Accountants of India to enroll and regulate insolvency professionals as its members in accordance with the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and read with regulations and functions incidental thereto.

It has been awarded with the registration certificate as the First Insolvency Professional Agency of India by Hon'ble Union Finance Minister Shri Arun Jaitley on 28<sup>th</sup> November 2016 at Delhi. IIPI has attracted members from a diverse stream including Chartered Accountant, Company Secretary, Cost Accountant, Advocates and Management Professionals. CAs continues to be the bedrock on which IIPI stands, contributing over 90% of the present membership. Out of total 2037 Insolvency Professionals registered with IBBI, 1241 i.e. are from IIPI.

The initial phase of IIPI's operations have been focused on building its membership base and with the strengthening of the same the activities have become more broad-based.

### Initiatives:

- **Arrangement with Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW)** - IIPI has entered into an arrangement with Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW) for knowledge partnership.
- **Association with World Bank Group** - IIPI entered into an arrangement for conducting joint programmes in association with World Bank Group (WBG). The **1<sup>st</sup> Select Training Program** for IPs in India was conducted in Mumbai in January this year and was a resounding success. Subsequently a **"Meet Up"** session with World Bank has been organized by IIPI in Delhi & Mumbai June, 2018. Meanwhile, IIPI is working closely with the World Bank for a **"Train The Trainers"** program for intensive knowledge dissemination.
- **Conducted Indian Banks Association (IBA) – IIPI Program for Banks** - IIPI, along with IBA, organised an Interactive Program of Banks, IPs and other related entities, with actual ground level exposure in this area, Mumbai.
- **Learning Management System of Indian Institute of Insolvency Professionals of ICAI** - IIPI jointly with ICAI, has designed a Learning Management System to enable the professionals to prepare for the Insolvency Examination.
- **IIPI Newsletter & Journal** - IIPI Newsletter, giving the details of important events and developments relating to the Insolvency Profession are being hosted on the website. "The Resolution Professional" – a quarterly Journal of IIPI has been launched.
- **International Conference** - International Conference on "New Corporate Insolvency Regime" in association with National Council for Insolvency and Bankruptcy Code, ASSOCHAM India, SIPI, INSOL India, Edelweiss, United Nations Commission on International Trade Law, A&M
- **IP Conclave** - IBBI Insolvency Professionals Conclave was organized by IIPI on 26th May, 2018 in Mumbai.
- **Association with BFSI sector Skill council and NSDC** - IIPI has joined hands with BFSI sector Skill council and NSDC to conduct (a) One-Day upskilling program for all the Insolvency Professionals (IPs) registered (b) To commence "Insolvency Associate Course" as a support service for IPs.
- **Knowledge Quest** - A successful soft launch of "Knowledge Quest" has been made where the keynote address was delivered by the Executive Director of NeSL, the country's 1<sup>st</sup> Information Utilities (IU).
- **Online Utilities** - IIPI has developed various online utilities in its website [www.iiipicai.in](http://www.iiipicai.in) to capture the status of insolvency & liquidation assignments



## 8. OTHER MATTERS

### 8.1 Annual Function of the ICAI

The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) celebrated a year of noteworthy achievements and multiple milestones at its 68<sup>th</sup> Annual Function organised on 6<sup>th</sup> February 2018 at Vigyan Bhawan in New Delhi. The occasion not only looked back at the success that ICAI achieved in the year 2017-18, but also looked ahead and pondered over the potential of the Institute and Indian accountancy profession as partner in nation building in times to come. Union Minister for Commerce and Industry CA. Suresh P. Prabhu and Union Minister for Railways and Coal CA. Piyush Goyal graced the occasion as Chief Guests, while the Union Minister of State for Law and Justice, and Corporate Affairs Shri P. P. Chaudhary was the Guest of Honour, who all spoke highly of the Indian accountancy profession. Newly-elected Member of Parliament (Rajya Sabha) and ICAI past President CA. Narain Dass Gupta was also felicitated on the occasion in presence of a large gathering including a host of dignitaries from the accountancy profession, Government and other stakeholders. Meritorious CA students, and outstanding Regional Councils, Branches and overseas chapters were also honoured for their accomplishments during the event, which also witnessed the release of many ICAI Publications.

### 8.2 Chartered Accountants Day & Platinum Jubilee Celebrations

On 1<sup>st</sup> July, i.e. CA Day, ICAI stepped into the 70<sup>th</sup> year of its glorious existence. The Platinum Jubilee celebrations were launched by Hon'ble President of India, Shri Ram Nath Kovind in the presence of Shri Manoj Sinha, Hon'ble Union Minister of State (I/C) for Communication and Minister of State for Railways and Shri P. P. Chaudhary, Hon'ble Union Minister of State for Corporate Affairs during a function held at New Delhi on 1<sup>st</sup> July to commemorate the CA Day.

Coinciding with Platinum Jubilee celebrations, the following activities have been launched:

- Department of Post has released special commemorative stamp signifying ICAI's stellar contribution in national economic development.
- Special Scholarship to meritorious wards of Indian Armed Forces, Para Military Forces and Railway Personnel.
- Release of History of Accountancy Profession, Vol –III
- Release of Treasure Trove of Wisdom from Visionaries-Part II
- Other major initiatives launched for the benefit of members and students Unique Documents Identification Number (UDIN) service , e-CPE and ICAI TV, ICAI Knowledge Bank, ICAI Learning Curve
- Skill Development Program on GST for under-graduate Girls students launched.
- Blood Donation Camps and awareness campaign for Organ donation among Members & Students of ICAI.

On the occasion, special Lectures on 'Power of Positive Thinking' by Swami Sukhabodhananda, 'ICAI@70: Celebrating the Past, Inspiring the Future' by Padma Shri CA. T. N. Manoharan, Past President ICAI and 'You can Win If you think you can' by Shri Shiv Khera were also held on 1<sup>st</sup> July, 2018, Vigyan Bhawan, New Delhi.

As per the past practice, based on the communication forwarded by the PR Group to the Regional Councils and Branches, the members/ students/ officials across the country got united in their efforts to celebrate this prestigious occasion by undertaking social activities and programmes.

### 8.3 Central Council Library

Central Council Library of the Institute caters to the information requirements of its stakeholders. Its aim is to provide comprehensive and up-to-date collection of primary and secondary print and non-print material to the present and anticipated members/ students, research scholars and officials of ICAI. Library has assumed greater responsibilities of serving committees, departments in imparting knowledge and valuable information through books, e-books, journals, magazines, on-line databases, print newspapers as well as

e-newspapers. Central council library is responsible for updating and providing journals and books required for the various committees work.

The Central Council Library is fully computerized and working through Liberty- library management software. Library material including database of Books, Journals & Articles can be searched through Subject, Author, Title, Topic, Keyword, & Publisher wise. These records are available on Internet Online Services [www.icaai.org](http://www.icaai.org) under "know your Institute – Central Council Library"-online search OPAC-Liberty for the books, Journals, articles etc. in the library.

Under the column *Accountants Browser* of the Institute's journal, an index of articles relevant to accounting profession are published every month. One may note that the *Accountants Browser* is an index of important/professional articles with archives of the past articles. Reference service from library is also provided to the Researchers & Scholars, faculties, students and members.

A number of online databases have been acquired by the Library, details of which are available at [www.icaai.org](http://www.icaai.org) – Central Council Library. These online knowledge databases have been installed in the Central Council Library premises as well as at various Departments and also installed in Regional Council Libraries of ICAI, to facilitate the search for required material by the students, members, faculties and the research scholars. Several online journals have also been subscribed by the Library. Details of new resources added in the Central Council libraries at the Head office and at the Noida office respectively for the period 1<sup>st</sup> April 2017 to 30<sup>th</sup> June 2018, are:

#### **CENTRAL COUNCIL LIBRARY (H.Q).**

<b>S.NO.</b>	<b>Title</b>	<b>Figures</b>
1.	Journals (Print)- national & International	37
2.	E-Access to Journals subscribed	8
3.	Online Resources	11
4.	No. of Books added during the period	826

#### **CENTRAL COUNCIL LIBRARY SEC.62, NOIDA**

<b>S.NO.</b>	<b>Title</b>	<b>Figures</b>
1.	Journals (Print) - national & International	32
2.	E-Access to Journals subscribed	02
3.	Online Resources	06
4.	No. of Books added during the period	207

Central Council Library is regularly updating its resources to provide the professional Members, students, faculties & other stakeholders with the latest & upto date knowledge and information.

### **8.4 Editorial Board**

**Editorial Board: Disseminating Professional Knowledge in 'Letter' and Spirit:** Editorial Board is a non-standing committee of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) with a MISSION to convey regularly to the members the professional knowledge, matters of interest of profession through the journal 'The Chartered Accountant'. The reach and impact of the Journal can be gauged by its circulation figure which stands at about 3 lakhs today.

A 'Brand Ambassador' of ICAI and the most visible indicator of the Institute's profile for the members, students and external audiences, *The Chartered Accountant* today matches the global standards of professional Journals. The Editorial Board is continuously surging ahead with its mission to keep the ICAI members and other readers of the journal up-to-date on various topics and issues. Following are the most significant achievements from 31<sup>st</sup> March 2017 till 30<sup>th</sup> June 2018:

**Wide range of topics covered:** From April 2017 to July 2018 issues of the journal, about 400 articles/features and reports on various topics were published under various innovative theme issues.

**July 2018 Collector's Edition of ICAI Journal Brought out:** To mark this CA Day coinciding with the launch of ICAI's platinum jubilee celebrations, the special July 2018 issue of the journal was brought out as a collector's edition. The 204 page journal embodied the spirit of celebrations by publishing as many as

18 articles specially authored for the journal by national and international personalities related to accountancy profession. Besides, the journal carried inspiring CA Day messages from 26 eminent dignitaries that included Vice President of India M Venkaiah Naidu and a host of Union Ministers, Ministers of State, Justice Vinit Kothari etc. Other highlights of the issue included interviews of Chairperson of Insolvency and Bankruptcy Board of India Dr MS Sahoo and Chairman and Managing Director of Reliance Industries Limited Mr Mukesh Ambani, and special features like 'Excellence with a Difference,' 'Down the Memory Lane,' and 'Tracing the Roots'. The 'Our Achiever' section of this issue featured Union Minister of Railways and Coal CA. Piyush Goyal. The cover page of the journal artistically portrayed the celebratory spirit of ICAI entering into its Platinum Jubilee year.

**Another Regular Feature 'Our Achiever' Introduced:** As part of brand building exercise and highlight the vision of our outstanding members in public/professional life, a new two-page feature titled 'Our Achiever' has been introduced with effect from March 2018 issue. March 2018 issue covered Executive Director of ICICI Bank CA. Vishakha Mulye, April 2018 issue featured Union Commerce and Industry, and Civil Aviation Minister CA. Suresh Prabhu, May 2018 issue featured sitting Delhi High Court Judge Justice (CA.) Rajiv Shakdher, June 2018 issue featured ITAT (Income Tax Appellate Tribunal) President CA. G. D. Agrawal while July and August 2018 issues covered Union Minister of Railways and Coal CA. Piyush Goyal and Joint Secretary in the Ministry of External Affairs CA. Mahaveer Singhvi, IFS, respectively.

**e-Flash on Annual Budgets Every Year:** In view of the time gap between presentation of Budget in Parliament and actual publication of Budget issue of the Journal, an e-publication of Finance Bill amendments (e-Flash) was hosted on ICAI website and its link mass-mailed to members soon after actual presentation of Budget in Parliament for real-time update of the members.

**Strengthening Legal Update (Decisions) Section of the Journal:** A system has been put in place to strengthen/improve on the Legal Decisions section/feature of the Journal for the benefit of readers/members at large as a value-added service, in cooperation and coordination with Board of Studies, Direct Taxes Committee, Indirect Taxes Committee, International Taxation Committee, Corporate Laws and Corporate Governance Committee, Banking, Insurance and Pension Committee, Editorial Board and Committee on Economic, Commercial Laws & WTO.

**Two New Series of Insolvency and Disciplinary Cases introduced under Legal Update section of the journal:** Legal Update was further strengthened and made more informative with the introduction of two new series of most relevant Insolvency & Bankruptcy cases and Disciplinary Cases with effect from June 2017 issue of the journal.

**Know Your Ethics Re-Introduced:** Another useful feature for the members, *Know Your Ethics*, was re-introduced from June 2017 issue onwards. Contributed by Ethical Standards Board, the feature highlights the ethical issues concerning the profession and members in Question-Answer format.

**Encapsulated Information on Webcasts Published:** The Editorial Board decided to publish encapsulated information on webcasts (topics of webcasts along with their weblinks) held over the last three months for information and use by the readers as frequently as possible from November, 2017 issue of the Journal.

**Introduction of a Regular Feature ICAI in Media:** A new feature titled 'ICAI in Media' was introduced with effect from December 2017 issue of the journal under which some selected press clippings of positive media coverage of the ICAI were published.

### Many Facets of Digital Versions Upgraded

**eJournal:** The electronic version of *The Chartered Accountant journal*, which is available online on ICAI website [www.icai.org](http://www.icai.org) hi-tech user-friendly e-magazine, was further upgraded and migrated to a completely new eMagazine platform V6 based on the latest HTML5 technology. The new version of e-Journal is faster and more responsive, carrying better user experience and offering better mobile compatibility, which is in line with the expectations of our new generation of chartered accountant.

**Journal in PDF format:** However, for the added and alternative convenience of readers, particularly for separate content-wise downloads, the journal continues to be hosted in the PDF format and also in Indexed mode. The archives of digital journal are available on ICAI website from July 2002 onwards.

**Journal on Mobile:** Further, this eJournal is now also available on mobile, compatible on iOS (iPad/iPhone etc.) and Android devices. It can be accessed at <http://www.icaai.org/> under 'e-journal' tab. The eJournal is also available on ICAI Mobile App.

**Journal Highlight emailers:** As an add-on service, the highlights of every issue of journal in capsule form and the President Message in the journal are now mass-emailed to all the members.

**All Journals since 1952 in DVD:** In an important initiative to provide a single point reference window to the readers of *The Chartered Accountant* journal and leverage the technology to serve them better, a DVD of past issues of the journal is also available for readers and other stakeholders. While a DVD of 10 years of the journal (July 2002-June 2012) in PDF format has been brought out for readers at a nominal cost, a more recent HTMLised DVD containing 63 years of *The Chartered Accountant* journal (July 1952 to June 2015) has also been released. In this HTML-version DVD in a searchable mode, readers can global search the contents through key words relating to accounting, auditing, taxation, etc., besides searching by month, year, volume, category (like Circulars & Notifications, ICAI News, Legal Decisions, etc.), author, etc.

**'I GO GREEN WITH ICAI' Initiative:** As part of a multifarious Green Drive of the ICAI, the green-thinking members and other readers of *The Chartered Accountant* journal were recently given an option to opt for various electronic versions of *the* journal while discontinuing the hard copy, to save trees. A micro-website has been made live to secure the responses in this regard. In an encouraging response more 7000 readers have opted to discontinue the hard copy of the journal. Special efforts are being taken to propagate this initiative through continuous announcement on ICAI Homepage, regular announcements in the journal, taglines of the emails etc.

#### **Contribution in ICAI International Conference**

- (a) Brought out ***Daily Chronicle*** (newspaper) with full coverage of the proceedings of every day of the Conference, which was circulated among the participants
- (b) Published a 300 page + **backgrounder** for Mumbai International Conference (7<sup>th</sup>8<sup>th</sup> December 2017) carrying duly edited 41 articles and speakers' presentations and papers.

#### **Other Achievements**

**Complimentary List Updated:** As part of the brand building exercise and to deepen ICAI reach among the prominent personalities relevant to the profession, and consequent to the decisions taken by Editorial Board at its 313<sup>th</sup> meeting held on 28<sup>th</sup> March 2017 and subsequent suggestions from the designated Sub-Group of the Editorial Board, a massive revision including deletion of 647 irrelevant entries and addition of 203 relevant ones have been finally carried out in the Journal's existing *Complimentary List*, which has come into effect from July 2017 issue of the journal.

**Monitoring of Paper Quality of Journal:** As part of the continuous precautionary/monitoring process followed to ensure quality of the paper used in the Journal by the printer, the office got tested at random the paper used by the Printer through the Central Pulp and Paper Research Institute (CPPRI), an autonomous organisation under the Ministry of Commerce and Industry.

**Switchover to a new vendor for Journal printing, marketing and dispatch:** With effect from August 2018 issue of the journal, ICAI has switched over to a new vendor SAP Prints of Mumbai for printing, marketing and despatch of our members journal, replacing Spenta Multimedia also from Mumbai after due tender process. The agreement to this effect was signed in March 2017.

**Renewal of RNI certificate and Licence to Post for the journal:** Renewed RNI Certificate of the journal and Licence to Post without prepayment as part of the legal compliance.

**Form B Revised to ensure hindrance-free and timely printing and dispatch of journal at Government Concessional rates:** As part of compliance-related procedures, the office has got revised the Form B Declaration of ICAI journal *The Chartered Accountant*, which was necessary for ensuring

hindrance-free and timely printing and dispatch of the journal at concessional government rates through Department of Post.

**Facility of Pay Online for Journal Subscription, Airmail Surcharge:** In line with concerted efforts to harness technology for added convenience and services to our members, the Editorial Board operationalised the online payment facility for The Chartered Accountant journal, to benefit its readers across the globe. This reader-convenient online payment facility is available on the ICAI website for 10 categories of readers including subscribers, members abroad, classified advertisers and student subscribers.

**Anti-Plagiarism Software Agreement renewed:** Taking cognizance of a steep rise in cases of submission of plagiarised content by authors including academicians, members and students of ICAI, etc. which had the potential to adversely affect the credibility and reliability of The Chartered Accountant journal, a comprehensive anti-plagiarism policy in place was strengthened with renewal and reoperationalisation of Anti-plagiarism software agreement for this year.

**Process of verification of total number of journal copies printed/despached further strengthened:** As decided by the Editorial Board, the process of the verification of number of journal copies printed and despached has been further strengthened with introduction of a mechanism whereby the personnel of ICAI Office (WIRC) in Mumbai have started conducting monthly inspection (with effect from May 2017 issue of the journal) at Mumbai GPO on the posting dates of journal to ascertain as to all journals mentioned in the print order are being despached. This mechanism is in addition to regular verification by a Navi Mumbai-based auditor.

## 8.5 Accountancy Museum of India

Accountancy Museum was set up in February 2009 at the C-1, Sector-1, Noida premises of the Institute. The name of the Museum was changed to Accountancy Museum of India, after procuring due permission from the Ministry of Consumer Affairs in April 2009. In the year 2011, the Museum was shifted to Sector 62, Noida premises of the Institute.

Accountancy Museum of ICAI proudly displays old manuscripts, sculptures, images of important historical relevance, among others. Images of Sumerian clay bulla-envelope (a hollow clay envelope that stored clay tokens), complex counting tokens, clay tablets, etc., containing inscription of accounts, first coins of India and the world, etc., have also been displayed. Among the items on display, there are an old ledger of 1848 AD and sculptures of a traditional accountant or munim, Kubera, the deity of wealth (based on Kubera sculpture in the National Museum), Chanakya and Luca Pacioli, author of the first published book on double entry accounting and also known as father of accountancy for the same reasons. Replicas of Harappan seals are also on display.

**Prototypes at Regional Councils, DCOs and Branches:** Museum's prototypes have been set up at all 5 Regional Council offices and 13 DCOs (decentralised offices) of the Institute. Later, it was decided to set up the same at all Branches of the Institute. So, the prototype has been set up at 107 Branches so far, except for those, which expressed their inability due to lack of space. Prototype of Accountancy Museum basically meant the working model of the *Accountancy Museum* for display—with the idea to communicate to stakeholders of accountancy profession about its heritage, as well as to spread words about the existence of the *Accountancy Museum of India* located at the Sector-62, Noida premises of the Institute. The purpose was also to popularise the intellectual and noble profession and its heritage.

**Publications:** With the inauguration, the Museum published a booklet containing its brief description along with a set of 5 postcards containing relevant images in February 2008. Later, the booklet was revised and its second edition was published, which today is nominally priced at Rs. 10/- per copy. However, its copies have been distributed free-of-cost among the participants/ delegates on various important events of the Institute. It is hosted on the Museum's website.

**Website of Museum:** An independent website of the Museum, i.e. <http://ami-icai.org/>, was also set up in the year 2017 to address the requirements of the Museum for the benefit of the Museum as well as the stakeholders of the profession.

## 8.6 Amendments in the Chartered Accountants Regulations, 1988

The Council, at its 375<sup>th</sup> meeting held from 24<sup>th</sup> to 26<sup>th</sup> May 2018 and adjourned to/continued on 13<sup>th</sup> & 14<sup>th</sup> June and 18th June 2018, considered the Report of the Group for review of the existing procedure, rules and regulations pertaining to triennial elections to the Council and Regional Councils including Electronic-voting. After deliberations, the Council accepted the recommendations made by the Group and approved draft amendments in the Chartered Accountants (Election to the Council) Rules, 2006, the Chartered Accountants (Election Tribunal) Rules, 2006 and Chartered Accountants Regulations, 1988. Accordingly, the said proposals for amendments have been submitted to the Central Government for approval.

## 9. MEMBERS

### 9.1 Membership

During the year ended 31<sup>st</sup> March, 2018, 11,886 new members were enrolled by the ICAI bringing the total membership to 2,82,193 as on 1<sup>st</sup> April, 2018. During the year ended 31<sup>st</sup> March 2018, 3,367 associates were admitted as fellows, in comparison to the figure of 6,712 in the previous year.

#### Total Members as on 1.4.2018

Category of Members	Fellow (1)	Associate (2)	Total of Columns (1) and (2)
In Full Time Practice	75093	49580	<b>124673</b>
In Part-time Practice	2741	5066	<b>7807</b>
Not in Practice	14255	135458	<b>149713</b>
Total	<b>92089</b>	<b>190104</b>	<b>282193</b>

### 9.2 Convocation

Since November 2008, the Institute has been organizing Convocation to confer membership certificates to newly enrolled members. ICAI has successfully organized 1<sup>st</sup> round of "Convocation 2018" for the newly enrolled members covering the period from November, 2017 to May, 2018 on 2<sup>nd</sup> September, 2018 at following nine places under five Regional Offices:-

1. Ahmedabad
2. Mumbai
3. Pune
4. Chennai
5. Hyderabad
6. Kolkata
7. Jaipur
8. Kanpur
9. New Delhi

### 9.3 Chartered Accountants' Benevolent Fund

Established in December, 1962, the Chartered Accountants Benevolent Fund provides financial assistance to needy persons who are or have been members of the Institute as well as their dependents, for maintenance, their emergent educational and medical needs etc. The financial and other particulars of the Fund are as follows:

#### Details of Membership

1.	Total Life Members as on 31 <sup>st</sup> March, 2017	132883
2.	Total Life Members as on 31 <sup>st</sup> March, 2018	134596
3.	Total Additions of New Life Members (as on 31 <sup>st</sup> March, 2018)	1713

#### Details of Financial Particulars

	During the year ended 31 <sup>st</sup> March, 2018 (Rs.)	During the year ended 31 <sup>st</sup> March, 2017 (Rs.)
1. Total Assistance provided	92,10,500	1,13,28,500
2. Administrative Expenses	1,000	567
3. Surplus of the Fund during the year	2,04,80,000	69,93,000
4. Balance of the Fund	3,68,34,000	1,63,54,000
5. Balance of Corpus	19,86,23,000	18,49,63,000

#### 9.4 S. Vaidyanath Aiyar Memorial Fund

The number of life membership of the Fund increased from 7682 as on 31<sup>st</sup> March, 2017 to 7795 as on 31<sup>st</sup> March, 2018. The balance in the credit of the Fund was Rs. 47,97,000 as on 31<sup>st</sup> March, 2018 as against Rs.46,84,000/- as on 31<sup>st</sup> March, 2017.

#### 9.5 Chartered Accountants Student's Benevolent Fund (CASBF)

The Fund was established in August, 2008 with the aim and objective to provide financial assistance to the students registered with ICAI. The Scholarships for the year 2017-2018, 480 articled assistants who are registered for IPCC and IIPCC have been granted assistance @ Rs. 1500 p.m. and 231 articled assistants who are registered for final course granted financial assistance @ Rs. 2000/- p.m. is under consideration. The balance in the credit of the general fund was Rs. 13,91,82,000/- as on 31<sup>st</sup> March, 2018 as against Rs. 12,59,75,000/- as on 31<sup>st</sup> March, 2017.

#### STATISTICS MEMBERS

AS ON 01/04/2018

			12/01/2022
<b>FELLOWS</b>	<b>:</b>	In Full Time Practice	75093
		In Part-time Practice	2741
		Not in Practice	14255
			<b>92089</b>
<b>ASSOCIATES</b>	<b>:</b>	In Full Time Practice	49580
		In Part-time Practice	5066
		Not in Practice	135458
			<b>190104</b>
<b>TOTAL MEMBERSHIP :</b>		<b>282193</b>	

	FELLOWS				ASSOCIATES				
	In Practice				In Practice				
<i>Region</i>	Full Time	Part Time	Not In Practice	Total	Full Time	Part Time	Not In Practice	Total	Grand Total
Western	21824	779	4133	26736	17388	1859	51436	70683	97419
Southern	16124	740	3416	20280	7357	1059	26317	34733	55013
Eastern	7400	204	1308	8912	3846	323	11437	15606	24518
Central	14266	365	1863	16494	10806	778	20510	32094	48588
Northern	15479	653	3535	19667	10183	1047	25758	36988	56655
TOTAL	75093	2741	14255	92089	49580	5066	135458	190104	282193

#### 10. Board of Studies:

Board of Studies (BoS) of the Institute is responsible for the administration of the Chartered Accountancy curriculum and imparting theoretical instruction to approx. 7,25,632 students undergoing Chartered Accountancy course. Significant initiatives and achievements of the Board during the period are mentioned below:

## I. Educational Inputs

**Implemented the New Scheme of Education and Training:** The New Scheme is in tandem with the contemporary requirements and expectations from the profession and is in sync with the requisites of the dynamic global business environment.

**Revision of Study Materials:** As a part of continuous process of updating the knowledge of students, the contents of study materials at Intermediate (IPC) and Final levels have been updated /revised. In addition to above, following material were also brought out:

1) Supplementary Study Materials:

- Accounting
- Business Laws Ethics and Communication
- Corporate and Allied Laws
- Indirect Tax Laws

2) Revision Test Papers and Suggested Answers

The same were also hosted on the web site with free downloading facility. Also, as per Revised Scheme, Content of Study materials at Foundation, Intermediate Course and Final Course have been designed and developed.

**Students' Journal:** Another prominent step taken by the BoS during the year 2017-18 was preparation and publication of subject wise capsules in the Student Journal. This step has helped students in their revision of respective subjects.

## II. IT Initiatives

ICAI Cloud Campus provides One-Stop-Window for information, enrolment, educational, administrative, examination, and other requirements of Students for the CA Course. Moving ahead from the brick-n-mortar campus system, it provides distance education for the CA Course at the doorsteps of Students at the click of a button. It provides the following distance education facilities FREE of cost:

- **Video Lectures:** Video Based Training (VBT) Lectures for all subjects of CA Course are available on the ICAI Cloud Campus, which aim to teach step-by-step practical problem-solving process for the practical subjects and provide conceptual clarity for the theoretical subjects. Currently, 274 lectures covering 469 hours for new scheme and 664 lectures covering 559 hours for old scheme have been hosted on the Cloud Campus, as on June 29, 2018.
- **Digital Learning Hub:** Chapter-wise e-Books for all subjects of the new Scheme of education and training are available at the ICAI Cloud Campus through Digital Learning Hub. Students are able to annotate and make notes which will be retained in their user account. Till date, more than one lakh students have registered on the platform and are using the facility.
- **Webcasts:** LIVE webcasts by eminent faculty members had been organized on the methodology to crack each subject for the Final and Intermediate (IPC) May, 2017 and November, 2017 examination. Specialized webcasts were also organized on topics such as GST, Concurrent Audit, Drafting of Appeals, Return Filing etc. Recordings of these webcasts are available on the ICAI Cloud Campus.
- **Online Mentoring Sessions:** The BoS has organized LIVE online mentoring sessions by BoS faculty members to address students' queries on a topic. Recordings of these sessions are available on the ICAI Cloud Campus.
- **BoS Knowledge Portal:** The BoS Knowledge Portal provides all educational content for CA Course.

Other facilities available on the Cloud Campus are Articles Placement Portal, Centralized Distribution System and Online Registration Portal for GMCS, OC and ITT Courses.

- **Articles Placement Portal:** The Articles Placement Portal link enables students to register online and get selected for practical training in CA Firms in their preferred location.
- **Centralized Distribution System:** Through this online store portal, students, members and other stakeholders are able to order all relevant publications and artifacts online. The books are delivered to them at their doorsteps.



- **Online Registration Portal for ICITSS and Advanced ICITSS Courses:** The Online Registration Portal enables students to register online for MCS/ OC/ ITT Courses, select convenient batches at preferred location, batch transfer, faculty allocation, course scheduling, feedback submission and certificate generation. The students are able to pay the fees on line through this portal.

### III. Other Initiatives

**Student Activity Portal:** In order to enable students to register online for the various students related events of the Institute (conferences, seminars, quiz, talent hunt, workshops, short time courses, mock tests, festivals, sport competition, special counselling program etc.) a common Student Activity Portal has been put in place. The students would be now able to register themselves through this portal for any activity of the Institute. This would save their time and energy. Moreover, this portal would enable to capture the feedback of the students on various events and would allow them to check their CPE hours.

**Online Articles Placement Portal:** The Institute has put in place an Optional Online Articles Placement Portal. This portal assist eligible students to get placement in CA Firms for their articles training. This also allows firms of Chartered Accountants having vacancies for Articled Assistants to short list the candidates from the data and call the candidates for interviews/interaction at their offices to interact with the candidates. No Fee is charged from the participating CA Firms and Students registering on the Portal.

**Reading Rooms :** In order to provide reading space to CA Students and help them to book their seats anytime anywhere at the place of their choice, BoS has launched Reading Room Portal. The students will be able to register online for a day/ a week / a month at the Reading Rooms being run by our Regional Council and branches, across the country for which the services are available 24 \*7 and confirm their seats by paying directly to the selected centre via Paytm (Credit card/Debit card/Net banking/ Paytm Wallet) within 24 hours of registration. As of now, 116 libraries-cum-reading rooms and 41 additional reading rooms are being operated by Regional Councils and Branches.

**Signing of MOU with Banking, Financial Services and Insurance, Skill Council of India:** ICAI entered into an MOU with the Banking, Financial Services and Insurance, Skill Council of India, Government of India (BFSI SSC) on 19<sup>th</sup> January 2018 which has been formed under the aegis of the National Skill Development Corporation (NSDC). As per the MOU, both ICAI and BFSI SSC would synergise together to achieve a target of generating employment to nearly 500,000 people across the country in five years chiefly in the areas of accounting, finance, insurance, banking and taxation including GST. BFSI SSC would launch the courses in the specified areas, ICAI would act as a knowledge partner. ICAI will aide BFSI SSC in curriculum building and content creation. ICAI will also provide its network of trainers across the country as resources besides creating awareness about training activities of BFSI SSC amongst its members. The MOU corroborates the ICAI's mission of being an active partner in Nation building and an effective medium to disseminate the initiatives of the Government and a catalyst in helping the Government achieve its desired objectives.

### II. Development Programmes

**Four-Week Residential Programme on Professional Skills Development:** Six batches (five at Centre of Excellence, Hyderabad, and one at Centre of Excellence, Jaipur) were held during the year and 191 students were trained.

**National Talent Hunt- 2017-18:** For the first time, Grand finale of elocution and quiz contest was organised under the banner of National Talent Hunt with huge success on 16<sup>th</sup> December 2017, wherein 20 best speakers of the countries after contesting with 1292 students at 89 branches participated. Board of Studies conducted grooming sessions on 13<sup>th</sup>-15<sup>th</sup> December 2017 to fine tune their oratory and presentation skills prior to the main event.

The event was graced by Shri Manoj Tiwari ( MP, Lok Sabha) as Chief Guest and the Jury comprised CA. Rohini Aggarawal, CA. Amey Naik, CA. Atul Chawla and CA. Dharmendra Gemini along with the Hon'ble Vice-President and Council Members of the Institute.

The first two winners of Elocution Contest and winner team of Quiz Contest participated at the Quiz and Elocution Contest organised by South India Federation of Accountants, a body consisting of SAARC countries on 30<sup>th</sup> January 2018 in Kathmandu. Ms. Janani Kadirvelu Palanivelu from Chennai, Mr. Satyam Shrey Gupta from Meerut was declared the first, second winners from India.

**Teachers' Day on 5th September, 2017:** Teachers' Day was celebrated with the theme *MY PRINCIPAL – MY STRENGTH* across the country through Regional Councils and Branches on 5<sup>th</sup> September 2017 so as to have a strong teacher and student relationship between CAs and CA students. To create a feel of reverence and gratitude in students for their mentor the Board facilitated the students with Display Picture (DP) related to theme, e-cards and SMS quotes.

Photo Competition on this occasion was also organised wherein students were required to upload his/her/their photos with their principal as per their theme on the portal. Essay competition and Quotation Competition was organized at Regional and Branch level.

On this occasion, webcast was conducted for the CA students and members, which was addressed by the ICAI President, BoS Chairman and Vice-Chairman, Padma Shri awardee CA. T. N. Manoharan, and Central Councils Members. Teachers Day Celebration was a grand success.

**CA Students Talent Search-2018:** BoS of ICAI organised 'CA Students' Talent Search' on 28<sup>th</sup> June 2018 in New Delhi, wherein students from all over the country participated in quiz contest, elocution, instrumental music and nukkad drama at various branches of ICAI and the winners reached the Regional level contest. 69 students were the final contestants and were invited for Grand Finale.

BoS groomed the twenty contestants of Elocution for a day prior of the Grand Finale so as to fine tune their oratory and presentation skills.

The event was graced by Ms. Rachel Grimes (President, IFAC) as Chief Guest and ICAI President, Vice-President, Chairman, BoS, Vice-Chairman, BoS, Central Council Member of ICAI, SAFA delegate. Jury comprised CA. Bhawana Singhal, CA. Arun Garg, Dr. P. C. Jain, and CA. Manpreet Singh.

**Mock Test Paper for the students of May,18 Examination:** Board of Studies organized Mock Test Paper for the students of Foundation, Intermediate/IPCC and Final (Old & New) for May 2018 Examination. The statistics regarding mock test paper for May 2018 Examination are as follows:

Course	Level	Series - I		Series - II	
		No. of RCs / Branches conducted	No. of students in all papers	No. of RCs / Branches conducted	No. of students in all papers
Old	IPCC	115	8695	32	6641
	Final	115	17447	32	14698
New	Foundation	115	2179	32	1559
	Intermediate	115	8027	32	6234
	Final	115	1430	32	1274

Similarly, Board of Studies organized Mock Test Paper for the students of CPT for June 2018 Examination. The statistics regarding mock test paper for May 2018 Examination are:

Course	Series - I		Series – II	
	No. of RCs / Branches conducted	No. of students in all papers	No. of RCs/ Branches conducted	No. of students in all papers
CPT	85	6694	73	4127

#### **Student Support Initiative: Toll Free Helpline at BoS, Sector 62, Noida**

- **Toll Free Helpline:** BoS initiated a **Toll-free Help line service** as a student support initiative from 11<sup>th</sup> May 2017 to redress queries/grievances of CA students from across the country.  
Number: **18001211330**  
Timings: **10 AM to 5:30 PM Monday to Friday**

- **Single point of contact:** The facility serves as a single point of contact for students located nationwide.
- **High response rate:** Over 150 calls are received daily, being answered to the students' satisfaction by a well-trained workforce of **four** executives under the supervision of Students' Counselor. Till date about **90,000** queries have been responded to from students all over the country.
- **Free access:** The service is free of cost to enable students from far-flung rural areas across the country to reach out to BOS through the easily accessible service.
- **Timely Delivery and Closure of grievances:** The purpose of this service initiative is to provide timely information (both generic and subject specific) to students up to their requirement and resolving students' grievances at the earliest.
- **Disseminating latest information (unambiguously):** The information disseminated is up to date and unambiguous to enable the student comprehend the regulations, systems and procedures threadbare and the related notifications posted on the website from time to time.

**1. Detail of GMCS, MCS Course and Orientation Course (01/04/2017 to 30/06/2018)**  
**GMCS Course (01/04/2017 to 30/08/2017)**

Sl. No.	Regions/Centres	No. of Centers	No. of batches	No. of students
1	WIRC & Branches	13	55	2597
2	SIRC & Branches	10	27	1182
3	EIRC & Branches	03	07	287
4	CIRC & Branches	17	31	1203
5	NIRC & Branches	09	28	1305
<b>TOTAL</b>		<b>52</b>	<b>148</b>	<b>6574</b>

**Advanced ICITSS-MCS Course (01/07/2017 to 30/06/2018)**

Sl. No.	Regions/Centres	No. of Centers	No. of batches	No. of students
1	WIRC & Branches	27	271	12164
2	SIRC & Branches	25	173	7940
3	EIRC & Branches	06	44	2071
4	CIRC & Branches	42	198	8196
5	NIRC & Branches	16	151	7025
6	Dubai	01	02	16
<b>TOTAL</b>		<b>117</b>	<b>839</b>	<b>37412</b>

**ICITSS -Orientation Course (01/04/2017 to 30/06/2018)**

Sl. No.	Regions/Centres	No. of Centers	No. of batches	No. of students
1	WIRC & Branches	35	459	21214
2	SIRC & Branches	43	559	25701
3	EIRC & Branches	9	99	4183
4	CIRC & Branches	45	370	16392
5	NIRC & Branches	21	182	7462
6	Dubai	1	1	17
<b>TOTAL</b>		<b>154</b>	<b>1670</b>	<b>74969</b>

Two-Day Master Training Programme (MTP) was conducted on 29<sup>th</sup>-30<sup>th</sup> January 2017 in New Delhi, whereat 36 faculty members were trained for the MCS course.

- 1. Development of ICITSS and AICITSS (IT and Adv. IT) course material:** Under the new scheme, the new contents have been developed / changed as per the syllabus approved by the Council. The suggested allocation of hours for IT and Adv. IT course content is:

**ICITSS - Information Technology**

Sr.	Topic	Duration (Hours)
1.	E Learning-Computer Fundamentals, OS, CBS	10
2.	MS - Word	6

3.	MS - Excel	30
4.	MS - PowerPoint	12
5.	MS - Access	6
6.	CAAT	18
7.	Accounting Package	18

### AICITSS - Advanced Information Technology

Sr.	Topic	Duration (Hours)
1.	Auditing in an ERP Environment	44
2.	Advanced Excel	18
3.	MS Excel as Audit Tool	18
4.	Database Application using MS Access	12
5.	Enterprise Resource Planning	18

- 2. Development / Updation of the Practice Manual for Adv. IT course:** A Practice Manual consists of 132 Exercise/Case Study has been introduced to provide greater practical hands-on training as a part the course.
- 3. Video Lectures on AICITSS - Advanced Information Technology:** 26 hours of video lectures have been recorded on syllabus covering MS-Excel as Audit Tool, Auditing in ERP Environment, Database Application using MS – Access, Advance MS - Excel and ERP (Tally).
- 4. Video Lectures on ICITSS - Information Technology:** 20 hours of video lectures have been recorded on syllabus covering MS-Excel, MS Word, MS PowerPoint, E- Learning on Computer Fundamentals, Operating System & CBS, CAAT, Accounting Package and MS-Access.
- 5. Faculty Development on AICITSS - Advanced Information Technology:** 3 (three) Faculty Development Programmes on Adv. IT course were organised in New Delhi, Hyderabad and Mumbai, wherein 116 faculties were given hands-on training on the updated course curriculum under new Scheme of education and training of CA course. The training focused on new topics namely Audit in ERP environment, MS-Excel as an audit tool, CAAT, overview of GST, etc.
- 6. Regional Offices and Branches have been organized and trained the students since 1<sup>st</sup> April 2017 to 30<sup>th</sup> June 2018 is:**

Course	No. of Batches	No. of students Trained.
ITT	837	26294
ICITSS- IT	1406	40089
Adv. IT	139	4026
AICITSS- Adv. IT	822	26668
<b>Total</b>	<b>3204</b>	<b>97077</b>

- 7. Status of Declaration of results of the Advanced Integrated Course on Information Technology and Soft Skills (AICITSS) - Advanced Information Technology Test:** After concerted efforts by the office, the current status of AICITSS - Adv. IT Exam held on 21<sup>st</sup> January 18<sup>th</sup> February, 18<sup>th</sup> March and 22<sup>nd</sup> April 2018.

Exam Date	Total Appeared Exam	Students Qualified Test
<b>January 21,2018</b>	2,956	2,843
<b>February 18, 2018</b>	5,070	4,890
<b>March 18,2018</b>	5,183	5,121
<b>April 22,2018</b>	2,373	2329
<b>Total</b>	<b>15,582</b>	<b>15,183</b>

Note: 8239 students will appear in 5th Test of (AICITSS) - Advanced Information Technology held on 8<sup>th</sup> July 2018.

### V. MoUs/ MRAs/Recognitions/Other Arrangements

**Recognition of CA Course for Ph.D Programme:** With the constant follow up with various Universities, the Board of Studies has been successful in obtaining recognition for CA Course from 102 Universities, 6 IIMs and 2 IIT Bombay & Madras (Total 110) for the purpose of pursuit of Ph.D./Fellow Programme.

**VI. Conferences/ Conventions/ Seminars and other activities**

**Students' Conferences :** National Conference, CA Student Conference and International Conference for CA students: During the period 2017-2018, Board of Studies organised 4 National Conferences at Mumbai, Chennai, Kolkata and Indore in addition to 39 CA Student Conference organised at various places all over the India and International Conference at Pune and around 33,000 students participated in these students conferences.

**Joint Seminars with Universities:** One Joint Seminar was organized with Pondicherry University, Puducherry.

**VII. Scholarships granted to students**

The Board of Studies awards Scholarships twice a year under various categories, namely Merit, Merit cum need, Need Based and Weaker Sections, Endowment. Accordingly, during the year, the Board of studies awarded 1144 Scholarships to selected students under above categories.

**11. REGIONAL COUNCILS AND THEIR BRANCHES**

The ICAI has five Regional Councils, namely Western India Regional Council, Southern India Regional Council, Eastern India Regional Council, Central India Regional Council and Northern India Regional Council with their Headquarters at Mumbai, Chennai, Kolkata, Kanpur and New Delhi respectively. Currently it has 164 Branches, 31 Chapters outside India and 15 Regional Libraries all over India.

**11.1 Award for Best Regional Council, Best Branch of Regional Council, Best Students' Association and Best Branch of Students' Association.**

These awards are given by the ICAI every year. The awards are given on the basis of overall performance and established norms. For the year 2017, these Shields were awarded at the Annual Function held on 6<sup>th</sup> February, 2018 to the following winners:-

**1. Best Regional Council**

- First Prize : Western India Regional Council
- Second Prize : Eastern India Regional Council

**2. Best Branch of Regional Councils**

1. Mega Category
  - First Prize : Ahmedabad Branch of WIRC of ICAI
  - Second Prize : Indore Branch of CIRC of ICAI
2. Large Category
  - First Prize : Ernakulam Branch of SIRC of ICAI
  - Second Prize : Nagpur Branch of WIRC of ICAI
3. Medium Category
  - First Prize : Siliguri Branch of EIRC of ICAI
  - Second Prize : Salem Branch of SIRC of ICAI
4. Small Category
  - First Prize : Bhilai Branch of CIRC of ICAI
  - Second Prize : Jalgaon Branch of WIRC of ICAI
5. Micro Category
  - First Prize : Sivakasi Branch of SIRC of ICAI
  - Second Prize : Tuticorin Branch of SIRC of ICAI

**3. Best Students' Association**

- First Prize : Western India Chartered Accountants Students' Association
- Second Prize : Eastern India Chartered Accountants Students' Association

**4. Best Branch of Students' Association**

- a. Large Category
  - First Prize : Ahmedabad Branch of WICASA of WIRC of ICAI
  - Second Prize : Nagpur Branch of WICASA of WIRC of ICAI
- b. Medium Category
  - First Prize : Bhilai Branch of CICASA of CIRC of ICAI
  - Second Prize : Aurangabad Branch of WICASA of WIRC of ICAI

- c. Small Category  
 First Prize : Sivakasi Branch of SICASA of SIRC of ICAI  
 Second Prize : Siliguri Branch of EICASA of EIRC of ICAI

## 11.2 Decentralised Offices

Recognising the value of expeditious and personalised service which are achievable through the process of decentralisation, the Council of the ICAI has set up eighteen Decentralised Offices as under:-

Mumbai	Chennai	Kolkata	Kanpur	New Delhi	Ahmedabad
Bangalore	Hyderabad	Pune	Jaipur	Nagpur	Surat
Vadodara	Thane	Ernakulam	Coimbatore	Indore	Chandigarh

## 12. FINANCE AND ACCOUNTS

The Balance Sheet as on 31<sup>st</sup> March, 2018 and the Income & Expenditure Account for the year ended on that date duly audited by the Auditors are published hereinafter.

## 13. APPRECIATION

The Council is grateful to members of the profession who functioned as co-opted members on its Committees, persons nominated on the Boards/ Committees constituted under the Chartered Accountants Act, 1949, the Regional Councils, its branches, and their members, and to the non-members who assisted the Council during the year 2017-18 in the conduct of its educational, technical and other developmental activities and in its examinations.

The Council wishes to place on record its appreciation of the continued assistance and support given by the Central Government and its nominees on the Council during the year 2017-18.

The Council wishes to place on record its heartfelt gratitude to Hon'ble President of India, Shri Ram Nath Kovind, Hon'ble Union Minister of State (I/C) for Communication & Minister of State for Railways, Shri Manoj Sinha, Hon'ble Union Minister State for Corporate Affairs, Shri P.P. Choudhary, Union Minister for Commerce and Industry CA. Suresh P. Prabhu and Union Minister for Railways and Coal CA. Piyush Goyal and other dignitaries who were kind enough to grace the various programmes of the ICAI.

The Council also desires to place on record its sincere appreciation to the various functionaries at State level who graced programmes organised by the organs of the ICAI.

The Council also acknowledges its appreciation of the sincere interest evinced by various State Governments in the numerous initiatives taken by the ICAI and the steps already/ being initiated by them, pursuant to such initiatives.

The Council also acknowledges its appreciation of the sincere and devoted efforts put in during the year 2017-18 and thereafter by all officers and employees of the ICAI.

## STATISTICS AT A GLANCE

### MEMBERS REGISTERED

(From 1<sup>st</sup> April, 2007)

TABLE I

Year (As on)		Western Region	Southern Region	Eastern Region	Central Region	Northern Region	TOTAL
1 <sup>st</sup> April, 2007	Associate	31159	18237	7829	9642	14182	81049
	Fellow	16896	13646	6488	8882	12880	58792
	Total	48055	31883	14317	18524	27062	139841
1 <sup>st</sup> April, 2008	Associate	32364	19203	7939	10045	14642	84193
	Fellow	17646	14034	6738	9472	13398	61288

	Total	50010	33237	14677	19517	28040	145481
1 <sup>st</sup> April, 2009	Associate	34294	20666	8193	10578	15951	89682
	Fellow	18442	14516	7002	10007	13951	63918
	Total	52736	35182	15195	20585	29902	153600
1 <sup>st</sup> April, 2010	Associate	36390	21733	8512	11252	17104	94991
	Fellow	19181	15076	7192	10615	14461	66525
	Total	55571	36809	15704	21867	31565	161516
1 <sup>st</sup> April, 2011	Associate	38608	22998	9154	12329	18547	101636
	Fellow	19831	15612	7406	11182	14943	68974
	Total	58439	38610	16560	23511	33490	170610
1 <sup>st</sup> April, 2012	Associate	45273	25505	11069	15963	23332	121142
	Fellow	20510	16132	7578	11720	15431	71371
	Total	65783	41637	18647	27683	38763	192513
1 <sup>st</sup> April, 2013	Associate	52846	28020	13258	20606	27743	142473
	Fellow	21522	16918	7815	12327	16051	74633
	Total	74368	44938	21073	32933	43794	217106
1 <sup>st</sup> April, 2014	Associate	56595	29401	14035	22978	29467	152476
	Fellow	22313	17460	8007	12915	16508	77203
	Total	78908	46861	22042	35893	45975	229679
1 <sup>st</sup> April, 2015	Associate	60229	30126	14514	24702	31137	160708
	Fellow	22838	17864	8137	13441	16986	79266
	Total	83067	47990	22651	38143	48123	239974
1 <sup>st</sup> April, 2016	Associate	64235	31919	15046	27353	32774	171327
	Fellow	23700	18495	8223	14071	17521	82010
	Total	87935	50414	23269	41424	50295	253337
1 <sup>st</sup> April, 2017	Associate	67746	33591	15580	30036	34632	181585
	Fellow	25742	19711	8718	15618	18933	88722
	Total	93488	53302	24298	45654	53565	270307
1 <sup>st</sup> April, 2018	Associate	70683	34733	15606	32094	36988	190104
	Fellow	26736	20280	8912	16494	19667	92089
	Total	97419	55013	24518	48588	56655	282193

**MEMBERS**(From 1<sup>st</sup> April, 1950)**TABLE II**

	Associate	Fellow	Total
As on 1 <sup>st</sup> April, 1950	1,120	569	1,689
As on 1 <sup>st</sup> April, 1951	1,285	672	1,957
As on 1 <sup>st</sup> April, 1961	4,059	1,590	5,649
As on 1 <sup>st</sup> April, 1971	7,901	3,326	11,227
As on 1 <sup>st</sup> April, 1981	16,796	8,642	25,438
As on 1 <sup>st</sup> April, 1991	36,862	22,136	58,998
As on 1 <sup>st</sup> April, 2001	51,603	44,789	96,392
As on 1 <sup>st</sup> April, 2002	54,666	47,064	1,01,730
As on 1 <sup>st</sup> April, 2003	60,619	49,637	1,10,256
As on 1 <sup>st</sup> April, 2004	63,384	52,707	1,16,091
As on 1 <sup>st</sup> April, 2005	68,052	55,494	1,23,546
As on 1 <sup>st</sup> April, 2006	73,778	57,168	1,30,946
As on 1 <sup>st</sup> April, 2007	81,049	58,792	1,39,841
As on 1 <sup>st</sup> April, 2008	84,193	61,288	1,45,481
As on 1 <sup>st</sup> April, 2009	89,682	63,918	1,53,600

As on 1 <sup>st</sup> April, 2010	94,991	66,525	1,61,516
As on 1 <sup>st</sup> April, 2011	1,01,636	68,974	1,70,610
As on 1 <sup>st</sup> April, 2012	1,21,142	71,371	1,92,513
As on 1 <sup>st</sup> April, 2013	1,42,473	74,633	2,17,106
As on 1 <sup>st</sup> April, 2014	1,52,476	77,203	2,29,679
As on 1 <sup>st</sup> April, 2015	1,60,708	79,266	2,39,974
As on 1 <sup>st</sup> April, 2016	1,71,327	82,010	2,53,337
As on 1 <sup>st</sup> April, 2017	1,81,585	88,722	2,70,307
As on 1 <sup>st</sup> April, 2018	1,90,104	92,089	2,82,193

**STUDENTS REGISTERED***(From 31<sup>st</sup> March, 2010)*

During the year	Foundation as per new CRET	Final	New Final	CPT	PCC	IPCC & IIPCC	Intermediate	ATC	Total
2009-10	-	24,172	-	1,67,073	1,860	80,745	-	3,376	2,77,226
2010-11	-	57,175	-	1,55,217	329	67,984	-	1,906	2,82,611
2011-12	-	47,515	-	1,61,712	-	85,053	-	2,099	2,96,379
2012-13	-	45,102	-	1,61,084	-	1,02,406	-	2,615	3,11,207
2013-14	-	39,348	-	1,54,742	-	96,285	-	3,209	2,93,584
2014-15	-	36,950	-	1,41,241	-	66,570	-	881	2,45,642
2015-16	-	31,669	-	1,25,140	-	77,962	-	1,249	2,36,020
2016-17	-	27,611	-	1,07,392	-	81,886	-	1,430	2,18,319
2017-18	9,788	26,291	14,056	73,804	-	22,657	63,693	-	2,10,289



**COMPOSITION OF THE COUNCIL - (2018-2019)**

<b>President</b>		<b>Members of the Council</b>	
CA. Naveen N.D. Gupta		<b>Elected Members</b>	
		CA. Ranjeet Kumar Agarwal	Kolkata
		CA. Sanjay Kumar Agarwal	New Delhi
		CA. Shyam Lal Agarwal	Jaipur
		CA. Manu Agrawal	Kanpur
		CA. Babu Abraham Kallivayalil	Kochi
		CA. Anil Satyanarayan Bhandari	Mumbai
		CA. Sanjiv Kumar Chaudhary	New Delhi
		CA. Jay Chhaira	Surat
		CA. Prafulla Preme Sukh Chhajed	Mumbai
		CA. M. Devaraja Reddy	Hyderabad
		CA. Tarun Jamnadas Ghia	Mumbai
		CA. Sushil Kumar Goyal	Kolkata
		CA. Atul Kumar Gupta	Delhi
		CA. Naveen N.D. Gupta	New Delhi
		CA. Vijay Kumar Gupta	Faridabad
		CA. Nandkishore Chidamber Hegde	Mumbai
		CA. Nihar Niranjan Jambusaria	Mumbai
		CA. Dhiraj Kumar Khandelwal	Mumbai
		CA. Mangesh Pandurang Kinare	Thane
		CA. Sripriya Kumar	Chennai
		CA. Mukesh Singh Kushwah	Ghaziabad
		CA. Madhukar Narayan Hiregange	Bengaluru
		CA. (Dr.) Debashis Mitra	Guwahati
		CA. G. Sekar	Chennai
		CA. Dhinal Ashvinbhai Shah	Ahmedabad
		CA. Prakash Sharma	Jaipur
		CA. Rajesh Sharma	Delhi
		CA. Kemisha Soni	Indore
		CA. Sanjay Vasudeva	New Delhi
		CA. M.P. Vijay Kumar	Chennai
		CA. Nilesh Shivji Vikamsey	Mumbai
		CA. Shiwaji Bhikaji Zaware	Pune
		<b>Nominated Members</b>	
		Shri. Anurag Agarwal (w.e.f. 05-06-2018)	New Delhi
		Shri. Manoj Kumar (12 <sup>th</sup> February 2016 – 23 <sup>rd</sup> March 2017)	New Delhi
		Shri. K. V. R. Murty (23 <sup>rd</sup> March 2017-05 <sup>th</sup> June 2018)	New Delhi
		Shri Vithayathil Kurian (11 <sup>th</sup> April, 2016 – 28 <sup>th</sup> August, 2018)	New Delhi
		Ms. Ritika Bhatia (w.e.f. 28 <sup>th</sup> August, 2018)	New Delhi
		Dr. Guruprasad Mohapatra (12 <sup>th</sup> February 2016-23 <sup>rd</sup> March 2017)	New Delhi
		Dr. Sudhanshu Pandey (w.e.f. 23 <sup>rd</sup> March 2017)	New Delhi
		Mr. Chandra Wadhwa	
		Dr. P. C. Jain	Delhi
		Shri. Sunil Kanoria	New Delhi
		Ms. Indu Malhotra (12 <sup>th</sup> February 2016-23 <sup>rd</sup> March 2017)	New Delhi
		Dr. Ravi Gupta (w.e.f. 23 <sup>rd</sup> March 2017)	New Delhi
		Shri. Vijay Kumar Jhalani	New Delhi
<b>Vice-President</b>			
CA. Prafulla Preme Sukh Chhajed			
<b>Period</b>			
12 <sup>th</sup> February 2018 onwards			
<b>Secretary to the Council</b>			
Mr. V. Sagar			

**Hingorani M. & Co.**  
**Chartered Accountants**

**Khanna & Annadhanam**  
**Chartered Accountants**

## **INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

### **To the Council of the Institute of Chartered Accountants of India**

#### **Report on the Financial Statements**

We have audited the accompanying financial statements of The Institute of Chartered Accountants of India ("the Institute"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2018, the Statement of Income and Expenditure and Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information (herein after referred to as "Financial Statements").

#### **Management's Responsibility for the Financial Statements**

The Institute's Management is responsible for the preparation of these Financial Statements in accordance with the Chartered Accountants Act, 1949 that give a true and fair view of the state of affairs, financial performance and cash flows of the Institute in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records for safeguarding of the assets of the Institute and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

#### **Auditor's Responsibility**

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors' consider internal control relevant to the Institute's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on whether the Institute has in place an adequate internal control system over financial reporting and the operating effectiveness of such controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

### **Opinion**

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements for the year ended March 31, 2018 are prepared in all material respect in accordance with the Chartered Accountants Act, 1949, and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India of the state of affairs of the Institute as at March 31, 2018, its surplus and its cashflow for the year ended on that date.

### **Other matters**

We did not audit the financial statements of the Institute's Decentralised offices, Computer Centre, Students Associations, Regional Councils and their Branches (collectively known as Branches) whose financial statements reflect total assets of Rs. 82141 lakhs, total revenues of Rs. 24123 lakhs and net cash flows / (outflow) amounting to Rs. 596 lakhs are considered in the financial statements, have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the Management. Our opinion on the financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these Branches are based solely on the reports of the other auditors.

### **Report on Other Regulatory Requirements**

#### **Further, we state that:**

- a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose our audit;
- b) In our opinion proper books of account have been kept by the Institute so far as appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purpose of our audit have been received from the decentralised office, computer centre, students association, regional council and their branches.
- c) The Institute's Balance Sheet, Statement of Income and Expenditure, and Statement of Cash Flow dealt with by this Report are in agreement with the books of account.

#### **For Hingorani M. & Co.**

Chartered Accountants  
Firm Reg. No.006772N

Sd/-

#### **CA. Jagdish Prasad Dhamija**

Partner  
Membership No.015020

#### **For Khanna & Annadhanam**

Chartered Accountants  
Firm Reg. No.001297N

Sd/-

#### **CA. B.J. Singh**

Partner  
Membership No.007884

Place: New Delhi.

Date: 26<sup>th</sup> September, 2018


**THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**

ICAI Bhawan, Indraprastha Marg, New Delhi - 110 002

**BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2018**

	Particulars	Note No	As at March 31,	
			2018	2017
			(₹ in Lakhs)	
<b>I</b>	<b>SOURCES OF FUNDS</b>			
	<b>i. SURPLUS AND EARMARKED FUNDS</b>			
	a. Reserves and surplus	3	1,28,239	1,13,941
	b. Earmarked funds	4	39,370	34,329
	<b>ii. NON - CURRENT LIABILITIES</b>			
	a. Other long-term liabilities	5	1,219	731
	b. Long-term provisions	6	22,941	16,338
	<b>iii. CURRENT LIABILITIES</b>			
	a. Trade payables	7	3,677	3,191
	b. Other current liabilities	8	24,274	19,345
	c. Short-term provisions	6	1,307	937
	<b>TOTAL</b>		<b>2,21,027</b>	<b>1,88,812</b>
<b>II</b>	<b>APPLICATION OF FUNDS</b>			
	<b>i. NON - CURRENT ASSETS</b>			
	a. Fixed assets			
	i) Tangible assets	9	54,363	51,615
	ii) Intangible assets	10	55	19
	iii) Capital work-in-progress	11	10,877	13,875
	b. Non-current investments	12	76,535	24,631
	c. Assets held for Earmarked and other Funds	13	5,229	3,630
	d. Long-term loans and advances	14	3,397	2,987
	e. Other non-current assets	15	678	1,684
	<b>ii. CURRENT ASSETS</b>			
	a. Current investments	12	2,506	8,091
	b. Assets held for Earmarked and Other Funds	13	54,704	70,388
	c. Inventories	16	1,080	1,001
	d. Cash and bank balances	17	6,824	5,035
	e. Short-term loans and advances	14	2,714	2,252
	f. Other current assets	15	2,065	3,604
	<b>TOTAL</b>		<b>2,21,027</b>	<b>1,88,812</b>

See accompanying notes 1 to 27 forming part of the financial statements

For and on behalf of the Council

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
<b>CA. Sudeep Shrivastava</b>	<b>V. Sagar</b>	<b>CA. Prafulla P. Chhajed</b>	<b>CA. Naveen N. D. Gupta</b>
Joint Secretary	Secretary	Vice-President	President

In our report referred to even date

**For Hingorani M. & Co.**

Chartered Accountants

Firm registration number: 006772N

**For Khanna & Annadhanam**

Chartered Accountants

Firm registration number: 001297N

Sd/-

**CA. Jagdish Prasad Dhamija**

Partner, Membership No. 015020

New Delhi, 26th September, 2018.

Sd/-

**CA. B.J. Singh**

Partner, Membership No. 007884


**THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**

ICAI Bhawan, Indraprastha Marg, New Delhi - 110 002

**STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2018**

Particulars		Note No	For the year ended March 31,	
			2018	2017
			(₹ in Lakhs)	
<b>I</b>	<b>INCOME</b>			
	a) Fees	18	62,526	48,585
	b) Seminars	19	5,761	5,529
	c) Other income	20	12,322	10,989
	<b>Total income</b>		<b>80,609</b>	<b>65,103</b>
<b>II</b>	<b>EXPENSES</b>			
	a) Seminars and training programmes		6,036	6,108
	b) Employee benefit expenses	21	16,872	17,190
	c) Printing and stationery		5,810	6,441
	d) Professional fees paid to examiners and consultants		8,005	6,812
	e) Depreciation and amortisation expense	9-10	2,257	2,334
	f) Other expenses	22	22,770	19,902
	<b>Total expenses</b>		<b>61,750</b>	<b>58,787</b>
<b>III</b>	<b>NET SURPLUS (I-II)</b>		<b>18,859</b>	<b>6,316</b>
<b>IV</b>	<b>APPROPRIATION TO FUNDS / RESERVES</b>			
	a) Education Fund [ See Note 2.6 (iii) ]		5,073	3,158
	b) Employees Benevolent Fund [ See Note 2.6 (iv) ]		78	43
	c) Earmarked Funds and Other Funds (Net of expenses)		2,296	2,281
	d) Information Technology Training Reserves [See Note 2.6 (vii)]		1,001	-
	e) General reserve		10,411	834
	<b>TOTAL</b>		<b>18,859</b>	<b>6,316</b>

See accompanying notes 1 to 27 forming part of the financial statements

For and on behalf of the Council

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
<b>CA. Sudeep Shrivastava</b>	<b>V. Sagar</b>	<b>CA. Prafulla P. Chhajed</b>	<b>CA. Naveen N. D. Gupta</b>
Joint Secretary	Secretary	Vice-President	President

In our report referred to even date

**For Hingorani M. & Co.**

Chartered Accountants

Firm registration number: 006772N

Sd/-

**CA. Jagdish Prasad Dhamija**

Partner, Membership No. 015020

New Delhi, 26th September, 2018.

**For Khanna & Annadhanam**

Chartered Accountants

Firm registration number: 001297N

Sd/-

**CA. B.J. Singh**

Partner, Membership No. 007884



**THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**  
**ICAI Bhawan, Indraprastha Marg, New Delhi - 110 002**  
**CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2018**

(₹ in Lakhs)

	Particulars	For the year ended March 31,	
		2018	2017
I	<b>Cash Flow from operating activities</b>		
	Net surplus after prior period adjustments	18,859	6,316
	Adjustments for:		
	-Depreciation and amortisation expense	2,540	2,334
	-Provision no longer required written back	(193)	(114)
	-Interest income	(8,743)	(7,686)
	-Admission fees from members directly allocated to reserves	367	242
	<b>Operating surplus before Working Capital changes</b>	<b>12,830</b>	<b>1,092</b>
	<b>Changes in working capital:</b>		
	<b>Adjustments for (increase) / decrease in operating assets:</b>		
	-Inventories	(79)	242
	-Long-term loans and advances	(8)	416
	-Short-term loans and advances	(462)	1,718
	<b>Adjustments for increase / (decrease) in operating liabilities:</b>		
	-Other long-term liabilities	488	(70)
	-Long-term provisions	6,603	6,647
	-Trade payables	679	(666)
	-Other current liabilities	4,904	634
	-Short-term provisions	370	609
		<b>25,325</b>	<b>10,622</b>
	Income tax deducted at source (recoverable)	(402)	318
	<b>Cash generated from operating activities (A)</b>	<b>24,923</b>	<b>10,940</b>
II	<b>Cash Flow from Investing Activities</b>		
	-Purchase of non-current investments	(51,904)	(24,631)
	-Sale / redemption / (purchase) of current investments	5,585	(8,091)
	-Capital expenditure on fixed assets	(2,104)	(2,858)
	-Proceeds from sale of fixed assets	(197)	103
	-Decrease in earmarked and other funds	14,085	18,434
	-Interest income received	11,288	6,033
	<b>Cash (used in) investing activities (B)</b>	<b>(23,247)</b>	<b>(11,010)</b>
III	<b>Cash Flow from financing Activities</b>		
	-Donation received for buildings	11	18
	-Contribution received	83	3
	-Other fund received/(utilisation)	19	(1)
	<b>Cash from financing activities (C)</b>	<b>113</b>	<b>20</b>

	<b>Net Increase / (Decrease) in cash and cash equivalents (A+B+C)</b>	1,789	(50)	
	<b>Cash and Cash Equivalents at beginning of the year</b>	5,035		5,085
	<b>Cash and Cash Equivalents at closing of the year</b>	<b>6,824</b>		<b>5,035</b>

See accompanying notes 1 to 27 forming part of the financial statements

Notes:

- 1) Cash and Cash Equivalents represent cash on hand and balances with banks (Refer Note. 17).
- 2) Figures in brackets represent outflows.

For and on behalf of the Council

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
<b>CA. Sudeep Shrivastava</b>	<b>V. Sagar</b>	<b>CA. Prafulla P. Chhajed</b>	<b>CA. Naveen N. D. Gupta</b>
Joint Secretary	Secretary	Vice-President	President

In our report referred to even date

**For Hingorani M. & Co.**

Chartered Accountants

Firm registration number: 006772N

Sd/-

**CA. Jagdish Prasad Dhamija**

Partner, Membership No. 015020

New Delhi, 26th September, 2018.

**For Khanna & Annadhanam**

Chartered Accountants

Firm registration number: 001297N

Sd/-

**CA. B.J. Singh**

Partner, Membership No. 007884



## THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

### NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

#### 1. General Information

The Institute of Chartered Accountants of India ("the Institute or ICAI"), having its Head Office at New Delhi, was established on 1st July 1949 under an Act of Parliament viz The Chartered Accountants Act, 1949 for the purpose of regulating the profession of Chartered Accountants in India. In terms of the said Act, the Council of the Institute is entrusted with the task of managing the affairs of the institute. For this purpose, the Council has constituted 5 Regional Councils, one each at Mumbai, Kolkata, Kanpur, Chennai and New Delhi, 5 Decentralised Offices, 13 Sub-Decentralised Offices, 163 branches and one overseas office in Dubai.

#### 2. Summary of Significant Accounting Policies

##### 2.1 Basis of Accounting

The financial statements that comprising Balance Sheet, Statement of Income and Expenditure and Statement of Cash Flow together with Notes, are prepared in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP) to comply with applicable Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India. The financial statements are prepared under the historical cost convention on going concern and on accrual basis unless other wise stated. The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements are consistent with those followed in the previous year.

##### 2.2 Use of Estimates

The preparation of the financial statements in conformity with Indian GAAP requires the Management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) and the reported income and expenses during the year. The Management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actual results could differ due to these estimates and the differences between the actual

results and the estimates are recognised in the periods in which the results are known / materialised.

### 2.3 Inventories

Inventories comprise of publications, study materials, stationery and other stores. Inventories are valued at the lower of cost calculated on first in first out ("FIFO") and the net realisable value after providing for obsolescence and other losses, where considered necessary.

Cost includes all charges in bringing the goods to the point of sale, including octroi and other levies, transit insurance and other incidental charges.

### 2.4 Cash and cash equivalents (for purposes of Cash Flow Statement)

Cash comprises cash on hand and demand deposits with banks. Cash equivalents are short-term balances (with an original maturity of three months or less from the date of acquisition), highly liquid investments that are readily convertible into known amounts of cash and which are subject to insignificant risk of changes in value.

### 2.5 Cash Flow Statement

Cash flows are reported using the indirect method, whereby net surplus is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments. The cash flows from operating, investing and financing activities of the Institute are segregated based on the available information.

### 2.6 Appropriation to Reserves and Allocation to Earmarked Funds

- i) Fee received from members for admission as fellow of the Institute is credited to Infrastructure Reserve Account.
- ii) Donations received for buildings and for research are credited directly to the respective reserve account.
- iii) 25% of the Distance Education Fee, not exceeding 50% of the net surplus of the year is transferred to Education Fund.
- iv) 0.75% of Membership Fee (Annual and Certificate of Practice Fee) received during the year is transferred to the Employees' Benevolent Fund.
- v) From the earmarked funds the following transfers are made to Education Reserve Account:
  - a) From Accounting Research Building Fund 100% of cost of additions (net of deductions if any) to Building Fund relating to Accounting Research Building Fund.
  - b) From Education Fund 50% of cost of additions (net of deductions if any) to Fixed Assets Fund.
- vi) Income from investments of Earmarked Funds is added to Earmarked Funds. The income is allocated based on opening balances of the respective earmarked funds on weighted average basis.
- vii) A reserve of 25% of the Information Technology Training (ITT)/Advance Information Technology Training course Fee has been created for future replacement of computers and other ITT centre infrastructure.

### 2.7 Depreciation and amortisation

Depreciable amount for assets is the cost of an asset, or other amount substituted as cost, less its estimated residual value.

Depreciation on tangible fixed assets has been provided on the written down value method as per the useful life as approved by the Council.

The useful life of the assets has been assessed as under based on technical advice, taking into account the nature of the asset, the estimated usage of the asset, the operating conditions of the asset, past history of replacement, anticipated technological changes, manufacturers warranties and maintenance support, etc. The amortisation rates used for the amortisation of fixed assets are as follows:

Class of Assets	Rate of Depreciation
i) Buildings	5%



ii)	Lifts, electrical installations and fittings	10%
iii)	Computers	60%
iv)	Furniture and fixtures	10%
v)	Air conditioners and office equipments	15%
vi)	Vehicles	20%
vii)	Library books	100%

Leasehold land is amortised over the duration of the lease.

Intangible assets are amortised over their estimated useful life on straight line method as follows:

Computers software - 3 years

The estimated useful life of the intangible assets and the amortisation period are reviewed at the end of each financial year and the amortisation period is revised to reflect the changed pattern, if any.

## 2.8 Revenue recognition

The Revenue is recognised as follows:

- i) Distance education fee is recognised pro-rata over the duration of the respective courses.
- ii) Class room training fee comprises fee received for General Management and Communication Skills Programme ("GMCS"), Information Technology Training ("ITT") and Orientation Programme ("OP"). The income for classroom training and coaching class income is recognised when services are rendered and related costs are incurred.
- iii) Examination fee is recognised on the basis of conduct of the respective examinations.
- iv) Seminar fee is recognised on the basis of conduct of the respective activity.
- v) Membership fee comprising of annual membership fee (including fee for certificate of practice and restoration fee) and entrance fee is recognised as under:
  - a) Annual membership fee (including fee for certificate of practice) is recognised as income when it becomes due for the year. Restoration fee is recognised when it is received.
  - b) Entrance Fee:
    - One third of entrance fee collected at the time of admission as associate member is recognised as income in the year of admission and the balance is recognised in Infrastructure Reserve.
    - Entrance fee collected at the time of admission of person as fellow member is recognised in Infrastructure Reserve.
- vi) Student registration fees is recognised pro-rata over the duration of the respective courses.
- vii) Student Association income is recognised when student is admitted for the course.
- viii) Revenue from post qualification and certificate course is recognised in the period in which services are rendered.

## 2.9 Other income

- a) Income from sale of publications are recognised when the risk and rewards are transferred to the buyer which normally coincide with delivery of goods. Income includes consideration received or receivable, net of discounts and other related taxes, (if any).
- b) Income from students news letter and journal subscription is recognised on pro-rata basis over the period of subscription.
- c) Income from campus interviews and expert advisory fee are recognised when services are rendered and related costs are incurred.
- d) Interest income comprises interest received on deposits with banks in general and earmarked funds.

## 2.10 Fixed Assets

### a) Tangible Assets

Tangible assets are carried at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any.

The cost of fixed assets comprises its purchase price net of any trade discounts and rebates, import duties and other taxes (other than those subsequently recoverable from the tax authorities), directly attributable expenditure on making the asset ready for its intended use. Other incidental expenses and interest on borrowings attributable to acquisition of qualifying fixed assets up to the date the asset is ready for its intended use are also capitalised. Subsequent expenditure on tangible assets after its purchase / completion is capitalised only if such expenditure results in an increase in the future benefits from such asset beyond its previously assessed standard of performance.

**b) Intangible Assets**

Intangible assets are carried at cost less accumulated amortisation and accumulated impairment losses, if any. The cost of intangible assets comprises its purchase price net of any trade discounts and rebates, import duties and other taxes (other than those subsequently recoverable from the tax authorities), directly attributable expenditure on making the asset ready for its intended use, other incidental expenses and interest on borrowings attributable to acquisition of qualifying fixed assets up to the date the asset is ready for its intended use. Subsequent expenditure on intangible assets after its purchase/completion is capitalised only if such expenditure results in an increase in the future benefits from such asset beyond its previously assessed standard of performance.

**c) Capital Work in Progress**

Expenditure incurred on construction of assets which is not ready for their intended use is carried at cost less impairment if any, under Capital Work-in-Progress. The cost includes the purchase cost including import duties and non-refundable taxes if any, directly attributable costs .

**2.11 Investment**

- a) The ICAI invests in Government of India securities approved by central government and fixed deposits with nationalized banks.
- b) Fixed Deposits are carried at cost.
- c) Investments in securities are carried at acquisition cost. The premium paid at the time of purchase is amortized over the remaining period to maturity. Amortization of premium is adjusted against income under the head "interest on investments"
- d) Accrued Interest paid at the time of purchase is set off against first receipt of interest.
- e) A provision is made for diminution in value, other than temporary, if any, for each investment individually.

**2.12 Foreign Currency Transaction**

Transactions in foreign currencies are accounted at the exchange rates prevailing on the date of the transaction.

Foreign currency monetary items outstanding at the balance sheet date are restated at the year-end rates. Non-monetary items are carried at historical cost.

Exchange differences arising on settlement / restatement of foreign currency monetary assets and liabilities are recognised as income or expense in the Statement of Income and Expenditure.

**2.13 Employee benefits**

Employee benefits include provident fund, gratuity fund, compensated absence, long service awards, pension scheme and post-employment medical benefits.

**i) Defined Contribution Plans**

The contribution to provident fund scheme to The Institute of Chartered Accountants of India Provident Fund Trust ('the Trust') are considered as defined contribution plans and are charged as an expense based on the amount of contribution required to be made and when services are rendered by the employees. The Trust is managed by the governing body elected by the Institute.

**ii) Defined Benefits Plans**

For defined benefit plans in the form of gratuity and post retirement pension, the cost of providing benefits is determined using the Projected Unit Credit Method, with actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Actuarial gains and losses are recognised in the Statement of Income and Expenditure in the period in which they occur. Past

service cost is recognised immediately to the extent that the benefits are already vested and otherwise is amortised on a straight-line basis over the average period until the benefits become vested. The retirement benefit obligation recognised in the Balance Sheet represent the present value of the defined benefit obligation as adjusted for unrecognised past service cost, as reduced by the fair value of scheme assets. Any asset resulting from this calculation is limited to past service cost, plus the present value of available refunds and reductions in future contributions to the schemes.

Gratuity liability is funded with Life Insurance Corporation of India. The present value of these defined benefit obligations are ascertained by an independent actuarial valuation as per the requirements of Accounting Standard (AS) - 15 Employee Benefits.

**iii) Short term employee benefits**

The undiscounted amount of short-term employee benefits (i.e. salary, allowances, exgratia etc) expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are recognised during the year when the employees render the service. The short-term employee benefits are expected to occur within twelve months after the end of the period in which the employee renders the related service.

The cost of short-term compensated absences is accounted as under :

- a) in case of accumulated compensated absences, when employees render the service that increase their entitlement of future compensated absences; and
- b) in case of non-accumulating compensated absences, when the absences occur.

**iv) Long-term employee benefits**

Compensated absences which are not expected to occur within twelve months after the end of the period in which the employee renders the related service are recognised as a liability at the present value of the defined benefit obligation as at the balance sheet date less the fair value of the plan assets out of which the obligations are expected to be settled.

**v) Other benefits**

**a) Pension scheme**

The Institute offers its employees benefits in the form of pension. The present value of the obligation as at the balance sheet date is recognised based on the actuarial valuation.

**b) Post retirement medical scheme benefit to retired employees and spouse**

The Institute offers its employees benefits in the form of medical scheme. The present value of the obligation as at the balance sheet date is recognised based on the actuarial valuation.

**2.14 Leases**

Lease arrangements where the risks and rewards incidental to ownership of an asset substantially vest with the lessor are recognised as operating leases. Lease rentals under operating leases are recognised in the Statement of Income and Expenditure on a straight-line basis over the lease term.

**2.15 Impairment of tangible and intangible assets**

The carrying value of assets at each balance sheet date are reviewed for impairment. If any indication of impairment exists, the recoverable amount of such assets is estimated and impairment recognised, if the carrying amount of these assets exceeds their recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the net selling price and their value in use. Value in use is arrived at by discounting the future cash flows to their present value based on an appropriate discount factor. When there is indication that an impairment loss recognised for an asset in earlier accounting periods no longer exists or may have decreased, such reversal of impairment loss is recognised in the statement of income and expenditure .

**2.16 Taxes on income**

The Institute has been granted exemption from Income Tax under section 10(23C) and Section 11 of the Income Tax Act, 1961.

**2.17 Assets held for Earmarked and Other Funds**

Earmarked fund and others funds in the form of deposits with banks maturing after a period of twelve months from the date of balance sheet are classified as non-current and others are classified as current. These are available for use freely at the discretion of the Council except to the extent of total of the earmarked and employee benefit funds.

**2.18 Provisions and Contingencies**

A provision is recognised when there is a present obligation as a result of past events and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation in respect of which a reliable estimate can be made.

Contingent liability is a possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Institute, or is a present obligation that arises from past event but is not recognised because either it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, or a reliable estimate of the amount of the obligation cannot be made. Contingent liabilities are disclosed and not recognised.

Contingent assets are neither recognised nor disclosed.



**THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**  
**NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS**

**NOTE # 3 RESERVES AND SURPLUS**

(₹ in Lakhs)

Particulars	General		Education		Infrastructure		Others*		Total	
	As at March 31,		As at March 31,		As at March 31,		As at March 31,		As at March 31,	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Balance at the beginning of the year	71,796	71,810	35,854	34,874	5,304	5,068	987	741	1,13,941	1,12,493
Add: Appropriation from Statement of Income and Expenditure	10,411	834	-	-	-	-	1,001	-	11,412	834
Transfer from / (to) General Reserve, Infrastructure Reserve and Other Reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfer from / (to) Earmarked Funds	-	(848)	2,489	980	-	(24)	-	247	2,489	355
Admission fees and allocated Entrance fees	-	-	-	-	367	242	-	-	367	242
Donation received for buildings	-	-	-	-	11	18	-	-	11	18
(Utilization)/Addition	-	-	-	-	18	-	1	(1)	19	(1)
<b>Balance at the end of the year</b>	<b>82,207</b>	<b>71,796</b>	<b>38,343</b>	<b>35,854</b>	<b>5,700</b>	<b>5,304</b>	<b>1,989</b>	<b>987</b>	<b>1,28,239</b>	<b>1,13,941</b>

\* Others comprises Library Reserves, Class Room Training Reserves, Foreign Currency Translation Reserve (Dubai branch) etc.



THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF  
INDIA  
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL  
STATEMENTS

## NOTE # 4 EARMARKED FUNDS

( ₹ in Lakhs)

Particulars	Research Funds		Accounting Research Building Fund		Education Fund		Medals and Prizes Funds		Students Scholarship Funds		Employees Benevolent Fund		Other Funds		Total	
	As at March 31,		As at March 31,		As at March 31,		As at March 31,		As at March 31,		As at March 31,		As at March 31,		As at March 31,	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Balance at the beginning of the year	2,282	2,094	793	727	25,204	21,107	236	222	127	120	661	572	5,026	4,357	34,329	29,199
Appropriation from Statement of Income and Expenditure	-	-	-	-	5,073	3,158	-	-	-	-	78	43	-	-	5,151	3,201
Transfer from / (to) Reserves and Surplus	-	-	-	-	(2,489)	(980)	-	-	-	-	-	-	-	625	(2,489)	(355)
Contribution received / Addition during the year	24	-	-	-	-	-	23	3	36	-	-	-	-	-	83	3
Interest income during the year appropriated through Income and Expenditure	173	188	61	66	1,925	1,919	15	16	10	11	50	52	83	92	2,317	2,344
Utilised during the year	-	-	-	-	-	-	(9)	(5)	(6)	(4)	-	(6)	(6)	(48)	(21)	(63)
Balance at the end of the year	2,479	2,282	854	793	29,713	25,204	265	236	167	127	789	661	5,103	5,026	39,370	34,329

Total earmarked funds of Rs 39,370 (previous year Rs 34,329) are held in fixed deposits and Government Securities (See Note 12 &amp; 13)



## THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

## NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

( ₹ in Lakhs)

NOTE # 5: OTHER LONG-TERM LIABILITIES			As at March 31,	
			2018	2017
(a) Fees received in advance				
(i) Education fees			1,206	723
(ii) Journal subscription			13	8
Total			1,219	731
NOTE # 6: PROVISIONS	As at March 31,		As at March 31,	
	2018	2017	2018	2017
	Long-term	Long-term	Short-term	Short-term
Provisions for employee benefits :				
(a) Post employment defined benefits				
(i) Gratuity				
	567	-	454	186
(ii) Pension				
	11,426	10,710	464	406
(b) Provision for leave encashment				
	3,748	3,528	389	345
(c) Provision for Branch Employees (Note-24.17)				
	2,800	2,100		

(d) Provision for Pay Revision (Note-24.18)	<b>4,400</b>	-	-	-
<b>Total</b>	<b>22,941</b>	16,338	<b>1,307</b>	937

<b>NOTE # 7: TRADE PAYABLES</b>		<b>As at March 31,</b>	
		<b>2018</b>	2017
Trade payables		<b>3,677</b>	3,191
<b>Total</b>		<b>3,677</b>	3,191

(₹ in Lakhs)

<b>NOTE # 8: OTHER CURRENT LIABILITIES</b>		<b>As at March 31,</b>	
		<b>2018</b>	2017
(a) Fees received in advance			
(i) Examination fees		<b>7,231</b>	7,106
(ii) Journal subscription		<b>21</b>	16
(iii) Membership fees		<b>2,876</b>	1,886
(iv) Education fees		<b>9,060</b>	7,327
(v) Post qualification courses fees		<b>111</b>	110
(vi) Certificate courses fees		<b>118</b>	40
(vii) Seminar fees :			
(a) Seminar Members		<b>105</b>	62
(b) Seminar Students		<b>2</b>	1
(viii) Class room training fees		<b>1,325</b>	652
(ix) Coaching class fees		<b>84</b>	133
(x) other collections		<b>64</b>	81
<b>Sub Total (A)</b>		<b>20,997</b>	17,414
(b) Other liabilities			
(i) Creditors for purchase of fixed assets		<b>29</b>	4
(ii) Contributions to PF, ESIC, Professional tax etc		<b>96</b>	166
(iii) Statutory dues (Withholding taxes)		<b>317</b>	258
(iv) GST Payable		<b>1,389</b>	-
(v) Security and earnest money deposit		<b>832</b>	787
(vi) Others		<b>614</b>	716
<b>Sub Total (B)</b>		<b>3,277</b>	1,931

<b>Total (A+B)</b>	<b>24,274</b>	19,345
--------------------	---------------	--------



**THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**  
**NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS**

(₹ in Lakhs)

<b>NOTE # 9: TANGIBLE ASSETS</b>		<b>Gross Block</b>				<b>Depreciation</b>				
<b>Particulars</b>	<b>As at march 31,</b>	<b>Cost at the beginning of the year</b>	<b>Additions</b>	<b>Transfers/Deletions</b>	<b>Cost at the end of the year</b>	<b>Accumulated depreciation at the beginning of the year</b>	<b>Charged for the year</b>	<b>Transfers/Deletions</b>	<b>Accumulated depreciation at the end of the year</b>	<b>Net book value at end of the year</b>
Freehold land	2018	19,214	270	(1,821)	17,663	-	-	-	-	17,663
	2017	18,817	397	-	19,214	-	-	-	-	19,214
Leasehold land	2018	5,879	112	1,558	7,549	668	107	49	824	6,725
	2017	5,682	197	-	5,879	582	86	-	668	5,211
Buildings	2018	28,441	3,096	263	31,800	6,600	1,449	(283)	7,766	24,034
	2017	27,789	680	(28)	28,441	5,492	1,127	(19)	6,600	21,841
Lifts, electrical installations and fittings	2018	1,863	342	(22)	2,183	1,063	106	(12)	1,157	1,026
	2017	1,806	63	(6)	1,863	973	92	(2)	1,063	800
Computers	2018	5,129	178	(74)	5,233	4,767	242	(61)	4,948	285
	2017	4,867	301	(39)	5,129	4,383	399	(15)	4,767	362
Furniture and fixtures	2018	4,192	401	(21)	4,572	1,990	241	(10)	2,221	2,351
	2017	4,070	151	(29)	4,192	1,756	237	(3)	1,990	2,202
Air conditioners and office equipments	2018	4,801	634	(48)	5,387	2,850	325	(40)	3,135	2,252
	2017	4,586	259	(44)	4,801	2,535	320	(5)	2,850	1,951
Vehicles	2018	135	-	-	135	101	7	-	108	27
	2017	135	1	(1)	135	92	9	-	101	34
Library books	2018	1,009	32	-	1,041	1,009	32	-	1,041	-
	2017	968	41	-	1,009	968	41	-	1,009	-
<b>Total</b>	<b>2018</b>	<b>70,663</b>	<b>5,065</b>	<b>(165)</b>	<b>75,563</b>	<b>19,048</b>	<b>2,509</b>	<b>(357)</b>	<b>21,200</b>	<b>54,363</b>
	<b>2017</b>	<b>68,720</b>	<b>2,090</b>	<b>(147)</b>	<b>70,663</b>	<b>16,781</b>	<b>2,311</b>	<b>(44)</b>	<b>19,048</b>	<b>51,615</b>

★ Includes Prior Period Depreciation



**THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA  
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS**

(₹ in Lakhs)

NOTE # 10: INTANGIBLE ASSETS	As at March 31,	
	2018	2017
<b>Computer Software</b>		
Cost at the beginning of the year	663	646
Additions	62	19
Transfers/Deletions	21	(2)
<b>Cost at the end of the year</b>	<b>746</b>	<b>663</b>
Amortisation at the beginning of the year	644	623
Charge for the year	31	23
Transfers/Deletions	16	(2)
Amortisation at the end of the year	<b>691</b>	<b>644</b>
<b>Net book value at the end of the year</b>	<b>55</b>	<b>19</b>
Net book value at the beginning of the year	<b>19</b>	<b>23</b>

  

NOTE # 11: CAPITAL WORK IN PROGRESS	As at March 31,	
	2018	2017
Opening balance	13,875	13,202
Add: Addition during the year	561	673
Less: Amount capitalised/adjusted during the year	(3,559)	-
<b>Closing balance</b>	<b>10,877</b>	<b>13,875</b>



**THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA  
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS**

(₹ in Lakhs)

NOTE # 12: INVESTMENTS (at cost)	As at March 31,		As at March 31,	
	2018	2017	2018	2017
	Non-current	Non-current	Current	Current
<b>a. Central Government Securities</b>				
<u>Tradable Securities</u>				
i. 8.27% Government of India 2020	2,588	2,628	-	-
ii. 7.46% Government of India 2017	-	-	-	1,651
iii. 7.49% Government of India 2017	-	-	-	861
iv. 7.80% Government of India 2021	2,588	2,618	-	-
v. 6.35% GOI 2020	995	-	-	-
	<b>6,171</b>	<b>5,246</b>	<b>-</b>	<b>2,512</b>
<u>Non-Tradable Securities</u>				
vi. 8.00% GOI Taxable Bonds- cumulative	11,200	-	-	-
vii. 8% Saving (Taxable) Bond 2003-non cumulative	44,000	-	-	-
	<b>55,200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Book Value</b>	<b>61,371</b>	<b>5,246</b>	<b>-</b>	<b>2,512</b>
<b>Market Value</b>				
-Tradable	6,112	5,214	-	2,514
- Non-Tradable	55,200	-	-	-



(Book value)					
		<b>61,312</b>	<b>5,214</b>	<b>-</b>	<b>2,514</b>
<b>b. State Government Securities</b>					
i. 8.47% Tamil Nadu SDL 2017		-	-	-	3,042
ii. 8.21% Rajasthan UDAY SDL 2018		-	-	-	2,537
iii. 7.75% Rajasthan UDAY SDL 2018		-	2,532	<b>2,506</b>	-
iv. 8.45% Punjab SDL 2023		<b>2,572</b>	-	-	-
v. 8.45% Karnataka SDL 2024		<b>3,068</b>	-	-	-
vi. 8.45% Karnataka SDL 2024		<b>2,045</b>	-	-	-
vii. 8.62% Maharashtra SDL 2023		<b>514</b>	-	-	-
viii. 8.75% West Bengal GS 2022		<b>514</b>	-	-	-
ix. 8.39% Raj Uday SDL 2022		<b>1,537</b>	-	-	-
x. 8.39% Raj Uday Bond 2021		<b>3,904</b>	-	-	-
<b>Book Value</b>		<b>14,154</b>	2,532	<b>2,506</b>	5,579
<b>Market Value</b>		<b>14,209</b>	2,527	<b>2,506</b>	5,574
<b>Sub-Total</b>		<b>75,525</b>	<b>7,778</b>	<b>2,506</b>	<b>8,091</b>

NOTE # 12: INVESTMENTS (at cost)		As at March 31,		As at March 31,	
		2018	2017	2018	2017
		Non-current	Non-current	Current	Current
<b>c. Public Sector Subordinate of Perpetual Basel III Bonds</b>					
i. 10.75% IDBI Bank Ltd.		-	3,018	-	-
ii. 10.95% Oriental Bank of Commerce		-	1,021	-	-
iii. 10.95% Oriental Bank of Commerce		-	1,532	-	-
iv. 9.00% State Bank of India		-	511	-	-
v. 9.00% State Bank of India		-	4,576	-	-
vi. 11.00% Bank of India		-	1,047	-	-
vii. 11.00% Bank of India		-	1,047	-	-
viii. 10.99% Andhra bank		-	3,101	-	-
<b>Book Value</b>		-	15,853	-	-
<b>Market Value</b>		-	15,878	-	-
<b>d. Investment in equity instruments of subsidiary (fully paid up)</b>					
i. Institute of Insolvency Professionals of ICAI 10,00,000 Ordinary shares of Rs. 100 each		<b>1,000</b>	1,000	-	-
ii. Investment ICAI Registered Valuers Organisation		<b>10</b>	-	-	-

Book Value	1,010	1,000	-	-
<b>Sub-Total</b>	<b>1,010</b>	16,853	-	-
<b>Total</b>	<b>76,535</b>	24,631	<b>2,506</b>	8,091
<b>NOTE # 13: Assets held for Earmarked and Others Funds</b>	<b>Non-current</b>	Non-current	<b>Current</b>	Current
Fixed deposits with banks (see note below)	<b>5,229</b>	3,630	<b>54,704</b>	70,388
<b>Total</b>	<b>5,229</b>	3,630	<b>54,704</b>	70,388
<b>Note: Assets held for earmarked comprise:</b>	<b>Non-current</b>	Non-current	<b>Current</b>	Current
-Investments (Note # 12)	<b>76,535</b>	24,631	<b>2,506</b>	8,091
-Assets held for Earmarked and others (Note # 13)	<b>5,229</b>	3,630	<b>54,704</b>	70,388
<b>Total</b>	<b>81,764</b>	28,261	<b>57,210</b>	78,479

Note: Assets held (Current & Non-Current) comprise:	As at March 31,	
	2018	2017
-Earmarked funds (Note # 4)	<b>39,370</b>	34,329
-Employee benefits (Note # 6)	<b>24,248</b>	17,275
-Others	<b>75,356</b>	55,136
<b>Total</b>	<b>1,38,974</b>	1,06,740

NOTE # 14: LOANS AND ADVANCES (Unsecured, considered good)	As at March 31,		As at March 31,	
	2018	2017	2018	2017
	Non-current	Non-current	Current	Current
(a) Security deposits	<b>190</b>	254	<b>362</b>	145
(b) Tax deducted at source	<b>2,256</b>	1,854	-	-
(c) Input Tax Credit	-	-	<b>966</b>	-
(d) GST on advances received from members	-	-	<b>366</b>	-
(e) Other loans and advances				
(i) Loans and advances to employees	<b>660</b>	634	<b>551</b>	561
(ii) Other receivables	<b>291</b>	245	<b>698</b>	1,878
Less: Provision for doubtful receivables	-	-	<b>(229)</b>	(332)
<b>Total</b>	<b>3,397</b>	2,987	<b>2,714</b>	2,252

NOTE # 15: OTHER ASSETS	Non-current	Non-current	Current	Current
(a) Interest accrued				
i. on fixed deposits with banks	<b>28</b>	452	<b>1,045</b>	3,449
ii. on investments	<b>506</b>	1,111	<b>981</b>	123
iii. on loans to employees	<b>144</b>	121	<b>39</b>	32
<b>Total</b>	<b>678</b>	1,684	<b>2,065</b>	3,604

NOTE # 16: INVENTORIES (At lower of cost and net realisable value)	As at March 31,	
	2018	2017
(a) Publication and study materials	<b>1,038</b>	949
(b) Stationery and stores	<b>42</b>	52
<b>Total</b>	<b>1,080</b>	1,001



**THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**

**NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS**

( ₹ in Lakhs)

<b>NOTE # 17: CASH AND BANK BALANCES</b>		<b>As at March 31,</b>	
		<b>2018</b>	2017
(a) Cash on hand		<b>43</b>	36
(b) Balances with banks		<b>6,781</b>	4,999
<b>Total</b>		<b>6,824</b>	5,035

  

<b>NOTE # 18: FEES</b>		<b>For the year ended March 31,</b>	
		<b>2018</b>	2017
(a) Distance education		<b>20,292</b>	18,971
(b) Class room training income		<b>9,209</b>	6,388
(c) Examination		<b>16,870</b>	13,099
(d) Students' registration		<b>948</b>	515
(e) Students' association		<b>414</b>	386
(f) Post qualification courses		<b>747</b>	797
(g) Membership		<b>10,830</b>	5,869
(h) Entrance		<b>106</b>	74
(i) Certificate courses		<b>1,825</b>	1,265
(j) Coaching		<b>1,285</b>	1,221
<b>Total</b>		<b>62,526</b>	48,585

  

<b>NOTE # 19: SEMINAR INCOME</b>			
(a) Members		<b>3,555</b>	3,529
(b) Students		<b>834</b>	904
(c) Non members		<b>1,328</b>	1,088
(d) E-Learning income		<b>44</b>	8
<b>Total</b>		<b>5,761</b>	5,529

  

<b>NOTE # 20: OTHER INCOME</b>			
(a) Interest income			
i. on bank deposit held in general funds		<b>3,234</b>	4,098
ii. from investments		<b>3,114</b>	1,172

iii.	on bank deposit held for earmarked funds	<b>2,317</b>	2,344
iv.	on loans to employees	<b>78</b>	72
(b)	Sale of publications	<b>1,568</b>	1,540
(c)	News letters	<b>187</b>	149
(d)	Journal subscription	<b>113</b>	52
(e)	Campus interview	<b>782</b>	759
(f)	Expert advisory fee	<b>23</b>	25
(g)	Provision no longer required written back	<b>193</b>	114
(h)	Miscellaneous income	<b>713</b>	664
<b>Total</b>		<b>12,322</b>	10,989

NOTE # 21: EMPLOYEE BENEFIT EXPENSE		For the year ended March 31	
		2018	2017
(a)	Salary, pension and other allowances	14,612	16,151
(b)	Contribution to provident and other funds	2,113	847
(c)	Staff welfare expenses	147	192
<b>Total</b>		<b>16,872</b>	<b>17,190</b>

<b>NOTE # 22: OTHER EXPENSES</b>			
(a)	Postage and telephone	<b>2,869</b>	2,639
(b)	Rent, rates and taxes	<b>5,242</b>	5,232
(c)	Domestic Travelling	<b>1,761</b>	1,418
(d)	Overseas related :		
(i)	Overseas travelling	<b>310</b>	256
(ii)	Membership fees for foreign professional bodies	<b>403</b>	342
(iii)	Others	<b>103</b>	52
(e)	Repairs and maintenance	<b>2,301</b>	1,775
(f)	Class room training expenses	<b>3,835</b>	4,833
(g)	Advertisement and publicity	<b>170</b>	398
(h)	Meeting expenses	<b>895</b>	595
(i)	Merit scholarship	<b>176</b>	124
(j)	Audit fees : Head office	<b>11</b>	11
	: Other offices	<b>35</b>	33
(k)	Payments from earmarked funds	<b>21</b>	63
(l)	Prior period adjustments (Net) (Note- 23)	<b>748</b>	227
(m)	GST expenses	<b>2,059</b>	-
(n)	Provision for doubtful advances	<b>229</b>	332
(o)	Loss on sale of investments	<b>285</b>	-
(p)	Other expenses	<b>1,317</b>	1,572
<b>Total</b>		<b>22,770</b>	19,902

<b>NOTE # 23: PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS (NET)</b>			
(i)	Income	<b>(116)</b>	(173)

(ii) Expenses (including depreciation)	864	400
<b>Total</b>	<b>748</b>	<b>227</b>



**THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**  
**NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS**

24 Additional Notes to the Financial Statements

24.01 Contingent liabilities and commitments

(₹ in Lakhs)

**2018      2017**

a. Contingent liabilities

- |  |              |       |
|--|--------------|-------|
| (i) Claims against the Institute not acknowledged as debts   | <b>1,830</b> | 1,216 |
| (ii) Income tax demand - (Refer Note # 24.03)  | <b>4,142</b> | 4,142 |
| (iii) The Institute has received a show cause notice from the Additional Director General, Goods and Service Tax Intelligence, that an amount of ₹ 7,032 lakhs is proposed to be demanded from the Institute claiming that annual fee, certificate of practice fee, entrance fee etc. are liable to service tax. The Institute is of the opinion that no service tax is payable as mentioned in show cause notice. Steps are being taken to send appropriate response to the show cause notice.<br>Based on the discussion with the solicitor, expert opinions taken/status of the case, the management believes that it has a strong chance of success in above mentioned cases and hence no provision there against is considered necessary at this point of time. |              |       |

b. Commitments

(₹ in Lakhs)

- |   |              |       |
|---|--------------|-------|
| (i) Capital commitments (net of advances) | <b>3,654</b> | 4,252 |
|---|--------------|-------|

24.02 Other Receivables in Note 14 # Long term loans and advances include ₹ 243.75 Lakh for stamp duty refund receivable on cancellation of principal and supplementary agreements of acquiring property at Nagpur which has been rejected by the Joint District Registrar (JDR), Nagpur. The Institute has filed two appeals before the Chief Controlling Revenue Authority, Pune under section 53 of Maharashtra Stamp Act challenging the orders passed by JDR, Nagpur which are still pending for final adjudication. The Institute has been advised that it has a good legal case to receive the refund of stamp duty.

24.03 For the assessment year 2014-15, a demand of ₹ 41.42 Crore was raised by income tax department against the Institute. The ITAT has remanded the case back to the Assessing Officer. The management is of the view that in the light of ITAT orders, no demand is likely to arise on completion of fresh adjudication by the assessing officer.

24.04 Directly attributable expenses on the seminar activity have been charged to seminar expenses and related indirect expenditure is charged to functional heads of expenditure.

24 Additional Note to the Financial Statements

24.05 Out of the fee received from the students towards Students Association Fee, a sum of ₹ 250 per student, in respect of students registered after 1st April, 2009, is remitted to Chartered Accountants Students Benevolent Fund.

24.06 Leasehold land includes ₹ 6.17 lakhs paid for the plot of land in Indraprastha Estate, New Delhi (adjacent to existing head office) allotted by Land and Development Authority, New Delhi for which execution of Memorandum of Agreement and Lease Deed is in progress.

24.07 The Institute had initiated a process for digitization of entire activities by undertaking a

project referred as 'Project Parivartan'. For this purpose, Institute had appointed a global integrated service provider (vendor) supervised by a globally reputed project management consultant at a total cost of ₹ 3,981 lakhs. A sum of ₹ 867 lakhs was incurred up to March 31, 2015.

Since the service provider did not carry out the development of digitization as per the requirement even after extended periods, the Institute cancelled the contract and encashed the bank guarantee of ₹ 295 lakhs in the month of June 2015 and the balance amount of ₹ 572 lakhs was written off in the year ended March 31, 2015.

The vendor submitted a proposal requiring the Institute to pay ₹ 807 lakhs including the amount encashed Bank Guarantee. This offer has been rejected by the Institute as the service providers have been terminated and vide letter dated February 08, 2017 has terminated the contract with vendor. No communication has been received from the vendors after contract was terminated.

- 24.08 A land measuring 225 sq. mtrs area of ICAI Bhawan Faridabad, had been acquired by DMRC in January 2013 for which, Faridabad branch had requested for another piece of land, adjacent to the branch in compensation against the acquisition by DMRC. The matter is currently under consideration by Haryana Urban Development Authority.

24 Additional Note to the Financial Statements

- 24.09 Other expenditure includes ₹ 262 lakhs (₹ 278 lakhs) being the reimbursement of costs incurred by Quality Review Board constituted under section 28-A of The Chartered Accountants Act, 1949. Other expenses also include contribution of ₹ 67.50 lakhs (₹ 25 lakhs) made to the Appellate Authority constituted under Section 22 of the Chartered Accountants Act, 1949. Expenses of the Quality Review Board and the Appellate Tribunal are required to be borne by the Institute. Other expenses also include grant of ₹10 lakhs ( Nil ) made to Extensible Business Reporting Languages (XBRL).

- 24.10 A detailed review of the various reserve funds and earmarked funds created in the earlier years and related earmarked investments has been taken up to restructure these funds as per the present requirements and functioning of the Institute.

- 24.11 During the year, the Institute has subscribed ₹ 10 lakhs towards the share capital of its wholly owned subsidiary ICAI Registered Valuers Organisation , a Company registered u/s 8 of the Companies Act, 2013. The investment has been classified as a long term investment and valued at cost.

- 24.12 The reconciliation of Inter branch transactions / balances at the year end is in progress, provision for the net difference of Rs 26.81 lakhs has been made in the accounts. The management is of the opinion that the impact of pending reconciliations will not materially affect the financial statements.

- 24.13 Although the income of the Institute is fully exempt under section 10(23-C)(IV) of the Income Tax Act, 1961, some of the entities have deducted tax at source on payment made to the Institute. The refund of tax deducted at source of ₹ 2,256 Lakhs is likely to be received on final outcome of the disposal of pending rectification / appeal etc.

- 24.14 The Institute has taken a view that the GST Act is applicable to it. The reconciliation of GST paid, payable and GST input is in progress. An amount of ₹ 2,059 Lakhs including ineligible input tax credits and credits attributable to exempted supplies and additional liability and ₹ 140 lakhs of interest on delayed payments has been charged off to the Income and Expenditure Account. GST payable at the end of the year of ₹1,389 lakhs has been included under other liabilities (Note No. 8). An amount of ₹ 966 lakhs as GST input recoverable has been shown under 'Advances (Note No. 14)'. The management is of the opinion that no material adjustments are likely to arise when the reconciliation is completed.

24 Additional Note to the Financial Statements

- 24.15 In view of the Management, the study circles, study chapters and overseas chapters are separate entities and their accounts are not consolidated.

- 24.16 During the year, the fixed assets at most of Branches have been physically verified and reconciliations of physical balances with the book balances is in progress. The management is of the opinion that the impact of the same will not materially effect the financial statements.

- 24.17 The Branch Employees Scheme 2006 has been replaced by new Branch Employee Scheme 2014 which has been approved by the Central Council but not yet implemented. Since 2014-15, a provision of ₹ 7 crore per year is being made in the accounts adding upto ₹ 28 crore as on March 31, 2018. The shortfall / excess of provision will be determined when the revised scheme is fully implemented.
- 24.18 Consequent to revision of salary and allowances of employees effective 1.1.2016 and 1.7.2017 respectively, a provision of ₹ 44 crores has been made during the year and included in Employee Benefit Expenses.



**THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**

**NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS**

**Disclosure under Accounting Standards**

**2 Employee Benefits**

5

**Defined Contribution Plans**

The Institute has recognised an amount of ₹ 597.36 lakhs for the year ended March 31, 2018 (Previous year ₹594.30 lakhs) towards contribution to Provident Fund.

**Defined Benefit plans**

The Institute has provided the following defined benefit plans to its employees

Gratuity :	Funded
Post retirement Pension :	Non-Funded
Compensated Absence:	Non-Funded

**25.1 Details of the Gratuity Plan are as follows**

(₹ in Lakhs)

Description	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
<b>1. Reconciliation of opening and closing balances of obligation</b>				
a. Obligation as at beginning of the year	2,510	2,358	2,213	2,057
b. Current service cost	187	202	184	167
c. Past service cost	915			
d. Interest cost	176	166	169	154
e. Actuarial (gain)/loss	(204)	44	(53)	32
f. Benefits paid	(286)	(260)	(155)	(197)
g. Obligation as at end of the year	3,298	2,510	2,358	2,213
<b>2. Change in fair value of plan assets</b>				
a. Fair value of plan assets as at beginning of the year	2,325	2,292	2,232	2,103
b. Expected return on plan assets	165	183	191	184
c. Actuarial gain/(loss)				

		6	2	6	3
	d. Contributions made by the Institute	84	132	78	239
	e. Benefits paid	(303)	(284)	(215)	(297)
	f. Fair value of plan assets as at end of the year	2,277	2,325	2,292	2,232
<b>3.</b>	<b>Reconciliation of fair value of plan assets and obligations</b>				
	a. Present value of obligation	3,298	2,510	2,358	2,213
	b. Fair value of plan assets	2,277	2,325	2,292	2,232
	c. Amount recognised in the balance sheet Asset/(Liability)	(1,021)	(185)	(66)	19
<b>4.</b>	<b>Expenses recognised during the year</b>				
	a. Current service cost	187	202	184	167
	b. Interest cost	176	166	169	154
	c. Expected return on plan assets	(165)	(183)	(191)	(184)
	d. Actuarial (gain)/loss	(210)	42	(59)	29
	e. Expenses recognised during the year	(12)	227	103	166
<b>5.</b>	<b>Investment details</b>	<b>% invested</b>	<b>% invested</b>	<b>% invested</b>	<b>% invested</b>
	a. Others - Funds with Life Insurance Corporation of India	100	100	100	100
<b>6.</b>	<b>Assumptions</b>				
	a. Discount rate (per annum)	7.65%	7.45%	7.92%	7.85%
	b. Estimated rate of return on plan assets (per annum)	7.45%	7.45%	8.85%	8.85%
	c. Rate of escalation in salary	Basic 3% : DA 6%	Basic 3% : DA 6%	Basic 3% : DA 6%	Basic 3% : DA 6%
	d. Attrition rate	2%	5.00%	5%	5%
	e. Mortality table	IAL 2006-08 Ultimate	IAL 2006-08 Ultimate	IAL 2006-08 Ultimate	IAL 2006-08 Ultimate

## 5.2 Details of the Post Retirement Pension Plans

	Description	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
<b>1.</b>	<b>Reconciliation of opening and closing balances of obligation</b>				
	a. Obligation as at beginning of the year	11,115	5,086	2,684	1,406
	b. Interest cost				



			<b>813</b>	357	211	110
	c. Actuarial (gain)/loss		<b>378</b>	6,063	2,210	1,169
	d. Benefits paid		<b>(416)</b>	(391)	(19)	(1)
	e. Obligation as at end of the year		<b>11,890</b>	11,115	5,086	2,684
<b>2.</b>	<b>Reconciliation of fair value of plan assets and obligations</b>					
	a. Present value of obligation		<b>11,890</b>	11,115	5,086	2,684
	b. Amount recognised in the Balance Sheet Asset/(Liability)		<b>(11,890)</b>	(11,115)	(5,086)	(2,684)
<b>3.</b>	<b>Expenses recognised during the year</b>					
	a. Interest cost		<b>813</b>	357	211	110
	b. Actuarial (gain)/loss		<b>378</b>	6,063	2,210	1,169
	c. Expenses recognised during the year		<b>1,191</b>	6,420	2,421	1,279
<b>4.</b>	<b>Assumptions</b>					
	a. Discount rate (per annum)		<b>7.50%</b>	7.30%	7.90%	7.90%
	c. Rate of escalation in salary		<b>Basic 3% : DA 6%</b>	Basic 3% : DA 6%	Basic 3% : DA 6%	Basic 3% : DA 6%
	d. Attrition rate		<b>2%</b>	5.00%	5%	5%
	e. Mortality table		<b>LIC 1996-98</b>	LIC 1996-98	LIC 1996-98	LIC 1996-98
			<b>Ultimate</b>	Ultimate	Ultimate	Ultimate

**25.3 Employee Benefits (Contd..)****Details of Leave Encashment**

( • in Lakhs)

	<b>Description</b>	<b>2017-18</b>	2016-17	2015-16	2014-15
<b>1.</b>	<b>Reconciliation of opening and closing balances of obligation</b>				
	a. Obligation as at beginning of the year	<b>3,873</b>	3,217	2,857	2,359
	b. Current service cost	<b>182</b>	305	280	338
	c. Interest cost	<b>274</b>	227	216	175
	c. Actuarial (gain)/loss	<b>188</b>	127	115	259
	d. Benefits paid	<b>(380)</b>	(348)	(251)	(274)
	e. Obligation as at end of the year	<b>4,137</b>	3,528	3,217	2,857
<b>2.</b>	<b>Reconciliation of fair value of plan assets and obligations</b>				
	a. Present value of obligation				

		<b>4,137</b>	3,528	3,217	2,857
	c. Amount recognised in the Balance				
		<b>(4,137)</b>	(3,528)	(3,217)	(2,857)
	Sheet Asset/(Liability)				
<b>3.</b>	<b>Expenses recognised during the year</b>				
	a. Current service cost	<b>182</b>	305	280	338
	b. Interest cost	<b>274</b>	227	216	175
	c. Actuarial (gain)/loss	<b>188</b>	127	115	259
	d. Expenses recognised during the year	<b>644</b>	659	611	772
<b>4.</b>	<b>Assumptions</b>				
	a. Discount rate (per annum)	<b>7.65 %</b>	7.45%	7.92%	7.85%
	c. Rate of escalation in salary	<b>Basic 3 % : DA 6%</b>	Basic 3 % : DA 6%	Basic 3 % : DA 6%	Basic 3 % : DA 6%
	d. Attrition rate	<b>2 %</b>	5.00%	5%	5%
	e. Mortality table	<b>IAL 2006-08</b>	IAL 2006-08	IAL 2006-08	IAL 2006-08
		<b>Ultimate</b>	Ultimate	Ultimate	Ultimate

## 26. Segment Reporting

The Institute's operations are confined to "furtherance of the profession of Chartered Accountancy" and predominantly spread in India. Hence all its operations fall under single segment within the meaning of Accounting Standard (AS) - 17 Segment Reporting.

27. Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever necessary to correspond with the current year's classification / disclosure.

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
<b>CA. Sudeep Shrivastava</b>	<b>V. Sagar</b>	<b>CA. Prafulla P. Chhajed</b>	<b>CA. Naveen N. D. Gupta</b>
<b>Joint Secretary</b>	<b>Secretary</b>	<b>Vice-President</b>	<b>President</b>

In our report referred to even date

<b>For Hingorani M. &amp; Co.</b>	<b>For Khanna &amp; Annadhanam</b>
Chartered Accountants	Chartered Accountants
Firm registration number: 006772N	Firm registration number: 001297N

Sd/-	Sd/-
<b>CA. Jagdish Prasad Dhamija</b>	<b>CA. B.J. Singh</b>
Partner, Membership No. 015020	Partner, Membership No. 007884

New Delhi, 26th September, 2018.

V. SAGAR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./239/18]